

आधुनिक विश्व में वैचारिक संघर्ष

लेखक
वी० कोर्तुनोव

राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, (प्रा०) लि०
जयपुर

THE BATTLE OF IDEAS IN THE MODERN WORLD
का हिंदी अनुवाद

English Edition

Progress Publishers, Moscow

In arrangement with Mezhdunarodnaya Kniga, Moscow

संपादन :

मोहन भोत्रिय

अनुवाद :

याज्ञवल्क्य गुरु

गिरधारीलाल व्यास

हिंदी संस्करण

© राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०

चमेलीवाला मार्केट, एम. आई. रोड,

जयपुर-302 001

दिसंबर 1984 (RPPH-3)

मूल्य : 12.50

भारती प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित तथा रामपाल द्वारा राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०, जयपुर की ओर से प्रकाशित ।

प्रकाशक की ओर से

यह पुस्तक कम्युनिस्ट विचारधारा एवं कम्युनिज्म विरोध के संघर्ष की समस्याओं के विस्तृत दायरे को अध्ययन-परिधि में ले आई है। डॉ० कोर्तुनोव ने एक-एक करके इस संघर्ष की विभिन्न अवस्थाओं की पड़ताल की है; ब्रूजर्ब विचारधारा के विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है; कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धांतों तथा मनगढ़ंत धारणाओं को खंडित किया है तथा कम्युनिस्ट दृष्टिकोण की व्याख्या को उभारा है। उनकी लेखन शैली तर्कपरक एवं स्पष्ट है।

यह पुस्तक सूचनापरक एवं तर्कपूर्ण होने के कारण पाठकों को रुचेगी।

अनुक्रम

	पाठकों से दो शब्द	9
	प्रस्तावना	11
अध्याय : 1	कम्युनिज्म के विरुद्ध धर्मयुद्ध	19
अध्याय : 2	विचारों के संघर्ष की नयी अवस्था	46
अध्याय : 3	मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन	73
अध्याय : 4	प्राविधिक नियतिवाद के कल्पनालोक	103
अध्याय : 5	आर्थिक विकास की अवधारणाओं का संकट	131
अध्याय : 6	विश्व पूँजीवाद का अधःपतन	146
अध्याय : 7	इजारेदारी-विरोधी-मोर्चे का निर्माण	172
अध्याय : 8	सामाजिक जीवन से युद्ध को निष्कासित करो	195
अध्याय : 9	आज का मूल मुद्दा	220
अध्याय : 10	अमिट शांति के आसार : मार्ग और प्रगाढ़ मैत्री	244
अध्याय : 11	भविष्य की देहलीज़ पर	279
	उपसंहार	307

वैचारिक संघर्ष की गहनता और उत्कटता की दृष्टि से हमारे युग की तुलना किसी अन्य युग के साथ नहीं की जा सकती, भले ही वह अनेक राष्ट्रों के इतिहास के पुनर्जागरण एवं बोधोदय जैसे निर्णायक युग ही क्यों न रहे हों। वर्तमान वैचारिक संघर्ष की तीव्रता हमारे समय में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रतिच्छाया है, जो पूँजीवाद और समाजवाद के बीच ऐतिहासिक मुकाबले से उत्पन्न होती है और इसका विद्यमान स्तर सामाजिक और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्तियों की जटिल अन्तःक्रिया से पूर्णता प्राप्त करता है।

लेखक का लक्ष्य, इस पुस्तक को लिखते समय, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर पूँजीवाद और समाजवाद के बीच चल रहे वैचारिक संघर्षों की मुख्य मंजिल का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने का रहा है। यह कार्य स्वयं इस कृति को विवादास्पद बना देता है क्योंकि एक या दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए लेखक को अनेक प्रचलित वैचारिक और राजनीतिक अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना पड़ा है।

पुस्तक में उठायी गयी समस्याओं का अधिक पूर्णता के साथ अध्ययन करने की दृष्टि से लेखक ने समस्याओं की, अतीत के ऐतिहासिक अभियान की सहायता से उनके विकास के आधार की, परीक्षा करने का प्रयास किया है। यह युद्ध और शान्ति की समस्या तथा कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विरोधी विश्व दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष के उदय की समस्या के सम्बन्ध में विशेष रूप से सही है। सभी मामलों में, लेखक ने उठायी गयी समस्याओं का बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण करने और उनके मध्य ऐतिहासिक रूप से सुसंगत और तर्कपूर्ण सम्बन्ध प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। सरचना के विचार से इस अध्ययन को खंडों में विभाजित करनेवाली रेखाएँ एक सीमा तक स्वैच्छिक है, किन्तु इन विभागों में निश्चित तर्क संगतता है।

आरम्भ के प्रकरणों में कम्युनिस्ट आन्दोलन के आदि से आज तक के युग के वैचारिक संघर्ष का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया गया है। और इसी के सामानान्तर सामाजिक, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्तियों के विकास पर आधारित कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्तों की परीक्षा की गयी है।

अनुवर्ती प्रकरणों में, अति प्रचलित वैचारिक सिद्धान्तों में पूँजीवादी विचारकों द्वारा हाल के वर्षों में उठायी गयी समस्याओं के वैकल्पिक उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं। यह कार्य मार्क्सवाद के सिद्धान्तों तथा समाजवाद की आन्तरिक एवं वैदेशिक नीतियों के अनुभवों के निष्कर्षों के आधार पर किया गया है।

अन्त के प्रकरणों में, जो एक प्रकार से पूर्ववर्ती प्रकरणों का उपसंहार है, लेखक ने भविष्य के समाज पर दृष्टिपात किया है और सामाजिक विकास, भावी पथ के लिए मनुष्य की खोज और तीसरी सहस्राब्दी के आरम्भ काल में सामने आने वाली समस्याओं की परीक्षा करने का प्रयास किया है।

इस प्रकार, पुस्तक के पहले भाग में निकटवर्ती अतीत की, दूसरे भाग में, वर्तमान की और तीसरे में भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। लेखक के विचार से पद्धति के अनुसार बीते कल, आज और आगामी कल की प्रक्रियाओं के द्वन्द्वात्मक अन्तःसम्बन्ध से जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है उसका पूर्ण चित्र प्राप्त करना सम्भव है।

हमारे समय में सामाजिक-राजनीतिक विषय पर कोई भी कृति, यदि उसका उद्देश्य वास्तविकता को यथार्थ रूप से समझना है तो, कुछ सीमा तक लेखक के अपने अनुसंधान और अपने साधियों के विचारों, विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना से प्राप्त परिणामों, अपने निरीक्षणों, सम्पर्कों और विचार-विनिमयों के निष्कर्षों का समन्वित रूप होगी।

वर्तमान पुस्तक भी लेखक के द्वारा सोवियत संघ और विदेशों में जनता के अनेक साक्षात्कारों का संक्षिप्त विवरण है।

इस सम्बन्ध में, लेखक उन सबके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित करना चाहता है जिन्होंने किसी भी प्रश्न पर हुई इन बहसों में उत्तरों को खोजने में सहायता की है, उससे विचार-विमर्श किया है या आलोचना की है।

निस्सन्देह, प्रस्तुत कृति किसी भी प्रकार, उठाये गये प्रश्नों का अन्तिम उत्तर देने का दावा नहीं करती। यह केवल वर्तमान प्रश्नों को सही ढंग से प्रस्तुत करने और उन पर विचार-विमर्श करने का प्रयास करती है। यह सम्भव है कि पाठक, विशेष रूप से पाश्चात्य पाठक इस पुस्तक की कुछ बातों पर बहस करें अथवा लेखक से अपनी असहमति व्यक्त करें अथवा उसके दृष्टिकोण के पूरी तरह नकार दें, तथापि यह पुस्तक अपना लक्ष्य पूरा करेगी, क्योंकि उनमें इसका यह भी एक लक्ष्य है कि यहाँ बहस की गयी समस्याओं में रुचि उत्पन्न करें। किसी भी प्रकार यह कोई सिद्ध मंत्र प्रस्तुत नहीं करती या लेखक द्वारा दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयत्न नहीं करती अपितु यह वर्तमान पीढ़ी की विद्यमान समस्याओं पर बहस या विचार-विमर्श करने का आमन्त्रण है। इस भावना के साथ यह पाठकों को समर्पित है।

प्रस्तावना

प्रत्येक पीढ़ी इस बात के लिए कारण खोज लेती है कि उसका अपना काल सभ्यता के इतिहास में एक विशेष काल है और उसका असाधारण और अनुपम रूपों में वर्णन करती है। वर्तमान पीढ़ी के पास ऐसा करने के पर्याप्त से अधिक आधार विद्यमान है।

विद्वानों, लेखकों, समाजशास्त्रियों और राजनीति वैज्ञानिकों ने बीसवीं शताब्दी के सारतत्व को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए इसे वैज्ञानिक व्याख्या दी है, शक्तिशाली शब्दों और सुमधुर सूक्तियों का प्रचुर उपयोग किया है, बड़ी ऐतिहासिक समानताएँ दिखायी हैं और आश्चर्यजनक विरोधाभास और लक्षण खोज निकाले हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ करेंगे।

अमरीकी राजनीति वैज्ञानिक हंस मॉर्गेन थाॅ का कथन है कि आधुनिक युग ने इतिहास में एक नये युग के द्वार का उद्घाटन किया है, वह पूर्ववर्ती युगों से इतना भिन्न है जितना कि विद्यमान युग मध्य युगों से अथवा मध्य युग प्राचीन युगों से भिन्न था।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं रिपब्लिकन रैडिकल एट रैडिकल सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जीन जेकयुइस सर्वेन श्राइबर कहते हैं "“औद्योगिक विश्व के कुछ भागों में, दो हजारहरे वर्ष का समाज आज हमारे जाने हुए समाज से इतना भिन्न होगा जितना कि इस समय हमारा भाग मिस और नाइजीरिया से है।”¹

पश्चिमी जर्मनी के पत्रकार और सनसनीखेज पुस्तक 'गाड्स ग्रेन्स एंड स्कालसें' के रचयिता सी० डब्ल्यू० सेरम का कहना है : "हम बीसवीं शताब्दी में मानवता के पाँच सहस्राब्दियों तक विस्तृत युग का उपसंहार कर रहे हैं” स्पेंगुलर के अनुमान के अनुसार पाश्चात्य ईसाइयत के आरम्भ के रोम की स्थिति में नहीं हैं अपितु ईसा पूर्व 3000 की स्थिति में हैं।”²

अमरीकी समाजशास्त्री आलविन टॉफ़लर कहते हैं : “अधिकांश विख्यात

1 जीन-जेकयुइस-सर्वेन श्राइबर, ले डेफी अमेरिकन, पेरिस 1969, पृ० 44

2. आल्विन टॉफ़लर, फ्यूचर शॉक, न्यूयार्क 1971, पृ० 15

अनुवर्ती प्रकरणों में, अति प्रचलित वैचारिक सिद्धान्तों में पूँजीवादी विचारकों द्वारा हाल के वर्षों में उठायी गयी समस्याओं के वैकल्पिक उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं। यह कार्य मार्क्सवाद के सिद्धान्तों तथा समाजवाद की आन्तरिक एवं वैदेशिक नीतियों के अनुभवों के निष्कर्षों के आधार पर किया गया है।

अन्त के प्रकरणों में, जो एक प्रकार से पूर्ववर्ती प्रकरणों का उपसंहार है, लेखक ने भविष्य के समाज पर दृष्टिपात किया है और सामाजिक विकास, भावी पथ के लिए मनुष्य की खोज और तीसरी सहस्राब्दी के आरम्भ काल में सामने आने वाली समस्याओं की परीक्षा करने का प्रयास किया है।

इस प्रकार, पुस्तक के पहले भाग में निकटवर्ती अतीत की, दूसरे भाग में, वर्तमान की और तीसरे में भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। लेखक के विचार से पद्धति के अनुसार चीते कल, आज और आगामी कल की प्रक्रियाओं के द्वन्द्वात्मक अन्तःसम्बन्ध से जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है उसका पूर्ण चित्र प्राप्त करना संभव है।

हमारे समय में सामाजिक-राजनीतिक विषय पर कोई भी कृति, यदि उसका उद्देश्य वास्तविकता को यथार्थ रूप से समझना है तो, कुछ सीमा तक लेखक के अपने अनुसंधान और अपने साधियों के विचारों, विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना से प्राप्त परिणामों, अपने निरीक्षणों, सम्पर्कों और विचार-विनिमयों के निष्कर्षों का समन्वित रूप होगी।

वर्तमान पुस्तक भी लेखक के द्वारा सोवियत संघ और विदेशों में जनता के अनेक साक्षात्कारों का संक्षिप्त विवरण है।

इस सम्बन्ध में, लेखक उन सबके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित करना चाहता है जिन्होंने किसी भी प्रश्न पर हुई इन बहसों में उत्तरों को खोजने में सहायता की है, उससे विचार-विमर्श किया है या आलोचना की है।

निस्सन्देह, प्रस्तुत कृति किसी भी प्रकार, उठाये गये प्रश्नों का अन्तिम उत्तर देने का दावा नहीं करती। यह केवल वर्तमान प्रश्नों को सही ढंग से प्रस्तुत करने और उन पर विचार-विमर्श करने का प्रयास करती है। यह सम्भव है कि पाठक, विशेष रूप से पाश्चात्य पाठक इस पुस्तक की कुछ बातों पर बहस करें अथवा लेखक से अपनी असहमति व्यक्त करें अथवा उसके दृष्टिकोण के पूरी तरह नकार दें, तथापि यह पुस्तक अपना लक्ष्य पूरा करेगी, क्योंकि उनमें इसका यह भी एक लक्ष्य है कि यहाँ बहस की गयी समस्याओं में रुचि उत्पन्न करें। किसी भी प्रकार यह कोई सिद्ध मंत्र प्रस्तुत नहीं करती या लेखक द्वारा दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयत्न नहीं करती अपितु यह वर्तमान पीढ़ी की विद्यमान समस्याओं पर बहस या विचार-विमर्श करने का आमन्त्रण है। इस भावना के साथ यह पाठकों को समर्पित है।

प्रस्तावना

प्रत्येक पीढ़ी इस बात के लिए कारण खोज लेती है कि उसका अपना काल सभ्यता के इतिहास में एक विशेष काल है और उसका असाधारण और अनुपम रूपों में वर्णन करती है। वर्तमान पीढ़ी के पास ऐसा करने के पर्याप्त से अधिक आधार विद्यमान हैं।

विद्वानों, लेखकों, समाजशास्त्रियों और राजनीति वैज्ञानिकों ने बीसवीं शताब्दी के सारतत्व को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए इसे वैज्ञानिक व्याख्या दी है, शक्तिशाली शब्दों और सुमधुर सूक्तियों का प्रचुर उपयोग किया है, बड़ी ऐतिहासिक समानताएँ दिखायी हैं और आश्चर्यजनक विरोधाभास और लक्षण खोज निकाले हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ करेंगे।

अमरीकी राजनीति वैज्ञानिक हंस मॉर्गन थॉ का कथन है कि आधुनिक युग ने इतिहास में एक नये युग के द्वार का उद्घाटन किया है, वह पूर्ववर्ती युगों से इतना भिन्न है जितना कि विद्यमान युग मध्य युगों से अथवा मध्य युग प्राचीन युगों से भिन्न था।

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं रिपब्लिकन रैडिकल एट रैडिकल सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जीन जेकयुइस सर्वन थाइबर कहते हैं "औद्योगिक विश्व के कुछ भागों में, दो हजारहवें वर्ष का समाज आज हमारे जाने हुए समाज से इतना भिन्न होगा जितना कि इस समय हमारा भाग मिस्र और नाइजीरिया से है।"¹

पश्चिमी जर्मनी के पत्रकार और मनसनीखेज पुस्तक 'गाइस् ग्रैन्स एंड स्काल्स' के रचयिता सी० डब्ल्यू० सेरम का कहना है: "हम बीसवीं शताब्दी में मानवता के पाँच सहस्राब्दियों तक विस्तृत युग का उपसंहार कर रहे हैं" स्पेगुलर के अनुमान के अनुसार पाश्चात्य ईसाइयत के आरम्भ के रोम की स्थिति में नहीं हैं अपितु ईसा पूर्व 3000 की स्थिति में है।"²

अमरीकी समाजशास्त्री आलविन टॉफ़लर कहते हैं: "अधिकांश विख्यात

1. जीन-जेकयुइस-सर्वन थाइबर, से डेफी अमेरिकन, पेरिस 1969, पृ० 44

2. आलविन टॉफ़लर, प्रयूवर शॉक, न्यूयार्क 1971, पृ० 15

सम्मतियाँ कहती है कि वर्तमान युग मानव इतिहास के द्वितीय महाविभाजन में किंचित् भी कम नहीं है, इसकी तुलना केवल ऐतिहासिक सातत्य में सर्वप्रथम हुए महाविभाजन से—बर्बर युग से सम्य युग में संक्रमण से—की जा सकती है।¹

पहली नज़र में, ये और इसी प्रकार के अन्य कथन कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भले लगें, परन्तु किसी हद तक उनकी प्रामाणिकता सन्देह से परे हैं।

निस्सन्देह, बीसवीं शताब्दी मानवता के इतिहास में सर्वाधिक क्रान्तिकारी शताब्दी है। इसका आरम्भ ही असाधारण गम्भीर सामाजिक परिवर्तनों से, विशाल सध्या में सामान्यजन के ऐतिहासिक विकास में सक्रिय और अपूर्व योगदान से और बौद्धिक क्षेत्र में व्यापक महत्व की प्रगति से लक्षित किया गया। इसी कारण इतिहास सामाजिक प्रगति के पथ पर दृढ़ता से उड़ान भर सका जैसी पहले कभी नहीं भर सका था। इतिहास का एक नया युग आरम्भ हुआ जिसके सारतत्व को लेनिन ने इन शब्दों में प्रकट किया : “पूँजीवाद और उसके अवशेषों का उन्मूलन तथा कम्युनिस्ट व्यवस्था के आधारों की स्थापना।”² दूसरे शब्दों में, इसके सारतत्व की शब्दावली में, हमारा ममय पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक संरचना से समाजवाद में संक्रमण का युग है।

तथापि, वर्तमान युग को केवल दो संरचनाओं के मध्य विभाजक रेखा के रूप में बताना पर्याप्त नहीं है। केवल इस परिस्थिति को ही इसके असाधारण युग होने का कारण मानना पर्याप्त नहीं है। यदि संरचना के परिवर्तन को ही एकमात्र कसीटी माना जाय तो हमारी शताब्दी किसी भी प्रकार उन दूसरी शताब्दियों से भिन्न नहीं है जिनमें एक उत्पादन प्रणाली का स्थान दूसरी ने लिया था। तथापि हमारे मामले में, यह गुणात्मक रूप से नयी संरचना में संक्रमण का प्रश्न है एक ऐसी संरचना में जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त कर देती है। इसी कारण हमारा युग, जैसाकि एंगेल्स का पूर्वानुमान था, केवल एक संरचना के स्थान पर दूसरी की स्थापना का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता अपितु “आवश्यकता के राज्य से स्वतंत्रता के राज्य पर मनुष्य के आरोहण” का भी प्रतिनिधित्व करता है।³

बहुत से पश्चिमी लेखक क्रान्तिकारी संक्रमण का वर्तमान युग की प्रकृति के रूप में उल्लेख करते हुए और उस पर बल देते हुए, कहते हैं कि यह जो पुरानी व्यवस्था का स्थान ले रहा है समाजवाद नहीं है, अपितु पूँजीवाद का ही नया

1. आल्विन टाफ्लर, *प्यूब्लिक रॉक*, न्यूयार्क 1917, पृ० 14

2. वी० आई० लेनिन “इटली की समाजवादी पार्टी के आन्तरिक सभ्य के सम्बन्ध में” सकलित रचनाएँ, खण्ड 31, पृ० 392

3. ए० एंगेल्स, *एंटोइग्नरिंग*, मास्को, 1975, पृ० 336.

रूपान्तरण है जो 'औद्योगिक' और 'औद्योगिकोत्तर' समाज में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति के प्रभाव के अन्तर्गत सम्मानित हुआ है। वे दावा करते हैं कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति पूँजीवाद और समाजवाद के बीच और मजदूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच विरोधों को स्वयमेव हटा देती है। नये के उनके वर्णन में, औद्योगिकोत्तर युग जिसे कि वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति कथित रूप से लग-भग स्वतः ही उत्पन्न करती है, सामान्यतया एक पहलू (यद्यपि वह बहुत महत्वपूर्ण है)—भौतिक सम्पदा का उत्पादन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है जबकि समाज की सामाजिक-राजनीतिक संरचना की आवश्यक रूप से उपेक्षा की गयी है। जबकि नयी सामाजिक-आर्थिक संरचना—कम्युनिस्ट समाज—का उदय और विकास केवल भौतिक संपदा में वृद्धि तक ही सीमित नहीं : इसका अर्थ है जनगण के समस्त सामाजिक-राजनीतिक सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन। यह 'मानव समाज' की प्रागैतिहासिकता की समाप्ति' को और उसके 'वास्तविक इतिहास' के आरम्भ को लक्षित करता है।

अपनी सार्थकता में, इतिहास में इस महान और विश्व-व्यापी परिवर्तन की तुलना वास्तविक रूप में केवल बर्बर युग से वास्तविक सभ्यता में सक्रमण के साथ ही की जा सकती है। जहाँ तक आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति की बात है वह एक प्रकार का विस्फोट (निस्सन्देह तात्कालिक नहीं, अपितु दीर्घ-कालिक) तथा उत्पादक शक्तियों के उभार के रूप में है जो उत्पादन सम्बन्धों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। निस्सन्देह, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगतियों का स्वयं में एक स्थायी मूल्य है। साथ-ही-साथ, वे सामाजिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करती हैं, उनको निरन्तर नया वेग प्रदान करती हैं, सामाजिक क्रान्ति के कदम को तेज करती हैं। यह वह महत्वपूर्ण पहलू है जिसे पूँजीवादी देशों के शोधकर्मी प्रायः विस्मृत कर देते हैं।

वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति का तथा वर्तमान की सामाजिक क्रान्तियों का उद्गम इस शताब्दी के आरम्भ तक पहुँचता है। पूरे विज्ञान को अपने सैद्धान्तिक शास्त्रीय आधारों की फिर से परीक्षा करनी पड़ी। इसे बहुत-सी पिछली अवधारणाएँ छोड़नी पड़ी और इससे भी आगे बढ़कर विश्व के सम्बन्धी वर्तमान समझ तक पहुँचने के लिए चिन्तन के समग्र ढाँचे को संशोधित करना पड़ा। जैसा कि हमें ज्ञात है, यह वैज्ञानिक क्रान्ति पिछली 19वीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सिद्धान्त में और प्रयोग में प्राप्त उपलब्धियों से प्रवर्तित हुई थी जिनमें से कुछ दो हैं :—क्यान्टम सिद्धान्त का और सापेक्षवाद के सिद्धान्त का निर्माण,

परमाणु के प्रतिमान का परिष्कार, और रेडियोधर्मिता के परिघटन की खोज। संक्षेप में, ये उपलब्धियाँ विज्ञान के इतिहास में 'भौतिकी में क्रान्ति' के रूप में दिखायी गयी, जिनके द्वारा अन्ततः श्रम के उपकरणों में क्रान्ति हुई—अर्थात् वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति (STR) का मार्ग प्रशस्त हुआ।

जैसे-जैसे वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रान्ति तेज रफ़्तार से आगे बढ़ी, उसने पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति पर आधारित समाज की अतिपक्षयता के रूप में परिभाषित प्रकृति का पर्दाफ़ाश कर दिया। जैसाकि व्यवहार से ज्ञात होता है, विज्ञान एवं प्राविधिकी की बहुत-सी उपलब्धियाँ साधारणतया अपने उग्र तरीकों से एकरूपता लाने वाली शैया के नीचे दबाकर नहीं रखी जा सकती, राज्य-इजारेदारी आर्थिक व्यवस्थाके ढाँचे में भी उनको नहीं बैठाया जा सकता। ऐसा करने के प्रयास गुलीवर के बूटो पर लिलीपुटियों के प्रयासों का स्मरण कराते हैं।

दूसरी ओर, वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रान्ति की उपलब्धियों की प्रकृति ही विशाल उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ सम्पृक्त होकर उत्पादन के साधनों पर पूँजीपतियों के स्वामित्व के सिद्धान्तों के साथ तथा पूँजीवाद की इजारेदारी मजिल के अन्तर्निहित कानूनों के साथ सुस्पष्ट विरोधों के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है। राजा आयट्रेस (Actes) के बीजों¹ की तरह वैज्ञानिक और प्राविधिक विचारों के आविष्कार, पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों की अस्वास्थ्यकर भूमि में बोये जाकर अन्ततः स्वयं बोने वाले के ही विरुद्ध हो जाते हैं, और प्रतिभा की शक्तिशाली उपलब्धियाँ मानव समाज के विरुद्ध हो जाती हैं। उत्पादन की अराजक पूँजीवादी पद्धति की स्थितियों में वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रान्ति की उपलब्धियाँ अनिवार्यतया भ्रष्ट और कभी-कभी उच्छृंखल हो जाती है। इजारेदार पूँजी की संपत्ति बनकर वे इसके द्वारा उसके निजी हितों के लिए काम में लाई जाती हैं और अब्याख्येय भ्रान्तियों तथा इससे भी बुरे आत्मविनाश के खतरे मानवता के सामने लाती हैं।

इस प्रकार वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रान्ति पूँजीवाद के उन्मूलन को न केवल आगे प्रगति की पूर्वावश्यकता ही बनाती है, अपितु स्वयं सम्भ्यता की रक्षा करने की शर्त भी बनाती है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति का सामाजिक क्रान्ति को तीव्र करने वाले कारक के रूप में तथा इसके आदर्शों के जनक के रूप में भी यही लक्ष्य है। इसमें दो प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया अभिव्यक्त होती है, जो यद्यपि स्वभावतः भिन्न है,

1. ग्रीकनी विषय के अनुसार कालजिस् के राजा आयट्रेस ने जैसन के कौशल और साहस की परीक्षा की जिसके लिए उसने उसे विषधर के दाँतो को बोने के लिए दिया। जब जैसन ने दाँतो को बोया, सगस्त मनुष्यों की एक फ़सल उग आयी और उसके विरुद्ध छड़ी हो गयी।

पर ऐतिहासिक रूप से सम्बद्ध है और दोनों साथ मिलकर हमारे युग की संक्रमण की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं।

एक सामाजिक-आर्थिक संरचना से दूसरी में संक्रमण बिना संघर्ष और पीड़ा के नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल उत्पादन की आर्थिक पद्धति के स्थान पर दूसरी का स्थापित होना नहीं है अपितु एक महान् सामाजिक और आत्मिक क्रान्ति भी है। इस प्रकार, पुरातन और नवीन के बीच, भ्रष्टासन्न और उदीयमान के बीच मुकाबला अपरिहार्य है। और यही है जो अपने क्रम में वैचारिक संघर्ष की उत्तेजना को—विरोधी विश्व दृष्टिकोणों के बीच, दार्शनिक दृष्टियों के बीच और आत्मिक भूल्यों की व्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को—तीव्र करता है। इसीलिए वर्तमान युग अन्य किसी भी संक्रमणकालीन युग से भी अधिक वैचारिक संघर्ष में भरा-पूरा है क्योंकि मौलिक सामाजिक उद्भेद होने को है, न केवल पुरानी पूँजीवादी राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है अपितु इसकी मानसिकता के प्रतिमान भी नष्ट हो रहे हैं। जनगण के मस्तिष्कों में एक क्रान्ति, विचारों का संघर्ष, प्रगति पर है। बड़े परिश्रम के साथ नया समाज जन्म ले रहा है; जैसाकि लेनिन ने इसके सम्बन्ध में कहा था—“यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह विश्व तैयार शुद्ध माल की तरह अस्तित्व में नहीं आता। जुपिटर के सिर से जैसे मिनर्वा निकला था उस प्रकार नहीं आता।”¹

इतिहास में इस प्रकार का कोई दूसरा युग नहीं देखने में आया जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का ऐसा सकेन्द्रण हो, इतनी अधिक संख्या में जटिल कार्य भार सामने आये हो और उनका इस प्रकार की अन्तर्विरोधी उसलतनों से भर दिया गया हो जैसाकि बीसवीं शताब्दी में। सामाजिक न्याय और समान अधिकार के लिए शोषित वर्गों के युगों से चले आ रहे संघर्ष में बहुत-सी ‘शाश्वत’ समस्याओं का समाधान अब राष्ट्रों के व्यवहार में प्राप्त हो गया है जिन्होंने समाजवादी रूपान्तरण का मार्ग स्वीकार किया है।

प्रतिदिन जीवन निरन्तर नयी माँगें सामने लाता है। पहले कभी भी मानव समाज के समक्ष उसके अपने अस्तित्व की समस्या इतने निकट रूप से उपस्थित नहीं हुई उदाहरण के लिए, यदि पहले कभी जनगण किसी अलौकिक शक्ति के हाथों विश्व के अन्तर्भासिक विनाश की कल्पना करते थे तो अब पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक जीवित वस्तु का विनाश स्वयं उनके अपने ही कार्यों के फलस्वरूप आत्मघाती आपणविक सर्वनाश के रूप में सामने आ सकता है। मानववंश के सदस्यों ने पहले कभी भी इतने स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया होगा कि वे सब उसी नाव में

1. वी० आई० लेनिन : ‘अमरीका के मजदूरों के नाम पर’ संकलित रचनाएँ, खण्ड 28 पृ० 74

सवार हैं जिसे कि पृथ्वी कहा जाता है। पहले कभी भी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच सहयोग इतना आवश्यक नहीं हुआ। और अन्ततः, पहले कभी भी मानवता के भविष्य के दौर का चुनाव इतना कठिन रहा।

विश्व शान्ति अथवा आणविक युद्ध, सामाजिक प्रगति के लिए व्यापक क्रिया-शीलता अथवा इजारेदारियों द्वारा किया जाने वाला प्रबल उत्पीड़न, प्रकृति पर मानव की शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग अथवा उसके संसाधनों का बर्बरतापूर्ण निशेध करण—ये और इसी प्रकार के अत्यधिक महत्वपूर्ण विकल्प अपूर्व तात्कालिकता प्राप्त करते जा रहे हैं; बिना किसी अतिशयोक्ति के, करोड़ों लोगों के लिए वे जीवन और मृत्यु के प्रश्न बनते जा रहे हैं। एक शब्द में, मानव समाज अपने इतिहास में एक ऐसे बिन्दु पर आ पहुँचा है जिसके परे असाधारण छलांग लगानी पड़ सकती है जहाँ या तो स्वर्ग का नन्दन कानन मिलेगा या अपना सर्वनाश।

बीसवीं शताब्दी ने अभी अपना सम्पूर्ण पथ पूरा नहीं किया और अभी गे अगली शताब्दी इसके समक्ष अपनी पर्यावरण, ऊर्जा, जनसांख्यिकी आदि विश्व-व्यापी समस्याओं की चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार हमारी शताब्दी के कार्यभार की जटिल ग्रन्थि नये समाजवादी विश्व के उदय और विकास, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति के विविध परिणामों और सामाजिक क्रान्ति तथा इसकी जटिल अन्तःक्रिया के साथ जुड़ी है।

अतीत में पूँजीवादी व्यवस्था के उदय के आरम्भ में प्रबोध का युग भी संक्रान्ति युग था जिसमें कठोर वैचारिक संघर्ष चल रहा था, जिसमें एक ओर सामंती नौकर-शाही-राजशाही गिरोहों के दूसरी ओर तीसरी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे जो समानता, स्वतंत्रता और कल्याण और न्याय के आदर्शों की माँग करते थे।

कम्युनिज्म और कम्युनिज्म विरोधियों के बीच आधुनिक वैचारिक संघर्ष में विशेष रूप से उन आदर्शों को उपलब्ध करने के प्रश्न पर आज परस्पर तलवारें टकरा रही हैं, लेकिन पूर्णतया भिन्न परिस्थिति में। पूँजीवादी समाज के शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली पूँजीवादी विचारधारा समानता और मानववाद के आदर्शों की घोषणा के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अस्पष्ट और निराकार स्थापनाओं को आधार बनाकर चलती है जैसेकि वह उनके सम्बन्ध में कहती है 'पवित्र' स्वतंत्रता, 'पवित्र' जनतंत्र, 'सार्वभौम' मानव अधिकार और इसी प्रकार की बातें, भलाई और दुराई के इस प्रकार की अमूर्त विचारों और उनसे उत्पन्न असंख्य भ्रमों के विरुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा ऐतिहासिक प्रक्रिया के वस्तुगत नियमों को प्रस्तुत करती है। उसने सन्तोषप्रद तरीके से दिखा दिया है कि सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए केवल वर्गीय दृष्टिकोण ही सार्वभौम मानवीय श्रेणियों को उनके उपयुक्त स्थान में रखता है और उनको यथार्थ सारस्वतत्व को पूर्ण करता है। यदि संदर्भ का यह बिन्दु छूट जाता है तो स्वतंत्रता, जनतंत्र, समानता, मानव

अधिकार आदि शब्द अर्थ खोकर खोखले हो जाते हैं।

हमारा विश्वास है कि सार्वभौम मानवीय आदर्शों की व्यावहारिक उपलब्धि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति की उपलब्धियों बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से जुड़ी है, सर्वोपरि वह सामाजिक क्रान्ति के उच्च पथ से तथा पूँजीवाद से कम्युनिस्ट निर्माण के संक्रमण के साथ जुड़ी है। कम्युनिस्ट अनुभव करते हैं कि आधुनिक विश्व अपने सम्मुख उपस्थित समस्याओं और भविष्य की विशाल चुनौतियों का सामना कर सकता है। हमारी विचारधारा ऐतिहासिक आशावाद की विचारधारा है।

कम्युनिज्म के विरुद्ध धर्म युद्ध

“तोपों से भी अधिक उच्चस्वर से विश्व में विचारों का गर्जन हो रहा है।”
पैक्सटन¹

विचारों के विरुद्ध बन्दूकें

सी से अधिक वर्ष हो गये, कम्युनिस्ट आन्दोलन और इसके सैद्धान्तिक आधार, मार्क्सवाद-लेनिनवाद, करोड़ों लोगों के भाग्य को अधिकाधिक प्रभावित करते हुए, समस्त विश्व के वैचारिक जीवन के प्रधान केन्द्र बन गये हैं।

इस काल में, वर्ग-शक्तियों के सन्तुलन में होने वाले परिवर्तनों को आधार बनाते हुए, कम्युनिज्म और कम्युनिज्म-विरोधियों के बीच वैचारिक संघर्ष तीन प्रमुख मंजिलों से गुजरा है, जिनमें से प्रत्येक मानव समाज के वैचारिक और राजनीतिक जीवन में हुए मूलभूत परिवर्तनों से समानता रखती है।

इसकी पहली मंजिल, मजदूर वर्ग के आन्दोलन के उदय के साथ अथवा अधिक स्पष्टता से कहे तो, जब मजदूर वर्ग के राजनीतिक अनुभव की मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की शिक्षाओं में व्याख्या की गयी और उसका सामान्यीकरण किया गया, जिसने कि श्रमिक जनता को पूँजी के विरुद्ध अपने मुक्ति-संघर्ष में हथियार बन्द किया, तब से आरम्भ हुई।

दूसरी मंजिल, 1917 में रूस में हुई अक्टूबर क्रान्ति की विजय से जानी जाती है, जो विश्व समाजवादी क्रान्ति की पहली विजय थी।

तीसरी मंजिल के आरम्भ के लिए दूसरे विश्वयुद्ध तक जाना होगा, जब फ्रांसिज्म पर जनवादी शक्तियों की विजय से समाजवादी समुदाय के निर्माण के

1 दिक्शनरी ऑफ अमेरिकन मैक्जिज्म, डेविड किन द्वारा संपादित, न्यूयार्क 1959 पृष्ठ

लिए, अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट एवं श्रमिक-वर्ग-आन्दोलन के नये शक्तिशाली उभार के लिए और साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था के उन्मूलन के लिए अनुकूल पूर्वस्थितियों का निर्माण हुआ।

प्रत्येक नयी मंजिल में वैज्ञानिक कम्युनिज्म की स्थिति विस्तृत और सुदृढ़ होती गयी और इसके शत्रुओं को अपनी कार्यनीति में संशोधन करने के लिए तथा नयी रक्षात्मक स्थितियों पर पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। क्योंकि मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी अवधारणाओं के विरुद्ध उस समय संघर्ष करना, जबकि वे केवल सिद्धान्त के रूप में थी, एक अलग बात थी। और तब यह भिन्न बात बन गयी जबकि अक्टूबर क्रान्ति की विजय से वे अवधारणाएँ समाजवाद के निर्माण में व्यावहारिक रूप से मूर्त होने लगीं। और फिर हमारे समय में यह एक पूर्णतया भिन्न बात है, जबकि समाजवादी देशों का समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय विकास की निर्णायक शक्ति बन गया, जबकि श्रमिक वर्ग के मुक्ति संघर्ष ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया, और जबकि पूँजीवाद के सामान्य संकट की गहनता ने इसके सभी अन्तर्विरोधों को पहले कभी की अपेक्षा अधिक तीव्रता से खुलकर सामने ला दिया।

कम्युनिज्म विरोध को निरन्तर अपने पहले बदलने को विवश होना पड़ा है। इसलिए अब यह मार्क्सवाद-विरोधी, बोल्शेविज्म-विरोधी रूप में, सोवियतवाद विरोधी के रूप में और कभी इन सबके मिलेजुले रूप में और अन्य रूपों में सामने आता है। एक प्रकार से, कम्युनिज्म विरोध का यह विकास मेहनतकश जनता के मुक्ति संघर्ष के समस्त पथ को प्रतिबिम्बित करता है और यह आधुनिक युग में सामाजिक-राजनीतिक विकास के सामान्य लक्षणों की दृष्टि से बहुत शिक्षाप्रद हो सकता है।

सर्वप्रथम, जब संगठित मजदूर आन्दोलन अभी उदय होने लगा था और मार्क्सवाद ने प्रगतिशील मजदूरों के मस्तिष्कों को प्रभावित करना आरम्भ ही किया था, तब कम्युनिज्म-विरोध की अनिवार्य कार्यनीति थी, स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक कम्युनिज्म की प्रामाणिकता को नकारना। कम्युनिज्म विरोध सामान्यतया एकदम आरम्भिक रूपों में था, इसके प्रचारक अधिसूक्ष्म मजदूर जनता की सैद्धान्तिक अनुभवहीनता पर ध्यान देते थे, जो राजनीतिक जीवन में अपने को सम्मिलित करने के लिए केवल शुरुआत कर रही थी। पूँजीवादी पंडित या तो मार्क्सवाद की उपेक्षा करते थे या इसे हानिकारक और मानव-विरोधी दृष्टिकोण समझते थे जो ऐतिहासिक विकास के तर्क का विरोधी और स्वयं मानव स्वभाव के ही विपरीत है।

1848 में 'कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र' के प्रकाशन के तुरन्त बाद पूँजीवादी प्रेक्षकों ने कहना आरम्भ किया कि कम्युनिज्म एक मिथ्याविश्वास है और किसी भी समाज का विरोधी है। उस काल में पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थकों को

यह भी आवश्यक नहीं प्रतीत होता था वे अपने लिए उचित शब्दों के चुनाव के लिए श्रम करें। इसके विपरीत, वे कम्युनिस्टों के विरुद्ध कठोर और अपशब्दों से भरी भाषा का प्रयोग करते थे, उस समय जनता को कम्युनिस्टों के 'घातक' प्रभाव से बचाने का यह सर्वोत्तम उपाय समझा जाता था। कम्युनिस्टों को पड़्यंत्रकारियों के छोटे गुट और अशान्ति उत्पन्न करने वालों, समाज का नाश करने वालों, आचार भ्रष्ट और सभ्यता के आधारों के जड़े खोदने वालों के रूप में चित्रित किया जाता था।

दूसरे शब्दों में, उस मंजिल में कम्युनिज्म-विरोध अनिवार्यतया मार्क्सवाद को मिटा देने का यत्न कर रहा था, पूंजीवादी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प को प्रस्तुत किये बिना वह कम्युनिस्ट शिक्षाओं को नकार रहा था। मुक्त उद्योग को ही प्रगति की एकमात्र प्रेरक शक्ति माना जाता था। सभ्यता को अभिव्यक्त करने का निजी सम्पत्ति के पवित्र सिद्धान्त के आधार के अतिरिक्त कोई मार्ग न था। पूंजीपतियों की उदारवादी सस्थाएँ सामाजिक विकास की सर्वोच्च उपलब्धि घोषित की जाती थी।

मजदूर वर्ग के आन्दोलन के उपाकाल में पूंजीपति कम्युनिस्ट 'पड़्यंत्रकारियों' और 'उपद्रवियों' के विरुद्ध संघर्ष के हिंसक उपायों के प्रयोग को स्पष्ट रूप से वरीयता देते थे। इसलिए अभिजात पूंजीवादी शासक, कम्युनिस्ट विचारों की वकालत करने वालों को 'विद्रोही अपराधी' घोषित कर उनका चालान करने, कारावास भेजने, आतंकित करने, निर्वासन आदि, दंड जो उस समय कम्युनिस्टों को दिये जाते थे, को न्यायसंगत समझते थे। कम्युनिस्टों की असहमति को प्रत्यक्ष दमन द्वारा कुचलने की नीति मजदूर वर्ग के समय आन्दोलन के विरुद्ध संघर्ष में पूंजीपतियों द्वारा अनुसरण की गयी आम नीति के रूप में प्रतिबिम्बित होती है। सर्वहारा वर्ग के पहले आन्दोलनों को—फ्रांस में 1831 का लियोन्सका और 1934 का विद्रोह जर्मनी में 1844 में साइलेशिया के बुनकरो के उपद्रव—खून में डुबो दिया गया तथा 1871 के पैरिस कम्यून की वस्तुतः हत्या कर दी गयी।

पैरिस कम्यून के बाद हुए यूरोपीय पूंजीवाद के अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण विकास के दौर में, प्रतिगामियों ने यह भ्रम पाल लिया कि केवल पुलिस दमन के द्वारा ही मजदूर-आन्दोलन को समाप्त किया जा सकता है। यह समझ लिया गया कि किसी कम्युनिज्म का वैचारिक प्रतिरोध करने के लिए किसी वैचारिक प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं है। यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया।

जैसे ही मुक्त प्रतियोगिता का पूंजीवाद इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकसित हुआ, इसके सभी अन्तर्विरोध एकत्र और तीव्र हो गये। सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी कार्रवाइयों ने अधिकाधिक बढ़ता क्षेत्र, सघनता और राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया। मजदूर वर्ग आन्दोलन में मार्क्सवादी विचार अधिकाधिक फैलते गये।

शताब्दी के बदलने के साथ, वर्ग-संघर्ष पूरी तेजी पकड़ चुका था। सत्ताधारी अभिजात वर्ग ने अपना आधिपत्य सुरक्षित रखने के लिए नये मार्ग खोजना आरम्भ कर दिया था। वे मार्क्सवाद के विरुद्ध वैचारिक सुरक्षा के लिए अधिकाधिक सहारा ढूँढ़ने के लिए विवश हो गये।

सर्वहारा जन-आन्दोलन के विकास और मार्क्सवाद के विस्तार ने यूरोप में वैचारिक मोर्चों पर स्थितियों को पूरी तरह बदल दिया। संभवतः मुख्य परिवर्तन यह हुआ कि समस्त पूँजीवादी सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्तों को उन्हीं समस्याओं पर आवश्यक रूप से ध्यान केन्द्रित करना पड़ा जिन्हें वैज्ञानिक कम्युनिज्म ने सामने रखा था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वैचारिक शत्रु ने वैज्ञानिक कम्युनिज्म के निष्कर्षों को ध्यान में रखा और उनके खण्डन के लिए उरी अपने अन्तर्हीन प्रयासों से नये तरीके खोजने पड़े। यह महत्वपूर्ण है कि प्रबोध युग के पूँजीवादी विचारकों के मानववाद की तुलना में इजारेदार पूँजीपति वर्ग के विचारकों ने मनुष्य की उपेक्षा की अपनी नयी स्वरलहरी चुनी : विवेक हेय समझा जाने लगा, और विवेकहीन, नैसर्गिक वृत्ति की पूजा की जाने लगी। दूसरे शब्दों में, ऐतिहासिक पहल को खोते हुए पूँजीपति वर्ग ने वैचारिक आक्रमण की अपनी स्थितियाँ भी खो दीं। पूँजीवादी सामाजिक-राजनीतिक विचार अथवा अधिकाधिक मार्क्सवाद-विरोध के रूप में प्रवाहित होने लगा क्योंकि उसने मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षाओं को विशेष रूप से सामाजिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक संज्ञान को और समाजवादी आदर्शों के मूल्य को कलंकित एवं खण्डित करने का निश्चय कर लिया था।

पूँजीवादियों के समर्थकों और अवसरवादियों की रैती

इसे केवल संयोग की बात नहीं समझा जा सकता कि आर्थर शोपेन हावर का विनाश के आदर्शवादी दर्शन¹, जो नियम शासित प्रकृति और मानव अस्तित्व की सार्थकता को ही नकारता है और जिसे लगभग विस्मृत किया जा चुका था, ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुनः जीवन प्राप्त कर लिया। वस्तुगत प्रक्रिया के रूप में ऐतिहासिक प्रक्रिया के मार्क्सवादी विचार के प्रति भार के रूप में कार्य करने के लिए अविवेकवाद के उपदेश तैयार किये गये। शोपेन हावर का अनुयायी एडुअर्ड बोन हर्टमान ने और आगे बढ़ कर अचेतन का अपना दर्शन सामने रखा।² वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आकर

1. आर्थर शोपेन हावर, 'डाइबेस्ट एल्स विल जटवोस्टेंलंग' बी. डी. I बर्लिन, एण्ड विएन, 1924, §§ 5-9

2. एडुअर्ड बोन हर्टमान 'फिलासोफी डैस अन विबुस्टन' बी. डी. II 'मैटाफिजिक डैस अन-विबुस्टन', बर्लिन, 1876, §§416-22, 446

इसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समानांतर विश्व की दुःखवादी और स्वेच्छावादी अवधारणा प्रस्तुत की जिसकी अटल नियति मानवीय प्रभाव के समक्ष नहीं झुकती।

पूँजीवादी दार्शनिक भी उदारवादियों से लेकर घोर प्रतिक्रियावादियों तक, समाज की सामाजिक-राजनीतिक संरचना की समस्याओं को अज्ञेयवाद और अविवेकवाद की दृष्टि से देखते हैं, उदाहरणार्थ, ये ऐसे विचार थे जो अपने काल में अपेक्षाकृत अधिक प्रचारित हुए इनमें प्रमुख थे 'अंग्रेजी व्यवहारवाद के प्रसिद्ध प्रवक्ता हर्बर्ट स्पेंसर जो अपने विकासमूलक संतुलन के सूत्र के आधार पर किसी प्रकार के क्रांतिकारी रूपांतरण का आवश्यक रूप से विरोध करते थे और कम्युनिज्म को प्रतिगामी मानते थे।¹

जर्मन दार्शनिक नीत्शे की सामाजिक-राजनीतिक शिक्षाएँ, नवजात इजारेदार पूँजीपति वर्ग के लिए, इसकी प्रतिक्रियावादी नीति और सैन्यवाद के लिए प्रत्यक्ष, नग्न और पागलपन भरा समर्थन थी। यह शोपेन हावर के निष्क्रिय निराशावाद से ऊपर उठने के लिए और विश्व के नये स्वामियों, स्वामीवंश की ऐक्यबद्धता के लिए, श्रमिक आंदोलन और समाजवाद के विरुद्ध निर्णायक और निर्मम संघर्ष के लिए आह्वान था।² यह अकारण नहीं था कि कुछ दशकों के बाद हुत्यारे फ़ासिस्ट नीत्शे को आदर्श मानते हुए आये और उनका दर्शन उनके विश्व आधिपत्य के दावे को नैतिक न्यायसंगतता प्रदान करता था।

इसी समय, उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांत के अवसरवादी विरूपण द्वारा पूँजीवाद को खुला समर्थन देकर पहले ही सुरक्षित कर दिया गया था। लेनिन ने लिखा : "इतिहास की द्वंद्वात्मकता इस प्रकार की है कि मार्क्सवाद की सैद्धान्तिक विजय ने इसके शत्रुओं को अपने को मार्क्सवादियों के रूप में छिपाने के लिए विवश किया था, भीतर-ही-भीतर सड़ चुका उदारतावाद समाजवादी अवसरवाद के रूप में स्वयं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा था।³ तभी से, मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी शिक्षाओं के विरुद्ध संघर्ष में अवसरवाद पूँजीवाद का मुख्य आरक्षित-दल है। इजारेदार पूँजीवाद ने अवसरवाद के साथ गुपचुप मैत्री कर ली, इस पर विश्वास किया और इसकी सहायता की। अवसरवाद भी, अपनी बारी में चूका नहीं। उसने स्वयं श्रमिक आन्दोलन की पाँतों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विरुद्ध एक प्रकार का 'दूसरा मोर्चा' खोल दिया।

जर्मन सामाजिक जनवादी एडुअर्ड बर्न्सटीन का कुख्यात नारा 'आन्दोलन ही

1. देखें हर्बर्ट स्पेंसर, 'फ़र्स्ट प्रिंसिपिल्स', न्यूयार्क, एस. डी. पृ० 314

2. फ्रेडरिक नीत्शे बियोड गूड एंड ईबिस, न्यूयार्क, एस. डी.

3. वी. आई. लेनिन 'द हिस्टोरिकल डेस्टिनी ऑफ इंडस्ट्रियल आर्बर्स' का संशोधित संस्करण, 'संकलित रचनाएँ', खंड 18, पृ० 584

सब कुछ है, अन्तिम लक्ष्य कुछ नहीं' सर्वहारा के वर्ग संघर्ष के समाजवादी उद्देश्य का सीधा विरोध था। यह संशोधनवाद और अवसरवाद का एक प्रकार का सैद्धांतिक ध्वज बन गया, जो उन्नीसवीं शती के अन्त तक एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना बन गया।

सैद्धांतिक स्तर पर, अवसरवाद अनिवार्य रूप से मार्क्सवादी शिक्षा की समस्त मौलिक प्रस्थापनाओं के विरुद्ध खड़ा हुआ। उसने मार्क्स द्वारा की गयी पूँजीवाद की आलोचना सर्वहारा एकाधिपत्य के और मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका के विचारों तथा साम्राज्यवाद और समाजवादी क्रान्ति के सम्बन्ध में लेनिन की शिक्षाओं को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया। यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि पूँजीवाद ने अभी तक अपनी सम्भावनाएँ समाप्त नहीं की और फलस्वरूप समाजवादी क्रान्ति की पूर्वावश्यकताएँ अभी परिपक्व नहीं हुईं। दक्षिणपंथी सामाजिक जनवादी नेताओं ने अपनी मिथ्या-वैज्ञानिक अवधारणाओं को विभिन्न नामपट्टों के अन्तर्गत विज्ञापित किया : 'प्रगतिशील पूँजीवाद' (बर्न्स्टीन), 'वित्तीय पूँजी का नया आर्थिक युग' (युनो), 'अतिसाम्राज्यवाद' (कौटस्की), 'संगठित पूँजीवाद' (हिल्फ़डिंग)। निस्संदेह, ये सभी 'रूपांतरित पूँजीवाद' के उपयोग में सम्मिलित थे और पूँजीवादी जनतंत्र की रक्षा के लिए आवरण के रूप में 'वर्ग शान्ति' का उपदेश देते थे और सर्वहारा वर्ग को पूँजीपति वर्ग के साथ 'सामाजिक सामंजस्य' के लिए प्रेरित करते थे।

उनके काल में ये विचार यूरोप में मजदूर वर्ग में व्यापक रूप से प्रचारित हुए। बाद में बड़ी कटुता एवं रोष के साथ जिसे कोई भी क्रान्तिकारी और मार्क्सवादी भली-भाँति समझता है, फ्रेंज मेहरिंग ने लिखा : "पहले का जर्मनी का सामाजिक जनवाद अपने पुराने परीक्षित दाव-पेचों के बावजूद छिन्न-भिन्न हो चुका है और साम्राज्यवाद की विजयिनी कार के पहियों के नीचे दबा पड़ा है।" यह पूर्ण निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं शती की अन्तिम तिहाई में वर्ग-सम्बन्धों के अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण विकास के प्रमुख कारणों में मजदूर आंदोलन में संशोधनवाद और अवसरवाद भी एक कारण रहा।

इस तथ्य के लिए 'द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय' के नेता सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, कि जब पूँजीवादी विश्व अपने गहनतम और सर्वाधिक ताटकीय संकट में प्रविष्ट हो गया था और राष्ट्र एक साम्राज्यवादी युद्ध की आग में झोंक दिये गये थे, तब मजदूर वर्ग को वैचारिक रूप से और संगठनात्मक रूप से निहत्था कर दिया गया

1. ऑफ़िसेस थेइवेन फ्रेंज मेहरिंग एन डाइवोल्लेबिकी, 3 जून, 1918, ऐन। फ्रेंज मेहरिंग, गैसमैस्ट थाइटन बी डी. 15, पोलिटिश पब्लिशिस्टिक् 1905 बिष् 1918, बर्लिन 1966, पृष्ठ 175

था जिसके कारण वह समय पर क्रांतिकारी कार्यवाई में असमर्थ रहा। एक ओर तो 'श्रमिक अभिजात वर्ग' पर भरोसा रखते हुए गैर-सर्वहारा स्तर से मजदूर वर्ग में लोग आ रहे थे, दूसरी ओर सामाजिक जनवादी पार्टियों के शीर्ष नेता मजदूर आंदोलन को मार्क्सवाद से विमुख करने में सफल हो गये थे और इसे पूंजीपतियों के साथ वर्ग सहयोग के पथ पर ढेल रहे थे।

इस प्रकार, वर्तमान शताब्दी के क्रांतिकारी विस्फोटों के आरम्भ के समय, सम्भवतः पहले से ही प्रत्यक्ष अपनी आरम्भिकता में, लेकिन सर्वथा भिन्न रूप से, विश्व प्रतिक्रियावाद ने मजदूर वर्ग की विचारधारा के विरुद्ध सामान्य नीति स्वीकार की थी : 'कम्युनिस्ट विद्रोह' को शक्ति के साथ कुचलने की दिशा में, और वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर, पूंजीवाद के समर्थकों और संशोधनवादियों के गैठजोड़ के रूप में, जो मार्क्सवाद को उसके क्रांतिकारी सारतत्व से रिकत करने के प्रयास थे।

इन दो दिशाओं के कारण संशोधनवाद मुक्ति आंदोलनों के लिए अधिक खतरनाक था (और आज भी है)। परजीवी रोग की तरह, इसने आंदोलन की पातों को दूषित कर दिया और मजदूर जनता को सच्चे समाजवादी लक्ष्य से पृथक् करने के लिए और 'सरलतर' तथा 'अधिक पीड़ाहीन' मार्गों की खोज के लिए समाजवादी शब्दावली का उपयोग किया। उस समय के बहुत से मार्क्सवादी जैसे ज्योर्जी प्लेखानोव, दिमित्र ब्लेगोयेव्, फ्रेड मेहरिंग, पॉल लाफार्ज, आदुरो लेन्नि-ओला, रोजा लक्सम्बर्ग और कार्ल लीब्रेख्त, ने स्पष्ट रूप से संशोधनवाद के खतरे को देखा और उन्होंने बर्न्स्टीन तथा बर्न्स्टीनवाद के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष किया।

लेनिन ने अवसरवाद की सामाजिक जड़ों और पूंजीवाद की इजारेदारी की मजिल के विशिष्ट रूपों के साथ इनके सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। उन्होंने मार्क्स और एंगेल्स की शिक्षाओं के आधार पर मजदूर वर्ग के लिए समाजवाद के एकमात्र सही मार्ग की रूपरेखा निर्धारित की। मार्क्सवाद की रक्षा तथा विकास करते हुए उन्होंने अवसरवादियों की विश्वामघाती भूमिका को सुस्पष्ट किया है।

अवसरवाद को निरावरण करना और क्रांतिकारी मार्क्सवाद की रक्षा करना यह सब बड़ा प्रभावशाली रहा क्योंकि ये केवल काल्पनिक युक्तिवाद पर आधारित नहीं थे, अपितु तीन रूसी क्रांतिकारियों के ठोस अनुभवों पर आधारित थे जो बीसवीं शताब्दी के क्रांतिकारी परिवर्तनों के अग्रदूत थे। लेनिन ने लिखा है : "रूस ने आधी सदी तक पीड़ाओं में से गुजरकर, अतुलनीय यातना झेलकर और अनुपम त्याग, क्रांतिकारी शौर्य, अविश्वसनीय ऊर्जा, आस्थापूर्ण खोज, अध्ययन, व्यावहारिक परीक्षण, निराशा, सत्यापन और यूरोपीय अनुभवों के साथ तुलना के द्वारा

माक्सवाद को एकमात्र सही क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में प्राप्त किया ?”।

बीसवीं शताब्दी का आरम्भ मुक्तिसंघर्ष के इतिहास में ऐसे युग के रूप में समाया हुआ है जिसने पूँजीवाद के आम सकट को तेजी से बढ़ते हुए देखा और श्रमिक आंदोलन के उस शक्तिशाली क्रांतिकारी उभार को भी देखा जो महान अवतूर समाजवादी क्रांति की विजय में परिपक्व हुआ। उस क्रांति ने रूस में समाज की व्यवस्था को लाखों लोगों के जीवन और मनोवृत्ति को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया। और विश्व के लाखों लोगों को स्वाधीनता, राष्ट्रीय मुक्ति और समाजवाद के लिए सक्रिय संघर्ष के लिए खड़ा कर दिया, इसने मानव समाज के इतिहास में नये युग का द्वार खोला, समाजवाद के युग का। समाजवादी क्रांति के युग में विश्वव्यापी वर्ग-संघर्ष ने अपना सर्वोच्च रूप-समाजवादी क्रांति का रूप-ग्रहण कर लिया।

सर्वहारा और पूँजीपति वर्ग के बीच वर्ग-संघर्ष ने अब वैचारिक संघर्षों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है और अब उसका अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र हो गया है। अवतूर क्रांति ने इस प्रकार के विभिन्न आंदोलनों को—जैसे शांति के लिए आम लोकतांत्रिक संघर्ष, भूमि के लिए किसानों का संघर्ष, उत्पीड़ित जनगण का राष्ट्रीय समानता के लिए संघर्ष, निस्सन्देह सर्वहारा का पूँजीवाद के उन्मूलन के लिए संघर्ष भी—साथ-साथ एक ही क्रांतिकारी धारा में एकत्र कर दिया है। इन आंदोलनों को एकजुट करके अवतूर क्रांति ने विश्वव्यापी स्तर पर उनके विकास के लिए शक्तिशाली आवेग प्रदान किया है।

सोवियत संघ का विरोध बनाम ऐतिहासिक प्रगति

रूस में समाजवादी क्रांति की विजय ने कम्युनिज्म विरोध पर सांघातिक प्रहार किया। अब पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थकों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक ओर तो उनका सामना वस्तुतः विद्यमान सर्वहारा राज्य से था, दूसरी ओर, वास्तव में सभी पूँजीवादी देशों में मजदूर वर्ग का आन्दोलन अद्वितीय रूप से अधिक परिपक्व, संगठित और सैद्धांतिक रूप से इस्पाती बन गया था।

माक्सवाद को ‘खंडित करने का’ पुराना तरीका निरर्थक हो गया था। पहले, जहाँ कि कम्युनिस्ट-विरोधी कुछ सत्याभासी युक्तियों के साथ सामने आ सकते थे यह कहते हुए कि पूँजीवाद ही एकमात्र संभव सामाजिक व्यवस्था थी, किन्तु अब इस तथ्य ने कि समाजवादी राज्य अस्तित्व में आ गया है, बड़ी हद तक उनके नीचे से जमीन खिसका दी।

उस समय से कम्युनिज्म विरोध का मुख्य सार तत्त्व सोवियत संघ के विरोध का सिद्धान्त बन गया। रूसी क्रान्ति के सम्बन्ध में कुछ भी जाने बिना, समाजवादी राज्य के विषय में पूँजीवादी राजनीतिज्ञों की पहली प्रतिक्रिया केवल उनकी वर्ग-स्थिति को ही प्रदर्शित करती थी। उन्होंने उद्दण्डतापूर्ण दुराग्रह के साथ इसे ताकत से कुचलने की कोशिश की और इस प्रकार, अनुदारवादी अंग्रेज विन्स्टन चर्चिल ने सोवियत गणतंत्र के विरुद्ध 14 राज्यों के युद्ध की घोषणा की। जर्मन सेनापति ऐरिक वॉनलुडेनडोर्फ ने जो हिण्डेनबर्ग का दायें हाथ था और बाद में म्यूनिख में नाजियों के विद्रोह में सक्रिय भागीदार रहा, एक लाख लोगों को हथियारबन्द और प्रशिक्षित करने का आह्वान दिया। उसने कहा, फौज उनकी कमान हाथ में ले, और दो महीने में मास्को या सोवियत रूस का नामोनिशान भी नहीं मिलेगा।

जैसे ही उन्होंने सोवियत राज्य के भीतरी मामलों में मीधा हस्तक्षेप सगठित किया, पश्चिमी शक्तियों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने पहले-पहल रूस में पूँजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की अपनी इच्छा को छिपाना आवश्यक नहीं समझा। नवम्बर 1917 के अन्त में, पेरिस में, एक सम्मेलन में, संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने रूस के साथ समझौता वार्ता शुरू करने की पूर्व शर्त के रूप में धृष्टतापूर्वक सोवियत सत्ता के उखाड़ फेंकने की माँग रखी थी।

बाद में, पराजित देशों के साथ शान्ति संधि की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1919 में वर्साई सम्मेलन किया गया, 'चार बड़े' विल्सन, क्लीमेंट्यू, लायड जॉर्ज और ऑर्लैण्डो उन कुछ देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने 'रूस के प्रश्न को' सर्वप्रथम उठाया, जो वस्तुतः सारी बहसों में प्रधान प्रश्न के रूप में छाया रहा। तथापि, सोवियत गणतंत्र को किसी भी प्रकार पराजित राष्ट्रों में नहीं गिना गया। और स्वभावतः ही इस प्रश्न पर अनौपचारिक स्तर पर भी बहस करने पर सहमति नहीं हो सकी। वर्साई के 'शान्ति-स्थापनकर्ताओं' का सोवियत रूस के विषय में रवैया 25 फरवरी 1919 को लिये गये निर्णय में स्पष्ट दिखायी दिया। शान्ति सम्मेलन में भाग लेने वालों की परिपक्व ने मार्शल फौज के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि पूर्वीय यूरोप के देशों को इसमें सम्मिलित करके सोवियत विरोधी हस्तक्षेप को विस्तृत किया जाए।¹ यद्यपि 'रूसी प्रश्न' औपचारिक रूप से सम्मेलन की विषय सूची में नहीं था, लेकिन यह उसमें भाग ले रहे सभी दिमागों पर छाया रहा, जो 18 जुलाई 1919 को वर्साई प्रासाद की डेस स्लेसिस् दीर्घा में, ठीक उसी हाल में जहाँ 48 वर्ष पूर्व 18 जनवरी 1871 को प्रशिया के साथ युद्ध में फ्रांस की पराजय के पश्चात् जर्मन साम्राज्य के निर्माण की घोषणा की गयी थी,

वही वर्साई सम्मेलन और शान्ति समझौता किया गया। दोनों ही पुरानी साम्राज्यवादी नीति की अभिव्यक्ति थे जिसने कि युद्ध को उभारा था तथा जो सोवियत रूस की क्रान्तिकारी चुनौती का सामना करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों का एक प्रयास था।

निस्मन्देह वर्साई समझौता, एक साम्राज्यवादी, अन्यायपूर्ण और परभक्षी संधि थी। इसने केवल शोषकों की सामान्य व्यवहार पद्धति का ही अनुसरण किया जिसमें विजेता पराजितों को लूटता है और जनता के हितों की चिन्ता किये बिना अपनी इच्छा पराजितों पर लाद देता है। वही पुराना रास्ता यहाँ भी अपनाया गया था।

सैडान में फ्रांसीसी सेना के पराजय के पश्चात् 1871 में हस्ताक्षरित शान्ति संधि के अन्तर्गत यह पूरी तरह समझ में आने योग्य बात है कि बिस्मार्क ने फ्रांस से अल्सास और लोरेन को अलग करने के लोभ का प्रतिरोध नहीं किया। और अब जर्मनी की हार के बाद फ्रांस ने न केवल अल्सास और लोरेन को वापस ले लिया बल्कि सार के देसिन में कोयले की खानों को भी अपने हाथों में ले लिया।

आक्रामक जर्मनी पर एक शान्ति थोप दी गयी। जर्मनी, जैसाकि हम जानते हैं, अपने क्षेत्र का आठवाँ भाग, अपनी आवादी का बारहवाँ भाग और अपने सभी उपनिवेश खो चुका है। समझौता करने वाले देशों ने जर्मनी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा कि परभक्षी पशु अपने शिकारगाह में अपने प्रतिद्वंद्वी का पीछा करते हुए करता है।

वर्साई का एक और अन्तर्निहित उद्देश्य भी था। जब अक्टूबर क्रान्ति पूँजीवादी विश्व-व्यवस्था में पहली दरार डाल रही थी और क्रान्तिकारी ज्योति जला रही थी उसी समय विश्व का साम्राज्यवादी पुनर्विभाजन हो रहा था। ऑस्ट्रो-हंगेरियायी और जर्मन राजतंत्र उस ज्वाला में भस्म हो गये, जबकि शेष यूरोप, एशिया और अमरीका में मजदूरों का जन-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। उन स्थितियों में, राजनीतिज्ञों ने विश्व के साम्राज्यवादी पुनर्विभाजन की अपेक्षा वर्साई में और अधिक देखा। वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो सोवियत रूस की विरोधी होती।

यद्यपि सैनिक कार्रवाई के रंगमंच पर रूसी सेनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और अक्टूबर क्रान्ति ने साम्राज्यवादियों को युद्ध बन्द करने को बाध्य कर दिया, सोवियत गणतंत्र को सम्मेलन में प्रवेश नहीं दिया गया, उनके बिना ही वर्साई संधि सम्पन्न हो गयी। यद्यपि संधि में सोवियत राज्य के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई का उल्लेख न था, इससे कोई भ्रम में नहीं पड़ सकता। अपने सार-तत्व में यह घोषित रूप से सोवियत विरोधी चरित्र रखती थी। स्पष्ट रूप से इन्हीं उद्देश्यों ने विल्सन और लायड जार्ज को जर्मनी के विभाजन के पायोनियर के

प्रस्ताव को नकारने को प्रेरित किया था। पश्चिमी राष्ट्रों को पूरी तरह सुदृढ़ जर्मनी की आवश्यकता थी—केवल फ्रांस का प्रतिरोध करने वाले की नहीं बल्कि सबसे पहले वे उसे सोवियत नीति-विरोधी उपकरण के रूप में चाहते थे। जर्मनी की सीमाओं के प्रश्न का निपटारा भी पश्चिमी देशों की सोवियत विरोधी योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया। “यह माना गया कि उनका विनाश अवांछनीय है” क्योंकि वे बोलशेविकवाद के विरुद्ध रक्षा के रूप में काम कर सकते हैं।” पेरिस सम्मेलन में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था।¹ जर्मनी को असमान और अपमानजनक स्थिति में डालते हुए वसाई संधि ने जर्मन जनगण में असन्तोष भड़काया और उसमें प्रतिशोध की भावना के बीज बो दिये। बाद में जिसकी क्रसक हिटलर ने काटी।

इस प्रकार एक नया ठोस तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जोड़ दिया गया। यह था पश्चिमी शक्तियों के प्रतिगामी समुदाय का सोवियत विरोध का सिद्धान्त, जो अपना मुख्य कर्तव्य समझता था विश्व बोलशेविकवाद का उन्मूलन और इसके प्रधान केन्द्र रूसी सोवियत गणतंत्र का विध्वंस।²

सशस्त्र हस्तक्षेप, घेराबन्दी, आर्थिक नाकेबन्दी, तोड़फोड़, सोवियत गणतंत्र के विरुद्ध उत्तेजना फैलाना—ये सब कार्रवाइयाँ अखंडनीय प्रमाण हैं कि साम्राज्यवाद ने नयी समाज व्यवस्था के विरुद्ध सबसे बढ़कर, विश्व ऐतिहासिक प्रगति के हिराबल दस्ते के खिलाफ, निर्मम वर्ग संघर्ष आरम्भ कर दिया था। साम्राज्यवाद ने इन संघर्षों के लिए अपने सभी ससाधनों को एकत्र किया। उस समय समाजवादी समाज के विरुद्ध हथियारबन्द लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी।

अनेक वर्षों के बाद, 1960 के मध्य में, प्रोफेसर जॉन एम० थाम्पसन ने हस्तक्षेप के दिनों के सोवियत विरोध के सिद्धान्त और शीत युद्ध के बीच ‘आश्चर्यजनक समानता’ का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था: “रक्षात्मक युद्ध के समर्थक 1919 में फोख की स्थिति को समझ में आने योग्य और सहानुभूति योग्य पायेंगे, विरोध नीति के प्रवक्ताओं को क्लेमेशू और दूसरों के विचार सुपरिचित और स्वीकारणीय लगेंगे जो 1919 में बोलशेविकों के इर्द-गिर्द सैनिकों की घेराबन्दी में ‘शक्ति के क्षेत्र’ निर्माण करने के पक्ष में थे। वे जो कुछ वर्ष पूर्व कम्युनिस्ट आक्रमण को पीछे धकेलने की माँग करते थे, वे 1919 में चर्चिल और दूसरों की ओर देखते थे और जो यह मानते थे कि बोलशेविज्म को पीछे हटाया जा सकता

1. समुक्त राज्य अमरीका के विदेश सम्बन्धों से सम्बद्ध दस्तावेज, पेरिस, शान्ति सम्मेलन, 1919, खंड IV, वाशिंगटन, 1943, पृ० 300

2. वी. आई. लेनिन : ‘छठी असाधारण अखिल रूसी मजदूर, किसान, कृषाक और लाल सेना के डिपुटियों की कांग्रेस’, खंड 28, पृ० 160-61

है और अन्ततः वह उनके द्वारा पराजित होगा जो राष्ट्रवादी राज्य और बोल्ले-विश्व के विरोध का झण्डा उठाये हुए हैं।¹ वस्तुतः, इस विश्व में हर चीज परिवर्तित होने वाली है किन्तु प्रतिक्रियावाद की सामाजिक प्रगति को रोकने की इच्छा कभी नहीं परिवर्तित होती।

कम्युनिज्म विरोध की नयी व्याख्या :

क्रान्ति 'विलम्बित सुधार' है

और इस प्रकार, यह शस्त्र बल से समाजवाद को नष्ट करने की, 'कम्युनिज्म के भूत को' भगाने की और वर्तमान से, शायद, भावी पीढ़ियों तक की भी, प्रथम उपलब्धियों को ध्वस्त करने की कार्यविधि थी। वर्षों से साम्राज्यवाद की विदेश नीति, और आज तक भी, इस सामान्य रणनीति के अनुरूप रही है।

पूँजीपतियों की वैचारिक सेवाएँ मुख्य रूप से इन प्रयासों पर केन्द्रित रही और अब भी हैं :

- (क) सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाजवाद की साख गिराने के लिए (सर्वोपरि यह प्रमाणित करके कि समाजवादी समाज युक्तिसंगत रूप से सामान्य विकास नहीं अपितु कृत्रिम, अप्राकृतिक और चलती चीज है।)
- (ख) पूँजीवाद को पुनः स्थापित करने के लिए, सर्वोपरि यह दिखाने का प्रयत्न करके कि पूँजीवादी सम्बन्धों के आधुनिकीकरण से पूँजीवादी समाज की वर्ग-विभाजित शत्रुतापूर्ण प्रकृति बदल जाती है।
- (ग) सोवियत संघ की विदेश नीति को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, सोवियत राज्य को आक्रामक के रूप में चित्रित करके इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अलगाव में डालने के लिए और इस प्रकार समाजवादी सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध के लिए जनता को तैयार करना।

सोवियत सत्ता के पहले वर्षों में पूँजीपति वर्ग के विचारकों ने कुछ समय तक निष्क्रियता से काम किया। वे समाजवादी विकास की विधि शासित प्रकृति को ही निरन्तर नकारते रहे, इसे अवैध और इतिहास की पूर्णतया आकस्मिक कुटिल घटना बताते रहे जिसने सोवियत संघ को सभ्य राष्ट्रों के दायरे से परे डाल दिया। वह प्रत्येक को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते थे कि अक्षुब्ध क्रान्ति जनता पर बोल्लेविकों ने अपनी मर्जी से थोप दी थी, और इससे जो समाजवादी व्यवस्था उदित हुई वह 'आकस्मिक' थी, स्वयं क्रान्ति भी आकस्मिक थी और इतिहास के आधार से उसके लिए कोई सम्भावना नहीं है। अमरीकी राजनयिक और इतिहासज्ञ

जार्ज एफ० केनन ने कहा : “उदाहरण के लिए, बोल्शेविकों ने शीतप्रासाद पर कब्जा कर लिया, यह इसलिए सम्भव हुआ कि उसके रक्षकों में बड़ी फूट और अस्थिरता थी और किसी ने असावधानी से पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया था।”¹ दिन-ब-दिन पूंजीवादी समाचार पत्र सोवियतों के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी करते रहे।

तथापि, जब सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि ये भविष्यवाणियाँ निराधार हैं, उन्होंने यह कहना आरम्भ कर दिया : सोवियत गणतन्त्र जो रूस की विशिष्ट स्थितियों में उत्पन्न हुआ ‘शुद्ध रूप से रूसी’ परिघटना है, जो दूसरे देशों में दुहराया नहीं जा सकती। तथ्यतः उन्होंने इसमें जोड़ दिया, कि रूस में भी यह आवश्यकता के कारण नहीं आयी, क्योंकि जो सुधार पहले से लागू किये जा चुके थे उन्होंने ‘बोल्शेविक प्रयोग’ को पूर्णतया निरर्थक कर दिया। उदाहरणार्थ, जैसाकि उस समय के ड्यूमा (रूसी संसद) के प्रख्यात सदस्य वी० एस० मैकलाकोव ने जो बाद में प्रवासी हो गये थे, लिखा था—“प्रत्येक क्रांति विलम्बित सुधारों के अतिरिक्त कुछ नहीं होती जो, नवोकि विलम्बित होती है, इसलिए अपनी गति में इतनी तूफानी होती है कि अपने सध्य से भी आगे बढ़ जाती है।”²

अक्तूबर क्रांति भी अपने सध्य से आगे बढ़ गयी, यह कम्युनिज्म विरोधी विचारकों की स्थापना है। इस प्रकार, उनका कथन था, कि यह मजदूर वर्ग के हिराबल दस्ते के रचनात्मक, क्रियाशील और वैज्ञानिक रूप से सुचिन्तित क्रिया-कलाप का परिणाम होने की अपेक्षा समस्त सामाजिक और उत्पादन सम्बन्धों का उप्पलव विध्वंस और विभेदन बन गयी।

उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की भूमिका को, इसके संघर्ष में सैद्धान्तिक और संगठनात्मक एकता के क्षेत्रों में और अक्तूबर क्रांति में इसके नेतृत्व के ऐतिहासिक महत्व को कम करके उसे मिथ्या प्रमाणित किया। बोल्शेविकों को षड्यन्त्रकारियों के एक छोटे गुट के रूप में चित्रित किया जिन्होंने अधिकांश जनगण को अपनी मनोवांछित योजनाओं का अन्धविश्वासी उपकरण बना लिया। यह वक्तव्य यहाँ तक कहता है कि पार्टी ने रूसी समाज की ‘मानसिक उदासीनता’ का और रूसी जनता की ‘निष्क्रियता’ का लाभ उठाया जिसने अभी तक पश्चिमी संसदीय प्रणाली की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ब्रिटिश सोवियत विज्ञापन की पत्रिका ‘स्लोवानिक रिव्यू’ के पृष्ठों में निम्नलिखित प्रकार के वक्तव्य पढ़े जा सकते हैं : न तो अपनी शिक्षाओं में और न अपने दावपेंच में बोल्शेविज्म मार्क्सवादी बोल्शेविज्म था, निश्चित रूप से इसमें मार्क्सवाद के कुछ तत्व थे, लेकिन इसके बजाय यह

1. जार्ज एफ० केनन, ‘रशालीब द बार’ प्रिन्सटन, न्यूजर्सी 1956, पृ० 6

2. दि स्लेवोनिक रिव्यू, खण्ड 11, बंक 5, दिसम्बर 1923 पृ० 225

ब्लाकीवाद, श्रमिक संघवाद और अराजकतावाद का मिश्रण है : यह मार्क्स से भी अधिक बाकूनिन के निकट है। यह रूसी नास्तिवाद (निहितिरम) का ही नैरन्तर्य है...। यह उत्पाद शुद्ध रूप से रूसी घटना है, जो रूसी चर्च द्वारा इतने लम्बे समय तक स्वीकृत विषय सम्बन्धी स्थिर दृष्टिकोण पर पश्चिम के अत्यधिक उग्रवादी विचारों के प्रभाव के कारण हुए अव्यवस्थित विकास का परिणाम है। बोलेविक फायरबाख के भौतिकवाद और नास्तिवाद के कारण उत्तेजित और उद्भ्रान्त रूसी साधु है।" (!?)¹

और अन्ततः, उन वर्षों में सोवियत विरोधवाद के विचारकों के बीच यह फैशन बन गया था कि वे क्रान्ति विरोध के काम में नहीं आयी क्षमता के सम्बन्ध में खूब गर्मा गर्म बातें किया करते थे। इस सम्बन्ध में, उनका ध्यान अक्सर क्रान्ति के वास्तविक नेता बोलेविकों की ओर इतना अधिक न या जितना कि उससे भागे हुए और इसके प्रत्यक्ष शत्रुओं पर। बाद में, हार्वर्ड में सरकार के प्रोफेसर तथा उसके रूसी अनुसंधान केन्द्र के शोध सहायक अदम उसान से अलङ्घित भाषा में पूछा गया कि कोई मेन्शेविकों को नापसन्द कैसे कर सकता है अथवा उनके इतिहास के कूड़ेदान की ओर अभियान में इस या उस अवसर पर यह या वह करो की चेतावनी देने का लोभ कैसे संवरण कर सकता है...। हम कैडेट्स को प्रेम करने और उनके साथ चलने को आतुर हैं...। उस बहुरूपी समूह—सामाजिक जनवादियों ने भी अपने भाव प्रवण इतिहासकारों को खोज निकाला है। उनके साथ सेविनकोव के धीरतापूर्ण कृत्यों तथा चेर्नोव के अनिर्णय के की पुनरावृत्ति का आनंद ले सकते हैं।²

तथापि, यह कोई बात नहीं कि पूँजीवादी विचारकों ने भले ही बोलेविकों की खूब निन्दा की और मेन्शेविकों तथा सामाजिक क्रान्तिकारियों की प्रशंसा की, खिन्दगी अपने रास्ते बढ़ती गयी। प्रत्येक क्षेत्र में सोवियत सफलताएँ अधिकाधिक विशिष्ट एवं अतुलनीय होती गयी। इन तथ्यों के समक्ष, यह वक्तव्य कि समाजवाद, ऐतिहासिक विकास की 'स्वाभाविक' गतिविधि में कम्युनिस्टों के द्वारा बलपूर्वक थोपी गयी घटना है, प्रभावहीन हीन होता चला गया। किन्तु फिर भी, कम्युनिज्म विरोधी आज तक उसका उपयोग कर रहे हैं। उन्हें अतिकुत्सित और आदिम प्रस्थापनाओं को त्यागना पड़ा किन्तु स्वयं यह विचार धीरे-धीरे मुख्य रूप से दो दिशाओं में रूपान्तरित हो गया।

- प्रथम, सोवियत गणतन्त्र की सफलताओं की स्वीकृति के साथ प्रायः कहा जाने

1. द स्लेवोनिक रिव्यू खंड 1, न० 1 जनवरी 1922 पृ० 12

2. द स्टेट ऑफ सोवियत स्टडीज, सपा० वाल्टर जेड, लाम्बेवर, और लियोपोल्ड लावेज, केम्ब्रिज, मास, 1965, पृ० 16

लगा कि जहाँ तक इन सफलताओं का सवाल है, अक्टूबर क्रान्ति का इनसे कोई लेना-देना नहीं है, यह उन मानवीय और भौतिक संसाधनों में अन्तर्निहित थी जो रूस क्रान्ति के बाद की किसी भी सरकार को दे सकता था।”¹

दूसरे, इन उपसब्धियों के सम्बन्ध में मुख्य स्पष्टीकरण यह दिया गया कि पहले तो यह दावा आविष्कृत किया गया कि सोवियत समाज ‘एकतन्त्रात्मक’ था और बाद में, समान रूप से बेतुका व्यंग्योक्ति भरा कि यह ‘सर्वसत्तावादी’ था, इसका अर्थ था कि समाज कृषि का औद्योगीकरण और सामूहिकीकरण कर रहा है और सामान्य रूप से कहा जाय तो पूरी तरह दमन के साधनों के द्वारा अधि-संख्य जनता अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध यह प्रगति की जा रही है।

इन प्रस्थापनाओं से यह नतीजा निकलता था जैसे कि स्थिति का ऐसा ही तर्क था कि इस ‘मिट्टी के पैरों वाले भीमकाय देव’ के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक युद्ध किया जाय। यह कहा जाता था कि आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिमी जनतन्त्र के विरुद्ध बोल्शेविकों की ‘विस्तारवादी योजनाओं’ को रोका जाय और ‘रूस की गुलाम जनता को मुक्त किया जाय’। यह सोचा गया कि इससे मानव समाज के ऐतिहासिक विकास को वापिस इसके ‘प्राकृतिक’ और उपयुक्त पथ पर लाया जा सकेगा।

पूँजीवाद की आर्थिक चिकित्सा

1924-1929 के काल में पूँजीवाद की आंशिक स्थिरता के कारण इसके विचारकों की रणनीति में कुछ नये तत्वों का समावेश किया गया। एक ओर, स्वयं इस तथ्य ने ही पूँजीवादी विश्व की भावी सभानाओं के सम्बन्ध में कुछ भ्रम—जो उस समय अति काल्पनिक थे—उत्पन्न कर दिये। दूसरी ओर, समाजवाद की ओर कठोरता से नकारात्मक रवैये की सुभेद्यता को समझते हुए पूँजीवादी राजनीति विज्ञानी स्थिति को अधिकाधिक चित्रित करने का प्रयास इस प्रकार करते रहे कि अन्ततः पूँजीवादी विकल्प का ही चुनाव किया जायगा। उन्होंने जनता के दिमागों में यह विचार बैठाने का प्रयास किया कि वास्तविक सामाजिक क्रान्ति पूँजीवादी समाज में हो रही है, और वही, समाजवाद नहीं, ऐसे बीज बो रही है जिसके फल मजदूर वर्ग को मिलेंगे।

फिर एक बार, केन्द्रीय समस्या संपत्ति के वितरण की थी, जो डेविड रिकार्डों और आदम स्मिथ के समय से ही पूँजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मार्ग में बड़ी बाधा बनी हुई थी।

1. राबर्ट, वी० डैनियल्स, “रेड अक्टूबर, बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ़ 1917” न्यूयार्क, 1967, पृ० 226-27.

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन लेव तिस्त ने इस समस्या को एक अशिष्ट (किन्तु पूँजीवादी दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत शिष्ट) अर्थ प्रदान किया। उसने उत्पादन के तीन तत्वों को 'प्राकृतिक शक्तियाँ' नाम देकर अलग-अलग कर दिया—धूम, पूँजी और भूमि तथा संपदा के वितरण को भी उसी प्रकार बाँट दिया—वेतन, मुनाफ़ा और किराया। मार्क्सवाद द्वारा संपदा के वितरण के वर्ग चरित्र प्रकट करने के बाद, पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों ने नये सिद्धान्त की खोज ईमानदारी से आरम्भ कर दी, पुनः सावधानी के साथ मुख्य मुद्दों की ओर इस गहन वर्ग समस्या के सामाजिक पहलू की ओर आकर्षित किया।

हर्बर्ट विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक (और अमरीकी अर्थशास्त्री जॉन क्लार्क के सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के प्रवक्ता)¹, थामस कार्वर ने अपनी भारी-भरकम नाम वाली पुस्तक "द प्रेजेण्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन दि यूनाइटेड स्टेट (1926)" में इस क्रान्ति को उत्पादन के और अधिक केन्द्रीकरण में तथा पूँजी के अंशपत्रों के विस्तार के रूप में देखा। 'सामूहिक संगठन' (कार्पोरेट ऑर्गनाइजेशन) कारवर के अनुसार बुनियादी रूप से पूँजीवाद के सारतत्व को परिवर्तित कर देते हैं, इस प्रकार मालिकों का मालिक होना तथा मजदूरों का मजदूर होना बंद हो जाता है। उसने लिखा कि सामूहिक कार्पोरेट संगठन का आधुनिक रूप हजारों लोगों का उद्योग के स्वामित्व में भाग लेना संभव बनाता है, बन्ध पत्रधारियों अथवा स्टाकधारियों के रूप में।²

निस्सन्देह कारवर की "खोज" नयी नहीं थी, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से ही स्वामित्व के अंश पत्रों के सम्बन्ध में लोग सुपरिचित हैं, और प्लेखानोव तथा लेनिन ने पहले ही बर्सेटीन और अन्य यूरोपीय संशोधनवादियों के प्रयासों की कड़ी आलोचना की जो मजदूर जनता को 'पूँजी के जनतन्त्रीकरण' को उदाहरण के रूप में बताकर मजदूर जनता को थोड़ा बदले हुए वेश में मूँडने के इस अतिरिक्त साधन का उपयोग करते थे।

जैसाकि विलियम जेड० फ़ोस्टर सर्वथा उचित रूप से लिखा था कि पूँजीवादी अमरीका की वास्तविकताओं ने 'सामूहिक पूँजीवाद' के भिद्यक का भण्डाफोड़ कर दिया। उदाहरण के लिए, 1920 के दशक में अमरीकी राज्य की 3 प्रतिशत आबादी स्टाक धारक थी, इसमें मजदूर भी जो इस समूह का एक महत्वहीन भाग थे, सम्मिलित थे। वस्तुतः वे देश के सामाजिक और उत्पादन-जीवन पर कोई

1. अपोलोजेटिक सिद्धान्त बीसवीं शताब्दी के पूर्व भाग में प्रस्थापित किया गया। बाद में बहुत से पूँजीवादी अर्थशास्त्री इसके अनुयायी बने।

2. थामस निक्सन कारवर, द प्रेजेण्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन दि यूनाइटेड स्टेट्स, बोस्टन, 1926, पृ० 115

प्रभाव नहीं डाल सकते थे और, यह कहना आवश्यक नहीं, वे पूँजीवादी, सम्बन्धों की प्रकृति को किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं कर सकते थे। तथापि, पास में कुछ अधिक अच्छा न होते हुए भी साम्राज्यवादी विचारकों ने इस वस्तु को विज्ञापित करने में कोई प्रयास नहीं उठा रखा और इसे समाजवाद के विवर्ण के रूप में चलाते रहे। यह (सामूहिक सभ्यता), क्रांति है, कारवर ने घोषणा की 'कि मजदूरों और पूँजीपतियों के बीच विद्यमान किसी भी प्रकार के भेद को, मजदूरों को पूँजीपति बनाकर और अधिकांश पूँजीपतियों को मजदूर बनने के लिए मजबूर करके समाप्त कर देगा।' क्योंकि उनमें से बहुत से केवल पूँजी के बदले मिलने वाले लाभ पर जीवित नहीं रह सकते थे। यह विश्व के इतिहास में कुछ नयी बात है।¹

तथापि, अमरीकी प्राध्यापक के इस उत्साह में एक बड़ी कमी रह गयी है : किसी भी प्रकार यह वास्तविक जीवन से जुड़ा नहीं है। कारवर ने भले ही फट्टिन धर्म करके यह दिखाया हो कि संयुक्त राज्य अमरीका में 'आर्थिक क्रांति' अमरीकी समाज के समग्र ढाँचे को बदल रही है, पर वास्तव में हर चीज पहले की तरह ही चल रही है, मजदूर अब भी मजदूर ही हैं केवल पहले से भी बुरी हालत में, और पूँजीपति पूँजीपति ही रहे, अपने शोषण से और अधिक धनी बन गये।

कारवर का यह सैद्धान्तिक रूप से निराधार सिद्धान्त समय के साथ कुछ कदम चला— किन्तु केवल इस अर्थ में कि इसने अपने ढंग से अमरीकी जनता की इजारेदारी विरोधी मानसिकता को अभिव्यक्त किया। यह कोई संयोग की बात न थी कि 1920 के दशक में ही पूँजीवाद के समर्थकों ने संपदा और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के प्रश्नों को उठाया और उनके अपने उत्तर खूँदकर उबरने की कोशिश की। क्योंकि तब उन्हें यह स्पष्ट रूप से आवश्यक प्रतीत हुआ कि उनके लिए निजी उद्योगों के संस्थानों की प्रतिष्ठा को बनाये रखना सत्काल आवश्यक हो गया था, सोवियत राज्य के अनुभव ने जिनकी जड़ें काट दी थी। साथ ही वे इजारेदारियों के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के अधिकाधिक केन्द्रीकरण के राष्ट्रव्यापी विरोध को कमजोर करना चाहते थे। पूँजी के 'सामूहिक' रूप की अवधारणा ने इस प्रकार का प्रयास किया।

साथ ही 1920 और 1930 के दशकों में पूँजीवादी सिद्धान्तों के द्वारा पूँजीवाद के प्रत्यक्ष समर्थन को पूरा किया गया, वे छिछली आलोचना करते थे और बड़ी स्वच्छन्दतापूर्वक मुखारवाद की बात करते थे। यह पूँजीवाद को उमरी कुछ कमियों की आलोचना करते हुए फिर से जमाने का प्रयास था। 1920 के दशक में, यह धारा दिखायी दी, विशेष रूप से, तथाकथित संस्थानिकतावाद (इंस्टीट्यूशनलिज्म) में। इस धारा के प्रवर्तक थे अमरीकी अर्थशास्त्री और समाज-

शास्त्री थोस्टेन वेब्लेन जो 20वीं शताब्दी के 'प्रूधों' थे। वेब्लेन को उनकी कृति 'न्यू बर्ड' से बड़ी लोकप्रियता मिली, पूँजीवादियों के परम्परागत जैसे जड़मूत्रों 'सामाजिक सतुलन' और 'हितों की समानता' के स्थान पर उन्होंने सामाजिक समूहों के व्यवहार और चिन्तन का अध्ययन करने और आधुनिक पूँजीवाद की रचना का विश्लेषण करने के तथा इसके प्राविधिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक रूपों या सस्थाओं के विकास के प्रश्न को उठाया (इसीलिए उसका नाम सांस्थानिकतावाद रखा गया)।¹

इस विकासक्रम में, सांस्थानिकतावाद के प्रवक्ताओं ने कतिपय अन्तर्विरोधों को स्वीकार किया और उनको अनिवार्य माना—उदाहरणार्थ, उत्पादन और व्यापार के बीच। तथापि, उन्हें इसका कारण पूँजीपतियों और सर्वहारा के विरोध में नहीं दिखायी दिया, अपितु 'हितों के विवाद में' जिसमें एक ओर लोग दोनों ही प्रकार के, उद्यमी और मजदूर जो प्रविधि से और उत्पादन के संगठन से सम्बद्ध थे, तथा दूसरी ओर वे वित्तीय व्यापारी जो पूँजी के संचालन के क्षेत्र में कार्यरत थे। सांस्थानिकतावादियों ने इस 'विवाद' का समाधान स्वामियों से अभियन्ताओं के हाथ में सत्ता के हस्तान्तरण में, और तथाकथित 'अभियन्ताओं की और प्राविधिकों की क्रान्ति में देखा जो 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध चला सकते थे। यह किस अर्थ में प्रूधों के 'निर्मित मूल्य' (कांस्टिट्यूटिड वैल्यू) से भिन्न है जिसके वास्तविक सार का कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति 'दर्शन की दरिद्रता' में पर्दाफाश किया था।

पूँजीवाद के अन्य समर्थकों की तरह ही जिन्होंने कि उसके कुछ पहलुओं की आलोचना के बहाने पूँजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, वेब्लेन ने भी पूँजीवाद के मुख्य अन्तर्विरोधों को गौण अन्तर्विरोधों का स्थान देने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के स्थान पर एक विकृत योजना निमित्त की।

लेकिन जैसे ही वेब्लेन ने अपना सांस्थानिकतावाद का सिद्धान्त तैयार किया और कारवर ने पूँजी के 'सामूहिक' रूपों की प्रशंसा की, कुछ समय बाद ही 1929-1933 का विश्व आर्थिक संकट आरम्भ हो गया। अभूतपूर्व तीव्रता के साथ इसने उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से अनेक पूँजीवादी देशों को उन्तीसवीं शताब्दी के अन्त की तथा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ की स्थिति में पहुँचा दिया, विशाल संख्या में मजदूर जनगण को बिनाश और बर्बादी में ला पटका—और तीन करोड़ लोगों को पूरी तरह बेरोजगार कर दिया। अब वेब्लेन की संस्था और कारवर की सामूहिक पूँजी का क्या अर्थ रह गया था? इन सिद्धान्तों में बताये नुस्खे बेरोजगारों, बर्बाद

1. उदाहरण के लिए देखें थोस्टेन वेब्लेन, एजीनियर्स एंड दि प्राइस सिस्टम, न्यूयार्क, 1936

और निर्धन लोगो के लिए स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त सिद्ध हुए। 1929-1933 के संकट द्वारा प्रवर्तित उथल-पुथल ने पहले से कहीं बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक स्तरों के मेहनतकश लोगो को पूंजीवाद का सही रूप जो आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी और असुरक्षा का प्रतीक था दिखा दिया।

साम्राज्यवाद के विचारक इन विभीषिकाओं को अनदेखा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। जहाँ 19वीं शताब्दी के अन्त में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वे यह स्वीकार करके चले कि पूंजीवादी व्यवस्था अपरिवर्तनीय और 'स्व-नियन्त्रित' है, वहाँ अब उनके प्रचार की आधारशिला थी यह सिद्धान्त कि राज्य के नियमन द्वारा पूंजीवाद का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

पूँजीवादी समाज को पूर्ण बनाने के लिए अपरिष्कृत समर्थनों के स्थान पर सुधरे हुए सिद्धान्त सामने आये।

संभवतः इस सम्बन्ध में अत्यधिक प्रचलित विचार थे अग्नेज अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के जिनकी पुस्तक 'द जनरल थियरी ऑफ़ एम्प्लायमेंट इण्टरेस्ट एंड मनी' 1933 में प्रकाशित हुई थी। इसने सनसनी उत्पन्न कर दी और लेखक को पूँजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सुधारक और पैगम्बर की प्रतिष्ठा प्रदान की। आर्थिक संकट के कुछ ही समय पश्चात् और उस समय जबकि सोवियत संघ योजनाबद्ध समाजवादी व्यवस्था लाभ प्रदर्शित कर रहा था यह कृति सामने आयी। कीन्स के सिद्धान्त में दूसरी चीजों के साथ, इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया था। वास्तव में इसने विकृत पूँजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के कुछ पुराने जड़ सूत्रों को ही, सीमान्त उत्पादकता के उपर्युक्त सिद्धान्त सहित, अपना आधार बनाया था। इससे भी आगे, कीन्स का सिद्धान्त इस तथ्य को मानकर चलता है कि पूँजीवाद में ऐसे अन्तर्विरोध रहते हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता और बाजार की शक्तियों का 'खुला खेल' उसे संकट से नहीं बचा सकता। दूसरे शब्दों में, कीन्स की मान्यता है कि स्वयं भू-संतुलन की यांत्रिकता और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का स्व-नियन्त्रित व्यवस्था के रूप में स्थिरीकरण—जिससे कि प्राचीन पूँजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ—अब अधिक समय तक काम नहीं दे सकता।

तथापि, कीन्स, यदि वह इस तथ्य से उचित निष्कर्ष निकालना चाहते अथवा निकालने योग्य होते तो पूँजीवादी अर्थशास्त्री नहीं होते। उनके लिए मानना केवल इसलिए अनिवार्य था कि अस्वीकार करना नितान्त असंभव था। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि पूँजीवादी समाज की संस्थाओं को सुधार करके इस

1. जॉन मेनार्ड कीन्स, द जनरल थियरी ऑफ़ एम्प्लायमेंट, इण्टरेस्ट एंड मनी, न्यूयार्क, 1933

दुःखद स्थिति से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विशेष रूप से, यह धन के संचलन तथा ऋणों के राज्य इजारेदारी और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक संस्थानों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य सभी पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों की कीन्स ने भी समस्त पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों की तरह कुछ मौलिक मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की बात करते हुए पूँजीवाद के आर्थिक नियमों के वर्गीय सारतत्व की उपेक्षा करने का प्रयास किया।

पूँजीवादी राज्य की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में कीन्स की व्यावहारिक सिफारिशें थी—वजट, व्यापारियों को ऋण एवं वित्तीय सहायता का विस्तार, अर्थ-व्यवस्था में निजी पूँजी निवेशन को प्रोत्साहन, 'नियन्त्रित' मुद्रा प्रसार, बेतनों को व्यवस्थित करने के लिए, और कुछ अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग तथा कुछ अन्य उपाय जिनको कि व्यापक रूप से लागू किया गया है, उदाहरणार्थ, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का 'न्यू डील', यह उपाय मेहनतकश जनता की क्रीमत पर राज्य इजारेदारी पूँजीवाद को सुदृढ़ करने के लक्ष्य से किये गये थे। इसलिए, इस तथ्य में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है कि कीन्सियनवाद (और बाद में नव कीन्सियनवाद, जिसके कि प्रवक्ता आर० हैरोड, जॉन राबिन्सन, आल्विन हैसन और अन्य लोग थे) पूँजीवादी देशों में बहुत प्रससित हुआ और आज भी वह पूँजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक मुख्य धारा है।

कीन्सियनवाद के उदाहरण से ज्ञात होता है कि 1920 और 1930 के दशकों के पूँजीवादी सामाजिक विचार में कुछ नयी महत्वपूर्ण विशेषताएँ प्राप्त कर ली थी। इसने विश्व में हो रहे वास्तविक परिवर्तनों पर ध्यान देना आरम्भ किया और जहाँ भी संभव हुआ वास्तविकता के आवरण में सामने आना आरम्भ कर दिया। पहले, बिना किसी विशेष प्रमाण अथवा साक्ष्य के, प्रत्यक्ष बुराई मानकर समाजवाद को सर्वथा नकार दिया गया था, जबकि पूँजीवाद को पवित्र, एवं बिना किसी सुधार के, सभी सुचिन्तित एवं अचिन्तनीय मुणों के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था। किन्तु, अब पूँजीवादी सिद्धान्तकारों को समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अनुभव में कतिपय सकारात्मक पहलुओं को—जैसे उत्पादन की दरो का तेजी से विकास एवं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की तथा सामाजिक नीति की सफलताएँ स्वीकार करने के लिए अनिच्छापूर्वक ही सही, विवश होना पड़ा। उन्हें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि पूँजीवाद की भावोद्दीप्त प्रशंसा का स्वर कुछ धीमा किया जाय।⁴

यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि तथ्यों के साथ यह समझौता सिर्फ इसलिए सहन किया गया कि तथ्यों ने पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थकों के सामने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। लेकिन अन्य तरीके खोजने का प्रयास जारी रहा, कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार में अधिक लचीला रवैया, ये तथ्य के विविध साक्ष्य थे कि जनता की राय में समाजवाद के पक्ष इतनी ठोस और स्पष्ट थी कि उसकी उपेक्षा

करना असभव था ।

इस ढाँचे में, जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ काल में समाजवाद और पूंजीवाद के बीच शक्तियों के परस्पर सम्बन्ध प्रदर्शित होते हैं, वर्तमान कम्युनिज्म-विरोधी बुनियादी दिशाएं देखी जा सकती थी : समाजवाद को सार्वभौम 'मानवीय मूल्यों' की कथित वास्तविक स्थितियों से गिराने के प्रयास, पूंजीवाद की इसके 'रूपान्तरणों' के आधार पर रक्षा, 'वर्ग-भागीदारी' के जनोत्तेजक आह्वान के साथ वर्ग संघर्ष को मजदूर करने के प्रयास, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच बुनियादी विभाजक रेखा को आँखों से ओझल करने के प्रयास । तथापि यह विशिष्ट दिशाएं पर्याप्त समय बाद पूरी तरह विकसित हुईं, जबकि समाजवाद के पक्ष में नये ऐतिहासिक परिवर्तन हुए और 'आणविक गतिरोध' ने सैनिक साधनों से समाजवाद को मिटाने सभी आशाओं को समाप्त कर दिया । अन्ततः पश्चिम के अत्यधिक वास्तविकता से सोचने वाले राजनयिकों की दृष्टि भी परिवर्तित हो गयी । तथापि विचाराधीन समय में, इस समय भी, साम्राज्यवाद की आमरण नीति में सैनिक साधनों से समाजवाद को छिन्न-भिन्न करने पर जोर था और सभी वैचारिक साधनों को सर्वप्रथम और पूरी तरह इस कार्य में लगा दिया गया था ।

कम्युनिज्म-विरोध का वास्तविक रूप

समाजवाद के प्रति सम्पूर्ण घृणा और इसका भय फ़ासिज्म में केन्द्रित हो गये । वह साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया का खूनी लक्ष्य था, जो मानव-समाज के विकास को रोकने और उसे पीछे फेंकने के लिए ऐतिहासिक मंच से विदा होने वाले का निराशापूर्ण प्रयास था । विश्व के दृश्यपट पर फ़ासिज्म के आने के साथ, कम्युनिज्म-विरोध ने नया रूप धारण किया, वह अत्यधिक प्रतिक्रियावादी, अत्यधिक अंधराष्ट्रवादी, और वित्तीय पूंजी के अत्यधिक साम्राज्यवादी तत्वों की एक खुली आतंकभरी तानाशाही थी ।¹ हिटलर की विदेश नीति का कार्यक्रम का अर्थ था 'जीवित अन्तरिक्ष' जिसे जर्मनी अपने फ़ासिस्ट सहयोगियों के साथ मिलकर जीतना चाहता था, पूर्व में अर्थात् जिसे वह सोवियत यूनियन से लेना चाहता था । पश्चिमी शक्तियों—संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हर तरीके से इस दुस्साहस को प्रोत्साहित किया, और वास्तव में समर्थन दिया । व्यवस्था को बड़ी स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया था : नाज़ी जर्मनी ने समाजवाद के विरुद्ध युद्ध में 'आक्रमणकारी टुकड़ी' की भूमिका ग्रहण की । पश्चिमी शक्तियाँ पृष्ठभूमि में उसकी रक्षा कर रही थी । हिटलर के सत्ता में आने के बाद, साम्राज्यवाद की समस्त यूरोपीय नीति अनिवार्य रूप से इन लक्ष्यों के अधीन हो गयी । इस प्रकार

समाजवादी सोवियत संघ के विरुद्ध फ्रांसिजम का युद्ध पहले से ही तय कर दिया गया। साथ-ही-साथ पश्चिमी शक्तियों ने इसे कई दिशाओं में तेज कर दिया।

युद्ध की तैयारी आर्थिक योजनानुसार की गयी, इसका अर्थ था जर्मनी में रहूर के लोहा और इस्पात तथा युद्ध-उद्योग पुनः स्थापित और विकसित किये जाएं। यह कार्य, भरम्मत के लिए ढास योजना की स्वीकृति के अनन्तर, अमरीका और ब्रिटेन की इजारेदारियों से प्राप्त शक्तिशाली सहायता से किया गया, इस प्रकार जर्मन उद्योगों में विदेशी पूंजी के, सर्वोपरि अमरीकी पूंजी के, तीव्र प्रवाह के लिए मार्ग खुल गया। अमरीकी डालरों की स्वर्णिम वर्षा ने हिटलर जर्मनी के भारी उद्योगों को, विशेष रूप से युद्ध उद्योगों को पुनर्जीवित कर दिया। ये अरबों-खरबों अमरीकी डालर मनुष्यपारीय इजारेदारियों ने युद्ध स्तरी जर्मनी की सैनिक अर्थव्यवस्था व जर्मनी की युद्धक्षमता के नवीनीकरण के लिए और आक्रमण की तैयारी के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्र हिटलर के शासन के हाथों में दे दिये।¹

युद्ध की तैयारी राजनीतिक रूप से भी की गयी। यह आवश्यक था कि वसाई सन्धि में जर्मनी की सशस्त्र सेनाओं के विकास पर लगायी गयी सीमाओं की व्यवस्था को समाप्त किया जाय, यूरोप में सामूहिक सुरक्षा के समर्थकों की पाँतो में फूट डाली जाय, और आक्रमण को रोकने के उपायों को महत्वहीन बना दिया जाय। और यह कार्य भी ब्रिटेन और फ्रांस के शासक हल्कों ने कर दिया, जो आक्रमणकारी को 'तुष्ट करने की' नीति का अनुसरण कर रहे थे। स्पष्ट रूप से, आंग्ल और फ्रांसीसी शासक हल्कों की यह नीति सामूहिक सुरक्षा को अस्वीकार करने, जर्मन आक्रामकता को पीछे हटाने से इन्कार करने, और हिटलर जर्मनी की आक्रामक भावों में रुचि लेने में अभिव्यक्त हुई जो द्वितीय महायुद्ध की ओर दुनिया को ले गयी।² तुष्ट करने की नीति की परिणति, जैसाकि हम जानते हैं, म्यूनिख सन्धि, जिसने न केवल चेकोस्लोवाकिया के सूडेटेन्लेण्ड को ही हिटलर के चरणों में डाल दिया, में हुई अपितु समकालीन लोगों ने सही निर्धारित किया कि इससे हिटलर को मास्को पर आक्रमण के लिए हरी-झंडी दिखा दी गयी। वास्तव में, म्यूनिख-वादियों ने इस बात को छिपाया भी नहीं। फ्रांसीसी समाचारपत्र—'ले जुमर, ईको दि पैरिस' ने लिखा : 'म्यूनिख बैठक का सर्वोपरि प्राथमिक लाभ यह हुआ कि रूस को इससे अलग कर दिया गया। रूस को यूरोप से बाहर रखने के लिए हर उपाय किया जाना चाहिए, उसे उसके एशिया में पीछे खदेड़ देना चाहिए। जैसाकि बूढ़ा क्लेमेशू सपने लिया करता था कंटोले तारों के पीछे उसे घेरने के लिए, वह

1. देखें : फाल्सीफायस ऑफ हिस्ट्री, एन हिस्टोरिकल रीफरेंस बुक, मास्को, 1952 पृ० 12 (रूसी में)

■ वही, पृ० 13

सदा तैयार है। इसका उपयोग किया जाय।¹ इस प्रकार युद्ध की राजनीतिक तैयारियों में न केवल तेजी लायी गयी अपितु उसने सोवियत-विरोधी आन्दोलन के प्रत्यक्ष संगठन का रूप ले लिया।

अन्ततः, युद्ध की तैयारी विचारधारात्मक रूप से भी की गयी, यह आवश्यक था कि शान्ति की शक्तियों को छिन्न-भिन्न करने के लिए और सोवियत संघ को अलग-अलग में डालने के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जाय। पश्चिम के तथाकथित जनतन्त्रों ने नाजीवाद की कम सेवा नहीं की। हिटलर सोवियत संघ को पश्चिम के विरुद्ध 'विश्वसक कार्रवाई' करने, एवं 'क्रान्ति का निर्यात करने के लिए' 'विश्व कम्युनिस्ट पद्धति संगठित' करने आदि के लिए दोषी ठहराने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। हिटलर को प्रचार के ये सुविधाजनक औजार विरासत में मिले थे। इसके अतिरिक्त, बेशक, फासिज्म ने सोवियत विरोध और समाजवाद विरोध को अपनी सरकारी नीति बनाया तथा समाजवादी सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध को अपना लक्ष्य घोषित किया। फिर हिटलर अन्य पश्चिमी शक्तियों की सहायता के बिना जनोन्माद की सीमा तक 'कम्युनिस्ट खतरे' के मिथक को प्रचारित नहीं कर सकता था। वास्तव में, यह जनगण के विरुद्ध हजारों दारियों के अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए जन-उत्तेजना का एक झीना आवरण था। बाद में, नूरेम्बर्ग केस में संयुक्तराज्य अमरीका के एक प्रतिनिधि डा० रॉबर्ट कैम्पनर ने कहा था कि 'यह कम्युनिस्ट खतरा मात्र बहाना था और उन कारणों में एक था जो द्वितीय युद्ध की ओर ले जा रहे थे।'²

फासिज्म इसका प्रत्यक्ष परिणाम था और साथ ही यह पूँजीवादी समाज के गम्भीर सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक संकट की अभिव्यक्ति था, उसका जन्म तनावपूर्ण वातावरण में हुआ और वह निरन्तर तनाव को बढ़ाता रहा। इसीसे हिंसा, सैन्यवाद और विस्तारवाद की सनक को प्रस्थापित करने में सहायता मिली। उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया और आतंक सम्मिलित रूप से नाजीवाद के सार हैं। लेकिन चेकोस्लावाक पत्रकार जूलियस फ्यूचिक जो स्वयं नाज़ियों का शिकार था, यह कहते हुए हजार बार सही था : "फासिज्म केवल, कारागार, यातना शिविर और फासियाँ ही नहीं हैं, और न सिर्फ़ खूनी आतंक, और जनता का शारीरिक उत्पीड़न भर नहीं है। यह विचारों का, दृष्टिकोणों का, धारणाओं का भी उत्पीड़न है जो फासिस्ट शासन के लिए खतरा पैदा करते हैं।" और आगे "केवल हिंसा बहुसंख्या पर अल्प-संख्या के शासन को बनाये रखने में कभी सफल नहीं हो सकती, इसके लिए, अधि-

1. जीन बोमायर, डी हिटलर ए टुर्मेन, पेरिस 1950 पृ० 21

2. ट्रायल ऑफ़ द मेजरवार क्रिमिनल्स बिफोर दि इन्टरनेशनल मिलिटरी ट्रिब्यूनल, खंड 5, नूरेम्बर्ग, 1947, पृ० 357

संख्य लोगों को ध्रुष्ट करना आवश्यक है, उन्हें वैचारिक रूप से पतित बनाना और इस प्रकार कमजोर करना आवश्यक है जिससे कि वह महत्व-हीन अल्प मत की विचारधारा से प्रभावित होकर उसकी सेवा करने लगे।”

नाजीवाद की विचारधारा ने व्यक्ति में हर मानवीय चीज को ध्वस्त कर दिया, इसमें निम्नतम वृत्तियों को उभारा और उसे एक बिना विचार किये हत्या करने वाले परपीड़क के रूप में बदल दिया। नस्लवाद, अन्धराष्ट्रवाद, सैन्यवाद और फ्यूहरर की शक्त जर्मनी में नागरिक के आदर्श घोषित कर दिये गये। सामाजिक संस्थाएँ—परिवार, स्कूल, जनसंस्कृति—पूर्णतया राज्य के नियंत्रण में आ गयी जिससे कि उनको नाजीवाद की बर्बर योजनाओं के अधीन कर दिया गया। मानव समाज के पूरे इतिहास को ‘मालिक नस्ल’ स्थितियों के अनुरूप पुनः परीक्षित किया जाय जिससे ‘1000 वर्ष की राइश’ को ममस्त सामाजिक विकास के पूर्ण होने के चरमबिन्दु के रूप में चित्रित किया जा सके। सशस्त्र सेनाओं की ओर तोपों की समस्त विश्व में ‘नया शासन’ स्थापन करने का आह्वान दिया गया।

जर्मनी में नाजियों के सत्ता पर आने के बाद, यूरोप अदम्य गति से श्रुद्ध की चल पड़ा। सोवियत संघ और अन्य जनतांत्रिक शक्तियों के पास अभी तक इतने पर्याप्त साधन नहीं थे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया द्वारा चलाए जा रहे आक्रमण के इजिन को रोक सके। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और चल पड़ा तब यह नहीं कहा जा सकता कि यह कैसे समाप्त होगा। यह वैसा नहीं था जैसाकि बर्लिन, वाशिंगटन, लन्दन और पैरिस में बैठे बैंक मालिकों, सैनिक-औद्योगिक धुरंधरों, जनरलों और राजनयिकों ने योजना बनायी थी, हिटलर और उसके अनुयायियों ने उनके सर्वथा भिन्न दृश्य तैयार किया था जिस पर अमल किया गया। उन्होंने सोवियत विरोधवाद और कम्युनिस्ट विरोध के आन्दोलन के नारे युद्ध आरम्भ करने और चलाने का विचार किया जो कि पश्चिमी देशों के सभी प्रतिक्रियावादियों को संयुक्त कर सके अथवा कम-से-कम विश्व जनता के एक भाग को जैसाकि एक इतिहासकार ई० एन० द्जेलेपी ने लिखा : “घटनाओं के तर्क के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध लालरूस के विरुद्ध हिटलर के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या भागीदारी सहित पश्चिमी सभ्यता का सच्चा घमंयुद्ध था। इसके रणनीति निर्धारकों के अनुसार यह घमंयुद्ध समाजवादी सोवियत संघ की विनाशक पराजय के साथ समाप्त होगा और सम्पूर्ण विश्व में पूंजीवादी इजारेदारियों की पुनः स्थापना करेगा। यह था वह परिदृश्य जिसकी रूपरेखा हिटलर और फ्रांसिस्म पर भरोसा रखनेवाली ताकतों ने मानवता की सामाजिक प्रगति को तथा समाजवाद की ओर उसकी गति को रोकने के लिए,

बनायी थी ।

फासिज्म के विरुद्ध विश्व-जनगण

लेकिन घटनाओं ने दूसरा रूप ले लिया । फासिज्म के विरुद्ध सोवियत संघ के संघर्ष ने सारी दुनिया की प्रगतिशील शक्तियों को संयुक्त कर दिया । इससे हिटलर विरोधी मोर्चा बना, हिटलर जर्मनी और उसके साथियों को कठोर पराजय का मुँह देखना पड़ा । अन्तिम विश्लेषण में, इसकी परिणति पूँजीवाद के आम संकट के गम्भीर रूप से गहरा होने और समाजवाद के और सुदृढ़ होने के रूप में हुई । सामाजिक प्रगति की ऐतिहासिक विजय के विविध साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए फासिज्म पर महान् विजय ने मजदूर वर्ग के संघर्ष को सामाजिक मुक्ति के संघर्ष तक उठा दिया, जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के स्तर तक, और साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता का लोकतान्त्रिक संघर्ष गुणरमक रूप में नये स्तरों को छूने लगा ।

घटनाओं में यह परिवर्तन किस प्रकार सम्भव हुआ ? निस्सन्देह, इसमें निर्णायक भूमिका सोवियत संघ की शक्ति ने अदा की । सोवियत जनगण के अतुलनीय कदमों ने, जिन्होंने फासिज्म के विरुद्ध संघर्ष का मुख्य भार वहन किया, और सोवियत कूटनीति की कुशलता ने जो साम्राज्यवादी शक्तियों के सोवियत विरोधी मोर्चे में फूट डालने में सफल हुई ।

लेकिन दूसरी ओर, फासिज्म की पराजय विश्व में सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों के नये विभाजन के कारण जो, युद्ध-पूर्व के वर्षों में ही दीखने लगा था और युद्ध की समाप्ति तक पूरी तरहपरि भाषित हो गया, प्रतिबन्धित हो गयी । यहाँ संदर्भ है समस्त जनवादी शक्तियों के-किसानों, दस्तकारों और बुद्धिजीवियों के-मजदूर वर्ग के चारों ओर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के झण्डे के नीचे एकजुट होने का । जर्मनी में फासिज्म के बलपूर्वक सत्ता में आने से और नये विश्व युद्ध के खतरे ने इस प्रक्रिया को केवल तीव्र कर दिया ।

कम्युनिस्टों ने जनवादी शक्तियों को एकताबद्ध करने के आन्दोलन का नेतृत्व किया । इस लक्ष्य में विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संघ को (जुलाई-अगस्त 1935 में) सातवीं कांग्रेस ने अपना योगदान किया जिसने कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए फासिज्म की वृद्धि के विरुद्ध और नये विश्व युद्ध की तैयारियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए कार्यनीति एवं रणनीति की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित की । यह विश्व इतिहास के अत्यधिक जटिल और सकटपूर्ण समय मजदूर वर्ग का, मेहनत-कश अवाम का, और समस्त जनवादियों का हथियार बन गया और इसने अनेक प्रकार से शक्तियों के इस संयुक्त मोर्चे को बल प्रदान किया और अन्त में फासिज्म पर विजय तक पहुँचाया ।

कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की सातवीं कांग्रेस ने सकेत किया कि जर्मनी में इजारेदार पूँजीवाद की खुली आतंकभरी तानाशाही के आगे बढ़ने और विश्व युद्ध के खतरे के समक्ष मुक्ति संघर्ष में भाग लेने वाले समाजवादियों और जनवादियों के नये अन्योन्याश्रय के रूप में मजदूर वर्ग का कार्य-भार मूर्त रूप ले चुका था। जबकि 1917 और 1923 के बीच क्रान्तिकारी उभार के युग में मजदूर वर्ग के सामने पूँजीवादी जनतन्त्र और समाजवाद के बीच चुनाव का प्रश्न था, 1930 के राजनीतिक संकट के काल में प्रश्न सामने आया, या तो फ़ासिस्म अथवा पूँजीवादी जनतन्त्र। इस विकल्प के प्रकाश में कांग्रेस मजदूरों और लोकप्रिय शक्तियों के संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति प्रस्तुत करती है। कार्यकाल एकता के लिए "सिवाय एक के कोई शर्त नहीं है, और आरम्भिक शर्त होगी जो सभी मजदूरों को स्वीकार करनी होगी" "कार्यगत एकता फ़ासिज्म के विरुद्ध निर्देशित होगी, पूँजी के हमले के विरुद्ध, युद्ध के खतरे के विरुद्ध।"¹

लोकप्रिय संयुक्त मोर्चे की रणनीति का अर्थ है गृहनीति के रूप में मजदूर वर्ग के आस-पास लाखों मेहनतकश जनता का और मध्य वर्ग के लोगों का इजारेदार प्रतिक्रिया के आक्रमण को रोकने तथा पीछे हटाने के लिए और मेहनतकश जनता की जनवादी उपलब्धियों की अधिकाधिक रक्षा के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय रूप में इसका अर्थ है साम्राज्यवादी युद्ध को रोकने के लिए समस्त जनवादी शान्ति प्रेमी शक्तियों का सर्वोपरि सोवियत संघ जोकि स्वाधीनता और जनतन्त्र का सुदृढ़ गढ़ है, के इर्द-गिर्द एकजुट होना।

इसमें सर्वहारा वर्ग के अपनी वर्ग स्थितियों से और अन्तिम लक्ष्य से पीछे न हटने की रणनीति अन्तर्निहित थी। नयी वास्तविकताओं के प्रत्युत्तर में कार्य करते हुए अपने समक्ष तात्कालिक समस्याओं के समाधान का लक्ष्य रखा और साथ-ही-साथ मजदूर वर्ग के और इसके कम्युनिस्ट हिराबल दस्ते के इर्द-गिर्द विशाल साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बनाने का लक्ष्य रखा।

इसी के साथ-साथ किसी भी प्रकार यह रणनीति केवल तात्कालिक हितों के अर्थात् फ़ासिस्म के आगे बढ़ने के तथा युद्ध के खतरे के विरुद्ध घोषी नहीं गयी थी। यह लेनिन की जनवाद के लिए संघर्ष एवं समाजवाद के लिए संघर्ष के मध्य अन्तः-सम्बन्धों की धारणा से और जनतान्त्रिक एवं समाजवादी लक्ष्यों की अभिमुखता एवं अन्तर्ग्रथितता की धारणा से चल रही थी। इस प्रकार इसने लोकप्रिय संयुक्त मोर्चा बनाने की सम्भावनाओं का मार्ग खोल दिया अथवा संघर्ष की समाजवादी स्थिति के लिए फ़ासिस्ट विरोधी जनतान्त्रिक राज्यों के सक्रमणकालीन संयुक्त मोर्चे का मार्ग खोल दिया।

कमिन्टर्न की सातवीं कांग्रेस द्वारा तैयार की गयी विश्व कम्युनिस्ट और मजदूर आन्दोलन की कार्यनीति सम्बन्धी मार्गदर्शक नीतियों ने बाद में होने वाली घटनाओं को अनेक प्रकार के पूर्व निर्धारित कर दिया। युद्ध पूर्व के वर्षों में, यूरोप में कई देशों में और कुछ अन्यत्र भी संयुक्त मोर्चे की विजय ने न केवल फ़ासिज़्म को पीछे हटाया अपितु वहाँ कतिपय प्रगतिशील सुधार लागू करना भी सम्भव बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में सातवीं कांग्रेस के विचारों ने प्रतिरोध आन्दोलन को व्यापक क्षेत्र प्रदान करने में सहायता दी जोकि अपने सार रूप में पहले से ही दुतरफ़ा संघर्ष था। फ़ासिस्ट हमलावरों से राष्ट्र की मुक्ति का और समाजवाद की ओर उन्मुख जनवादी शासनो की स्थापना का संघर्ष था। इन उच्च आदर्शों के नाम पर संघर्ष कर रहे थे ग्रीस और यूगोस्लाविया के साथी, फ़्रांसीसी माकिविस और पोलिश देशभक्त, स्लोवाक राष्ट्रीय विद्रोह तथा प्राग के विद्रोह के शूरमा, डेन्मार्क और नार्वे में मुक्ति संघर्ष के योद्धा, और स्वयं जर्मनी में फ़ासिस्ट विरोधी योद्धा।

फ़ासिस्ट विरोधी प्रतिरोध ने नाज़ीवाद के विरुद्ध प्रत्येक देश में देशभक्ति पूर्ण और साथ-ही-साथ अन्तर्राष्ट्रीय रूप में जनगण का संघर्ष छेड़ दिया। इसने फ़ासिस्ट लुटेरों के विरुद्ध नेतृत्व किया और साथ-ही-साथ जनवादी रूपान्तरण और सामाजिक प्रगति के लिए भी संघर्ष किया। उपनिवेशों और पराधीन देशों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए संघर्ष का आन्दोलन चल रहा था। सोवियत संघ के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के आरम्भ के साथ ही प्रतिरोध आन्दोलनों की साम्राज्यवाद विरोधी दिशा और उसका सामयिक सारतत्त्व व्यापक बन गया। अनेक देशों में, जैसाकि हमें ज्ञात है, यह अन्ततः लोकप्रिय जनतान्त्रिक क्रान्तियों के रूप में विकसित हुआ।

युद्धोत्तर वर्षों में, लोकप्रिय संयुक्त मोर्चे के विचार, उन देशों में जहाँ कि पूँजीवादी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी जनता के जनतन्त्र की स्थापना का साधन बने। वे नीतियाँ आज भी क्रान्ति, जनतन्त्र और समाजवाद के लिए उनके संघर्ष में मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है।

विचारों के संघर्ष की नयी अवस्था

फ़ासिज्म की पराजय : शिक्षाएँ और चेतावनियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद के पक्ष में हुए विश्वव्यापी परिवर्तनों के साथ कम्युनिज्म और कम्युनिज्म विरोध के बीच संघर्ष की नयी अवस्था आरंभ हुई।

फ़ासिज्म पर विजय ने दिखा दिया कि संसार की कोई भी शक्ति अक्षुण्ण समाजवादी क्रान्ति द्वारा आरम्भ किये गये क्रान्तिकारी रूपान्तरण की शक्तिशाली धारा को पीछे नहीं हटा सकती। साम्राज्यवाद के गढ़ फ़ासिस्ट जर्मनी की पराजय ने अनेक प्रकार से विश्व के युद्धोत्तर विकास को पूर्व निर्धारित कर दिया। यह विजय नये क्रान्तिकारी उभार के लिए प्रस्थान बिन्दु बन गयी, जिसने पश्चिम एवं पूर्व के बहुसंख्यक देशों में पूँजीवाद के विनाश का नेतृत्व किया। इस विजय से विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विचारधारा और लोगों की मानसिकता में गंभीर परिवर्तन लक्षित किये गये।¹

युद्ध के बाद के दशकों में कई ऐतिहासिक घटनाएँ लक्षित की गयी। विश्व समाजवादी व्यवस्था का जन्म, मजदूरों और कम्युनिस्टों के आन्दोलनों में वृद्धि, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का विस्तार और शांति के लिए और विश्व तापनाभिकीय युद्ध के विरुद्ध विश्वव्यापी आंदोलन।

फ़ासिज्म के साथ घातक मुठभेड़ ने लोगों के दिमागों पर गहरी छाप छोड़ी। युद्ध ने करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर से प्रभावित किया और वह संपूर्ण मानव समाज के लिए भयानक विपदा बना। इसने राजनीतिक पार्टियों के वास्तविक रूप को उजागर कर दिया और उनके नारी और कार्यक्रम का पर्दाफाश कर दिया, इसने विश्व राजनीति के छिपे स्रोतों को प्रकट कर दिया और संघर्ष में भाग लेने

1. एल० आर्द० ब्रेझनेव, 'फ़ालोइंग लेनिन्स बोर्स' खंड 1, मास्को, 1970 पृष्ठ 144 (रूसी भाषा में)

वाली शक्तियों के वास्तविक उद्देश्यों को सामने ला दिया। युद्ध ने सारी दुनिया को प्रकंपित कर दिया, और वैचारिक और राजनीतिक जीवन को ऊर्जा से भर दिया तथा जनवादी आन्दोलन को नया वेग प्रदान किया।

हिटलर की जर्मनी पर विजय ने समाजवाद की अभेद्य शक्ति को स्पष्ट रूप से दिखा दिया, इसके फलस्वरूप बहुत से कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्त जो तब तक बढ़े ठोस माने जाते थे, नितान्त निरूपयोगी हो गये।

वर्षों तक पूँजीवादी प्रचारतंत्र दुहराता रहा कि समाजवाद एक 'ऐतिहासिक संयोग' के अतिरिक्त कुछ नहीं है और नये समाज का निर्माण 'बोलशेविकों के प्रयोग' के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका कि असफल होना अनिवार्य है। तथापि, युद्ध ने दिखा दिया कि सोवियत संघ अजेय शक्ति थी और जो अकेला ही विश्व की फ्रांसिस्ट वर्धरता से रक्षा के लिए समग्र जनवादी आन्दोलन का नेतृत्व कर सकता था। इसी प्रकार उसने यह भी दिखा दिया कि इस शक्ति का स्रोत समाजवाद था। सोवियत संघ ने फ्रांसिज्म का सामना केवल अपनी शक्तिशाली सेना और औद्योगिक क्षमता से ही नहीं किया अपितु अपने क्रान्तिकारी एवं वास्तविक मानवीय विश्व दृष्टिकोण और उच्च सामाजिक आदर्शों से एकताबद्ध जनगण की शक्ति के कारण भी यह यह कर सका।

युद्ध ने फ्रांसिज्म को इजारेदार पूँजी के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी पक्ष के वैचारिक और राजनीतिक सिद्धान्त के रूप सामने लाकर नैतिक रूप से नंगा कर दिया। मानवता के विरुद्ध नाज़ियों द्वारा किये गये भीषण अपराधों ने विश्व को रसातल की बह गहराई दिखा दी जिसमें साम्राज्यवाद उसे धकेल रहा था। सामान्य जनता ने यूरोप के बहुत से देशों पर 'नये शासन' के तम्बे और कटु अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि पूँजीवादी समाज उदार जनवादी सत्थाओं को किस प्रकार खुले रूप से और तुरन्त अलग फेंक दिया गया इस प्रकार इजारेदार पूँजी के दक्षिणपन्थी तत्वों के प्रभुत्व के सार को स्पष्ट रूप से दिखा दिया।

फ्रांसिज्म के अधिकारपूर्ण वर्षों ने वित्तीय अल्पतंत्र के हितों के लिए समस्त विश्व को यातना शिविर बनाने एवं समस्त राष्ट्रों को मिटा डालने के लिए तत्पर कम्युनिज्म-विरोध के सारतत्त्व को पूरी तरह दिखा दिया। फ्रांसिज्म के वैचारिक और राजनीतिक सिद्धान्तों और अपराधपूर्ण कृत्यों ने साम्राज्यवाद की विश्व-आधिपत्य की, जनतंत्र में कटौतियाँ करने की, हर प्रकार से प्रतिक्रिया को पुष्ट करने की आम प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। हिटलर इन कार्यों में पहले के लोगों की अपेक्षा और आगे बढ़ गया, अपितु उसने ऐसा करते हुए अनुपम वैचारिक और राजनीतिक मार्ग दर्शक नीति का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसी का इजारेदारी प्रतिक्रियावाद ने समस्त विश्व में उपयोग किया।

फ्रांसिस्ट विचारधारा को आधार-शिला है कम्युनिज्म विरोध। समकालीन

कम्युनिस्ट विरोधियों ने कोई भी परिधान पहन रखे हों, हिटलर के बाद उन्होंने कोई भी मुखौटा लगा रखा हो, अंतिम विश्लेषण में, अनुभव ने यह दिखा दिया है कि वे दुनिया को कहाँ ले जाने में समर्थ हैं। तथापि, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए, कि उनके पीछे नूरेम्बर्ग के 'वीरो' की दानवी छायाएँ निरन्तर मँडरा रही हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और उसके सहयोगियों की विजय का अर्थ साम्राज्यवाद के हिराबस दस्ते की केवल सैनिक और राजनीतिक पराजय ही नहीं थी अपितु सामान्य रूप से पूँजीपति वर्ग के अत्यधिक प्रतिक्रियावादी और अतिवादी पक्ष की विचारधारा की विश्वव्यापी हार थी।

बूज्वा 'भूत्यों' की रसार्थ खड़े होने में जनवादी संस्थाओं की हिचकिचाहट, उनकी नपुंसकता तथा प्रतिक्रिया की हत्यारी टुकड़ी द्वारा उनके विध्वंस के कारण बूज्वा उदारवाद के परंपरागत अनुयायियों की दृष्टि में इन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया से गंभीरता के साथ समझीते किये। इससे पूँजीपति वर्ग की दोमुँही नीति का वैचारिक और राजनीतिक आधार सर्वथा नष्ट हो गया जिसका कि वह मजदूर वर्ग के साथ सदा पालन करता था : प्रत्यक्ष दमन और आतंक की कठोर नीति, जिसका गठजोड़ उदारवाद के आवरण में युक्तिपूर्वक काम निकालने की नीति के साथ था।

स्वभावतः इन समस्त कारकों ने विचारधारात्मक एवं राजनीतिक मोर्चे पर शक्तियों के समीकरण व समजन को बदल दिया तथा कम्युनिस्ट विरोधियों के लिए पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा करने के कार्य को और अधिक जटिल बना दिया।

पोट्सडम से शीत युद्ध तक

द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में और इसके तत्काल बाद हुए फ्रांसिजम के पतन और यूरोप तथा एशिया में समाजवादी क्रान्तियों के विकास ने पूँजीवाद के आम सकट की पहली मजल को समीप ला दिया। यदि हम उस काल की मुख्य वैचारिक और राजनीतिक धाराओं के आम विवरण देने का प्रयास करें तो चित्र कुछ इस तरह का होगा। विदा होने वाले वर्ग सदा जो भूलें किया करते हैं उसी प्रकार की परिस्थितियों में उन्हीं भूलों को दुहराते हुए साम्राज्यवाद के रणनीति निर्माता समाजवाद की जीवन्तता का अथवा अकतूवर क्रान्ति के फलस्वरूप विश्वव्यापी पैमाने पर हो रहे गंभीर सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का सही अनुमान लगाने में असमर्थ रहे। पश्चिम के अत्यधिक परिष्कृत राजनीतिक, वर्साई के निर्माताओं से लेकर, विल्सन, लॉयड जार्ज, और क्ली मेश्यू से म्भूनिख के शान्ति निर्माता चेम्बरलेन, दलादियर और उनके समुद्रपारीय सहयोगी तक, सभी सोवियत राज्य की वास्तविक शान्ति और क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उससे सम्बन्धित किसी भी बात को सही रूप में समझने में असहाय रूप से दिवालिया प्रमाणित हुए।

इसका कारण यह था कि वे सब नये समाज को नापने के लिए पुराने पैमाने

काम में ले रहे थे। बूज्वा राजनीतिज्ञ सोवियत गणतंत्र के भौतिक संसाधनों की सटीक गणना में, इसका सैनिक और आर्थिक क्षमता निर्धारित करने में, और बहुत से मात्रात्मक सूचकों की सही तुलना करने में कमोवेश सक्षम थे लेकिन वे सदा ही मुख्य चीज को—समाजवादी व्यवस्था की मौलिक रूप से नयी प्रकृति, इसके जीवन को, और इसकी विचारधारा में निहित गुणात्मक रूप से भिन्न नियमों को—दृष्टि परिधि के बाहर छोड़ जाते थे। इस प्रकार, उनके निष्कर्षों की आधारहीनता और त्रुटिपूर्ण गणनाओं के कारण अनेक बार पूँजीवादी नेताओं को कटु पराजय का मुँह देखना पड़ा।

साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार समाजवाद पर आसान विजय की मृग-मरीचिका से निरन्तर स्तब्ध होते रहे, इसने उनको चीजों को उनके सही रूप में देखने से रोक दिया। उन वर्षों में कम्युनिज्म विरोध की वैचारिक और राजनीतिक अवधारणाएँ प्रारंभिक, कुण्ठित, युयुत्सु थी जो स्पष्टतया इस विचार से ही उत्पन्न हुई थी। नये समाज के पूँजीवादी राष्ट्रों से घिरे होने का लाभ उठाते हुए, पश्चिमी देशों के नेताओं ने समाजवादी राज्य को, अलगाव में डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। वैचारिक स्तर पर, साम्राज्यवाद ने तथाकथित 'लौह आवरण' लगाने के लिए बहुत कठिन श्रम किया ताकि शेष विश्व की मेहनतकश जनता से समाजवाद से दूर रखा जाय और समाजवादी सोवियत संघ के विषय में सच्ची जानकारी से उन्हें वंचित रखा जाय। साम्राज्यवादी सिद्धान्तकारों ने कम्युनिस्टों के साथ वाद-विवाद में उलझने के बजाय समाजवाद को ही विश्व से काट देने को प्राथमिकता दी, जिससे कि जहाँ तक संभव हो बोल्शेविक 'प्रयोग' को स्थानीय बना दिया जाय और यही कारण था कि पश्चिमी देशों को डराने के लिए समाजवाद के सम्बन्ध में सभी तरह की कात्पनिक कहानियाँ प्रचारित की गयीं।

अनिवार्यतया बहिष्कार की यही नीति सोवियत विदेश नीति के सम्बन्ध में भी व्यवहार में लायी गयी। सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय क्रिया-कलाप के विषय में आमतौर से मौन साधा गया, इसके शान्तिप्रस्ताव बिना विचार किये अस्वीकार कर दिये गये, और इसके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की जनवादी व्यवस्था स्थापित करने के कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया।

निर्वासन की यही नीति सामाजिक जनोत्तेजन का मुलम्मा चढ़ाकर स्वयं पूँजीवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए काम में लायी गयी। कम्युनिस्टों को 'मास्को के दलाल' के रूप में अलग कर जनवादी शक्तियों के साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे को नेतृत्वविहीन और निरस्त्र कर दिया जाय—यह थी मुख्य राजनीतिक नीति जो उन वर्षों में प्रतिक्रिया ने ग्रहण कर रखी थी। और जब, समाजवादी सोवियत संघ की उपलब्धियों के समक्ष, पूरी दुनिया में मुक्ति, आंदोलनों की सफलता और पूँजीवाद के आम संकट के गहरे होने

के साथ-साथ यह राजनीतिक रणनीति अविश्वसनीय बन गयी, तब प्रतिक्रियावाद ने फ्रांसिस्म को राजनीतिक जीवन में घुसकर खेलने को छोड़ दिया।

इसी बिन्दु से जो कि साम्राज्यवाद की नीति का सधम था अब वह घुले रूप से समाजवादी समाज के सेना द्वारा विध्वंस पर आ गयी और सिद्धान्तकारों को यह कार्यभार सौंप दिया गया कि वे इस नीति को 'न्यायसंगत' टहराये। सिद्धान्तकारों ने यह कार्य दो प्रकार से किया : मास्को से उभरने वाले सैनिक खतरे का बार-बार उल्लेख करके उन्माद भड़काकर तथा सोवियत संघ पर अशिष्टतापूर्वक यह आरोप लगाकर कि उसने 'सोव्यों को गुलाम बना रखा है तथा वे भुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं'—उसे साछित करके।

इस प्रकार, उस काल में—जबकि पूंजीवाद के आम सफ़ट की पहली मंजिल ही चल रही थी—समाजवादी समाज के विरुद्ध संघर्ष में प्राथमिक रूप से शक्ति-शाली सैनिक साधनों का उपयोग किया गया था; बिचारधारा को, कुछ समय के लिए मात्र सहायक हथियार ही माना गया।

इसी प्रकार की कट्टर रणनीति—जैसी कि रोम की सीनेट में कैटो दि ऐल्डर ने अपना रखी थी, जो अपने हर भाषण की समाप्ति इन शब्दों के साथ किया करता था कि 'कार्पेज को निश्चय ही ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए'—सड़ाकू कम्युनिस्ट विरोधियों ने युद्धोत्तर वर्षों में अपना रखी थी। पश्चिम के साम्राज्यवादी चर्चों ने प्राविधिक और वैचारिक रूप से नये विश्वयुद्ध की तैयारियाँ शुरू कर दी। सर्वोपरि इसके कारण विज्ञान और अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व रूप से सैग्यीकरण विकसित किया गया, जनता को 'लास खतरे का' होवा' दिखाकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाया जाने लगा—संशेष में, ये तमाम चीजें शीतयुद्ध के रूप में जानी जाने लगी।

विश्व के विनाश के लिए नये युद्ध का उपक्रम किता भी अर्थ में कम्युनिज्म विरोध की रणनीति में आकस्मिक घटना न थी। अन्ततः, पश्चिम के साम्राज्यवादी क्षेत्र द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि अनिवार्य रूप से यह जनवादी, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों की विजय जानी जाती थी और साथ ही इसे साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद की रणनीति का दिवालियापन माना गया। पश्चिमी शक्तियाँ, जो परिस्थितियों के कारण हिटलरी जर्मनी के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष के लिए समाजवादी सोवियत संघ के साथ एकता करने के लिए विवश हुई थी, अब उस संयुक्त मोर्चे को ध्वस्त करने की दिशा में बढ़ने लगी।

युद्ध के उपरान्त, हिटसर विरोधी संयुक्त मोर्चे के भीतर स्वयं नवीकृत शक्तियों के साथ अन्तर्विरोध दिखायी देने लगे। उस संयुक्त मोर्चे में सोवियत संघ को आक्रमणकारी को पीछे हटाने के सामूहिक विचारों के व्यावहारिक मूर्त रूप दिखाई दिया जिसके लिए सोवियत कूटनीति ने युद्ध के आरंभ में इतना कठोर श्रम

किया था। शान्ति की रक्षा के लिए उस नीति को जारी रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुभव किया गया। पश्चिमी शक्तियों को भी इसी नीति को संयुक्त सम्मेलनों में और इस प्रकार के समझौतों में जैसे याल्टा और पोट्सडम समझौते और संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र में, सरकारी मान्यता देते हुए देखा गया। जैसा कि हम जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की युद्धोत्तर व्यवस्था के ये और इस काल के अन्य दस्तावेज और सामान्य मानचित्र इसी समय रेखांकित किये गये थे।

किन्तु, जल्दी ही यह स्पष्ट होने लगा कि हिटलर विरोधी मोर्चे हाल के सह-योगी विश्व के युद्धोत्तर संगठन के सम्बन्ध में भिन्न अवधारणाएँ रखते हैं। सोवियत संघ के लिए याल्टा, पोट्सडम और सन्क्रासिक्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन का निर्माण, उसकी सामूहिक सुरक्षा की नीति की निरन्तरता थी और स्वभावतः ही इस नीति को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया जो विश्व के युद्धोत्तर संगठनों को निर्धारित करती थी। किन्तु, पश्चिमी शक्तियों लिए ये अन्तर्राष्ट्रीय समझौते उनकी समग्र पूर्ववर्ती नीति के विपरीत समाजवाद की दिशा में जाते थे। इसलिए विश्व को फ्रांसिज्म की पराजय के पश्चात् किस मार्ग का अनुसरण करना है, यह प्रश्न अधर में झूल रहा था। या तो महान् फ्रांसिस्ट विरोधी युद्ध के सकारात्मक परिणामों को प्रगतिशील शक्तियाँ सुदृढ़ करने में समर्थ हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद घटनाओं के विकास की दिशा बदल देगा।

साम्राज्यवादी अमरीका इस समय प्रत्यक्ष रूप में सोवियत-विरोधी राजनीति की अगली पंक्ति में आ गया। विश्व प्रतिक्रियावाद के हिराबल दस्ते द्वारा रिक्त स्थान को ग्रहण करते हुए और अनेक प्रकार से उसके अन्तर्निहित तारों को लेते हुए, अमरीकी साम्राज्यवाद ने द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रगति की शक्तियों की विजय को समाप्त करने का और मानव समाज पर अपने आदेश लागू करने का प्रयास आरम्भ किया। मुश्किल से ही दुनिया नाज़ियों की गुलामी के खतरे से अपने को मुक्त अनुभव करने लगी थी कि तभी इसके सामने बालस्ट्रीट के बैंकपतियों के पैरों तले झुक जाने का खतरा उपस्थित हो गया।

यह वह समय था जब, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद अब भी समाजवादी सोवियत संघ के और मुक्ति आंदोलनों के सम्बन्ध में 'शक्ति की स्थिति से' नीति का अनुसरण करने का भ्रम पाले हुए था। अमरीका की इजारेदार पूँजी ने स्वयं विश्व-पुलिस की भूमिका ग्रहण करली और कम्युनिज्म विरोध का ध्वज धारण कर लिया। इसने पूँजीवादी देशों को अपनी ढाल के अन्तर्गत संयुक्त करने का प्रयास किया, सोवियत संघ को अलग करने का, तथा इस पर यह दबाव डालने का कि यह रियायतें दे, आत्मसमर्पण करे, समाजवादी समुदाय के उत्थान को रोके और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को खत्म कर दे। दूसरे शब्दों में, मानव समाज ने जो प्रगति की

धी उसे शून्य में परिवर्तित कर दे।

शक्ति के चल पर : योजनाएँ और दिवालियापन

शीत युद्ध का आरम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में अमरीकी इतिहासज्ञों में विभिन्न दृष्टिकोण पाये जाते हैं। कुछ इतिहासकार इसका आरम्भ 1947 से मानते हैं, जबकि ट्रूमेन के सिद्धान्त और मार्शल योजना की घोषणा की गयी थी; दूसरे कहते हैं कि इसका आरम्भ 1946 के मार्च में फुल्टन में चर्चिल के भाषण से हुआ था। अब भी कुछ दूसरे अनुभव करते हैं कि इसका आरम्भ अप्रैल 1945 में ठीक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद हुआ था। लेकिन सभी कम्युनिज्म विरोध के अनुयायी इतिहासकार इस शीत युद्ध की जिम्मेदारी अमरीकी साम्राज्यवाद और यूरोप से उसके सहयोगियों पर न डालकर इसके लिए सोवियत संघ को उत्तरदायी प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। वे दावा करते हैं कि सोवियत संघ ने युद्धोत्तर समझौते से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया और 'मुक्त विश्व' के देशों के विरुद्ध कम्युनिस्ट आक्रमण की योजना बनायी। किन्तु अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए वह कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करते। कम्युनिज्म के 'आक्रामक सार' के बारे में उनका सामान्य तर्क यह है कि वह अपने स्वभाव से ही 'स्वतंत्र विश्व' के लिए सम्भावित खतरा है।

तथापि, तथ्य सभी के लिए सुपरिचित है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के चन्द महीने बाद, संयुक्त राज्य अमरीका के नये राष्ट्रपति हैरी ट्रूमेन ने जापानी नगरों हीरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम डालने की स्वीकृति दी। आज भी हीरोशिमा स्मारक संग्रहालय की घड़ी उस समय को दिखा रही है जो विस्फोट के समय रुका था—6 अगस्त 1945 प्रातः 8.15। क्या वह शोकपूर्ण घड़ी इतिहास से खुरचकर मिटायी जा सकती है! बहरहाल, अनुवर्ती घटनाक्रम ने के आलोक में,

1. प्रख्यात अमरीकी वैज्ञानिक हर्बर्ट यार्क की पुस्तक 'रेस् टू ऑब्लिवियन' में उक्त घटना का निम्नलिखित विवरण दिया गया है—लेखक स्वयं बायुधों की नयी प्रणाली जिसमें आणविक बम भी सम्मिलित है विकसित करने में भाग ले चुका है और निस्सन्देह अपनी पुस्तक को यह उप शीर्षक देने का पूर्ण अधिकारी है 'हथियारों की दौड़ में भागीदार का दृष्टिकोण' विवरण आगे दिया जा रहा है—पहला परमाणु बम जापान नगर हीरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को डाला गया था। कम-से-कम 66,000 लोग विस्फोट होते ही तुरन्त मारे गये और बाद में आये ज्वालामुखी भरे तूफान के कारण दसियों हजार और मारे गये। हीरोशिमा के 80 प्रतिशत मकान और भवन धराशायी हो गये और जो शेष बचे वे वह भी टूट-फूट गये। बम का वजन भी हजार पाउण्ड था, वह 10 फुट सम्बा 28 इंच व्यास का था। इससे जो विस्फोटक रखा था वह यूरेनियम धातु था जो यू 235 के कठिनता से उपलब्ध होने वाले आइसोटोप से परिष्कृत किया गया था।

जापानी नगरों का बर्बर विध्वंस, जिसे किसी भी सैनिक अथवा अन्य आवश्यकता से प्रेरित नहीं कहा जा सकता, शीत युद्ध की प्रत्यक्ष क्रिया-कलाप का पहला कारनामा दिखायी देता है। यह अमरीकी सम्राज्यवाद का विश्व को भयभीत करने का एक प्रयास था, आणविक हथियार द्वारा डराने-धमकाने का और विश्व में अपनी श्रेष्ठता घोषित करने का।

6 मास से कुछ अधिक समय बीतने के बाद, राष्ट्रपति की एक विशेष गाड़ी से हैरी ट्रुमैन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल अमरीका के छोटे से नगर फ्रुल्टन में पहुँचे। वही चर्चिल ने भावी 'उत्तरी अटलांटिक संधि' (नार्थ एटलांटिक एलाइन्स) की स्पष्ट रूप से सोवियत विरोधी योजना की रूपरेखा तैयार की। 5 मार्च 1946 को दिये गये उस भाषण में, एक अमरीकी नगर में राष्ट्रपति की उपस्थिति में चर्चिल ने कहा — बाल्टिक के स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक के ट्रीस्ट तक महाद्वीप को चीरता हुआ एक सौहार्द आवरण अवतीर्ण हो चुका है।¹ उस भाषण का सार संक्षेप एक अमरीकी लेखक ने निम्न प्रकार दिया है : "विश्व अब पूँजीवादी और समाजवादी खेमों में विभक्त हो गया है। कम्युनिस्ट खेमे के विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजी बोलने वाली जनता को, पिछले समय तक जो 'प्रभु वंश' था, शीघ्र ही एक संघ बनाना चाहिए। उन्हें तुरन्त एक सैनिक संगठन के रूप में सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और अपने सैनिक संस्थानों को परस्पर जोड़ना चाहिए। उन्हें क्रिश्चियन सभ्यता को कम्युनिस्ट विरोधी धर्म-युद्ध में नेतृत्व देना चाहिए।"

इसमें एक और चीज जो जोड़ी जानी चाहिए वह है कि पूर्ववर्ती ब्रिटिश प्रधान मंत्री की सोवियत संघ के विरुद्ध धर्म-युद्ध का उन्मत्त आह्वान केवल उस नीति को सूत्रित करता है जो वस्तुतः उस समय पहले से ही व्यवहार में लायी जा

आणविक विस्फोट की भौतिक क्रियाएँ एक सैकण्ड के दस सातवें से भी कम समय में हो गयीं और ऊर्जा की जो मात्रा विस्फोट से मुक्त हुई वह उस मात्रा में भी जितनी कि चौदह हजार टन टी० एन० टी० के विस्फोट के बराबर थी। बम बी० 29 एयरक्राफ्ट से मेरियानाह के टिनायन द्वीप से फेंका गया था जो लक्ष्य से लगभग 1500 मील दूर था। यह जमीन से हजार फुट ऊपर विस्फोटित किया गया जिससे कि अधिकाधिक क्षेत्र अपने उच्च दाब वाले विस्फोट की तरंगों के और सघन ताप तथा रेडियेशन से घेर सके" (हर्वर्ट मार्क, 'रेस टू ओन्नीविन' ए पाटिसिपेण्ट्स व्यू ऑफ दि आम्स रेस न्यूयार्क 1971, पृ० 27)

1. विस्टन एस० चर्चिल, हिज़ कम्प्लीट स्पीचिज़ 1897 से 1963; राबर्ट रोड्स द्वारा सम्पादित, खण्ड VII 1943-1949, चैम्सी हाउस पब्लिशर्स इन एक्सोसिएशन आर० आर० बोकर कम्पनी सहित, न्यूयार्क और लन्डन 1974, पृ० 7290
2. जेम्स पी० बारबर्ग, द यूनाइटेड स्टेट्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, एन हिस्टोरिकल एनेलसिस ऑफ अमेरिकन फ़ौरन पॉलिसी, जी०पी० पुटनेम सन न्यूयार्क, 1954, पृ० 416

रही थी। यह कोई संयोग नहीं था कि तुरन्त ही चर्चित का समर्थन उस समय राज्य के सचिव डेमोक्रेट जेम्स बायरन्स ने और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के राजदूत (बाद के काल में स्टेट सेक्रेटरी) रिपब्लिकन जॉन फ्रास्टर डलेस ने किया। इस प्रकार शीत-युद्ध को वाशिंगटन की सरकारी विदेश नीति के अनुरूप साररूप में दोनों मुख्य पार्टियों द्वारा स्वीकृत किया गया था।

निर्विवाद रूप से, उस समय अमरीकी विदेश नीति के इन निर्माताओं की दलीय सम्बद्धता में इस बात का अत्यधिक महत्व है कि उनका सम्बन्ध बड़े व्यवसायियों, विशेष रूप से उन समुदायों के साथ था जिनके युद्ध उद्योग से घनिष्ठ सम्पर्क थे। इनमें से कुछ व्यक्तियों के परम्परागत सम्बन्ध जर्मनी की युद्ध का सामान बनाने वाली फर्मों से था। उदाहरण के लिए जॉन फ्रास्टर डलेस, जिसने अपने को शीत-युद्ध का जोशीला समर्थक प्रमाणित किया, एक समय, सुलिवान और ग्रामबेल की कानूनी फर्म का जो थोडरफ़ जर्मन बैंक घराने के जरिये नाज़ी पार्टी को वित्तीय सहायता देती थी, सहयोगी स्वामी था। दूसरे शब्दों में, वह उन अमरीकी व्यक्तियों में था जिन्होंने स्वयं कम्युनिस्ट विरोधी धर्म-युद्ध के संगठनकर्ता के रूप में हाल ही में कार्य किया था।

चर्चित की फ़्लूटन की कारंबाई एक प्रकार से शीत-युद्ध की सरकारी घोषणा के लिए सैद्धान्तिक तैयारी थी जो एक वर्ष बाद वाशिंगटन में अमरीकी सरकार की ओर से की गयी। वह 12 मार्च 1947 को कांग्रेस के लिए ट्रुमैन का सन्देश था जिसमें उसने ग्रीस और टर्की को 'सहायता' के कार्यक्रम की रूपरेखा दी थी और घोषणा की थी कि अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा इसमें निहित थी। अमरीकी विदेश नीति का मुख्य कार्य, यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया, कम्युनिस्ट 'ख़तरे' को जहाँ कहीं भी वह उठे समाप्त करना है।¹ इस सन्देश में अमरीकी साम्राज्यवाद की दीर्घ-कालीन विदेश नीति के कार्यक्रम को सूत्रित किया गया था जिसमें कम्युनिस्ट विरोध के अग्नि आवरण में उसकी विश्व आधिपत्य की आकांक्षा छिपी थी।

बर्कले में, केलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं इतिहास के प्राध्यापक फ्रैंज श्वर्मन इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सर्वोपरि स्पष्ट रूप से ये विस्तारवादी आकांक्षाएँ अशक्त ग्रेट ब्रिटेन के कन्धों से साम्राज्य का आमा खिसकने के बाद देखी गयी। अपनी इस प्रस्थापना को विकसित करते हुए वह आगे लिखते हैं: "भले ही रूस विस्तारवादी था या नहीं था यह जानना महत्वपूर्ण नहीं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि नये सारतत्व की धारा वाली विदेश-नीति की आवश्यकता क्यों हुई। जॉर्ज केनन जैसे प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत

1. ए डिक्ड ऑफ़ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, बेसिक डॉक्यूमेण्ट्स 1941-49, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, वाशिंगटन, 1950, पृ० 1253 और 1254

तथ्यों ने जो पहले से ही वांशिंगटन की विद्यमान आवश्यकता की पूर्ति कर रहे थे... उभरती हुई राष्ट्रीय सुरक्षा की अफसरशाही, जो ह्वाइट-हाउस के इर्द-गिर्द जमा है, को एक ऐसी विश्व दृष्टि की आवश्यकता है जो उनके द्वारा आरम्भ की जा रही नीतियों के अनुकूल हो।¹

मार्शल योजना द्वारा शीघ्र ही ट्रूमैन सिद्धान्त को व्यवहार में लाया गया, जो पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था में अमरीकी पूँजी को निवेशन के उद्देश्य में तैयार की गयी थी। इसका उद्देश्य, उस काल के अमरीका के स्टेट सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल के कथनानुसार, था : विश्व में कार्यशील अर्थव्यवस्था को इस प्रकार पुनर्जीवित करना कि वह ऐसी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को उत्पन्न करे जिसमें स्वतन्त्र संस्थाएँ कार्य कर सकें।² सैन्य क्षेत्र में इसे 'कम्युनिज्म को रोकने' या 'पीछे हटाने' की नीति के द्वारा पूर्ण बनाया गया।

ट्रूमैन सिद्धान्त, मार्शल योजना, और कम्युनिज्म को 'रोकने' या 'पीछे हटाने' की नीति साम्राज्यवाद की शीत-युद्ध की नीति के मुख्य उपकरण थे। ट्रूमैन सिद्धान्त घोषणा करता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद को किसी भी देश के, जहाँ पूँजीवाद की कथित अर्थव्यवस्था के लिए ख़तरा उत्पन्न होता है, भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मार्शल योजना भी अमरीका के नियन्त्रण में पश्चिमी यूरोप की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और वहाँ सामाजिक संपर्क को कमजोर करने के उद्देश्य से चलायी गयी। कम्युनिज्म को रोकने का सिद्धान्त सीधे-सीधे सोवियत विरोधी था।

शीत-युद्ध की नीति का दूसरा पहलू यह था कि इसे अमरीका की समस्त आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखा गया। सरकारी योजना निर्माता अनुभव करने लगे कि उनको अन्ततः काल के लिए एक आश्चर्यजनक जीवन सूत्र उपलब्ध हो गया। उनको आश्चर्य होने लगा कि अन्ततः निरन्तर गतिशील यंत्र की तरह यह पहले से ही विद्यमान था। शीत-युद्ध उत्प्रेरक था, और एक स्वयं चालित आर्थिक सहायता। हैडिल पकड़कर घुमाइये और जनता युद्ध के लिए नये खर्च की माँग करने लगती है। दूसरे को बघुमाओ माँग समाप्त हो जाती है। ट्रूमैन का आत्मविश्वास, उसकी आत्म-संतुष्टि इस ट्रूमैन सिद्धान्त सूत्र पर निर्भर थी।

इस प्रकार शीत-युद्ध को एक चमत्कारी औपधि के रूप में देखा गया जो साथ-ही साथ अमरीकी अर्थव्यवस्था की रक्षा करती थी, देश में आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती थी और विदेश नीति की समस्याओं को सुलझाती थी। और यह सब

1. फ्रेड श्वर्मैन, द लॉजिक ऑफ़ बटर्ड पावर, एन इन्व्हायरी इनटु दि ओरिजिन्स, करेंट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन्स ऑफ़ बटर्ड पॉलिटिक्स", न्यूयार्क 1974, पृ० 92

2. द न्यूयार्क टाइम्स, जून 6, 1947.

आपस्यंजनक रूप से बढ़ा सीधा लगता था, लगभग स्वयंचालित। यदि वाल्टेयर जीवित होता तो वह अपनी प्रसिद्ध सूक्ति को फिर से लिखता : “यदि शीत-युद्ध विद्यमान न रहता तो उसे खोजकर लाना पड़ता” इसलिए इजारेदारियों के पादरी इस आदर्श की पूजा करते हैं और इसके लिए असीम बलिदानों के लिए तत्पर रहते हैं।

अमरीका के नेता जैसे-जैसे अत्यधिक स्वीकरणीय प्रस्थापनाओं की खोज कर रहे थे जिनसे कि उनकी विश्व-आधिपत्य की नीति को बल मिले, अमरीकी विचारक इसे सिद्धान्तिक आधार देने के प्रयासों में संलग्न थे। उदाहरण के लिए, प्रो० जेम्स बर्नहेम ने अपनी पुस्तक ‘द स्ट्रगल फॉर द वर्ल्ड’ में इस दृष्टिकोण की व्याख्या की है कि आणविक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ऐसे सिद्धान्त, जैसे सम्प्रभुता, हस्तक्षेप न करना, राष्ट्रों के समान अधिकार, आदि स्वतः ही त्याग दिये जाते हैं। और व्यावहारिक रूप से, “जहाँ तक कि विश्व के राजनीतिक सम्बन्धों को प्रभावित करने का मामला सम्बन्धित है तो कार्य-विधि शीघ्र, सुदृढ़, पर्याप्त हस्तक्षेपयुक्त होनी चाहिए न कि अहस्तक्षेप की।”¹

इन प्रश्नों पर कि यह हस्तक्षेप क्या-क्या रूप ले सकता है और विश्व में किस प्रकार बाढ़ की घटनाएँ घट सकती है, यदि पैटागोन आणविक आयुधों की इजारे-दारी को कब्जों में रखता है, दूसरे अमरीकी प्राध्यापक, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डा० हैरॉल्ड सी० यूरी बड़ी स्पष्टतापूर्वक इसका उत्तर देते हैं—“या तो अमरीका विश्व के समस्त देशों को आणविक आयुधों के उत्पादन से रोकने के लिए उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण सुरक्षित कर लेता है और जिससे युद्ध पर पूर्ण नियन्त्रण हो सके अथवा हम तुरन्त तीसरे विश्व युद्ध के आरम्भ करने की तैयारी करें जिसमें कि आणविक बमों का उपयोग किया जाय।”²

बेशक, इस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थन के लिए सदा एक ‘ठोस’ तर्क अवश्य तैयार मिलेगा और इसे कम्युनिज्म की ओर से हमले के उसी पुराने खतरे के सन्दर्भ के रूप में शीघ्र उत्पन्न कर लिया गया। यह उस नये दक्षिण से जो अतिरिक्त ‘प्रमाणों’ के साथ अब प्रस्तुत किया गया है बहुत भिन्न है।

सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि, विकास के समाजवादी मार्ग को चुनने में अनेक देशों के जनगण की रुचि, कम्युनिस्ट पार्टियों की बढ़ती हुई भूमिका, कुल मिलाकर विश्व जनवादी आन्दोलन का दृढ़ होना, युद्धोत्तर वर्षों में होने वाले समस्त प्रगतिशील परिवर्तनों को साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकारों ने भास्की के ‘पड़घत्तों’ के रूप में चित्रित किया जिन्हें कि अमरीका और उसके

1. जेम्स बर्नहेम, द स्ट्रगल फॉर द वर्ल्ड, न्यूयार्क, 1947, पृ० 177.

2. दि यूनाइटेड स्टेट्स न्यूज, अगस्त 30, 1946, पृ० 52

साधियों को, जहाँ कहीं भी वे 'स्वतन्त्र विश्व के लिए' खतरा पैदा कर रहे हो, रोकना था।

कम्युनिज्म को 'सर्वाधिपत्यवादी' और 'आक्रामक' फासिज्म के साथ एक ही धेले में डाल दिया गया। इसपर हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। सड़कों पर घूमने वाले व्यक्तियों को 'सोवियत विस्तारवाद' की कहानियों से निरन्तर आतंकित किया गया। जार्ज केनन ने लिखा कि समाजवादी सोवियत सघ कथित रूप से दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है कि अमरीका के साथ जीवन बिताना सम्भव नहीं है उसके लिए यह वांछनीय और आवश्यक है कि हमारे समाज की आन्तरिक समस्वरता छिन्न-भिन्न हो जाय, हमारी परम्परागत जीवन पद्धति नष्ट हो जाय, और हमारे राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार टूट जाय...।¹

कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार का ढोल पीटने के लिए साम्राज्यवाद ने द्वितीय विश्व-युद्ध में सोवियत जनता के महान कदमों की निन्दा करने के पागलपन भरे प्रयास किये। पाश्चात्य इतिहास लेखन नाट्यियों के उस वक्तव्य पर जा पहुँचा कि समाजवादी सोवियत सघ के विरुद्ध जर्मनी का युद्ध रक्षात्मक युद्ध था।² 'सोवियत खतरे' के मिथक को पुनर्जीवित करते हुए साम्राज्यवादी प्रचार ने घटनाओं के वास्तविक क्रम को ही गड़बड़-मड़बड़ कर दिया। वास्तव में युद्ध उभारने वालों को साफ़ बरी करके सोवियत संघ पर बार-बार 'आक्रामक आकांक्षाओं' के आरोप लगाये गये।

शीत-युद्ध की नीति मानव समाज को बहुत महँगी पड़ी। अमरीका में यह मेकार्थीवाद के रूप में परिवर्तित हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसने अपना काला झण्डा क्रांतिकारियों और जनवादी आन्दोलनों के विरुद्ध लड़ने वालों को थमा दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम आक्रामक कार्रवाइयों की शृंखला के रूप में सामने आया। स्पानीश युद्ध, लगभग हर महाद्वीप में, कोरिया से बर्लिन तक क्यूबा से वियतनाम तक, कांगो से मध्यपूर्व तक सैनिक घड्यंत्र और भड़काने वाली कार्रवाइयाँ, और आक्रामक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की पूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। और निस्सन्देह, इस सबका परिणाम था अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का वातावरण, अविश्वास का, और युद्धोन्माद का वातावरण। शीत-युद्ध उन विशाल भौतिक और सांस्कृतिक संसाधनों को चट कर गया जो हथियारों की होड़ और विध्वंसक कार्रवाइयों पर व्यय किये गये थे। नैतिक रूप से यह एक जहर बन गया, जिसने जनमण की आत्मा को खा डाला, किन्तु³ अन्तिम गणना में, यह नीति भी

1. जॉर्ज केनन 'मैमाथर्स' 1925-1950, बोस्टन, 1967, पृ० 557

2. जॉर्ज केनन, 'मैमाथर्स' 1925-1950, बोस्टन, 1967, पृ० 55

3. इस देशभक्त का व्यापक उपयोग नाज़ी प्रचार द्वारा सोवियत सघ पर हमला करने के लिए सैयारी के रूप में किया जा रहा था और पूरे युद्ध के दौरान किया जाता रहा है।

असफल हो गयी।

सर्वप्रथम, इसका अपने मुख्य उद्देश्य में असफल होना निश्चित था, वह उद्देश्य था समाजवाद के विरुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमण करना। युद्ध के बाद, समाजवाद की पूँजीवाद के मुकाबले ऐसी श्रेष्ठता सिद्ध हुई कि कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता था। सोवियत संघ को रणदोत्र में दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक हानि पहुँची थी, पर उसने स्वतन्त्र रूप से और तेजी के साथ अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर लिया और आर्थिक विकास में, विज्ञान और प्रविधि के विकास में भारी छलांग लगायी, सैनिक प्रविधि भी इसमें सम्मिलित थी। इस अकेले तथ्य ने ही शीत-युद्ध के संगठनकर्ताओं की सारी रणनीति को और 'कम्युनिज्म को पीछे फेंकने' की उनकी योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया। सोवियत संघ की बढ़ती हुई आर्थिक और सैनिक शक्ति ही वह अतिमहत्वपूर्ण तत्व था जो, यूरोप और एशिया के बहुत से देशों के जनगण द्वारा विकास के समाजवादी मार्ग का चुनाव किये जाने का और साथ ही समाजवादी समुदाय के आविर्भाव और सशक्त होने का भी कारण बना। इसके साथ-ही-साथ औपनिवेशिक व्यवस्था के विनाश ने और इस तथ्य ने कि बहुत से देशों ने स्वतन्त्रता एवं प्रगति का मार्ग अपना लिया है, इससे साम्राज्यवाद की कमर टूट गयी।

जहाँ तक समाजवादी सोवियत संघ और विश्व मुक्ति आन्दोलन के विषय में 'शक्ति की स्थिति से' की नीति के अनुसरण की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में पाले गये धर्मों की बात है वह धीरे-धीरे टूटते चले गये। उनके कम्युनिज्म को 'रोकने' 'मुक्त करने' या 'पीछे हटाने' के सिद्धान्तों पर पर्दा उठा दिया गया। अन्ततः साम्राज्यवाद के अभिजात शासक वर्ग को उन्हे ताक में रख देना पड़ा।

पाँचवें दशक के अन्त में और छठे दशक के आरम्भ में ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखायी दिये। राजनीतिक स्तर पर यह परिवर्तन हंगरी में प्रतिक्रान्ति की असफलता मिस्र में स्वेज की दुस्साहसिकता के अन्त और क्यूबा में क्रान्ति की विजय और पूँजीवादी देशों में मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों की बढ़ती हुई भूमिका में दिखायी दिये। 1960 में कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की घोषणा में उल्लेख किया गया : "इन वर्षों के मुख्य परिणाम हैं : विश्व समाजवादी व्यवस्था की तेजी से वृद्धि और उसकी शक्ति तथा अन्त-

फिशे, गोएवल्स के मन्त्रिमंडल में एक उच्च अधिकारी था, उसने नूरेध्वगं ट्रायल में यह स्वीकार किया था कि, सोवियत संघ पर हमले के बाद, जर्मन प्रचार का यह मुख्य काम था कि इस आक्रमण की आवश्यकता को न्यायसंगत सिद्ध किया जाय। अतः हमें इस बात पर बार-बार जोर देना पड़ता था कि हमें सोवियत आक्रमण की रोक-थाम करनी है।" (अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य ट्रिब्यूनल के सामने बड़े मुद्द अपराधियों की जाँच खंड XVII, नूरेम्बर्ग, 1948, पृ० 226)

राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि राष्ट्रीय भुक्ति आन्दोलन के प्रभाव के कारण औपनिवेशिक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होते की शक्तिशाली प्रक्रिया, पूँजीवादी विश्व में संघर्ष का विस्तार, और विश्व पूँजीवादी व्यवस्था का पतन और ह्रास। साम्राज्यवादी शक्तियों से समाजवादी शक्तियों की श्रेष्ठता, जंगखोर तात्त्वों से शान्ति की शक्तियों की श्रेष्ठता विश्व-ध्यापी पैमाने पर लक्षित की गयी।¹ बाद के वर्षों में समाजवाद के पक्ष में शक्तियों के सन्तुलन में यह सामान्य धारा तेजी से विकसित हुई और साम्राज्यवाद की ओर से कोई प्रत्याक्रम नहीं हुआ। भुक्ति संघर्षों में कोई भूलें या पराजय नहीं हुई, चीनी नेताओं के सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद के उद्देश्य के साथ दुःखद विच्छेद और विश्वासघात भी इसको नहीं बदल सके।

विदेशनीति के 'चतुर्थ क्षेत्र' की सक्रियता

जैसे-जैसे 'शक्ति के बल पर' कार्य करने की नीति का संकट गहराने लगा पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष के गुरुत्व का केन्द्र वैचारिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए विवश हो गयी। धीरे-धीरे वैचारिक संघर्ष कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेश नीति के 'चतुर्थ स्तर' तक पहुंचा दिया गया। जबकि वैचारिक क्षेत्र पहले ही महत्वपूर्ण था, अब से इसे वस्तुतः विस्तृत कार्य-क्षेत्र उपलब्ध होगा।

जब अक्तूबर 1957 को अमरीका के शीत-युद्ध की रणनीति के निर्माताओं के सिर पर सोवियत अन्तरिक्ष उपग्रह घूमने लगा तब 'शक्ति के बल पर' कार्य करने की नीति की असफलता जगजाहिर हो गयी। अमरीका की वायुसेना के राज्य सचिव थोमस फ़िनलेटर ने इस घटना को अमरीका के लिए संभावित परिणामों की दृष्टि से निम्न प्रकार लक्षित किया—“तब प्रायः रातों-रात ही घटनाओं की एक ऐसी स्थिति से जिसमें कि अमरीका के लिए सामान्य युद्ध कोई खतरा नहीं प्रतीत होता एक अतिभीषण विनाश की, जिसमें लाखों अमरीकियों के मरने से और लाखों अमरीकियों के धायल होने से नागरिक विनाश की स्थिति में पहुँच गये।”

“1917 की रूसी क्रान्ति के अतिरिक्त मैं ऐसी किसी घटना को नहीं जानता, जिसने ऐसा परिवर्तन किया हो जो हमारे देश की सुरक्षा एवं सत्ता के लिए इतना बुरा हो।”

यह कहना अनावश्यक होगा कि इसके कारण अमरीकी विदेशनीति में कुछ सुधार करने पड़े। यही कारण था कि 1950 के अन्त में, अमरीकी राजनयिकों की भाषा में, अमरीकी-सोवियत सम्बन्धों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा

1. दि स्ट्रगल फ़ार पीस, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, पृ० 37-38.

2. थोमस के० फ़िनलेटर, 'फ़ॉरेन पॉलिसी : द नैक्स्ट फ़्रंट', न्यूयार्क, 1958, पृ० 23

करते समय 'मुकाबलों के युग से बातचीत के युग तक' की शब्दावली प्रयुक्त होने लगी। इन प्रयासों की बुनियादी दिशा को सक्षित करते हुए रिचर्ड एम० निक्सन ने जो उस समय तक अमरीका के राष्ट्रपति नहीं बने थे, अपनी पुस्तक 'सिक्स काइसिस्' (प्रथम संस्करण, 1960) में लिखा था : "सैनिक शक्ति अनिवार्य है— वशतः कि इसे आर्थिक, राजनीतिक और प्रचारात्मक कार्यक्रमों में इसे पूर्ण किया जाय।"¹ कुछ वर्षों बाद, रिचर्ड निक्सन पहले अमरीकी राष्ट्रपति बने जिन्होंने मास्को की सरकारी यात्रा की।

वे कायल हो गये कि समाजवादी सोवियत संघ, समाजवादी समुदाय और मुक्ति आन्दोलनों के सम्बन्ध में पुरानी कठोर नीति न केवल निरर्थक अपितु खतरनाक भी थी, साम्राज्यवाद के रणनीति निर्माताओं ने अब यथार्थवादी विकल्प के विषय में विचार करना आरम्भ कर दिया 'प्रभावशाली प्रतिकार' के धमकी भरे सिद्धान्त से 'लचकीला प्रत्युत्तर' के सिद्धान्त पर आ पहुँचे।² समाजवादी देशों के विरुद्ध आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव की नीति से 'पुल बनाने की' रणनीति की ओर मुक्ति आन्दोलनों और मजदूर वर्ग के जनवादी संघर्षों के प्रत्यक्ष दमन के स्थान पर संशोधित सामाजिक और राजनीतिक कूटनीति तक पहुँच गये।

इस नीति के आधार पर, साम्राज्यवाद ने प्रचार की प्रवृत्तियों की नयी योजना बनाना आरम्भ किया इसके लिए उस काल की अनेक मुख्य समस्याओं के साथ समाजवाद और पूँजीवाद के बीच शक्ति संतुलन से परिवर्तन को ध्यान में रखना पड़ा। दूसरे शब्दों में, उनको अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर कुल मिलाकर मजदूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच संतुलन के विकास को और इसी प्रकार प्रत्येक पूँजीवादी देश के विकास को और साथ ही पूँजीवाद के राज्य इजारेदार रूपों के विकास द्वारा उपलब्ध कुछ नयी घटनाओं को भी और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति के विकास को भी ध्यान में रखना था।

यह वह काल था, पाँचवें और छठे दशक का संघिकाल, जबकि पूँजीवादी देशों के नेताओं, राजनयिकों और सिद्धान्त निर्माताओं ने, संभवतः पहली बार समाजवाद के साथ ऐतिहासिक प्रतियोगिता का पूर्ण महत्व आत्मसात् किया। इससे साम्राज्यवादी वैचारिक सेवाओं का ठोस रूप में पुनः संगठन आवश्यक हो गया, अथवा अधिक स्पष्टता से कहें तो शब्द के व्यापक अर्थ में इसकी वैचारिक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। इसमें नया तत्व था कि कम्युनिज्म के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष में पूँजीपति वर्ग द्वारा प्रयुक्त साधनों की आपूर्ति के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक क्षेत्रों के क्रिया कलाप, मौलिक महत्व के स्वतंत्र मोर्चे बन गये।

अब पूरे विश्व में, समाजवाद और जनवादी आन्दोलन के विरुद्ध 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' साम्राज्यवादी शक्तियों की नीति का अभिन्न अंग बन गया।

इन समस्याओं के एक अध्येता विल्सन डिजार्ड ने जो पहले अमरीकी सूचना एजेंसी से सम्बद्ध था, 1960 के आरम्भ में यह टिप्पणी की थी : "जब तक आत्मघाती आणविक युद्ध न हो तब तक कम्युनिस्टों और हमारे बीच शक्ति-संतुलन अधिकांश में विश्व जनमत के क्षेत्र में निर्धारित होगा।"¹

ठीक इसी प्रकार की स्पष्ट सम्मति अमरीकी राजनयिक ज्यार्ज बी० एलेन ने ह्यूक विश्व यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए प्रकट की थी। उन्होंने कहा : यह प्रचार व्यापक रूप में बना रहेगा और प्राविधिक प्रगति ने इसको कूटनीति के लिए इतना आवश्यक बना दिया है जितना कि सेना के लिए बारूद थी।²

यह मस्तिष्क में रखकर, साम्राज्यवादी शिविर, सर्वोपरि अमरीका ने अपने विदेश नीति के प्रचार को अभूतपूर्व क्षेत्र प्रदान किया है, वैचारिक संघर्ष के लिए एक शक्तिशाली मशीनरी तैयार की है, प्रचार सम्बन्धी क्रिया-कलाप के लिए अधिक प्रभावशाली संगठनात्मक रूपों की जोरो के साथ खोज की है, और इसके तरीकों को अधिक परिष्कृत करने पर अधिकाधिक ध्यान दिया है। फलस्वरूप, छठे और सातवें दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वैचारिक संघर्ष में नयी मंजिल आ गयी इसे इस प्रकार लक्षित करने का हमारे पास आधार है। इसे साम्राज्यवाद की विदेश नीति के प्रचार के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से लक्षित किया गया — दोनों क्षेत्रों में ये प्रयोग किये जा रहे हैं, कार्यनीतिक तरीकों के प्रयोग में और कुछ वैचारिक अवधारणाओं के सारतत्त्व में।

वैचारिक प्रचार सेवाओं का पुनर्गठन

जब एक बार यह पूँजीवादी देशों की सर्वोच्च राज्य इजारेदारियों की चिन्ता का विषय बन गया, इस क्षेत्र ने नये महत्वपूर्ण संगठनात्मक रूप से लिये। पूँजीवादी राज्य के विशिष्ट क्रिया कलाप के रूप में, वैचारिक संघर्ष का निर्देशन पूँजीवाद की वर्तमान मंजिल के विशिष्ट रूपों को पृथक्-पृथक् प्रतिबिम्बित करता है। विशेष रूप से, यह राज्य इजारेदारी ढाँचों की वृद्धि का, अन्तर्राष्ट्रीय समेकीकरण और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति की उपलब्धियों के एकीकरण का उपयोग करता है। यह सारी प्रक्रिया पूरी मात्रा में 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' तक विस्तृत कर दी जाती है। और भी, इजारेदारी के समक्ष पूँजीवादो राज्य की और अधिक अधीनता,

1. विल न, पी० डिजार्ड; द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ यू एस इन्फर्मेशन सर्विस वाशिंगटन, 1961, पृ० 186
2. जान डब्ल्यू हैडरसन, द यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन एजेंसी, न्यूयार्क, वाशिंगटन-लन्दन 1966, पृ० 14 से उद्धृत।

गमाजवाद के विरुद्ध बहुराष्ट्रिक इजारेदारियों के संयुक्त मोर्चे की ओर प्रवृत्ति और विज्ञान एवं प्रविधि की उपलब्धियों का साम्राज्यवाद के हित में उपयोग करने के प्रयास इस क्षेत्र में सम्भवतः पहले से कहीं अधिक स्पष्टता के साथ देखे जा सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध के साम्राज्यवादी शक्तियों के राष्ट्रीय क्रिया-कलाप के रूप में नियमीकरण का परिणाम सर्वोपरि साम्राज्यवाद की वैचारिक सेवाओं के कठोर केन्द्रीकरण के रूप में हुआ। इसने शासक अभिजात वर्ग को इस क्रिया-कलाप को अपूर्व व्यापकता प्रदान करने का अवसर मिला गया, इसमें प्रचार की संस्थाओं के साथ सरकारी संस्थानों जैसे मेना, गुप्तचर सेवा और विदेशों में उनकी शाखाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। हाल के वर्षों में एवं विदेशी प्रचार की पूरी व्यवस्था, संगठन और केन्द्र साम्राज्यवादी देशों में निर्मित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत कई परस्पर अन्तःक्रिया युक्त 'चक्र' हैं।

'वैचारिक पर्वत' के शिखर पर बैठा सिद्धान्त कारों का छोटा-सा गुट अपने आपको समकालीन मानव समाज का आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक मानता है। उसका काम है 'नये' विचार देना, आधुनिक अवधारणाओं की रचना करना, घिसी-पिटी युक्तियों को नया रूप देना और वैचारिक क्षेत्र में स्वर निर्धारित करना।

"मध्यवर्ती चक्र में ये विचार इस प्रकार पिरो दिये जाते हैं (सामान्यतया बड़े परिष्कृत ढंग से) कि ये विभिन्न प्रकार के दशकों, हितों और माँगों के अनुरूप हो सकें। यहाँ सामान्य प्रस्थापनाएँ लोकप्रिय रूपों में सुसज्जित की जाती हैं और उनको विशेष रूप से चुने हुए तथ्यों से चित्रांकित किया जाता है, उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक ध्यान के साथ।

और अन्ततः, जनप्रचार है। चक्रों की इस बहुशाखीय व्यवस्था में, सभी कड़ियाँ सरकारी पद-सोपान-परम्परा व विभागों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं।

कम्युनिज्म के विरुद्ध प्रचार के इस क्रिया कलाप में समस्त पूँजीवादी देश भाग लेते हैं। किंतु संयुक्त राज्य नेतृत्वकारी भूमिका अदा करता है, वहाँ इन उद्देश्यों के लिए भारी धन-राशि व्यय की जाती है जहाँ अत्यधिक शक्तिशाली विदेश नीति की प्रचार मशीनरी निर्मित की जाती है, जहाँ इस क्षेत्र में अधिकतम संख्या में संगठन कार्यरत हैं, मुख्य प्रचार संघों से लेकर सभी प्रकार के संगठन केन्द्र और ग्रुप वैज्ञानिक संघर्ष के नवविरचित रूपों, पद्धतियों और साधनों से कार्य कर रहे हैं। वहाँ भारी मात्रा में कम्युनिस्ट विरोधी सामग्री तैयार की जाती है और कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार के 'सामूहिक गान की' तान-लय तय की जाती है।

अमरीका की प्रचार मशीनरी अधिकतम केन्द्रीकरण और कठोर पद सोपान तंत्र की अधीनता के सिद्धान्त पर कार्य करती है। मुख्य चालक यंत्र ह्वाइट हाउस

के स्टेट विभाग के, और केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण (सी० आई० ए०) के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। विचारधारा और प्रचार में राज्य इजारेदारी केन्द्रीकरण की दिशा में प्रवृत्ति विशेष रूप से अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी देशों में राजनीतिक जीवन में देखी जाती है और उससे कुछ बड़े ठोस परिणाम निकलते हैं। यह, सर्वप्रथम, वस्तुतः किसी भी सरकारी अभिकरण के क्रियाकलाप को कम्युनिज्म विरोध के कार्य के अधीन कर देती है, दूसरे, व्ययसाध्य विदेशी प्रचार मशीनरी का व्यय राज्य की कीमत पर चलाती है अर्थात् करदाताओं के धन पर और तीसरे, इस क्षेत्र में अन्तःसरकारी स्तर पर अपने प्रयासों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करती है।

इस समय, वैचारिक संघर्ष के मुख्य क्रियाकलाप अतीत की भाँति विशिष्ट प्रचार संस्थानों द्वारा नहीं भापे जाते, जैसे प्रत्यक्ष रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्य मशीनरी, वैज्ञानिक संस्थान और प्रचार मशीनरी के सभी सम्पर्कों के बीच घनिष्ट अन्तःक्रिया सहित, और ये अब असम्बद्ध क्रियाएँ नहीं रही अपितु निर्विवाद रूप से, सावधानी से निमित्त, पृथक्-पृथक् व्यवस्थित, सोद्देश्य वैचारिक आन्दोलन बन गये हैं जो विश्वव्यापी पैमाने पर स्वतंत्रतापूर्वक चलाये जा रहे हैं।

व्यापक रूप से वित्तीय नियमन के चालको सहित राज्य सत्ता के साधनों का उपयोग करते हुए, पूँजीवादी देशों की सरकारें अपनी विविध प्रचार-प्रवृत्तियों की अन्तःक्रिया को सावधानी के साथ संयुक्त करते हैं और उसका सारतत्त्व निर्धारित करते हैं।

हाल के वर्षों में एक आवश्यक रूप से नया बहुविभागीय उद्योग दुनिया में स्थापित किया गया है—जनमाध्यम (मासमीडिया) इस पर लाखों-लाख डॉलर व्यय किये गये और किये जा रहे हैं। पूँजीवाद ने जहाँ अति भारी वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति उपलब्ध की है, यह क्षेत्र जन-संहार के अस्त्रों के क्षेत्र को छोड़कर किसी से पीछे नहीं है।

सूचना इस समय एक सामाजिक रूप से आवश्यक वस्तु बन गयी है और बड़े व्यापार की एक मद बन गयी है। इजारेदार तथा प्रेस, रेडियो और टेलिविज़न के राजा उनसे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरी ओर, बहुत से प्रचार के कार्य विशेष रूप से बाहर विदेश में बहुत व्ययसाध्य हैं उनको किसी प्रकार का लाभ-नहीं मिलता। इजारेदारियाँ इन क्षेत्रों में राज्य का हाथ रहने को वरीयता देती हैं, जनता पर वैचारिक प्रभाव की अधिक व्ययसाध्य शाखाओं को व्यापक बनाने और पूर्ण बनाने का कार्य वे सरकार पर छोड़ देती हैं तथा निस्सन्देह इसके लिए सारा व्यय करदाताओं की जेब से आता है। इस प्रकार, वहाँ पूँजीवादी इजारेदारियों और पूँजीवादी राज्य के बीच या अधिक स्पष्टता से कहे तो इजारेदारियों के हित में

सरकारी सेवाओं की और अधिक अधीनता हो जाती है।

विदेशनीति सम्बन्धी प्रचार पर संकेन्द्रण साम्राज्यवादियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में इन प्रश्नों पर अपने बीच नयी समझ पर पहुँचने में समर्थ बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे पश्चिमी शक्तियों की सरकारें समाजवाद के विरुद्ध सैन्य योजना के क्षेत्र में संयुक्त हुई और घनिष्ठ आर्थिक समुदाय बनाने के लिए साथ आयी, इसी प्रकार वे कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार के क्षेत्र में भी अपने प्रयासों को संयुक्त करके एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारात्मक निकाय स्थापित कर सकती है।

उदाहरण के लिए, नाटो के ढाँचे के अन्तर्गत बड़ा सत्रिय सहकारी प्रचार केन्द्र है, सरकारी तौर पर इसका नाम है अन्तर्राष्ट्रीय सूचना और सांस्कृतिक विषयों का कार्यालय लेकिन यह मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप की सशोधन समिति के रूप में सुपरिचित है। औपचारिक रूप से, नाटो के प्रधान कार्यालय एवरे में सूचना सेवा उत्तरी अतलान्तिक संधि संगठन (नाटो) के 'सुरक्षा' उद्देश्यों एवं 'सांस्कृतिक' क्रियाकलाप के स्पष्टीकरण का कार्य अंजाम देती है। वास्तव में यह युद्ध के मनो-वेगों को भड़काती है और कम्युनिज्म विरोध के ध्वज के अन्तर्गत हथियारबन्दी की दौड़ को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करती है। नाटो की प्रचार सेवाएँ अपने उपविभागों के द्वारा सदस्य देशों में वैचारिक मस्तिष्क शुद्धि की योजनाएँ बनाती हैं और समस्त खंडों के भागीदारों के प्रचार-तंत्र का उपयोग करती हैं और इस प्रकार अपने क्रियाकलाप को ब्लॉक की सीमाओं के बाहर पहुँचा दी हैं।

इसी प्रकार की प्रचार-इकाइयाँ पाश्चात्य देशों के सैनिक-राजनीतिक और अन्य आर्थिक संगठनों के अन्तर्गत भी अन्तःसरकारी स्तर पर कार्य करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति के साथ अपने नियमित संयोजित क्रियाकलाप को बढ़ाते हुए वे साम्राज्यवाद की सामान्य विदेश नीति की प्रचार-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रत्येक देश में इसकी मशीनरी कम-अधिक मात्रा में निम्न सम्पर्क रखती है : विशेषीकृत सरकारी सेवाएँ, निजी स्वामित्व वाले जन-सम्पर्क माध्यम, और विभिन्न प्रकार के मिश्रित केन्द्र। प्रत्येक संपर्क के अपने विशिष्ट कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कतिपय कारणों से शासक वर्ग के लिए यह सुविधा-जनक हो एक सरकारी एजेन्सी निजी आवरण के अन्तर्गत या निजी सरकारी आवरण में कार्य कर सकती है। यह नहीं, यहाँ प्रत्येक विभाजन सापेक्ष होता है, यह प्रायः साम्राज्यवाद के आन्तरिक और विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार की व्यवस्था की एक या दूसरी सेवाओं के लिए केवल पर्दे का काम करती हैं।

उदाहरणार्थ, अमरीका में, मुख्य सरकारी विदेश नीति प्रचार एजेन्सी 'यूनाइटेड स्टेट्स इन्फॉर्मेशन एजेन्सी' (यू० एस० आई० ए०) थी, अपने तरह का विश्व का बृहत्तम संस्थान। इसका मुख्य सिद्धान्त या विदेश नीति प्रचार की संमस्त

मुख्य प्रवृत्तियों का केन्द्रीकरण । जिससे कि, इसकी सम्पूर्ण विशाल प्रचार मशीनरी जनमाध्यमों और जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाले अन्य साधनों सहित, कुशलतापूर्वक काम में लायी जा सके ।

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राज्यों में, जो अमरीकी आकाशवाणी के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं में वैचारिक प्रवेश पाने के उद्देश्य से अमरीका ने यू० एस० आई० ए० के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संचार सेवा और अमरीकी स्टेट विभाग का सांस्कृतिक ब्यूरो स्थापित किया । निश्चित रूप से, जीवन की अमरीकी पद्धति व्यापक का प्रचार का विषय रहती है । पेन्टागन की बहुमुखी प्रचार मशीनरी, जिसकी रेडियो स्टेशनो की प्रकाशन-गृहों आदि की विदेशों में अपनी व्यवस्था है, इसी प्रकार के कार्य करती है । सी० आई० ए० और दूसरे बहुत से संगठनों के भी सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के विरुद्ध कार्यों के लिए विशिष्ट विभाग हैं ।

ब्रिटेन में यह कार्य (बी० बी० सी०) ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन करता है जो विदेशों में रेडियो और टी० बी० पर प्रचार के साथ प्रकाशन का कार्य भी करता है । ब्रिटिश कौंसिल भी इन कार्यों में सलग्न है, जिसके प्रतिनिधि दुनिया-भर के बहुत से देशों में हैं, जो वहाँ पुस्तकालयों के संचालन, प्रचार और प्रदर्शनियाँ, फिल्म प्रदर्शन और अंग्रेजी अध्यापन आदि का कार्य करते हैं ।

संघीय जर्मन गणतंत्र में सब कार्य फ्रेडरल प्रेस और सूचना विभाग द्वारा पूरे किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत सरकारी रेडियो स्टेशन, ड्यूडश्लेड-फ्रैंक और सोवियत विरोधी ड्यूडशेवले प्रसारण करते हैं । विकासशील देशों में कार्य के लिए वहाँ गोड्डे ड्यूडशेज कुल्लूर इंस्टीट्यूट है और वैचारिक विध्वंस के लिए सुप्रसिद्ध ओस्ट्रोडशुग है ।

फ्रांस में प्रचार कार्य 'लिवरल' एजेन्सी फ्रांसीसी प्रेस (AFP) द्वारा किया जाता है, फ्रांसीसी रेडियो और टेलिविजन सेवाओं के माध्यम इसके साथ हैं (ऑफिस डी रेडियो डिप्लूजन एट टेलिविजन फ्रेंकाइज) ।

इस प्रकार पूँजीवादी राज्यों की वैचारिक सेवाएँ समाजवाद विरोधी, सोवियत विरोधी प्रचार व्यापक उत्पादन की नीति पर चलाती हैं ।

निजी जन-माध्यम : छद्म वस्तुनिष्ठता और वास्तविक उद्देश्य

कम्युनिज्म के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष की चाहे जितनी बड़ी सरकारी मशीनरी हो, यह वैचारिक मोर्चे पर संघर्षरत शक्तियों का केवल एक शस्त्र है । दूसरा, जो इससे कम शक्तिशाली नहीं, निजी स्वामित्व वाला जनमाध्यम जो सीधे सीधे इजारेदारियों के अधिकार में है । ये हैं अतिविशाल विश्वव्यापी टेलीग्राफ़

एजेन्सियाँ, समाचार-पत्रों के ट्रस्ट, चल चित्र कम्पनियाँ, रेडियो का विस्तृत जाल आदि। आधुनिक पूँजीवादी राज्यों के वैचारिक क्रियाकलापों का विस्तार किसी प्रकार भी इनके लिए बाधक नहीं है अपितु उलटे जन माध्यमों को इजारेदारियों के हाथों में केन्द्रित करने की सुविधाएँ प्रदान करता है।

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखें कि साम्राज्यवादी क्षेत्र अपनी 'झूठी' स्वतंत्रता से जनता को सम्मोहित करने के लिए 'निजी प्रेस' की स्थिति का भी उपयोग करते हैं और इस बहाने वास्तव में झूठी सूचनाएँ देने में संलग्न रहते हैं।

पूँजीवादी देशों में स्थिति समाजवादी देशों से बुनियादी रूप से भिन्न है, जहाँ समस्त सूचना माध्यम राज्य के हैं, पार्टियों या जन संगठनों के हैं जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि समाचारपत्र अथवा रेडियो स्टेशन ऐसी सूचना प्रसारित करते हैं जिसके लिए जनता के सामने कोई उत्तरदायी नहीं होता। न केवल पूँजीवादी राज्यों की सरकारों के पास बल्कि पूँजीवादी पार्टियों के पास भी प्रायः अपना आधिकारिक समाचारपत्र नहीं होता। इसके स्थान पर, वे निजी फर्मों के निजी व्यक्तियों के पत्रों का उपयोग करते हैं, तथाकथित 'स्वतंत्र' पर व्यवहार में यह अत्यधिक भ्रष्ट और लोभुप्रेस होता है जिसके लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं लेता।

'स्वतंत्र' सूचना केन्द्रों की स्थिति का दुरुपयोग व्यवहार में जनता की राय को मनमाने ढंग से विकृत करता है, जैसे-जैसे इसका क्षेत्र बढ़ता है यह अधिकाधिक खतरनाक होता जाता है। इसलिए पूँजीवादी समाज में, शासक वर्ग द्वारा सूचना प्रसारण के स्रोतों और साधनों के केन्द्रीकरण के प्रयासों को प्रेस, आकाशवाणी और टेलिविज़न के पदों तक उन सबकी पहुँच को रोकने का प्रयास समझना चाहिए जो 'विपरीत' मत रखते हैं। स्वतंत्र जनमाध्यम की इजारेदारियाँ सूचना के अन्य सभी स्रोतों को समाप्त करने का और सूचना पर पूर्ण इजारेदारी प्राप्त करने का प्रयास करती हैं जिससे कि अपनी इच्छानुसार वे उसे दे सकें।

उदाहरण के लिए, अमरीका में, व्यवस्था मोटे तौर पर निम्न प्रकार होती है : तैयार सामग्री से देश में और विदेश में समस्त अमरीकी सूचनाओं को जो उपयुक्त भावनाओं में पहले से संसाधित होती है प्रवाहित करने वाली मुख्य घमनियाँ हैं : दो अति विशाल टेलिग्राफ एजेन्सियाँ, एसोशिएटेड प्रेस, और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के उनके दैनिक सार संक्षेप समस्त अमरीकी प्रचार संगठनों के लिए मार्ग दर्शक का कार्य करते हैं।

संभवतः इस प्रकार के कार्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है द न्यूयार्क टाइम्स जो अपने सिण्डिकेट एवं अन्य प्रणालियों से अति महत्वपूर्ण विवरणों की दैनिक संक्षिप्तियाँ और अग्रिम पृष्ठ के लिए दिये गये लेखों की सूची प्रेषित करता है। रेडियो और टेलिविज़न में, यह भूमिका कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग सिस्टम अमेरिकन

ग्राहकास्तिग कम्पनी और नेशनल ग्राहकास्तिग कम्पनी द्वारा अदा की जाती है। इन समाचारपत्रों और रेडियो और टेलीविजन कम्पनियों का प्रभाव अमरीका के वास्तविक शासकों से उनकी घनिष्ठता द्वारा प्रदर्शित होता है। और तथ्य यह है कि वे पूरी स्पष्टता के साथ राज्य इजारेदारी सत्ता पर बैठे अभिजात वर्ग के हितों को प्रकट करते हैं।

पूँजीवादी विश्व के अन्य भागों में, यह भूमिका इसी प्रकार के पूँजीवादी प्रचार के स्तम्भों द्वारा जैसे सन्दन के टाइम्स पेरिस के ले मॉण्टे और पश्चिम जर्मनी में स्प्रिंगर के विशाल प्रेस सिण्डिकेट द्वारा अदा की जाती है।

ये सभी शक्तिशाली प्रचार ट्रस्ट उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं। प्रकट रूप में 'मुक्त', 'स्वतंत्र' 'गैर पार्टीजन' प्रेस के प्रतिनिधित्व का दिखावा करते हैं वे सदा सत्ताधारी वर्ग द्वारा दिये सामाजिक आदेशों को पूरा करते हैं और उसके हितों की रक्षा करते हैं। वस्तुतः कुछ तो घोर प्रतिक्रियावाद के पक्षपाती होते हैं, अपनी सरकार की आधिकारिक स्थिति से भी अधिक दक्षिणपन्थी।

सोवियत संघ और समाजवादी देशों के विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए विशेष रूप से निर्देशित संगठन की आमतौर से 'गैर सरकारी' सूचना केन्द्रों के आवरण के अन्तर्गत कार्य करते हैं। रेडियो स्टेशन 'लिवर्टी' और 'फ्री यूरोप' इसके उदाहरण हैं। जे० विलियम फुलब्राइट ने जो एक समय सीनेट की विदेश सम्बन्धों की समिति के अध्यक्ष रहे थे ज्ञात रूप में उसके क्रियाकलाप के विषय में लिखा था : "कई वर्षों तक 'फ्री यूरोप' और 'लिवर्टी' रेडियो के बारे में अमरीकी जनता को बताया जाता रहा कि ये निजी चन्दों पर आधारित निजी संगठन हैं और पूर्वी यूरोप की जनता के सम्बन्ध में 'सच्चाई' प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वास्तव में, ये दोनों प्रसारण केन्द्र सी० आई० ए० से लाखों डालर प्राप्त करते हैं...।"

निरन्तर पर्दाफाश होने के बाद इस बात से इन्कार करना कि रेडियो लिवर्टी और रेडियो फ्री यूरोप सी० आई० ए० के प्रत्यक्ष निर्देशन में काम करते हैं असम्भव हो गया। और इसका अर्थ था कि सोवियत संघ और यूरोप के समाजवादी देशों के विरुद्ध प्रचार उन्हीं संगठनों द्वारा निर्देशित था जिन्होंने क्यूबा के प्रधानमंत्री फिडेल कास्ट्रो और अरब गणतंत्रमिश्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर की हत्या के प्रयत्नों में भाग लिया था और कांगो की सरकार के प्रथम अध्यक्ष पैंट्रिक लुमुम्बा की हत्या में और चिली की वैद्य लोकप्रिय संयुक्त सरकार को, जिसके नेता सत्त्वाडोर अलेन्दे थे, उखाड़ने के कार्यों में भूमिका निभाही थी जब इनको अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सका, तो ये तथ्य सयोगवश अमरीकी कांग्रेस की कमेटी द्वारा सार्वजनिक रूप

से प्रकट कर दिये गये। इसके बाद शीत-युद्ध के प्रचार के इन विध्वंसक केन्द्रों के सम्बन्ध में मुश्किल से ही किसी गवाही की आवश्यकता रह जाती है।

साथ ही रेडियो लिबर्टी और रेडियो फ्री यूरोप के भण्डाफोड़ के क्रम में मनो-वैज्ञानिक युद्ध—गुप्तचरी और प्रचार के मुख्य स्रोत, सरकार और इजारेदारियों की अन्तःक्रियाएँ जग-जाहिर हो गयीं। इनके पीछे एक और चीज थी जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता था वह भी प्रकट हो गयी। वह थी कि सी. आई. ए. के अति रिक्त मुख्य अमरीकी कम्पनियाँ (जनरल मोटर्स, वॉल्टिंग हाउस, फ़ोर्ड और अन्य) भी जो हथियारों की दौड़ में और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में भारी रुचि रखती थीं इन गतिविधियों के पीछे थीं। कम्युनिज्म विरोध के स्पष्ट रूप से विध्वंसक केन्द्रों के लाञ्छनापूर्ण मामले स्पष्ट रूप से और आधिकारिक रूप से खुलकर सामने आ गये। समाजवाद के विरुद्ध विध्वंसक प्रचार संगठित करने में साम्राज्यवादी राज्य और इजारेदारियों के मध्य परस्पर साहचर्य की प्रणाली का भी भण्डाफोड़ हो गया।

कम्युनिज्म विरोध के 'ज्ञान केन्द्र' के रूप में 'सोवियत विद्या' के अनेक अनुसन्धान केन्द्रों के निर्देशन में राज्य-इजारेदारियों का साहचर्य कुछ अधिक रहस्य से आवृत है। केवल अमरीका में ही इस व्यवस्था के अन्तर्गत कई दर्जन बड़े विशिष्ट केन्द्र हैं (युद्ध, क्रान्ति और शान्ति का हूवर संस्थान, केलिफोर्निया, ग्लूयार्क में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में रूसी भाषा का संस्थान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रूसी अनुसन्धान केन्द्र, वाशिंगटन में 1976 में स्थापित जार्ज केनन इन्स्टीट्यूट और अन्य) और बहुत से विश्वविद्यालयों के विभाग और पाठ्य क्रम, कम्युनिस्ट विरोधी प्रकाशन गृह आदि। जैसाकि अमरीकी प्रोफ़ेसर हैस मौरेंग्यो ने स्पष्ट रूप से देखा था, अमरीका में, सैनिक औद्योगिक समुच्चय के अतिरिक्त, राजनीतिक समस्याओं पर अकादमिक समुच्चय भी है जो देश के बहुत से अनुसन्धान केन्द्रों पर अपने प्रभाव का विकास करते रहते हैं।

कम्युनिस्ट विरोधी हठधर्मी की 'सामाजिक व्यवस्था'

इस प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् और विशेष रूप से 1950, 1960 और 1970 के दशकों में साम्राज्यवादी देशों के शासक हल्कों ने समाजवाद और विश्व मुक्ति आन्दोलन द्वारा अर्जित नयी सफलताओं के समेद, अपनी शक्तिशाली प्रचार मशीनरी को पूर्ण बनाया। जनता की मस्तिष्क शुद्धि को इस जटिल व्यवस्था में अनेक प्रकार से पूँजीवादी व्यवस्था को न्यायोचित ठहराने वाली बहुत-सी इकाइयाँ समाविष्ट हैं।

यह व्यवस्था बड़ी विचित्र है। यह समाजवाद, कम्युनिस्ट आन्दोलन और जनवादी तापतों के विरुद्ध राजनीतिक कार्यों के लिए साधन जुटाती है। समाजवादी समाज की विचारधारा और नैतिकता का विरोध करने के उद्देश्य से 'जन संस्कृति'

का विज्ञापन करते हुए पूंजीवादी विश्व के जन प्रचार के विस्तृत क्षेत्रों में कार्य करती है। यह पूंजीवादी सिद्धान्तकारों की आकांक्षा को—जो जितनी पुरानी है उतनी ही निरर्थक भी—सामाजिक प्रक्रिया के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के सामाजिक-दार्शनिक विकल्प की खोज या फैशन को प्रतिबिम्बित करती है।

इसमें पूर्व कभी भी पूंजीपति वर्ग ने वैचारिक सुरक्षा की ओर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया था या इस मोर्चे का निर्देशन नहीं किया था। विदेश नीति के 'चतुर्थ क्षेत्र' पर इतने प्रयास नहीं किये थे जितना हमारे समय में किये जा रहे हैं। यह सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच, दो सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच, पूंजीवाद के आम संकट की तीसरी मंजिल की स्थितियाँ जब परिपक्व हो रही हैं, ऐतिहासिक संघर्ष में वर्तमान दौर के कुछ अति महत्वपूर्ण रूपों को प्रतिबिम्बित करता है। यह मंजिल किसी विश्व युद्ध के सम्बन्ध में आरम्भ नहीं हुई जैसा कि पूर्व-वर्ती दो मंजिलों में हुआ था बल्कि शान्ति की स्थितियों में (अर्थात् एक ठोस ऐतिहासिक परिस्थिति में जिसमें कि साम्राज्यवाद अपने अन्तर्विरोधों को सुलझाने के लिए नये विश्व युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता) और यह तीनों में सर्वाधिक गहन और व्यापक रूप में विकसित हो रही है।

साम्राज्यवाद विश्व के विकास में समाजवाद को निर्णायक शक्ति बनने से रोक नहीं सकता। यह औपनिवेशिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न होने से नहीं रोक सकता और आर्थिक एवं पूंजीवादी देशों में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ने से नहीं रोक सकता।

साम्राज्यवाद सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों के शान्ति-अभियान को विफल करने में असमर्थ है। समग्र विश्व राजनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह अभियान अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करेगा और विश्व के क्षेत्र में वर्ग-संघर्ष के विकास की शब्दावली में मेहनतकश जनता के जनवादी और भुवितकामी लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। आणविक गतिरोध के उदय से, जिसने कि नये विश्व-युद्ध को निरी मूर्खता सिद्ध कर दिया, इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को और अधिक कम करके आँका।

इन परिवर्तनों ने साम्राज्यवाद को कम्युनिज्म के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष की अपनी रणनीति को सुधारने के लिए विवश किया। मार्क्सवाद के उदय ने पूंजीवादी विचारधारा की वैज्ञानिक आधारहीनता प्रकट कर दी; अतः क्रान्ति की विजय और समाजवादी सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण ने पूंजीवाद की ऐतिहासिक पहलकदमी को पस्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत जनता और विश्व की जनता की शक्तियों की विजय ने, फ्रांसिज्म के उन्मूलन और इसकी नैतिक एवं राजनीतिक पराजय ने, और तत्पश्चात् समाजवाद के पक्ष में विश्व शक्तियों के समतुलन में परिवर्तन ने, साम्राज्यवाद को फिर एक बार

अपनी वैचारिक सुरक्षा की समग्र व्यवस्था को वस्तुतः पुनः सज्जित करने के लिए बाध्य कर दिया।

कुल मिलाकर, इस पुनर्गठन में भी साम्राज्यवाद की रणनीति में समाजवादी सोवियत संघ और समाजवादी समुदाय के सम्बन्ध में अनुशासी परिवर्तन प्रति-विम्बित हुए और यह मुठभेड़ के युग से दातचीत के युग में संक्रमित हो गयी।

यह संक्रमण वेदनाहीन या अन्तर्विरोधों से रहित नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे कि साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद वर्षों तक अक्तूबर क्रांति के पश्चात् विश्व में मूर्त हो रही नयी स्थिति के साथ अपना सामजस्य बैठाने को तैयार नहीं हुआ था और उसने हठपूर्वक सोवियत राज्य का बहिष्कार किया था, इसी प्रकार अब द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी पराजय से उचित निष्कर्ष निकालने से कतरा रहा था। वर्ष-पर-वर्ष बीतते गये और समाजवाद की शक्ति में वृद्धि के अकाट्य प्रमाण पूँजीवादी विश्व के शासक वर्ग के समक्ष प्रकाशित होते गये और अन्ततः उसने हो रहे अपरिवर्त्य परिवर्तन को स्वीकारा, लेकिन ऐसा होने से पूर्व एक निरन्तर और लम्बी छोज ऐसी वैचारिक धारणाओं की चलती रही जो शीतयुद्ध की बर्त में— 'अवरोधार्थक युद्ध' (1945-1948) 'निरोध' या कम्युनिज्म 'पीछे धकेलने' का, (1975 से आरम्भ) 'सीमित युद्ध' (1957-1960) सैनिक रणनीति के सिद्धांतों की शृंखला के रूप में उत्पन्न हुई थी।

वर्तमान में कार्यरत साम्राज्यवाद की वैचारिक प्रचार की व्यवस्था शीत युद्ध के समय उत्पन्न हुई है। निरन्तर इसकी स्मृतियाँ आती रहती हैं क्योंकि यह दो दुनियाओं के बीच तीव्र टकराव के विपाकत वातावरण में तैयार की गयी थी, इसकी सांगठनिक संरचना, कार्यविधि और वैचारिक अवधारणाएँ 'शीत' विचारों की भावना से परिपूर्ण हैं।

इसी के साथ-साथ, कम्युनिज्म विरोध के दावपेंचों को चाहे जितना सुधारा गया हो तथापि इसकी वैचारिक प्रस्थापनाओं का सारतत्त्व अपरिवर्तित ही रहा। आजकल जनता का दिमाग साफ करने के तरीके और साधन अत्यन्त भिन्न प्रकार के हैं; सावधानी के साथ तैयार किये गये वैचारिक अभियान एक दिन की समसनी-सेज घटनाओं से मिला दिये जाते हैं, तथ्यपूर्ण सूचना विघ्रान्त चालवायुधियों से और प्रत्यक्ष गलत सूचनाओं से बदल दी जाती है। वैचारिक प्रचार विविध प्रकार के रूपों में किया जाता है: मिथ्या वैज्ञानिक कृतियों में लेकर हलकी-फुलकी चित्र कथाओं तक, विश्वविद्यालय के भाषणों से सस्ती विज्ञापनबाजी तक, पार्श्व मंच से जागूसी उपन्यासों तक।

लेकिन प्रवृत्तियों के रूपों और पद्धतियों की इन सब भिन्नताओं के साथ कम्युनिज्म विरोध की विचारधारा और राजनीति तथा इसका सोवियत-विरोध का सारतत्त्व एक सामाजिक व्यवस्था को भरने के लिए और समाजवाद की उन्नति

को रोकने के लिए और समय की क्रांतिकारी शक्तियों के सप्रवाह को एक विषव-धारा में परिवर्तित होने से रोकने के लिए—उनके राजनीतिक क्रियाकलाप को कम करने के लिए और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को निष्प्राण करने के लिए तैयार की गयी थी।

पूँजीवादी देशों में सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के क्षेत्रों में, समाजवादी देशों में, साम्राज्यवाद की प्रचार सेवाएँ प्रत्येक सुलभ साधन से निराशावाद की भावनाओं के बीज बोने, सामाजिक प्रगति की संभावनाओं में विश्वास को समाप्त करने और अविश्वास पैदा करने, मेहनतकश वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति को सामाजिक, राष्ट्रवादी, नस्लवादी, उपभोक्ता और अन्य पूर्वाग्रहों की संकीर्ण दुनिया में सीमित करने का प्रयास करता है।

पश्चिमी देशों में, सामान्य जनता में, घटनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की समझ, एक वैचारिक प्रतिबाधित प्रतिच्छाया, घिसी-पिटी मानसिकता विकसित करने की ओर ध्यान देना विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है जिससे कि लोगों को कम्युनिज्म से बचाया जा सके। निरन्तरतापूर्वक, दिन-प्रतिदिन प्रेस, रेडियो, टी० वी०, सिनेमा और तथाकथित जन-संस्कृति के समस्त साधनों से सामान्य व्यक्ति पर यह प्रभाव डाला जाता है कि : कम्युनिज्म हर प्रकार की बुराई का संपिंडित रूप है। इसकी 'ईश्वरविहीन' 'सर्वाधिपत्यवादी' विचारधारा मानव प्रकृति के विरुद्ध है। कम्युनिस्ट कथित रूप से लोगों को उनकी सम्पत्ति से वंचित करना चाहते हैं, स्वतंत्रताओं और अधिकारों को अपनी 'आक्रामक' योजनाओं के साधन के रूप में बदलना चाहते हैं। वे फूट के बीज बोते हैं और असन्तोष की आग भड़काते हैं। यदि कम्युनिज्म ने कुछ परिणाम आर्थिक और राजनीतिक विकास में दिखाये भी हैं, वह जनता के जीवन-स्तर की कीमत पर पैदा किये गये हैं। नये कार्य-भार जो मानव समाज के समक्ष उत्पादन के विकास के, विज्ञान और प्रविधि के विकास के आधुनिक स्तर पर हैं उनका समाजवाद से कोई सामंजस्य नहीं है इसलिए जल्दी या देर से कम्युनिस्ट अपने मतान्धतापूर्ण सिद्धान्तों को त्यागने के लिए विवश हो जायेंगे।

'मुक्त' निजी उद्यमों की दुनिया ही सम्मानित रूप से 'समस्त अवसरों' का समाज है। इसकी आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थान अधिकतम व्यावसायिक क्रियाकलाप की, जनतंत्र की, वैयक्तिक पहलकदमी और अन्तिम विक्षेपण में—व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारण्टी है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्भावित रूप से सफलता का अवसर प्राप्त होता है (जैसे कि गरीब एलिस की कहानी में कला-मर्मज्ञ नायिका अपने परिश्रम से मितव्ययता के कारण राजकुमारी बन गयी)। वे कहते हैं कि हर चीज स्वयं आप पर निर्भर है। और यदि आप अब तक लखपति नहीं बने तो यह केवल आपका अपना दोष है। आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति ने

अपनी वैचारिक सुरक्षा की समग्र व्यवस्था को वस्तुतः पुनः सज्जित करने के लिए बाध्य कर दिया।

कुल मिलाकर, इस पुनर्गठन में भी साम्राज्यवाद की रणनीति में समाजवादी सोवियत सघ और समाजवादी समुदाय के सम्बन्ध में अनुगामी परिवर्तन प्रति-विम्बित हुए और यह मुठभेड़ के युग से बातचीत के युग में संक्रमित हो गयी।

यह संक्रमण वेदनाहीन या अन्तर्विरोधों से रहित नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे कि साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद वर्षों तक अक्तूबर क्रान्ति के पश्चात् विश्व में मूर्त हो रही नमी स्थिति के साथ अपना सामंजस्य बैठाने को तैयार नहीं हुआ था और उसने हठपूर्वक सोवियत राज्य का बहिष्कार किया था, इसी प्रकार अब द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी पराजय से उचित निष्कर्ष निकालने से कतरा रहा था। वर्ष-पर-वर्ष बीतते गये और समाजवाद की शक्ति में वृद्धि के अकाट्य प्रमाण पूर्णवादी विश्व के शासक वर्ग के समक्ष प्रकाशित होते गये और अन्ततः उसने हो रहे अपरिवर्त्य परिवर्तन को स्वीकारा, लेकिन ऐसा होने से पूर्व एक निरन्तर और लम्बी खोज ऐसी वैचारिक धारणाओं की चलती रही जो शीतयुद्ध की बर्तमान में— 'अवरोधात्मक युद्ध' (1945-1948) 'निरोध' या कम्युनिज्म 'पीछे धकेलने' का, (1975 से आरम्भ) 'सीमित युद्ध' (1957-1960) सैनिक रणनीति के सिद्धांतों की शृंखला के रूप में उत्पन्न हुई थी।

वर्तमान में कार्यरत साम्राज्यवाद की वैचारिक प्रचार की व्यवस्था शीत युद्ध के समय उत्पन्न हुई है। निरन्तर इसकी स्मृतियाँ आती रहती हैं क्योंकि यह दो दुनियाओं के बीच तीक्ष्ण टकराव के विषाक्त वातावरण में तैयार की गयी थी, इसकी सांगठनिक संरचना, कार्यविधि और वैचारिक अवधारणाएँ 'शीत' विचारों की भावना से परिपूर्ण हैं।

इसी के साथ-साथ, कम्युनिज्म विरोध के दावपेचों को चाहे जितना सुधारा गया हो तथापि इसकी वैचारिक प्रस्थापनाओं का सारस्त्व अपरिवर्तित ही रहा। आजकल जनता का दिमाग साफ करने के तरीके और साधन अत्यन्त भिन्न प्रकार के हैं : सावधानी के साथ तैयार किये गये वैचारिक अभियान एक दिन की सनसनी-खेज घटनाओं से मिला दिये जाते हैं, तथ्यपूर्ण सूचना विभ्रान्त चालवाजियों से और प्रत्यक्ष गलत सूचनाओं से बदल दी जाती है। वैचारिक प्रचार विविध प्रकार के रूपों में किया जाता है : मिथ्या वैज्ञानिक कृतियों से लेकर हलकी-फुलकी चित्र कथाओं तक, विश्वविद्यालय के भाषणों से सस्ती विज्ञापनवाजी तक, पार्श्व मंच से जासूसी उपन्यासों तक।

लेकिन प्रवृत्तियों के रूपों और पद्धतियों की इन सब भिन्नताओं के साथ कम्युनिज्म विरोध की विचारधारा और रणनीति तथा इसका सोवियत-विरोध का सारस्त्व एक सामाजिक व्यवस्था को भरने के लिए और समाजवाद की उन्नति

‘स्वतंत्र विद्वत्’ के लिए सुभावनी सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं जिन्हें लेकर बिना किसी वर्ग-संघर्ष के, सब स्वयं को जन-उपभोग और सार्वभौम समृद्धि के आश्चर्यप्रद युग में पा सकते हैं।

—मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, वर्ग-संघर्ष, इजारेदारियों का आधिपत्य—ये सब निस्सन्देह कम्युनिस्टों की कूट रचनाएँ हैं। यदि अतीत में इन अघोर घटनाओं के लिए कोई आधार था, वह अधिक समय तक नहीं रहा। अन्ततः, पूँजीपति भी आज एक थमिक (कामगार) है (!), और कोई मजदूर जो स्टॉक खरीदता है, उद्यमी है। ‘गोरे लोग’ हर जगह अनि-वार्यतया ‘काले लोगों’ का स्थान ले लेंगे। वर्ग समाप्त हो रहे हैं, सामान्य-तया वर्ग-संघर्ष निरर्थक और हानिकारक है क्योंकि यह औद्योगिक समाज की समृद्धि की ओर स्वयं भू-गति के मार्ग में केवल बाधा डालता है;

—आधुनिक विश्व की सब बुराइयाँ और इसके भविष्य के ख़तरे या तो कम्युनिस्टों के भ्रष्ट पड़्यों से अथवा मानव प्रकृति की अपूर्णताओं जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण और इसके अंधकारपूर्ण संस्कारों की तर्क-हीनता के कारण होते हैं। इसी प्रकार ये जनसंख्या विस्फोट के, अत्यधिक शहरीकरण के, पर्यावरणिक प्रदूषण के और दुर्भाग्यों के परिणाम हैं जो अकस्मात् मानव-समाज पर आ पड़ते हैं। निस्सन्देह, इनके लिए पूँजीवाद उत्तरदायी नहीं है और फिर इन विपदाओं पर विजय पाने के लिए हमें वर्ग-संघर्ष को भूल जाना चाहिए और इन सार्वभौम समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

ये और इसी प्रकार के विचार प्रचारित करने के अपने प्रयासों में साम्राज्य-वाद के सिद्धान्तकार एक ओर तो जनता पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। वे सामान्यतया लोगों की तर्क-बुद्धि को सम्बो-धित नहीं करते बल्कि वे उसकी भावनाओं को और पूँजीवादी समाज को परम्परागत जीवन-पद्धति से उत्पन्न आदतों को या जब यह समाजवादी देशों की ओर आते हैं, लोगों की मनो में अतीत के अवशेषों को आधार बनाते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक पूँजीवाद के सिद्धान्तकार कम्युनिज्म का विरोध करने के लिए सैद्धांतिक युक्तियाँ देने का प्रयास करते हैं जिससे पूँजीपति वर्ग की स्थितियों से जीवन में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे सकें। लेकिन जीवन स्वयं इन सब प्रयासों की निरर्थकता दिखा देता है।

मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन

नये वैचारिक मिथकों की खोज

जब साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद समाजवाद के दुर्ग को आक्रमण द्वारा नहीं ले सका और विश्व की क्रान्तिकारी प्रक्रिया को पीछे नहीं धकेल सका तो इसने समाजवादी देशों की सुदीर्घ घेराबन्दी की तरफ पाँव बढ़ाये और किसी उपयुक्त कोण से उसे घेरने के प्रयास आरम्भ किये। उसका उद्देश्य उन्हें सोवियत संघ से अलग फोड़ देना और मुक्ति आंदोलनों की पाँतों में घुसपैठ करके भीतर से तोड़ देना था।

राजनीतिक रूप से, इसकी अभिव्यक्ति 'सेतुबध' की कार्य नीतियों के रूप में हुई। इसके पीछे समाजवादी देशों में नयी समाज संरचना के उद्भव और विकास की जटिल प्रक्रिया से उत्पन्न कुछ कठिनाइयों का लाभ उठाने का दृष्टिकोण था।

बौद्धिक क्षेत्र में, कम्युनिस्ट विरोधियों के प्रयासों ने वैचारिक संघर्ष के वर्गीय सार को धुँधला करने के लिए इस राजनयिक नीति को पूरा किया गया। वे वस्तुओं को इस प्रकार चित्रित करते थे कि यह दिखायी दे कि समाजवादी देशों में वैचारिक जिज्ञासा उनके सर्वसत्तावादी अलोकतांत्रिक शासन के अधीन है जबकि उसके विपरीत पूँजीवादी समाज की वस्तुपरकता 'वैचारिक अंधविश्वास' से मुक्त है। और उसने समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

काफी समय पहले, अक्टूबर क्रान्ति के आरंभ में, लेनिन ने लिखा था : समाजवाद के समस्त मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध खुला, सिद्धान्तपरक और सीधा संघर्ष करने के स्थान पर यूरोप और अमरीका के पूँजीपति और उनके प्रतिनिधि सिद्धान्तकार और राजनीतिक नेता निजी संपत्ति की पूर्ण अनुल्लंघनीयता की और प्रतियोगिता की स्वतंत्रता की रक्षा में, अधिकाधिक आगे आते गये समाजवादी क्रान्ति के विचार का विरोध करने के लिए तथाकथित सामाजिक

‘स्यतंत्र विद्व’ के लिए सुभावनी सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं जिन्हें लेकर बिना किसी वर्ग-संघर्ष के, सब स्वयं को जन-उपभोग और सार्वभौम समृद्धि के आश्चर्यप्रद युग में पा सकते हैं।

—मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, वर्ग-संघर्ष, इजारेदारियों का आधिपत्य— ये सब निस्सन्देह कम्युनिस्टों की कूट रचनाएँ हैं। यदि अतीत में इन अवधारणाओं के लिए कोई आधार था, वह अधिक समय तक नहीं रहा। अन्ततः, पूँजीपति भी आज एक थमिक (कामगार) है (!), और कोई भजदूर जो स्टॉक खरीदता है, उद्यमी है। ‘गोरे लोग’ हर जगह अनिवार्यतया ‘काले लोगों’ का स्थान ले लेंगे। वर्ग समाप्त हो रहे हैं, सामाज्य-तया वर्ग-संघर्ष निरर्थक और हानिकारक है क्योंकि यह औद्योगिक समाज की समृद्धि की ओर स्वयं भू-गति के मार्ग में केवल बाधा डालता है;

—आधुनिक विश्व की सब बुराइयाँ और इसके भविष्य के खतरे या तो कम्युनिस्टों के दृष्ट पड़्यों से अथवा मानव प्रकृति की अपूर्णताओं जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण और इसके अंधकारपूर्ण संस्कारों की तर्कहीनता के कारण होते हैं। इसी प्रकार ये जनसंख्या विस्फोट के, अत्यधिक शहरीकरण के, पर्यावरणिक प्रदूषण के और दुर्भाग्यों के परिणाम हैं जो अकस्मात् मानव-समाज पर आ पड़ते हैं। निस्सन्देह, इनके लिए पूँजीवाद उत्तरदायी नहीं है और फिर इन विपदाओं पर विजय पाने के लिए हमें वर्ग-संघर्ष को भूल जाना चाहिए और इन सार्वभौम समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

ये और इसी प्रकार के विचार प्रचारित करने के अपने प्रयासों में साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार एक ओर तो जनता पर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। वे सामान्यतया लोगों की तर्क-बुद्धि को सम्बोधित नहीं करते बल्कि वे उसकी भावनाओं को और पूँजीवादी ममाल की परम्परागत जीवन-पद्धति से उत्पन्न आदतों को या जब यह समाजवादी देशों की ओर आते हैं, लोगों की मनो में अतीत के अवशेषों को आधार बनाते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक पूँजीवाद के सिद्धान्तकार कम्युनिज्म का विरोध करने के लिए सिद्धांतिक युक्तियाँ देने का प्रयास करते हैं जिससे पूँजीपति वर्ग की स्थितियों से जीवन में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे सकें। लेकिन जीवन स्वयं इन सब प्रयासों की निरर्थकता दिखा देता है।

मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन

नये वैचारिक मिथकों की खोज

जब साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद समाजवाद के दुर्ग को आक्रमण द्वारा नहीं ले सका और विश्व की क्रान्तिकारी प्रक्रिया को पीछे नहीं धकेल सका तो इसने समाजवादी देशों की सुदीर्घ घेराबन्दी की तरफ पांव बढ़ाये और किसी उपयुक्त कोण से उसे घेरने के प्रयास आरम्भ किये। उसका उद्देश्य उन्हें सोवियत सघ से अलग फोड़ देना और भुवि आदोलनो की पांती में घुसपैठ करके भीतर से तोड़ देना था।

राजनीतिक रूप से, इसकी अभिव्यक्ति 'सेतुबध' की कार्य नीतियों के रूप में हुई। इसके पीछे समाजवादी देशों में नयी समाज सरचना के उद्भव और विकास की जटिल प्रक्रिया से उत्पन्न कुछ कठिनाइयों का लाभ उठाने का दृष्टिकोण था।

बौद्धिक क्षेत्र में, कम्युनिस्ट विरोधियों के प्रयासों ने वैचारिक संघर्ष के वर्गीय सार को धुंधला करने के लिए इस राजनयिक नीति को पूरा किया गया। वे वस्तुओं को इस प्रकार चित्रित करते थे कि यह दिखायी दे कि समाजवादी देशों में वैचारिक जिज्ञासा उनके सर्वसत्तावादी अलोकतांत्रिक शासन के अधीन है जबकि उसके विपरीत पूँजीवादी समाज की वस्तुपरकता 'वैचारिक अंधविश्वास' से मुक्त है। और उसने समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

काफी समय पहले, अक्टूबर क्रान्ति के आरंभ में, लेनिन ने लिखा था : समाजवाद के समस्त मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध खुला, सिद्धान्तपरक और सीधा संघर्ष करने के स्थान पर यूरोप और अमरीका के पूँजीपति और उनके प्रतिनिधि सिद्धान्तकार और राजनीतिक नेता निजी संपत्ति की पूर्ण अनुत्लंघनीयता की और प्रतियोगिता की स्वतंत्रता की रक्षा में, अधिकाधिक आगे आते गये समाजवादी क्रान्ति के विचार का विरोध करने के लिए तथ्यांकित सामाजिक

सुधारों की रक्षा में। उदारवाद बनाम समाजवाद नहीं, बल्कि मुधारवाद बनाम समाजवादी क्रांति यह है फार्मूला आधुनिक, 'अग्रगामी' शिक्षित पूंजीपति वर्ग का।¹

1960 और 1970 के दशकों में इस निष्कर्ष की पुष्टि हो गयी, सर्वोपरि 'विसिद्धान्तीकरण' के सिद्धान्त के रूप में, अथवा विचारधारा की समाप्ति के रूप में। इस सिद्धान्त के, जिसकी जड़ें पीछे पूंजीपतियों के यथार्थवाद में गह्वरती हैं, अब अनेक रूप हैं।

यथार्थसंभव अधिक-से-अधिक जनता को प्रभावित करने के लिए साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार आवादी की विभिन्न श्रेणियों में अपील करने के लिए विभिन्न धारणाओं का उपयोग करते हैं। कुछ निम्न पूंजीपति वर्ग को लक्ष्य करके जो कुल मिलाकर इजारेदारी विरोधी स्थितियाँ ग्रहण किये होते हैं, प्रतिक्रियावादी भ्रमों का उपयोग करते हैं स्वतंत्र प्रतियोगिता दिनों के सौटने की संभावना के विषय में। दूसरों का लक्ष्य होता है शिक्षित अकादमीशियन, और विद्यार्थी समुदाय जो वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति द्वारा सक्रिय सार्वजनिक जीवन से खींच लिये गये हैं और वस्तुगत रूप से इजारेदारी पूंजी का विरोध करते हैं लेकिन अभी तक साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष में अपना स्थान नहीं बना पाये हैं, और कुछ गुटों को मिला करके भी जो मजदूर वर्ग के अन्दर हैं जो अभी तक अवसरवादी भ्रमों से विषाक्त हैं। कुछ विभिन्न लोग हैं विशेष रूप से नव स्वाधीन देशों की ओर निर्देशित, जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व को नकारते हैं लेकिन सदा यह नहीं पहचान पाते कि कौन उनके मित्र हैं कौन शत्रु, उनके स्थायी गुणों की ओर ध्यान दिया जाता है—समाजवादी देशों के भीतर जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विरोध की ओर झुकाव रखते हैं।

इस परस्पर विरोधी शक्तियों को दिशा परिवर्तन के लिए उनको, मार्क्सवाद लेनिनवाद से अलग करने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद से उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए साम्राज्यवाद हर तरह के कम्युनिस्ट विरोधी—दक्षिणपन्थी अवसरवादी से उग्र धार्मिक आंदोलन का उपयोग करता है तथा मजदूर वर्ग की विचारधारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद का विरोध करने वाली किसी भी धारणा का उपयोग करता है। सबसे बढ़कर, प्रतिक्रियावादी सभी धाराओं के मुक्ति आंदोलनों में संयुक्त होने से डरते हैं। इस प्रकार वे इस आंदोलन के विभिन्न सभाओं के पिछड़ेपन, कमजोरी और विसंगतियों को कायम रखने का हर समय प्रयास करते हैं।

1. यो० आई० लेनिन, रूसी सामाजिक जनवादी आंदोलन में सुधारवाद, संकलित रचनाएं भाग 17 पृ० 229

प्रतिगामी साम्राज्यवाद समाजवादी देशों के विरुद्ध अपने संघर्ष में उन कतिपय अल्पसंख्यक दलों पर निर्भर रहता है जिनकी सामाजिक चेतना उनके सामाजिक जीवन से अत्यधिक पिछड़ी होती है। तथा वह पूंजीवाद के उत्तराधिकार के रूप में छोड़े गये राष्ट्रवादी अवशेषों का उपयोग करता है। वह उन विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की भिन्नताओं का लाभ उठाने की कोशिश करता है जिन्होंने समाजवादी मार्ग को स्वीकार किया है, राष्ट्रवाद को उभारने का व इस प्रकार सर्व-हारा अन्तर्राष्ट्रवाद सिद्धान्तों और समाजवादी समुदाय की एकता के सम्बन्ध में पूर्वाग्रह उत्पन्न करने का प्रयास करता है।

पूंजीवादी सिद्धान्तकार विकसित पूंजीवादी देशों में 1960 के दशक में हुए आर्थिक विकास का और पूंजीवाद की सामाजिक संरचना से वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति से सम्बद्ध नयी घटना का, राज्य एकाधिकारिता की प्रवृत्तियों के विस्तार का और पूंजीवादी उत्पादन तथा पूंजीवादी बाजार की एकता का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह प्रचारित करना होता है कि पूंजीवादी समाज बदल चुका है, उसने अपने सामाजिक वैर-भावों पर काबू पा लिया है, तथा वर्ग-संघर्ष और मजदूर-आन्दोलन अपनी मौत मर चुके हैं। साम्राज्यवाद के देवदूत जनता के जनतांत्रिक आंदोलनों की मिश्रित वर्ग संरचना को जानते हैं, जो स्वतः ही निम्न पूंजीवादी लोगों को आकर्षित करता है (सिद्धान्तहीन समझौतों की ओर उनकी प्रवृत्ति या वामपंथी उग्रवादी दुस्साहसिकता की ओर उनकी प्रवृत्तियों सहित) जिससे कि मजदूर वर्ग की हराबल दलों की भूमिका को कमजोर किया जा सके।

राष्ट्रीय भुक्ति-आन्दोलन को ध्वस्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की अस्थिरता का, स्थानीय आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के मार्ग में आनेवाली विभिन्न बाधाओं का जातीय एवं जनजातीय पूर्वाग्रहों का, नये स्वाधीन राज्यों की पूंजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था पर निर्भरता का और पुराने महानगरों वाले देशों के साथ उनके आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों का लाभ उठाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि राष्ट्रीय भुक्ति संघर्ष की प्रक्रिया जहाँ कहीं ऐतिहासिक अनिवार्यता के कारण साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप ले रही हो, उसे रोका जाय।

साम्राज्यवादी देशों में, 1950 के दशक के मध्य एवं 1960 के दशक के पूर्वार्ध से आर्थिक विकास एवं वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के क्षेत्रों में राज्यीय प्रोत्साहन, इतनी बड़ी मात्रा में देखा गया जितना कि पूंजीवादी समाज में पहले कभी नहीं देखा गया था। इन उपायों में आधुनिक पूंजीवाद की अपने को नयी विश्व-स्थिति के अनुकूल बनाने की, समाजवाद की चुनौती का सामना करने की और साथ-ही-साथ पूंजीवादी देशों में आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल को रोकने की

इच्छा प्रतिबिम्बित थी। निस्सदेह, मिलते-जुलते वैचारिक समर्थन ने इस लाइन की पुष्टि कर दी।

संभवतः इस तथ्य को उद्धृत करके कि साम्राज्यवाद ने वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति की सहायता से कुछ समय के लिए सामाजिक उत्पादन की कुशलता को उठाने की व्यवस्था कर ली, किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। तथापि, पूंजीवादी सिद्धांतवेत्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद एक नये समाज के रूप में रूपान्तरित हो गया है जो अपने अन्तर्विरोधों को बिना संघर्षों के और शुद्ध व्यावहारिक रूप से सुलझाना सीख चुका है। इसी आधार पर उन्होंने मार्क्सवादी 'मताग्रहों' को धो डालने के लिए शीघ्रता की।

इसी उद्देश्य से विसिद्धान्तीकरण (सिद्धान्तविहीनता) की अवधारणा सामने लायी गयी। 1960 में पूंजीवादी प्रचार द्वारा क्रांशन के रूप में चल रहे अन्य सिद्धान्तों के साथ धनिष्ठ रूप में संयुक्त करके इसका उपयोग किया जाता था। वे थे 'औद्योगिक समाज' और दो प्रणालियों की 'समरूपता' के सिद्धान्त। वे सब एक ही भूमि से उत्पन्न होते हैं और एक वृक्ष की शाखाओं की तरह परस्पर जुड़े रहते हैं। एक ही काम करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है—राज्य इजारेदारी पूंजीवाद की जीवन्तता प्रमाणित करने और उसकी रक्षा करने के लिए वे कभी एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं और एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं।

दूसरी सिद्धान्तिक संरचनाओं के लिए 'दार्शनिक आधार' होने का दावा करने वाले 'विसिद्धान्तीकरण' या 'विचारधारा की समाप्ति' का सिद्धान्त केवल सिद्धान्तिक अवधारणा ही नहीं अपितु पूंजीवादी चिन्तन की प्रणाली है। इसे वास्तविकता के मार्क्सवादी-लेनिनवादी वर्ग विश्लेषण के मुकाबले घटनाओं एवं विकास के मूल्यांकन के लिए वर्गविहीन (विसिद्धान्तीकृत) दृष्टिकोण के रूप में तैयार किया गया है।

यह सामान्य प्रवृत्ति पूंजीवादी और सामाजिक सुधारवादी प्रचार के रूपों और पद्धतियों के व्यापक कार्यक्रम में प्रसारित की गयी जिसमें सामाजिक जीवन के विसिद्धान्तीकरण की धारणा भी रूप से सम्मिलित थी।

साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार यह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे-जैसे आधुनिक विश्व वैज्ञानिक प्राविधिक क्रांति के ढाँचे में औद्योगिक रूप में विकसित होता है, विचारधारा विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों के अन्तिम सामाजिक आदर्शों को निर्धारित करने वाले विचारों की प्रणाली के उनके विश्व दृष्टिकोण और राजनीतिक क्रिया-कलाप के रूप में अपनी भूमिका खोती जाती है और अन्ततः विलुप्त होती जाती है।

वृद्धा व्यवहारवादी अपरिपक्व समुदायों के वैचारिक आवेगों के संघर्ष को छोड़ देते हैं जिसके बारे में वे कहते हैं कि अपने आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक

अधुरेपन के कारण वे 'कानूनी तरीके से समय-समय पर उभरने वाले विवादों को सुलझाने में असफल रहते हैं। लेकिन यह तर्क यही नहीं रखता, और आगे जाता है। औद्योगिक देशों में वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता एक स्थाई सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे के कारण स्वयं लुप्त हो जाती है। वे तात्कालिक समस्याओं का सामान्य 'जनतांत्रिक' तरीके से समाधान कर सकते हैं। यहाँ व्यावहारिक अनुभव सिद्धान्तिक मतवाद का स्थान ले लेता है। ऐच्छिक क्रिया-कलाप का स्थान विज्ञान पर आधारित जिज्ञासा ले लेती है। सिद्धान्तकार की अपेक्षा प्रबन्धक मुख्य व्यक्ति बन जाता है और सिद्धान्त स्वयं व्यवहार को मार्ग दे देता है।

सामाजिक जीवन की घटनाओं के प्रति यह रवैया इजारेदार पूँजी के सिद्धान्तकारों के लिए अत्यधिक आकर्षक होता है। उनकी दृष्टि में सिद्धान्तहीनता के सिद्धान्त में कुछ इस प्रकार के लाभ विद्यमान रहते हैं जिसके अन्तर्गत सर्वग्राही कम्युनिस्ट विरोधी धारणाएँ आ जाती हैं। राजनीतिक कार्यनीति में किसी भी परिवर्तन के लिए और कम्युनिस्ट विरोधी कार्यनीति में सुधारों के लिए यह रास्ता साफ कर देती है। पूर्वाग्रह जो उतने ही पुराने हैं जितना कि स्वयं पूँजीवादी समाज, कहना चाहिए कि राष्ट्रवाद से लेकर आज तक की विविधताओं जैसे कि 'सेतु निर्माण' आदि का उपयोग किया जाता है। मेहनतकश जनता के सघर्षों की वर्गीय व्याख्या के मुकाबले किसी को भी उचित ठहराने और भ्रमण लगाने के उद्देश्य से सिद्धान्तहीनता का निर्माण किया गया है।

'स्वतंत्र विश्व' के घोषित सिद्धांत के रूप में विसिद्धान्तिकरण साम्राज्यवाद के सिद्धांतकारों की समस्त कम्युनिस्ट विरोधी अस्त्रागार का उपयोग करने की आकांक्षा का मूलरूप है, साथ ही पूँजीवाद के आध्यात्मिक संकट के निर्विवाद गहराते जाने का भी। क्योंकि वह इसी संकट से उत्पन्न होता है, विसिद्धान्तिकीकरण स्वभावतः अपने अनिवार्य लक्षणों को प्रदर्शित करता है, सर्वोपरि पूँजीवादी विचार और आधुनिक युग की वास्तविकताओं के बीच विद्यमान खाई को दिखाता है।

विचारधारा का अस्तित्व है, भले ही उसे कोई स्वीकार करे या न करे। विचारधारा का विरोध पूँजीवाद के मर्मकों की केवल आत्मगत आकांक्षा है जिससे कि जनता पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रभाव के साथ भीतरघात कर सकें। विसिद्धान्तिकरण की सहर का लक्ष्य था मार्क्सवाद लेनिनवाद का उन्मूलन और साथ-ही-साथ पूँजीवादी प्रणाली की रक्षा।

आज पूँजीवादी जगत में प्रत्येक संकेत ऐसा मिलता है कि जनता को सिद्धान्त-शून्य बनाने की शासक वर्ग की इच्छा का परिणाम यह हो रहा है कि उसे फिर से विचारधारा दी जा रही है अर्थात् अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उसकी विचारधारा को फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि नित नयी वैचारिक धारणाओं का गहराई से विस्तार किया जा रहा है और जनता के दिमागों

मे उनको बैठाया जा रहा है, तथा प्रचार की सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य मे अधिकाधिक चल रहे वैचारिक संघर्ष की दृष्टि से आधुनिक किया जा रहा है।

लेकिन पश्चिमी देशों मे सिद्धान्तशून्यता की धारणाओं को उठाकर ताक मे नहीं रख दिया गया है और वे समाजवादी देशों के विरुद्ध अपने प्रचार में व्यापक रूप से सलग्न हैं।

वर्तमान स्थितियों मे सिद्धान्तशून्यता वस्तुतः पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष की अपनी कार्य मीति को सुधारने का ही एक प्रयास है। विचारधारा को अस्वीकार करना और फिर नयी विचारधारा को स्थापित करना परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ नहीं हैं; वे कम्युनिस्ट विचारों के खिलाफ संघर्ष में केवल भिन्न-भिन्न पद्धतियों के रूप मे प्रयुक्त किये गये हैं।

पश्चात्य सिद्धान्तकारों के प्रयत्नों का एक विशिष्ट उदाहरण है 'मानव अधिकारों की रक्षा' के लिए प्रचार अभियान जो फिर से विचारधारा को स्थापित करने के नारे के अन्तर्गत समाजवाद के विरुद्ध प्रत्याक्रमण है।

समाजवाद पर अपने हमलों मे उसके विरोधी अब जनतंत्र स्वतंत्रता और मानव अधिकारों जैसी शब्दावली के प्रयोग को तरजीह देने लगे हैं। वास्तव में उनका विश्वास है कि इन शब्दावलियों से उन्हें अपने प्रचार कार्यों में कुछ लाभ मिलता है क्योंकि इनमे तथ्यों और आँकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन यह निश्चित रूप से भ्रान्त धारणा है। वास्तव में स्वतंत्रता, जनतंत्र और मानव अधिकार सामाजिक जीवन की अन्य घटनाओं की तरह ही ठोस घटनाएँ हैं।

तथापि पश्चिम में मानव अधिकारों के सम्बन्ध मे जितना अधिक शोर मचाया जा रहा है उससे यह और भी स्पष्ट हो गया है कि पूँजीवादी जगत इस समस्या पर ठोस और गम्भीर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है। समय बीतने के साथ-साथ ऐसे अभियान का वास्तविक उद्देश्य स्वयं दिखाई देने लगता है। मानव अधिकारों के सम्बन्ध मे चल रही बहस को ओछी राजनीतिक सोदेवाशी के रूप मे मोड़ देने के लिए उठाया गया है अथवा स्पष्ट रूप से कहा जाय तो फूहड़ सोवियत-विरोध की स्थिति तक पहुँचाना इसका उद्देश्य रहा है। यह बात स्पष्ट हो गयी है कि पश्चिमी राजनीतिज्ञ जब उन देशों के सम्बन्ध मे बात करते हैं जहाँ कि वे स्वतंत्रता और जनतंत्र की 'रक्षा करना' आवश्यक समझते हैं तब उनके दिमाग में केवल समाजवादी सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देश होते हैं। समाजवादी दुनिया में लाखों लोग रहते हैं लेकिन ये राजनीतिज्ञ केवल मुट्ठी भर असतुष्टों मे ही रुचि रखते हैं और जहाँ तक स्वाधीनताओं का सम्बन्ध है वे केवल समाजवाद-विरोधी कार्यों के लिए स्वतंत्रता की रक्षा का ही ध्यान रखते हैं।

पश्चिम मे कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इस प्रकार का रबैया राजनीतिक

रूप से लाभप्रद है। पहली नज़र में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कुछ दुखदायी सवालों से छुटकारा मिलेगा, पूँजीवादी जगत में प्राथमिक मानवीय अधिकारों के पागलपन-भरे दबाव के तथ्यों के सम्बन्ध में चुप रहना होगा और समाजवाद आदमी को क्या देता है और पूँजीवाद आदमी से क्या लेता है के बीच तुलना की उपेक्षा की जा सकेगी, लेकिन यह स्थिति मानने योग्य नहीं है क्योंकि सबसे बढ़कर इसे अपना करके वे महत्वपूर्ण समस्याओं को मुलज्ञाने के लिए कदम उठाने के बजाय निरर्थक शब्दावली का सहारा लेते हैं।

दूसरी ओर समाजवादी सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में मानव अधिकार दैनिक जीवन के अविभाज्य अंग हैं। सोवियत जनता का दृढ़ विश्वास है कि स्वाधीनता जनतंत्र और मानव अधिकारों पर अत्यधिक भाव-भरे भाषण निरर्थक बातचीत के अलावा कुछ नहीं है जब तक कि उनके व्यवहार को पूर्णतया सुनिश्चित न बना दिया जाय। जैसा कि हम पूर्णतया जानते हैं कि मानव अधिकार प्राथमिक रूप से एक सामाजिक अवधारणा है जिसके अन्तर्गत सुनिश्चितताओं का एक व्यापक क्षेत्र आ जाता है जिसमें उत्पादन एवं राजनीतिक क्रिया-कलाप में मनुष्य के स्थान को परिभाषित करना होता है और भौतिक तथा सांस्कृतिक लाभों का आनन्द उठाने के वास्तविक अवसरों को और सार्वजनिक समस्याओं में भाग लेने के अधिकार को परिभाषित करना होता है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात समाज के पास भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य कितनी मात्रा में और कितने विशिष्ट हैं। कौन इन मूल्यों का निर्माण करता है और कैसे? तथा समाज के सदस्यों के बीच इनका वितरण किस प्रकार होता है? और निःसन्देह यह वितरण किस प्रकार व्यक्ति के विकास में योग देता है और उसकी स्वतंत्रता और नागरिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है?

देखना यह है कि आज विश्व में विद्यमान दो प्रणालियों में से कौन इन कठिन समस्याओं के समाधान की कठिन कसौटी पर कितनी मात्रा में खरी उतरती है?

पूँजीवाद ने अपने सदियों के शासन में मानव समाज की उत्पादक शक्तियों को यद्यपि समुचित मात्रा में विकसित किया है तथापि इसका इतिहास निर्विवाद रूप से प्रमाणित करता है कि पूँजीवादी समाज चाहे जितना भी सम्पन्न क्यों न हो जाय यह अनिवार्य रूप से शोषण की, सामाजिक असमानता की और अपरिहार्य वर्ग-संघर्षों की व्यवस्था रहेगी। पूँजीवादी देशों में लाखों बेरोजगार और शिक्षा से वंचित जनगण, और गृहविहीन, चिकित्सा की सुविधाओं से वंचित लोग यही अनुभव कर रहे हैं और करोड़ों मेहनतकश लोग जो कि अपनी रंगीन चमड़ी के कारण अपनी राष्ट्रीयता या राजनैतिक आस्थाओं के कारण समुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी यूरोप, चिली और निकारागुआ में, लेबनान और दक्षिणी अफ्रीका में यही अनुभव कर रहे हैं।

मानव अधिकारों के सम्बन्ध में बात करने का अधिकार केवल उभी समाज को है जिसने मात्र घोषणा नहीं की बल्कि जनता की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यावहारिक कदम उठाये हैं। समाजवाद ही इस प्रकार का समाज है। अल्पविकसित उत्पादक शक्तियों को विरामत में प्राप्त कर अविश्वसनीय रूप से कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला सोवियत संघ भी वपों तक, और आज तक भी, सोवियत जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका यद्यपि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता रहा है, किंतु यह निर्विवाद है कि वह इस दिशा में लगे हुए भर रहा है।

सोवियत संघ ने सदा के लिए बेरोजगारी को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में, जो मानवीय क्रियाशीलता का मुख्य क्षेत्र है, प्रत्येक नागरिक का भाग लेना सुनिश्चित कर दिया है। सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय असमान-बेतन सुनिश्चित कर दिया गया है। समान कार्य के लिए समान-ताओं को और अन्य अधिकारों की कमी को समाप्त करते हुए सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक और राजकीय मामलों में भाग लेना सम्भव बना दिया है। सोवियत जनता के स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा और राजनीतिक क्रियाशीलता के प्रोत्साहन के लिए तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए चिन्ता देश में सभी राजकीय और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की क्रियाशीलता की आधारशिला है। इतिहास में पहली बार जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर का निरंतर उन्नयन और परिणामस्वरूप वास्तविक मानव अधिकारों का विस्तार पूरे समाज के भौतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित हो गया है।

‘विचारधारा का अंत’ : सामाजिक आधार एवं छद्म-वैज्ञानिक चरित्र

वर्तमान युग में दोनों जगह विश्व परमाने पर और प्रत्येक पूँजीवादी देश के भीतर वर्ग विचारधारा के विवादों की अभूतपूर्व तीव्रता के प्रकाश में यह देखा जा सकता है कि यह मुझाव देना कि सिद्धान्त का युग पतनोन्मुख है, स्पष्ट रूप से बेतुकी बात है, लेकिन विसिद्धान्तीकरण के सिद्धान्तकारों को इसकी जरा भी चिन्ता है। तथ्यों की परवाह न करके वे अपने छद्म वैज्ञानिक तर्कों को बिना सामने लाये ही सहमति योग्य दिखाने के लिए दम्भपूर्ण आते हैं।

अन्य प्रचारात्मक सिद्धान्तों की सामने आता है तो ऊपरी तौर पर

सामने

हो रहे परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। यहाँ विशेष रूप से संकेत बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन की प्रबन्ध व्यवस्था की बनावट में परिवर्तनों की ओर है जिन्हें यूज्वा अध्येता समूचे सामाजिक जीवन में स्थानान्तरित करना पसन्द करेंगे जिसमें कि सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र भी सम्मिलित है। आमतौर पर वे इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाते हैं कि किसी औद्योगिक समाज के प्रबन्ध की जटिल रचना—सामाजिक प्रकृति के विचार के बिना—वैचारिक आदर्शों से निकलने वाले राजनीतिक निर्णयों की अपेक्षा नहीं रखती लेकिन सावधानी से संयोजित मामलों पर आधारित तकनीकी गणनाओं की अपेक्षा रखती है।

नये औद्योगिक राज्य में अमरीकी पूंजीपति वर्ग के उदार समुदाय में सामान्य रूप से स्वीकृत प्राधिकारी प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉन कॅनेथ गॉलग्रेथ की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तकनीकी और संगठन के अनिवार्यताएँ न कि विचारधारा की प्रतिभा, आर्थिक समाज के रूप को निर्धारित करती है।”

—(ज़ोर लेखक का)¹

यह निश्चित है कि जैसे-जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तीव्र होती जाती है वैसे-वैसे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही देशों में विज्ञान द्वारा प्रदत्त अवसरों का व्यवहार में व्यापक रूप से निरन्तर प्रयोग बढ़ता जाता है तथापि तथ्यों के इस सही वक्तव्य से आरम्भ करते हुए विस्मयान्तीकरण के सिद्धान्त के समर्थक अपने राजनीतिक उद्देश्यों से इसकी संगति बैठाने के लिए स्पष्ट रूप से वाग्जाल लेकर आगे आते हैं।

उत्पादन में वस्तुतः सामाजिक सम्बन्धों सहित सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबन्धकों के कार्य के कुछ विशिष्ट पहलुओं का विस्तार करते हुए, व 'औद्योगिक समाज' के किसी लक्षणिक चरित्र की समस्या का समाधान करते हुए उसे सार्वभौम भाषण बना लेते हैं।

अमरीकी विद्वान डेनियल बैल की दृष्टि से उत्पादन के संगठन के लिए प्रबन्ध का सामाजिक कार्य निर्णायक होता जाता है। औद्योगिक समाज प्रकृति और मानव कार्यों के प्रति तकनीकी रक्षान से पहचाना जा सकता है।

सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के विपरीत, वैचारिक तथा परिणामस्वरूप वर्गीय आदर्श प्रश्न के इस सूत्रण में उपेक्षित रहे हैं। पूंजीवादी राज्य कल्याणकारी एवं निष्पक्ष 'परिवार का अभिभावक' दिखाई देता है जो सब तरह की राजनीतिक सहानुभूति से मुक्त होता है और प्रत्येक मामले में पूरे समाज के हित में अत्यधिक तर्कसंगत निर्णय उपलब्ध करता है।

पूँजीवादी राज्य की प्रकृति एवं क्रिया-कलाप के प्रति तकनीकी रक्षान का

मानव अधिकारों के सम्बन्ध में बात करने का अधिकार केवल उमी ममाज को है जिसने मात्र घोषणा नहीं की बल्कि जनता की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यावहारिक कदम उठाये हैं। समाजवाद ही इस प्रकार का समाज है। अल्पविकसित उत्पादक शक्तियों को विरामत में प्राप्त कर अविश्वसनीय रूप से कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में आगे बढ़ने वाला सोवियत संघ भी वर्षों तक, और आज तक भी, सोवियत जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका यद्यपि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता रहा है, किंतु यह निर्विवाद है कि वह इस दिशा में लंबे डग भर रहा है।

सोवियत संघ ने सदा के लिए बेरोजगारी को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में, जो मानवीय क्रियाशीलता का मुख्य क्षेत्र है, प्रत्येक नागरिक का भाग लेना सुनिश्चित कर दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर दिया गया है। सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय असमानताओं को और अन्य अधिकारों की कमी को समाप्त करते हुए सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक और राजकीय मामलों में भाग लेना सम्भव बना दिया है। मोक्षित जनता के स्वास्थ्य के लिए, उसकी शिक्षा और राजनीतिक क्रियाशीलता के प्रोत्साहन के लिए तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए चिन्ता देश में सभी राजकीय और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की क्रियाशीलता की आधारशिला है। इतिहास में पहली बार जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर का निरंतर उन्नयन और परिणामस्वरूप वास्तविक मानव अधिकारों का विस्तार पूरे समाज के भौतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित हो गया है।

‘विचारधारा का अंत’ : सामाजिक आधार एवं
छद्म-वैज्ञानिक चरित्र

वर्तमान युग में दोनों जगह विश्व पैमाने पर और प्रत्येक पूँजीवादी देश के भीतर वर्ष विचारधारा के विवादों की अभूतपूर्व तीव्रता के प्रकाश में यह देखा जा सकता है कि यह सुझाव देना कि सिद्धान्त का युग पतनोन्मुख है, स्पष्ट रूप से बेतुकी बात है, लेकिन विसिद्धान्तिकरण के सिद्धान्तकारों को इसकी जरा भी चिन्ता है। तथ्यों की परवाह न करके वे अपने छद्म वैज्ञानिक तर्कों को बिना सामने लाये ही सहमति योग्य दिखाने के लिए दम्भपूर्ण चालवाजियों से भरा बैला लेकर सामने आते हैं।

अन्य प्रचारात्मक सिद्धान्तों की तरह विसिद्धान्तिकरण का सिद्धान्त भी जब सामने आता है तो ऊपरी तौर पर यह आधुनिक विश्व में वास्तविक रूप से घटित

हो रहे परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता है। यहाँ विशेष रूप से प्रकेत बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन की प्रबन्ध व्यवस्था की बनावट में परिवर्तनों की ओर है जिन्हें वृज्वा अध्येता समूचे सामाजिक जीवन में स्थानान्तरित करना पसन्द करेंगे जिसमें कि सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र भी सम्मिलित है। आमतौर पर वे इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाते हैं कि किसी औद्योगिक समाज के प्रबन्ध की जटिल रचना—सामाजिक प्रकृति के विचार के बिना—वैचारिक आदर्शों से निकलने वाले राजनीतिक निर्णयों की अपेक्षा नहीं रखती लेकिन सावधानी से संयोजित सामग्री पर आधारित तकनीकी गणनाओं की अपेक्षा रखती है।

नये औद्योगिक राज्य में अमरीकी पूँजीपति वर्ग के उदार समुदाय में सामान्य रूप से स्वीकृत प्राधिकारी प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉन कँनेथ गॉलब्रेथ की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तकनीकी और संगठन के अनिवार्यताएँ न कि विचारधारा की प्रतिभा, आर्थिक समाज के रूप को निर्धारित करती हैं।”

—(जोर लेखक का)¹

यह निश्चित है कि जैसे-जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तीव्र होती जाती है वैसे-वैसे पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही देशों में विज्ञान द्वारा प्रदत्त अवसरों का व्यवहार में व्यापक रूप से निरन्तर प्रयोग बढ़ता जाता है तथापि तथ्यों के इस सही वक्तव्य से आरम्भ करते हुए धिसिद्धान्तीकरण के सिद्धान्त के समर्थक अपने राजनीतिक उद्देश्यों से इसकी संगति बँटाने के लिए स्पष्ट रूप से बाग़जाल लेकर आगे आते हैं।

उत्पादन में वस्तुतः सामाजिक सम्बन्धों सहित सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबन्धकों के कार्य के कुछ विशिष्ट पहलुओं का विस्तार करते हुए, व 'औद्योगिक समाज' के किसी लाक्षणिक चरित्र की समस्या का समाधान करते हुए उसे सार्वभौम मापदण्ड बना लेते हैं।

अमरीकी विद्वान डेनियल बेल की दृष्टि से उत्पादन के संगठन के लिए प्रबन्ध का सामाजिक कार्य निर्णायक होता जाता है। औद्योगिक समाज प्रकृति और मानव कार्यों के प्रति तकनीकी रक्षान से पहचाना जा सकता है।

सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के विपरीत, वैचारिक तथा परिणामस्वरूप वर्गीय आदर्श प्रश्न के इस सूत्रण में उपेक्षित रहे हैं। पूँजीवादी, राज्य कल्याणकारी एवं निष्पक्ष 'परिवार का अभिभावक' दिखाई देता है जो सब तरह की राजनीतिक सहानुभूति से मुक्त होता है और प्रत्येक मामले में पूरे समाज के हित में अत्यधिक वर्कसंगत निर्णय उपलब्ध करता है।

पूँजीवादी राज्य की प्रकृति एवं प्रिया-वलाप के प्रति तकनीकी रक्षान का

1. जॉन कनेथ गॉलब्रेथ, द न्यू इन्स्टिट्यूट स्टेट, बोस्टन, 1967, पृ० 7

उद्देश्य सम्पत्ति के स्वामित्व के रूपों के ठोस विश्लेषण का स्थान लेना है और उत्पादन के संगठन व प्रबन्ध के लिए आधार प्रस्तुत करना है; सामाजिक विधि के क्षेत्र में उपायों को क्रियान्वित करना तथा राज्य के नियन्त्रण की पद्धतियों का प्रयोग करना है। उनकी क्रियाशीलता की व्याख्या राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक अन्तर्विरोधों के माध्यम से न करके प्राविधिक प्रगति के सामान्य सन्दर्भों के माध्यम से की जाती है। और यह माना जाता है कि यह स्वयं सामाजिक सम्बन्धों के नये रूपों को उत्पन्न करती है। प्रत्येक धारणा का निर्माण व्यावहारिक तार्किकता के अति प्राचीन विचार के आधार पर किया जाता है तथा यह मान लिया जाता है कि वह व्यावहारिक अनुभव से अपना मार्ग बनाएगी।

इससे भी वे काल्पनिक लाभ का निष्कर्ष निकालते हैं कि पूँजीवादी समाज में अनुभवों के तथ्यों की सीमा के परे होने वाली बड़ी सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में सूत्रण नहीं हो सकते (समाधान की बात तो दूर)। तथापि समूची सामाजिक प्रक्रिया के विश्लेषण की माँग निरन्तर बनी रहती है।

यह पहचानना कठिन नहीं है कि पूँजीवादी समाजवैज्ञानिकों की मंशा क्या है। वे उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच पूँजीवाद और समाजवाद के बीच विवाद को विसर्जित करना पसन्द करेंगे, व्यावहारिक मवालों को अलग करने में और इस प्रकार मेहनतकश जनता को मार्क्सवाद-मेनिनवाद से और वर्ग-संघर्ष की बुनियादी समस्याओं से दूर हटाना पसन्द करेंगे। शोषकों का सदा से यही सपना रहा है कि जहाँ तक बन सके जनता को समाजवादी क्रान्ति के विचार से दूर रखा जाय। बूज्वा विद्वान मेहनतकश जनता से पूछते हैं जिस समाज में आप रह रहे हैं वही यदि तात्कालिक समस्याओं का विशुद्ध व्यावहारिक रूप से आशाजनक हल प्रस्तुत कर दे तो किसे क्रान्ति की आवश्यकता होगी?

उनका तर्क है कि अतीत में सामाजिक विवाद वर्ग-संघर्ष के रूप में विकसित हो सकते थे, उदाहरण के लिए जैसे 20वीं शताब्दी के आरम्भ में रूस की विशिष्ट परिस्थितियों में। उस समय सिद्धान्त का होना आवश्यक था लेकिन अब पूँजीवादी समाज के लाभ के लिए इनको उठा रखा जा सकता है। वे इसका कारण बताते हैं कि आधुनिक पूँजीवादी राज्य ने अपने प्रतिष्ठानों की क्रमिक पूर्णता के जरिये वहाँ उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान का मार्ग प्राप्त कर लिया है।

वे कहते हैं वास्तव में इन समस्याओं की प्रकृति ही मूल रूप से परिवर्तित हो गई है। गालब्रेथ लिखते हैं जब पूँजी आर्थिक सफलता की कुजी थी—अमीर और शरीर के बीच सामाजिक विवाद था—लेकिन हाल के समय में शिक्षा के कारण भिन्नता उत्पन्न हो गयी है जो इनको अलग करती है—राजनीति भी नये विभाजन को प्रतिबिम्बित करती है। संयुक्त राज्य अमरीका में अब, सन्देह या

असन्तोष पूंजीपतियों या सिर्फ धनिकों के खिलाफ नहीं है। मात्र बुद्धिजीवियों को सन्देह एवं खतरे की दृष्टि से देखा जाता है।

इस प्रकार, वर्ग-संघर्ष के सम्बन्ध में मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षा को चल-ताऊ काट दिया जाता है।

साम्राज्यवाद के समर्थक मेहनतकश जनता के मन में यह वैठाने की कोशिश करते हैं कि अब वर्ग-संघर्ष और सैद्धान्तिक संघर्ष के दिन सब चुके हैं और अब 'तकनीशियनों के युग' में (सर्वोपरि संयुक्त राज्य अमरीका में) वर्ग और विचार-धाराएँ अनावश्यक वस्तु होने के कारण लुप्त होती जा रही हैं।

पूँजीवादी प्रचार मजदूर वर्ग और उसकी विचारधारा की क्रान्तिकारी भूमिका को समाप्त करने के प्रयासों में स्वयं मार्क्स की शिक्षाओं के ही विसिद्धान्तीकरण की कोशिश करता है। न्यूयार्क विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के आचार्य सिडनी हुक लिखते हैं, "भविष्य के बुद्धिमान इतिहासकार को 20वीं शती के उत्तरार्ध में एक आश्चर्यजनक घटना की चुनौती का सामना करना होगा—कार्ल मार्क्स के पुनरागमन का। अपने इस पुनः अवतरण में वह 'कैपिटल' के लेखक धूल-धूसरित कोट पहने किमी अर्थशास्त्रों के रूप में, कम्युनिस्ट घोषणापत्र के जोशीले प्रचार-पुस्तिका के लेखक के रूप में नहीं होगा। इस समय वह आयेगा दार्शनिक या नैतिक उपदेशक के रूप में : वर्ग, पार्टी या भुट के सकीर्ण क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ, मानवीय स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में प्रसन्न उद्गारों से पूर्ण गाड़ी में उसके सहयात्री विश्व के औद्योगिक मजदूर नहीं होंगे अपितु साहित्यिक बुद्धिजीवी होंगे..."सबंहारा नहीं अपितु विद्वान प्रोफेसर, सामाजिक, दृष्टि से उपेक्षित लोग नहीं, अपितु मनो-वैज्ञानिक रूप से विरक्त और लेखकों तथा कलाकारों का विविध समुच्चय।"

प्रथम तो यह तीखी उत्तेजक व्यंग्योक्ति हर्बर्ट मार्क्युस की सुप्रसिद्ध धारणा की ही व्याख्या है, साथ ही मार्क्स की शिक्षाओं का व्यंग्य चित्र भी है। दूसरे अपनी अक्षमता के कारण अथवा अधिक सम्भव है कि जान-बूझकर, हुक हर चीज को उलटा घुमाता है और ऐसा दिखाने का प्रयास करता है मानो हमारे समय में मार्क्स की शिक्षा पुरानी पड़ गयी हो, अपना क्रान्तिकारी महत्त्व खो चुकी हो और किसी भी पुराने तरीके में उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा इस प्रकार के दोषदर्शियों की वह प्रिय चाल होती है जिससे वह मार्क्सवाद के सम्बन्ध में अपने अज्ञान को छिपाते हैं।

वैज्ञानिक कम्युनिज्म में मिलावट करने के प्रयासों के लिए यह बड़ी सुविधा-जनक स्थिति है; हमारे समय में स्वीकृत मार्क्स के विचारों के अभिप्राय को स्पष्ट-

1. जॉन कॅनेथ गालब्रेथ, ■ न्यू इन्डस्ट्रियल स्टेट, पृ० 244-45

■ न्यूयार्क टाइम्स बुक रिव्यू, मई 22, 1966 पृ० 2

रूप से अस्वीकृत किये बिना ही यह उसके मुख्य सारतत्त्व की वर्ग मंषय और सामाजिक क्रान्ति सम्बन्धी शिक्षा को अस्वीकृत करता है।

सामाजिक क्रान्ति की धारणा पूरी तरह ठुकरायी नहीं गयी अपितु उसे सामान्य व्यवहारवाद के रूप में भ्रष्ट कर दिया जाता है। सामाजिक जीवन के हर पहलू को शब्दशः प्रभावित करने वाले मुख्य रूपान्तरणों के सम्पूर्ण समुच्चय को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के अर्थात् विशुद्ध रूप से आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के द्वारा। प्रत्येक क्रान्ति—पूँजीवादी हो या समाजवादी—की व्याख्या समाज के औद्योगीकरण के पथ पर चलते हुए सुधारों की व्यापक प्रक्रिया के 'विशेष मामलों' के रूप में व्याख्या की जाती है।

कम्युनिस्टों के विरोधी इन 'सैद्धान्तिक' स्थापनाओं से अनेक निष्कर्ष निकालते हैं जिनका उद्देश्य मार्क्सवाद लेनिनवाद की शिक्षाओं का तथा समाजवाद के निर्माण का विरोध करना होता है। वे दावा करते हैं कि समाजवाद इसके सिद्धान्त और व्यवहार आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के लिए सामाजिक विकास के कतिपय सम्भव विविध रूपों में से केवल एक है। कम्युनिस्ट पार्टियों को केवल पूँजीवादी व्यवस्था के आरम्भिक काल में मजदूर वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाने वाली के रूप में चित्रित किया जाता है। जैसे ही आधुनिकीकरण को सामाजिक विकास की प्रक्रिया का मुख्य प्रेरक घोषित किया जाता है वैसे ही सामाजिक रूपान्तरण के लक्ष्यों का स्थान प्राथमिक रूप से, उचित समय में, वैज्ञानिक और प्राविधिक परिवर्तनों को देखते व उनसे प्रतिक्रिया करने में समर्थ आर्थिक व्यवस्था को 'अनुकूल' करने का कार्य ले लेता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद के समर्थक सर्वोपरि 'विचारधारा की समाप्ति' की आड़ में वैज्ञानिक कम्युनिज्म की विचारधारा को अभिशापित करने के लिए ही विसिद्धान्तीकरण को आवश्यक बताते हैं।

वास्तव में दर्शन न होना भी एक दर्शन है, वैसे ही जैसे कि अवसरवाद केवल सिद्धान्तों की कमी नहीं, बल्कि अवसरवादी सिद्धान्तों की प्रमुखता होता है। इसी प्रकार विसिद्धान्तीकरण भी एक सैद्धान्तिक हथियार है। इसे हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद को नष्ट करने के लिए आधिकारिक पूँजीवादी विज्ञान का एक और प्रयत्न समझते हैं।

वैचारिक संघर्ष के विध्वंस के सम्बन्ध में चलायी जा रही बात-चीत के पीछे पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थकों की वर्गीय स्थिति स्पष्ट दिखायी देती है क्योंकि वैचारिक संघर्ष में किसी प्रकार की कमी होने का लाभ केवल पूँजीपतियों को ही मिलता है जैसा कि लेनिन ने लिखा था : एक मात्र विकल्प है या तो पूँजीवादी या समाजवादी सिद्धान्त। इसके बीच में कोई मध्यम मार्ग नहीं है (मानवता के

लिए कोई 'तीसरी' विचारधारा नहीं बनायी गयी) और इससे भी आगे, वर्ग विरोधों द्वारा भग्न समाज में विचारधारा कभी वर्गहीन अथवा वर्गों से ऊपर नहीं हो सकती।¹

आधुनिक काल पर लागू किये जाने पर यह स्थापना अन्य किसी भी चीज से अधिक सिद्धान्तशून्यता की अवधारणा के वास्तविक सारतत्त्व को स्पष्ट कर देती है। भले ही इसके प्रचारक इसको छद्म वैज्ञानिक रूप दिया करें, चाहे उदार जनवादी इसे सजाकर प्रस्तुत करें अथवा इसके लिए भाववादी अकादमिक मुहावरों का उपयोग करें, यह सत्य है कि यह कट्टर कम्युनिस्ट विरोधियों का एक सक्रिय हथियार है। यही नहीं यह समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष में एक विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति करता है।

तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि सिद्धान्तहीनता का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निराधार एवं उद्देश्यमूलक है, यह इससे सम्बद्ध अन्य सिद्धान्तों की भाँति पश्चिम में व्यापक रूप से प्रचारित है। अपेक्षाकृत रूप से इसके अधिक लोक-प्रचलित होने का कारण समग्र रूप में पूँजीवादी सामाजिक विचार के गम्भीर संकट की परिस्थितियाँ हैं जो कतिपय सामाजिक समुदायों और राजनीतिक धाराओं के समकालीन पूँजीवादी समाज में—सामाजिक व्यवहार और हितों को मान्यता प्रदान करती हैं।

यह बात सबसे अधिक उदार पूँजीपति वर्ग पर लागू होती है जो वास्तव में पिछले कुछ दशकों में फ्रांसिस्म की सर्वाधिपत्यवादी विचारधारा के लज्जाजनक पराभव को देख चुका है और परम्परागत उदार विचारधारा के निरन्तर गहराते आंतरिक संकट को भी देख चुका है।

जीवन के सभी क्षेत्रों में इजारेदारी आकस्मिक आक्रमणों से मुक्त प्रतियोगिता के युग के पुराने बन्धनों को तोड़ देती है, प्रचलित धारणाओं को नष्ट कर देती है। संक्षेप में, पूँजीवादी उदारवाद और उसकी विचारधारा के पारम्परिक आधारों को ध्वस्त कर देती है। और यही कारण है कि बहुत से पूँजीवादी सिद्धान्तकार पूँजीवादी विचारधारा के दिवालियापन को आँकने लगे हैं, इसके संकट के रूप में नहीं बल्कि सामान्य रूप में 'विचारधारा की समाप्ति' के रूप में आँकते हैं।

सिद्धान्तहीनता का सिद्धान्त सुधारवादियों के हाथों की कठपुतली बन जाता है जो कि पूँजीपतियों के साथ सिद्धान्तहीन समझौतों के लिए समाजवादी समझ को ही त्याग देते हैं। मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी शिक्षा को ताना पर रखते हुए दक्षिणपंथी सामाजिक जनवादियों के नेता और अन्य सुधारवादी व्यक्ति स्व-भावतः सिद्धान्तहीनता के सिद्धान्त को बड़ी पूँजी के साथ अपने समझौतों के

औचित्य के रूप में देखते हैं। अनिवार्य रूप से यही मुद्दे 'वामपंथी' अतिवादियों तथा संशोधनवादियों को सिद्धान्तहीनता के सिद्धान्त के साथ जोड़ देते हैं।

लेनिन ने कभी लिखा था कि "पूँजीपतियों की कुटिल कार्यविधियाँ मजदूर आंदोलन के भीतर संशोधनवाद को फैलाती हैं और अक्सर मजदूर आंदोलन के मतभेदों को स्पष्ट विभाजन की रेखा तक ले जाती हैं।" यही है जो हुआ है। हर रंग के अवसरवादियों को पूँजीवादी कार्यनीतियों की व्याख्या पूँजीवादी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लक्षणों के रूप में करने की उनकी जल्दबाजी से पहचाना गया है और वास्तविक समाजवाद के स्थान पर वैयक्तिक आंशिक सुधारों को लागू करते पाया गया है।

निस्सन्देह, अद्यतन संशोधनवादी अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा आम तौर से कुतर्क का अधिक आश्रय लेते हैं। इस सदो के आरम्भ में वॉर्सेटीनवाद के मुकाबले जो स्वयं स्पष्ट रूप से क्रान्तिकारी मजदूर आंदोलन का विरोध करता था, आधुनिक संशोधनवाद 'समाजवाद का बेप धारण करके' काम करता है, और जैसा कि कहा जाता है कि वह इजारेदारी विरोधी आंदोलन को भीतर से तोड़ने के प्रयासों में पचभोगी (गुप्तचर) की भूमिका अदा करता है। यह कार्यनीति अधिक खतरनाक है क्योंकि यह आधुनिक अवसरवाद के उपयोग में कुछ नयी घटनाक्रियाओं के साथ जुड़ गयी है। 1967 में यह उत्पन्न हुई और आज की वैचारिक संघर्ष की समस्त नयी स्थिति का लक्षणिक चरित्र बन गयी। इनसे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं—

प्रथम, समस्त अवसरवादी धारणाओं का गहरे सोवियत विरोधी रंग में रंगा जाना।

दूसरे, अवसरवाद की अधिकांश विविधताओं में विद्यमान पूँजीवादी राष्ट्रवादी आधार का सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद से अलगाव, तथा वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्त और व्यवहार से स्पष्ट सम्बन्ध-विच्छेद के मुख्य कारक के रूप में।

तीसरे, इस आधार पर दक्षिण एवं वाम अवसरवाद का वास्तविक सम्मिश्रण, जो अनेक मामलों में एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध है और एक-दूसरे को प्रभावित करता है।

ये और अन्य लक्षण पूरी तरह स्पष्ट हैं। सार रूप में, समाजवाद के सामाजिक व्यवहार को सिद्धान्तहीन बनाने के प्रयासों में लगे अवसरवादी एवं संशोधनवादी समाजवाद के सभी तरह के—'सुधरे हुए' और 'आदर्श' रूपों जैसे 'जनवादी', 'उदार' या 'मानवीय समाजवाद' या 'मानवीय आकृति वाला समाजवाद' आदि की खोज में बड़े प्रयुत्पन्नमति सिद्ध संपन्न हुए हैं। और इन सबको सोवियत संघ तथा अन्य

1. वी० आई० लेनिन, डिग्रसेड इन द यूरोपियन लेबर मूवमेंट, कलेक्टड वर्क्स, बंड 16, पृ० 351

समाजवादी देशों में वास्तव में विद्यमान समाजवाद के मुकाबले रखा जाता है, प्रतिरूपों की भाँति प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें देखते हुए एक विचित्र विरोधाभास आँखों में खटकता है : मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सार्वभौम चरित्र से और समाजवादी रूपांतरण के अनुभव में इन्कार करते हुए इस प्रकार की तर्कहीन धारणाओं के प्रतिपादक स्वयं कृत्रिम रूप से निमित्त अपने आदर्शों को सभी समाजवादी देशों के लिए अनिवार्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे उनको समस्त मानवता के लिए 'सार्वभौम' फार्मूले से कम किमी रूप में रखने को तैयार नहीं हैं।

इस प्रकार, बीसवीं शती के आरम्भ के सशोधनवाद के विपरीत जो कि वैज्ञानिक समाजवाद और सर्वहारा वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त के—और इस प्रकार उनके अन्तिम ध्येय समाजवाद के—विरुद्ध उत्पन्न हुआ या अद्यतन संशोधनवादी, वास्तव में विद्यमान समाजवाद के विरुद्ध, समाजवादी संरचना के व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

उनकी विध्वंसक कार्यवाहियों का मुख्य लक्ष्य समाजवाद-विरोध है। जैसा कि जर्मन के प्रख्यात मार्क्सवादी दार्शनिक प्रो० अल्फ्रेड कौसिंग ने लिखा है : "लेनिनवाद के विरुद्ध आज के सशोधनवाद का संघर्ष वैचारिक संघर्ष से कुछ अधिक है। यह गत 60 वर्षों की क्रान्तिकारी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक उपलब्धियों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन को वंचित करने के उद्देश्य से किया जा रहा प्रहार है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन को महान् अवतुर्बर समाजवादी क्रान्ति की पूर्ववर्ती स्थिति तक नीचे गिराने का प्रयास है।"¹

लेनिन सदा जोर देकर कहा करते थे कि अवसरवाद आरम्भ तो करता है 'मार्क्स' के सम्बन्ध में वैयक्तिक 'संशोधनों से' और अन्ततः अनिवार्य रूप से क्रान्तिकारी मार्क्सवाद से अपने को पूरी तरह तोड़ लेता है। इतिहास इस निष्कर्ष की पूरी तरह पुष्टि करता है। पूँजीवादी प्रचार के पिछलगू दक्षिण-पन्थी सुधारवादी सिद्धान्तविद् और सशोधनवादी मार्क्सवाद को जीर्ण धोषित करते हैं, सिद्धान्तहीनता के सिद्धांत की घोषणा करते हैं, 'जनता के पूँजीवाद का उपदेश देते हैं, आदि-आदि। वे सामाजिक और राजनीतिक विवादों को सुलझाने के स्वतः उद्भूत विकास के लिए पूर्णतया काल्पनिक शैली में सामने आते हैं। और हमारे युग के सैद्धान्तिक संघर्ष के समस्त आधारभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में कम्युनिज्म विरोधी नीति को ग्रहण करते हैं और वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं।

'वामपन्थी' अतिवादी कुछ भिन्न शब्दावली का व्यवहार करते हैं। शब्दों में तो वे इजारेदारियों के सबसे भयावक शत्रु होते हैं और क्रान्तिकारी संघर्ष के कट्टर समर्थक। तथापि, कार्यरूप में विभिन्न प्रकार के भिन्न पूँजीवादी अति क्रान्ति-

कारियों, अराजकतावादियों, नवत्रात्स्कीवादियों, 'नव वामपंथियों' जो—हर्बर्ट मार्थुस के शब्दों की बकासत करते हैं—और मोशीज्या, जो पूंजीवादी प्राविधिजो के सिद्धान्त के स्पष्ट प्रभाव में हैं, के नये रूपों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होते। ये सब अत्यधिक अनुदार (सकीण) सामाजिक जनवादी धारणाओं से अधिक दूर नहीं हैं। दोनों की ही सैद्धांतिक संरचना, सार रूप में, उन्ही तत्वों के विभिन्न प्रकार के संयोजन से होती है, दक्षिणपन्थी सुधारवादी की तरह 'वामपन्थी' संशोधनवादी भी समाजवादी क्रान्ति की मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षाओं को विकृत करते हैं। वर्ग-संघर्ष के नियमों का प्रत्याख्यान करते हैं और मजदूर वर्ग के नेतृत्वकारी भूमिका को अस्वीकार करते हैं—इसी प्रकार समाजवाद की सम्पूर्ण विश्व-व्यवस्था का प्रत्याख्यान करते हैं, वर्तमान मुक्ति आन्दोलन का भी। दूसरे शब्दों में सिद्धान्तहीनता का सिद्धान्त अपने सभी मुख्य रूपों में उनकी भावनाओं से सादृश्य रखता है।

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1960 के दशक के दौरान समाजवाद के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष में (जो 1968 में चेकोस्लावाकिया की घटनाओं से और तीखा हुआ) दक्षिणपन्थी सामाजिक जनवादी और 'वामपन्थी' अतिवादी साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया के साथ वर्गीय मोर्चे की उसी दिशा में चले गये।

दो व्यवस्थाओं की समरूपता का भ्रम

दो व्यवस्थाओं की समरूपता का सिद्धान्त भी विसिद्धान्तिकीकरण के सिद्धान्त का ही विस्तार है। यह उसी स्थापना से, कि वैचारिक वर्ग-संघर्ष क्षीण होता जा रहा है, निस्तुत हो करके हाल के दशकों में पूंजीपति वर्ग द्वारा संचित सामाजिक आंदोलन के समस्त अनुभव का सार प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त कम्युनिज्म को पूर्णतया अस्वीकार करने और पूंजीवादी व्यवस्था का खुला समर्थन करने की नयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने के लक्ष्य का अनुसरण करता है जबकि उससे किसी लाभ की गुंजाइश नहीं है।

स्पष्ट रूप से कम्युनिज्म विरोध के समर्थक और उदारमना पूंजीवादी सिद्धान्तकार पुनः 'एकताबद्ध' समाज के विचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद व्यवस्थित रूप से सम्भावित हो। फिर एक बार, साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार सुधारवादी और संशोधनवादी संयुक्त हो रहे हैं और इस मंच पर सहयोग कर रहे हैं।

समरूपता के प्रवक्ता मेहनतकश जनता को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि पूंजीवादी एवं समाजवादी समाजों के बीच विद्यमान सामाजिक-राजनीतिक भिन्नताएँ औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विशेष रूप से तकनीकी क्रांति के युग में मिटायी जा रही हैं। वे कहते हैं कि समाजवाद में कम्युनिस्टपन

निरन्तर कम होता जा रहा है और पूँजीवाद में लगातार पूँजीवादीपन कम होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के समीप आ जायेंगे; एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी परिणति समान आर्थिक एवं सामाजिक रूपों वाले 'संकर समाज' के निर्माण के रूप में होगी।

समरूपता के सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि औद्योगिक समाज के दोनों प्रारूपों के बीच भिन्नताएँ क्षीण होती जायेंगी। जब दोनों प्रकार के समाज जीवन के उसी स्तर पर पहुँच जायेंगे, इस सिद्धान्त का मानना है, उनके एक ही संगठन होंगे।

इस विचार का प्रमाणीकरण वैज्ञानिकता से उतनी ही दूर है जितना कि इसके प्रवर्तक वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने की इच्छा से दूर है। जैसीकि उनकी आदत है, वे समस्याओं की जटिलता की पूरी तरह जाँच करने से कतराते हैं, और खास तौर से ऐसे 'विवरणों' के सम्बन्ध में जैसे कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से रहित समाजवादी समाज एवं मजदूरी के शोषण पर आधारित समाज के बीच बुनियादी भिन्नताएँ। फलस्वरूप वे अपने से सर्वथा विपरीत वर्ग-संरचना, उत्पादन-सम्बन्ध, उत्पादन के लक्ष्य आदि पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार के सिद्धान्तकार औद्योगिक रूप से विकसित देशों की वर्तमान वास्तविकता के तथ्यों को किङ्कृत रूप में प्रस्तुत करते हुए शुद्ध रूप से सतही रूपों, लक्षणों पर विचार करने को प्रमुखता देते हैं।

समरूपता के पक्ष में सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त युक्तियों में प्रथम और प्रमुख वे हैं जो भौडी प्राविधिकता की स्थितियों से, अर्थात् उन स्थितियों से जबकि सामाजिक जीवन का समस्त क्रियाकलाप यात्रिक रूप से प्रत्यक्ष रूप में प्राविधिकता के स्तर से निर्धारित किया जायगा, उठाया जाती है। इसमें सारा ध्यान दोनों व्यवस्थाओं की आर्थिक क्षेत्र की कुछ समान घटनाक्रियाओं पर दिया जाता है—राष्ट्रीय आधिक्यता में उद्योग के हिस्से में वृद्धि और कुल मिलाकर उद्योग में भारी उद्योग की वृद्धि, नये उद्योगों का विकास, स्वचालन का व्यवहार तथा प्रचार-प्रसार के साधन आदि। संक्षेप में, प्रविधि के विकास पर बल दिया जाता है, लेकिन प्रश्न के दूसरे और मुख्य पहलू के सम्बन्ध में जानबूझकर चुप्पी साध ली जाती है। इस प्रविधि का स्वामी कौन है, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, कौन इससे मुनाफ़ा लेता है। दूसरे शब्दों में, युग के मुख्य वर्ग-विवाद को आँखों से ओझल कर दिया जाता है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व निजी सम्पत्ति को निरस्त कर देता है।

समरूपता का सिद्धान्त औद्योगिक रूप से विकसित आधुनिक समाजों में संरचना सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रसंग उठाता है : मजदूरी कमाने वालों के अनुपात में वृद्धि, श्रमिकों की शिक्षा व कुशलता में वृद्धि, मशीनों द्वारा नियंत्रण की ओर संक्रमण आदि। तथापि, इन समस्त वास्तविक प्रक्रियाओं को कथित सामाजिक व्यवस्था

के बगैरे-आधार के साथ उनके सम्बन्ध का उल्लेख किये बिना उठाया जाता है, समरूपता के सिद्धान्त के प्रतिपादकों द्वारा पूर्णतया गलत व्याख्या की जाती है, पूंजीवाद के अन्तर्गत और समाजवाद के अन्तर्गत सामाजिक जीवन के एक प्रकार के स्तरीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ-ही-साथ, उक्त सिद्धान्त के समर्थक सामान्यतया इन विशेष रूप से सादृश्यपूर्ण घटनाओं के सारतत्त्व में विद्यमान बुनियादी भिन्नताओं के विषय में कुछ भी नहीं कहते। इन भिन्नताओं की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि पूंजीवाद की सामाजिक प्रकृति समाजवाद की प्रकृति से पूर्णतया विपरीत है।

अन्ततः, समरूपता के विकास के प्रवक्ताओं की युक्तियों में जिनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है वे विशुद्ध रूप से भावनापूर्ण और नैतिक प्रकृति की हैं। खास तौर से, इस स्थापना पर बहुत अधिक चर्चा की जाती है कि समाजवादी देशों में जीवन-स्तर के उन्नत होने का परिणाम यह होगा कि वहाँ की जनता में उपभोक्ता-मानसिकता की ओर सम्मान बढ़ेगा जो समाजवाद को पूंजीवादी 'जन-उपभोग' समाज की दिशा में बढ़ने के लिए विवश करेगा। बेशक, यह एक सच्चाई है जिसे सावधानी के साथ छिपाया गया है कि पूंजीवादी समाज में संपूर्ण जीवन व्यवहार में सांसारिक उपभोक्ता मानसिकता बना दी गयी है जिसकी समाजवाद के आदर्शों से ज़रा भी समानता नहीं है। समाजवाद में, बढ़ती हुई समृद्धि यद्यपि स्वयं महत्वपूर्ण है, पर प्राथमिक रूप से इसका अर्थ है सामाजिक प्रगति की उपलब्धि और व्यक्ति का सर्वतोमुखी विकास।

तथापि, समरूपता सिद्धान्त के प्रतिपादक इन बुनियादी भिन्नताओं के सम्बन्ध में ध्यान न देने का बहाना करते हैं। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में, केवल दोनो व्यवस्थाओं में विद्यमान समान रूप ही रहते हैं। इस पहलू पर अपनी दृष्टि को केन्द्रित करते हुए फ्रांसीसी विद्वान एच पत्रकार रेमण्ड आरों पूछते हैं "....उत्पादन की उन्हीं शक्तियों से शुरू करते हुए (और उत्पादन शक्तियाँ—विज्ञान और प्रविधि सभी विकसित समाजों में कमोबेश समानता रखती हैं।) किस सीमा तक उत्पादन सम्बन्ध और सामाजिक संगठन भिन्न हो सकते हैं?"¹

क्या यह वास्तव में समस्या को सही ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है?

यह सत्य है कि आधुनिक उत्पादक शक्तियाँ, विशेष रूप से, अपने आगे के विकास में, सर्वदा भिन्न सामाजिक-आर्थिक रूपों में नहीं रह सकती। शीघ्र अथवा विलम्ब से अनिवार्यतया वे एक विश्वआर्थिक व्यवस्था में विलीन हो जायेंगे। लेकिन यह विलय ठीक उसी प्रकार नहीं होगा जैसाकि श्री आरों चाहते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद का इस रूप में विलीनीकरण नहीं होगा कि समाजवाद अपनी बुनि-

यादी वर्ग स्थिति को छोड़ देगा और यह कि पूँजीवादी व्यवस्था में प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप भी नहीं होगा।

स्वभावतः, इस प्रकार का निष्कर्ष पूँजीवादी विद्वानों को अनुकूल नहीं प्रतीत होता। उनका काम तो विरोध को ही सामने लाना है। इसलिए इस बुनियादी सवाल का कि उनकी पसन्द का समरूप 'मिथित' समाज किस रूप का होगा, उनका उत्तर उन्हें घेनकाव कर देता है।

समरूपता के सिद्धान्त के भाष्यकार प्रायः वस्तुओं को इस ढंग से चित्रित करते हैं कि एकीकृत संकर समाज पूँजीवाद एवं समाजवाद द्वारा उपलब्ध श्रेष्ठतम को विरासत में प्राप्त करेगा अर्थात् यह उनकी कमियों से मुक्त रहेगा तथा दोनों व्यवस्थाओं के गुणों से युक्त होगा। इस प्रकार, अमरीकी अर्थशास्त्री पीटर ड्रुकर—जिन्होंने इस सिद्धान्त के विज्ञापन में भारी थम किया है, कहते हैं—“मुक्त औद्योगिक समाज” निश्चित रूप से उससे बहुत भिन्न होगा जैसा कि हम पारम्परिक रूप से ‘पूँजीवाद’ के सम्बन्ध में सोचते हैं। यह उससे भी बहुत भिन्न होगा जैसा कि हम परम्परागत रूप से ‘समाजवाद’ के सम्बन्ध में सोचते हैं। एक ऐसा औद्योगिक समाज जो पूँजीवाद और समाजवाद से परे होगा। यह एक नया समाज होगा जो दोनों से बढ-चढकर होगा।”

विषय को इस ढंग से मोड़ देने से प्रतीत होता है कि पूँजीवादी पण्डित सामाजिक जीवन के नये और अधिक पूर्ण रूपों की खोज में लगे हैं। इस कारण उनको दोनों व्यवस्थाओं के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष निर्णायक के रूप में आघात करने की छूट मिल जाती है।

अच्छा, क्यों न ऐसा किया जाय कि पूँजीवाद और समाजवाद की उपलब्धियों में से प्रत्येक साकारात्मक वस्तु अलग कर ली जाय और इन तत्त्वों से दोनों में श्रेष्ठतर समाज-व्यवस्था का निर्माण किया जाय? लेकिन पूँजीवादी पण्डित इतने अनजान नहीं हैं कि वे यह भी न जानते हों कि समाजवाद और पूँजीवाद दोनों ही अपने-अपने वस्तुगत नियमों के आधार पर विकसित हो रहे हैं। और यह भी कि उनकी सामाजिक संस्थाएँ परस्पर उतनी ही पृथक् हैं जितने कि उनके वर्गों की विरोधी बुनियादें।

इस प्रकार के ‘संकर’ समाज के निर्माण के विषय में आरम्भ की गयी समस्त चर्चा का स्पष्ट उद्देश्य जनता को इस निष्कर्ष से परे ले जाना था कि पूँजीवाद से समाजवाद में सफ़्रमण अनिवार्य है। लेकिन समरूपता के प्रवक्ता इसे कितना ही बड़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत क्यों न करें कि पूँजीवाद तथा समाजवाद के कौन-से दोष नष्ट

हो जायेगे और कौन-से गुण रह जायेगे और विकसित होंगे, चर्चा सदा इस ओर मुड़ जाती थी कि 'सकर समाज' पूँजीवादी व्यवस्था के मुख्य रूपों का—उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और पूँजी का—प्रभुत्व बना रहेगा। चाहेजितनी खोज की जाय, चीजों को बड़े आकार में दिखाने वाले कांच से भी देखा जाय आपको उसमें समाजवाद का एक दाना भी नहीं मिलेगा।

सारांश में, समरूपता के भाष्यकार समाजवाद के विद्यमान रहने के अधिकार को उसी सीमा तक मान्यता देते हैं जिस सीमा तक वह औद्योगिक समाज में पूँजीवादी आदर्श के अनुसार धीरे-धीरे विकास करता रहे। उदाहरण के लिए, अमरीकी विद्वान वाल्टर एस० बर्किघम जूनियर निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हुए स्पष्ट रूप में कहते हैं—“...पूँजीवाद की चार बुनियादों में से तीन शुद्ध पूँजीवाद से आगे ले जायी जाती है और नये रूप में उदीयमान आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित कर ली जाती है। प्रथम, पूँजी, कारखाना तथा उपकरण में निजी सम्पत्ति वैसे-वैसे बढ़ती जाती है जैसे-जैसे उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं में उद्योग का विस्तार होता है यद्यपि इसको जनशक्ति तथा यातायात सेवाओं के जरिये आंशिक रूप से और आगे बढ़ाया जाता है। दूसरे, आर्थिक प्रेरणाएँ और लाभ को प्रोत्साहन सुस्थापित हो जाते हैं और भावी कर-नीतियाँ उनको सुदृढ़ करने वाली प्रतीत होती हैं। तीसरे, बाजार की व्यवस्था सर्वत्र वस्तुओं और सेवाओं के विनियोजन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य यांत्रिकता के रूप में अपनी प्रभावशीलता प्रमाणित कर देता है।”¹

जिबग्निएव ब्रजेजिन्स्की तथा सेमुएल हंटिंगटन और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं : “पश्चिम में, ...व्यापक रूप से प्रचारित समरूपता के सिद्धान्त की मान्यता है कि भविष्य में किसी अनिश्चित ऐतिहासिक अवसर पर अमरीका एव रूस के 'समरूप' होने के बाद जनतंत्र के बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण पहलू बने रहेंगे...”। इस प्रकार निकट से परीक्षा करने पर पता चलेगा कि तथाकथित समरूपता के अधिकांश सिद्धान्त वास्तव में समरूपता के रूप में न माने जाकर विरोधी व्यवस्था के विलय के रूप में माने जाने चाहिए।”²

और अन्ततः मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय में रूसी अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक ए० सी० मेयर प्रश्न के सारतत्त्व इस रूप में स्पष्ट करते हैं : “समरूपता के सिद्धान्त को तानाशाही (समाजवादी देशों में राजनीतिक व्यवस्था के लिए परिभाषित शब्द, धी० के०) तथा सिद्धान्त (अर्थात् मार्क्सवाद-लेनिनवाद—धी० के०) की काट के रूप में देखा जाता है : और आगे “पश्चिमी समरूपता के सिद्धान्त में

1. वाल्टर एस० बर्किघम जूनियर, थ्योरिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स : ए क्पेरेटिव एनेलिमिस, न्यूयार्क, 1958 पृ० 485
2. जिबग्निएव ब्रजेजिन्स्की और सेमुएल पी० हंटिंगटन, पोलिटिक्स पावर : यू० एस० ए० यू० एस० ए० आर० न्यूयार्क 1964, पृ० 419

बड़ी मात्रा में यह मान्यता अन्तर्निहित है कि पश्चिमी समाज और विशेष रूप से अमरीकी समाज आदर्श है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयास सभी समकालीन समाज कर रहे हैं।¹

तथापि, पूँजीवादी समाज विज्ञान के सभी पण्डित इस सीमा तक स्पष्ट नहीं हैं। इसके विपरीत, उनमें से अधिकांश तो समरूपता के सिद्धान्त के वास्तविक अर्थ को छिपाने की कोशिश करते हैं और इसे—दो व्यवस्थाओं के समरूप विकास के विचार को—समाजवाद को दी जा रही रियायत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति की उपलब्धियों के सम्बन्ध में अनुमान लगाते हैं और इस तथ्य के सम्बन्ध में भी कि उत्पादक शक्तियों का विकास वास्तव में कुछ समान रूप की समस्याएँ उत्पन्न करता है। इसी के साथ-साथ दोनों व्यवस्थाओं के बीच दुनियादी वर्ग-भिन्नताओं के सम्बन्ध में वे मौन रहते हैं, इस विचार का उपयोग करते हैं कि समाजवाद और पूँजीवाद दोनों विभिन्न रास्तों से नजदीक आते जा रहे हैं।

निस्सन्देह मुख्यतया इस दखलन्दाजी का उद्देश्य समाजवाद का विरोध है। क्योंकि जब सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों की उपलब्धियों से अधिक समय तक इन्कार नहीं कर सकते, तो समाजवाद के पूँजीवादी आलोचक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वे इस बात से इन्कार करते हैं कि ये उपलब्धियाँ समाजवादी सामाजिक सम्बन्धों पर निर्भर हैं और वे सामान्यतः औद्योगिक विकास के मात्र विशिष्ट सुधारों के रूप में इस अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। और औद्योगिक विकास समाजवाद और पूँजीवाद दोनों में लगभग अथवा अधिकांश में समान है। समाजवाद एवं पूँजीवाद के बीच भिन्नताओं के सम्बन्ध में उनका कहना है कि इसकी व्यवस्थाओं में नहीं अपितु केवल विकास की मंजिल के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे ही समाजवाद उत्पादन के स्तर में पूँजीवाद को 'पकड़ लेता' है धीरे-धीरे ये भिन्नताएँ अदृश्य हो जाती हैं।

साथ-ही-साथ, पूँजीवादी प्रचार-चालवाजी तथा सचाई को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के उपायों द्वारा हमें इस निष्कर्ष पर लाना चाहता है कि यद्यपि समाजवाद औद्योगिक समाज के दो रूपों में से एक है तथापि यह वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के मामले में पूँजीवाद की अपेक्षा कम संवेदनशील है। इससे भी आगे, उनके अपने तरीके के अनुसार जब वे विभिन्न समाज-व्यवस्थाओं वाले देशों के विभिन्न प्राविधिक और वैज्ञानिक संकेतकों की तुलना करते हैं तो हमारे विरोधी इस तथ्य के सम्बन्ध में मौन धारण किये रहते हैं कि पूँजीवादी देश उच्च वैज्ञानिक

1. ए० सी० मेयर 'थ्योरीज ऑफ कन्वर्जेंस' चेंज इन कम्युनिस्ट सिस्टम स० चापसं
जॉनसन स्टैण्डर्ड, कैलिफोर्निया 1970 पृ० 320, 324

एवं प्राविधिक स्तर उपस्थित कर रहे हैं तो आर्थिक क्षेत्र में, सदियों के विकास में महानतकष जनता का पाशविक शोषण और दूसरे देशों की लूट के फलस्वरूप, तथापि समाजवाद पूरी तरह अपने निजी आंतरिक संसाधनों के बल पर विकास कर रहा है और उसे केवल साठ वर्ष हुए हैं (यदि हम विश्व के प्रथम राज्य को ध्यान में रखें तो)। साथ ही, इस दौर में भी बहुत से और अत्यधिक कठोर वर्ष उसे झेलने पड़े हैं—गृह युद्ध, विदेशी हस्तक्षेप को पीछे हटाना, द्वितीय विश्वयुद्ध जिसके फल-स्वरूप अत्यधिक आर्थिक विध्वंस हुआ तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के वर्ष।

पश्चिमी अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री बड़ी सावधानी के साथ इस तथ्य से कतराकर निकल जाते हैं कि सोवियत संघ सहित कई देशों में अर्धविकसित पूंजीवाद की स्थितियों में समाजवादो क्रान्ति विजयी हुई। जिसके कारण, अनेक क्षेत्रों में—औद्योगीकरण शुरू किया गया, मजदूर वर्ग का और बुद्धिजीवियों का निर्माण हुआ, सार्वभौम शिक्षा के लिए प्रावधान तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य—'पूँजीवाद के काम' समाजवाद ने किये। दूसरे शब्दों में, इसे वे काम भी पूरे करते हैं (वेशक, अपने तरीकों से और अतुलनीय रूप से अधिक त्वरा के साथ) जो विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत पूँजीवादी समाजों में पूरे किये जा चुके हैं।

दूसरी ओर, पूँजीवादी विचारक पूँजीवाद के बचाव के लिए समरूपता के सिद्धान्त का ध्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इस सिद्धान्त का मूल्य इजारेदार पूँजीपति वर्ग के लिए इस तथ्य में निहित है कि यह उसको पूँजीवाद के 'पुराने' पापों से जिनसे कि उसने मजदूर वर्ग के देखते-देखते स्वयं समझौते किये थे, अपने को मुक्त करने का मौका देता है। इस लक्ष्य से, बूर्ज्वा प्रचार एक सीधी-सादी चालाकी करता है: वास्तविकतावादी मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए यह समान मात्रा में समाजवाद और पूँजीवाद दोनों की गलतियों को खिलाफ़ अपने को प्रदर्शित करता है। निर्णय की शब्दावली कठोर होती है और ऊपरी तौर पर दोनों व्यवस्थाओं को अस्वीकार करती है। तथापि, समस्त चालबाजी समाजवाद के खिलाफ़ काम आती है। पूँजीवाद की तात्कालिक व्यावहारिकता के मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाता बल्कि आज राजकीय 'इजारेदारी की मंजिल की स्थिति में ही नहीं अपितु इससे पूर्ववर्ती मंजिल की भी आलोचना की जाती है।

बूर्ज्वा पण्डित पुराने (शास्त्रीय) पूँजीवाद के विरुद्ध दोषारोपण करते हैं और तुरन्त बहने लगते हैं कि यह जीर्ण हो गया है। लेकिन वे ऐसा साहसिक निष्कर्ष केवल इसलिए निकालते हैं ताकि वे इसकी आधुनिक मंजिल को पुराने 'परम्परागत पूँजीवाद' का विषय बहकर प्रस्तुत कर सकें, जिसकी प्रत्यक्षरूप में पुराने में कोई समानता नहीं हो। जहाँ तक अद्यतन पूँजीवाद का सम्बन्ध है इसके सिद्धान्तकार दम्भ के साथ घोषणा करते हैं कि यह निरन्तर महानतकष जनता के

हितों की ओर बढ़ रहा है और समाजवाद के श्रेष्ठ पहलुओं को अपने में सम्मिलित करने में सक्षम है, स्वयं समाजवाद से भी अधिक सफलता के साथ ।

ये सभी विचार श्रोताओं को ध्यान में रख कर विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किये जाते हैं । पूँजीवादी देशों की मेहनतकश जनता के लिए ये 'औद्योगिक समाज' के सम्बन्ध में प्रवचनों के रूप में सामने आते हैं प्रविधि पर पूर्ण निर्भरता का सुझाव देते हुए । इसके पीछे सोच यह है कि मजदूर और पूँजी के बीच वर्तमान मुख्य अन्त-विरोध को सुलझाया जाय, जिसमें कि आगे चलकर विश्वयुद्ध के खतरे को समाप्त किया जा सके । और भी, दो व्यवस्थाओं की इस ममरूपता को दोनों व्यवस्थाओं के बीच सैनिक संघर्ष के एकमात्र विकल्प के रूप में देखा जाता है । इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के लिए ये विचार 'अफ्रीकी' या 'एशियायी' समाजवाद के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके आधारभूत तत्त्व तीसरी दुनिया के निम्न पूँजीवादी समुदायों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं जो एक ही समय में दो परस्पर पूर्णतया भिन्न व एकात्मिक कार्यभारों—निजी सम्पत्ति के एकीकरण के तथा बड़ी पूँजी के जुए से मुक्ति प्राप्त करने के कार्यों—को साथ-साथ पूरा करने की सम्भावना का भ्रम पाले हुए हैं ।

समाजवादी देशों की आबादी में प्रसारित वस्तुव्यो में वे विभिन्न रूपों—जनतांत्रिक, 'उदार', 'मानवीय' समाजवाद के सुधार के रूपों—में दिखायी देते हैं । सारी योजना समाजवादी समाज को विकसित करने की आड़ में भीतर से तोड़ने के लिए है ।

आमतौर पर, विशेष रूप से, समाजवादी देशों तथा कम्युनिस्ट पार्टियों के विषय में प्रचार का लक्ष्य होता है कि सामाजिक जीवन के विसंद्धान्तिकरण से इसको घनिष्ठ रूप से जोड़कर किसी भी उपाय से उनमें राष्ट्रवाद की भावना सुलगायी जाय ।

समाजवादी विश्व के विषय में इसकी सभी कार्यनीतियों की फिर से परीक्षा करने के लिए विवश होकर साम्राज्यवाद ने अपनी कम्युनिस्ट विरोधी कार्यवाहियों के अत्यधिक परस्पर विरोधी पहलुओं में कुछ सुधार किये हैं अनेक पश्चिमी राज-नयिकों ने एक नया और अधिक लचीला राजनीतिक मार्ग तैयार करने की आवश्यकता की बात उठायी है ।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति जॉन एफ कॅनेडी द्वारा 1960 में प्रकाशित पुस्तक 'शांति की कार्यनीति' (द स्ट्रेटजी आफ पीस) में और अधिक स्पष्टता के साथ यह विचार प्रकट किया गया है । "पोलेण्ड में—और लौह-आवरण में दिखायी देने वाली किसी अन्य दरार में—घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता के बीज बोने के लिए, हम सावधानी के साथ शान्तिपूर्वक अपना काम धीरे-धीरे शुरू

कर सकते हैं।¹ केनेडी के उत्तराधिकारी लिण्डन जॉनसन इस योजना के सम्बन्ध में अधिक सजग थे। उन्होंने 'शान्तिपूर्ण तनाव' या 'पुलों के निर्माण' की धारणा को संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारी विदेश नीति का स्तर प्रदान किया और उसको सभी समाजवादी देशों के मामले में समस्त पश्चिमी शक्तियों की संयुक्त नीति के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया। लैंकिसगटन, वर्जीनिया के वर्जीनिया मिलिटरी इस्टीम्यूट(सैनिक सस्थान) में मई 1964 में भाषण देते हुए जॉनसन ने कहा : "हम पूर्वी यूरोप से हमको पृथक् करने वाली खाई को पार करने के लिए पुल बनाने का काम जारी रखेंगे। वे पुल होंगे विचारों के बढ़ता हुआ व्यापार के, दर्शकों (यात्रियों) के और मानवीय आधार पर सहायता के।"² इस स्थापना की जो व्याख्या की गई वह विशुद्ध निहित स्वार्थों पर आधारित थी। संयुक्त राज्य अमरीका की इजारेदार पूंजी से और कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। जल्दी ही व्यवहार से इसकी पूर्णतया पुष्टि होगयी।

यद्यपि परवर्ती काल में इस कार्यक्रम को अनेक बार संशोधित और परिवर्तित किया गया लेकिन इसके मुख्य अंश आज तक भी साम्राज्यवादी शक्तियों की कथित पूर्वीय नीति के मार्गदर्शक के रूप में अवस्थित है। जहाँ तक इस नीति के सैद्धान्तिक पहलू का प्रश्न है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। सैद्धान्तिक सेवाओं को छद्म उदारता के विचारों के प्रसार के लिए तथा समाजवादी विश्वदृष्टिकोण को ध्वस्त करने के उद्देश्य से जनमत की जाँच करने के लिए आगे ले आया गया है।

सर्वाधिक घातक प्रहार विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर किये गये जो समाजवादी विश्व समुदाय और विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की एकता के सशक्त स्पष्ट थे : मार्क्सवाद-लेनिनवाद सभी देशों के कम्युनिस्टों की सैद्धान्तिक एकता के सुदृढ़ आधार के रूप में, मजदूर वर्गों की और उसकी पार्टियों की नेतृत्वकारी भूमिका, जो सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के विचार को आगे बढ़ाती है, और समाजवादी समुदाय के अनुभवों का सार्वभौम महत्व। ये सभी घटक अविधान्त सैद्धान्तिक बमबारी के लक्ष्य बने।

लेकिन जब पूंजीवाद दो व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक सघर्ष में समाजवाद को परास्त करने में सफल नहीं हो पाता तो वह अपनी सैद्धान्तिक सुरक्षा के प्रयास बढ़ा देता है। इसे सामाजिक प्रक्रिया के विश्लेषण को सैद्धान्तिक और वर्गीय अर्थ से पृथक् करने के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयासों के साथ जोड़ देता है।

यह सच है कि समय-समय पर, विशेष रूप से इस समय, पश्चिम में निरन्तर आह्वान किये जाते रहे हैं—मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सामाजिक विकास के

1. जॉन एफ केनेडी, द स्ट्रेटजी ऑफ पीस, स० एलन नेबिन्स, न्यूयार्क 1960, पृ० 18

2. द न्यूयार्क टाइम्स, 24 मई 1964

व्यावहारिक (सकारात्मक) सिद्धान्त के प्रति तुलन के लिए 'सिद्धान्त की ओर वापस मुड़ो', इसे पूंजीवादी मनोवृत्ति की ओर 'वापस लाओ'।

वैश्वक, इन आह्वानों को समझा जा सकता है। सैद्धान्तिक संघर्ष की ओर विशुद्ध रूप से व्यावहारिक रुख के जरिये कभी भी कोई क्रियात्मक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हाल के वर्षों में पूंजीवादी जगत को दुनिया में जिन प्रहारों का सामना करना पड़ रहा है (सामाजिक-राजनीतिक अन्तर्विरोध की तीव्रता, वियतनाम में अमरीका की हार, 1974-75 का संकट आदि), इनसे यह अधिकाधिक प्रमाणित होता जा रहा है कि केवल 'प्राविधिक समाधानों' से वास्तव में कुछ नहीं सुलझाया जा सकता। हमारे समय की क्रांतिकारी शक्तियों के शक्ति-शाली उभार की स्थितियों में, सामाजिक जीवन के विसैद्धान्तिकीकरण की धारणा क्रियात्मक रूप में अधिकाधिक असफल होती जा रही है और कभी-कभी तो वह स्वयं साम्राज्यवादी सिद्धान्तों को ही अपनी गोली का निशाना बना देती है। यह न तो जनता को क्रियाशील बना सकती है और न उनका सकल विश्वास ही प्राप्त कर सकती है।

इस प्रकार, पुनःसिद्धान्तिकरण के नारों का प्रयोजन उच्च आदर्शों और लक्ष्यों की निरन्तर खोज ही होता है। 'न्यू स्टेटमेण्ट' नामक ब्रिटिश पत्रिका ने 1975 के अन्त में लिखा था : "1976 का विश्व एक संकट भरे भयानक दौर में प्रवेश कर रहा है। सम्पन्नता की राजनीति इसे अधिक समय तक नहीं बचा सकती। इसके स्थान पर हमारी पोल अभाव की राजनीति के रूप में अधिकाधिक खुलती जा रही है और इसके गम्भीर दबाव अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दिखायी देंगे। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम औद्योगिक युग के अन्त की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें साहस, कल्पनाशीलता एवं दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारा संक्रमण अधिक उपयुक्त समाज में सहज भाव से होगा, आकस्मिक विप्लव द्वारा नहीं।

"हमें इतिहास के प्रति नयी दृष्टि की आवश्यकता है। हमें इस आश्वासन की आवश्यकता है कि हमारे सिर पर खड़ा भविष्य चुनौतियों से भरा होने पर भी संतोषप्रद होगा।"

तथापि इस प्रकार के नारों में कुछ भी नया नहीं है। और वे सदा अतीत की तरह भली किन्तु निष्फल आकांक्षाएँ ही बनी रहेंगी, इगमें कोई संदेह नहीं है। वृज्वा सिद्धान्तकार पूंजीवाद के समर्थन के नये विविध रूपों के अतिरिक्त नया

विचार देने में अममय है।

सतही तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक सिद्धान्त के स्थान पर दूसरा रखा जा रहा है। लेकिन वास्तव में, विचारधारा (सिद्धान्त) की भूमिका को ही अस्वीकार करना (विसिद्धान्तिकीकरण) और इसके महत्व को स्वीकार करना (पुनः सिद्धान्तिकीकरण) कम्युनिज्म विरोध के ही दो पक्ष हैं। दोनों ही के प्रयासों का लक्ष्य है कम्युनिस्ट विचारधारा के विरुद्ध कठोर संघर्ष के लिए, मजदूर वर्ग की विचारधारा का विरोध करने वाले वैचारिक मतों के प्रसार और प्रचार के लिए, वर्ग-संघर्ष और सामाजिक क्रांति से संबंधित मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षाओं के विरोध के लिए जनता पर वैचारिक प्रभाव डालने के समस्त साधनों को संयुक्त करना। यदि हम 1960-1970 के बीच पूंजीवादी पंडितों द्वारा आविष्कृत लोक-प्रचलित वैचारिक सिद्धान्तों की परीक्षा करें तो हम आसानी से इस तथ्य को देख सकते हैं।

राष्ट्रवाद पर दाव

कम्युनिज्म के 'विशेषज्ञों' में एक अमरीकी विद्वान् एच० गोर्डन स्किलिंग की अति विशिष्ट अनुशांसा के अनुसार 'कम्युनिज्म के सम्बन्ध में हमारा रवैया कुशलता-पूर्ण और संयत होना चाहिए। शोर भरे प्रचार और हस्तक्षेप के खतरे से बचते हुए तथा कम्युनिस्ट समुदाय के भीतर राष्ट्रीय कम्युनिज्म के शांतिपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए।

—(जोर हमारा—बी० के०)¹

जर्मन मार्क्सवादी गुंथर रोज का विचार था : "यूरोप के समाजवादी देशों के विरुद्ध 'सैद्धान्तिक आक्रमण' का कार्यनीतिक लक्ष्य विचारधारा के क्षेत्र में परिवर्तनों को तीव्र करना है जो, समरूपता के सिद्धान्त के अनुसार, जनसंख्या में प्राविधिक क्रांति के कारण स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं और उसको विसैद्धान्तिकीकरण की वांछित दिशा में ले जा रहे हैं" ये इस विचार को मन में जमा देने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवाद का पूंजीवाद की दिशा में तथाकथित परिवर्तन प्राविधिक क्रांति की वस्तुगत प्रक्रिया है और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और रोकने के बजाय समर्थन करना चाहिए..... (समाजवादी देशों की—बी० के०) आंतरिक सहृदयता के लिए किये गये प्रयत्नों का परिणाम यह होगा कि इनकी विदेश नीति राष्ट्रवादी लक्ष्यों एवं प्रवृत्तियों की अपील के रूप में पूर्ण बन

जायगी।¹

यह पिछला मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्युनिस्ट आन्दोलन के युनियादी सिद्धान्त—सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का ही मूलोच्छेद करता है। लियोनिद ब्रेझनेव ने कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में कहा था : साम्राज्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा-एकता की शक्ति से सुपरिचित है। “इसीलिए समाजवादी शक्तियाँ, क्रान्तिकारी आन्दोलन से सघर्ष करते हुए राष्ट्रवाद पर भरोसा करते हैं। वे आशा करते हैं कि इसके जरिये कम्युनिस्ट आन्दोलन को बारहवाँट कर देंगे, क्रान्तिकारी दस्तों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देंगे।”

बूज्वा राष्ट्रवाद अपने नाना रूपों में—जैसे महाशक्तियों का अध राष्ट्रवाद, स्थानीय राष्ट्रवाद, नस्लवाद, सार्वदेशिकतावाद आदि—सदा ही प्रतिगामिता का हथियार रहा है। जैसा कि लेनिन ने लिखा था : “पूँजीवादी राष्ट्रवाद और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद में दोनों पूरे पूँजीवादी विश्व में दो बड़े वर्गों के शिविरो के परस्पर कट्टर विरोधी नारे हैं जो राष्ट्रीय प्रश्न पर दो नीतियों को (या दो विश्व दृष्टिकोणों को) व्यक्त करते हैं।”² हाल के वर्षों में साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद विशेष रूप से राष्ट्रवाद को मड़काने के अपने प्रयासों में विशेष रूप से क्रियाशील है जिससे कि इसे कम्युनिज्म विरोध एवं सोवियत विरोध की सम्पूर्ण प्रणाली का अंग बना दिया जाय। विसंद्धान्तिकीकरण और पूँजीवादी राष्ट्रवाद की धारणा को साथ-साथ सजाने के प्रयास इसके साक्ष्य हैं।

बूज्वा पण्डित राष्ट्रवाद को एक ऐसी समस्या समझते हैं जिसके सम्बन्ध में वर्गीय, सामाजिक-आर्थिक या ऐतिहासिक भौतिकवादी रवैया अंगीकार नहीं किया जा सकता। वे समस्त सामाजिक-आर्थिक कसोटियों को या तो रही की टोकरी में डाल देते हैं या उनको विरुद्ध कर देते हैं। वे देशभक्ति के मुकाबले अन्तर्राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं और राष्ट्रीय स्वायत्तता के मुकाबले जनवादी केन्द्रीयता का; अन्तर्राष्ट्रवाद के मुकाबले सार्वदेशिकतावाद पर अधिक ध्यान देते हैं, देशभक्ति को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं आदि। यह सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विरोध शाश्वत और असमाधेय है, वे विषुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक कारण प्रस्तुत करते हैं जो मानव स्वभाव के अन्तर्निहित अहंकार से अंतर्कर्म प्रवृत्तियों से या अज्ञेय विशिष्ट परम्पराओं से उद्भूत होते हैं, वह तर्क करते हैं कि न तो उनका सामाजिक

1. देखें—फारेन माफिस्ट्स इन द स्ट्रगल अगैस्ट बूज्वा आइडियलाजी, मास्को 1971, पृ० 206 (रूसी में)

2. इन्टर्नेशनल भीटिंग आफ कम्युनिस्ट एंड वर्कर्स पार्टिज, मास्को, 1969, प्राग, 1969 पृ० 74

3. वी०आई० लेनिन, “क्रिटिकल रिमाक्स ऑन दि नेशनल क्वेश्चन” कलेक्टिड वर्क्स खंड 20 पृ० 26

विश्लेषण संभव है, और न नियंत्रण ।

पूँजीवादी प्रचार राष्ट्रीयताओं के सवाल को विसंज्ञान्तिकीकरण के चौखटे में क्यों रखता है इसको भली-भाँति स्पष्ट किया जा सकता है । क्योंकि इससे उनको मार्क्सवाद-लेनिनवाद के उन बुनियादी रूप से नये लक्षणों पर आक्रमण करने के लिए सुविधाजनक स्थिति प्राप्त होती है जिन्हें कि उसने आधुनिक युग की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या के विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने के लिए सम्मिलित किया है ।

जैसा कि जीवन स्वयं प्रदर्शित करता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, सामान्य और विशेष के युग्म, किसी भी प्रकार अपना महत्व नहीं खोते लेकिन इसके विपरीत अनेक नये रंग ग्रहण करते हैं, जैसे-जैसे मानव समाज पूँजीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होता है । ये प्रश्न मजदूर वर्ग और मुक्ति आंदोलन तथा जनवादी आंदोलनों की प्रत्येक धारा में विभिन्न समुदायों में व्यावहारिक संघर्ष की तात्कालिक प्रमुखता प्राप्त कर लेते हैं । वास्तव में इससे भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता जब हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में पहले से ही भारी मात्रा में दाहक सामग्री विद्यमान है तथा देशों और जनगण के बीच सामाजिक राजनीतिक स्तर पर मतभेद विद्यमान हैं और हर मामला अपना विशिष्ट राष्ट्रीय रूप प्रस्तुत करता है ।

इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयताओं के प्रश्न के समाधान की प्रक्रिया एक ओर तो जनगण के क्रान्तिकारी अनुभव से समृद्ध होती है और दूसरी ओर प्रधान रूप से निम्न पूँजीवादी प्रकृति की, प्रायः गंभीर-आत्मगत गलतियों और विकृतियों को पैदा करती है ।

अतीत में, ऐतिहासिक युगों के समस्त दौर में, राष्ट्रीयताओं का प्रश्न सामान्य जनतांत्रिक सुधारों के ढाँचे के आगे नहीं बढ़ पाया । सर्वथा स्वाभाविक रूप से इन सीमाओं के अन्तर्गत बहुत-सी धारणाएँ पूँजीवादी जनतांत्रिक स्थिति की आवश्यकताओं से घिरी थी जो मजदूर जनता में उभर आयी या उनमें उत्पन्न कर दी गयी ।

वर्तमान युग में, राष्ट्रीयताओं के प्रश्न का समाधान अपने द्वन्द्वात्मक विकास में पुरानी सीमाओं से बहुत आगे पहुँच गया है । समग्र समस्या के अंग के रूप में मानव समाज के उस आंदोलन की सामान्य प्रक्रिया में विशिष्ट स्थान है जो अपने संक्रमणकालीन एवं मध्यवर्ती रूपों की समस्त भिन्नताओं में पूँजीवाद से समाजवाद के लिए चलाया जा रहा है ।

राष्ट्रीयताओं की समस्या का नया सारतत्त्व इसके संबंध में नये रूख की आवश्यकता प्रदर्शित करता है, जहाँ एक ओर मेहनतकश जनता का अग्रणी भाग है जो कम्युनिस्टों का अनुगामी है वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के निर्देशों के द्वारा प्रवर्तित परि-

वर्तनों का अनुसरण करता है, दूसरा भाग, जो अब तक पूंजीवादी निम्न पूंजीवादी परम्पराओं और विचारों से प्रतिबद्ध है वह साम्राज्यवादियों और उनकी संशोधन-वादी कठपुतलियों के जाल में फँसा है। राष्ट्रीयताओं का प्रश्न समाजवाद और पूंजीवाद के बीच तीव्र वैचारिक संघर्ष का क्षेत्र है, पूंजीवादी और संशोधनवादी विचारधारा के विरुद्ध मार्क्सवाद-लेनिनवाद के संघर्ष का क्षेत्र में है।

राष्ट्रीयताओं की समस्या की जटिलता पर अटकलबाजी करते हुए पूंजीवादी और संशोधनवादी सिद्धान्तकार जल्दी से कह देते हैं कि इसका समाधान कम्युनिस्ट आंदोलन से नहीं किया जा सकता। सभी तरह के राजनीति वैज्ञानिक दावा करते हैं कि आत्मगत भूलें या कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद से अलग हो जाना स्वाभाविक हैं और सामाजिक विकास के अनिवार्य लक्षण हैं। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस क्षेत्र में कम्युनिस्टों के सिद्धान्तिक नियम अमान्य हैं। जहाँ तक कि 'राष्ट्रीयताओं के प्रश्न के समाधान का समाजवाद के व्यावहारिक अनुभव की बात है उसकी आमतौर से उपेक्षा कर दी जाती है।

इस सम्बन्ध में, साम्राज्यवाद के तथा आधुनिक संशोधनवाद के सिद्धान्तकार जहाँ तक संभव हो सकता है इस समस्या के विसिद्धान्तीकरण के लिए मुख्य रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। वे मजदूर वर्ग को इस मुख्य मार्क्सवादी-लेनिनवादी निष्कर्ष से पृथक् करने का प्रयास करते हैं कि 'राष्ट्रीय मुक्ति का प्रश्न, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का, राष्ट्रीय स्वाधीनता को मजबूत करने और विकसित करने का प्रश्न है यह कोई अलग-थलग समस्या नहीं है, अपितु विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का अभिन्न अंग है। जैसा कि लेनिन ने प्रस्तुत किया : आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ जनतंत्र की पृथक् भाँति कोई निरपेक्ष माँग नहीं है अपितु सामान्य जनतांत्रिक विश्व आंदोलन के (अब सामान्य समाजवादी आंदोलन के) छोटे भाग है।' राष्ट्रीयताओं की समस्या का सुसंगत एवं व्यापक समाधान अर्थात् राष्ट्रीय भेदभाव की पूर्णतया समाप्ति और राष्ट्रीयताओं की पूर्ण समानता केवल मजदूर वर्ग के नेतृत्व के अन्तर्गत ही संभव है। यह परिणाम समस्त देशों के मजदूर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता के फलस्वरूप ही प्राप्त किये जा सकते हैं। जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध सम-झौताहीन संघर्ष में ही उपलब्ध की जा सकती है।

यह इन स्थापनाओं के विरुद्ध है कि साम्राज्यवाद के सिद्धान्तकार लड़ रहे हैं। और यह इस कारण से ही है कि पूंजीवादी राष्ट्रवाद अधिकाधिक सोवियतवाद विरोधियों के साथ हाथ-में-हाथ मिलाकर चलता है और सोवियत विरोधी उकसावों ने राष्ट्रवादी बाना धारण कर रखा है। वास्तव में

समाजवाद के भीतरघात की कोशिश के लिए इस हथियार का उपयोग किया जाता है ।

किन्तु साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को चाहे जितना उकसाये, चाहे जितना ऊँचे से इसके सिद्धान्तकार मुक्ति आंदोलनों की अलग-अलग इकाइयों की 'स्वतंत्रता' के सम्बन्ध में या 'राष्ट्रीय कम्युनिज्म' के विषय में शोर मचाये यह सब किसी को भ्रम में नहीं डाल सकता । प्रतिगामियों ने सदा बूज्वा राष्ट्रवाद का उपयोग किया है—और इन दिनों पहले से कहीं अधिक—मुख्य वर्ग हित के साधन के रूप में और समाजवादी समुदाय को, विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को और सोवियत संघ के प्रभाव को कमजोर करने के लिए इसका प्रयोग किया है ।

प्राविधिक नियतिवाद के कल्पना लोक

मैं अवश्य बरबाद हो गया होता यदि स्वयं मेरे हाथों में शक्ति नहीं होती। मैंने अपनी ही चोटी पकड़ के स्वयं को और अपने घोंडे को जिसे मैं अपनी जाँघों के बीच खींच से पकड़े हुए था, दसदल से बाहर निकाला।

—जी० बर्गर बॅरॉन : मन्छासेन की 'मनोरंजक साहसिक यात्राएँ'

सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में प्राविधिक रवैया

कम्युनिज्म-विरोध के लिए नाना प्रकार के सर्वाधिक प्रचलित सिद्धान्तों का निर्माण 1960 एवं 1970 के वर्षों में 'औद्योगिकतावाद' अथवा 'प्राविधिक नियतिवाद' के सुपरिचित सिद्धान्तों के इर्द-गिर्द किया गया। मुख्य रूप से इसका अभिप्राय है कि पूँजीवादी व्यवस्था में सामाजिक और अन्य सभी विषयों पर प्राविधिक और औद्योगिक विषयों का प्राधान्य रहेगा। अन्तर्निहित स्थापना यह है कि आधुनिक पूँजीवाद का और फलस्वरूप सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं का विकास—पूँजीवाद के मौलिक नवीकरण का परिणाम होगा। इसका अभिप्राय समझा गया है कि यह मानव-समाज को समाजवाद को लाँघकर एकमात्र सार्वभौम औद्योगिक समाज तक और तत्पश्चात् 'औद्योगिकोत्तर' समाज की ओर ले जाएगा जो सिद्धान्त रूप से वर्ग विरोध एवं सामाजिक अन्तर्विरोधों से पूर्णतया मुक्त होगा।

इसकी पुष्टि में हर क्षमतावान पश्चिमी पण्डित अनेक मिथ्या वैज्ञानिक युक्तियाँ देता है जिनमें वह मार्क्सवाद के खण्डन का और उसको पीछे छोड़ देने का दावा किया करता है। इसमें वे मुख्यतया वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति के विविध पहलुओं को आधार बनाते हैं। पूरी तरह विसिद्धान्तिकीकरण के सामान्य विचार की भावना में भरे हुए वे कहते हैं कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति के कार्यों को पूरा कर रही है और इसलिए वह समाजवाद को

रद्द कर देती है। वे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करने वालों तक, मजदूरों तक विज्ञान एवं प्रविधि के पहुँचाए जाने का विरोध करते हैं और वर्ग-संघर्ष को अनावश्यक तथा अव्यवहार्य घोषित करते हैं और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षाओं को असामयिक (अथवा समय सापेक्ष) बताते हैं।

ये प्रयत्न अकस्मात् नहीं अपितु सुविचारित रूप से किये जाते रहे और हाल के वर्षों में इन्हे तेज किया गया, जैसे-जैसे पूँजी के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष बढ़ता गया और साथ ही आधुनिक पूँजीवाद को अपने ढाँचे के भीतर ही नये तीखे संघर्ष की प्रक्रियाओं की गंभीर परीक्षाओं का निरन्तर 'सामना' करना पड़ा। क्योंकि पूँजीवाद अपनी ऐतिहासिक पहलकदमी खो चुका था, इसके सिद्धान्तकारों के लिए एक विशेष स्थिति, जिसमें कि सैद्धांतिक संघर्ष में विजय की स्थिति में अधिक समय तक वे बने नहीं रह सकते थे, उत्पन्न हो गयी थी। विवश होकर उन्हें उस क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ा जिसमें पूँजीवादी समाज का भविष्य किसी भी प्रकार उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता, आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति के परीक्षा क्षेत्र में तथा उनकी अनुरूप व्याख्याओं में। यह पूँजीवाद के लिए सर्वाधिक घातक स्थिति है क्योंकि वैज्ञानिक प्राविधिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पादक शक्तियों के विकास में शक्तिशाली विस्फोट और साथ-ही-साथ गंभीर सामाजिक प्रक्रिया पूँजीवादी समाज के आधारों को ही अनिवार्य रूप से ध्वस्त कर देगी।

मार्क्स की एक स्थापना में कहा गया है: "नयी उत्पादन शक्तियों को ग्रहण करने के साथ ही मनुष्य अपने उत्पादन की पद्धति बदल देता है और उत्पादन की पद्धति परिवर्तित होते ही वे समस्त उत्पादन सम्बन्ध जो उस विशिष्ट उत्पादन पद्धति के अनुरूप थे परिवर्तित हो जाते हैं।"¹ यदि हम इस स्थापना को वर्तमान युग पर लागू करते हैं तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि हमारे युग की वैज्ञानिक प्राविधिक क्रान्ति पूँजीवादी सम्बन्धों को समाजवादी में परिवर्तित करने वाला मुख्य कारक है।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और वर्कर्स पार्टियों की (1960 की) बैठक के दस्तावेज में लिखा गया है: कि "वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति मानव समाज की प्रकृतिक पुनर्निर्माण की, असीम मात्रा में भौतिक संपदा उत्पन्न करने की और मनुष्य की रचनात्मक क्षमताओं को बहुगुणित करने की अभूतपूर्व संभावनाएँ प्रदान करती है।" और आगे कहा गया है कि "पूँजीवाद वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति का उपयोग अपने मुनाफ़े को बढ़ाने तथा मेहनतकश जनता का शोषण बढ़ाने के लिए कर रहा है—न सिर्फ दीर्घकाल से चले आ रहे पूँजीवाद के अन्त-

¹ 1. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेल्स, सिलेक्टड वारक्सोर्ट्स मास्को 1975, पृ. 31

विरोध तेज हो गये हैं, बल्कि कुछ नये अन्तर्विरोध भी उठ खड़े हुए हैं।¹ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्पादन की सामाजिक प्रकृति और इसके नियंत्रण की राज्य-एकाधिकार की प्रकृति के बीच अन्तर्विरोध सत्ता में बने रहते हैं (काम करते रहते हैं)। इसके साथ-साथ केवल श्रम और पूँजी के बीच संघर्ष का बढ़ना ही नहीं जारी रहता अपितु वित्तीय अल्पतंत्र और राष्ट्रों की विशाल बहुसंख्या के बीच विरोध गहरा होता जाता है। इन निष्कर्षों की पुष्टि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं (1971) तथा 25वीं (1976) कांग्रेसों ने की। आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति साथ-ही-साथ (एक ही समय में) पूँजीवादी और समाजवादी देशों में हो रही है किन्तु मेहनतकश जनता के लिए प्रत्येक व्यवस्था में भिन्न प्रकार के परिणाम दे रही है और परस्पर विरोधी सामाजिक परिणाम प्रदर्शित कर रही है। समाजवादी समुदाय के देशों में यह प्रत्यक्ष रूप से मेहनतकश जनता के हितों की सेवा कर रही है तथा कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार के निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण बन गयी है। पूँजीवादी राज्यों में, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति का उपयोग सर्वोपरि इजारेदारियों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए किया जाता है, जो निस्संदेह विज्ञान और प्रविधि की उपलब्धियों का उपयोग मेहनतकश जनता की भलाई के लिए नहीं अपितु अपने निजी मुनाफों को बढ़ाने के लिए करती हैं। परिणामस्वरूप, इजारेदार पूँजी की सम्पदा बढ़ती जाती है जबकि मेहनतकश जनता की सामाजिक आवश्यकताएँ अतृप्त ही बनी रहती हैं। इससे पूँजीवादी समाज में वर्ग-संघर्ष और तीव्र होता है और अंतिम परिणति में मेहनतकश जनता को समाजवादी क्रान्ति तक ले जाता है। इस प्रकार आधुनिक उत्पादक शक्तियों के विकास में क्रान्तिकारी छलांग विश्वव्यापी रूप में उत्पादन की कम्युनिस्ट पद्धति के भौतिक आधार के निर्माण के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

लेकिन स्वभावतः पूँजीवादी विश्व में विद्यमान शक्तियाँ इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में निश्चित नहीं रह सकती। उनकी सेवा में लगे सिद्धान्त-शास्त्री अनेक छद्म-वैज्ञानिक धारणाओं द्वारा इस संभावना का विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। निस्संदेह, इस सबके पीछे साम्राज्यवाद तथा समाजवादी क्रान्ति के साथ इसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया की व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षाओं के खण्डन का विचार रहता है।

पूँजीवादी सिद्धान्त शास्त्रियों के चित्रण के अनुसार वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का रूप या तो मसीही होता है अथवा राक्षसी। उनका कहना है कि मनुष्य स्वयं अपनी मुक्ति सुनिश्चित कर सकता है।

—या तो स्वयं को विज्ञान और प्रविधि के विकास के लिए (विशेष रूप से

रोस्तोव, गालब्रैथ, बैल, ब्रजेज़िन्स्की की एवं टॉफनर द्वारा प्रस्तावित 'औद्योगिक' अथवा 'औद्योगिकोत्तर समाज' के सिद्धान्त में प्राविधिक प्रबन्धक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के रूप में) अपने को अधीनस्थ बनाने की कीमत पर।

—अथवा विज्ञान और प्रविधि के विकास को कृत्रिम रूप से रोक कर (जैसे रोम के क्लब के सदस्यों की भाँति)

—या अन्ततः पूर्णतया भिन्न मूल्यों के मानदण्ड की पोज करके और 'जीवन की गुणवत्ता' सुधार कर।

इन सिद्धान्तों की सीमाएँ परस्पर इतनी निकट हैं और कभी-कभी परस्पर गुथ जाती हैं। साथ ही ब्रूजर्वा विचार के सामान्य विकास के दृष्टिकोण से ये भिन्न विकास का मार्ग ग्रहण कर लेती हैं। पूँजीवादी विश्व में और विशेष रूप से इसके विकास की संभावना के संबंध में स्थिति के अत्यधिक आघावादी दृष्टिकोण से अतिनिराशावादी दृष्टिकोण के मूल्यांकनों तक। यह विकास साक्ष्यिक और शिक्षाप्रद है।

1960 में पूँजीवाद के विकास के अपने मूल्यांकन में ब्रूजर्वा पण्डितों में आशावादी धारा प्रधान थी। विकसित पूँजीवादी देशों में अनुकूल आर्थिक स्थिति बन रही थी जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दसियों वर्ष बाद इस प्रकार का उचित वातावरण बनता दीख रहा था।

वर्तमान शताब्दी में अन्य किसी भी समय से अधिक मात्रा में स्थिर पूँजी का पुनर्नवीकरण, श्रम शक्ति के विस्तार के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के उपयोग और मेहनतकश जनता के शोषण के नये रूपों के विकास इसी प्रकार 'तीसरी दुनिया' के देशों को लूटने के नवऔपनिवेशिक तरीकों और व्यापक 'राज्य-इजारेदारी, आर्थिकता के विनियमन आदि इन सबने कई वर्षों तक विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के उच्च रूप से औद्योगिकीकृत क्षेत्र के विकास को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। समाजवाद के साथ प्रतियोगिता ने पूँजीवादी देशों के सत्ताधारी अर्थतंत्र को पूँजीवादी समाज के सभी संभव संघर्षों को और अधिक समेकित करने को मजबूर किया। फलस्वरूप पूँजीवादी विश्व के कुछ भागों ने उत्पादन कौशल में कुछ वृद्धि प्राप्त की, आर्थिक सुधार, और जीवन-स्तर में एक निश्चित वृद्धि प्राप्त की।

साम्राज्यवादी सिद्धान्तकारों ने दूरगामी मनोरम परिणाम निकालने में जल्दबाजी की। वे इससे अधिक या कम की घोषणा करने को ही तैयार नहीं हुए कि पूँजीवाद का नया युग आरम्भ हो गया है। उनका कहना था कि मार्क्सवादियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पूँजीवाद के आश्चर्यजनक पुनरुत्थान का आधार दुनिया भर में व्याप्त औद्योगिकीकरण की शक्तिशाली लहर का दिखायी देना ही था। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने दावा

किया कि इसने पूंजीवाद को जीवनदायिनी शक्तियों से भर दिया है। गुणात्मक वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रवेग के फलस्वरूप पूंजीवाद को (लेनिन के सिद्धान्त के विपरीत) और आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। अपने दूसरे प्रवाह को प्राप्त कर वह स्पष्ट रूप से इसके दोषों को दूर करने के लिए इस उत्तोलक का उपयोग करते हुए इसे 'सार्वभौम समृद्धि' वाले समाज में क्रमशः विकसित कर रहा था। इस सिद्धान्त के तर्क के अनुसार ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि यह पूंजीवाद है।

मोटे तौर से मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के विरोध के लिए निम्न योजना प्रस्तावित है। दूसरी औद्योगिक क्रांति दुनिया को औद्योगिकीकरण के अदम्य प्रवाह में बहा ले गई है। इस क्रांति ने आधुनिक समाज के समस्त सामाजिक-राजनीतिक भिन्नताओं को और अंतर्विरोधों को वस्तुतः बराबर कर दिया है और स्वतः ही यह मानव समाज को 'जन-उपभोग' की समृद्धि की ओर ले गया है। विभिन्न स्तरों पर इस आश्चर्यप्रद भविष्य का पथ शुरू हो रहा है। इसी लिए, औद्योगिकीकरण के विभिन्न प्रारूप प्रस्तुत हो रहे हैं। वेशक, अंततोगत्वा ये सब 'सार्वभौम समृद्धि' की स्थिति जैसे अकेले समाज की ओर बढ़ेंगे जो संयुक्तराज्य अमरीका में तथाकथित रूप से निर्मित हो चुका है। कुख्यात वैचारिक मतान्धता इस अप्रगामी आंदोलन को रोक ही रही है क्योंकि औद्योगिक विवशताओं (बाध्यताओं) के वेग को न तो सिद्धान्तकार ही भलीभांति समझ सकते हैं न राजनीतिज्ञ ही; अपितु सिद्धान्त और राजनीति से पृथक् एवं ऊपर खड़े प्राविधिक कुलीन ही समझ सकते हैं।

इसके अलावा, औद्योगिकीकरण को पूंजीवाद के समस्त सामाजिक अंतर्विरोधों के समाधान को स्वतः पूर्व निर्धारित शक्ति के रूप में स्वयं प्रेरित शक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। जैसा कि—1960 के आरंभ में औद्योगिकीकरण और उसके परिणाम के संबंध में पुस्तक लिखने वाले लेखकों ने कहा था—और यह एक विशिष्ट बात है—“दुनिया एक नए युग में, पूर्ण औद्योगिकीकरण के युग में प्रवेश कर रही है। अब हमारे समय में कम्युनिज्म का भूत जिसने यूरोप को आतंकित कर रखा था, नहीं ठहर सकता अपितु इसके बजाय नाना रूपों में औद्योगिकीकरण उभर रहा है जो सारी दुनिया के सामने है। औद्योगिकीकरण का दानव पुराने और परंपरागत समाज के प्रायः सभी रूपों को परिवर्तित करते हुए पृथ्वी पर इठला रहा है।” (जोर हमारा—वी० के०)¹

जहाँ तक 'नये युग' के सारतत्व की बात है विभिन्न लेखकों ने इसे विभिन्न रूप से देखा है : उदाहरण के लिए, कुछ (फ्रांसीसी समाज शास्त्र रेमण्ड आरौ) इसे

1. इंडस्ट्रियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल मैन, द प्रोब्लम्स ऑफ़ लेबर एंड मैनेजमेन्ट इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ब्लांक केरे, जॉन० टी० डनलप, फ्रेडरिक एच० हार्बिसन एंड चार्ल्स ए० मेयर्स हाइनमेन, लन्दन 1962, पृष्ठ 9, 11।

'औद्योगिक समाज' कहते हैं, तथा अन्य (अमरीकी राजनीति वैज्ञानिक डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्तोव) इसे 'सामूहिक जन उपभोग की स्थिति' कहते हैं, और कुछ दूसरे (फासीसी सशोधनवादी आर० गैरॉदी) इसे समाजवाद कहते हैं। लेकिन यह कहने में ये सब एकमत है कि वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के प्रभाव से पूँजीवाद की प्रकृति परिवर्तित हो गई है और इसके वर्ग अंतर्विरोध समाप्त हो गए हैं। समाजवाद भी बदल रहा है, प्राथमिक रूप से यह पूँजीवाद की दिशा में बदल रहा है। और इसी क्रम में दोनों सामाजिक व्याख्याएँ एक 'औद्योगिक समाज' के अंतर्गत एकाकार हो जाएँगी।

सुधारने, परिपूर्ण बनाने अथवा 'यथार्थ रूप से' इसकी व्याख्या करने के यद्वाते, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सैद्धांतिक रूप से उन्मूलन के लिए उपकरण के रूप में प्रयुक्त इन प्रस्थापनाओं (आधार वाक्यों) से, कुकरमुत्ते की तरह बहुत से सिद्धांत पैदा हो गए हैं—जो सार रूप में कम्युनिज्म विरोधी हैं तथा जो विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति में वैज्ञानिक कम्युनिज्म की जीवन्तता को एकमत से नकारते हैं।

आधुनिक पूँजीवाद के सिद्धांतकार सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के नियमाधीन रूपांतरणों से संबंधित मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षाओं की बुनियादों की ही काट कर देना चाहते हैं। यही उनके आक्रमण का मुख्य निशाना है। और सामाजिक संबंधों के विकास में उत्पादक शक्तियों की यही भूमिका है कि वे उनमें से अधिकांश को विसैद्धांतिकीकरण अथवा 'आर्थिक भौतिकवाद' की स्थितियों से—भ्रष्ट (विकृत) कर देते हैं। सार रूप में, वे सामाजिक प्रक्रिया की समस्त जटिलता को उत्पादन प्राविधिकता के कारकों और उपभोग के स्तर तक नीचे ले आते हैं। वे उत्पादक-शक्तियों (और जिनमें से वे मनमाने ढंग से मुख्य तत्त्व को—स्वयं उत्पादकों को अर्थात् मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को अलग कर देते हैं) तथा उत्पादन संबंधों के बीच द्वंद्वात्मक संबंध को धृष्टतापूर्वक छिन्न-भिन्न कर देते हैं। वे उत्पादन की शक्तियों और संबंधों की एकता को कृत्रिम रूप से पृथक् कर देते हैं और सामाजिक विकास को अलग कर देते हैं, जिसे कि उन्होंने सीधे-सीधे प्राविधिक प्रगति के साथ जोड़कर उसके वर्ग-सार से रिक्त कर दिया है।

एक सीमा तक इस प्राविधिक धारा के सभी प्रतिनिधियों का, सबसे बढ़कर रोस्तोव, गैलब्रेथ, वेल, टॉफ़लर जैसे अमरीकी राजनीतिक वैज्ञानिकों का, रवैया एक सा है। 1960 से 1970 के बीच जिन सिद्धांतों को लेकर वे सामने आए उनका विस्तृत आलोचनात्मक विश्लेषण अनेक सोवियत लेखकों की कृतियों में पाया जाता है जिनमें सोवियत विद्वानों की तीन भागों वाली संकलित ग्रंथावली भी सम्मिलित है जिसका 'शीर्षक है—द स्ट्रुगल ऑफ़ आइडियाज़ इन द मॉडर्न

वर्ल्ड ("वर्तमान विश्व में विचारों का संघर्ष") उन्होंने इनकी समीक्षा "विचार-धारा और राजनीति" (आइडियो एंड पॉलिटिक्स)¹ में भी की है पर भिन्न दृष्टिकोण से।

तथापि, इन पर एक और दृष्टि में (प्रायः उन्हीं लेखकों की नई कृतियों और वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए), हात्स के वर्षों में पूंजीवादी वर्ग के सामाजिक विचारों के विकास की सामान्य धारा पर विचार करना भी उपयुक्त होगा।

'औद्योगिक समाज'—निराधार आशाएँ

डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्तोव को औद्योगिक समाज के सिद्धांत का जनक माना जाता है। सही तो यह है कि उसने इस 'जीवन रक्षक' विचार का आविष्कार नहीं किया। इसकी कतिपय प्रस्थापनाएँ बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के और 19वीं सदी की उत्तरार्ध के पूंजीवादी और सुधारवादी लेखकों की कृतियों में देखी जा सकती है। जैसे : हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कांटे, अलैक्सैंडर डि तांकुविले, मैक्स वेबर, रुडोल्फ हिल्फडिंग, जॉन कीन्स, जेम्स बर्नहम और अन्य। लेकिन औद्योगिक समाज के सिद्धांत को अंतिम रूप रोस्तोव की कृति "आर्थिक उन्नति की अवस्थाएँ : गैर कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र (द स्ट्रेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एनान् कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो) से प्राप्त हुआ जो पहले-पहल 1960 में प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण बात क्या है? वह यह है कि उस काल में इसे पूंजीवादी प्रचारकों ने कम्युनिज्म विरोध के वैचारिक उपकरणों में प्रमुखता दी। निस्संदेह यह भी अकारण नहीं था कि रोस्तोव ने अपनी कृति का उप शीर्षक दंभपूर्ण तरीके से रखा—एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। उसने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि वर्तमान स्थितियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांत का स्थान सामाजिक विकास के एक 'अत्याधुनिक' सिद्धांत में ले लिया है।

रोस्तोव ने सामाजिक-राजनीतिक संरचनाओं के संबंध में मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षाओं के मुकाबले मानव समाज के विकास की अपनी योजना प्रस्तुत की। उनका कहना है : सभी समाजों की पहचान उनके आर्थिक आयामों से जो प्राचीन श्रेणियों में से किसी में भी विद्यमान रहते हैं, की जा सकती है : परंपरागत समाज

1. द स्ट्रगल ऑफ आइडियाज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड (वीन जिल्डो में), मॉडर्न कैपिटलिज्म: कंट्राडिक्शन्स एंड डॉक्ट्रिन्स (अदर द जनरल एडीटरशिप ऑफ एफ० कोसोवित्स्की) मास्को, 1976 (रूसी संस्करण)

2. वी० कोर्तुनोव 'आइडियालोजी एंड पॉलिटिक्स' द स्ट्रगल ऑफ आइडियाज़ एंड इवोल्यूशन ऑफ एन्टी कम्युनिस्ट आइडियालॉजिकल कांसेप्ट्स इन् 1950-1970 मास्को, 1974 (रूसी में)

प्रस्थान के लिए पूर्वं स्थितियाँ (वह इसको समाज का मंत्रमण कालीन युग भी कहते हैं—वी० के०), प्रस्थान, परिपक्वता की ओर परिचलन और उच्च जन उपभोग का युग।”¹ ये स्थापनाएँ अपेक्षाकृत सुपरिचित बन गई हैं, जनता के मस्तिष्कों में सचेष्टता के साथ बँटाई गई हैं तथा विभिन्न पाठ्य-पुस्तकों में और अन्यत्र लिखी गई हैं।

लेकिन यहाँ खास बात क्या है: रोस्तोव के मत के अनुसार, प्रत्येक वस्तु “उच्च सामूहिक उपभोग के युग” में परिणत हो जाती है, जहाँ कि समस्त उच्च रूप से विकसित औद्योगिक समाज क्रमशः एक में विलीन हो जाते हैं। रोस्तोव कहते हैं: यह एक दौर है जिनसे अमरीकियों का उदय आरंभ हुआ है, जिसकी अस्पष्ट प्रसन्नताओं की पश्चिमी यूरोप और जापान उरसाहपूर्वक पड़ताल आरंभ कर रहे हैं और जिसके साथ सोवियत समाज असहज प्रेम प्रदर्शन में व्यस्त है।²

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान के भविष्य की रोस्तोव को खरा भी चिंता नहीं है। उन सबके भंडार में पृथ्वी पर एक स्वर्ग रखा है, उच्च सामूहिक उपभोग के समाज के रूप में। बेशक, इस प्रकार, वह सोवियत संघ के संबंध में चिंता अनुभव करते हैं जहाँ कि उन्हें सोवियत समाज के लिए सामूहिक संपन्नता के राज्य तक पहुँचने में ही बाधा दिखाई देती है। वह बाधा है कम्युनिज्म। एक ओर, रोस्तोव तर्क करते हैं: इस समय सोवियत संघ उच्च सामूहिक उपभोग के युग के लिए प्राविधिक रूप से उद्यत समाज है। यह संरचनात्मक रूप में अपनी श्रम शक्ति की शिक्षा और कौशल की शब्दावली में उद्यत है...लेकिन दूसरी ओर, उनका मानना है कि जो चीजें पूंजीवादी देशों में सामूहिक उपभोग की ओर ले जा रही हैं उनका समाजवादी जगत् में उचित उपयोग नहीं किया जा रहा। वह चिंता-पूर्वक कहते हैं कि इसका कारण है कि कम्युनिज्म समाज का ऐसा रूप है जो “वृद्धि की समस्या के केवल आपूर्ति के पक्ष के लिए ही उपयुक्त है लेकिन उपभोग पक्ष की प्रगति के लिए नहीं।”³ इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के युग में सोवियत संघ विकास में अन्य राज्यों से न पिछड़ जाय इसलिए उसे अपनी विचारधारा और राजनीतिक संगठन से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

दूसरे शब्दों में, विकास की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित प्राविधिक प्रगति के ‘विशिष्ट आदेश’ पूरी विश्वसनीयता के साथ पूंजीवाद में ही कार्य करते हैं, जो

1. डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्तोव, द स्टेटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नान-कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैम्ब्रिज, 1967, पृष्ठ 4

2. वही, पृष्ठ 10

3. वही, पृष्ठ 133

स्वभावतः ही, इसके अनुकूल परिणामों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती हैं। जहाँ तक कुछ समाजवादी देशों की बात है यद्यपि उन्होंने औद्योगिक विकास का ऊँचा स्तर प्राप्त कर लिया है, पर वह उनके लिए काफी नहीं है। प्राविधिक आधुनिकता की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए उन्हें राज्य इजारेदारी पूँजीवाद के कुछ नियम अनिवार्यतः स्वीकार करने होंगे।

इस प्रकार रोस्तोव के निष्कर्षों में पूँजीवाद का उचित समर्थन, एक ऐसे समय में जबकि प्राविधिक प्रगति दो व्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष प्रतियोगिता का क्षेत्र बनती जा रही है, वैज्ञानिक कम्युनिज्म के लिए सैद्धांतिक विकल्प प्रस्तुत करने के प्रयास में बदल जाता है। इस स्थापना से रोस्तोव का सिद्धांत एक समय में तीन समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करता दिखाई देता है। यह मिश्र करके कि प्राविधिक प्रगति पूँजीवाद के विरुद्ध मेहनतकश जनता को वर्ग संघर्ष की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, सोवियत अनुभव को अविश्वसनीय बना देता है वह निस्संदेह विश्व समाज-व्यवस्था के विकास के लिए अमरीकी जीवन पद्धति को सर्वोच्च शिखर घोषित करते हैं।

जॉन केनेथ द न्यू इंडस्ट्रियल सोसायटी (नया औद्योगिक समाज) (1967) में इस सदी के उत्तरार्ध में प्राविधिक नियतिवाद की स्थिति से 'औद्योगिकीकरण' के सिद्धान्त के लिए आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रकार से यह जॉन कीन्स की इस शती के पूर्वार्ध में पूँजीवादी सम्बन्ध की राज्य इजारेदारी पद्धति का स्मरण दिलाता है जो उनकी पुस्तक 'द जनरल थियरी ऑफ एंफ्लायमेंट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी' में निरूपित है।

गालब्रेथ 'औद्योगिक' समाज की संपूर्ण आर्थिक संरचना की व्याख्या के लिए प्राविधिक नियतिवाद से आरंभ करते हैं। हम इस प्रस्थापना को ध्यान में रख सकते हैं "आर्थिक परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया की परीक्षा के लिए प्राविधिक ज्ञान स्वयं अपनी पहलकदमी की क्षमता के कारण उसके भीतर प्रवेश के लिए एक तर्क संगत बिन्दु है लेकिन प्रविधि परिवर्तन का कारण ही नहीं है, परिवर्तन का प्रत्युत्तर भी है।"¹ फलस्वरूप, गालब्रेथ की मुख्य स्थापना यह है कि वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति 'औद्योगिक राज्य' की अर्थव्यवस्था में योजना के नियमों के विकास को स्वयं पहले से निर्धारित कर देती है। परिणामस्वरूप बड़ी इजारेदारी, ट्रेड यूनियन और राज्य की अन्तःक्रिया में एक प्रकार का आदर्श सतुलन कायम कर देती है जिसको पूरे समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। परिपक्व नियम जो स्पर्धा समाप्त करते में सक्षम है, बाजार-अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के साथ, और उसके प्रमुख अंग बन जाते हैं।

इस प्रकार, गालब्रेथ के अनुसार, अधिकतम लाभ (मुनाफ़ा) पूँजीवादी उत्पादन

की मूल प्रेरणा नहीं रहती अपितु प्रविधि एवं परियोजना की माँगें उसकी प्रेरक बन जाती हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था में प्रभावी पक्षों का प्रश्न है, वे उनके विधिसम्मत स्वामियों के हाथ से निकलकर सुप्रशिक्षित प्रशासनिक तथा प्राविधिक माध्यमों को प्राप्त हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि अधिकाधिक लाभ (मुनाफ़े) में रुचि रखने वाले पुराने उद्योगों को उत्पादन के नियन्त्रकों की सूची से पृथक् करके उसके स्थान पर प्रविधिज्ञों के अपरिचित समुदाय (प्राविधिक संरचना) को रख दिया जाता है जिसकी रुचि मुनाफ़े की रक्षा में नहीं बल्कि अपनी सत्ता बनाए रखने में होती है सिद्धान्त रूप से ये सामान्य हितों की देखभाल करते हैं—सामूहिक उत्पादन की प्रमत्तः वृद्धि तथा मूल्यों में कमी के द्वारा बाजार का विस्तार जिससे समस्त जनगण को लाभ पहुँचे।

यह काल्पनिक संरचना वास्तविकता से बहुत दूर है। रोस्तोव के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत की भाँति ही मालवेंच का आविष्कृत कम्पनालोक (जो आधुनिक पूँजीवाद के आयोजन के तत्त्वों का परिचय, प्रबन्धकों की बढ़ती हुई भूमिका, संपदा के आकारहीन नैगम रूप जैसे वस्तुतः विद्यमान कतिपय तत्त्वों पर आधारित है) मुख्य बात की—पूँजीवादी पुनरुत्पादन के वस्तुपरक नियमों की—उपेक्षा करता है। तथापि, ये नियम तेज़ी से तीव्र होते हुए प्रतियोगितारमक सघर्ष का निजी पूँजी से सामना कराते हैं जिसके दौरान हर व्यापारी अधिकतम मुनाफ़ा कमाने का प्रयास करने के लिए विवश होता है। और बाजार की माँग की कोई भी भविष्यवाणी, कोई 'प्रवृत्तकीय क्रान्ति' चाहे वह 'अतिपरिपक्व' निगमों के विद्यमान रहते हुए ही पैदा हुई हो—इस स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती।

और न प्राविधिक नियतिवाद के पक्ष-पोषक ही इस तथ्य से बच सकते हैं, भले ही उन्होंने अपनी सैद्धान्तिक संरचनाओं में माक्स से उधार लिये इस विचार को अपना आधार बनाया हो कि उत्पादक शक्तियों का विकास ही ऐतिहासिक प्रगति का आधार है। वस्तुतः वे इस विचार को पूर्णतया विकृत कर देते हैं, इस अर्थ में वे उत्पादन सम्बन्धों से उत्पादन शक्तियों को पृथक् कर देते हैं और किसी एक या अन्य सामाजिक-राजनीतिक रूप से उनके संबंधों को विच्छिन्न करके उस पर बहस करते हैं। वे सम्पत्ति की प्रकृति, सामाजिक संबंध, वर्ग-शक्तियों के संतुलन और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कमौटियों की उपेक्षा करते हैं तथा इन सबके स्थान पर जनसंख्या के कतिपय घटकों के जरिए प्रति व्यक्ति उपभोग के यांत्रिक संकेतों को प्रस्थापित कर देते हैं।

यहाँ हम इस बात से इन्कार नहीं कर रहे हैं कि वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति और उपभोग का स्तर समाज के विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतक हैं। किंतु वे कितने भी वास्तविक हों, हैं तो सामान्य स्थिति के अंश मात्र ही। उदाहरण के लिए, क्या कोई इन मूलभूत सक्षमों को, जिन पर कि वह आधारित है, छोड़कर वर्तमान

पूँजीवादी उत्पादन का सही वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकता है, - इसके सम्मुख लक्ष्य क्या है ? यह किनके हितों की पूर्ति करता है ? इस पर किसका स्वामित्व है ? क्या केवल उपभोग के स्तर से मेहनतकश जनता के भौतिक कल्याण को मापना उचित है ? क्या श्रम शक्ति के विस्तार, श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन के लिए धन में निरन्तर वृद्धि, सामान्यतया आधुनिक मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की जा सकती है ?

तथापि रोस्तोव, गालव्रेथ और 'उद्योगवाद' के अन्य धुरन्धरो ने यही मार्ग ग्रहण किया। सामाजिक प्रक्रिया का सर्वांगीण विश्लेषण करने के स्थान पर वे प्रायः मनमर्जी से चुनी हुई कतिपय घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और इसी आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका में और समस्त पूँजीवादी विश्व में पूँजीवादी वास्तविकता का भ्रामक चित्र खींचते हैं और उसके भविष्य के संबंध में भविष्यवाणियाँ करते हैं। इन स्थापनाओं में बृज्वा पण्डित एक समस्या के समाधान की बार-बार कोशिश करते हैं जैसे कोई गोलाकार को वर्गाकार बनाने का, असंगत को संगत करने का, प्रयास कर रहा हो। 'सार्वत्रिक समृद्धि' के समाज में, जिसे कि वे संयुक्त राज्य अमरीका में पहले से ही अर्थात् अमरीका की तीसरी शताब्दी के आरम्भ से ही निर्मित मानते हैं, वे एक ही समय में व्यापार में अधिकाधिक मुनाफ़ा तथा मेहनतकश जनता के लिए वृद्धिमान उपभोग का वायदा करते हैं। किंतु इसमें कोई सदेह नहीं कि यह कितनी ही अतिरंजित कलाकृति क्यों न हो, यह एक स्वप्नलोक ही है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पूँजीवाद के नियम और उसका दैनिक व्यवहार इस प्रकार की सभादना को ही समाप्त कर देता है। पूँजीपतियों के समाज का समस्त इतिहास, जिसमें अमरीकी समाज भी सम्मिलित है, इसका प्रमाण है।

संयोगवश, 1776 में, जिस वर्ष कि संयुक्त अमरीका ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, स्कॉटलैंड के प्रोफ़ेसर एडम स्मिथ अपनी प्रसिद्ध कृति "राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की जाँच" (इन्क्वायरी इनटु द नेचर एण्ड काजेज ऑफ द वैल्यू ऑफ नेशन्स) प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने अपने समय की पूँजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की व्याख्या की थी।

पूँजीवादी आर्थिक विचार धारा के जनक इस बात के पूरी तरह कायल थे कि प्रतियोगिता के लाभप्रद प्रभाव के अंतर्गत पूँजीवादी संबंधों के विकास में निश्चित रूप से उद्यमियों द्वारा कम-से-कम कीमत पर अच्छी-से-अच्छी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयास सम्मिलित होंगे और इस प्रकार आम जनता के कल्याण में निरन्तर उभार सुनिश्चित होगा। यह स्वीकार करते हुए कि प्रतियोगिता को निबन्ध स्वातंत्र्य प्रदान किया जाए जैसाकि प्रकृति ने स्वयं वस्तुओं के क्रम में किया है। उन्होंने बड़ी आशा के साथ अपनी कृति 'निपुलता की बाइबिल' (बाइबिल

ऑफ एप्लुएन्स) में सामूहिक उत्पादन के उत्थान, समस्त वैयक्तिक हितों में समन्वय और सभी के लिए चिंतामुक्त एवं सुरक्षित जीवन की पूर्वकल्पना की थी।

इस प्रकार, 'सामूहिक उपभोग' के समाज की घोषणा एक प्रकार से दो सौ वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी, ठीक उस समय जब कि संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे राज्य का निर्माण आरंभ करने जा रहा था जिसे कि 'स्वतंत्र उद्योग' वाले राज्य के आदर्श के रूप में मान्यता दी जानी थी।

वर्तमान काल में, पूँजीवादी व्यवस्था के रक्षक क्रमशः पूँजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्रोतों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन आदर ग्रंथों के विपरीत, वे स्वयं को इजारेदार पूँजी के प्रत्यक्ष समर्थन के घेरे में अधिकाधिक बन्द करते जा रहे हैं। कोई भी आरम्भगत लक्ष्य 'औद्योगिक' और 'औद्योगिकोत्तर समाज' के मिथक में अन्तर्निहित नहीं हों, सार रूप में इसकी सब विविधताएँ ऐसे प्रयास प्रमाणित हो रही हैं जो उन्नत विधि और प्रविधि सहित अथवा नई उत्पादन प्रबन्धक पद्धति सहित आधुनिक राज्य इजारेदारी को सामूहिक उपभोग की दृष्टि से लक्षित करती है। जैसी कि कहावत है, ये मायावी रंगों में पूँजीवाद के अस्तित्व को दीर्घजीवी बनाने के प्रयास हैं।

इन प्रयासों ने इस सत्य को ही प्रमाणित किया है कि हमारे समय में पहले कभी की अपेक्षा पूँजीवाद को पुनः स्थापित करने का कोई भी प्रयास अधिक जटिल और कम प्रभावशाली होगा। प्रचार की मिथ्या गायियों के माध्यम से प्रदर्शित 'सामूहिक उपभोग' की सफल और उज्ज्वल संभावना समय की कसीटी पर खरी नहीं उतरी है। जीवन ने इस मनोरंजक कथा की उपेक्षा कर दी है। और इसके कारण पूँजीवादी विश्व को ऐसे जटिल अन्तर्विरोधों का सामना करना पड़ेगा जो वस्तुतः इसके क्रिया-कलाप के प्रत्येक पहलू को अपने में लपेट लेंगे। 1970 के दशक के पूँजीवादी सिद्धान्तकार पूँजीवाद की पुरानी व्याधियों के लिए चिकित्सा के नए नुस्खे तैयार करने के लिए अन्य सिद्धान्तों की खोज करते रहे। ऐसे समय में जबकि पूँजीवादी विश्व अन्तर्विरोधपूर्ण घटना क्रियाओं के प्रवाह में बहता जा रहा है उन्होंने अपने जिम्मे एक जटिल और सामान्यतया अव्यावहारिक कार्य भार—मजदूर वर्ग के सामाजिक आदर्शों को पूँजीवाद की वास्तविकताओं के साथ मिलाने का—ले लिया है। उनमें से कुछ अब भी प्रविधि के सहज विकास पर अपनी आशाएँ लगाए बैठे हैं, इसके विपरीत, दूसरों की दृष्टि में यही समस्त संकटों का कारण है, लेकिन उनमें से लगभग सभी पूरी तरह प्राविधिक रख को त्यागना पसन्द नहीं करते और आधुनिक पूँजीवाद के विश्लेषण में सामाजिक एवं वर्गीय पक्षों को सुनियोजित तरीके से नजरन्दाज कर देते हैं।

श्रेष्ठतर भविष्य की आशाओं और साथ ही वर्तमान के लिए लौछटन दोनों की ही वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के साथ जोड़ दिया गया है। इस संबंध में अमरीका

के प्रमुख इतिहासकार आर्थर श्लेसिंजर का वक्तव्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है : "यदि समुक्त राज्य अमरीका में आज अन्य कहीं की भी अपेक्षा अत्यधिक उत्कट संकट दिखायी देता है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के चरित्र के कारण नहीं अपितु, उन शक्तियों के कारण है जिनको कि विज्ञान और प्रविधि द्वारा लाया गया है जैसाकि दूसरी जगह कहीं नहीं हुआ है। प्राविधिक विकास में अत्युन्नत राष्ट्र के रूप में अमरीका ने ही पहले-पहल क्षिप्रगामी परिवर्तन का अजस्र आघात और विप्लवकारी गहनता का अनुभव किया। हम जिन सकटों में जी रहे हैं वे आधुनिकता के सकट हैं। कोई भी राष्ट्र जब प्राविधिक विकास की अपेक्षाकृत उच्च स्थिति को प्राप्त करना आरम्भ करता है तब उसे अपेक्षाकृत इसी प्रकार के सकटों का सामना करना पड़ता है।" इस प्रकार औद्योगिक समाज के सकट का निपेद्य नहीं किया गया, बल्कि इसे प्रगति के अनिवार्य पुरस्कार के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जहाँ तक श्रेष्ठतर समय की आशाओं का संबंध है, उन्हें कुछ थोड़ा और आगे भविष्य के लिए बढ़ा दिया गया है और अब उनका संबंध अद्यतन औद्योगिक समाज से इतना अधिक नहीं रहा जितना कि इसके स्थान पर आने वाली सामाजिक व्यवस्था का।

क्या 'औद्योगिकोत्तर समाज' मुक्ति है ?

औद्योगिकोत्तर समाज की नई सुप्रचारित अवधारणा के जनक अमरीकी समाजशास्त्री डेनियल बेल थे। हरमन काहन, स्विग्निएव ब्रजेजिन्स्की, जॉन गॉलब्रेथ, रेमण्ड आरॉ, एडोल्फ बर्ले और जीन फ़ौरेस्टी सहित अन्य अन्वेषकों ने भी इस अवधारणा को विकसित करने में कठिन श्रम किया। लेकिन इसकी सर्वाधिक पूर्ण व्याख्या बेल की न्यूयॉर्क में 1970 में प्रकाशित कृति-द कमिंग ऑफ़ पोस्ट इण्डस्ट्रियल सोसायटी, ए बेचर इन सोशल फ़ोरकास्टिंग में की गई। ठीक सामूहिक उपभोग समाज की अवधारणा की तरह ही औद्योगिकोत्तर समाज का विचार भी अनेक पहलुओं में पूँजीवादी पंडितों द्वारा पहले से प्रदर्शित विचारों की पुनरावृत्ति मात्र है। इस विषय में यह थोस्टॉन वेब्लेन की कृतियों में आशिक रूप से उठाया गया प्रश्न है लेकिन सर्वोपरि अमरीकी प्रोफ़ेसर जेम्स बर्नहम के, 'द मेनेजरियल रेवोल्यूशन' (प्रबंध में शक्ति) का प्रश्न भी है। विश्व में क्या हो रहा है— के माध्यम से इसे 1941 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थक बर्नहम ने उन्ही वर्षों में औद्योगिकोत्तर समाज के बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने समस्त उचित सीमाओं को लाँचकर उत्पादन में लगे उच्चाधिकारियों की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर बखानते हुए और मजदूर वर्ग की

क्रांतिकारी भूमिका को नकारते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद नहीं आएगा अपितु समाज के अन्य सामाजिक संगठन आएंगे।

इन प्रस्थापनाओं के आधार पर बेल औद्योगिकोत्तर समाज का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं और इसके पाँच विशिष्ट आयामों का उल्लेख करते हैं : प्रथम, माल-उत्पादन से सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन; द्वितीय, व्यावसायिक एवं प्राविधिक श्रेणी की श्रेष्ठता; तृतीय, समाज के लिए नवीकरण और नीति निर्माण के स्रोत के रूप में सैद्धांतिक ज्ञान की केन्द्रिकता, चतुर्थ प्रविधि एवं प्राविधिक मूल्यांकन का नियंत्रण तथा पंचम, नवीन 'बुद्धिवादी प्रविधि' की संरचना¹

इस व्यवस्था में बेल विज्ञान को प्रमुख स्थान देते हैं। वह लिखते हैं—'ठीक वैसे ही जैसे कि गत सौ वर्षों से व्यापारिक संस्थान बुनियादी संस्थान थे... विश्व-विद्यालय और इसी प्रकार के ज्ञान के संस्थान अगले सौ वर्षों तक केन्द्रीय संस्थान रहेंगे क्योंकि नवीकरण और ज्ञान के नये स्रोत के रूप में इनकी भूमिका है।'² वह आगे लिखते हैं "औद्योगिकोत्तर समाज की जड़े उत्पादन पद्धतियों पर विज्ञान के अक्षय प्रभाव में निहित है—और विज्ञान अर्ध स्वायत्त शक्ति के रूप में पूंजीवाद के आगे तक चलता जाएगा। इस संकेत से कोई कह सकता है कि वैज्ञानिक सपना, इसकी प्रकृति और इसके संगठन ऐसा प्रजीवाणु है जिसमें भावी समाज की प्रतिभा अन्तर्निहित है।'³

जैसे कि बेल इसे देखते हैं मानव समाज का समग्र इतिहास उत्पादन के एक रूप से दूसरे रूप की ओर अग्रसर है : कृषि से उद्योग और उद्योग से सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर। प्रत्येक अवस्था के अपने शक्ति के वितरण और सामाजिक संगठनों के लक्षणिक उत्कर्ष होते हैं। औद्योगिकोत्तर समाज में निर्णय वैज्ञानिकों एवं उच्चतम योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों—ज्ञान के धारकों—पर निर्भर होता है। इसके सिखर पर रहेंगे विश्वविद्यालय और अकादमिक केन्द्र। चुने हुए श्रेष्ठ 'राज नीतिक प्रबन्धक' साधुता और न्याय निष्ठा से समाज का मार्ग-दर्शन करेंगे।

जहाँ तक पूंजीपति और मजदूरों के शत्रुतापूर्ण वर्गों की बात है वे भी औद्योगिकोत्तर समाज में उसी प्रकार एकीकृत हो जाएँगे जैसे कि उत्पादन का वर्तमान वैज्ञानिक पुनर्गठन स्वयं पूंजीवाद को विलीन कर देता है। पहली स्थिति वैज्ञानिक स्थिति के रूप में क्रमशः साई जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे कि अपने समय में सामंती अभिजात वर्ग पूंजीपति वर्ग में विलीन हो गया, जबकि बाद वाली स्थिति

1. डी० बेल, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसायटी, ए वेंचर इन लोकल क्रोरनास्टिग न्यूयॉर्क, 1973, पृष्ठ 14

2. वही, पृष्ठ 344

3. वही, पृष्ठ 378

ऐतिहासिक पुरातत्व के रूप में परिवर्तित हो जाएगी अर्थात् इसका भाग्य वही होगा जैसाकि औद्योगिक समाज में कृषकों का हुआ। इसका परिणाम यह होता है कि बेल 'औद्योगिक' एवं 'औद्योगिकोत्तर' समाजों के अपने विश्लेषण में से उत्पादन संबंधों को तथा इसके बाद वर्ग-संघर्ष की श्रेणियों को ही गायब कर देते हैं।

व्यापार से राजनीतिक प्रबंध में सत्ता का पुनः वितरण व्यावहारिक रूप में किस प्रकार होगा? बेल इस सामान्य तथ्य को विस्मृत नहीं कर सकते कि वर्तमान पूँजीवादी समाज में वैज्ञानिक और प्राविधिक विचार इजारेदारियों की विशुद्ध व्यावहारिक भाँगों की सेवा करता है। वह इस अन्तर्विरोध से सुपरिचित है। और वह प्रायः वेब्लेन की आलोचना करते हैं जिन्होंने आधी सदी पूर्व केवल प्राविधिक संगठनों को आधार माना था। बेल ने लिखा था—यह श्रम-संघवादी विचार कि बीसवीं सदी में क्रान्ति केवल औद्योगिक उसट-फेर ही हो सकती थी—वेब्लेन के विचार में निहित भ्रान्ति का एक निदर्शन है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि सामाजिक प्रक्रियाएँ चाहे जितनी प्राविधिक हों समाज में परिवर्तन का निर्णायक बिन्दु 'राजनीतिक रूप में ही आता है। सत्ता अंतिम रूप से प्राविधिक के हाथ में नहीं आती बल्कि 'राजनीतिज्ञ के' इस प्रकार दो अन्य तत्व भी हैं—'राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाएँ—जो लेखक की कृति 'औद्योगिकोत्तर समाज का आगमन' के लेखक के अभिप्राय में इसकी सामाजिक संरचना के साथ विद्यमान है। लेकिन औद्योगिकोत्तर समाज को इन तीन क्षेत्रों में पुनः विभक्त करते हुए जिनमें से प्रत्येक बेल के मतानुसार स्वायत्त रूप में कार्य करता है, विषय को विल्कुल स्पष्ट नहीं करता। और उनका राजनीतिक प्रबंध के संबंध में यह कहना कि वह लंबे काल में राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त कर लेगा अधिक संतोषजनक न होने से स्वीकरणीय नहीं है। कोई सोच सकता है कि वेब्लेन के आलोचक बेल स्वयं उनके 'श्रम संघवाद के' विचार से ही विमोहित हो जाते हैं, जिसको वह छोड़ देते हैं।

बेल एक सीमा तक बेतावनी देते हैं विशेष रूप से भविष्यवाणी करने के संबंध में, और इस प्रकार के निष्कर्षों की उपेक्षा करते हैं जो एकदम निरपवाद प्रतीत होते हैं। लेकिन उनके साथी प्रो० जिबग्नि एवं ब्रज्जेन्स्की ऐसा नहीं करते जो औद्योगिकोत्तर समाज की अपनी धारणा के समर्थन में सर्वथा निरपेक्ष हैं। बेल की तरह ही वह सामाजिक प्रक्रिया तथा उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्राविधि एवं ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं और औद्योगिकोत्तर समाज की अवधारणा को प्राविधिक वैद्युतिक युग द्वारा रूपांतरित करके इस दृष्टिकोण को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि उनकी खोज सामान्यतया न्यूनाधिक मात्रा में

वैल, गालब्रेथ, रोस्तोव और 'प्राविधिक नियतिवाद' के अन्य समर्थकों द्वारा पुनः स्थापित प्रस्थापनाओं की ही छद्म भरी प्रतिलिपि है। ब्रजेज़िन्स्की दावा करते हैं कि यह समस्या के प्रति नया दृष्टिकोण है। वह घोषणा करते हैं कि प्रविधि एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों के बीच संयुक्ति मानव समाज के विकास में निर्णायक शक्तिपूर्ण हैं। उनका दावा है कि यह संयुक्ति केवल अर्थ-व्यवस्था को ही परिवर्तित नहीं करती अपितु मानव जीवन के सामाजिक 'सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों' को भी परिवर्तित कर देती है।

ऐसा रबैया लेखक को अपनी धारणा को नये रूप में प्रस्तुत करने योग्य बना देता है, और महत्वपूर्ण यह है, कि वह इस विचार को आगे बढ़ाते हैं कि 'प्राविधिक वैद्युतिक युग' पूरी तरह अथवा लगभग औद्योगिकोत्तर समाज का विपर्यय है तथा प्राविधिक वैद्युतिक युग की विजय (जिसमें कि उनके दावे के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका प्रवेश करना आरंभ कर रहा है) एक नये युग की शुरुआत है जो मानव समाज के इतिहास में मूल रूप में पिछले सभी युगों से सर्वथा भिन्न है। लेखक स्पष्ट रूप से बिशवास करते हैं कि प्रश्न को इस प्रकार प्रस्तुत करना उन्हें इस बात के लिए विवश करता है कि वह पूंजीवाद की विद्यमान वास्तविकता को इस प्रकार विश्लेषित करें कि वह स्वयं को भविष्य के प्राविधिक-वैद्युतिक युग के सम्बन्ध में गूढ़ अनुभावों में तल्लीन कर सकें। जहाँ तक वर्तमान संघर्ष का सम्बन्ध है लेखक उनका चित्रण बढ़ती हुई पीड़ा के रूप में करता है जो कि विश्वव्यापी मानवता के विकास की उच्चतर अवस्था के लिए विश्वव्यापी संक्रमण के लिए अनिवार्य है और ये पीड़ाएँ आने वाले युग में सामने आने वाली समस्याओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

दूसरे शब्दों के ब्रजेज़िन्स्की यह सिद्ध करना चाहते होंगे कि वर्तमान क्रांति के लिए संक्रमणकालीन युग को दोषी ठहराया जाना चाहिए जिससे कि मनुष्य समाज गुजर रहा है, न कि पूंजीवाद को। जैसे ही यह युग अपने हर्षप्रद अन्त तक पहुँचेगा, हर चीज कल्याण के लिए परिवर्तित हो जाएगी।

प्राविधिक-वैद्युतिक समाज में वैज्ञानिक और प्राविधिक ज्ञान जो वर्धमान उत्पादन क्षमताओं से संपन्न है जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए त्वरित गति से प्रवाहित होता है। इस 'सत्य' की खोज करके ब्रजेज़िन्स्की इसके समर्थन में कोई शंभोर तर्क प्रस्तुत करके स्वयं को और पाठकों को परेशानी में डाले बिना इसके आधार पर प्रस्थापनाओं की संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

प्राविधिक-वैद्युतिक समाज में औद्योगिक कार्य इसकी सेवा में प्रयुक्त होगा और साइबर्नेटिक्स तथा स्वचालन यंत्र विधि नियंत्रण में मनुष्य का स्थान ग्रहण करेगा। व्यवसायों के शीघ्र विलुप्त होने से सम्बन्धित समस्याएँ केन्द्रीय स्थान प्राप्त

करेंगी। "“अपेक्षाकृत सुरक्षित लेकिन क्षमता की दृष्टि से लक्ष्यहीन निम्न मध्यम वर्ग के मँले-कुचँले कपड़ों वाले लाखों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी।”¹ तथा उनके विश्राम के समय को संगठित करने और लाभांश में भागीदारी की समस्या का समाधान करना होगा। व्यक्तिगत क्षमताओं का उन्नयन 'सामाजिक प्रगति के लिए प्रस्थान बिन्दु' के रूप में सामाजिक सुधारकों का मुख्य लक्ष्य होगा।

ज्ञान शक्ति का एक साधन (उपकरण) हो जाएगा। विश्वविद्यालय चिन्तन-सागर बन जायेंगे : आयोजन के सामाजिक नवीकरण के स्रोत। जन प्रचार माध्यम के विकास का परिणाम तेजी से परिवर्तन के रूप में होगा। विश्व दृष्टिकोण की अस्थिरता 'सामाजिक विवादों को संख्यात्मक एवं मात्रात्मक आयामों में घटाने' के लिए बढ़ती हुई क्षमता सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक स्पष्ट रवैये की ओर ले जाएगी। औद्योगिक समाज में राजनीतिक पार्टियाँ सहयोग और अपेक्षाकृत सामान्य विचारधारात्मक कार्यक्रम के आधार पर बनायी जाएँगी। तथा ये राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित होंगी। प्राविधिक-वैद्युतिक समाज में जन-प्रचार माध्यम की सहायता से जनता की भावनाओं को प्रभावित करना और उनकी मनोवृत्ति को निमंत्रित करना संभव होगा। राष्ट्रभाषा के स्थान पर दूरदर्शन के प्रतीकों (प्रतिमाओं) द्वारा घटनाओं की अधिक सार्वजनिक और प्रभावशाली समझ की ओर बढ़ाया जा सकेगा। आर्थिक शक्ति का बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति में विलय होगा और वह निर्व्ययक्त हो जाएगी।

ब्रजेजिन्स्की के मत से नये समाज के निर्माण का पता विश्व की वास्तविकता के साथ मनुष्य के नए सम्बन्धों के आरम्भ से चलेगा जिसकी रोशनी में पुरानी अवधारणाएँ और उनके साथ पुरानी विचारधाराएँ अपना महत्व खो देंगी।

कुल मिलाकर, अपनी अंतिम प्रस्थापना को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत तर्क वही है जिसका उपयोग विसिद्धान्तिकीकरण की अवधारणा के समर्थक पहले ही कर चुके थे। भविष्य की विचारधारा सभी विचारधाराओं का उन्मूलन होगी। कारण यह कि, ठीक जैसे मार्क्सवाद ने औद्योगिक युग के लिए इस प्रकार का सिद्धान्त रचा वैसे ही हमारे समय ने भी अपनी क्रान्ति की निजी अवधारणा निर्मित की। प्राविधिक-वैद्युतिक युग में संक्रमण तीसरी अमरीकी क्रान्ति के सदृश है। पहली ने स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकृति दी। दूसरी ने खेतिहर एवं अंशतः दास स्वामित्व वाले समाज को शहरी औद्योगिक राष्ट्र में रूपांतरित किया। तीसरी ऐसी क्षिप्रगामी प्रक्रिया है जिसमें 'प्राग औद्योगिक', 'औद्योगिक' और 'प्राविधिक-वैद्युतिक' अमरीका का विलय हो रहा है।

इस निष्कर्ष द्वारा वह सिद्ध करते हैं कि प्राविधिक-वैद्युतिक अमरीका अनिवार्य रूप में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसका विरोध उसी प्रकार निष्फल होगा जैसे कि मशीनों के विरुद्ध लुड्डाइट आंदोलन हुआ था। और इससे भी बढ़कर अमरीका केवल अपने निजी हितों के लिए चिंतित नहीं है बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए चिंतित है। इसलिए ब्रजेजिन्स्की का दावा है कि यह अमरीका का विशिष्ट ध्येय है कि वह औद्योगिक राज्यों के समुदाय का निर्माण करे और उसका नेतृत्व करे।

ब्रजेजिन्स्की के 'प्राविधिक नियतिवाद' के विचार तथा उनके अनुरूप लक्ष्यों की देन को भी परिभाषित करना सरल है। जहाँ तक कि प्रश्न के सैद्धांतिक पहलू का सम्बन्ध है: वह किंचित परिवर्तित शब्दावली का उपयोग करते हुए इस विकास की उसी ज्ञात, अति सरलीकृत ऐतिहासिक प्रक्रिया—'प्राग औद्योगिक', 'औद्योगिक' और प्राविधिक-वैद्युतिक, (अर्थात् औद्योगिकोत्तर) को बहुराते मात्र है। उनका प्राविधिक-वैद्युतिक समाज का वर्णन मुख्य रूप से वैल की 'औद्योगिकोत्तर समाज' की परिभाषा का पुनः कथन मात्र है।

तथापि, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अमरीकी प्रोफेसर की रचनाओं को इस विषय पर लिखी गयी अन्य रचनाओं से भिन्न एवं विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं।

उनमें से एक है इसका सुस्पष्ट समर्पण का स्वभाव। ब्रजेजिन्स्की ने 'प्राविधिक-वैद्युतिक युग' को पाठक के समक्ष अमरीका के राज्य-इजारेदारी पूंजीवाद की प्रतिमा के रूप में प्रयुक्त किया है जो प्राविधिक रूप से आधुनिकीकृत है और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्तियों द्वारा सुदृढ़ की गयी है। वह बलपूर्वक कहते हैं कि प्राविधिक-वैद्युतिक युग अमरीका का युग है जो समाजवाद के अस्तित्व को आरंभ से ही नकार देता है। दोनों व्यवस्थाओं के अभिसरण के विचार का विरोध करते हुए वह स्पष्ट रूप से आह्वान करते हैं कि समाजवादी व्यवस्था को अखिल अमरीकीवाद के नये रूप में विलीन कर दिया जाये।

'प्राविधिक-वैद्युतिक युग' की समस्त परिकल्पना साम्राज्यवादी हल्को की घोर प्रतिस्पर्धावादी धारा को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। इसके प्रस्तावित संस्थानों को समस्त राज्य और सामाजिक सत्ता को आत्मसमर्पण करने और सब पर और अधिक तथा सामाजिक जीवन की समस्त जनतांत्रिक क्रियाविधि पर अपना नियंत्रण कायम करने और उसे और अधिक मजबूत करने के लिए अति व्यापक प्रशासकीय मशीनरी के उपकरण के रूप में निर्मित किया गया है। भावी 'प्राविधिक-वैद्युतिक' विश्व के आदर्श को लेखक नागरिकों पर राज्य के नियंत्रण को अधिकतम व्यापक बनाने के कार्य को प्राविधिक प्रगति का सर्वोच्च लक्ष्य घोषित करता है। इन प्रस्थापनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रजेजिन्स्की की सामाजिक जीवन के विसंद्धान्तिकीकरण से संबंधित स्थापना है जबकि जनता ने बौद्धिक क्रियाकलाप

को राज्य के नियंत्रण में रखा जाएगा और कतिपय पूर्वनिर्धारित पद्धतियों (आदर्शों) तक सीमित कर दिया जाएगा। इस प्रकार ब्रजेजिन्सकी का नया विचार इजारेदार पूंजीवाद तथा विशेष रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद के स्पष्ट समर्थन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन औद्योगिकोत्तर समाज में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसका सीधा-सा कारण यह है कि इस कृत्रिम योजना का वास्तविकता से संबंध नहीं है।

‘नवीनीकृत’ पूंजीवाद की मरीचिकाएँ

‘औद्योगिकोत्तर समाज’ की अवधारणा ही तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के समाधान को तब तक के लिए टाल देती है जब तक कि किसी समय भविष्य में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के अनुग्रह के अंतर्गत पूंजीवाद के यांत्रिक नवीकरण के विचार से एक प्रकार अपने को पृथक् नहीं कर लेती। जहाँ तक प्राविधिक-वैद्युतिक युग की अवधारणा की बात है, इसका संबंध ठोस पूंजीवादी वास्तविकता से कम ही है।

यह कहना आवश्यक नहीं कि ऐसे समय में जबकि वास्तविक घटनाएँ पूंजीवाद के सरल रूपांतरण द्वारा स्वयं श्रेष्ठतर भविष्य की क्षीणप्राय आशा को प्रकट करती हैं, साम्राज्यवादी सिद्धान्तकारों की स्थिति में इस प्रकार के परिवर्तन आकस्मिक नहीं समझे जा सकते। एक ओर तो वे पूंजीवाद के स्वचालित पुनर्नवीकरण के संबंध में टूट रहे भ्रम को प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर, मेहनतकश जनता के ध्यान को वर्तमान की ठोस समस्याओं से हटाने की इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं।

साम्राज्यवादी सिद्धान्तकार यह प्रभाव उत्पन्न करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन शीघ्र होने वाले हैं जो वर्तमान समाजों से भिन्न एक नये समाज के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे जिसके लिए विद्यमान मूल्यांकन, अवधारणाएँ और कसौटियाँ अव्यवहार्य होगी। इस विचार को क्रान्तिकारी नवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूंजीवादी विचारक कहते हैं कि सामाजिक जीवन में कम्प्युनिस्टों की कल्पना से भी अधिक गंभीर और सर्वग्राही परिवर्तन होने वाले हैं। दूसरा वक्तव्य यह है कि समाजवादी रूपांतरण समकालीन संसार की अति सामान्य प्रक्रिया का अंश मात्र है। वास्तविक तथ्य यह है कि यह सामाजिक विकास की निरंतरता (सातत्य) को, घटनाओं की ऐतिहासिक निरंतरता को, और अंतिम विश्लेषण में ऐतिहासिक प्रक्रिया की नियम शासित प्रकृति को अप्रभावित करने का प्रयास है। प्रश्न को इस प्रकार उपस्थित करना साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के सामाजिक आदर्शों को और इसकी प्रेरक शक्तियों को अत्यधिक मनमाने दुरुपयोग की वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है।

एक और विषय प्रासंगिक है जिस पर बहुत चर्चा की गई है : इस सिद्धान्त को प्रसिद्ध अमरीकी समाजशास्त्री आल्विन टॉफ़लर ने अपनी पुस्तक *फ्यूचर शॉक* में और तत्पश्चात् दि इकोस्पाज्म में सूत्रित किया है। लेखक इस प्रस्थापना से आरम्भ करता है कि वर्तमान समाज ऐसे युग में पहुँच गया है जिसे मुख्य रूप से परिवर्तन द्वारा पहचाना जाता है, और इस समय यह अति गंभीर रूपान्तरणों के कगार पर है। वह मानव समाज के समग्र इतिहास के लगभग 65-65 वर्षों के 800 जीवनकालों में विभाजित करते हुए कहते हैं कि इनमें से 650 जीवनकाल गुफाओं में बिताए गए। केवल पिछले 70 में ही उसके पास लिखित भाषा रही। केवल पिछले छः कालों ने छापे के शब्द देखे हैं। केवल पिछले चार ही सटीकता से समय को माप सके और पिछले दो ने ही बिजली की मोटर का उपयोग किया। मनुष्य समाज के अधिकांश लोग वर्तमान वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के लाभों का उपयोग करने में समर्थ हैं, 800वें जीवन काल में।¹ केवल हाल की और विशेष रूप से विद्यमान जीवित, पौढ़ियाँ ही जीवन की ऐसी प्रचंड गति में सम्मिलित हैं जिनकी कल्पना भी पूर्ववर्तियों में कोई नहीं कर सकता था। उनके पास अत्यधिक जटिल प्राविधिक उपकरण हैं, वे अधिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उनके पास सूचना की क्षिप्रतम व्यवस्था है और वैज्ञानिक विकास पर पहले कभी की अपेक्षा अधिक खर्च कर सकते हैं।

टॉफ़लर मानते हैं कि आधुनिक पूँजीवादी समाज अब अधिक समय तक सामान्य तरीकों से विज्ञान और प्रविधि के विकास को जारी नहीं रख सकता, लेकिन अपने इन सचमुच निर्विवाद बक्तव्यों में से लेखक निजी निष्कर्ष निकालता है। जबकि प्रत्येक कल्पनीय क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार की जा रही है वह वर्ग सबधों के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पृथक् कर देता है। ब्रजेजिन्स्की की तरह ही उसने भी वर्तमान युग के पूँजीवाद और समाजवाद के बीच मुख्य अन्तर्विरोधों को गीण अन्तर्विरोधों के समूह में विलीन करने का निश्चय कर रखा है तथा पूँजीवाद के दोषों को सक्रमण काल की विशेषताओं के रूप में मान लिया है। वह लिखते हैं—“क्रान्ति सस्याओं व सत्ता संबंधों को छिन्न-भिन्न कर देती है।” स्पष्ट रूप से यही है जो आज सभी उच्च प्राविधिक राष्ट्रों में हो रहा है***। यह एक ऐसा समाज है जो क्रान्तिकारी परिवर्तन की पीड़ा से ग्रस्त है*** जो आज हो रहा है वह पूँजीवाद का संकट नहीं है, अपितु स्वयं औद्योगिक समाज का है, भले ही इसका राजनीतिक रूप कुछ भी क्यों न हो। हम इसके साथ ही साथ एक युवा क्रान्ति का अनुभव कर रहे हैं, एक लैंगिक क्रान्ति का, एक जातीय क्रान्ति का, एक औपनिवेशिक क्रान्ति का, एक आर्थिक क्रान्ति का और इतिहास में सर्वाधिक गहन और क्षिप्रगामी प्राविधिक क्रान्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम औद्योगिकवाद के सामान्य

संकट में जी रहे है। एक शब्द में, हम सर्वोच्च औद्योगिक क्रान्ति के मध्य में है। वह अनुभव करते है “इसकी परिणति एक नई आश्चर्यपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में होगी जिसका अनुभव आज तक किसी व्यक्ति को नहीं हुआ।” यह जिन मुद्दों को उठाएगी वे “बीसवीं शताब्दी के भीषण संघर्ष को कम कर देगी—पूँजीवाद एवं कम्युनिज्म के संघर्ष को तुलनात्मक रूप से महत्वहीन कर देगी। क्यों ये मुद्दे आर्थिक और राजनीतिक कठमुत्थापन में दूर ले जाएँगे।” इसके अनुसार टॉफ़लर की ‘सैद्धान्तिक खोज’ यह है कि वह एक साथ ही पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा का भी प्रयत्न करते हैं और क्रान्तिकारी की भूमिका भी निभाना चाहते है। इस दृष्टि से वह पूँजीवाद तथा कम्युनिज्म के बीच विद्यमान विवाद को गौण बना देते है और इसका सही अभिप्राय स्पष्ट किए बिना सर्वोच्च औद्योगिक क्रान्ति के पक्ष में बात करने लगते हैं।

अपनी नई कृति ‘दि इको-स्प्राज्म रिपोर्ट’² (न्यूयार्क, 1975) में टॉफ़लर संकट के समाधान के सबध में अपनी अनुशंसाओं को ठोस रूप देने का प्रयास करते हैं। वह अपनी कृति के मुख्य विचार को सादे कागज पर सूत्रित करते है। वास्तव में वह ‘पूँचर शॉक’ की सामान्य अवधारणा को ही दुहराते है लेकिन 1974-75 में पूँजीवादी देशों को जकड़ने वाले संकट की स्थितियों के अनुकूलित करते हुए। उनका यह विश्वास है कि आज जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सामान्य आर्थिक उथल-पुथल नहीं है, बल्कि कुछ अधिक गहरी घटना है जिसे पारंपरिक अर्थशास्त्र के ढाँचे में नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि चकित (उद्भ्रान्त) अर्थशास्त्री शिकायत करते है कि “पुराने नियम अधिक समय तक काम नहीं दे सकते।” टॉफ़लर स्वीकार करते हैं कि हम औद्योगिकवाद के सामान्य संकट के साक्षी हैं और साथ ही अर्थव्यवस्था के ह्रास के, पश्चिम के ऊर्जा पर आधारित होने और इसके मूल्यों की समस्त व्यवस्था का ह्रास होने के साक्षी हैं। उनके पर्याप्त रूप से युक्तिहीन निराशावादी निष्कर्ष उन्हें इस धोषणा से नहीं रोक्ते कि सर्वोच्च औद्योगिक सभ्यता का उदय हो गया है जो औद्योगिक न हो कर प्राविधिक है।

निस्संदेह, व्यावहारिक अनुशंसाएँ (‘संक्रमण काल के लिए कार्य नीति’) प्रस्तुत करने के लिए टॉफ़लर के प्रयास पूर्णतया असहाय है। अधिक से अधिक, वे केवल प्रक्रिया का पुनरुत्पादन करते हैं जो पहले से ही इजारेदार पूँजीवाद की गहराइयों में विकसित हो रही है : अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के संक्रमणकालीन क्रियाकलाप, दीर्घकालीन आयोजनों का समेकन—श्रम शक्ति का सेवा उद्योगों में संचरण और इसी

1. वही पृ० 165-66

2. वही—पृ० 195

3. टॉफ़लर ‘इको-स्प्राज्म’ का प्रयोग समकालीन पूँजीवाद के संकटों को वर्णित करने के लिए करते है।

10/28/88

प्रकार के कार्यों की पूर्ति। यह केवल गलत अवधारणा का परिणाम है कि इन्हे पूँजीवाद के विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

‘पयूचर शॉक’ से तुलना करने टॉफ़लर की इस वाद की रचना को उनके आगे बढ़े कदम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तथापि यह इस अर्थ में कुछ रुचि उत्पन्न करती है कि यह पूँजीवादी समाजशास्त्रीय चिन्तन के विकास की 1970 के आरंभ की निश्चित धारा को प्रकट करती है। ‘प्राविधिक नियतिवाद’ की सामान्य अवधारणा की रक्षा के लिए किए गए प्रयास की और बढ़ती हुई दरारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। साम्राज्यवादी मिद्वान्तकार कुछ अधिक ठोस निष्कर्षों और सिफारिशों से उसे और पुष्ट करते हैं। यही टॉफ़लर ने भी किया है और डब्ल्यू० रोस्तोव, डी० वैंस तथा जो० गॉलब्रेथ ने भी निस्मंदेह अपने-अपने ढंग से। तथापि तथ्य यह दिखाते हैं कि पूँजीवादी धारणा के समर्थक इस मार्ग से थोड़ा ही प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की अमूर्त प्रस्थापनाओं का कोई भी अनुमान और वास्तविकता में उसकी तुलना या तो कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्तों का अति दिवालियापन प्रदर्शित करती है अथवा सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं वास्तविक संशोधन द्वारा सुधार की आवश्यकता प्रदर्शित करती है। प्राविधिक नियतिवाद के समर्थकों के संघर्ष में भी यह सच है।

इसके प्रमाण बॉल्ट रोस्तोव की कृति “पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रेज ऑफ प्रॉय” में पाए जा सकते हैं जहाँ कि वह गृह-नीति एवं विदेश नीति के ठोस मुद्दों पर सामान्य निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस स्थापना से आरंभ करके कि 1970 का दशक राजनीति का दशक होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि 1960 का दशक आर्थिक उन्नति में लक्षित किया गया था, वह राजनीति की दृष्टि को सुरक्षा, कल्याण और संवैधानिक व्यवस्था—जिसमें विकास की मंजिलें भी सम्मिलित हैं—की आर्थिक समस्याओं के साथ समन्वित और संतुलित करने के प्रयास के रूप में परीक्षा करने का प्रयास करते हैं।¹ वह अब भी विश्वास करते हैं कि उनका मुख्य कार्य संयुक्त राज्य अमरीका में प्राविधिक समाज के अभाव के लिए बोलना है लेकिन वह वितरण के स्तरीकरण और अन्य मानवीय कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों के हक बढ़ाए जाने पर अधिक बल देते हैं।

यह स्वीकार करते हुए कि 1970 के दशक के आरंभ में संयुक्त राज्य अमरीका को गंभीर कठिनाइयों तथा अन्तर्विरोधों का सामना करना पड़ा, रोस्तोव अपनी अनुशंसाओं में स्पष्ट रूप से स्वयंसिद्ध बातों को दुहराने से आगे नहीं बढ़ते। गृहनीति के क्षेत्र में वह अत्यन्त अस्पष्ट दुविधापूर्ण फार्मूलों का—क्रियाकलाप के

गतिशील संतुलन, आर्थिक उन्नति, कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जहाँ तक विदेश नीति का संबंध है वह अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शांति सन्तुलन की एक बार फिर वकालत में अच्छी कोई बात नहीं सोच पाते। एक शब्द में, रोस्तोव वर्तमान घटनाओं के वर्गीय सारतत्व से पाठकों को पृथक् रखने की और पूँजीवाद को पुनः स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। जहाँ तक व्यावहारिक सुझावों का मामला है, वह टॉफ़लर जैसे ही है उनमें सत्ताधारी वर्गों द्वारा पहने गये व्यवहृत सरकारी नीति से अधिक कुछ नहीं।

क्या पूँजीवाद के अन्तर्गत नियोजित अर्थव्यवस्था संभव है ?

इस बात को जानते हुए भी कि वर्तमान में पूँजीवाद सकटापन्न है न तो रोस्तोव और न टॉफ़लर ही कोई गंभीर सिफारिशें करने का साहस करते हैं, वे वस्तुतः न चाहते हुए भी अपनी अवधारणाओं की विशुद्ध रूप से प्रचारात्मक प्रकृति को ही सामने ला रहे हैं।

जे० के० गालब्रेथ की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। केवल इसलिये नहीं कि वह स्वीकार करते हैं कि पूँजीवाद में अन्तर्विरोध बढ़ रहे हैं, और तदनुसार वह अपने पुराने विचारों में संशोधन भी करते हैं, अपितु वह शासक वर्ग से भी हो रहे परिवर्तनों के प्रति विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करने का अनुरोध भी करते हैं। उनके विचारों का यह विकास सचमुच महत्वपूर्ण है।

यह एक लाक्षणिक बात है कि पिछले कुछ ही वर्षों के भीतर उनकी प्रकाशित पुस्तक "द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट" में वह इस बात से सहमत हो जाते हैं कि विरोधी शक्तियाँ—इजारेदारियों, ट्रेड यूनियनों और राज्य—का सामान्य संतुलन एक तो इजारेदारियों के पक्ष में बदल जाता है और दूसरे, 'परिपक्व निगम' मूल्य कम करने की इच्छा नहीं रखते। दूसरी ओर, यह स्पष्ट हो गया है कि बढ़ती हुई समृद्धि के बावजूद मेहनतकश जनता वर्ग संघर्ष को समाप्त करने की तत्पर नहीं है। गालब्रेथ की मान्यता है इन तत्वों के सम्मिलित हो जाने के आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है।

इसके अनेक कारणों में से एक की ओर इशारा करते हुए वह ध्वनिते नहीं। गत 1969 में उन्होंने अपनी पुस्तक "हाउ टु कन्ट्रोल द मिलिटरी" में लिखा था : "यहाँ हम अमरीका की राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली, जिसकी रूपरेखा इसके पूर्वजों ने बनाई थी और जो आज भी युवकों के समक्ष चित्रित की जाती है, के स्पष्ट विपर्यय को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वह दृष्टिकोण अन्तिम सत्ता, अन्तिम संप्रभुता के जनता में निहित होमे की स्वीकार करता है। और माना जाता है कि यह सत्ता सर्वग्राही है। राज्य की परिधि के अन्तर्गत नागरिक उन व्यक्तियों—राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से जिन्हें कि वह चुनता है अपनी

इच्छा को अभिव्यक्त करता है। निजी क्षेत्र में वह इस कार्य को बाजार में वस्तुओं की खरीद करने द्वारा करता है। वे (नागरिक) सम्बन्धित आपूर्ति-क्रमों को—जैसे जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, न्यूजर्सी का स्टैंडर्ड आयल—हिदायत देते हैं कि वे किस वस्तु का निर्माण करेंगी और बेचेंगी।

“तथापि, यहाँ हम सशस्त्र सेनाएँ और निगमों को पाते हैं, जो उनकी आपूर्ति करते हैं, निर्णय करते हैं और कांग्रेस को तथा जनता को निर्देश देते हैं। जनता उनको स्वीकार करती है और बिल चुकाती है।”¹

संयुक्त राज्य अमरीका में तथ्यांकयित सोवियत खतरे और कम्युनिस्ट विरोधी उन्माद को खिल्ली उड़ाते हुए गालब्रेथ कहते हैं—“पुराने नारे—हमें विश्वव्यापी कम्युनिस्ट हमले का मुकाबला करना चाहिए, हमें आक्रमण को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, हमें अपने बहादुर साथियों का साथ देना चाहिए—सिर्फ तब तक ही नहीं लगाये जाते रहे जब तक कि बार-बार दुहराने से ही उनका अर्थ समाप्त नहीं हो गया बल्कि घटनाओं ने ही उन्हें हास्यास्पद सिद्ध नहीं कर दिया।”² लेकिन बड़ी इजारेदारियों के प्रवक्ता के रूप में वह उनकी भूमिका को सैनिक औद्योगिक कॉम्प्लैक्स के आधिपत्य में कम करके आँकते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी पेंटागन तथा सेना पर ढाल देते हैं।

स्पष्ट रूप से समस्या के समाधान से कतराते हुए गालब्रेथ अनिवार्य रूप से अस्थिर और अनिश्चित निष्कर्षों पर पहुँच जाते हैं। वह कहते हैं कि सैनिक औद्योगिक कॉम्प्लैक्स की सत्ता में कटौती से अमरीकी अर्थव्यवस्था सबल हो सकती थी लेकिन इस प्रस्ताव के साथ वह इतनी शर्तें लगा देते हैं कि वह स्वयं ही अपनी सिफारिशों की व्यावहारिकता पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं।

कुछ समय पश्चात् ही गालब्रेथ को फिर एक बार आधुनिक पूँजीवाद के लक्षणों के अपने मूल्यांकन में सशोधन के लिए विवश होना पड़ा। फ़रवरी 1971 में पेरिस में दिए भाषण में तथा उसके बाद अप्रैल 1972 में इटली की एक पत्रिका को दिये माक्षातृकार में, उन्होंने कहा कि पूँजीवादी समाज संसाधनों और उत्पादन के वितरण के अपने तरीकों में न्याय संगत नहीं रहा और मुद्रास्फ़ोति की प्रवृत्ति पर विजय पाने में इसकी अक्षम रही। यह आवादी की मकान, नगरीय यातायात, चिकित्सा सहायता आदि प्राथमिक आवश्यकताओं को विवेकपूर्वक संतुष्ट करने में अक्षम है और साथ-ही-साथ भारी मात्रा में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगा है जो या तो निरर्थक हैं अथवा सामान्य रूप से हानिकारक हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर तथा प्रशासनिक तंत्र के भरण-पोषण पर अत्यधिक व्यय ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है।

1. जॉन केनेथ गालब्रेथ, हाउ टू कंट्रोल द मिलिट्री ब्यूजर्क 1969 पृ० 30-31

2. वही पृ० 149

उनका विचार है कि इस दयनीय स्थिति का उपचार क्रिमतो और वेतनो पर राज्य के नियंत्रण की नई व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है जिसे प्रमुख निगमों के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए। पूँजीवादी देशों को आतंकित कर रहे सामाजिक छतरे के अपने ममता विद्यमान रहते निगम वस्तुतः ऐसा करने में रचि ले सकते हैं।

तत्पश्चात्, उन्होंने इन विचारों को 1973 में बोस्टन से प्रकाशित अपनी पुस्तक "इकोनॉमिक्स एण्ड पब्लिक पर्वज" में विस्तृत किया है। यह नई प्रमुख कृति उनकी ग्रन्थप्रयी में अन्तिम है। (अन्य दो हैं "दि एक्सप्लूएण्ड सोसायटी" और "द न्यू इण्डस्ट्रियल स्टेट" जो क्रमशः 1958 और 1967 में प्रकाशित हुईं)। एक ओर तो वह पुराने निष्कर्षों को दुहराते हैं और दूसरी ओर उनको संशोधित करते हैं। गाल-थ्रेष का अन्तर्विरोधी गिढान्न स्वयं पूँजीवादी वास्तविकता के अन्तर्विरोधों को प्रतिबिम्बित करता है। उनके इस प्रयास से कुछ नये लक्षण भी, जो हाल के वर्षों में उभरे हैं, सामने आये हैं।

घटनाक्रम ने, विशेष रूप से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की निरंतरता ने, उनके इन पुराने कथनों को कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के विकास के साथ धर्मिक जनगण को उधर ले जा सकेगी जिसे वह 'समुद्र समाज' कहते हैं—पूर्णतया खंडित कर दिया है।

गालथ्रेष के पुराने कथनों के बावजूद तथाकथित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (अर्थात् प्रौढ़ निगम) और बाजार व्यवस्था जिसमें छोटी फर्मों और साधारण उद्यमी भी सम्मिलित हैं, के बीच शक्तियों के परस्पर संबंधों में अत्यंत गहन और स्पष्ट परिवर्तन हो गया है। 'गालथ्रेष का उद्देश्य (आशय) वर्तमान पूँजीवादी समाज वर्ग विरोधों के स्थान पर 'नियोजन' और 'बाजार' अर्थव्यवस्था के बीच विरोध में विश्वास उत्पन्न करना है। वह इन दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक को कुछ-कुछ स्वायत्त, पृथक्कृत तथा सामाजिक रूप से सजातीय घटनाक्रिया मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में बड़े निगम, जो राज्यतंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, तथाकथित बाजार व्यवस्था का अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर वे पूँजीवादी समाज के सामाजिक अंतर्विरोधों को तीव्र कर रहे हैं।

यह अधिकाधिक प्रमाणित होता जा रहा है कि निगमों और पूँजीवादी राज्य द्वारा व्यवहार में लाई जा रही आर्थिक उन्नति की नीति किस प्रकार पूँजीवाद को सुदृढ़ नहीं कर सकती। इसके विपरीत, पहले से विद्यमान अंतर्विरोधों के साथ-साथ पूँजीवादी विश्व नए अंतर्विरोध उत्पन्न कर रहा है जिनमें निरंकुश मुद्रास्फीति का संकट महानगरो का संकट और पर्यावरण के भग होने का संकट भी सम्मिलित है।

इन सब पर तथा अन्य नकारात्मक घटनाओं पर विचार करते हुए गालब्रेथ अमरीकी अर्थव्यवस्था के संबंध में एक अति कठोर टिप्पणी करते हैं—कि, अर्थ-व्यवस्था में अपने को पूर्ण बनाने की प्रवृत्ति होती है अब इस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। असमान विकास, असमानता, अर्गंभीर तथा अनिर्मित नव्य प्रयोग पर्यावरण पर आक्रमण, व्यक्तित्व की उपेक्षा, राज्य पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति, अंतर औद्योगिक सहयोग में असफलता व्यवस्था के अंग बन गए हैं जैसे कि वे वास्तविकता की ही अंग हैं। ये साधारण खामियाँ नहीं हैं, जैसे कि मशीन पर विकृत आकृति का चक्का हो जिसे कोई एकदम पहचान सकता है और हटा सकता है और इस प्रकार वह ठीक कर दी जाती है। वे गहराई में व्यवस्था से जुड़ी हैं।”

तो फिर, उनकी राय में क्या किया जाना चाहिए? “न तो, अर्थशास्त्री ही क्रांतिकारी होते हैं और न उनकी पुस्तकें ही,” वह अपनी पुस्तक के आरंभ में ही यह लिखते हैं किंतु फिर भी वह अपने कार्यक्रम को ‘नया समाजवाद’ कहता है। जिसके संबंध में उनका विश्वास है कि वह गंभीर असुविधा, उल्लेखनीय सामाजिक अव्यवस्था और कभी स्वास्थ्य और जनकल्याण को घातक क्षति पहुँचाने की कोशिश प्रदा करके ही हम उससे निस्तार पा सकते हैं।

“नया समाजवाद विचारधारात्मक नहीं होगा यह परिस्थितियों की विवशता से उत्पन्न होगा।”³

अब, आर्थिक उन्नति के प्रभाव और राज्य, इजारेदारियाँ और ट्रेड यूनियनों के बीच गतिशील सतुलन प्राप्त करने की अपेक्षा गालब्रेथ ‘नियोजन व्यवस्था’ तथा ‘बाजार व्यवस्था’ के बीच अंतर्विरोधों को समाप्त करने के कार्य को केंद्रीय महत्व देते हैं। वह उनके विषय में मूलरूप से नई आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के रूप में सोचते हैं जिनकी रूपरेखा समस्त पूँजीवादी विश्व विकास और परस्पर क्रिया के क्रम में नवीकरण के लिए तैयार की गई थी।

उनके मत में इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच के विरोध को, जिसे कि वह मुख्य सामाजिक विरोध के रूप में चित्रित करते हैं, नियोजन व्यवस्था को (अर्थात् इजारेदारी को) समेकित करके समाप्त किया जा सकता है। सीधे-सादे रूप से आवश्यकता यह मान्यता देने की है कि हमारे विश्वास एवं सुविधाजनक सामाजिक गुण स्वयं हमारे अंदर से नहीं उत्पन्न हुए अपितु नियोजन व्यवस्था से प्राप्त हुए हैं।⁴ इसलिए वह इसे राजनीतिक एवं आगे बढ़े हुए विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र के रूप में चित्रित करते हैं जिस पर कि विश्वास के साथ दावा किया जा सके क्योंकि

1. जॉन कैंपेय गालब्रेथ, इकॉनॉमिक्स एंड द पब्लिक पर्वेज, बोस्टन, 1973, पृष्ठ 211

2. वही पृष्ठ 17

3. वही, पृष्ठ 277

4. वही, पृष्ठ 225

“नियोजन व्यवस्था के स्वयं अपने प्रयोजन होते हैं और वह उसके अनुसार जनता को व्यवस्थित कर देती है।”¹

दूसरी ओर, वह राज्य की भूमिका को भी बढ़ाना आवश्यक समझते हैं जिसे कि पूरे समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए क्योंकि ‘आधुनिक राज्य’... ‘पूँजी-पतियों की कार्यकारिणी समिति नहीं है अपितु यह प्राविधिक संरचना की कार्य-कारिणी अधिक प्रतीत होती है।”² सिद्धांततः वह उत्पादन के साधनों के समाजीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि वह यह सोचते हैं कि सत्ता की समस्या की जड़ें सामान्यतया संगठन में हैं, निजी उद्योगों में नहीं। लेकिन उसके साथ-ही-साथ वह इस स्थापना का भी विरोध करते हैं एक सीमा तक ऐसी कुछ शाखाओं के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करके जिनमें लाभ कम होता है किंतु वे समाज के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं (मकान निर्माण, चिकित्सा संस्थान... नगर यातायात और कुछ अन्य भी); और अश्वधारकों से युद्ध उद्योगों के खरीदने की भी बात करते हैं।

उसका दावा है कि इन उपायों से अधिक प्रगतिशील कर निर्धान, प्रत्येक नागरिक के लिए निश्चित आय, स्त्रियों के लिए आर्थिक मुक्ति की सुरक्षा, शिक्षा के समान अधिकार सुरक्षित करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारना और इसी प्रकार के कार्य, जो सब ‘जीवन के गुणों’ को निर्मित करते हैं, करना संभव होगा।

इसका अर्थ यह है कि गालब्रेथ की ‘नए समाजवाद’ की अवधारणा के पीछे अति सावधानी भरे ऐसे सुधारों के कार्यक्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका राज्य इजारेदारी पूँजीवाद के मुख्य आधारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता हो। यह तथ्य अपरिवर्तित रहता है, यद्यपि अपने नवीनतम दक्तव्य में गालब्रेथ सैनिक-औद्योगिक कॉम्लैन्स के क्षेत्र सहित उद्योगों की कतिपय पिछड़ी शाखाओं के राष्ट्रीयकरण के रूप में कतिपय अतिवादी उपायों की संभावनाओं को भी स्वीकार करते हैं। यह सर्वथा स्पष्ट है कि इजारेदारी के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण से पूँजीवादी समाज की अंतर्विरोधों से पूर्ण सामाजिक प्रकृति सुधर नहीं सकती।

‘प्राविधिक’ संप्रदाय के दूसरे प्रतिनिधियों की तरह गालब्रेथ भी वैज्ञानिक कम्युनिज्म के निष्कर्षों की अपेक्षा करते हैं। वह ऐतिहासिक प्रक्रिया की मूल नियमितताओं, वर्ग-संघर्ष और मजदूर वर्ग की भूमिका, लेनिन के साम्राज्यवाद के विश्लेषण और समाजवादी क्रांति के उसका सिद्धांत जैसे मूल मुद्दों पर अप्रत्यक्ष रूप से विवाद खड़ा करते हैं। इस प्रकार, वर्तमान पूँजीवादी वास्तविकताओं के बहुत से रूपों पर अपने आलोचनात्मक रवैये तथा पूँजीवाद के समर्थन के अति-

1. वही, पृष्ठ 241

2. वही, पृष्ठ 172

घृणित जड़ चितन के संशोधन के बावजूद जॉन गालब्रैथ अंतिम विश्लेषण में स्वयं को स्वप्नलोक के निष्कर्षों तक सीमित कर लेते हैं।

वास्तव में, अपनी नवीनतम पुस्तक में उनके तर्क उसी विचार तक सीमित हैं, यानी कि प्राविधिक संरचना के हार्थों में पूंजी के क्रियाकलाप का पूंजी के स्वामित्व से तथाकथित पृथक्करण कर दिया जाता है। इसी कारण, वह दावा करते हैं कि प्राविधिक संरचना सामान्य जन हित से संबद्ध होकर स्वयं वर्गोपरि संस्थान में बदल जाती है, अधिक संचित मुनाफों से नहीं। और यह संस्थान सोद्देश्य रूप से अंश-धारकों के लिए उदार और निश्चित लाभार्थों को सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों के लिए उच्च एवं स्थायी वेतन के लिए चिंता करेगा।

वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूंजीवादी विश्व का समग्र चित्र पूर्णतया भिन्न है। इजारेदारियाँ अपने लिए अधिकतम संभव मुनाफा कमाने में लगी हैं। श्रमिक निरंतर किंतु असफलता के साथ अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं जबकि प्राविधिक संरचना के प्रतिनिधि इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि इस मामले में वे कुछ भी करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसलिए, जॉन गालब्रेथ की अवधारणा न तो कुछ स्पष्ट करती है, और न व्यावहारिक मूल्य का कुछ देती ही है।

आर्थिक विकास की अवधारणाओं का संकट

निराशावाद के उत्स

1970 के पूर्वार्ध में ही यह स्पष्ट हो गया था कि 'प्राविधिक नियतिवाद' का विचार अपने समर्थकों की असमाधेय अन्तर्विरोधों की अधी गली में ले जा रहा है। पूँजीवादी संबंधों के ('प्राविधिक' सिद्धान्तों में इस प्रकार की परिघटनाएँ जैसे बेरोज़गारी, मुद्रा स्फीति एवं वर्ग संघर्ष सुस्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी) सामाजिक वर्गीय सारतत्व से बच निकलने के प्रयाम औद्योगिकवाद के समर्थकों के विरुद्ध मुड़ गये।

आज ये सब परिघटनाएँ इतने विशाल अनुपात प्राप्त कर चुकी हैं कि प्रचार संबंधी कोई भी वस्तुस्थिति अधिक समय तक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

इन घटनाओं के विद्यमान रहते हुए रोस्तोव, वैस, टॉफ़लर और गालब्रेथ पूँजीवादी विश्व में नये और अधिक गंभीर अन्तर्विरोधों के विषय में बात करते हैं। वे सभी 'औद्योगिकवाद' की अवधारणा को किसी भी प्रकार नया रूप देना चाहते हैं और व्यावहारिक सिफ़ारिशें प्रस्तुत करते हैं, जो परीक्षा किये जाने पर सर्वथा असफल प्रमाणित होती हैं ?

वैज्ञानिक विचार की यह व्यावहारिक अक्षमता है जो कि 'औद्योगिकवाद' के विचार के गंभीर संकट को सबसे आगे होकर प्रकट करती है। लेनिन के साम्राज्यवाद एवं समाजवादी क्रान्ति के सिद्धान्त के विरोध के लिए प्रचार की एक अवधारणा के रूप में उसकी कल्पना की गयी। इसका जीवन के साथ तीक्ष्ण एवं शान्त न होने वाला अंतर्विरोध है। और यह इस तथ्य के बावजूद कि इस मंच पर विपरीत ही नहीं विरोधी—अत्यधिक आशावादी और अत्यधिक निराशावादी—भविष्यवाणियाँ साथ-साथ भली-भाँति देखी जा सकती हैं। दूसरी ओर, औद्योगिक समाज की अवधारणा को पूँजीवाद के बढ़ रहे संकट द्वारा उत्पन्न नयी परिघटना के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हुए गालब्रेथ और उनका अनुसरण करने वाले अन्य दूर्ज्वा पण्डितों ने अपनी विचारधारा में एक नये महत्वपूर्ण तत्व को प्रविष्ट किया।

अन्य चीजों के साथ उन्हें सुझाव दिया कि मुद्रा-स्फीति और संकट की अन्य परिघटनाओं की जड़ें भी अत्यधिक आर्थिक विकास व सामान्य उत्पादन में सतत वृद्धि के लिए प्रयास की नीति में निहित हैं जो दीर्घकाल में जीवन के गुणों को क्षति पहुँचाती है।

1950 और 1960 के दशकों में पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने जो सिया और बोला उससे तुलना करने पर इन विचारों पर कुछ अन्य अभिप्राय हावी दिखायी देते हैं। उनकी वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के मंगलकारी परिणामों की रंगीन आशाओं का स्थान ये वक्तव्य ले रहे हैं कि यह मानव समाज के लिए उपयोगी होने की अपेक्षा अधिक हानिकारक प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी पंडितों के झूठे आशावाद का स्थान मायूसी और क्रान्ति ने ले लिया है। बेल निष्कर्ष निकालते हैं; युक्तिसंगतता की, अथवा कहना चाहिए कि एक विशिष्ट प्रकार की तर्क संगति की आशाएँ निश्चित रूप से मन्द हो गयी हैं। "समाज के न्याय संगत संगठन की अवधारणा गड़बड़मड़ हो गई है।"¹ औद्योगिकवाद एक अन्य प्रमुख प्रवक्ता फ्रांसीसी विद्वान् रेमण्ड आरों ने अपनी पुस्तक का नाम रखा है : ला डिस्इल्यूज़न्स डू प्रोग्रेस।²

'औद्योगिक' अथवा 'औद्योगिकोत्तर' समाज, के पूर्ववर्ती वर्णनों में वर्तमान पूँजीवाद के स्थायी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, समाज के समस्त चारित्रिक और नैतिक मूल्यों का बढ़ता हुआ संकट—जैसे भयानक रूपों को साधारणतया मौन रह कर उपेक्षा कर दी जाती थी, इस विश्वास पर कि विज्ञान एवं प्रविधि के विकास होने पर मनुष्य समाज इन सब बुराइयों से स्वतः मुक्त हो जाएगा। अब बुराइयों को सहज रूप से ही सीधे-सीधे अशुभ वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के मापे मढ़ दिया जाता है जिसे कि भद्दे नगरीकरण के लिए, आबादी के विस्फोट के लिए, पर्यावरण को छिन्न-भिन्न करने के लिए और आणविक युद्ध के खतरे के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मान लिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका की वैज्ञानिक 'राष्ट्रीय अकादमी' के अध्यक्ष फ़िलिप हैडलर कहते हैं कि विज्ञान एवं प्रविधि को दोषी ठहराना (अभिशाप देना) 'राष्ट्रीय सनक बन गयी है, अभी कल तक इनको जीवन के बाहुल्य का वरदान माना जाता था।

आज अधिकाधिक चिन्ताकुल आवाजें उठ रही हैं कि परमाणु के विषय में बात करने का अर्थ है भविष्य में होने वाला आणविक सर्वनाश, रेडियो-धर्मिता का विस्तार और प्रजनन संबंधी घातक परिवर्तन; कि भारी उद्योग प्रत्यक्षतया

1. डैनियल बेल 'टैक्नोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स' इन सर्वे 1971, खंड 16, अंक 6, पृ० 52-24

2. रेमण्ड आरों 'ला डिस्इल्यूज़न्स डू प्रोग्रेस' ऐसे गुरला डायलेक्टिक डि ला मोर्नैनिटी, पेरिस 1969

पर्यावरण समुद्रो और नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है; आधुनिक औषधि विज्ञान की उपलब्धियाँ कुरूप अपग बच्चों के जन्म के लिए और औषधि सेवन के व्यसन के लिए जिम्मेदार है। 'मानव भस्तिष्क' के कार्यों के संबंध में तथा प्रजनन संबंधी यांत्रिकता के विषय में बढ़ता हुआ ज्ञान निरंकुशता की ओर ले जा रहा है; चिकित्सा और स्वच्छता के क्षेत्र में प्राप्त सफलताएँ आबादी बढ़ने के लिए उत्तर-दायी हैं आदि-आदि।

यह बहुत पहले की बात तो नहीं है जब पूंजीवादी सिद्धांतशास्त्री प्राविधिक प्रगति तथा आर्थिक विकास के प्रशंसा भरे गीत गाया करते थे और भावुकतापूर्ण तर्क देते थे कि इससे वाहुल्य की ओर जाना संभव होगा; और बहुलता से 'सामूहिक उपभोग' की ओर जिससे सार्वभौम समृद्धि सुनिश्चित होगी। किन्तु यही आवाजे तब शोकगीत बन गयी जब यह दिखाई देने लगा कि प्राविधिक प्रगति दो स्वामियों की सेवक नहीं है और वह पूंजीवाद को अन्तर्विरोधों से नहीं बचा सकती। बूर्ज्वा पंडितों के लिए यह अधिक उपयुक्त होता कि वे अपनी कृतियों को 'प्रगति से मोह भंग' के बजाए 'प्रगति की भ्रान्ति' का नाम दें।

किसी भी प्रकार के जादूटोनों से चाहे वे वैज्ञानिक और प्राविधिक ही क्यों न हो सामाजिक प्रगति को नहीं रोका जा सकता। आज की दुनिया में आर्थिक प्रगति को रोकने का आह्वान देना और वह भी ऐसे समय जबकि बहुत से देश शताब्दियों से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं, और लाखों लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आज उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं और कल वे अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त कर सकेंगे या नहीं।

फिर भी पूंजीवादी सिद्धान्तकार 'प्राविधिक' सिद्धान्त के संबंध में इस नये वक्तव्य के विषय में प्राविधिक विकास के नकारात्मक परिणामों को सामने लाते हुए अपने अनुमानों को जारी रखेंगे। उनका खयाल है कि पूंजीवाद के अन्तर्गत प्राविधिक प्रगति की विध्वंसक प्रकृति बन गयी है वह स्वयं प्राविधिक प्रगति के कारण उत्पन्न हुई है, पूंजीवाद के कारण नहीं।

अधिसंख्य न होने पर भी, अनेक पूंजीवादी अन्वेषक आर्थिक उन्नति में अपने मोहभंग की अर्थात् उन आशाओं के नष्ट होने की अभिप्रेरित करते हैं कि विज्ञान और प्राविधिक विकास से पूंजीवादी समाज की अधिकांश तात्कालिक समस्याओं को सुलझाना संभव होगा। वे सभी अब ऐसे बलि के वकरे को खोज रहे हैं जिस पर इन आशाओं के पूरा न होने की जिम्मेदारी डाल सकें, और स्वभावतः वे पूंजीवाद को मुख्य अपराधी नहीं मानते। उनमें से बहुत से पूछते हैं कि क्या आधुनिक समाज के अन्तर्विरोध आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न हुए हैं या इसके बिना ही उत्पन्न हुए हैं। और अधिकाधिक बूर्ज्वा सिद्धान्तकार माँग करते हैं कि 'अतिशय' आर्थिक उन्नति को प्रतिबंधित (सीमित) कर देना चाहिए। 'सामूहिक उपभोग'

और 'सार्वभौम समृद्धि' पर आधारित समाज की सन्निकटता के संबंध में आशावादी भविष्यवाणियों के स्थान पर विश्वव्यापी पर्यावरणिक महाविनाश अथवा प्रलय के बारे में अनुभूत भविष्यवाणियों की जा रही हैं।

रोम का पलव : जीवित रहने के उपाय

प्रलय के नये विचार का सर्वाधिक पूर्ण रूप से नया विवरण रोम के बलब' के तत्वावधान में आयोजित एक मौलिक अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रविधि के मैसाक्यूट्स संस्थान के डेनिस मीडोज के नेतृत्व में किया गया था। पुस्तक' में अनेको दृष्टान्त, तालिकाएँ, रेखाचित्र दिए गए हैं : इसमें औद्योगिक समाज के विकास की 'घतरनाक' प्रवृत्तियों के न केवल सांगोपांग विश्लेषण का दावा किया गया है बल्कि यह दावा करने का भी साहस किया गया है कि इसमें आसन्न संकट को दूर करने के लिए ठोस उपायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।

पूँजीवादी विचारकों के मध्य हाल के वर्षों में निरंतर विद्यमान प्रवृत्ति के अनुरूप रोगकों ने वर्तमान काल की संकटपूर्ण प्रकृति और आसन्न परिवर्तन के भविष्यकारी धरित को पूरे बल के साथ प्रदर्शित किया है। 'प्राविधिक' दिशा के अन्य अनुयायियों की तरह ही उन्होंने भी इसके समस्त विद्यमान समस्याओं की जटिलता के संबंध में मानव समाज को चेतावनी दी और यह उल्लेख किया है कि 'परंपरागत संस्थाएँ और नीतियाँ उनका सामना नहीं कर सकती और न वे उनके सारतत्त्व को ही पूरी तरह ग्रहण कर सकती हैं।' इस सामान्य वक्तव्य से सतुष्ट न होकर रोगकों ने इन समस्याओं के सार को इस प्रकार स्पष्ट किया है : धन के ढेर के बीच निर्भरता, शोषणता में दृष्टिहीनता, वातावरण का अधःपतन, संस्थाओं में विश्वास का अभाव, अतिरिक्त नगरीय विस्तार, नियोजन की असुरक्षा; युवा

पीढ़ी का अलगाव, परंपरागत मूल्यों का अस्वीकार, और मुद्रास्फीति और अन्य वित्तीय एवं आर्थिक विघटन।”¹

ऐसा प्रतीत हो सकता था कि इस प्रकार की स्पष्ट व बेलाग घोषणा के बाद उपर्युक्त सभी तथ्यों का उचित मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन लेखकों ने भिन्न मार्ग को ही वरीयता दी। उन्होंने वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर मौन रहना ही ठीक समझा : जैसे, श्रम और पूंजी के बीच सामाजिक अन्तर्विरोधों का बढ़ना, मेहनतकश जनता के शोषण का बढ़ना, और मजदूर वर्ग का अधिकाधिक विस्तार और बेरोजगारी में वृद्धि। पूंजीवादी विश्व में औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए विरोध के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया, नव उपनिवेशवाद की नीति के विरोध में, हथियारबंदी की दौड़, समस्त मानवता के विरुद्ध सैन्यवाद और आक्रमण की नीति के ज़हरीले परिणामों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया।

मीडोफ और उसके सहयोगी अपने प्रतिवेदन में विश्व से संबंधित पांच मुख्य प्रवृत्तियों की गतिशीलता की खोज करते हैं : औद्योगीकरण का तेजी से विस्तार, जनसंख्याओं में तेजी से वृद्धि, व्यापक कुपोषण, नवीकरणयोग्य संसाधनों की समाप्ति और वातावरण का विकृत होना। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व विकास के दुनियादी कारकों का चुनाव इस प्रकार किया गया है कि उन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जो कमोबेश समान रूप से पूरे मानव समाज से संबंध रखते हैं, बिना इस बात का विचार किए कि उसकी सामाजिक संरचना कैसी है। एक शब्द में, लेखकों ने सारांश में दो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विश्व के विभाजन की उपेक्षा की है और वे ‘एकमात्र विश्व समाज’ के नए किंतु निरर्थक प्रतिरूप के साथ सामने आते हैं।

प्रतिवेदन के लेखकों का विश्वास है कि इन घातक शक्तियों, विश्व के विकास के पांच कारकों, की अंतः क्रिया सहजभाव से मानवता को महानाश की ओर धकेल रही है। सामान्य रूप से कहा जाए तो, उपर्युक्त पांचों अंग अपरिहार्य रूप से परस्पर क्रिया करते हैं और उनका विकास मानव समाज को अंधी गस्ती में धकेलता है। उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बिना आबादी नहीं बढ़ सकती और यह केवल औद्योगिक विकास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक विकास खनिज संसाधनों के उत्पादन बढ़ने पर निर्भर है जिनके शोषण से पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता है, और इससे कृषि उत्पादन को क्षति पहुँचती जो इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि को रोकती है।

लेखक कहते हैं, इस अविभाज्य और अन्तर्विरोधी परस्पर क्रिया के सभी

और 'सार्वभौम समृद्धि' पर आधारित समाज की सन्निकटता के संबंध में आशावादी भविष्यवाणियों के स्थान पर विश्वव्यापी पर्यावरणिक महाविनाश अथवा प्रलय के बारे में अशुभ भविष्यवाणियाँ की जा रही है।

रोम का कलव : जीवित रहने के उपाय

प्रलय के नये विचार का सर्वाधिक पूर्ण रूप से नया विवरण रोम के क्लब¹ के तत्वावधान में आयोजित एक मौलिक अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रविधि के मैमाच्यूट्स संस्थान के डेनिस भीडोज के नेतृत्व में किया गया था। पुस्तक² में अनेकों गणनाएँ, तालिकाएँ, रेखाचित्र दिए गए हैं; इसमें औद्योगिक समाज के विकास की 'खतरनाक' प्रवृत्तियों के न केवल साँगोपाँग विश्लेषण का दावा किया गया है बल्कि यह दावा करने का भी साहस किया गया है कि इसमें आसन्न संकट को दूर करने के लिए ठोस उपायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।

पूँजीवादी विचारकों के मध्य हाल के वर्षों में निरंतर विद्यमान प्रवृत्ति के अनुरूप लेखकों ने वर्तमान कल की संकटपूर्ण प्रकृति और आसन्न परिवर्तन के क्रांतिकारी चरित्र को पूरे बल के साथ प्रदर्शित किया है। 'प्राविधिक' दिशा के अन्य अनुगामियों की तरह ही उन्होंने भी इसके समक्ष विद्यमान समस्याओं की जटिलता के संबंध में मानव समाज को चेतावनी दी और यह उल्लेख किया है कि 'परंपरागत संस्थाएँ और नीतियाँ उनका सामना नहीं कर सकती और न वे उनके सारतत्त्व को ही पूरी तरह ग्रहण कर सकती हैं।'³ इस सामान्य वक्तव्य से संतुष्ट न होकर लेखकों ने इन समस्याओं के सार को इस प्रकार स्पष्ट किया है : धन के ढेर के बीच निर्धनता, संपन्नता में दरिद्रता, 'वातावरण का अधःपतन, संस्थाओं में विश्वास का नष्ट होना, अनियंत्रित नगरीय विस्तार, नियोजन की अमुरक्षा; युवा

1. रोम का क्लब : वैज्ञानिकों, व्यवस्थापकों, जननेताओं, राजनीतिज्ञों का 1968 में स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन। रोम के क्लब के संगठनकर्ताओं में इटली के किएट उद्योग की निरीक्षक कौसिल पूर्व अध्यक्ष भीतियो पेस्सेई भी शामिल हैं। इन्होंने इसे उल्लेखनीय राजनीतिक अधिकार प्रदान देने की भी व्यवस्था की। उदाहरण के लिए, फरवरी 1974 में भावी कार्यक्रम पर विचार के लिए साल्वेबर्ग के सभोध हुई बैठक ॥ आस्ट्रिया के चासलर बुनो प्रोस्वी, गैबिसको के राष्ट्रपति लुइस एन बैरिया, सेनेगल के राष्ट्रपति तियापोल्टे डेन्गोर, कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे इलियट ट्रूदो, स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलोफ पाम, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जे-एम डेन यूइल और अन्य प्रसिद्ध राजनयिक उपस्थित थे।

2. डोनेला एच० भीडोज, डेनिस एवं भीडोज, जार्जेन रेंडर्स विलियम डब्ल्यू ब्रैडरस 'द लिमिटेड टु डेय', 'ए रिपोर्ट फार ए क्लब ऑफ रोमस प्रोजेक्ट ऑन द प्रेडिक्मेंट ऑफ मेनकाइड', यूनिवर्सल बुक्स, न्यूयार्क, 1972.

3. वही, पृ० 9-10

पीढ़ी का अलगाव, परंपरागत मूल्यों का अस्वीकार, और मुद्रास्फीति और अन्य वित्तीय एवं आर्थिक विघटन।”¹

ऐसा प्रतीत हो सकता था कि इस प्रकार की स्पष्ट व बेलाग घोषणा के बाद उपर्युक्त सभी तथ्यों का उचित मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन लेखकों ने भिन्न मार्ग को ही वरीयता दी। उन्होंने वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर मौन रहना ही ठीक समझा : जैसे, श्रम और पूंजी के बीच सामाजिक अन्तर्विरोधों का बढ़ना, मेहनतकश जनता के शोषण का बढ़ना, और मजदूर वर्ग का अधिकाधिक विस्तार और बेरोजगारी में वृद्धि। पूंजीवादी विश्व में औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए विरोध के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया, नव उपनिवेशवाद की नीति के विरोध में, हथियारबंदी की दौड़, समस्त मानवता के विरुद्ध सैन्यवाद और आक्रमण की नीति के जहरीले परिणामों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया।

मोडोउ और उसके सहयोगी अपने प्रतिवेदन में विश्व से संबंधित पाँच मुख्य प्रवृत्तियों की गतिशीलता की खोज करते हैं : औद्योगीकरण का तेजी से विस्तार, जनसंख्याओं में तेजी से वृद्धि, व्यापक कुपोषण, नवीकरणयोग्य ससाधनों की समाप्ति और वातावरण का विकृत होना। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व विकास के बुनियादी कारकों का चुनाव इस प्रकार किया गया है कि उन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए जो कमोबेश समान रूप से पूरे मानव समाज से संबंध रखते हैं, बिना इस बात का विचार किए कि उसकी सामाजिक संरचना कैसी है। एक शब्द में, लेखकों ने सारांश में दो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विश्व के विभाजन की उपेक्षा की है और वे ‘एकमात्र विश्व समाज’ के नए किंतु निरर्थक प्रतिरूप के साथ सामने आते हैं।

प्रतिवेदन के लेखकों का विश्वास है कि इन घातक शक्तियों, विश्व के विकास के पाँच कारकों, की अंतः क्रिया सहजभाव से मानवता को महानाश की ओर धकेल रही है। सामान्य रूप से कहा जाए तो, उपर्युक्त पाँचों अंग अपरिहार्य रूप से परस्पर क्रिया करते हैं और उनका विकास मानव समाज को अंधी गली में धकेलता है। उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बिना आवादी नहीं बढ़ सकती और यह केवल औद्योगिक विकास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक विकास खनिज संसाधनों के उत्पादन बढ़ने पर निर्भर है जिनके शोषण से पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता है, और इससे कृषि उत्पादन को क्षति पहुँचती जो इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि को रोकती है।

लेखक कहते हैं, इस अविभाज्य और अन्तर्विरोधी परस्पर क्रिया के सभी

तत्वों का बढ़ता हुआ प्रभाव गति की निरन्तरता द्वारा एक सामान्य रेखीय प्रक्रिया के रूप में नहीं होता। यह उस नियम के अन्तर्गत आता है जिसे घातांकीय नियम कहते हैं अर्थात् उसका वेग सदा तीव्र होता रहता है। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि पर ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि की वही दर लागू होती है जिस दर से फ़ैक्टरियों और नगरों की संख्या बढ़ती है और यह माँग करती है संसाधनों की निरन्तर वृद्धि की। आर्थिक प्रगति पहले से भी ऊँची संख्या की माँग करती है ठीक उस सोच कथा की तरह जिसमें कि शतरंज के चतुर आविष्कर्ता ने करने की कोशिश की थी। पुरस्कार के रूप में उसने सुल्तान से कहा कि पहले वग में वह चावल का एक दाना रखे और हर वग में उसे दुगुना करता जाए। शतरंज फलक की पहली पंक्ति में उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं और बहुत धीरे-धीरे बढ़ती थी, लेकिन अगली पंक्ति में संख्या लाखों तक, फिर करोड़ों तक और फिर वह खगोलीय अंकों तक जा पहुँची! खेल के आविष्कर्ता को दिए वचन को निभाने के लिए सुल्तान को सारी दुनिया को जीतकर उसे चावल के सेत में बदल देना पड़ता। निन्दकों का कहना है कि चालाक सुल्तान ने इसका सौधा-सा समाधान ढूँढ़ निकाला—उसने केवल उस बुद्धिमान को मौत के घाट उतार दिया।

क्या यह समाधान ऐसा ही नहीं है जिसे कि रोम की गोष्ठी के विद्वान् प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति की माँगों के सम्मुख अपने को अधम पाते हैं? वे कहते हैं कि इस आसन्न महासंकट से बचने का एकमात्र मार्ग है विश्व की जनसंख्या को और साथ-ही-साथ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को रोकना। संगणक यंत्र की सहायता से इन पाँचों तत्वों (अंगों) की संभावित गतियों का आकलन करते मीडोज दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जन्म दर और मृत्यु दर संतुलित रही चाहिए तथा पूँजी-विनियोग भी मूल्य-ह्रास निधि से अधिक नहीं होना चाहिए। उनके मत से वृद्धि के स्थान पर स्थिरीकरण होना चाहिए। वे लिखते हैं: “वस्तुतः, हमारा विश्वास है कि नयी नयी क्रियाओं और प्राविधिक विकास का पक्षधर समाज, समानता और न्याय पर आधारित समाज संभवतः वर्तमान में अनुभव की जा रही वृद्धि की स्थिति की अपेक्षा वैश्विक संतुलन का स्थिति में ही विकसित हो सकता है।”¹

इस प्रकार का है उनका निष्कर्ष। यद्यपि प्रतिवेदन के लेखक उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान पूँजीवाद में जिनकी गहरी जड़ें हैं, शून्य वृद्धि जैसी अवधारणा उनके सही समाधान में किंचित भी लाभदायक नहीं है। ये काल्पनिक और प्रतिपामी दोनों प्रकार की हैं। काल्पनिक, क्योंकि पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा तथा ऊँचे मुनाफ़ों के

लिए दोड़ की स्थितियों में उत्पादन को जाम कर देने की बात सर्वथा अकल्पनीय है, स्वयं इजारेदारियां ही कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि वे पूंजी के संचय किए बिना जीवित नहीं रह सकती।

प्रतिगामी, क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक यथास्थिति को बनाये रखने में है और इसका सुझाव है कि पूंजीवाद की स्थिरता के लिए पूंजीवादी देशों में मेहनतकश जनता को अपने पर अतिरिक्त भौतिक त्याग का—बढ़ती बेरोजगारी, उपभोग में कटौती और जीवन के सामान्य स्तर में ह्रास आदि—भार उठाना चाहिए। पूंजीवादी दुनिया में मेहनतकश जनता स्वभावतः सबसे अधिक कष्ट भोगेगी।

शून्य-वृद्धि की अवधारणा वैचारिक रूप से मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक शक्तियों को नष्ट करने के लिए तैयार की गयी है क्योंकि यह विद्यमान पूंजीवाद के गहराते संकट पर पर्दा डालती है। मानव समाज की कठिन स्थिति के आरोप को यह भौतिक, प्राविधिक एवं जन संख्या के तत्वों पर डाल देती है। इसका लक्ष्य वर्ग-संघर्ष की तीव्रता को नष्ट करना है।

रोम की गोष्ठी की द्वितीय एवं तृतीय परियोजनाएँ

‘वृद्धि को सीमित करो’ प्रतिवेदन ने पश्चिमी विचारकों में हड़कम्प पैदा कर दिया। बादविवाद में इसकी कतिपय स्थापनाओं पर प्रश्न उठाये गये इसकी आँकड़ों संबंधी भविष्यवाणियों की बार-बार जाँच की गयी और उनमें से कुछ की आलोचना भी की गयी।

अन्त में रोम की गोष्ठी को मीडोज और उसके दल द्वारा निकाले निष्कर्षों को अस्वीकृत करने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ भूलें और खामियाँ थीं अपितु मुख्य रूप से इसलिए कि शून्य वृद्धि की अवधारणा इजारेदारी पूंजी के हितों से मेल नहीं खाती थी।

इसके बाद रोम की गोष्ठी की दूसरी रिपोर्ट सामने आयी। इसे अमरीका के कनीवलेड विश्वविद्यालय के प्रणाली विश्लेषण के विशेषज्ञ प्रोफेसर मिहाजलो मेसरोविक तथा पश्चिमी जर्मनी के प्रोफेसर एडुअर्ड पेस्टल ने तैयार किया। यद्यपि दूसरी रिपोर्ट के निष्कर्ष उतने क्रान्तिकारी नहीं हैं (लेखकों ने सामान्यतया आर्थिक वृद्धि को अस्वीकृत नहीं किया, अपितु इसे सीमित करने की ही सिफारिश की है) क्योंकि इसने गोष्ठी के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण की सामान्य रूपरेखा को पूर्णतया बनाये रखा है।

अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही लेखकों ने समकालीन पूंजीवाद की संकटपूर्ण स्थिति के संबंध में चर्चा की है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि सन् 2000 से 2025 में विश्व में अभूतपूर्व जनसंख्या-विस्फोट होगा, प्राकृतिक संसाधन निःशेष हो जाएँगे, गरीब और अमीर के बीच आर्थिक असमानता भयानक रूप से गहरी

हो जायेगी और वह आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को तीव्र कर देगी। इस 'प्रलय दिवस' को टालने के लिए लेखकों ने जिन उपायों की सिफारिश की है उन्हें वे अत्यधिक निर्णायक समझते हैं। उनके मत से विश्व की व्यवस्था मौलिक रूप से पुनः संगठित की जानी चाहिए। अन्यथा, अस्वस्थ कैंसर रूपी वृद्धि के, स्वभावतः, विश्व के विभिन्न भागों में अपने विशिष्ट रूपों में व्यक्त, समस्त परिणामों का खतरा है। और इसके विपरीत, सुव्यवस्थित वृद्धि के अन्तर्गत विभिन्न अंगों के बीच घनिष्ठ संबंध उनमें से प्रत्येक के विकास को नियंत्रित करते हैं।

एक वैश्विक सत्ता के रूप में मानवता एक विकल्प तक आ पहुँची है : या तो कैंसररूपी यह वृद्धि निरंतर होती रहे अथवा सुव्यवस्थित विकास की ओर संक्रमण हो।

लेखकों ने साहस के साथ यह प्रस्तावित करते हुए कि, विश्व व्यवस्था भौतिक रूप से पुनर्संगठित की जानी चाहिए, बड़े अस्पष्ट मुद्दों और व्यावहारिक सिफारिशों प्रस्तुत की है। कुल मिला कर वे मानव समाज को समस्त परेशानियों (चिंताओं) से मुक्त करने में इतनी रुचि नहीं रखते जितनी कि पूँजीवाद को बचाने में जिससे कि यह सुचारू रूप से कार्य कर सके। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच की खाई को पाट कर प्राप्त किया जा सकता है। अपने मुद्दों में मैसारीविक और पेस्टल दोनों समान रूप से विश्व के दो व्यवस्थाओं में विभक्त होने की और स्वयं पूँजीवाद के आन्तरिक विकास के नियमों की उपेक्षा करते हैं। कुल मिलाकर वे निरर्थक खींच-तान करते हैं और पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से असहाय हैं।

उदाहरण के लिए जब 'सुव्यवस्थित' अथवा 'संतुलित' वृद्धि का विचार रखते हुए जिसके विषय में वे समझते हैं कि यह विद्यमान 'असंतुलित एवं विभेदित वृद्धि' का स्थान लेगी, लेखकों के पास अत्यधिक महत्व की वस्तु के विषय में स्वभावतः कहने के लिए कुछ नहीं है—कि पूँजीवाद की योजनाविहीन और अराजकतापूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

उनकी यह मान्यता है कि विश्व-समस्याओं के संबंध में विभेदीकृत दृष्टिकोण इस विषय में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने अध्ययन में उन्होंने "साझी परम्परा, जीवन शैली व इतिहास, आर्थिकविकास का स्तर (मंजिल), समाजिक-राजनीतिक क्रम और उन मुख्य समस्याओं की जो समय-असमय इन देशों के समक्ष आती रहती हैं, विश्व-व्यवस्था को दस भागों में विभक्त किया : (1) उत्तरी अमरीका (2) पश्चिमी यूरोप (3) जापान (4) आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और विकसित बाजार अर्थव्यवस्था वाले शेष देश (5) सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप (6) लैटिन अमरीका (7) उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व (8) उष्ण कटिबन्धीय अफ्रीका (9) दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व एशिया तथा (10)

अंतर्राष्ट्रीय, वर्गीय और वैचारिक संघर्ष का तीव्र होना आदि उनकी नज़र से ओझल हो जाता है। उनकी व्यावहारिक सिफ़ारिशें—विश्व बैंक की स्थापना और ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों, खाद्य, औद्योगिक विनियोजन और अन्य मामलों के संबंध में इसी कारण से टिक नहीं पाती। इन संस्थाओं के क्रियाकलाप का वर्णन भी बड़ी अस्पष्ट भाषा में है क्योंकि लेखक विश्व को सम्पूर्ण सामान्यीकृत इकाई के रूप में देखते हैं, मसलों की वास्तविक स्थिति से पृथक्कृत काल्पनिक रूप में।

पूँजीवादी विश्व में वर्तमान परिस्थिति के दिवालियापन को आवश्यक रूप से स्वीकार करते हुए रोम गोष्ठी की तीसरी रिपोर्ट असाधारण समस्याओं के क्रान्तिकारी समाधान ढूँढने में पूँजीवादी आर्थिक विचार की असमता का और प्रमाण प्रस्तुत करती है।

इससे ज्ञात होता है कि मीडोज़, फिर मेसरोविक और पेस्टल, तथा अन्त में टिब्वरजन् के नेतृत्व में दलों के लेखकों द्वारा तैयार की गयी भिन्न-भिन्न तीनों रिपोर्टें जो गोष्ठी के सिद्धान्तिक अध्ययन है वास्तव में पूँजीवाद के काल्पनिक समर्थन के विभिन्न रूप हैं। वे इस प्रकार के नव्य प्रयोग प्रस्तुत करती हैं जो तथ्य रूप में चीजों की उसी रूप में छोड़ देते हैं जैसी कि वे हैं, पूँजीवाद के आधारों को रचमात्र भी प्रभावित नहीं करते और काल्पनिक आशाओं के प्रकट करने से आगे नहीं बढ़ती तथा पूँजीवादी विश्व के शासकों को अपनी भूख को थोड़ा कम करने की सलाह देते हैं।

दूसरी ओर, 'विश्व के विनाश की अवधारणा' स्पष्ट रूप से इस तथ्य की स्वीकृति है कि आर्थिक प्रगति पूँजीवाद की समस्याओं का समाधान नहीं है और कि पूँजीवाद के अन्तर्गत वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति के लाभों का उपयोग मानव समाज को अंधी गली में ले जाता है। क्या यह पूँजीवादी सामाजिक संबंधों के दिवालियापन की स्वीकृति नहीं है? युगों से यह सोचा जा रहा है कि आर्थिक विकास और पूँजीवाद अविभाज्य हैं। पूँजीवादी सिद्धान्तकार सदा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते रहे हैं। आर्थिक प्रगति दोनों ही थी, आवश्यक भी और वांछनीय भी, और आज वे यदि 'सीमित वृद्धि' 'वृद्धि को सीमित करो' और 'शून्य वृद्धि' की बात करते हैं तो क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि पूँजीवाद की क्षमता सकुचित हो रही है, कि यह कुछ सीमाओं में ही काम कर सकती है और यह कि इसके आरक्षित भंडार खाली हो रहे हैं?

जीवन की गुणवत्ता की पहलियाँ

यह कहना आवश्यक नहीं कि कम्युनिज्म के विरोधी विचारक सर्वाधिक प्रयास इस बात के लिए कर रहे हैं कि जनता को यह समझने से रोका जाये कि पूँजीवाद मोत की घड़ियाँ गिन रहा है। कुछ समय से वे लोग 'जीवन की गुणवत्ता'

को मुद्रारतने के नारे का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि लक्ष्य सिद्धि का पथ प्रकाशित हो गये। यह शब्दावली जॉन गालब्रेथ द्वारा प्रचारित की गयी थी। जबकि अमरीकी विद्वान ने इसका उपयोग सामान्य रूप से यूरोपी के उन्मूलन की आवश्यकता पर बन देने के लिए किया था, धीरे-धीरे इसकी अधिक व्यापक व्याख्या की जाने लगी विशेषतः यूरोप में जहाँ कि पूँजीपतियों ने और सामाजिक जनवादी विद्वान्तरों ने इसे उत्सुकता के साथ ग्रहण कर लिया।

जो लोग आज भी विश्वास नहीं करते कि मानव-समाज के समस्त विद्यमान समस्याएँ प्राविधिक साधनों और आर्थिक उन्नति की सहायता से हल कर ली जाएँगी, वे पश्चिम जर्मनी के दार्शनिक ज्यार्ज पिङ्गन की दृष्टि पर और अधिक आश्रित हैं। पिङ्गन कहते हैं—“मानव जाति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कोई गुणरमक छाना सामूहिक भौतिकता और सामूहिक बुद्धि को ऊँचे स्तर तक उठायेगी अथवा नहीं—आकाशित भविष्य आसमान से नहीं आयेगा, नयी संपदा की खोज, और हमारी प्राविधिक और औद्योगिक संसाधनों का बहुगुणित होने सफलताओं के परिणामस्वरूप, क्योंकि ये उपलब्धियाँ चाहे कितनी भी आवश्यक हों केवल विनाश की प्रक्रिया को तीव्र कर सकती हैं जब तक कि कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनायी जाती जो इन संसाधनों का समझदारी के साथ सुविचारित उपयोग कर सके। जर्मन दार्शनिक ने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किया : “मानव-समाज अपना भविष्य केवल नैतिक तथा आध्यात्मिक पहलकदमी की सहायता से ही सुरक्षित कर सकता है जो इतिहास में अनुपम होगा।”¹

पश्चिमी विचारकों को समस्या की ऐसी विस्तृत व्याख्या बड़ी अनुकूल लगी। उन्होंने इसे एक ऐसे सामान्य मंच के रूप में माना जिस पर कि 1960 एवं 1970 के दशकों के पूँजीवादी विचारों की भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाली धाराएँ विद्यमान रहें और एक-दूसरे की पूरक भी बन सकें। आधुनिक समाज के जीवन में वस्तुतः ‘प्राविधिक नियतिवाद’ को अस्वीकृत किए बिना (‘औद्योगिकवाद’ और ‘औद्योगिकोत्तरवाद’ की अवधारणाएँ) ‘जीवन की गुणवत्ता’ को बढ़ाने की अपील साथ ही अत्यधिक आर्थिक विकास के विरुद्ध चेतावनी है (पर्यावरणिक विध्वंस की अवधारणा)। इस विचार पर भी जोर दिया जाता है कि विश्व इस समय इस प्रकार गंभीर परिवर्तनों की देहरी पर खड़ा है जिसके समक्ष समाजवादी परिवर्तन पृष्ठभूमि में चले गए हैं और निरर्थक हो गए हैं।

‘जीवन की गुणवत्ता’ का नारा सबसे बढ़कर जनता का ध्यान पूँजीवाद के अंतर्विरोधों से, इसके सामाजिक विरोधों की कटुता से दूर हटाने के लिए, इस तथ्य

को छिपाने के लिए कि मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ गया है, तथा उसकी समाज के वास्तविक क्रांतिकारी रूपांतरण के सही उद्देश्य से अलग हटाने के लिए, दिया गया है। यह नारा यह भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है कि मजदूरों के पक्ष में सामाजिक स्थितियों का सुधार—शरीबी का उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी, जन-स्वास्थ्य में सुधार, शैक्षणिक सुअवसर और काम और विधायन की स्थितियाँ तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सम्मान की सुरक्षा—पूँजीवाद के अंतर्गत ही संभव है। यह सब करने के लिए, वे कहते हैं, कि यह अनिवार्य है कि अधिक उन्नति को स्थायी किया जाय (जब कभी भी उत्पादन के पूँजीवादी संबंधों से इसका विवाद अधिक मुखर हो उठे) और विद्यमान पूँजीवादी संस्थानों के स्वरूप को सबसे बढ़कर, गुणात्मक लक्षणों पर विश्वास करते हुए बदला जाय (समाजवादी देशों की तुलना में जो कथित रूप से शुद्ध 'परिमाणात्मक' सुधार की आकांक्षा रखते हैं)।

बहुत से सामाजिक जनवादी नेता इस दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सहमत हैं। वे मानते हैं कि कतिपय ब्रूज्वा संस्थाओं का विकास आवश्यक है कि पूँजीवादी समाज को अधिक समय तक पूँजीवाद न माना जाय अपितु उसका रूप 'जनतांत्रिक समाजवाद' के रूप में स्वीकृति प्राप्त करे। हंस जोशन बोगेल घोषणा करते हैं, 'जीवन की गुणवत्ता' जनतांत्रिक समाजवाद का केंद्रीय विचार है।

दक्षिणपंथी सामाजिक जनवादी नेता उदारतापूर्वक इन संभावनाओं को चित्रित करते हैं जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम में लिखा गया है 'जीवन की गुणवत्ता' साधारण रूप से जीवन का ऊँचा स्तर ही नहीं है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता है, जिसमें भय से मुक्ति, आत्म-निर्णय और आत्मोपलब्धि के लिए, प्रशासन में भागीदारी और उत्तरदायित्व में हिस्सेदारी, ऊर्जा को भ्रम में समझदारी के साथ के प्रयोग का अवसर... प्रकृति के साथ तादात्म्य, और सांस्कृतिक मूल्यों की अधिक उपलब्धि, स्वस्थ बने रहने का अवसर अथवा पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करना, सम्मिलित है। जीवन की गुणवत्ता का अर्थ है हमारे जीवन की संपन्नता तथा भौतिक उपभोग की सीमाओं के परे जाकर श्रेष्ठ होना।¹

तथापि, मजदूर जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की उसकी सभी प्रतिज्ञाएँ तब तक योधी आवाजे रहेगी जब तक इस बात की गारंटी नहीं होगी कि इनको प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा। और इस प्रकार की पूर्ण विश्वसनीयता स्वयं श्रमिक जनता की शक्ति में है।

'जीवन की गुणवत्ता' की अवधारणा के अन्य सामाजिक परिघटनाओं के साथ द्वंदात्मक संबंध की परीक्षा करके एक सौ वर्ष पूर्व वैज्ञानिक कम्युनिज्म के संस्थापकों की कृतियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। मार्क्स और एंगेल्स ने

जर्मन विचारधारा में लिखा था : "उत्पादन की इस प्रणाली को सामान्यतया केवल व्यक्तियों के शारीरिक अस्तित्व के पुनरुत्पादन के रूप में ही नहीं समझना चाहिए। बजाय इसके वह इन व्यक्तियों की क्रिया का निश्चित रूप है, उनके जीवन को प्रकट करने का निश्चित रूप, उनकी ओर से जीवन की एक निश्चित प्रणाली है। वे क्या हैं... इसकी सगति (उनके उत्पादन के साथ) वे क्या उत्पादित करते हैं और कैसे उत्पादित करते हैं—के साथ व्यक्त होती है। अतः व्यक्ति क्या हैं यह उनके उत्पादन की भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"³

'जीवन की गुणवत्ता' सर्वोपरि एक सामाजिक अवधारणा है। इसके मुख्य सूचक हैं: प्रथम, समाज में जो भी सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्य उपलब्ध हैं; दूसरे, कौन और किन परिस्थितियों में इन मूल्यों को पैदा करता है; तीसरे, समाज के सदस्यों में उनका वितरण किस प्रकार किया जाता है और अंततः किस प्रकार यह वितरण मानव व्यक्तित्व के विकास को प्रोन्नत करता है। अंतिम विश्लेषण में यह मनुष्य ही है जो सब वस्तुओं को मापता है और फलस्वरूप किसी भी समाज का जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार मनुष्य की भौतिक और आत्मिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है।

इस समय तक के पूंजीवादी समाज के विकास का समस्त अनुभव अकादम्य रूप से सिद्ध करता है कि भले ही इसने चाहे जितने मूल्यों का संघर्ष किया हो पूंजीवादी व्यवस्था सदा शोषण की, सामाजिक असमानता की और गंभीर वर्ग-संघर्ष की व्यवस्था रही है। यह मानव समाज की किसी विकट समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसके पक्षपोषक चाहे जितने वायदे क्यों न करें, पूंजीवाद सदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेगी, यह सामाजिक विरोध की, बेरोजगारी की, भविष्य में असुरक्षा की, नैतिक अधःपतन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध की व्यवस्था बनी रहेगी। पूंजीवाद के अंतर्गत 'जीवन की गुणवत्ता' के सुधार के संबंध में बात करना कैसे संभव है जबकि परोपकार की धारणा के बजाय श्रमिक जनता के शोषण द्वारा मुनाफ़े के ढेर जमा करना सदा और आगे भी इस व्यवस्था की मूल प्रेरक शक्ति रहेगी? और बड़ी-से-बड़ी मानवीय परियोजनाएँ भी इस स्थिति को नहीं बदल सकती।

यह एक अलग बात है कि साम्राज्यवाद के सिद्धांतकार जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में प्रश्न उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं और इस प्रकार की समस्याओं के विषय में जैसे गरीबी का उन्मूलन, जनस्वास्थ्य सेवाओं का और शिक्षा का सुधार, काम और विश्राम की स्थितियों का सुधार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की बात करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसके पीछे दो कारण हैं जिनसे वे प्रेरित हुए हैं।

सर्वप्रथम, उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ता है कि इन समस्याओं को समाजवाद के अतर्गत भलीभाँति हल कर लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि 'जीवन की गुणवत्ता' में सुधार का नारा समाजवाद की चुनौती के प्रत्युत्तर में पूँजीवादी सिद्धांतकारों की पाखंड पूर्ण प्रतिक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। बल्कि पूँजीवादी प्रचार इस अवधारणा को अपनी नीति का हथियार बना लेता है, इसके लिए वह इसे उस अर्थ से जो समाजवादी विचारधारा में लिया जाता है वचित कर देता है इसे सारहीन बना कर वह इसको पश्चिमी आदर्श में ढाल देता है।

इजारेदार पूँजीपतिवर्ग के सिद्धांतकार 'जीवन की गुणवत्ता' के नारे को समाजवाद का विकल्प मानते हैं, एक ऐसा विकल्प जो वर्तमान प्रशासन में केवल थोड़ा-सा सुधार प्रस्तुत करता है, पूँजीवादी विश्व में समस्याओं के संबंध में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की बात नहीं करता। ;

साम्राज्यवादी शक्तियों के शासक वर्ग इस नारे का उपयोग वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति तथा पूँजीवादी देशों में चल रहे वर्ग-संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियों के जवाब के रूप में करते हैं। सर्वोपरि यह श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन के संबंधित है जो तेजी से हो रही प्राविधिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, और काम करने की स्थितियों में सुधार पर अतिरिक्त विनियोजन के बिना सोचा भी नहीं जा सकता; पूँजीपति वर्ग यह भार उठाने के लिए विवश है, किसी लोकोपकार के विचार से नहीं, अपितु स्वयं उत्पादन की माँगों को पूरा करने के और मुनाफे बटोरने के लिए। दूसरी ओर, पूँजीवादी देशों में वर्ग-संघर्ष का वर्तमान स्तर पूँजीवादीयों के सामने वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं रहने देता सिवाय इसके कि वह मजदूर-वर्ग जनता को कुछ और रियायतें दे।

तथापि इस अवधि में उल्लेख योग्य मुख्य बात है, कि 'जीवन की गुणवत्ता' की धारणा के विषय में कोई समान रवैया नहीं अपनाया जाता। इस संबंध में पूँजीवाद का और समाजवाद का अनुभव एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है व परस्पर विरोधी भी है बशर्ते कि उसका मूल्यांकन सीमित और शुद्ध रूप से सब ही तुलना तक सीमित हो।

अन्त में, क्या पूँजीवादी सिद्धांतकारों को यह नहीं दिखाई देता कि 'जीवन की गुणवत्ता' के संबंध में बात उठाने में उन्होंने बहुत बिलब कर दिया? यह एक सच्चाई है कि यह विषय पश्चिम में कम-से-कम तीन सौ वर्षों तक यूरोप में पूँजीवादी शासन रहने के बाद उठाया गया। यह इस कठोर सत्य की, कि पूँजीवाद जनता के हित में इस समस्या का समाधान करने में अक्षम है, अप्रत्यक्ष स्वीकृति है।

x

x

x

इस प्रकार उपर्युक्त समीक्षा ने साम्राज्यवाद की बुनियादी वैचारिक अवधारणाओं को और समकालीन पूँजीवादी और सुधारवादी विचारों के सामान्य विकास को

निरावृत कर दिया है। गत 15-20 वर्षों में इन विचारों में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। पचास के दशक की उल्लास की स्थिति से आगे बढ़ कर यह तेजी से पूंजीवादी विकास के अधिक तर्कपरक मूल्यांकन करने की ओर प्रवृत्त हुआ और तब निराशावाद की गहराइयों में डूबने-उतरने लगा। स्पष्ट रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत जिसकी कोई संभावना नहीं उसी 'जीवन की गुणवत्ता को सुधारने' के आह्वान के साथ उस भविष्यवाणी के पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके क्रयामत तक पहुँचने की बात कही गई है।

यह वह समय था जब साम्राज्यवादी सिद्धांतकार कम्युनिज्म का वास्तविक विकल्प ढूँढ़ने के लिए पागलपन भरा निरर्थक प्रयास कर रहे थे। वृज्वा विद्वानों की सैद्धांतिक अवधारणाओं में वर्तमान वास्तविकता के अलग-अलग पहलुओं को सही ढंग से तराश कर किया प्रस्तुत जाता है। कभी-कभी इनमें कुछ बहुत मनोरंजक बातें भी दिखाई दे जाती हैं। किंतु इनमें से कोई भी समग्र सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत नहीं करता और इसलिए कोई भी सैद्धांतिक प्रबन्ध होने का दावा नहीं कर सकता। कुल मिलाकर पूंजीवादी विचारधारा आज तक जो उत्पन्न कर पाई है वह है जीवन से असंपृक्त स्थापनाएँ, मानवता के अंधी गली में पहुँच जाने से संबंधित वक्तव्य, और ऐतिहासिक प्रगति की नई 'कसौटी' के पाखंडपूर्ण पदों के पीछे आज की विशिष्ट समस्याओं को टालने का प्रयास। यह वर्तमान युग के मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्लेषण के समक्ष टिक पाने में एकदम असमर्थ है।

विश्व पूंजीवाद का अधःपतन

कारण दूर कर दीजिए, रोग अपने आप चला जायेगा ।

—हिप्पोक्रेट्स

लेनिन द्वारा साम्राज्यवाद का विश्लेषण

साठ वर्ष से अधिक हो गए, 1916 की गर्मियों में, लेनिन ने अपनी 'साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था' नाम की पुस्तक पूरी की, जो कि आगामी दशकों में विश्व-मुक्ति-आन्दोलन की कार्यनीति एवं रणनीति के विविध पहलुओं को कई तरह से पूर्व निर्धारित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

इस काल में पूंजीवाद के विकास में गुणात्मक रूप से नये रूप सामने आ रहे थे : श्रम और पूंजी के बीच अन्तर्विरोधों ने अभूतपूर्व तीव्रता प्राप्त कर ली थी और प्रभावशाली के पुनः वितरण के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के संघर्ष का परिणाम विश्व युद्ध के रूप में आया । पूंजीवादी सम्बन्धों के विकास के कारण उत्पन्न संकट ने मानव समाज को महानाश के कगार पर ला खड़ा किया ।

लेनिन की पुस्तक उस काल की ऐतिहासिक स्थिति का प्रत्युत्तर थी । इसने उसके मूल कारणों और पूंजीवाद के साम्राज्यवाद में विकसित होने के रचनाक्रम पर प्रकाश डाला । और साम्राज्यवाद के लक्षणिक रूपों को तथा गहराई में विद्यमान अन्तर्विरोधों को निरावृत किया । इस कृति में लेनिन ने इतिहास में साम्राज्यवाद के स्थान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया—समाजवादी क्रान्ति के उदय के रूप में, एक वर्ष से थोड़े अधिक समय में हुई 1917 की अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय ने, भविष्यवक्ता के निष्कर्षों को पुष्ट कर दिया । बाद के दशकों ने भी लेनिन के दूसरे निष्कर्षों को सही सिद्ध कर दिया ।

लेकिन जीवन जितना अधिक लेनिन के साम्राज्यवाद के विश्लेषण के समर्थन में और प्रमाण देता जा रहा है, उतना ही उनको साम्राज्यवादी विचारक गलत सिद्ध करने के कठिन प्रयास कर रहे हैं । वे सभी उपलब्ध बहानों का उपयोग करके मजदूर

वर्ग को यह गमझाने की कोशिश करते हैं कि लेनिन द्वारा किया गया वैज्ञानिक विश्लेषण अपूर्ण है। वे कहते हैं कि समाजवादी क्रान्ति के नेता ने आगे होने वाले विकास द्वारा उत्पन्न परिघटनाओं को पहले से नहीं देखा और इसलिए पूंजीवाद की 'क्षमता' को कम करके आंका और इसके सामाजिक अन्तर्विरोधों की तीव्रता को भी 'बढ़ा-चढ़ाकर' बताया और इस प्रकार इसका परिणाम यह हुआ कि उनके निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण रहे।

बड़े पैमाने पर, लेनिन की रचना के सम्बन्ध में बार-बार अपनी एकांगी आलोचना के साथ-साथ पूंजीवादी सिद्धान्तकार कम्युनिस्टों को वास्तविकता को सरल बनाकर दिखाने के लिए लांछित करते हैं। उनका विश्वास है कि आजकल, और वर्तमान युग में, सामाजिक विकास की परिघटना उस समय से कहीं अधिक जटिल है जिसकी कल्पना वैज्ञानिक कम्युनिज्म के शास्त्रीय ग्रन्थों में की गई थी। इस प्रकार कट्टरता का आरोप लगाते हुए वे कहते हैं कि मार्क्सवादी जानबूझ कर उन नये अवसरों की उपेक्षा करते हैं जो हाल के वर्षों में पूंजीवाद के समक्ष उद्घाटित हुई हैं। कम्युनिस्टों पर लचीलेपन की कमी का आरोप लगाया जाता है : कि वे तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संबंध में नया और व्यापक दृष्टिकोण काम में लेने की बजाय इनकी ओर अपनी आंखें मूंद लेते हैं।

लेनिन और उसके अनुयायियों को 'अपदस्थ करने' 'सुधारने' और उनका 'अतिक्रमण करने' के असंभव कार्य को हाथ में लेकर ये दोषान्वेपी पूंजीवादी और संशोधनवादी वस्तुतः कम्युनिस्ट विचारों की आलोचना नहीं करते। वे वास्तव में जिस पर आक्रमण करते हैं वह एक प्रकार से उनका अपना आविष्कृत भ्रष्ट सिद्धान्त है जिसकी लेनिनवाद से कोई समानता नहीं है। वास्तव में वे ऐतिहासिक विकास की मथार्य रूप से विद्यमान प्रक्रिया की परीक्षा नहीं करते, बल्कि केवल उसकी अलग-अलग, मनमाने ढंग से चुनी गई और असंबद्ध परिघटनाओं की परीक्षा करते हैं।

कई दशक पहले लेनिन ने उस वैचारिक संघर्ष की मुख्य दिशाओं की भविष्यवाणी कर दी थी जो पूंजीवाद के विकास के साम्राज्यवादी युग में प्रवेश करते समय आरम्भ हुआ था। उन्होंने लिखा : "यहाँ हम पूंजीवाद के नवीनतम दौर—अर्थात् साम्राज्यवाद के सैद्धांतिक मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं वह यह है कि पूंजीवाद इजारेदार पूंजीवाद हो गया है। इस बाद की अवस्था पर जोर देना चाहिए क्योंकि पूंजीवादी सुधारवादियों के त्रुटिपूर्ण दावे ये हैं कि इजारेदार पूंजीवाद या 'राज्य-पूंजीवाद' कोई पूंजीवाद नहीं है बल्कि उसे—'राज्य-समाजवाद' कहा जाना चाहिए। लेनिन ने आगे बताया कि बावजूद कुछ परिवर्तनों के "हम आज भी पूंजीवाद के अन्तर्गत रह रहे हैं—उसकी नई अवस्था में, यह सही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अब भी यह पूंजीवाद है। इस प्रकार के पूंजीवाद

की समाजवाद से समीपता सर्वहारा वर्ग के सच्चे प्रतिनिधियों के हाथ में समाजवादी क्रान्ति की समीपता, सुविधा व्यावहारिकता और तात्कालिकता के लिए एक तर्क है, इस बात के लिए सर्वथा नहीं कि इस प्रकार की क्रान्ति के उन्मूलन को सहन किया जाय। यह पूंजीवाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करने जैसा है। सभी सुधारवादी इस तरह के प्रयास किया करते हैं।" (जोर हमारा बी० के०)¹

अपनी कृति "साम्राज्यवाद : पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था" में लेनिन ने प्रमाणित कर दिया है कि (प्राविधिक प्रगति एवं उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप) उत्पादन और पूंजी के केन्द्रीकरण से मुक्त प्रतियोगिता का पूंजीवाद बनेगा जो अधःपतित और मरणासन्न पूंजीवाद के रूप में होगा—साम्राज्यवाद जो पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था होगी और समाजवादी पूर्व संध्या क्रान्ति होगी।"

लेनिन ने लिखा "साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था है। इसके तीन विशिष्ट लक्षण हैं : (1) इजारेदारी पूंजीवाद, (2) परजीवी या क्षीयमाण पूंजीवाद, (3) मरणासन्न पूंजीवाद।"²

हमारे वैचारिक विरोधी इन बुनियादी परिणामों के विरुद्ध मुख्य रूप से आक्रमण करते हैं। इसका सीधा-सा कारण है कि ये पूंजीवाद की कलाई खोलते हैं, उसकी ऐतिहासिक नियति को प्रकाश में लाते हैं, विद्यमान वर्ग-संघर्ष के सार को स्पष्ट करते हैं और विविध प्रकार से विरोधी शक्तियों के परस्पर सम्बन्ध को पूर्व निर्धारित करते हैं। इसके लिए यदि पूंजी की और इजारेदारी की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है जैसे इसकी परजीविता निरंतर बढ़ती जाती है तो इसका अर्थ है कि कम्युनिस्ट सही कहते हैं—जब वे पूंजीवादी विश्व में वर्ग-शक्तियों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और वहाँ विरोधात्मक अंतर्विरोधों के विषय में और पूंजीवाद के नाश के लिए वस्तुगत पूर्वावश्यकताओं के संबंध में बात करते हैं। दूसरी ओर यदि इन प्रक्रियाओं को अमदेखा किया जाए तो ज्ञात हो जाएगा कि पूंजीवाद के नवीकरण में पूंजीवादी सिद्धान्त रेत पर नहीं खड़े हैं। वास्तविक स्थिति क्या है? हमें तथ्यों को देखना चाहिए।

श्रमिक जनता के हितों की चिन्ता किए बिना पूंजी का संचयन

साम्राज्यवाद के सारतत्त्व को रंगीन बनाकर प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत कोई भी सिद्धांत पूंजी और उत्पादन के, और फलस्वरूप, मुनाफ़ों के संकेन्द्रण के तथ्य को बदल नहीं सकता। यह आधुनिक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का केवल एक विशिष्ट

1. बी० आई० लेनिन, 'द स्टेट एंड रिवोल्यूशन', कलेक्टेड वर्क्स खंड 25, पृ० 447-48

2. बी० आई० लेनिन 'इंपीरियलिज्म एंड द स्पिस्ट इन सोशलिज्म', कलेक्टेड वर्क्स, खंड 23, पृ० 105

रूप नहीं है अपितु इसके विकास को शामिल करने वाला क्रान्ति भी है। इजारेदारियों अधिकतम संभव मुनाफे के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती। लेकिन क्योंकि मुनाफे की मात्रा पूँजी की दर के बढ़ने पर निर्भर होती है इसलिए इजारेदारियाँ वस्तुगत रूप में इसके उच्चतम संभव संकेन्द्रण के लिए प्रयास करती हैं।

लेनिन ने इस सामान्य नियम की ओर इंगित किया है। किन्तु जब उनकी कृति "साम्राज्यवाद: पूँजीवाद की उच्चतम अवस्था" प्रकाशित हुई तब यहाँ उद्योग की समस्त शाखाओं को नियंत्रित करने वाले मात्र चन्द उद्योग थे। स्टील और सोडा उद्योग में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन, तेल उद्योग में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और ऑटोमोबाइल उद्योग में जनरल मोटर्स कारपोरेशन। निस्संदेह आज 350 इजारेदारियाँ उत्पादन का नियंत्रण करती हैं जिनमें पूँजीवादी दुनिया की दो-तिहाई कथशक्ति लगी है। उदाहरण के लिए फ्रांस में केवल 25 औद्योगिक और विशाल वित्तीय कंपनियाँ सर्व शक्तिमान इजारेदारियों के उच्च स्तर पर हैं। संघीय जर्मनी में लगभग 200 परिवार अर्थ-व्यवस्था के मूल केन्द्रों पर स्थित हैं, और अमरीका में 500 कंपनियाँ दो-तिहाई औद्योगिक उत्पादन का नियंत्रण करती हैं, और इस क्षेत्र के तीन-चौथाई मुनाफे को हड़प जाती हैं।¹

हमारे समय में उत्पादन बड़ी तेजी के साथ संकेन्द्रित होता जा रहा है। यह उन महत्वपूर्ण कारकों के क्रम में स्वाभाविक ही है—जिन्हें संयोगवश, पूँजीवादियों और मुधारवादी सिद्धांतकारों ने बेहद झुठलाने का प्रयास किया है।

प्रथम, इस समय संकेन्द्रीकरण और केन्द्रीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति की स्थितियों के अंतर्गत बढ़ती जा रही है। इसने जिस विशेषीकरण और प्राविधिक आधुनिकीकरण को संगठित किया है वह अधिक पूँजी लगाने की तथा आर्थिक सहयोग—अर्थात् उत्पादन के सामाजिकीकरण—की माँग करता है। यह सभी जानते हैं कि पूँजीवाद के अन्तर्गत ये तत्व प्रत्यक्ष सीधे-सीधे पूँजी के संचयन की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर, प्राविधिक प्रगति के सारांश को ग्रहण करके पूँजीवाद ने अत्यधिक औद्योगीकृत देशों में उत्पादक शक्तियों के लक्षित विकास को प्राप्त करने का किसी स्तर तक प्रबंध किया है। उदाहरण के लिए, युद्ध के काल से इन देशों में धर्म की उत्पादकता कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ, वेतन में वृद्धि बहुत नीची रही है। इस प्रकार वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति की स्थिति में मेहनतकश जनता के शोषण का स्तर पूँजीवादी विश्व में घटा नहीं, अपितु इसके विपरीत, तेजी के साथ बढ़ा है। पूँजीवादी प्रचार इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। इसका स्पष्ट और सीधा-सा कारण यह है कि यह 1960 के दशक में दिखाएँ इसके आर्थिक चमत्कार के वास्तविक कारणों को प्रकट कर देता है। यह केवल आर्थिक अतिरिक्तताओं की कीमत पर हुआ

अर्थात् अतिरिक्त मूल्यों की कीमत पर (जिसे कि उत्पादन के साधनों के विकास में प्रगति करके सुनिश्चित किया गया), श्रम के और अधिक विस्तार के कारण और विकासशील देशों की खुली लूट के निरंतर जारी रहने की कीमत पर संभव हुआ जिसका पूँजीवाद ने अपनी ऐसी व्यापक विज्ञापित समृद्धि प्राप्त करने का कुछ समय तक जुगाड़ बैठाया। लेकिन पूँजीवाद के अन्तर्गत इस उत्पादन वृद्धि के क्या परिणाम रहे और इससे किसके हित पूरे हुए? पूँजीवादी प्रचार इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता जब कि यह विषय बुनियादी महत्व का है। उत्पादन की वृद्धि से पूँजी का सघन संचयन हुआ इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक और वित्तीय इजारेदारियों के हाथ में और अधिक आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो गयी और उनका अधिपत्य भी बढ़ गया।

दूसरे, सान्दीकरण की प्रक्रिया ने राज्य इजारेदारी का रूप धारण कर लिया। इसकी नई गुणवत्ता इस सध्य में प्रदर्शित हुई कि पूँजीवादी राज्य वास्तविक रूप में सान्दीकरण की प्रवृत्तियों का संगठनकर्ता अथवा संरक्षक बन गया। इस क्षमता से युक्त होकर विशेष रूप से आधुनिक आयुधों का निर्माण करने वाले उद्योगों में, जो शासक वर्ग दीर्घकालीन राजनीतिक हितों तथा इसकी वैदेशिक नीति के लक्ष्यों के साथ सम्बद्ध हैं, इसका निहितार्थ है ऐसी कुजियाँ जैसे कानून निर्माण, वजट तथा करो की नीतियाँ सरकारी अनुदार और इसी प्रकार की अन्य चीजें।

इस प्रकार पूँजीवादी राज्य उन क्रिया-कलाप को जिन्हें कि पहले निजी पूँजी द्वारा सम्पन्न किया जाता था अधिकाधिक अपने हाथ में लेता जाता है। निस्संदेह, ऐसा करते हुए वह समूचे समाज के हितों को पूरा करने का प्रयास नहीं करता। इसके विपरीत, इसका लक्ष्य इजारेदारियों के मुनाफ़े बढ़ाना हो जाता है, दोनों ही तरह से, जनता का शोषण जारी रखकर और सरकारी निधियों का उपयोग करके। बड़ी पूँजीवादी इजारेदारियों के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए राज्य वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति के फलों को हड़पने की कोशिश करता है जिससे कि श्रम शक्ति का विस्तार किया जा सके और शोषण को छिपाया जा सके और इस प्रकार बाहरी विस्तार को सुविधाजनक बनाया जा सके। और इस पर जो व्यय हो उसे निरपवाद रूप से मजदूर वर्ग उठाए।

तीसरे, हमारे समय में इजारेदारियों का विस्तार एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना बन चुका है। विशाल इजारेदारियों और उच्च इजारेदारियों ने राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दिया है, राज्यों की सीमाएँ ताँघकर संघ बना लिये हैं, जिनका कोई एक नाम नहीं है और उन्हें विभिन्न रूपों में जैसे परराष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अतिराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय आदि नामों से पुकारा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पहले-पहल इस शताब्दी के मोड़ पर दिखाई दी थी, लेकिन वे शताब्दी के मध्य से बड़ी विशेष भूमिका निभा

रही हैं। 1971 में परराष्ट्रीय कंपनियों ने पूँजीवादी विश्व के कुल विनियोग के 90 प्रतिशत पर नियंत्रण कर रखा था और उनका अपने बड़े हुए सामान्य राष्ट्रीय उत्पादन तथा विदेशी व्यापार के व्यवसाय के तीसरे भाग पर नियंत्रण था। कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार 1980 तक तथा कुछ अन्य के अनुसार 1985 तक 300 प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम विश्व के निर्माता उद्योगों के 75 प्रतिशत पर नियंत्रण रखेंगे और दस या बीस वर्षों के बाद कुछ उत्पादन के 75 प्रतिशत पर वे नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे।¹

अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों में निरंतर हो रहा विस्तार स्पष्ट रूप से हमारे समय में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का एक निश्चित लक्षण है। यह तथ्य निस्संदेह रूप से स्पष्ट करता है कि उत्पादन के, पूँजी के निर्यात का तथा इजारेदार गुटों का विभाजन तथा पुनर्विभाजन अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में बढ़ रहा है जैसा कि लेनिन ने कई दशक पहले स्पष्ट रूप से बताया था।

अंतर्राष्ट्रीय बड़े प्रतिष्ठानों के पास विपुल पूँजी है और कपट कौशल का उपयोग करने की उन्हे पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए उनके क्रियाकलाप से समकालीन साम्राज्यवाद को आर्थिक विस्तार के लिए सीमातीत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। सार यह है कि स्थानीय अधिकारियों से और राष्ट्रीय सरकारों से अनियंत्रित तथा व्यापार और चुंगी की तयशुदा नीति के प्रतिबंधों से व्यावहारिक रूप से मुक्त, ये वित्तीय व्यापारिक-आर्थिक 'सर्वोच्च शक्तियाँ' राज्य के ऊपर राज्य, 'अपने ही कानून' लागू करते हैं जो राज्यों की सीमाओं के पार चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ (जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत से विषयों में स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर लगी अमरीकी पूँजी के आधिपत्य को छिपाने के लिए एक मुखौटा है) पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था की समस्त शाखाओं पर नियंत्रण रखती है। और इससे भी बढ़कर, वे बहुत से मामलों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को निर्धारित करती हैं और इन राज्यों की नीतियों पर गहरा प्रभाव रखती हैं। एक समय था जब विदेशी पूँजी उपनिवेशों पर आधिपत्य रखती थी अब औद्योगिक रूप से आगे बढ़े हुए देश भी उसके शिकार बन गये हैं।

बहुत से अध्ययनों में इसके प्रमाण मिलते हैं। इनमें से एक है अमरीकी अर्थ-शास्त्री रिचर्ड वॉनट और रोनाल्ड मूलर की 'पावर ऑफ़ मल्टिनेशनल कारपोरेशन्स' नामक कृति। लेखकों ने स्पष्ट रूप से इस संबंध में लिखा है—इसे वे विश्व अर्थव्यवस्था का अमरीकीकरण कहते हैं और शिकायत करते हैं कि अमरीकी इजारेदारियाँ दूसरे देशों में कठिनाइयाँ—विशेष रूप से राजनीतिक और वैचारिक

1. देखिए रिचर्ड जे. वॉर्बर; दि अमेरिकन कारपोरेशन, इट्स पावर, इट्स मनी, इट्स पॉलिटिक्स, न्यूयॉर्क 1970 पृ० 264

कठिनाइयाँ—पैदा करती है। कृति की नीचे लिखी पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। 'लेकिन क्योंकि निगम आधिकारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, विश्व व्यवस्थापकों की विचारधारा कुछ महत्वपूर्ण संस्थापित धारणाओं के साथ संघर्ष में आती है।'¹ निस्संदेह यह राष्ट्रीय संप्रभुसत्ता; राज्यों की आर्थिक स्वाधीनता, पूँजीवादी जनतंत्र में मेहनतकश जनता के बुनियादी अधिकार आदि की ओर ही सकेत है।

निजी पूँजीवादी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों की रचना के साथ-साथ पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया भी विकसित हो रही है। इस संघर्ष में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) एक संकेत है जिसे कि इजारेदारियों और बैंकों का पश्चिमी यूरोप कहा जा सकता है।

अनिवार्यतया पूँजीवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों के क्रियाकलाप सम्बद्ध प्रक्रियाएँ हैं। ये एक सुनिश्चित प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जिसे पूँजीवाद द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की इच्छा—जो विश्वमुक्ति आंदोलन के ऐतिहासिक रूप से पूर्व निर्धारित आक्रमण को दृष्टि में रखते हुए की गयी है—कहा जा सकता है। तथापि ई०ई०सी० के उदाहरण को आधार बनाकर देखें तो एकीकरण का राज्य इजारेदारी रूप निजी पूँजी से बहुत पिछड़ गया है। ऐसा किस कारण हुआ? निस्संदेह रूप से इसके अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण है जनसंख्या (आबादी) की बहुसंख्या का प्रतिरोध।

जबकि निजी उद्योग के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों के संगठन को छिपाना संभव है जो नियम के तौर पर, अपने कार्य पदों के पीछे करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघों का निर्माण गुप्त नहीं रखा जा सकता। 'संयुक्त पश्चिमी यूरोप' के प्रवक्ताओं के जनता को कायल करने के प्रयासों के बावजूद बहुत से श्रमिक-जन स्वभावतः इसे इजारेदारियों का एक सहयोग ही मानते हैं। इसका लक्ष्य है उन्हें मुनाफे सुनिश्चित करना, पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा करना, क्रान्तिकारी आंदोलन और विश्व समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष करना तथा हथियारों की दौड़ को सुरक्षात्मक उपायों के पदों में और तेज करना—(स्वभावतः लाल पतले के खिलाफ)।

दूसरा कारण है कि अंतर्राष्ट्रियवादी अंतर्विरोध निर्विवाद रूप से गहरे होते जा रहे हैं। समकालीन साम्राज्यवाद के भीतर दो उभार साथ-साथ विकसित हो रहे हैं : इजारेदारियाँ और प्रतिस्पर्धा; तथा दो मनोवृत्तियाँ—अभिकेन्द्रीय और उपकेन्द्रीय (केन्द्राभिमुखी एवं केन्द्रापसारी) : अपने वर्ग शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए सभी शक्तियों को संयुक्त करने की अभिलाषा और इसके अपने अंतर्विरोधों

1. रिचर्ड जे० बर्नेट, रोनाल्ड ई० मूसर 'ग्लोबल रीव' द पावर ऑफ़ द मल्टिनेशनल कारपोरेशन्स, न्यूयार्क, 1974, पृ० 47

का गहरा होना। प्रथम महायुद्ध के बाद के वर्षों में, शीत युद्ध के समय में और सापेक्ष तथा अनुकूल आर्थिक स्थिति में केन्द्राभिमुखी शक्तियाँ पूँजीवादी विश्व में प्रमुख थी। तथापि, बाद में विशेष रूप में 1974-75 के सकटकाल के संबंध में स्थिति इसके विपरीत है। केन्द्रापसारी आवेग और साम्राज्यवादी अन्तर्विरोध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। लेनिन यह लिखते समय सर्वथा सही थे “कि विकास की प्रवृत्ति एक विश्व न्यास (ट्रस्ट) की दिशा में है जो बिना किसी अपवाद के सभी उद्योगों को और बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों को अपने भीतर समेट लेगा।” आगे चलकर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसे जीवन ने पूर्णतया पुष्ट कर दिया है: “यह विकास ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, ऐसी रफ़्तार से, ऐसे अंतर्विरोधों, विवादों और विप्लवों के माध्यम से—केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, राष्ट्रीय आदि—जिनसे कि साम्राज्यवाद और पूँजीवाद अनिवार्यतया फट जाएँगे। और अपने विरोधी रूप में बदल जाएँगे, इससे बहुत पहले जबकि एक विश्व न्यास आकार ग्रहण कर पाये अतिसाम्राज्यवाद’, कि इससे पूर्व राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी वा विश्वव्यापी समायोजित हो पाये।”¹ हमारा समय और युग विश्वसनीय रूप से प्रमाणित करता है कि पूँजी का इजारेदारीकरण तेज़ रफ़्तार से होने के साथ-साथ पूँजीवाद के विद्यमान अंतरविरोधों को बड़ी तीव्रता से बढ़ाता है और नये विरोध को उभारता भी है।”

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक शक्तियों के सहयोग के संदर्भ में निम्न-लिखित की ओर ध्यान दिलाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पैमानों पर उत्पादन और पूँजी का सघन साद्रीकरण वस्तु-गत रूप से पूँजीवादी विश्व के शासक वर्ग को क्षीण करता है और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के मोर्चे को व्यापक बनाता है। उनके बीच विद्यमान विरोध अधिक तीव्र और गहरे हो जाते हैं। पूँजीवादी समाज के विभेदीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण की यह प्रक्रिया राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में चलती है। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारी की भूख राष्ट्रीय पूँजीपतियों के हितों की अधिकाधिक विरोधी होती जाती है। इस प्रकार नए विवादों को उभारती है और तीव्र करती है।

इस प्रकार, साम्राज्यवाद की पहली ऐतिहासिक विशेषता—जिसकी ओर लेनिन ने इशारा किया था वह थी: पूँजी के इजारेदारीकरण की ओर इसकी प्रवृत्ति जो आज की वास्तविकता के प्रकाश में सतह पर दिखाई देने लगती है। कम्युनिज्म विरोध के सिद्धांतकार ‘औद्योगिक’ और ‘औद्योगिकोत्तर’ समाज के प्रवक्ता, ‘पूर्ण विकास’ अथवा ‘जीवन की गुणवत्ता’ के प्रवक्ता इस तथ्य के प्रत्युत्तर में क्या

1. वी० आई० लेनिन, एन० बुखारिन की पुस्तिका, ‘साम्राज्यवाद और विश्व अर्थव्यवस्था’ की भूमिका, संकलित रचनाएँ, भाग 22, पृ० 107

कठिनाइयाँ—पैदा करती है। कृति की नीचे लिखी पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। “लेकिन क्योंकि निगम आधिकारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, विश्व व्यवस्थापकों की विचारधारा कुछ महत्वपूर्ण संस्थापित धारणाओं के साथ संघर्ष में आती है।”¹ निस्संदेह यह राष्ट्रीय संप्रभुसत्ता, राज्यों की आर्थिक स्वाधीनता, पूँजीवादी जनतंत्र में मेहनतकश जनता के बुनियादी अधिकार आदि की ओर ही संकेत है।

निजी पूँजीवादी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों की रचना के साथ-साथ पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया भी विकसित हो रही है। इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) एक संकेत है जिसे कि इजारेदारियों और बैंकों का पश्चिमी यूरोप कहा जा सकता है।

अनिवार्यतया पूँजीवादी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों के क्रियाकलाप सम्बद्ध प्रक्रियाएँ हैं। ये एक सुनिश्चित प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं, जिसे पूँजीवाद द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की इच्छा—जो विश्वभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक रूप से पूर्व निर्धारित आक्रमण को दृष्टि में रखते हुए की गयी है—कहा जा सकता है। तथापि ई०ई०सी० के उदाहरण को आधार बनाकर देखें तो एकीकरण का राज्य इजारेदारी रूप निजी पूँजी से बहुत पिछड़ गया है। ऐसा किस कारण हुआ? निस्संदेह रूप से इसके अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण है जनसंख्या (आबादी) की बहुसंख्या का प्रतिरोध।

जबकि निजी उद्योग के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों के संगठन को छिपाना संभव है जो नियम के तौर पर, अपने काम पदों के पीछे करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघों का निर्माण गुप्त नहीं रखा जा सकता। ‘संयुक्त पश्चिमी यूरोप’ के प्रवक्ताओं के जनता को कायल करने के प्रयामों के बावजूद बहुत से श्रमिक-जन स्वभावतः इसे इजारेदारियों का एक सहयोग ही मानते हैं। इसका लक्ष्य है ऊँचे मुनाफे सुनिश्चित करना, पूँजीवादी व्यवस्था की रक्षा करना, क्रान्तिकारी आंदोलन और विश्व समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष करना तथा हथियारों की दौड़ को सुरक्षात्मक उपायों के पदों में और तेज करना—(स्वभावतः साल खतरे के खिलाफ)।

दूसरा कारण है कि अंतर्राष्ट्रियवादी अंतर्विरोध निर्विवाद रूप से गहरे होते जा रहे हैं। समकालीन साम्राज्यवाद के भीतर दो उभार साथ-साथ विकसित हो रहे हैं : इजारेदारियाँ और प्रतिस्पर्धा; तथा दो मनोवृत्तियाँ—अभिकेन्द्रीय और उपकेन्द्रीय (केन्द्राभिमुखी एवं केन्द्रापसारी) : अपने वर्ग शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए सभी शक्तियों को संयुक्त करने की अभिलाषा और इसके अपने अंतर्विरोधों

1. रिचर्ड जे० बर्नेट, रोनाल्ड ई० मूलर ‘ग्लोबल रीज’ द पावर ऑफ द मल्टिनेशनल कारपोरेशन्स, ग्युआर्क, 1974, पृ० 47

सुनिश्चित करने में दिन-ब-दिन असमर्थ होती जा रही है। फलतः पूँजीवादी विश्व के समस्त अंतर्विरोध ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पर पहुँच गए हैं जहाँ उसका समाधान समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण से हो ही सकता है।

पूँजीवाद की राज्य-इजारेदारी की स्थिति में इसका ऐतिहासिक रूप से पूर्व-निर्धारित अद्यःपतन विशेष रूप से प्रकट होता है, उदाहरण के लिए सैन्यीकरण की ओर प्रवृत्ति में, जिसकी नियेधात्मक भूमिका की नीचे परीक्षा की जा रही है। इसका अद्यःपतन उत्पादन शक्तियों के विकास दर की गिरावट में, सभी मनुष्यों के लाभ के लिए आधुनिकतम उपकरणों, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय श्रम का उपयोग करने में समकालीन पूँजीवाद की अक्षमता में प्रत्यक्ष दिखाई देता है और यह पूँजीवादी समाज के राजनीतिक और नैतिक अद्यःपतन से भी प्रदर्शित होता है।

ये परिघटनाएँ न तो अस्थायी हैं और न आंशिक, उनकी जड़ें पूँजीवाद प्रकृति में ही हैं ये और निरपवाद रूप से सभी पूँजीवादी देशों में स्थानीय रूप से चुकी हैं, उसके (पूँजीवाद के) सभी सामाजिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक संगठनों के विकास को तथा समस्त मानव समाज के महत्वपूर्ण हितों के बीच मौलिक विरोधों को सतह पर लाते हुए इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ लंबे समय में स्वयं साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोड़ ले लेती हैं।

वस्तुतः क्या यह मजदूर वर्ग के लिए संभव है कि वे अनिश्चित समय तक ऐसी स्थिति से मेल बैठायें जिसके अंतर्गत अत्यधिक फूल रहे सैनिक-औद्योगिक समूह निरंतर बढ़ती हुई खतरनाक मात्रा में मजदूर वर्ग का जीवन रक्त परजीवी जाकों की तरह चूसते रहते हैं? साथ ही, यह वैज्ञानिक और प्राविधिक उपलब्धियों को समूची मानवता के लिए एक खतरे के रूप में बदल देता है। और यह एक भयानक विसंगति है कि जैसे-जैसे मानव समाज अधिक संपन्न होता जाता है और उसके हाथों में प्रकृति पर अधिक सत्ता केंद्रित होती जाती है, उसका अपना ही अस्तित्व अधिकाधिक असुरक्षित हो जाता है।

सैन्यवाद स्वभाव और सारवस्तु की दृष्टि से दोनों ही रूपों में परजीवी होता है। इसका अभिप्राय है कि न केवल श्रम और भौतिक संसाधनों का ही भयावह अपव्यय होता है अपितु शनैः-शनैः सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को वस्तुतः सारे समाज को ही वह प्रभावित करता है। महान् जर्मन क्रांतिकारी कार्ल लिन्गेस्त ने अपने समय में लिखा था : "सैन्यवाद सबसे पहले स्वयं सेना के रूप में ही प्रस्तुत होता है, तत्पश्चात् सेना से परे एक निर्मित व्यवस्था के रूप में, जो सैन्यवादियों और अर्ध-सैन्यवादी संस्थानों के जाल के जरिए पूरे समाज में प्रवेश पा लेता है"।¹ तब से

1. कार्ल लिन्गेस्त, मिलिटैरिज्म एण्ड एंटी-मिलिटैरिज्म, विद स्पेशल रिगार्ड टू द ग्रे सोशलिस्ट मूवमेंट, ग्लासगो, 1917, पृ० 39

कह सकते हैं? उनकी खोजतान कर की गई स्थापनाएँ और वर्तमान प्रक्रिया को झुठलाने के प्रयास वास्तविकता के संपर्क में आते ही विनष्ट हो जाते हैं; यह बार-बार इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हमारे समय में विद्यमान नई परिघटनाओं को, जो कि बड़े पैमाने पर हो रही हैं, केवल मानसवाद-लेनिनवाद की स्थितियों से साम्राज्यवाद के सच्चे वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर सही ढंग से समझा जा सकता है और इसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

परजीविता, पूंजीवाद का विशिष्ट लक्षण

लेनिन ने साम्राज्यवाद को परजीवी और पतनशील पूंजीवाद के रूप में भी चित्रित किया था। इस निष्कर्ष को खंडित करने के लिए किए गए प्रयास में कम्युनिज्म विरोध के सिद्धांतकार प्रायः यह सर्क देते हैं कि 'लाल' झंडे वालों की भविष्यवाणियों के बावजूद वर्तमान पूंजीवादी उत्पादन निरंतर विकसित हो रहा है, इतना ही नहीं, पहले की अपेक्षा तेजी से भी। क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी है इसलिए लेनिन का साम्राज्यवाद का विश्लेषण समर्थन योग्य नहीं है। कोई भी सोच सकता है कि लेनिनवाद के बूजवा आलोचक अपने निष्कर्षों में अधिक सही हो सकते थे यदि उन्होंने थोड़ा भी ध्यान दिया होता कि वास्तव में लेनिन ने इस संबंध में क्या लिखा है। उन्होंने पूंजीवाद के आधुनिकीकरण की अथवा नई परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने की उसकी क्षमता से अथवा निरंतर विकास से कभी इंकार नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने अपनी कृति 'साम्राज्यवाद-पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था' में लिखा था "यह विश्वास करना भूल होगी कि पतन की ओर यह प्रवृत्ति पूंजीवाद की वृद्धि को रोक देगी। यह ऐसा नहीं करती। साम्राज्यवाद के युग में, उद्योग की कुछ शाखाएँ, पूंजीपति वर्ग के कुछ समूह और कुछ देश, थोड़ी या बहुत मात्रा में, इन प्रवृत्तियों को जब-तब प्रतिबिंबित करते हैं। कुल मिलाकर, पूंजीवाद पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह वृद्धि न केवल सामान्यतया अधिकाधिक असमान हो रही है यह असमानता दिखाई भी देती है, विशेष रूप से उन देशों के पतन में जो कि पूंजी में सर्वाधिक धनी हैं।" (जोर हमारा वी० के०)¹

लेनिन के विचार के अनुसार पूंजीवाद के अघ.पतन और परजीविता का कारण इसका उच्चतम सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में संक्रमण के लिए आर्थिक रूप से पूर्णतया परिपक्व होना था। पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं इस बात को सिद्ध कर रही है कि वह भौतिक संसाधनों और उत्पादक शक्तियों के पूर्ण उपयोग तथा समग्र समाज के हितों के लिए उनका उनके बुद्धिमत्तापूर्ण विकास को

1. वी० आई० लेनिन : इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ़ कैपिटलिज्म सकलित ग्रन्थावली, भाग 22, पृ० 300

मुनिश्चित करने में दिन-ब-दिन असमर्थ होती जा रही है। फलतः पूँजीवादी विश्व के समस्त अंतर्विरोध ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पर पहुँच गए हैं जहाँ उसका समाधान समाज के क्रांतिकारी रूपांतरण से हो ही सकता है।

पूँजीवाद की राज्य-इजारेदारी की स्थिति में इसका ऐतिहासिक रूप से पूर्व-निर्धारित अद्यःपतन विशेष रूप से प्रकट होता है, उदाहरण के लिए सैन्यीकरण की ओर प्रवृत्ति में, जिसकी निपेधात्मक भूमिका की नीचे परीक्षा की जा रही है। इसका अद्यःपतन उत्पादन शक्तियों के विकास दर की गिरावट में, सभी मनुष्यों के लाभ के लिए आधुनिकतम उपकरणों, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय श्रम का उपयोग करने में समकालीन पूँजीवाद की अक्षमता में प्रत्यक्ष दिखाई देता है और यह पूँजीवादी समाज के राजनीतिक और नैतिक अद्यःपतन से भी प्रदर्शित होता है।

ये परिघटनाएँ न तो बर्खास्त हैं और न आंशिक, उनकी जड़ें पूँजीवाद प्रकृति में ही हैं और निरपवाद रूप से सभी पूँजीवादी देशों में स्थानीय रूप से चुकी हैं, उसके (पूँजीवाद के) सभी सामाजिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक संगठनों के विकास को तथा समस्त मानव समाज के महत्वपूर्ण हितों के बीच मौलिक विरोधों को सतह पर लाते हुए इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ लंबे समय में स्वयं साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोड़ ले लेती हैं।

वस्तुतः क्या यह मजदूर वर्ग के लिए संभव है कि वे अनिश्चित समय तक ऐसी स्थिति से मेल बैठायें जिसके अतर्गत अत्यधिक फूल रहे सैनिक-औद्योगिक समूह निरंतर बढ़ती हुई खतरनाक मात्रा में मजदूर वर्ग का जीवन रक्त परजीवी जाकों की तरह चूसते रहते हैं? साथ ही, यह वैज्ञानिक और प्राविधिक उपलब्धियों को समूची मानवता के लिए एक खतरे के रूप में बदल देता है। और यह एक भयानक विसंगति है कि जैसे-जैसे मानव समाज अधिक संपन्न होता जाता है और उसके हाथों में प्रकृति पर अधिक सत्ता केन्द्रित होती जाती है, उसका अपना ही अस्तित्व अधिकाधिक असुरक्षित हो जाता है।

सैन्यवाद स्वभाव और सारवस्तु की दृष्टि से दोनों ही रूपों में परजीवी होता है। इसका अभिप्राय है कि न केवल श्रम और भौतिक संसाधनों का ही भयावह अपव्यय होना है अपितु शनैः-शनैः सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को वस्तुतः सारे समाज को ही वह प्रभावित करता है। महान् जर्मन क्रांतिकारी कार्ल लिब्नेख्त ने अपने समय में लिखा था : "सैन्यवाद सबसे पहले स्वयं सेना के रूप में ही प्रस्तुत होता है, तत्पश्चात् सेना से परे एक निमित्त व्यवस्था के रूप में, जो सैन्यवादियों और अर्ध-सैन्यवादी संस्थानों के जाल के जरिए पूरे समाज में प्रवेश पा लेता है..."¹ तब से

1. कार्ल लिब्नेख्त, मिलिटैरिज्म एण्ड एटीएमिलिटैरिज्म, विद स्पेशल रिगार्ड टू द ग्रे सोशलिस्ट मूवमेंट, ग्लासगो, 1917, पृ० 39

(अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य समेत) किसी एक भी पूँजीवादी देश ने वास्तव में सैन्य-वाद को अस्वीकृत नहीं किया है। इसके विपरीत, पूँजीवादी विश्व के शासक युद्ध के लिए भौतिक संसाधनों को बढ़ाने का हर प्रयास कर रहे हैं और समूचे सामाजिक जीवन को सैन्यवादी भावना से भर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप को, जनसंचार माध्यमों को, और विदेश नीति को सैनिक-औद्योगिक समूह की इच्छा के अधीन कर दिया जाय। सैन्यवाद वर्तमान पूँजीवाद के एकदम नग्न और भयानक रूप से अधःपतन और परजीविता का ही प्रकट रूप है।

परजीविता के अन्य रूप भी, जो उत्पादक शक्तियों की वृद्धि की गति को मद्धिम करने के साथ प्रत्यक्ष रूप में संबद्ध हैं, विकसित हो रहे हैं। निस्संदेह, विश्व साम्राज्यवाद ने अब तक प्राविधिक प्रगति को प्रोत्साहित करने, थम उत्पादकता को ठठाने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं बनाये रखी है। तथापि, यह भी सत्य है कि और आगे वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई अस्थिरता व वैसी ही सामाजिक अस्थिरता के मूल्य पर ही की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि विनियोजन प्रथमतया समाज के लिए आवश्यक क्षेत्रों में नहीं अपितु उन क्षेत्रों में होता है जहाँ अधिकतम मुनाफ़ा उपलब्ध करने की संभावना होती है। इसके कारण होने वाले परिणाम हर जगह दिखाई दे रहे हैं पूँजीवाद के और अधिक अधःपतन एवं परजीविता के रूप में।

वूजर्वा सिद्धांतकार शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि पूँजीवादी उत्पादन में आयोजन और संगठन ने वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति तथा राज्य कानूनों के द्वारा अव्यवस्था पर विजय प्राप्त कर ली है। वे दावा करते हैं, कि पूँजीवादी उत्पादन बुद्धिमत्तापूर्ण हो गया है और इससे भी बढ़कर विज्ञान और प्राविधिकी नवीनतम उपलब्धियों का उससे भी अच्छा उपयोग कर सकता है जैसा कि समाजवाद में किया जा रहा है। लेकिन वे इस तथ्य को प्रस्तुत नहीं करते कि यद्यपि पूँजीवाद अपने निजी उद्देश्यों से विज्ञान एवं प्रविधि का उपयोग करता है, साथ-ही-साथ उनकी प्रगति को मन्द करता है और इसकी उपलब्धियों का उपयोग समाज को क्षति पहुँचाने के लिए करता है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति सार रूप में पूँजीवाद के नियमों की विरोधी है। पूँजीवाद को पूँजी से अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने की अधिक चिंता रहती है, जिसे यह निरपवाद रूप से चुनता है वजाय उत्पादन की उपयुक्तता के। तथापि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक आविष्कारों का उपयोग अनिवार्य रूप से उत्पादन के खर्चों को बढ़ाता है जो एक स्तर पर पहुँचकर उनके मुनाफ़े में गिरावट का कारण बन जाता है। यह वह समय होता है जब इजारेदारयाँ वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति को बनाए रखने के लिए चिंतित रहती है और निरंतर उनका उपयोग करने के लिए क्षेत्रों की खोज करती रहती हैं : उदाहरणार्थ,

शस्त्रास्त्रोत्पादन जिसमें मुनाफ़ों के निरंतर बढ़ते रहने का विश्वास रहता है। दूसरे शब्दों में, यह उच्च रूप से औद्योगिकृत देशों को अपनी प्राविधिक क्षमता विकसित करने में समर्थ बनाती है जिससे कि वह एकछास कालावधि के दौरान वस्तुओं का और अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके। वेशक इसी प्रकार शस्त्रास्त्रों का। भी, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति धनी को और धनी बना देती है। दूसरी ओर, यह किसी भी प्रकार पूंजीवाद के परजीविता के स्वभाव को नहीं बदलती और न यह उसे बदलने की स्थिति में ही होती है। इससे भी आगे, यह मजदूर वर्ग के साथ पूंजीवाद के संघर्ष को बढ़ाती है।

क्या कोई गंभीरतापूर्वक उस समय 'जीवन की गुणवत्ता' सुधारने की बात कर सकता है जबकि बेरोजगारी, मुद्रा प्रसार और महँगाई पूंजीवादी देशों में बढ़ती जा रही है। वेशक, ये परिघटनाएँ पूंजीवाद के लिए नई नहीं हैं, बल्कि हाल के वर्षों में उनके रूप विशेष रूप से सर्वव्यापी बन गये हैं। आम बेरोजगारी अब एक जीर्ण व्याधि, पूंजीवादी वास्तविकता का एक स्थायी पहलू बन गयी है। और व्यापारिक क्रियाकलाप की वृद्धि भी इसे नीचे उतारने का नाम नहीं लेती। लाखों लोग केवल अस्थायी तौर पर ही नौकरी से नहीं निकाले जाते जैसा कि अतीत में हुआ करता था, बल्कि उनसे काम छुड़ा दिया जाता है : वे स्थाई रूप से अपने को उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित पाते हैं। काम की आज की गति के कारण वह व्यक्ति जो काम नहीं पा सकता या जो उसे छो चुका है, अपनी व्यावसायिक कुशलता खो बैठता है और फलस्वरूप उद्यमी के लिए वह अपना मूल्य भी खो देता है।

कुछ समय पूर्व, सितम्बर 1976 में 'यू० एस० न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट' ने निम्न टिप्पणी की थी : "अधिकाधिक नवयुवक अत्यधिक प्रतियोगिता पर आधारित व्यवसाय बाज़ार के दुष्प्रकार को तोड़ने में असफल होकर गलियों में घूम रहे हैं।¹ इसी ने एक काले परिवार की ज़िंदगी पर एक विशेषज्ञ को उद्धृत किया है जिसका कहना है : "हम अपने काले समुदाय (जाति) में 30 या उससे अधिक आयु के मुवा लोग हैं जिनको कभी काम नहीं मिला, इसलिए हम एक स्थायी बेरोजगार उपसमाज विकसित कर रहे हैं, जिसके परिणाम अकल्पनीय रूप से भयानक होंगे।² और इस पर संपादक की टिप्पणी थी : "भोटे तौर पर अल्पशिक्षित और कार्यकौशल की कमी वाले काले हजारों और लाखों नवयुवक गरीबी, शराब, अपराध और हिंसा के निरर्हेश्वर जीवन की ओर झुक रहे हैं।"³ यह केवल अमरीका की काली या गोरी आबादी के लिए ही सत्य नहीं है बल्कि साम्राज्यवाद के गढ़ के लिए यह नैवांभौम,

1. यू. एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, स० 13, सितंबर 27, 1976, पृ० 62.

2. वही, पृ० 14

3. वही, पृ० 11

मान्यता प्राप्त सत्य है।

इस संबंध में ऊँचे दर्जे की कुशलता अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से भी किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। वेरोजगारों में बहुत से लोग, विशेष रूप से युवक और युवतियाँ, उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। कोई समय था जब विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र न्यूनाधिक मात्रा में जीवन के एक स्तर के लिए गारंटी ममज्ञा जाता था। आज, जैसा कि पश्चिम में कहा जाता है यहमात्र एक महंगा लाटरी टिकट बन गया है। उत्पादन में बढ़ता हुआ यंत्रीकरण और स्वचालन मेहनतकश जनता के बड़े भाग के लिए नष्ट होने का खतरा बन गया है। यदि आगे बढ़े हुए समृद्धतम पूँजीवादी देशों में इस प्रकार की स्थिति है, तब विश्व के उन विशाल क्षेत्रों के लिए क्या कहा जा सकता है जहाँ पूँजीवाद ने स्थानीय आबादी को उत्पादक शक्तियों के विकास की दृष्टि से विषम स्थिति में डाल रखा है? आज भी, जैसा कि एक सौ वर्ष पूर्व होता था, सामान्य रूप से लोग ज़मीन पर, खेती के लिए, हल का उपयोग करते हैं। वस्तुतः साम्राज्यवाद ने इन देशों में वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति को पहुँचने से रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी है। उन सबको बाहर निकाल कर साम्राज्यवाद सभी द्वीपों के जनगण को गरीबी और अज्ञान में रखकर दंड देना चाहता है और इस प्रकार उनको ऐतिहासिक प्रगति में भाग लेने से रोक देता है। इजारेदारियों के लिए इन लोगों का कोई उपयोग नहीं है, उनको वे अतिरिक्त मुँह समझते हैं और उनको न तो वे काम देना चाहते हैं न भोजन ही दे सकते हैं। संभवतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवादी सिद्धान्तकार मानवसमाज को, विशेष रूप से विकासमान देशों को, 'आबादी के विस्फोट' का नारा देकर अतंकित करना चाहते हैं।

दूसरी एक और महाविपत्ति हाल के वर्षों में पूँजीवादी देशों के श्रमिकों में प्लेग की तरह फैलाई जा रही है, वह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की प्रक्रियाएँ स्थायी रूप से पूँजीवादी विश्व को झंझोड़ती रहती हैं आर्थिक मन्दी के समय में भी, जब कि खाद्य तथा निर्मित वस्तुओं की कीमतें आमतौर से नीची रहती हैं। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का सामान्य अस्थायित्व बजट के घाटे को पूरा करने में पूँजी के अत्यधिक उपयोग ने—वह भी इजारेदारियों के हित में—हथियारों पर अत्यधिक व्यय ने तथा इसी प्रकार साम्राज्यवाद की परजीविता की अन्य अभिव्यक्तियों ने पूँजीवादी समाज में मुद्रास्फीति को स्थायी संस्था बना दिया। शासक वर्गों ने इसे बेतनो में कटौती के प्रच्छन्न साधन में बदल दिया है, अर्थात् मजदूर जनता के शोषण के एक अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया है। मजदूर वर्ग की पूँजीवादी लूट की सारी मशीनरी इस तरीके से काम करती है कि पहले कष्ट भोगने वाले होते हैं बेतनों, पेंशनों, छात्रवृत्तियों आदि के रूप में निश्चित आय वाले लोग। लाखों छोटे उद्यमी, स्वयंनियोजित कारीगर, व्यापारी और

किसान उसी सीमा तक प्रभावित होते हैं जिस सीमा तक उनके उत्पादों की कीमत अनिवार्यतया उस दर से अधिक मन्द गति से बढ़ती है जितनी कि इजारेदारियों द्वारा निर्दिष्ट है। स्पष्ट रूप से छोटे पूंजी-निवेश वालों को भी क्षति पहुँचती है, क्योंकि वे स्वयं को अवमूल्यित संपत्ति के स्वामी के रूप में पाते हैं। दूसरी ओर वित्तीय धन्नासेठ जिन्होंने पहले लगाई कम पूंजी को मुद्रा के रूप में वापस लौटा दिया है जो अपना वास्तविक मूल्य खो चुकी है। शब्दशः कहा जाए तो मुद्रास्फीति वेतनों में वृद्धि को चट कर जाती है जिसे कि मजदूरों ने स्वयं अर्जित किया है।

इन इजारेदारियों के क्रियाकलाप किस प्रकार विकासमान देश को प्रभावित करते हैं? पूंजीवादी सिद्धान्तकार ऊर्जा संकट को पार करने की आवश्यकताओं व कच्चे माल की कमी के संबंध में बात करते हैं तथा आमतौर से इस समस्या को पर्यावरण की सुरक्षा की समस्या से जोड़ते हैं। लेकिन इजारेदारियाँ इसके समाधान के लिए कैसे प्रयत्न करती हैं? निस्संदेह यह सिद्ध करने के लिए अनेक तथ्य दिये जा सकते हैं कि वे विकासशील देशों के शोषण के कुछ सुधरे (नवीन) रूपों की सहायता से ऐसा करना चाहते हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमत की उन्हे चिन्ता है लेकिन पर्यावरण के विनाश की बिल्कुल नहीं, इजारेदारियाँ विशेष रूप से बहु-राष्ट्रीय कर्पनियाँ अपनी औपनिवेशिक स्थितियों की क्षति की पूर्ति का प्रयास करते हैं, बड़े साफ-सुधरे तरीकों की मदद से : पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकासमान देशों को लाकर। वे उच्च रूप से विशेषीकृत (विशिष्टता प्राप्त) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रम और तीव्र ऊर्जायुक्त प्रक्रिया वाली और उच्च पर्यावरणिक प्रदूषणयुक्त—इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर देती है। नवउपनिवेशवादी तीन उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं : सस्ते श्रम का शोषण, उनके कच्चे माल के स्रोतों को हाथ में ले लेते हैं और विकासशील देशों की पूंजीवादी शक्तियों पर आधिक निर्भरता सुदृढ़ कर देते हैं। और इस सबके ऊपर इन देशों पर कुछ उपकारों का भार लाद देते हैं और उनको सामाजिक सुधारों के जरिये करने से रोक देते हैं। तथापि, साम्राज्यवादी परजीविता की नयी व्यवस्था के निर्माण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उनके प्रयास में इजारेदारियाँ विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विपमता को और अधिक गहरा कर देती हैं और इसके आन्तरिक और बाह्य अन्तर्विरोधों को बढ़ा देती हैं।

इजारेदार पांतों में व्याप्त प्रतिक्रियावाद : इसे कैसे समझा जाए

इजारेदारियों की अपनी स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की इच्छा अनिवार्य रूप से गृह एवं विदेशनीति के समस्त क्षेत्रों में जनतंत्रविरोधी प्रवृत्तियों को मजबूत करने की माँग करती है। पहले अपने समय में लेनिन ने साम्राज्यवाद की व्याख्या करते हुए इसे पांतों के मध्य प्रतिक्रियावाद को गुप्त करने के रूप में परिभाषित

किया था। आगे होने वाले पूँजीवादी समाज के विकास ने इस निष्कर्ष के समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर दिये। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणासदा ही, स्पष्ट रूप से, राजनीतिक जीवन में प्रतिक्रियावाद सुदृढ़ धनाती है। यह समझ में आने योग्य तथ्य है।

इजारेदार पूँजीवाद का राज्य इजारेदारी में विकास पहले से शतविशत वर्तमान बूर्जा जनतंत्र के मुख्य आधारों को नष्ट कर देता है। यह लोगों के सामाजिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार के व्यवहार के नियमन की एक निश्चित पद्धति के साथ और निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत बाँध देने की एक अत्यधिक कठोर प्रक्रिया है (जो सदा सतह पर दिखायी नहीं देती है)। कभी-कभी वहाँ जनता को दबाने के लिए फ़ासिस्ट तरीके लागू करने की प्रवृत्ति भी दिखायी देती है। पूँजीवादी सविधानो में घोषित मेहनतकश जनता के अधिकार भी अधिकाधिक कुचले जाते हैं। साम्राज्यवाद ने ही फ़ासिज्म के राजनीतिक आतंक एवं मृत्यु शिविरों की व्यवस्था को पैदा किया है। 1969 की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का मुख्य दस्तावेज कहता है: "जहाँ कहीं भी इसके लिए संभव होता है वही साम्राज्यवाद जनतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विरुद्ध आक्रमण शुरू कर देता है। मानव समाज को यह पैरों तले कुचल देता है और नस्लवाद को उत्पन्न करता है।"

इन दिनों फ़ासिज्म के प्रत्याक्रमण करने के प्रयत्न आवश्यक रूप से शोर भरे प्रदर्शनों के साथ नहीं होते जैसा कि अतीत में आम तौर से होता था। उदाहरणार्थ, फ़रवरी 1933 में रीस्टाग में आग लगाने का शैतानी भरा उत्तेजक फ़ारनामा था जिसके जरिये हिटलर के जल्सादों ने अपने सत्ता में आने की सूचना दी थी। इसके विपरीत, आजकल 'परंपरागत' फ़ासिज्म के अवशेष, नव-फ़ासीवादी आमतौर से राजनीतिक मंच के पीछे काम करने को वरीयता देते हैं। तब तक जब तक कि साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग फ़ासिस्ट आंदोलन को राजनीतिक आरक्षित सेना की भाँति देखता है, इसके 'कार्यकर्ता' इस प्रकार रहते हैं जैसे आधे भूमिगत हों और किसी भी उपयुक्त मौके पर काम के लिए तत्पर हैं। तो भी फ़ासीवादी विचारों के राजनीतिज्ञ जनतंत्र के विरुद्ध संघर्ष की अगली पाँत में हैं, जैसाकि चिली की घटना थी। अथवा प्रतिक्रियावाद उनका उपयोग कुछ समय के लिए एक सहायक सेना के रूप में करता हो जैसाकि कुछ पूँजीवादी देशों में हुआ है। फ़ासीवादी और नवाफ़सीवादी आंदोलन सदा ही साम्राज्यवाद के उपकरण रहे हैं, अधिक प्रतिक्रियावादी और अधिक आक्रामक : और इसमें यह भी जोड़ना चाहिए कि वे पूँजीपति वर्ग के सहयोगी तत्व हैं। पिछला तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपेक्षाकृत नयी परिघटना है जो बाद में

दैनिक अभ्यास के रूप में विकसित होता रहा है। काफ़ी समय अब से यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि विदेशी इजारेदारियाँ प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपनी सरकारों के जरिये किसी भी देश में वहाँ के विभिन्न राजनीतिक पक्षों के आन्तरिक संघर्ष में हस्तक्षेप करती हैं, और, स्वभावतः जनतंत्र विरोधी शक्तियों का पक्ष लेती हैं। चिली में यही हुआ इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रपति के चुनावों से वहाँ एक लोकप्रिय संयुक्त सरकार सत्ता पर आ गयी थी, आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिक्रियावादियों ने सीधे रूप में हमला किया और उसे सैनिक फ़ासिस्ट विद्रोह के रूप में पूरा किया। यही पुर्तगाल में भी हुआ जहाँ देश के भीतर और बाहर प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने कम्युनिस्टों को सरकार से बाहर रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता था सभी किया, जिन्होंने संसदीय चुनावों में समाजवादियों सहित लगभग 50 प्रतिशत मत प्राप्त कर लिये थे। यही इटली में भी हुआ, जबकि अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियाँ सरकार में कम्युनिस्टों के शामिल होने के विरुद्ध चेतावनी लेकर सामने आयी और उस पर भारी दबाव डाला इस अकाट्य तथ्य को अस्वीकार करते हुए कि 1976 के चुनावों में कम्युनिस्टों ने समद के एक-तिहाई स्थानों से अधिक पर अधिकार कर लिया था।

हाल ही के ये और अन्य उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि इजारेदारियाँ मेहनतकश जनता के विरुद्ध खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिशें करती हैं। यह है नया 'पवित्र संयुक्त मोर्चा' जो प्रतिक्रियावाद को पैदा करता है, निस्संदेह जिसका सबसे प्रमुख रूप फ़ासिज्म है। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध संघर्ष केवल संसदीय और संसदेतर क्षेत्रों को ही प्रभावित नहीं करता, वास्तव में यह पूँजीवादी समाज के समस्त आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को ही घेरे में ले लेता है।

राज्य-इजारेदारी पूँजीवाद के विकास के साथ, न केवल राजनीतिक और सार्वजनिक संगठन ही अति प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों के बाहुक बन जाते हैं बल्कि स्वयं राज्य मशीनरी भी, साम्राज्यवादी देशों की अकसरशाही मशीनरी भी, अपनी समग्र आर्थिक, प्रशासनिक और विधायिका शक्तियों के साथ—स्वभावतः, जिसमें गुप्तचर एवं दण्डदात्री संस्थाएँ भी आती हैं सम्मिलित रहती है।

वर्तमान में साम्राज्यवादी शिविर में जो कुछ हो रहा है उसे तर्कसंगत रूप से बड़ी इजारेदार पूँजी की तानाशाही का आगे विस्तार के रूप में ही लक्षित किया जा सकता है। यह एक विविध रूपों वाली प्रक्रिया है जिसमें पूँजीवादी समाज के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक क्षेत्र आ जाते हैं और हर जगह यह साम्राज्यवाद की ऊपरी इजारेदारी सतह और समाज के बीच कभी दूर न होने वाले अंतर्विरोध को तीव्र करती है। ये परिघटनाएँ जो कि पूँजीवादी जनतंत्र के गंभीर संकट को प्रकट करती हैं यह भी साबित करती हैं कि ये इसके विकास का ही स्वाभाविक परिणाम हैं। पूँजीवाद के ऐतिहासिक रूप से

पूर्वनिर्धारित पतन का ।

व्यापक रूप से प्रचारित पूंजीवादी जनतंत्र में पूंजीवादी व्यवस्था जो उत्पन्न करती है वह है स्पष्ट रूप से त्रुटियों से भरा कुरूप प्रतिक्रियावाद । भले ही सामं-वादी व्यवस्था की तुलना में इसने भारी उन्नति का कदम उठाया हो अथवा मेहनतकश जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के चाहे जितने अवसर दिये हों, जनतंत्र अपने पूंजीवादी रूप में कभी यह दावा नहीं कर सकता कि जनता द्वारा (बनाई गयी) सरकार की शब्दावली के सही मूलार्थ से इसकी कोई समानता नहीं है ।

मनुष्य को शोषण के विषय के रूप में देखते हुए (पूंजीवाद, अपने सारतत्व और मानव विरोधी प्रकृति के कारण अन्य किसी आधार से उत्पन्न नहीं हो सकता) सामाजिक संबंधों की पूंजीवादी अवधारणा अपने अंतिम विश्लेषण में हिंसा का रूप ले लेती है । लेनिन ने लिखा था "बूज्वा वर्ग किसी भी राज्य को केवल तभी सुदृढ़ मानता है जबकि सरकारी मशीनरी की सहायता से वह जहाँ भी पूंजी-वादी शासक चाहे जनता को फेंकने की सामर्थ्य रखता हो ।" दूसरे शब्दों में वे जनता का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करते हैं ।

इस प्रमुख लक्ष्य को ध्यान में रखकर शासक वर्ग अपने सम्पूर्ण जटिल राज्य-तंत्र और प्रशासकीय सत्ता का—सरकारी संस्थानों, दण्डदायक संगठनों और सेना का—निर्माण करता है और यह भी निर्धारित करता है कि विचारघोरात्मक जन-प्रभाव के मुख्य उत्तोलकों जैसे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, प्रचार की मशीनरी, जनसंचार माध्यम, तथाकथित जनसंस्कृति, आदि में नियुक्तियाँ किस आधार पर की जाएँ । ये सभी एक ही लक्ष्य की उपसब्धि के लिए चलायी जाती हैं वह है—मजदूर जनता को सामाजिक जीवन में स्वतंत्र भूमिका निभाने से और साम्राज्य-वादी नीति के वास्तविक उद्देश्यों को समझने से रोका जाये और उनको शासक अभिजात वर्ग का अंधा हथियार बना लिया जाय । यदि जुझारू सघर्षों के दौरान मजदूर वर्ग पूंजीवादी देशों में कुछ राजनीतिक स्वतंत्रताएँ अर्जित करने की व्यवस्था कर लेता है, तो यह सत्ता के अनुग्रह के कारण नहीं होता, जैसा कि उनका प्रचार दावा करता है, बल्कि उनकी मजबूरी से उत्पन्न सुविधा है । ऐसी प्रत्येक रियायत संबंधित देश में वर्ग शक्तियों के वास्तविक पारस्परिक संबंधों को प्रति-बिम्बित करती है, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी । इसी के साथ-साथ बूज्वा वर्ग इन्हें शून्य में बदलने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयास करता है । इसी संघर्ष के दौरान जनतंत्र के पूंजीवादी पथ का विकास होता है ।

महान अकतूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय ने अन्य सिद्धान्तों की रचना की,

1. यो० आई० लेनिन "द्वितीय अखिल रूसी सोवियत मजदूरों और सैनिक प्रतिनिधियों की कांग्रेस" संकलित रचनाएँ खंड, 26, पृ० 256

जोकि पूंजीवादी प्रजातंत्र के विरोध में थे। इसने प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक क्षमताएँ विकसित करने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने का कर्तव्य सामने रखा तथा इस प्रकार मेहनतकश जनता को समाज के सक्रिय और समझदार रचयिता के रूप में बदलने का कार्यभार रखा जैसा कोई भी पूर्ववर्ती समाज नहीं कर सका था। लेनिन ने लिखा : “शक्ति का हमारा विचार सर्वथा भिन्न है। हमारा विचार यह है कि राज्य तब ही शुद्ध हो सकता है जब जनता राजनीतिक रूप से समझदार हो और यह तब ही मजबूत हो सकता है जब जनता हर चीज जानती हो, हर चीज के बारे में राय कायम कर सकती हो और समझदारी के साथ हर काम कर सकती हो।”¹

जीवन ने दिखा दिया है कि पूंजीवादी जनतंत्र के अलग अलग लक्षणों की तुलना में सोवियत राज्य अपनी सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अन्य समस्याओं का समाधान बुनियादी रूप से भिन्न तरीके से करता है इस तथ्य ने पूंजीवाद के गंभीर संकट के आरम्भिक दौर को स्पष्ट कर दिया है। यह संकट ‘कम्युनिस्टों का’ आविष्कार नहीं है, जैसा कि सोवियत सच के शत्रु दुनिया को विश्वास दिलाना चाहते हैं, अपितु स्वयं पूंजीवादी समाज में चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक ओर तो, पूंजीवादी उदारवाद की पारंपरिक आर्थिक परंपरा, निजी उद्यमों की स्वतंत्रता (जो अब पहले ही काटी जा चुकी है) का दौर समाप्त हो रहा है और इजारेदारियों ने उसका स्थान ले लिया है। यही नहीं पूंजीवाद ने, जो 1930 के आरंभ में विनाशक मंदी के चंगुल में था, अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप के लिए अपने द्वार खोल दिये जिससे कि वह अपना सिर ऊंचा बनाये रख सके। इस प्रकार करते हुए उसने पूरी तरह पूंजीवाद राज्य इजारेदारी की तानाशाही के लिए भौतिक आधारशिला रख दी। दूसरी ओर तात्कालिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को हल करने में पूंजीवादी जनतांत्रिक संगठनों की अक्षमता के कारण मजदूर जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। इस क्रम में, कुछ पूंजीवादी देशों में यह अत्यधिक अस्थिर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर देता है, प्रतिक्रियावाद जिसका व्यापक रूप से उपभोग करता है—जनता पर आधिपत्य के लिए फासिस्ट तरीके लागू करने के लिए। फलस्वरूप, इजारेदारी पूंजीवाद के दक्षिणपंथी भूषो और आतंकवादी तानाशाही के समर्थकों के प्रभुत्व के लिए सैद्धान्तिक और राजनीतिक आधार आकार ग्रहण कर लेता है।

‘कानून और व्यवस्था’, ‘मजबूत सरकार’ और, ‘धोष्ठतम नस्ल का शासन’ का नारा देकर वे बहुधा निम्न मध्यमवर्गीय जनता को पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा के लिए अपने साथ बहा ले जाते हैं।

1. वी० आई० लेनिन ‘द्वितीय अखिल रूसी सोवियत कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों की कांग्रेस’ संकलित रचना, भाग 26, पृ० 256

साथ-ही पूंजीवादी जनतंत्र का संकट, जो एक समय मानवता और क्रासिद्धि के बीच विश्वव्यापी संघर्ष के लिए भी उत्तरदायी था और शक्तिशाली रूप से किसी भी पूंजीवादी देश में एक अन्य संघर्ष के खतरे को अभी भी बनाये हुए है, स्वयं पूंजीवाद के भीतर शक्तियों के विभेदीकरण की ओर ले जाता है। इस स्थिति में इजारेदार पूंजी की तानाशाही को मजबूत करने की आकांक्षाएँ निरंतर बढ़ते हुए विरोध उभारती हैं। उदार पूंजीवादी जनतांत्रिक संस्थानों के पूंजीवादी समर्थकों की ओर से भी विरोध होने लगता जिन्हें अपना कार्य निरन्तर जारी रखने के लिए मजदूर वर्ग पर भरोसा करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि पूंजीवादी जनतंत्र अपने परम्परागत आधार पर निर्भर नहीं रह सकता। यह उन शक्तियों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता जो इजारेदारियों के आर्थिक और राजनीतिक आधिपत्य के विरुद्ध युद्ध के द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।

यह मूल रूप से एक नया तथ्य है। यह ऐसे कार्यक्रम के आधार पर जो पूंजीवादी जनतंत्र की सीमाओं से का अतिक्रमण करता है, व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा स्थापित करने के लिए अवसर खोलता है। इस प्रकार का संयुक्त मोर्चा 'समस्त जनतांत्रिक धाराओं के एक राजनीतिक संयुक्त मोर्चे में आने से बन सकता है जो निश्चित रूप से समग्र देशों की अर्थव्यवस्थाओं में इजारेदारियों द्वारा निभायी जा रही भूमिका को सीमित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, बड़ी पूंजी की शक्ति को समाप्त कर सकता है तथा इस प्रकार के क्रान्तिकारी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकता है जो समाजवाद के लिए संघर्ष जारी रखने हेतु सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सकते हों।¹

हमारे समय में पूंजीवाद के पतन एवं ध्वंस की प्रक्रिया जैसा कि लेनिन ने अपनी कृति साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में चित्रित किया था, ने सार्वभौम रूप धारण कर लिया है।

साम्राज्यवाद जिन संकटों से गुजर रहा है, यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के 1976 के सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया, "वे पूंजीवादी व्यवस्था के आम संकट के और बढ़ जाने के फलस्वरूप प्रकट होते हैं और विभिन्न देशों में विभिन्न रूप और आयाम ग्रहण करते हैं।" पूंजीवादी समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सम्मेलन में यह भी कहा गया : "वर्तमान गंभीर संकट के इस प्रकार के लक्षण—जैसे स्थायी मुद्रास्फीति, मौद्रिक व्यवस्था का संकट, उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक कम उपयोग होना और मेहनतकश जनता के लाखों व्यक्तियों का बेरोजगार होना

—बड़ी गहराई के साथ अनुभव किये जा रहे हैं।”

पूँजीवाद के अन्तर्गत ये परिघटनाएँ नयी नहीं हैं। तथापि, जो नया है, वह यह है कि ये स्थायी बन गयी हैं और अपने को विशेष रूप से विध्वंसक रूप में प्रदर्शित करने लगी हैं। उत्पादन में वृद्धि, जिसके पश्चात् प्रायः मंदी आती है, अधिक समय तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती; और आर्थिक गिरावट होने पर आवश्यक तौर पर कीमतें नहीं गिरती। थम की उत्पादकता में वृद्धि और उत्पादन की प्रभावशालीता महगाई को कम नहीं कर सकती। मजदूरों की स्थिति अधिकाधिक निराशाजनक होती जाती है लेकिन पूँजीवादी देशों की आर्थिक स्थिति में हो रहे परिवर्तनों के बावजूद—चाहे उत्पादन क्षमताओं का भार बढ़े, बेरोजगारी में गिरावट आये या वह बढ़े, मुद्रास्फीति में घटत या बढ़त हो—एक क्षेत्र ऐसा है जो सदा एक जैसा रहता है जिसमें कभी गिरावट नहीं आती। वह है इजारेदारियों के मुनाफ़ों का क्षेत्र। यह कहना ही काफी होगा कि अमरीकी इजारेदारियों के मुनाफ़े 1970 से 1974 के बीच ही दुगुने हो गये। 1975 में (1929-33 की मंदी के बाद के अनुपम आर्थिक संकट की वृद्धि के समय) बेरोजगारी की तेज़ी से वृद्धि के साथ और मुद्रास्फीति की प्रक्रिया में तथा महगाई में वृद्धि के साथ, अमरीकी व्यापार क्षेत्रों के प्रभावशाली मासिक क्लार्प्यून के अनुसार, सबसे बड़ी 50 कंपनियों के व्यवसाय में 30,000 मिलियन डालर तक बढ़ोतरी हो गयी, और शुद्ध मुनाफ़ा 1971 की तुलना में 12,000 मिलियन डालर तक बढ़ गया था।

यह इस विषय का मूल प्रश्न है। सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था जो निर्बाध रूप से पूँजी के संचय को सुनिश्चित बनाने से और मुनाफ़ों की राशि जमा करने से संबंध रखती है, तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति से सरोकार नहीं रखती, अन्य कोई परिणाम प्रस्तुत कर ही नहीं सकती। व्यक्तियों के हितों पर संभवतः इस व्यवस्था में विचार किया जाता हो लेकिन वह भी गौण महत्व का विषय है, क्योंकि वे भी सदा पूँजी के हित में त्याग दिये जाते हैं और कभी-कभी उनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी जाती है। पश्चिम जर्मनी की वर्टेंश्चाफ़्टसोचे ने लिखा : चूहों के बाद विश्व में मनुष्य ही सर्वाधिक संख्या में है। लोगों के अतिरेक ने प्रत्येक व्यक्ति के अलग महत्व को कम कर दिया है। मानव जीवन, जो किसी भी मानवीय नैतिकता का सार है अत्यधिक उपेक्षित हो गया है और अब इसका मूल्य एक पाउण्ड स्टर्लिंग के फ़ैंक साथ मिलाने से अधिक नहीं है।¹

वर्तमान पूँजीवादी विश्व में पूँजीवादी समाज और व्यक्ति के बीच असाध्य अंतर्विरोध अत्यधिक गहरा और दुःखद बन गया है। इजारेदारियों की शक्ति

1. यूरोप में शांति, सुरक्षा, सहयोग और सामाजिक प्रगति के लिए' मास्को, 1976, पृ० 36

2. वर्टेंश्चाफ़्टसोचे स. 12, मार्च 15, 1974 S, 24

ने भविष्य में व्यक्ति की आस्था को तोड़ दिया है, वह उसकी नागरिक प्रतिष्ठा को कुचल देती है, उसकी मनोवृत्ति को कुरूप और दास बना देती है, दवाओं की आदत, और नशाखोरी, अपराधों की अकल्पनीय वृद्धि, समूहों की मानसिक अराजकता, आदि वे कीमतें हैं जिन्हें वर्तमान पूँजीवादी समाज व्यक्ति के साथ संबंधों की समस्या को सुलझाने में अपनी असमर्थता के लिए अदा करता है।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूँजीवादी विश्व के अधःपतन के उक्त लक्षणों के मुख्य केन्द्र हैं सर्वाधिक उद्योगीकृत और सम्पन्नतम पूँजीवादी देश। अमरीका में, उदाहरण के लिए, आवादी की वृद्धि की अपेक्षा 9 गुना तेजी से सामूहिक अपराध बढ़ रहे हैं। इस साम्राज्यवादी शक्ति में इसी प्रकार अन्य कई की सूचियाँ भी सबसे ऊँची हैं। अमरीका के युद्धोत्तर विकास के परिणामों की चर्चा करते हुए 1976 में राष्ट्रपति के चुनाव अभियान में जिराल्ड फ़ोर्ड जो उन दिनों अमरीका के राष्ट्रपति थे, ने विवाद की उत्तेजना में स्वीकार किया था कि वर्तमान पीढ़ी के अधिकांश जीवनो के माध्यम से अमरीका ने संकट का सामना किया। अमरीका के कई नेताओं को कत्ल कर दिया गया, एक युद्ध हुआ जिसमें अमरीका न तो जीत सका और न उसे समाप्त हो कर सका। अमरीका की सड़कों और विश्वविद्यालय परिसरों में उत्पाती दंगे हुए। “असीमित मुद्रास्फीति भुगतनी पड़ी और सबसे खराब मंदी सहनी पड़ी। उन्होंने कहा : “सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार ने हमारा पर्दाफाश किया।”¹

यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि फ़ोर्ड आत्मालोचना कर रहे थे। वह केवल वास्तविकता से बच निकलने में असमर्थ हो गये थे। अमरीका का यंत्रणापूर्ण अनुभव पूँजीवादी विश्व में कोई अपवाद नहीं है : यह सीधे-सादे ढंग से सामान्य शब्दावली में उस मार्ग के विषय में पूर्वानुमान है जिस पर औद्योगीकृत पूँजीवादी देश वर्तमान में चल रहे हैं। यह स्थिति चाहे जितनी अपमानजनक हो वह इस पर बढ़ने चले जाएँगे यन्त्रुगत अनिवार्यता के साथ तब तक जब तक कि उनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ अमरीकी रथ के साथ जुड़ी हैं और उनके वैचारिक केन्द्र उनको अमरीकी पद्धति की ओर निर्देशित करते रहे।

यदि संयुक्त राज्य अमरीका में, जहाँ यूरोप की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय तीन गुना ऊँची है, विकास और समृद्धि ने गरीबी को हटा दिया होता, सामाजिक अन्याय और मजदूर वर्ग की कुछ श्रेणियों के शोषण, को समाप्त कर दिया होता तब वहाँ उनके उदाहरण का अनुसरण करना लाभदायक होता। स माई हिप्पोजेमेट्रिक के संपादक बर्नार्ड जूनिपन ने अपनी पुस्तक ‘ले सुईमाइड्स टेमोकेटोस्’ में लिखा : “लेकिन उस देश का अनुभव जो यूरोप से आगे बढ़कर प्राविधिक और उपभोग के

युग में प्रवेश कर चुका है, सारे भ्रमों को तोड़ देता है : उत्पादन के विस्तार से गरीबी का अन्त नहीं हुआ, जीवन की गुणवत्ता की अपेक्षा जीवन का स्तर ऊँचा हुआ, कामों की संख्या, जहाँ मजदूरों को समस्त मानवीय हित के सभी अधिकारों से वंचित है, कई गुना बढ़ गयी है... और अन्ततः पार्यावरणिक प्रदूषण ने सभी सीमाएँ तोड़ दी हैं—और आज सारा यूरोप अमरीका के क्रदमों का अनुसरण कर रहा है।”¹

फ्रांसीसी पत्रकार का चेतावनी भरा वक्तव्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इस संकट की रोशनी में जो निरंतर पूँजीवादी विश्व को कंपा रहा है और 1970 के मध्य में विशेष रूप से गंभीर हो गया है।

सत्तर का दशक : पूँजीवाद के नवीकरण का शोकगीत

यदि ‘प्राविधिक नियतिवाद’ की अवधारणा तथा ‘जीवन की गुणवत्ता’ सुधारने की पूँजीवादी शैली के नारे का दिवालियापन प्रमाणित करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है, तो वह 1970 के मध्य अत्यधिक तीव्र संकट के रूप में स्वयं प्रकट हो गया, जिस संकट में समस्त पूँजीवादी विश्व को कंपा दिया। पूँजीवाद के इतिहास में इतनी अधिक संख्या में आये, पूर्ववर्ती आर्थिक संकटों से इतना भिन्न, 1974-75 का यह संकट बहुमुखी परिघटना के रूप में विकसित हुआ। “यह केवल एक आर्थिक संकट होने से कुछ अलग हट कर था, यह राजनीतिक और नैतिक संकट भी था।” 1976 में यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के सम्मेलन में लियोनिद ब्रेजनेव ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि “जनगण अधिकाधिक समझते जा रहे हैं कि पूँजीवादी समाज ऐसा समाज है जिसका भविष्य नहीं है।”²

यह ऐसे समय में प्रकट हो रहा है जब पूरे विश्व में वर्ग शक्तियाँ अपने को पुनर्गठित कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नये परिवर्तन हो रहे हैं, यह संकट पूँजीवादी समाज के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में—अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा में—फैलता जा रहा है। परंपरागत रूपों की विविधता के अतिरिक्त इसके बड़ी संख्या में नये पहलू हैं जो मौलिक महत्व रखते हैं।

1930 के दशक के प्रारंभ में उत्पन्न संकट से कुछ भिन्न, जबकि विश्व पूँजीवाद की राज्य इजारेदारी की व्यवस्था अभी आरंभ हो रही थी, आकार ले रही थी, वर्तमान संकट उस समय आया जब कि इस व्यवस्था का निर्माण पूरा हो चुका था और जब यह इसके नियामक उत्तोलकों जिनमें से कुछ प्रभावहीन हो चुके थे, को

1. क्लॉड जूलियन, ले मुईसाइड द डेमोक्रेसीस, पेरिस 1972, पृ० 174

2. यूरोप में शांति, सुरक्षा, सहयोग और सामाजिक प्रगति के लिए, वर्णित जून, 28-30, 1976, मास्को, 1976, पृ० 5

पुनः नियन्त्रित करने में लगा था। इन अर्थों में 1974-75 का संकट और उसके परिणाम वास्तव में स्वयं राज्य-इजारेदारी व्यवस्था के संकट के अतिरिक्त कुछ न थे।

अर्थव्यवस्था के राज्य द्वारा नियमन, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय इजारेदारी में एकीकरण ने इस संकट को विशेष रूप से गहरा और तीव्र बना दिया है। एक ही समय आयी उत्पादन में चक्रिक मंदी ने पूँजीवादी विश्व में अर्थव्यवस्था की सभी मूलशाखाओं को और साम्राज्यवाद के सभी शक्ति केन्द्रों को, प्रभावित कर दिया, और ऐक्यबद्धता की सीमाओं को पार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक भी पूँजीवादी देश दूसरे देश की क्रीमत पर संकट से बाहर नहीं निकल सका। दूसरी ओर, सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा, अपनी इजारेदारियों सहित, डाला गया निरंतर दबाव संकट को और अधिक बढ़ा देता है और नयी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं जिन्हें इसके 'कनिष्ठ भागीदार' मेहनतकश जनता के कंधों पर ढालने की कोशिश करते हैं।

पूँजीवाद अब इस स्थिति में नहीं है कि अतिरिक्त उत्सर्जन तथा कमी की आपूर्ति, तथा धन के व्यय के लिए पर्याप्त मात्रा में योग्यता के साथ कीम्स के नुस्खों का उपयोग कर सके जैसे कि क्लासिकीय रूपों के काल में किया जाता था—मंदी के और बेरोजगारी के साथ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की स्फीति विल व्यवस्था से जुड़ गयी है। मुद्रास्फीति वास्तव में नियंत्रण को तोड़ चुकी है और इसने संपूर्ण विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मुद्रा-क्षेत्र में भयानक संकट उत्पन्न कर दिया है। इससे भी आगे, निरंतर बढ़ती हुई कीमतों, और इसी प्रकार इजारेदारियों के सरकारी अनुदानों और शास्त्रास्त्र निर्माण पर अत्यधिक व्यय ने संकट में बाहर निकलने के रास्ते खोजने और उसके परिणामों का सामना करने के अवसर समाप्त कर दिये हैं।

इस प्रकार, क्लाड जूलियन तब सर्वथा सही थे जब 1974 के अंत में उन्होंने संकटापन्न परिघटनाओं के वास्तविक आयामों को कम आंकने और इस प्रकार सामान्य मूल्यांकन को विकृत करने के प्रयासों के विरुद्ध चेतावनी दी थी। उन्होंने 'ल मांड डिप्लोमैटिक' में लिखा था : "रिनॉल्ड स्टेट फैंक्टेरीज बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा : एक बाजार का संकट... एक दीर्घकालिक बाजार संकट, अमरीकी अधिक संतुलित निर्णय देते हुए कहते हैं, एक लंबी अवधि का संकट, बेलेरी गिस्कांड डीएस्टेंग पुष्टि करते हैं। कोई भी स्पष्ट रूप से इसके चरित्र के संबंध में एक शब्द भी कहने का साहस नहीं करता, व्यवस्था के संकट के रूप में, और यह स्पष्टतः विषय का मर्म है।"¹

1974-75 का आर्थिक संकट साम्राज्यवाद की पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था की छिन्न-भिन्न होने की स्थितियों के तथा गंभीर विरोधों के ऊँचे होने की स्थितियों के अंतर्गत चल रहा था। औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच। यह उस समय उभरा जबकि नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था के संगठन का प्रश्न विचारणीय मुद्दा बन चुका था। इसने न केवल पूँजीवाद के लिए वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करना अधिक कठिन बना दिया अपितु वह इसके आम संकट की अगली व्यवस्था का चुनियादी कारक भी बन गया।

वास्तव में, हम तथाकथित विकासमान देशों की विस्तृत कीमत पर संघर्ष एक और दौर के आरंभ के साक्षी हैं जो इस समय आर्थिक क्षेत्रों में है। यद्यपि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के आघातों ने साम्राज्यवाद को एशिया और अफ्रीका में बहुत से देशों की राजनीतिक स्वाधीनता को मान्यता देने के लिए बाध्य किया है, वस्तुतः वे विश्व के इन विशाल क्षेत्रों के जनगण की तथा उनके कच्चे माल की और ऊर्जा ससाधनों की लूट को जारी रखे हुए है।

1953 में 1973 के पिछले दो दशकों में, पूँजीवादी और विकासशील देशों के प्रतिष्ठापित सामान्य राष्ट्रीय उत्पादन के बीच का अन्तर दुगुना बढ़ गया है। और आज यह अनुपात 16:1 के बराबर है। यह आश्चर्यप्रद नहीं है, यदि हम यह ध्यान में रखें, उदाहरणार्थ, यह तथ्य कि पश्चिम जर्मनी मुख्य रूप से जो कच्चा माल विकासमान देशों से आयात करता है वह 1962 से 1972 के बीच 2.1 प्रतिशत बढ़ गया जबकि तैयार माल का निर्यात मूल्य 24.5 प्रतिशत तक पहुँच गया—इसी काल में। हमने इस प्रकार बहुत से उदाहरण उद्धृत किए हैं जो स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं नव उपनिवेशवाद के नाम से जिस परिघटना की चर्चा की जा रही है वह पुराने उपनिवेशवाद से अधिक भिन्न नहीं है। इसका अर्थ है कि मुट्ठी भर आर्थिक रूप से विकसित देश विकासमान देशों को अभी भी निरंतर लूट और कुचल रहे हैं।

और अधिक समय तक इस स्थिति को जारी रखने के अनिच्छुक विकासशील देश अपने यहाँ के ऊर्जा ससाधनों और कच्चे माल के स्वामित्व और मुनाफ़ों (जो विदेशी इजारेदारियाँ ले रही हैं) के बीच साम्राज्यवादियों द्वारा लागू किए गए असंतुलन को सुधारने, उसकी रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। दूसरे शब्दों में वे अधिक न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था चाहते हैं जो श्रम के अन्तराष्ट्रीय विभाजन पर आधारित हो, जो समस्त मानव समाज के हितों को पूरी तरह ध्यान में रख सके।

कुछ क्षेत्रों में और कुछ मुद्दों पर विकासमान देश पहले से ही स्थिति को अपने पक्ष में परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ मामलों में साम्राज्यवाद अधिक समय तक पहले की तरह कच्चे माल की कीमतें मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों ने इजारेदारियों को अतिरिक्त ससाधनों की खोज के लिए

मजदूर कर दिया है जिससे कि कच्चे माल और ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकें और विकासशील देशों की क्रोमट पर संकट से बचने की उनकी परम्परागत संभावनाओं में कटौती भी कर दी है।

1974-75 का आर्थिक संकट पहला था जो विश्व समाजवादी व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद आया। अब एक ही समाजवादी देश नहीं है, बल्कि समाजवादी देशों का समुदाय है जो सक्रिय रूप से विश्व की घटनाओं को प्रभावित करता है, स्वयं पूँजीवादी देशों की घटनाओं पर भी प्रभाव डालता है। फलस्वरूप, पूँजीवाद अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर सकता। साम्राज्यवाद भी समाजवादी व्यवस्था और मेहनतकश जनता के मुक्ति आंदोलन के विरुद्ध इसी प्रकार अपने स्वयं के अन्तर्विरोधों को हल करने के लिए अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक साधनों के व्ययन में अधिकाधिक सीमित होता जा रहा है। यह उसकी दोनों, गृह तथा विदेश—नीतियों पर लागू होता है। मेहनतकश जनता की कीमत पर और विदेश नीति के विस्तार के जरिये अन्तर्विरोधों को सुलझाने के परम्परागत तरीकों को इजारेदारी विरोधी शक्तियों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

विश्व एकाधिकारवाद ने कभी अपने तरीकों को नहीं छोड़ा जब कभी इसके मुताफों के लिए खतरा पैदा हुआ इसने अत्यधिक खतरनाक जुएबाजी और उपवादी उपाय किए। उदाहरण के लिए, यह सभी जानते हैं कि पहला विश्वयुद्ध अत्युत्पादन के चार्किक संकट के दौरान शुरू हुआ था जो 1913 में आरंभ हुआ और उसने आर्थिक रूप से सभी पूँजीवादी देशों को प्रभावित किया था। 1929-33 का विध्वंसकारी आर्थिक संकट और उसके बाद 1937-38 की मंदी दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व आई थी। इसी तरह वर्तमान संकटापन्न स्थिति पूँजीवादी देशों में सैन्यवादी शक्तियों के क्रियाकलाप को बढ़ावा दे रही है जो तनाव-शैथिल्य को सर्वथा अस्वीकार करते हैं। यही ताकतें हथियारबंदी की दौड़ को और अधिक मात्रा में तेज करना चाहती हैं, और समय रहते विश्व नीति के क्रम को शीतयुद्ध की तरफ उलटा घुमाना चाहती हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत हल्के इस स्थिति में नहीं है कि विश्व घटनाओं के क्रम को निर्देशित कर सकें और अपनी इच्छा जनगण पर लाद सकें जैसा कि कभी अतीत में वे किया करते थे।

जब कभी पूँजीवाद को आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह अपने सामाजिक प्रभुत्व को बचाने और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, और राजनीतिक स्थिरता की कमी का लाभ उठाने की कोशिश में घोर प्रतिक्रियावादी तरीके काम में लाते हैं। मजदूर वर्ग पर और सामान्यतया आम जनता पर चोट करने के लिए। यही जर्मनी में फ्रांसिस्म ने किया था।

वर्तमान संकटापन्न परिघटना भी नव फ्रासीवादी शक्तियों को और अन्य

उग्र दक्षिण पंथी धाराओं को उत्तेजित करती है। उनका वेद वाक्य है 'शिकंजा कसो', जिससे कि मजदूर वर्ग को 'अपने पेटियाँ कसने को बाध्य किया जा सके तथा 'कानून और व्यवस्था' स्थापित की जा सके।

तथापि, आज इन प्रवृत्तियों का विरोध जनतांत्रिक शक्तियों के मोर्चे द्वारा दोनों तरह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, तथा अलग-अलग पूँजीवादी देशों में भी, किया जा रहा है। एक पूर्णतया भिन्न स्थिति आकार ले रही है। नव पूँजीवाद, जबकि निस्संदेह रूप से अपने साम्राज्यवादी रूप में रहते हुए, वह अधिक समय तक मात्र अपने स्वयं के कानूनों द्वारा अस्तित्व में नहीं रह सकता, इससे भी बढ़कर, यह समाजवाद में संक्रमण का रूप धारण करता जा रहा है। लेनिन ने लिखा था—“पूँजीवाद अपनी साम्राज्यवादी अवस्था में, उत्पादन के प्रत्यक्ष तथा अत्यधिक समझदारी भरे समाजीकरण की दिशा ग्रहण करता है; या कहना चाहिए, कि यह पूँजीपतियों को, उनकी इच्छा और चेतना के विरुद्ध खींच ले जाता है, एक प्रकार की नई सामाजिक व्यवस्था में ले जाता है, जो कि संक्रमण काल की अवस्था है, एक पूर्णतया मुक्त प्रतियोगिता से पूर्ण समाजीकरण की दिशा में।”¹ एक ओर तो इसे राज्य इजारेदारी पूँजीवाद की कार्य विधि में मुख्य परिवर्तन द्वारा लक्षित किया गया है और दूसरी ओर सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के सहसंबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में भी जो समाजवादी क्रांति के आरंभ में इजारेदारी विरोधी मोर्चा बनाता है। इसके लिए यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के सम्मेलन के दस्तावेज में लिखा गया है—“समाज में पहले से बहुत बड़े भाग पूँजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करने की ऐतिहासिक आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं जो प्रत्येक जनगण की इच्छाओं के अनुरूप निर्मित की जाएगी।”²

1. वी. आई. लेनिन, साम्राज्यवाद : पूँजीवाद की सर्वोच्च अवस्था, संकलित, रचनाएं भाग 22 पृष्ठ 205

2. फ्रॉर पीस सिग्योरिटी, कोऑर्डेशन एंड सोशल प्रोग्रेस इन यूरोप, पृष्ठ 35

इजारेदारी-विरोधी-मोर्चे का निर्माण

"अब इतिहास स्वयं ही न्यायाधीश है, तथा सर्वहारा उसके निर्णय का निष्पादक।"¹

—कार्ल मार्क्स

सामाजिक विकास की मूल शक्ति

पूँजीवादी दुनिया में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता दरअसल समय की पहचान बन गई है। पूँजीवादी विश्व में आज न तो कोई भी ऐसा दल या सामाजिक आंदोलन है जो जन-असंतोष की अवहेलना कर सकता हो और न ही एक या दूसरे सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन को समर्थन देने से चूक सकता हो। सन् 1974-75 का संकट और उसके बाद के प्रभावों ने इस प्रवृत्ति को मजबूत ही किया है। सारी समस्या का केंद्र इन मूलभूत परिवर्तनों की विषयवस्तु है—कि ये किसके पक्ष में हैं और किस तरह घटित होते हैं।

लेनिन के अनुसार, मार्क्सवादी हमेशा "एक निर्धारित क्षण में ऐतिहासिक प्रक्रिया के वस्तुगत सार तत्त्व का विश्लेषण करते हैं, निश्चित और ठोस परिस्थितियों में उसकी जाँच करते हैं; वे ऐसा यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि प्रमुखतया कोई आंदोलन किस प्रकार का है, उन ठोस परिस्थितियों में वह किस वर्ग के मूल नेतृत्व में, किस उद्देश्य के लिए, किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है।"²

मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षण के अनुसार 'प्रेरणास्रोत' मजदूर वर्ग होता है। इस निष्कर्ष के समर्थन में हमारा अनुभव समुचित प्रमाण उपलब्ध कराता है, पिछले 150 वर्षों में सर्वहारा वर्ग अपरिहार्य वर्ग-संघर्षों के बीचोंबीच रहा है और उसने मुक्ति और लोकतांत्रिक आंदोलन में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है। अपेक्षाकृत अल्प ऐतिहासिक अवधि में मजदूर वर्ग ने राजनैतिक शक्ति के रूप में विशाल प्रगति की है। यह हमारे युग के प्रगतिशील परिवर्तनों का नेता है। पूँजीवादी देशों में इसका संघर्ष सामाजिक विकास की प्रमुख शक्ति बन चुका है और "सारी मेहनतकश जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, और

1. मार्क्स/एंगेल्स, वर्क, खंड 12, पृ० 4

2. बी. आई. लेनिन, 'अदर ए फ़ाल्स प्रीच', कलेक्टेड वर्क्स, खंड 22, पृ० 143

सबसे बढ़कर राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है।¹

मजदूर वर्ग ने मुक्ति और लोकतांत्रिक संघर्ष के नेतृत्व को, साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध भारी लड़ाइयों के दौरान लीने हुए जीतकर हासिल किया है। समकालीन समाज के अन्य वर्गों में इसकी भूमिका और इसका स्थान क्रमशः पहचाना गया था। एक ऐसा भी समय था जब सर्वहारा, जोकि पहले से ही लोकतांत्रिक आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, अपने ही बलवृत्त पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में काम नहीं कर सकता था और न अपना खुद का कार्यक्रम ही सामने रख सकता था; उसने जो संघर्ष छेड़ा था वह अपने वर्ग शत्रु—बूज्वा वर्ग—के खिलाफ सीधे तौर पर लक्षित नहीं था किंतु वह उसके दुश्मन के दुश्मनों के विरुद्ध था—अर्थात् सामंती प्रभुओं और तानाशाही के विरुद्ध था। अठारहवीं शताब्दी के अंत की स्थिति ऐसी ही थी अर्थात् फ्रांसीसी क्रांति और अमरीकी उपनिवेशों के स्वाधीनता संग्राम की अवधि के दौर में। दूसरे शब्दों में, उस अवस्था में यह फिर भी आवश्यक था कि बूज्वा वर्ग के सामाजिक-राजनैतिक और सैद्धांतिक प्रभाव से सर्वहारा की मुक्ति की समस्या को हल किया जाय अर्थात् इसे अपने आपको एक स्वाधीन, और उससे भी अधिक, सामाजिक प्रगति की मूल शक्ति के रूप में स्थापित करना था।

यह लक्ष्य कुछ दशकों के दौर में ही पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया। सर्वहारा वर्ग 1830 और 1840 के दशकों के वर्ग युद्धों (ग्रेट ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन और फ्रांस और जर्मनी में मजदूर संघर्ष) में लोकतांत्रिक आंदोलन की स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने लगा था। अगले दशकों में, विशेषतया मार्क्सवाद के उदय के बाद, यह प्रक्रिया तीव्र गति से विकसित होने लगी, अधिकाधिक देशों को प्रभावित करती हुई। समय के साथ मजदूर वर्ग ने अपने खुद के कार्यक्रम का निर्माण किया जो दूसरे तमाम लोकतांत्रिक आंदोलनों के कार्यक्रमों की अपेक्षा, कहीं अधिक व्यापक और अधिक प्रगतिशील था। इस विकास की द्वंद्वत्मकता ऐसी थी कि स्वयं के द्वारा निर्मित मंच के आधार पर एक के बाद दूसरी स्थिति पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वहारा अपने ऐतिहासिक मिशन को न केवल अपने ही हितों को प्राप्त करने के लिए ही पूरा करने लगा, किंतु वह उसे सारे ही श्रमिक जनसमुदाय के हितों की प्राप्ति के लिए पूरा करने लगा। तब से आवादी के व्यापक गैर-सर्वहारा हिस्सों के साथ इसका पुनर्मिलन हुआ जिसका आधार था मौलिक सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्धारित एक स्वतंत्र कार्यक्रम। सामाजिक विकास के तर्क ने इस सह मिलन को अनिवार्य बना दिया था। ठीक जैसे कि बूज्वा वर्ग ने अपनी आरंभिक अवस्था में अपनी ही बत्त खोदने वालों को, अर्थात् सर्वहारा को, पैदा कर दिया था उसी तरह पूंजीवाद—एक व्यवस्था के रूप में नष्ट होने के दौर में—ऐसी वस्तुगत परिस्थितियाँ पैदा कर देता

है जिनसे एक ऐसा व्यापक इजारेदारी-विरोधी मोर्चा संगठित हो जाता है जिसमें सभी वास्तविक प्रगतिशील सामाजिक शक्तियाँ मजदूर वर्ग के चारों ओर एकता-बद्ध हो जाती हैं तथा जो देर-सवेर पूँजीवादी व्यवस्था को उल्ट देती हैं।

प्रत्येक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, युद्ध को रोकने के लिए सच्ची लोकतांत्रिकता तथा एक अन्य विश्व युद्ध को टालने के लिए सघर्ष समाजवादी क्रांति की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो रहा है। लेनिन ने लिखा—“सर्वहारा को लोकतांत्रिक क्रांति को पूर्ण करना ही होगा, अपने आपको किसानों के समुदाय से मंत्री के द्वारा एकताबद्ध करके ताकि निरंकुश एकात्मन के प्रतिरोध को शक्ति के द्वारा कुचला जा सके और बूर्ज्वा अस्थिरता को शक्तिहीन बनाया जा सके।” इसके आगे उन्होंने स्पष्टतया कहा—“सर्वहारा को समाजवादी क्रांति को पूर्ण करना होगा, अपने आपको आबादी के अर्द्ध-सर्वहारा तत्त्वों से मंत्री के द्वारा एकताबद्ध करके, ताकि बूर्ज्वा प्रतिरोध को शक्ति के द्वारा कुचला जा सके और किसानों और टट्पुजियों के वर्ग की अस्थिरता को संज्ञा शून्य किया जा सके।”¹

लेनिन ने यह निष्कर्ष इस शताब्दी के आरंभ में निकाला था, उस प्रारंभिक अनुभव के आधार पर जो सन् 1905-07 की रूसी क्रांति के दौरान प्राप्त हुआ था। उन्होंने पूँजीवाद से समाजवाद में मानवता के संक्रमण के आगामी युग के सार तत्त्व तथा आधारभूत दायित्वों व उन्हें पूरा करने वाली शक्तियों का व्यापक पूर्वानुमान लगा लिया था।

जब से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ तब से यह एक अक्षुण्ण सैद्धांतिक और राजनैतिक संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। और स्वभावतः इस रूप में वह सम-कालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया और सामाजिक विकास के मुख्य सामाजिक-राज-नैतिक दिशा-निर्देशों के सार तत्त्व के मूल्यांकन कारक बन गया है। यहाँ दो प्रकार के सिद्धांत सूत्र हो सकते हैं। यदि यह मान लिया जाय की समकालीन समाज की नेतृत्वकारी शक्ति सर्वहारा है, तो ऐतिहासिक विकास की धारणा वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत है जिसके अनुसार पूँजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति, प्रगति करते हुए विश्व स्तर पर प्रत्येक देश की वर्ग शक्तियों की प्रसंगानुसार मंत्री और एकता को साथ लिये समाजवादी क्रांति में रूपांतरित हो जाती है। यदि, दूसरी ओर यह मान लिया जाय कि सर्वहारा ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और, यह भी कि अब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है (जो कि मार्क्सवाद विरोधियों का मत है), तो बहुत ऐसी गुंजाइश है कि मनमाने नतीजे, आम तौर पर कम्युनिस्ट-विरोधी प्रकृति के, निकाले जा सकें।

1. वी० आई० लेनिन—“टू टेक्ट्स ऑफ सोवियल-डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन”
संकलित रचनाएँ, खंड 9 पृ० 100

आजकल मजदूर वर्ग की भूमिका के विषय में विशद रूप से विवादपूर्ण संघर्ष चल रहा है। यह सब उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के विरोध में हो रहा है जो अन्य कारकों के अलावा वैज्ञानिक प्राविधिक क्रांति के द्वारा अधिक घटित किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि श्रमिक वर्ग के आंदोलन के पक्ष में वर्ग शक्तियों के विश्व संतुलन के दायरे में घटित होने वाली तब्दीलियों की चर्चा तर्कसंगत बन जाती है।

इस तथ्य का खंडन करने से प्रतिबद्ध बूज्वा सिद्धांतकार मजदूर वर्ग के 'क्षय' 'विलय' और 'अदृश्य' हो जाने की बात भी करते हैं। एसेन तूरेन जोर देकर कहते हैं—“एक कार्यक्रमबद्ध समाज में मजदूर वर्ग अब कोई इतिहास का नेतृत्वकारी नायक नहीं है।”¹ इससे भी अधिक स्पष्ट वक्तव्य सिप्रिद ह्यूक के हैं जो पश्चिम में लोकप्रिय दार्शनिक और राजनैतिक रचनाओं की लेखिका हैं। वह अपनी पुस्तक, जिसका एक महत्वाकांक्षा पूर्व आडवरी शीर्षक ‘पोस्ट-कम्युनिस्ट मेनिक्रेस्टो’ है, में लिखती हैं—“मार्क्स का प्रतिरूप परिवर्तित समाज के अनुरूप सिद्ध नहीं होता। अब सर्वहारा वर्ग का कोई चिह्न बाकी नहीं बचा है। प्रत्येक निवर्तमान दिन के साथ मजदूर वर्ग के संबंध में बात करने का बहुत कम औचित्य दिखता है। यह काफी समय पहले से मध्यम स्तर के साथ एकजुट हो चुका है। अब वर्ग संघर्ष में उसकी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि क्लासिकी मार्क्सवाद के अर्थ में देखें तो अब गरीब वर्ग है ही नहीं, सर्वहारा में यह भावना नहीं है कि वह अपने आप में एक माल है; उसका न कोई शोषण होता है न कोई दमन तथा न ही आर्थिक संबंधों का दबाव।”²

सिप्रिद ह्यूक कहती हैं कि वह घोषित मार्क्सवाद-विरोधी है और हम उनसे कुल मिलाकर इसी बात पर सहमत हो सकते हैं। वह जिस महत्वाकांक्षी काम को पूरा करने में संकल्पबद्ध हैं—“युवा पीढ़ियों को मार्क्सवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियारबद्ध करना।”³ वह कुछ बहुत घिसेपिटे और पूर्णतया भ्रामक विचारों को, जिनके अनुसार ‘सामाजिक भागीदारी’ की संभावना व्यक्त की गई है—व्यक्त करने के अलावा कुछ भी नया विचार पैदा करने में असमर्थ है। अतः उनकी रचनाएँ पाठक को वापस भौड़े कम्युनिज्म-विरोधी विचारों की ओर धकेलती हैं। तूरेन, ह्यूक और दूसरे बूज्वा विचारकों से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जो समकालीन युग के विकास की वास्तविक प्रवृत्तियों की ही उपेक्षा करना चाहते हैं। आज के बूज्वा विश्व की सामाजिक संरचना की सच्ची तस्वीर को विकृत करके वे

1. एलेन तूरेन, —‘स’ सोसाइटी पोस्ट-इंडस्ट्रीने’, पेरिस, 1969, पृ० 25

2. सिप्रिद ह्यूक, दास नाक-कम्युनिस्टिक मेनिक्रेस्ट, डेर डाइलेक्टिक यूनिटैरिज्मस एल्स आल्टरनेटिव, स्टूटगार्ट 1974, पृ० 15

3. वही, पृ० 11

जानबूझकर इसकी मूल प्रवृत्तियाँ—किराए के मजदूरों की संख्या में तीव्र वृद्धि और मजदूर वर्ग के लगातार बढ़ते हुए अनुपात—को नजरंदाज करते हैं।

दोनों प्रवृत्तियाँ आधुनिक उत्पादन की वस्तुगत आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती हैं, और ये समाजवादी और पूँजीवादी दोनों प्रकार के देशों में विकसित होती हैं। किंतु इसमें वस्तुगत अंतर यह है कि जहाँ तक समाजवादी देशों का संबंध है वहाँ उनमें सब काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और सब कुछ मेहनतकश लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, जबकि पूँजीवादी देशों में वे काम सहज गति से होते रहते हैं और इसलिए आगे चलकर सामाजिक विरोधों और संघर्षों को अनिवार्यतः तीव्र करते हैं।

सोवियत संघ में सन् 1960 से 1974 तक, जबकि कृषि मजदूरों की संख्या और उनके अनुपात में ह्रास हुआ, तो औद्योगिक मजदूर वर्ग की संख्या 459 लाख से बढ़कर 702 लाख हो गई। सक्रिय पोश मजदूरों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई—88 लाख से बढ़कर इसी अवधि में 214 लाख हो गई।¹ ये सभी प्रक्रियाएँ—जो एक विकसित समाजवादी समाज में, अंतिम विश्लेषण में, औद्योगिक, यांत्रिक और उन्नत कुशल श्रम के अनुपात से निर्धारित होती हैं सोवियत संघ में भविष्य में भी जारी रहेंगी। समाजवाद के अंतर्गत ये प्रक्रियाएँ सारे समाज को फ़ायदा पहुँचाती हैं और इसलिए इनके साथ-साथ मजदूर लोगों की सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में भी तेजी के साथ विकास होता है तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाता है। समाजवादी समाज में श्रमिक लोगों में बीच के विभिन्न सामाजिक पृष्ठ-भूमि के भेदभाव को मिटा दिया है जो उनकी बढ़ती हुई संबद्धता और नैतिक और राजनैतिक एकता में अभिव्यक्त होता है।

पूँजीवाद के अंतर्गत किराये के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने और मजदूर वर्ग के आकार में वृद्धि होने का परिणाम होता है श्रम और पूँजी के बीच में मुख्य विरोध का तीव्र होना।

उत्पादन के साधनों के सँकेंद्रीकरण की तरफ पूँजीवाद का स्थायी रहान एक ऐसे सँकेंद्रीकरण की तरफ से जाता है जो उसके विपरीत ध्रुव में होता है। यह सँकेंद्रीकरण जनसंख्या के उस विशाल जन समुदाय में होता है जिसे जीवन के सभी साधनों से—सिवाय उनकी मानवी शक्ति के—बंचित किया जा चुका है, तथा यह समूचे पूँजीवादी विश्व में, खास कर उन्नत औद्योगिक देशों में बलूची देखा जा सकता है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार किराये के मजदूरों का अनुपात, फ़ायदे वाली नियुक्त आबादी में लगातार बढ़ता जाता है। 1970 के दशक के मध्य में वह 70 से 85 प्रतिशत तक ऊँचा चला गया, उन देशों में जो

1. देखिए: सोवियत संघ की सन् 1975 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आँकड़ों की वर्ष पुस्तिका, माँस्को: 1976 पृ० 9 (रूसी भाषा में)

औद्योगिक पूँजीवादी देश हैं। ये आँकड़े लाखों-लाख लोगों की जिंदगी तथा सैकड़ों-हजारों परिवारों की तबाही की कहानी कहते हैं, आबादी के विशाल हिस्से के सर्वहाराकरण, मोहभंग, पुराने विचारों की दुखद अस्वीकृति, तथा साथ ही वर्गीय विरोधों व सामाजिक शक्तियों के सशक्त होने को भी व्यक्त करते हैं। इजारेदारों के शासन के विरोध में, पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रिया में इन शक्तियों को ही आगे लाया गया था।

निस्संदेह वृज्वा समाज के सामाजिक ध्रुवीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मजदूरों की संख्यात्मक और अनुपातात्मक वृद्धि ही होती है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले दशक में वे दरअसल एक विशाल वर्ग बन चुके हैं। पिछली सदी के अंत में सारी दुनिया में लगभग 300 लाख औद्योगिक मजदूर थे, जबकि आज 2000 लाख से अधिक मजदूर केवल औद्योगिक पूँजीवादी देशों में ही हैं, और दुनिया भर में काम पर लगे हुए लोगों की कुल संख्या अनुमानतः 7000 लाख है।¹

तथापि, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के रूप में मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका केवल इसकी संख्या शक्ति की वजह से ही नहीं है, अपितु सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में इसके स्थान की वजह से कही अधिक है; संगठन के स्तर, इसकी राजनैतिक चेतना और सम्मान की वजह से भी है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति के प्रभावाधीन मजदूर वर्ग की स्थिति के गंभीर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं; अर्धव्यवस्था में इसकी भूमिका बढ़ जाती है और इसी प्रकार उसका शैक्षिक स्तर और उसकी राजनैतिक सक्रियता बढ़ जाती है।

1. पिछले सौ सालों में औद्योगिक पूँजीवादी देशों में मजदूर वर्ग का विकास निम्नांकित प्रकार से था—

19 वीं सदी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में 41 लाख औद्योगिक मजदूर थे (1951), फ्रांस में 25 लाख (1848), जर्मनी में 9 लाख (1850), संयुक्त राज्य में 14 लाख (1850)।

20 वीं सदी के मोड़ पर संयुक्त राज्य में सर्वहारा वर्ग की संख्या थी—104 लाख (1900), ग्रेट ब्रिटेन में 85 लाख (1901), जर्मनी में 85 लाख (1907), फ्रांस में 34 लाख (1906), इटली में 29 लाख (1901) और आस्ट्रिया-हंगरी 23 लाख (1900) आदि।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ी कि सड़का विषम हो गई। संयुक्त राज्य में 225 लाख से बढ़कर (1971) में 313 लाख हो गई, ग्रेट ब्रिटेन में 1951 में 115 लाख से बढ़कर 1966 में 125 लाख हो गई, फ्रांस में 1954 में 66 लाख से बढ़कर 1971 में 85 लाख हो गई, पश्चिमी जर्मनी में 1950 में 82 लाख से बढ़कर 1971 में 137 लाख हो गई, इटली में 1954 में 46 लाख से बढ़कर 1970 में 80 लाख, जापान में 1950 में 11 लाख से बढ़कर 1970 में 197 लाख हो गई (देखिए—ग्रेट सोवियत एंसाइक्लोपीडिया खंड 21 पृ० 110-14, 314)

हर जगह जहाँ सर्वहारा की कतारों में ताज़ा शक्तियाँ के लामबंद होने से शक्ति आती है वस्तुगत रूप में मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों के फैलने की अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और उनके झंडे के नीचे लोकतांत्रिक शक्तियों का व्यापक साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा बन जाता है। इस सबसे गंभीर सामाजिक आर्थिक रूपांतरणों के लिए अनुकूल पूर्वापेक्षाएँ तैयार हो जाती हैं जिन्हें मजदूर वर्ग का हिराबल दस्ता इजारेदारी शासन के विरुद्ध अथक संघर्ष के दौर में जीवन के भीतर उतारने का काम करता है।

इस दिशा में उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम स्वभावतः पूँजीवाद द्वारा उन्मत्त प्रतिरोध को प्रेरित करता है। जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूँजीवाद जीवित रहता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह मजदूर वर्ग पर इस दृष्टि से दबाव डालता रहता है कि वह अपने मित्रों से अलग हट जाय और संघर्ष के मुख्य उद्देश्य से उसका ध्यान हट जाय। साम्राज्यवादी गिरोह श्रमिक वर्ग व उसके संगठनों के पंचमेल तथा बूज्वा परंपराओं एवं भ्रांत धारणाओं—जो कि बाहर से श्रमिक वर्ग में प्रविष्ट करायी जाती है—का दोहन करता है तथा करता रहेगा। यह दिमाग में रखना चाहिए कि आज के बहुत से मजदूर कल तक आवादी के गैर-सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे। उनमें राजनैतिक संघर्ष का सही अनुभव नहीं है और इसलिए प्रायः वे बूज्वा सिद्धांत और टटपुंजिया मध्यमवर्गीय सुधारवाद के लिए उपजाऊ भूमि का काम करते हैं।

पूँजीवादी दुनिया में मजदूर वर्ग की स्थिति विभिन्न राष्ट्रों की अनिश्चितताओं भरी आर्थिक स्थिति में बहुत विषमता लिये होती है। प्रत्येक पूँजीवादी देश में मजदूर लोगों की यही स्थिति विभिन्न श्रेणियों की होती है। पूँजीवादी प्रणाली के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास में विषमता बढ़ती रहती है जो आगे चलकर हालात को और अधिक तेजी से बिगाड़ने लगती है और मजदूरों के कुछ हिस्सों में तमाम प्रकार के भ्रमों को बढ़ावा देने लगती है। पूँजीवाद ने हाल ही में बहुत कुछ सीखा है और ऐसे हजारों छलछंदों का आविष्कार किया है जिनसे मजदूर वर्ग के संघर्ष को झूठी राह पर धकेल दिया जाय और इस प्रकार उनकी चोट घूमकर उनपर ही पड़े, वह स्वयं निशाना न बने।

इस विषय में वैचारिक तोड़फोड़ किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है। पूँजीवादी दक्षिणपंथी अवसरवादी और 'वाम' उग्रपंथी प्रचारतंत्र दो दिशाओं से अपनी बढ़क का निशाना मार्क्सवाद-लेनिनवाद की उस शिक्षा और विचारधारा को बनाते हैं जिसमें लोकतांत्रिक आंदोलनों और समाजवाद के लिए संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया गया है। सभी बूज्वा विद्वान, सुधारवादी नेताओं की तो बात ही क्या, अपने विचारों में उतने स्पष्ट नहीं होते जितनी कि 'पोस्ट-कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' की लेखिका है। उनसे बहुत से न

तो किराये के मजदूरों के अनुपात में वृद्धि में इन्कार करते हैं, न ही आधुनिक उत्पादन में उनकी भूमिका की बढ़ोतरी से इन्कार करते हैं, और न ही, स्वभावतः इस तथ्य से कि सर्वहारा नये समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करता है—सफलतापूर्वक, व्यापक स्तर पर। इसलिये वे एक नई दलील देते हैं जो स्पष्टतः इन वास्तविकताओं पर विचार करती है। एक समय था जब मात्र आदिम क्रिस्म के तर्क दिये जाते थे : मजदूर वर्ग, इसके प्रतिनिधि, “साधारण मशीन-ओजार पर काम करने वाले लोग” लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता की भूमिका का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव था और उनके पास आवश्यक अनुभव भी नहीं था कि आबादी के दूसरे हिस्से सर्वहारा का समर्थन करते। अब एक नया विचार प्रस्तुत किया जाने लगा है कि सर्वहारा और उसकी जीवन स्थितियों में इतने मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं कि मजदूर वर्ग के लिए नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने की आवश्यकता और परिणामतः समाजवादी क्रांति के लिए भी इसकी आवश्यकता स्वतः समाप्त हो गई है। कारण यह दिया जाता है कि सभी या लगभग सभी भूतकालीन पापमयी समस्याएँ सुलझा दी गई हैं या इस सामान्य अभिजात्य प्रजातंत्र में शीघ्र और सर्वोत्तम विधि से सुलझा दी जाएँगी। या इसके विपरीत इस बात पर लगातार जोर देकर कहा जाता है कि परिवर्तनों के परिणामस्वरूप दूसरे वर्ग और पूँजीवादी समाज के दूसरे हिस्से ठीक वैसे ही हो गए हैं—उतने ही ‘क्रांतिकारी’ या उससे भी अधिक—और इसीलिए इजारेदारी-विरोधी सघर्ष में नेतृत्व की भूमिका का दावा करने का अधिक अधिकार उनको है।

इस समस्या के संबंध में व्यापक साहित्य में विभिन्न दृष्टिकोण पाये जाते हैं। कुछ लेखक मजदूरों के श्रम को शारीरिक श्रम के रूप में ही पहचानते हैं और यह विचार आगे बढ़ाते हैं कि वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के विकास के साथ मजदूर वर्ग लुप्त हो जायगा। दूसरे, जो परंपरागत ब्रूज्वा राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान हैं तथा थामस कार्वर के समय की भोड़ी धारणाओं से प्रतिबद्ध हैं—वे इसी व्याख्या को विस्तार देते हैं कि निगमीय मुनाफों में हिस्सा बँटाने के पश्चात् सर्वहारा अब अभावग्रस्त वर्ग नहीं रह गया है और लगभग या पूरी तरह पूँजी का सहस्वामी बन चुका है। तीसरा दल इस बात को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि सर्वहारा अब उतना संगठित वर्ग नहीं रहा जितना कि वह पहले था तथा अब अनेक छोटे-छोटे गुटों और ‘स्तरो’ में बिखर रहा है। किन्तु ये सब नतीजे इस दृष्टि से आपस में मेल खाते हैं कि आधुनिक श्रमिक ने अपने लिए अचानक इस तथ्य का पता लगा लिया है कि ‘मुनाफ़ों में क्रांति’ हो चुकी है जिसने उसको उपक्रमी के ‘सामाजिक भागीदार’ के रूप में बदल दिया है और अब उसमें क्रांतिकारी की क्षमता नहीं रही है तथा वह पूरी तरह अभिजात्य वर्ग में बदल गया है जिसकी कि इजारेदारी पूँजी के शासन के साथ संगति है।

जे० गालब्रेथ अपनी पुस्तक 'द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट' में जोर देकर कहते हैं कि पुराने पूँजीवाद से एकदम पृथक्, वर्ग-संघर्ष इसलिए समाप्तप्रायः हो गया है कि 'पहले जो तीव्र विरोधी हित हुआ करते थे अब उनमें तालमेल कायम हो गया है।'

लाक्षणिक दृष्टि से देखें तो गालब्रेथ, बैल और लिपसैट आदि जैसे प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानवेत्ता 'नव औद्योगिक' और 'औद्योगिकोत्तर' समाज और 'प्राविधिक विद्युतीय युग' के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए 'मजदूर वर्ग' की धारणा को शारीरिक श्रमिकों की श्रेणी तक ही सीमित रखते हैं। इसके विपरीत सशोधनवादी और 'वामपंथी' शोधकर्ता नियमानुसार कम-से-कम अपनी रचनाओं में तो समाज के दूसरे स्तर में इस वर्ग के 'विलय' की दलील देते हैं। वर्ग के रूप में वे सर्वहारा की सामाजिक एकात्मता पर ही प्रश्न-चिह्न लगाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार क्रांतिकारी और रूपांतरणकारी शक्ति के रूप में इसके ऐतिहासिक मिशन को ही कम करके आँकते हैं।

हेनरी लिफेवर, जो एक फ्रांसीसी विद्वान् है, पूछते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी प्रारंभ के काल की श्रमिक वर्ग कितना क्रांतिकारी है और किन परिस्थितियों में वह सामाजिक व्यवहार की अपनी क्रांतिकारी सामर्थ्य एवं संभावना को कायम रखता है? अपने प्रश्न के उत्तर में वह यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान पूँजीवादी समाज के सामाजिक विखराव से उत्पन्न सामान्य सर्वहाराकरण के परिणामस्वरूप मजदूरवर्ग के साथ अन्य स्तर उभर आए हैं जिनका उसके साथ फोवोव निकाट का संबंध है। ये तत्त्व ऐसे हैं जो कुछ सुधारों को लागू करवाने के लिए काम करने को तैयार हैं, किन्तु बुनियादी क्रांतिकारी रूपांतरणों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

हेनरी लिफेवर जोर देकर कहते हैं—“वर्ग संघर्ष, जीवन और मृत्यु के संघर्ष के रूप में फिलहाल कम-से-कम हमारे औद्योगिक देशों में तो ग्रायब ही हो चुका है श्रमिक वर्ग के रूप में वहाँ अपेक्षाकृत ऐसा समरूप गुट है जो शोषण का प्रतिरोध करता है, तो भी उसमें कुछ दकियानूसी प्रवृत्तियाँ हैं जिससे वह अधिकतम रूपांतर का निषेध कर देता है अर्थात् समाज के मूलभूत रूपांतर को मना करता है।”¹

वूजर्वा सिद्धांतकार और सुधारवादी मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका को उपेक्षित करने की कितनी भी चालाकीभरी कोशिशें क्यों न करें, वे इस अकाट्य तथ्य को छिपा नहीं सकते कि पूँजीवादी दुनिया में समकालीन सर्वहारा उत्पादन के साधनों से बेगानापन अनुभव करता है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भागीदारी से वंचित कर दिया जाता है : कि वह केवल अपनी श्रम शक्ति को बेच कर ही जीता है। दूसरे शब्दों में, यह अब भी निस्संदेह पूँजीवाद का मुख्य दुश्मन है

1. जॉन कॅनेथ गालब्रेथ, 'द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट' पृ० 263

2. 'ल' होम एट सा सोसाइटी, पेरिस, 1971, अंक 21 पृष्ठ 154

और ऐसा कोई प्रसंग नहीं दिखाई देता कि पश्चिम में मजदूर की जिन्दगी के भौतिक स्तर में हाल ही में कोई ऐसा सुधार हुआ हो जो इसके विपरीत किसी बात को सिद्ध करता हो। कुछ औद्योगिक देशों में मजदूरों की भौतिक और जीवन संबंधी परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, मजदूरों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में कोई फ़र्क नहीं, तथा कोई भी शब्दजाल इस मूल वस्तुतक को नहीं काट सकता कि हमारे इस युग में भी किराए का मजदूर शोषित वर्ग ही है जो पूँजीपति वर्ग के लिए अपने श्रम से अतिरिक्त मूल्य का निर्माण करता है। विकास के द्वारा प्रदत्त अवसरों और मजदूरों के जीवन स्तर के बीच का अंतर बढ़ रहा है। कभी-कभी मजदूर इस खाई को पाटने का प्रयास करते हैं, किंतु जब तक आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति के साधन इजारेदारियों और बूर्ज्वा राज्य के हाथों में हैं, तब तक सर्वहारा वर्ग के काम के हासात बुनियादी तौर पर वही रहते हैं। एक पूँजीवादी देश में मजदूर केवल यही कर सकता है कि वह उन अधिक अनुकूल परिस्थितियों के लिए लड़े जिनके अधीन, जैसे मार्क्स ने कहा है कि उसे "पूँजीपति की दौलत बढ़ाने, पूँजी की शक्ति का विस्तार करने," की छूट दी जाती है तथा उन सुनहरी जंजीरों को घड़ने की छूट दी जाती है जिनका प्रयोग करके बूर्ज्वा वर्ग उसे अपने साथ रहने पर विवश करता है।"¹

पूँजीवादी उत्पादक शक्तियों में हाल के दशकों में जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं अर्थात् वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति और राज्य-इजारेदारी पूँजीवाद का मजबूत होना—उन्होंने किराये के मजदूरों की स्थिति में कोई बुनियादी सुधार नहीं किया। इसके विपरीत, इनसे मजदूर वर्ग का शोषण और बढ़ता ही है: वे मजदूरों की संख्या में वृद्धि, असह्य मानसिक तनावों तथा बढ़ती हुई व्यावसायिक दुर्घटनाओं के भी कारक बनते हैं। इन सब तथ्यों के आलोक में एक निष्पक्ष प्रेक्षक 'वर्ग शान्ति' और 'सामाजिक भागीदारी' की जोर-शोर से विज्ञापित धारणाओं पर बहुत ही कम भरोसा करता है।

पूँजीवादी देशों में आधुनिक सर्वहारा, आर्थिक एवं राजनैतिक संघर्ष के समूचे मोर्चे पर इजारेदारी पूँजीवाद के विरुद्ध खड़ा है। वैचारिक क्षेत्र में भी वह समाजवादी मार्ग का अनुसरण करने और वैज्ञानिक कम्युनिज्म के कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए संकल्पबद्ध दिखता है। इसका प्रमाण है मजदूर वर्ग की मार्क्सवादी-लेनिनवादी हिरावल—कम्युनिस्ट पार्टियों—का विकास, उनकी बढ़ती हुई सदस्यता और जनसमूह में उसकी पैठ और कुल मिलाकर विश्व-कम्युनिस्ट आंदोलन का विस्तार।

अक्टूबर क्रांति से पहले, रूस को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का आंदोलन लगभग अविच्छिन्न रूप से सुधारवादी सामाजिक जनवादियों द्वारा नियंत्रित

या जो उसे अवसरवाद के रास्ते पर धकेलते चले जा रहे थे। सोवियत क्रांति की विजय और सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण और कॉमिंटर्न की स्थापना ने दुनिया की क्रांतिकारी शक्तियों की सक्रियता को अत्यधिक तेजी से बढ़ावा दिया और बहुत से देशों में लड़ाकू मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियों के निर्माण को प्रेरित किया। सन् 1919 की कॉमिंटर्न की प्रथम कांग्रेस में 30 देशों के कम्युनिस्ट संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और सन् 1935 में सातवीं कांग्रेस में 75 कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन पार्टियों की कुल सदस्य संख्या 30 लाख से अधिक थी।

विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में फासिज्म के खिलाफ कड़े संघर्ष में तथा बाद में शीत युद्ध के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण जीतें हासिल की। हाल के वर्षों में इन्होंने विकास के और भी उन्नत स्तर को प्राप्त कर लिया है। उन वर्षों के कुछ परिणामों का मूल्यांकन करते हुए अक्टूबर सन् 1976 में हुए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के महाधिवेशन में लियोनिद ब्रेझ्नेव ने रेखांकित किया कि कड़े वर्गीय-संघर्षों में अनेक पूँजीवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने बहुत बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं। उन्होंने अपने सामाजिक आधार को व्यापक किया है और अपने सम्मान को सुदृढ़ किया है, राजनैतिक जीवन में उनका असर बढ़ा है। आज छः बड़े पूँजीवादी देशों में से तीन—फ्रांस, इटली और जापान में व्यापक आधार वाली कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं जिनको 200 लाख से अधिक मत-दाता मत देने हैं। पिछले चुनावों के परिणामस्वरूप इटली की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसी स्थिति बना ली कि व्यवहारतः उस देश में कोई भी बड़ा प्रश्न उसकी भागी-दारी के बिना हल नहीं किया जा सकता। फ्रांस में यह सामान्य मान्यता है कि कम्युनिस्टों की सोशलिस्टों और दूसरी वामपंथी ताकतों के साथ मित्रता देश के राजनैतिक जीवन की एक बजनदार हकीकत है...। भारत, फिनलैंड, डेनमार्क और कुछ लैटिन अमरीकी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने देशों में समुचित राजनैतिक प्रभाव रखती हैं।”¹

आज दुनिया में कोई भी ऐसा वैचारिक और राजनैतिक आंदोलन नहीं है जो कम्युनिस्ट आंदोलन की तुलना में जनसमूह से अधिक जुड़ा हुआ हो और जिसके अधिक समर्थक हों। बहुत से देशों में बड़े जनसमूहों के द्वारा इसकी विचारधारा को स्वीकार कर लिया गया है और दुनिया की विचारधारा और राजनीति पर इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है।

वर्तमान समाजवाद के वास्तविक अनुभव को आधार बनाकर दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन ने ऐसी महत्वपूर्ण विशिष्टताएँ अर्जित की हैं जो कि विचार-

1. एल. आई ब्रेझ्नेव, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की प्लेनरी मीटिंग में दिया गया भाषण, मॉस्को, 1976, पृष्ठ 52

धारात्मक एवं राजनीतिक क्षेत्र में इसके लक्ष्यों को व्यापक बनाती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि सामान्य लोकतांत्रिक संघर्ष में कम्युनिस्ट हिराबल दस्ते की विजयी नेतृत्वकारी भूमिका का सवाल जो स्वभावतः वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों के साथ घुल-मिल जाता है—न केवल मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु मजदूर वर्ग के दूसरे समूहों के आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के साथ भी अपने सपकों को मजबूत करना पड़ता है, और इसका अर्थ यह होता है कि विकासमान देशों में उनकी नेतृत्वकारी क्रांतिकारी शक्तियों में वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को फैलाना आवश्यक है।

ये दोनों बिन्दु किसी तरह के अस्थायी कारणों के साथ संबंधित नहीं हैं जो कल आसानी से बदल सकते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत समकालीन पूँजीवादी विकास के समूचे दौर में उभरकर सामने आये हैं—वह भी इसकी औपनिवेशिक प्रणाली के संकट के कारण। इससे भी और अधिक, वे एक ऐसी आवश्यकता के रूप में हैं जो राज्य-इजारेदारी पूँजीवाद की बढ़ती हुई परोपजीविता तथा वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के बढ़ते हुए संवेग के द्वारा आदेशित होते हैं, जोकि इजारेदारी शासन के अधीन व्यापक पैमाने पर सामाजिक विरोधों के पुनरुत्पादन की ओर ले जाती है, और वह भी पहले से अधिक तीव्रता के साथ। सन् 1969 में कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में यह नोट किया गया—“यह केवल पूँजी और श्रम के विरोध का विकास ही नहीं है, अपितु राष्ट्र के विशाल बहुमत के हितों और द्वितीय अल्पसंख्यक के हितों के बीच के गहराते हुए शत्रुतापूर्ण विरोधों का विकास भी है।”¹ व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इस पर मार्क्सवादी-लेनिनवादी जो जवाब देते हैं वे व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होते हैं। यह एक तथ्य है कि ‘मुनाफों में क्रांति’ और ‘सामाजिक भागीदारी’ के विषय में सारी बातों के बावजूद पूँजीवादी शोषण बढ़ रहा है। श्रमिकों के वेतन इजारेदारियों के मुनाफों की दर की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और उत्पादन में वृद्धि और श्रम के विशदीकरण से बहुत पीछे रह जाते हैं तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं। छोटे किसानों की स्थिति लगातार गिरती जाती है और मध्यम स्तर के जीवन की परिस्थितियाँ और अधिक कठिन होती जाती हैं।

टट्पूँजिया और बुद्धिजीवी : वे कहाँ से संबंधित हैं ?

गैर-समाजवादी देशों की आवादी के विशाल बहुमत का दैनिक जीवन इजारेदारी शासन के अधिकाधिक अविचल विरोध में खड़ा हो रहा है और यह परिस्थिति

अत्यधिक विचारपूर्वक अपनाए गए साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के सामाजिक आधार को व्यापक बनाती है। परिणामस्वरूप गैर-सर्वहारा आवादी के अधिक जन-समूहों में एकजुटता कायम करने की प्रवृत्ति तैयार की जाती है, इसमें मजदूर वर्ग के इर्द-गिर्द हैं—किसान, शहरी टट्पुंजिया, कार्यालयी कर्मचारी, बुद्धिजीवी आदि सम्मिलित होते हैं। ये हिस्से असली लोकतांत्रिक मांगों के लिए और अंततः समाजवाद के लिए इजारेदारी के दमन के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के स्वाभाविक मित्र बनते हैं।

पूँजीवादी देशों में आधादी का एक भाग जो सामान्यतया मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है—एक बहुत ही पंचमेल जनसमूह है। कारीगर और छोटे व्यापारी, कार्यालयी कर्मचारी, बुद्धिजीवी और अन्य पेशेवर लोग पूँजीवादी समाज में दोनों तरह से अर्थात् सामाजिक संरचना तथा उत्पादन अत्यंत और राजनीतिक जीवन में—भिन्न-भिन्न स्थानों पर अधिकार रखते हैं। कुछ के पास पूँजी की निश्चित राशि है, दूसरों के पास अपनी मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है जो उनकी आजीविका का साधन बन सके। कुछ विशाल एवं सघु उत्पादन से जुड़े हुए हैं, तो दूसरे उत्पादन क्षेत्र में नियुक्त ही नहीं हैं। निष्कर्षतः कुछ तो भौतिक साधनों से संपन्न हैं, जबकि दूसरे, सरल भाषा में कहा जाय तो गरीबी से प्रताड़ित हैं। इन समूहों के सामाजिक और राजनीतिक हित, और इसलिए उनकी विचारात्मक अभिवृत्तियाँ, तदनुसार अस्थिर और प्रायः विरोधपूर्ण होती हैं।

किसान, दस्तकार और छोटे व्यापारी, जो टट्पुंजियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, का अतीत उन्हें पूँजीवाद से जोड़ता है, जबकि उनका भविष्य उन्हें निस्संदेह सर्वहारा की तरफ खींचता है। वे बड़े व्यापार के विरुद्ध असमान और कठिन संघर्ष छेड़ते हैं, किन्तु 'न्यून-माल-उत्पादन के खंड' होने के कारण वे अवसर अपने पुराने दृष्टिकोण के अनुरूप ही कार्य करते हैं। स्वतंत्र उद्योग के 'सुनहरे अतीत' के प्रति उनका विरह भाव तथा अपनी क्षणिक स्वाधीनता—जो यथार्थ में काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है—को सुरक्षित रखने का उनका अटल संकल्प उन्हें समाजवादी विचारों को अपनाने से रोकते है। दूसरी ओर, पूँजीवादी विश्व का यथार्थ निर्दयता पूर्वक इन भ्रातियों के टुकड़े कर देता है और उनको इजारेदार-विरोधी मोर्चे की कतारों में सा खड़ा करता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व इन सामाजिक समूहों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिक्रियावादी पार्टियों का प्रायः फ़ासिस्ट दिमाग वाले जनोत्तेजकों का अनुसरण करता था तथा दक्षिण-पंथी बूर्ज्वा प्रवृत्तियों का सामाजिक आधार निर्मित करता था। समाजवाद के पक्ष में ऐतिहासिक परिवर्तनों, पूँजीवादी प्रणाली के सामान्य संकट को गहराने और इजारेदारी प्रतिक्रियावाद के और अधिक दक्षिणपंथी समूहों के निन्दनीय पतन की स्थिति में पहुँचने के कारण, उन्होंने अपनी विचारधारात्मक अभि-

मुखता को वास्तव में सशोधित कर लिया ।

सन् 1950 और 1960 के दशकों में टट्पुंजिया तबके ने अपने सबसे अधिक हलके में वृज्वा प्रचार के सभी प्रकार के उदारतावादी विचारों के लिए भूमिका का निर्माण किया । हाल के सालों में, खासतौर से 1974-75 के संकट के संवध में, ऐसे सकेत मिले हैं कि उनका झुकाव वापस कम्युनिस्ट-आन्दोलन की तरफ हो गया है और वैज्ञानिक समाजवाद में उनकी रुचि बढ़ गई है ।

निस्संदेह, यह परिवर्तन आसानी से संपन्न नहीं हुआ । पूंजीवादी संबंधों और परंपराओं के बोझ के दबे हुए टट्पुंजिया तबके के प्रतिनिधि प्रायः वैचारिक संघर्ष के क्षेत्र में सुधारवादी, उग्र वामपंथी, अराजकतावादी या अन्य अवैज्ञानिक दृष्टि-कोण ले आते हैं । पूंजीवाद की उनकी आलोचना अवसर एकागी एवं अस्थिर होती है तथा समाजवादी विचारों की स्वीकृति सभी प्रकार की उदार वृज्वा प्रतिबद्धों से बंधी हुई होती है ।

मध्यम वर्गों के विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच न तो सीधे समुदाय के हित और न ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क होते हैं और न ही वे किसी एक ही वर्ग संगठन के साथ एकताबद्ध होते हैं । इसलिए, मार्क्स के कथन के अनुसार "वे अपने वर्ग हितों को अपने ही नाम से सबल अभिव्यक्ति नहीं दे सकते ।"¹ बहुत-सी बातों में उनकी स्थिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग शक्तियों के सहसंबंध पर निर्भर करती है तथा मजदूर वर्ग और विश्व समाजवाद के प्रभाव पर आधारित होती है ।

फिर भी, जैसे कि सन् 1969 की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की अंतर-राष्ट्रीय बैठक में नोट किया गया—"उनमें एकता की कमी और पूंजीवादी विचार-धारा के प्रति विशेष भावुकता के बावजूद, मध्यमवर्ग का विशाल जनसमूह अपने हितों की रक्षा करने के लिए आगे आ रहा है, सामान्य लोकतांत्रिक मांगों के लिए व्यापक संघर्ष में शामिल हो रहा है और मजदूर वर्ग के संपुक्त संघर्ष के बहुत बड़े महत्व के प्रति तेजी से सचेत हो रहा है ।"²(जोर लेखक का)³

एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे समय में पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग के मुख्य दोस्त केवल मध्य स्तरीय लोग (सामाजिक दृष्टि से, किसी न किसी रूप में अभिजात्य वर्ग से संबद्ध) ही नहीं हैं, अपितु किराये के मजदूरों के बढ़ते हुए जनसमूह के प्रतिनिधि भी हैं, जिनका प्रायः पूंजीपति के साथ कोई वर्गीय संबंध नहीं होता ।

बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा से मजदूर वर्ग का काफ़ी भरोसेमंद और शक्तिशाली

1. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, 'घयनिष्ठ रचनाएँ' तीन खंडों में, खंड-1 पृ० 479

2. कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक, माँस्को, 1969 पृ० 25

दोस्त है, और रहा है। वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रांति के आगे के विकास की दृष्टि से सामान्यतया उत्पादन प्रक्रिया में यह एक बहुत प्रभावशाली शक्ति है, विशेषतौर पर सामाजिक जीवन में तो और भी अधिक। राज्य-इजारेदार पूंजीवाद बुद्धिजीवी वर्ग का समूहों में बाँटने के प्रति अपना उत्साह एवं संकल्प प्रदर्शित कर रहा है, इजारेदार पूंजी के आधिपत्य के खिलाफ संघर्ष के दौरान उनका बहुमत मजदूर वर्ग और सामाजिक क्षेत्र में उसके आदर्शों की तरफ खिंच जाता है।

आज बुद्धिजीवियों का बड़ा भाग उन कर्मचारियों से भरा पड़ा है जिनका अनिवार्यतः उत्पादन के साधनों पर कोई स्वामित्व नहीं है। वे सरकारी अधिकारी हैं, इजारेदार-निगमों और निजी फर्मों के कर्मचारी हैं, इंजीनियर और तकनीशियन तथा पेशेवर लोग हैं। हमारी दृष्टि से इन समूहों के सामाजिक कार्य और संपत्ति की दृष्टि से इनकी हैसियत एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। यह तथ्य कि उनका बड़ा भाग सरकारी विभागों में नियुक्त है या निजी उद्योगों में प्रशासक के रूप में कार्यरत है उन्हें विचारधारात्मक दृष्टि से बूज्वा वर्ग निकट लाता है। इसका उन सफेदपोशों पर प्रभाव पड़ता है तथा वे मार्क्सवादी विचारधारा को आत्मसात् कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण जो आबादी की इन श्रेणियों से संबंधित होते हैं—वे मजदूर वर्ग के घनिष्ठ संपर्क में आते हैं।

कार्यालय कर्मचारियों का बड़ा भाग, इंजीनियर और तकनीशियन और पेशेवर लोग मजदूर परिवारों से आते हैं और अपनी आजीविका अपने ही थम से कमाते हैं। वेतन-भोगी होने के कारण वे स्वभावतः बड़े पूंजीपति के द्वारा शोषित होते हैं। उनका जीवन स्तर कुशल मजदूर से कुछ ही भिन्न होता है और कभी-कभी तो नीचे भी चला जाता है। उनकी स्थिति अतिशय अस्थिर होती है और पूरी तरह पूंजीवादी देशों की आधिक्यताओं के उतार-चढ़ाव पर आधारित होती है, अक्सर मालिक की सनक पर भी निर्भर करती है।

इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो दशकों में, जबकि इजारेदार पूंजी ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की मलाई को हड़पने का बंदोबस्त कर लिया था, इन समूहों का भौतिक स्तर कभीबेश स्थिर था। उसी समय बूज्वा प्रचारतंत्र ने सफेदपोशों के पक्ष में 'मुनाफों के वितरण में इंकलाब' की गुहार लगाना प्रारंभ कर दिया, तो भी यह एक खुला रहस्य है कि ज्यों ही पूंजीवादी देशों ने 1970 के दशक के मोड़ पर आर्थिक विकास की दर में कुछ गिरावट तथा मुद्रा और मुद्रास्फीति की कठिनाइयों का अनुभव किया, तो सफेदपोश भी मजदूर वर्ग के इन परिवर्तनों के शिकार हो गये। 1974-75 के संकट ने इस बात का मान्य सख्त पेश किया कि पूंजीवादी देशों में यही तलवार बुद्धिजीवी तबके पर भी स्यांसी तीर पर लटकने लगी है।

राजनैतिक प्रतिक्रियावाद का विशदीकरण, सामाजिक जीवन का नैतिक एवं बौद्धिक पतन और बूज्वा सस्कृति का गंभीर संकट आदि ऐसे बिन्दु हैं जो बुद्धिजीवी तबके को पूंजीवाद के सामाजिक विकल्प पर अधिक गहराई से सोचने को मजबूर करते हैं। यह परिस्थिति उन्हें समाजवादी विश्व दृष्टिकोण को आत्मसात करने की ओर ले जाती है। 1960 के दशक के आखिर के अत्यंत व्यापक एवं उग्र छात्र संघर्ष (अर्थात् भावी सफेदपोशों का संघर्ष) पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध बुद्धि-जीवियों के उभरते हुए विरोध का प्रथम भयंकर आभास था।

ऐसे समय जब इजारेदार पूंजीवाद सिर्फ अपना आकार ही ग्रहण कर रहा था, लेनिन को यह पूर्वाभास हो गया था कि इसके विकास का लक्षण दो विरोधी प्रक्रियाएँ होंगी अर्थात् एक तरफ बुद्धिजीवी समूह का सर्वहाराकरण तथा दूसरी ओर मजदूर वर्ग का बौद्धिकीकरण।¹ गत कई दशकों में, और खासतौर से वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति के बाद, पूंजीवाद ने लगभग पूरी तरह से बुद्धिजीवी को उसके स्वतंत्र स्तर से वंचित कर दिया है और उसे श्रम-बाजार की सभी सनक भरी स्थितियों का शिकार बना कर एक साधारण वेतन भोगी के रूप में बदल कर रख दिया है। यह दरअसल बुद्धिजीवियों के बड़े समूह का सर्वहाराकरण था जो ताजा शक्ति के साथ खुलकर सामने आया। साथ ही एक जैसे कारणों की वजह से शारीरिक और गैर-शारीरिक श्रम के बीच एक ध्यान देने योग्य अभिमुखता भी उभरकर सामने आयी है। शिक्षास्तर में विचारणीय सुधार हुआ है और मजदूरों की कुशलता के बढ़ने से उनका बौद्धिकीकरण हुआ है। इंजीनियर, तकनीशियन और कुशल मजदूर के बीच का भेदभाव आधुनिक बड़े औद्योगिक संस्थान में बहुत घट गया है। निस्संदेह वे, अपने भौतिक स्तर, श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक व्यय और श्रम के प्रकृति के अनुरूप ही इकट्ठा हुए हैं।

इस नयी वास्तविकता के जवाब में बूज्वा सिद्धांतकार भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो बुद्धिजीवी तबके को मजदूर वर्ग से अलग किया जाये तथा सफ़ेद कालर वाले बुद्धिजीवियों और नीली कॉलर वाले श्रमिक वर्ग के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाये।

डेनियल बेल और अन्य समान विचार के लोगों ने, उदाहरण के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह प्रस्तावित किया कि समाज में व्यावसायिकों और तकनीशियनों के रूप में जो बुद्धिजीवी तबका है उसकी भूमिका को ऊपर उठा दिया जाये तथा सम्मान दिया जाये। एक नये वर्ग के रूप में यह बुद्धिवर्ग मानवता के मसीहा की भूमिका अदा करने को था। वास्तव में नेतृत्व का यह रास्ता इस

1. देखिए : बी० आई० लेनिन, 'रिष्यु काल कौटुंबी, वनस्टोन अंड हास सोवियल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, इन एंटी-मिंटिक' सङ्कलित रचनाएँ, खंड 4, पृ० 202 'रिवोल्यूशनरी एडवेंचरिज्म', सङ्कलित रचनाएँ, खंड 6, पृ० 198

प्रकार की 'गुणशाही' को आत्म-असमाव की तरफ ही ले जा सकता था और इसे बड़े व्यापार की निर्भरता से मुक्त नहीं कर सकता था।

शोधकर्ता और इंजीनियर तथा सामान्यतया बुद्धिजीवी तबक़े का समुदाय कुल मिलाकर बेतनभोगी लोगों की किस्मे ही होती है। फलस्वरूप सफेदपोशों का सारा समूह इजारेदारियों के विरुद्ध अपना आधार कायम रखेगा और अपने अधिकारों के लिए एक व्यापक लोकतांत्रिक मोर्चे के चौखटे में ही लड़ेगा।

लोकतांत्रिक बहुमत और इजारेदार पूँजी के बीच जारी विद्वेष एवं विरोध में अत्यंत व्यापक समस्याएँ निहित होती हैं। उनके अंतर्विरोध न केवल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक ही फैले हुए होते हैं, अपितु संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा आदि के दायरे में भी फैल जाते हैं। इसी कारण मुक्ति आंदोलन की लोकतांत्रिक और समाजवादी अवस्थाओं के बीच आगे के पुनर्मेल की अनिवार्य प्रवृत्तियाँ सामने दिखाई देने लगती हैं। यद्यपि चरित्र, लक्ष्यों और प्रेरणाओं की भिन्नता के बावजूद वे एक-दूसरे से गुथे हुए होते हैं और एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। प्रत्येक देश में, सबसे पहले बुद्धिजीवियों के मध्य घास विचारधारारत्मक घटनाक्रियाएँ होती हैं—जिनकी विषयवस्तु अंतर्राष्ट्रीय होती है तो जिनका आकार राष्ट्रीय—जो कि इजारेदारी आधिपत्य को लक्ष्य करती है। सब बातों में वह चाहे, सामान्य लोकतांत्रिक समस्याओं का समाधान हो या समाजवादी रूप परिवर्तनों का—वे अनिवार्यतः सर्वहारा और पूँजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष के मोर्चे को व्यापक बनाते हैं और राजनैतिक दृष्टि से, मजदूर जन-समूह को मार्क्सवादी, लेनिनवादी कार्यक्रम अपनाते की ओर ले जाते हैं।

नवउपनिवेशवाद के खिलाफ, इजारेदारी-विरोधी सहमेल के लिए

लोकतांत्रिक और समाजवादी उद्देश्य अधिकाधिक घनिष्ठता के साथ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के क्षेत्र में आपस में अंतर्ग्रथित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि दमन और हिंसा की विश्व साम्राज्यवादी प्रणाली ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की समस्याओं को अविभाज्य बना दिया है।

राजनीतिक स्वाधीनता हासिल कर लेने के बाद पुराने उपनिवेशों ने सामंती संबंधों (कुछ बातों में पूर्व सामंती संबंधों) को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति गंभीर सजगता प्रदर्शित की। यह भी नितांत आवश्यक था कि ऐसे अनेक रूपांतरण किये जाएँ जो 18वीं और 19वीं सदियों में पूँजीवादी जनतांत्रिक, क्रांतियों के दौरान यूरोपीय जनगण ने किये थे। लेकिन हमारे समय का सामाजिक विकास एक विलुप्त नयी ऐतिहासिक परिस्थिति में घटित हो रहा है, जनगण की आँखों में पूँजीवाद का सम्मान समाप्त हो चुका है, और विश्व प्रक्रिया में समाजवाद एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है—यह संघर्ष एक नयी अंतर्वस्तु और नयी

आकृतियाँ ग्रहण कर रहा है।

पहले की बूज्वा जनतांत्रिक क्रांतियों ने केवल पूँजीवाद को मजबूत बनाया जबकि आज के राष्ट्रीय आंदोलन चाहे वे बूज्वा-जनतांत्रिक रूपांतरणों की सीमाओं में ही क्यों न हों, अनिवार्यतः साम्राज्यवाद पर चोट मारते हैं। यूरोप में बूज्वा-जनतांत्रिक क्रांतियाँ मुख्यतया घरेलू प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध ही निर्देशित थी अर्थात् सामंती प्रभुओं तथा सामंती और महाराजाओं की तानाशाही के विरुद्ध थी। आज के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन स्पष्टतया साम्राज्यवाद और उसकी अन्दरूनी ताकतों—जो कार्यक्रम की दृष्टि से एक दूसरे में सम्यद्ध है—के विरुद्ध निर्देशित है। अपने बलासिकी स्वरूप में, बूज्वा जनतांत्रिक क्रांतियों ने स्वभावतः मोटे तौर पर भी कभी यह संकेत तक नहीं दिया कि समाजवादी रूपांतरणों की संभावना है। समसामयिक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियाँ या तो सीधे तौर पर समाजवादी निर्माण के रास्ते की ओर ले जाती हैं, या अपनी समाजवाद की ओर अभिमुखता की घोषणा कर देती है, और कुछ मामलों में तो जिस किसी तरह समाजवादी उद्देश्यों को लेकर सभी अवधि के कार्यक्रमों की ओर अपने आपको मोड़ देती है। जब तक कि रास्ते का अंतिम चुनाव नहीं हो जाता—कि आगे का सामाजिक-राजनैतिक विकास किस तरह का हो—और जब तक वर्ग शत्रुताएँ नवस्वतंत्र देशों में कायम रहती हैं तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियाँ शक्तिशाली नव-उपनिवेशवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों से—अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद, व्याप्त कंप्राडोर बूज्वा वर्ग और सामंती प्रभुओं से प्रभावित होती रहेगी ! कुल मिलाकर ये क्षेत्र सबसे तीखे संघर्ष का अखाड़ा बने रहेंगे। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की अवधि में जो साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा बनता है वह विभिन्न वर्ग-शक्तियों को एकजुट कर देता है जिससे उन देशों में जहाँ बुनियादी सामाजिक समस्याएँ अब भी जलझी हुई हैं, विचारधारात्मक संघर्षों की तीव्रता अनिवार्य हो जाती है।

क्योंकि मजदूर वर्ग एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में उभर आया है समूचे आंदोलन को समाजवाद की ओर मोड़ दे सकता है और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को क्रमशः सुदृढ़ कर सकता है। किन्तु राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बहुत से देशों में यह वर्ग अभी भी छोटा है और उसके पास राजनैतिक संघर्ष के आवश्यक अनुभव का अभाव है। इन देशों में किसानों का जनसमूह, जो आवादी का बहुत बड़ा भाग है, सगठनात्मक दृष्टि से विभाजित है तथा अधिकांश देशों में वे राष्ट्रीय बूज्वा वर्ग का अनुसरण करते हैं जिसकी कि वाक्यादा दुहरी भूमिका होती है; एक तरफ़ वह साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंतवाद विरोधी क्रांति को पूरा करने के लिए वास्तव में आतुर होता है तो दूसरी ओर साम्राज्यवादियों और सामंती प्रभुओं से सहमेल और समझौता करने में भी लगा रहता है।

अभी तक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन मात्र अपनी शक्तियों को तैनात कर रहा है तथा अपनी बढ़ती हुई संभावना-सामर्थ्य को उद्घाटित कर रहा है। विकासमान देशों को अपनी आर्थिक स्वाधीनता हासिल करने का सबसे कठिन काम अभी भी पूरा करना है। जब साम्राज्यवादी शक्तियों को परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं कि वे नवस्वतंत्र देशों की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें तो, अनुभव बताता है कि, वे शक्तियाँ फुर्ती में ऐसे उपाय करती हैं जिनसे कि पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था नवऔपनिवेशिक प्रणाली के रूप में वापस कायम हो जाये। 'सहयोग' के प्रत्यक्षतः सम्मानजनक स्वरूप के अधीन यह प्रणाली उपनिवेशवादी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के जनगण के शोषण और लूट को जारी रखने में सहायक हो सकती है। अतः, यह स्पष्ट है कि अंततः विकासमान देशों का आर्थिक स्वतन्त्रता का आंदोलन समाजवाद की ओर अभिमुख होने के निर्णय पर ही अनिवार्य रूप से निर्भर करता है क्योंकि उसी में उनके अधिकारों की समानता सन्निहित होती है।

आर्थिक क्षेत्र में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के नये दौर की यही दिशा होगी। सारी संभावना यह है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश ऐसे व्यावहारिक कदम उठाएँगे ताकि साम्राज्यवादी आर्थिक प्रणाली से उनके संबंध टूट जाएँ। निश्चित रूप से यह सबसे कठिन लड़ाई होगी और इसके लिए यह एक जटिल दौर भी होगा क्योंकि यह सीधे तौर पर विदेशी आधिपत्य के आधार स्तंभों पर प्रभाव डालता है तथा वह उन जड़ों पर चोट करता है जिन पर कि इन देशों के राष्ट्रीय संसाधनों की लूट करने वाली साम्राज्यवादी प्रणाली खड़ी हुई है।

विकासशील देशों में करोड़ों लोगों को समाजवाद में संक्रमण जैसे महान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जरूरी है कि समाजवादी व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग—राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में सलग देशों के संदर्भ में ये दोनों ही शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्ति आंदोलन का हिराबल दस्ता हैं—की घनिष्ठता कायम हो।

यही कारण है कि साम्राज्यवाद के सिद्धांतकार और उनके टटपुंजिया पिछलग्गू इस सैन्नी पर हमला करते हैं। एक समय था जब बूर्ज्वा प्रचारतंत्र यह मानता था कि सामान्यतया औपनिवेशिक देशों में मुक्ति आंदोलन की अपनी सामाजिक जड़ें नहीं हैं और वे बाहर से 'कम्युनिस्ट पड़यंत्रों' के द्वारा पैदा की गयी है। उसके बाद वे एक बिल्कुल अलग सिद्धांत की ओर धूम गये, अर्थात् मुक्ति आंदोलन को एक भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और जातीय अनन्यता के गुण से मंडित बताने लगे। वे यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि न तो समाजवाद का और न ही पूँजीवादी देशों के मजदूर वर्ग का इससे कोई सरोकार है। तथापि समकालीन

वर्ग शक्तियों के वास्तविक सामान्य सहमेल में, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन शांति, जनतंत्र और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग एवं समाजवाद का शक्तिशाली दोस्त होता है।

शस्त्ररहित शांतिमय मार्ग.....

अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने सार्वभौम आयाम प्राप्त कर लिये है; यह अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और हर जगह सचमुच ऐतिहासिक महत्व के रूप परिवर्तनों के अवसर तैयार कर रहा है। सब महाद्वीपों में, यह आंदोलन वहाँ के विशाल जनसमुदाय को—जो वर्गीय विकास की असंग-अलग अवस्थाओं में है तथा विभिन्न सामाजिक स्तरों से निर्मित है—क्रांतिकारी प्रक्रिया में खींच रहा है। दुनिया भर का जनसमूह उस सक्रिय राजनैतिक जीवन के प्रति अधिकाधिक चेतना संपन्न हो रहा है, जो समाजवाद और कम्युनिज्म के रूपांतरण की ओर अत्यधिक तीव्रगति से बढ़ता चला जा रहा है।

फिर भी, यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया इस राजनैतिक संघर्ष के भँवर में ऐसे बहुत से लोगों को भी खींच ले जाती है, जो अभी अभिजात्य प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं और अपने साथ मुक्ति आंदोलन में दकियानूसी दृष्टि-कोणों, भ्रातियों और मध्यम वर्गीय दुस्सुलपन को भी ले आते हैं। प्रायः एकदम विपरीत, सामाजिक दृष्टि से पंचमेल शक्तियाँ साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ती हैं, तथा समाजवाद को अपना चरम लक्ष्य घोषित करके इस अवधारणा में अपने विचार ठूस देती हैं। कभी-कभी ये विचार उनके आज के निजी संकीर्ण आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वार्थों के साथ मेल खाते हैं और साफतौर पर यही वह भूमि है जिस पर विभिन्न गैर-माक्सवादी सिद्धांत बड़ी लुभावनी अदा से पनपने लगते हैं।

कम्युनिस्टों के लिए इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। वेबल मताग्रही और संकीर्णतावादी ही यह आशा करते हैं कि जो जनसमूह अभी-अभी क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुआ है वह किसी तरह की मिथ्या 'विचारधारात्मक शुद्धता' का प्रदर्शन करे। वहरहाल, दृष्टिकोण का विकास संघर्ष के दौर में ही होता है, विभिन्न भ्रातिपूर्ण धारणाओं पर विजय तथा विरोधी विचारधारा से श्रमिक मुक्ति के परिणामस्वरूप ही संभव होता है।

लेनिन के मूल्यांकन इस बात को पुष्ट करते हैं—“समाजवादी क्राति... समस्त विविध प्रकार के दलितों और असंतुष्ट तत्वों के चहुँमुखी जनसमूह में जन आंदोलन के रूप में एक विस्फोट के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती। मध्यमवर्ग के अनेक हिस्से और पिछड़े हुए मजदूर इसमें अनिवार्यतः भाग लेंगे, क्योंकि बिना इस प्रकार की भागीदारी के जन संघर्ष अमंभव ही है और इसके

बिना कोई भी क्रांति संभव नहीं है और ठीक इसी तरह अनिवार्य रूप से वे आंदोलन में अपने साथ अपने पूर्वग्रहों को भी लाएंगे, अपनी प्रतिक्रियावादी ध्रात कल्पनाओं, अपनी कमजोरियों और गलतियों को भी साथ लाएंगे। किन्तु वस्तुगत रूप से वे पूँजी पर आक्रमण करेंगे, और क्रांति का वर्ग-सचेत हिराबल प्रगतिशील सर्वहारा वर्ग इस विविधरूपा, विशृंखलित, सतरंगे और बाहर से टुकड़ों में बँटे हुए उनके वस्तुसत्य को उसी रूप में अभिव्यक्त करते हुए इस जन-सघर्ष में उनको एकजुट करेगा और उनका दिशा निर्देश करेगा।”

आज यह निष्कर्ष आर्थिक, वैज्ञानिक और प्राविधिक कारकों, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं और आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की जटिल अंतः-क्रियाओं में ठोस रूप में प्रकट हो रहा है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों की बढ़ती हुई अंतःनिर्भरता दोनों तरह चाहे वह अलग-अलग देशों के रूप में हो या एक विश्व व्यापी स्तर पर—आधुनिक युग का प्रमुख लक्षण है। वैज्ञानिक, प्राविधिक और सामाजिक क्रांति की इस वर्तमान अवधि को, मजदूर वर्ग की मुक्ति और उनके जनतांत्रिक लक्ष्यों तथा साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की सामान्य धारा के सभी श्रमिक जनसमुदायों की घनिष्ठता के साथ गुथी हुई एकजुटता के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

ऐसे अनेक लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनके अनुसार पूँजीवादी प्रणाली फिल-हाल गंभीर और तेजी से महराते हुए सकट की गिरफ्त में है। इस पर काबू पाना आसान नहीं है तथा यह निष्पूरता से पूँजीवादी सामाजिक संबंधों को अंतिम रूप से ढह जाने की ओर ले जा रही है। इससे उबरने का कोई मार्ग निकलता न देख-कर पूँजीवाद के पक्षधर मानवता को सबसे अधिक दुसाहसिक कार्यों के लिए भड़काने की तैयारी करते हैं। फ्रांसीसी विद्वान ऐरिक मूरेज़ ने अपनी पुस्तक ‘टेस्टामेंट पोअर अन मांद प्र्यूवरे’ में मानवता की मरणासन्नता की रणताभरी निराशापूर्ण तस्वीर को चित्रित किया है। उसके अनुसार, वह या तो भूख की बजह से मृत्यु को प्राप्त होगी या परिस्थितिजन्य संकट से या ऊर्जा स्रोतों के सूख जाने से। मानवता को केवल एक ही वस्तु बचा सकती है और वह है युद्ध। उनकी मान्यता है—“काफ़ी विरोधाभास के बावजूद उपर्युक्त कारकों को, आणविक युद्ध की संभावित घटना ही प्रतिकारक औपधि की तरह संभाल सकती है। इससे न केवल प्राविधिक सम्यता के उपभोक्ताओं की संख्या में ही वास्तविक कमी होगी, उनका जीवन-स्तर ही नीचा न होगा और अस्त-व्यस्त वैज्ञानिक प्रगति ही बदनाम न होगी, अपितु ‘संतुलित’ विनिमय की शर्तों के अधीन यह जीवित प्रकृति का अपेक्षाकृत कम बिनाश करेगी, परिस्थिति वैज्ञानिक बंध्याकरण के परिणामस्वरूप

1. पी० आई० लेनिन, “आत्म-निर्धारण पर विवाद का उपसंहार” संकलित रचनाएँ,

होने वाले इसके विकास की तुलना में। इस तरह इससे औद्योगिक अवस्था से पूर्व की स्थितियों वाले युग में लौटना संभव हो पाएगा अथवा इन स्थितियों एवं नियंत्रित प्राविधिक की अवशिष्ट उपलब्धियों का संयोजन संभव हो पाएगा।¹

कम्युनिस्ट एकदम भिन्न विकल्प प्रस्तावित करते हैं। सन् 1976 के ग्रीष्म में बर्लिन (जी० डी० आर०) में यूरोप की 29 कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के दस्तावेज में टिप्पणी की गई कि—“पूँजीवादी समाज का आर्थिक और सामाजिक ढाँचा मजदूर वर्ग और सामान्य जनसमुदाय की आवश्यकताओं और सामाजिक प्रगति और जनतांत्रिक राजनैतिक विकास की जरूरतों के साथ अधिकाधिक असंगत होता जा रहा है। यूरोप के पूँजीवादी प्रभुत्व वाले हिस्से के मजदूर वर्ग और श्रमिक लोग संकट को हल करने का जनतांत्रिक समाधान प्राप्त करने के लिए सचपं कर रहे हैं जो व्यापक जनसमूह के हितों से अनुरूप होगा और समाज के समाजवादी रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।”²

अतः मजदूर वर्ग शांतिपूर्ण तरीकों के द्वारा जनतांत्रिक समाधान के पक्ष में है। क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। वैज्ञानिक कम्युनिज्म का सारा सिद्धांत मानवतावाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक आशावाद का सिद्धांत है जो हिंसा—पूँजीवादी हिंसा के विरुद्ध मजदूर वर्ग की आत्मरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो जाए तो दूसरी बात है—को अस्वीकार करता है।

इस संबंध में, समाजवादी संक्रमण के शांतिपूर्ण स्वरूपों के प्रश्न से जुड़े हुए तरीकों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अपने समय में मार्क्स का विश्वास था कि एक “समाज का संक्रमणकालीन राज्य” हो सकता है जिसके अंतर्गत “एक ओर मौजूदा आर्थिक आधार अभी रूपांतरित नहीं हो पाया है, तथा दूसरी ओर श्रमिक जनसमूह ने पर्याप्त शक्ति इकट्ठी कर ली है कि वह संक्रमण काल के उपायों—जो कि अंतिम विश्लेषण में बुनियादी पुनर्गठन को संभव बनाएंगे—के क्रियान्वयन को अपरिहार्य बना सके।”³

उनकी दृष्टि में इस प्रकार की घटना प्रवाह दूर की ही सही, संभावना अवश्य बना हुआ था। अब, पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की विश्वव्यापी परिस्थितियों के अंतर्गत तथा स्वयं पूँजीवादी विश्व में वर्ग-शक्तियों का एक भिन्न सहसंबंध उभरने की वजह से इस प्रकार का विकास वास्तविकता बन गया है। यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की बर्लिन कान्फ्रेंस में इस बात की ओर संकेत किया गया—“साम्राज्यवाद की स्थिति, जिसने अपनी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वह शक्ति-संतुलन में उत्पन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप कमजोर हो चुकी है। यह बात इस तथ्य में व्यक्त होती है कि साम्राज्यवाद न तो समाज-

1. एरिक मूर्रेज, ‘टेस्टामेंट पोअर अन माद फ्यूचर’, पेरिस, 1971, पृ० 22

2. ‘यूरोप में शक्ति, सुरक्षा, सहयोग और सामाजिक प्रगति’, पृ० 38

3. मार्क्स-एंगेल्स, वर्क चट 16, पृ० 368-69

वाद की ऐतिहासिक उपलब्धियों को ही उलट सकता है, न ही प्रगतिशील ताकतों को बढ़ने से रोक सकता है और न ही लोगों के मुक्ति और स्वाधीनता के लिए संघर्षों पर ही उसका अंकुश लगा सकता है।”

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आज फ़िलहाल मजदूर वर्ग और सब मिलाकर इजारेदारी-विरोधी आंदोलन उस स्तर को प्राप्त कर चुका है जहाँ वह शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दरअसल, पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों ने अपने कार्यक्रमों में कुछ ऐसे आधार बिंदु तैयार किए हैं जैसे—इजारेदारी-विरोधी लोकतंत्र की मांगें, वामपंथी दलों की सामूहिक सरकारों का निर्माण और निःशस्त्रीकरण की नीति—जो समाजवाद के लिए उनके संघर्ष की अंतरिम अवस्थाएँ अथवा उसके संक्रमणकालीन रूप हैं।

निस्संदेह, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रूपांतरण के मार्ग का यह कतई अर्थ नहीं है कि वर्ग-संघर्ष के भेदे पड़ने का आरंभ हो रहा है। इसके विपरीत, पूँजीवाद के खिलाफ़ मजदूर वर्ग का स्थायी, सक्रिय और शक्तिशाली हमला भाग ही इस आंदोलन को गतिशील रख सकता है। यह इसलिए कि क्रांति मुधारों का योगफल नहीं होती और जहाँ तक वर्ग संघर्ष के मुख्य मुद्दे का प्रश्न है अर्थात् शक्ति हथियाने की समस्या या फलस्वरूप उत्पादन के साधनों पर कब्ज़ा करने का प्रश्न—जब तक इसका हल नहीं होता तब तक किसी भी प्रगतिशील प्राप्ति को स्थायी मान लेना असंभव है। इसलिए, क्रांति के शांतिमय रास्ते का अर्थ है कि प्रत्येक पूँजीवादी देश में और विश्व व्यापी पैमाने पर, दोनों रूपों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनतांत्रिक शक्तियों के राजनीतिक संघर्ष को धीमा न होने दिया। बल्कि और अधिक मजबूत और तेज़ किया जाय।

जहाँ तक इस समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पहलू का संबंध है यह आवश्यक हो जाता है कि युद्ध और प्रतिक्रियावाद की ताकतों का मुकाबला करने वाली जनतांत्रिक शक्तियों के विश्वव्यापी स्तर पर एक मोर्चा बनाया जाय, क्योंकि जैसा कि लेनिन ने कहा था—“जनतंत्र की सबसे अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति युद्ध और शांति के मूलभूत प्रश्न में निहित होती है।” और जब राष्ट्रीय स्तर पर जनतांत्रिक शक्तियाँ मजदूर वर्ग और उसके कम्युनिस्ट हिरावस की ओर उन्मुख हो जाती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समाजवादी समुदाय की ओर भी उन्मुख हो जाती हैं जिसका नेतृत्व सोवियत संघ—जो जनगण के बीच शांति और सहयोग के लिए किए जाने वाले संघर्ष की अग्रगामी शक्ति है—करता है।

1. 'यूरोप में शांति, सुरक्षा, सहयोग और सामाजिक प्रगति के लिए, पृ० 37

2. बी० आई० लेनिन “अखिल रूस केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सातवें कन्वोकेशन के प्रथम सत्र में प्रस्तुत अखिल रूस केन्द्रीय कार्य समिति और जन कमिस्तर परिषद् के कार्य-कलापों पर रिपोर्ट”, सक्तित रचनाएँ, खंड 30 पृ० 319

सामाजिक जीवन से युद्ध को निष्कासित करो

शांति : अतीत के विचारकों ने
जिस रूप में इसे देखा

विश्व इतिहास की समकालीन अवधि की समस्त आधारभूत समस्याओं में युद्ध और शांति की समस्या निश्चित रूप से सबसे अधिक तीव्र एवं प्रासंगिक है। यह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ बाँध लेती है, दो व्यवस्थाओं की मुठभेड़ के आधारों को उद्घाटित करती है, तथा बिना अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है, कि यह सारी मानवजाति के भविष्य को निर्धारित करती है।

जनसमूहों की युगों पुरानी शांति संबंधी आकांक्षा आज व्यावहारिक कार्रवाई की प्रभावशाली योजना में साकार हो रही है। शांति के लिए सोवियत संघ के संकल्पबद्ध संघर्ष के परिणामस्वरूप, जिसका दुनिया की सभी जनतांत्रिक शक्तिपाँ समर्थन करती है—तनाव-शैथिल्य की नीति फिलहाल अपना पहला सुफल देने लगी है। इस शानदार संघर्ष में शान्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जनगण की स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता के भावी संघर्ष का कार्यक्रम जिसे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस में निर्धारित किया गया—नये क्षितिज खोलता है। यदि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है तो राजनैतिक तनाव-शैथिल्य-सैनिक तनाव-शैथिल्य और राज्यों के बीच व्यापक बहुसुखी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा संरक्षित किया जा सकेगा। अंततः शाश्वत शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मानक बन जायेगी। दरअसल उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आगे के विकास में यह मूलभूत काम है जिसे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यक्रम के लक्ष्य के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया है—“युद्ध को नेस्तनाबूद करना और पृथ्वी पर स्थायी शांति स्थापित करना कम्युनिज्म का ऐतिहासिक मिशन है।”

युद्धों को समाप्त करने की समस्या में कुछ विरोधाभास दिखाई दे सकता है, कम-से-कम उतने भर में जितना कि परवर्ती ऐतिहासिक अनुभव इस संभावना को नकारता है। फिर भी अन्य सामाजिक-राजनैतिक समस्याओं की तरह इसके समाधान के लिए ऐतिहासिक नजरिया आवश्यक है। युद्ध कैसे पैदा होता है, इसमें कौन-सी शक्तियों का हित निहित होता है या इसमें कौन अभिरुचि रखता है, क्या मानव जाति बिना युद्ध के जी सकती है, या क्या यह एक ऐसा अभिशाप है जो सदा खून का दरिया बहाने के लिए ही होता है? इन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का जवाब देने के लिए यह आवश्यक है कि कारकों के जटिल संयोग की परीक्षा की जाये—सामाजिक-आर्थिक घटनाओं से लेकर कानूनी तथा अन्य विविध रूपों में अभिव्यक्त और परस्पर अंतःक्रिया में संलग्न—किन्तु स्वभावतया यह भी आवश्यक हो कि यह परीक्षा सटीक स्थितियों के आलोक में ही हो।

मानवता ने शांति के अपने स्वप्न को सँजोकर रखा है, हजारों सालों के इतिहास में लगातार प्रचुर मात्रा में खतरंजित युद्धों के दौर में से गुजरते हुए भी कई शताब्दियों से शांति के इस दर्शन ने जनगण के जीवन से सप्तस्र संघर्षों को समाप्त करने के मानवतावादी विचारों को पोषित और विकसित किया है। कभी-कभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक समान बनाने वाली मूलभूत और निर्भीक योजनाओं का मूर्तरूप भी धारण किया।

दार्शनिक शोधग्रंथों अथवा सत्ताधारियों की घोषणाओं में निरूपित शांति के आह्वान कितने भी प्रभावकारी क्यों न हों, वास्तविकता से तुलना करने पर वे अनिवार्यतः व्यावहारिक दिवालियापन को ही प्रकट करते हैं। या फिर इनके नीचे दबी-ठंडकी उनकी स्वार्थपरक योजनाएँ दिखती हैं, जनता के कल्याण को बढ़ावा देने की वास्तविक आकांक्षा से जिनका दूर का भी वास्ता नहीं है। हिंसा पर आधारित समाज से और क्या आशा की जा सकती थी? दास-स्वामियों ने अधिक दास पाने के लिए युद्ध छेड़े, सामंती प्रभुओं ने सीमा विस्तार और कृषि-धारों को बढ़ाने के लिए युद्ध छेड़े, पूँजीपतियों ने, कच्चे मालों के स्रोतों के लिए, व्यापार-क्षेत्र बढ़ाने के लिए—जहाँ वे अपनी पूँजी लगा सकें—और आगे चलकर बड़े हुए शोषण के द्वारा अधिक समृद्धि अर्जित करने के युद्ध छेड़े। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 5,500 वर्षों में 14,500 से अधिक युद्ध हुए जिनमें करोड़ों की संख्या में जानें गयीं। कितने हैरतअंगेज आँकड़े हैं ये।

शोषण की व्यवस्थाओं के प्रारंभ से ही युद्ध निरंतर उनसे संबद्ध रहा है। फिर भी, जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है वह यह कि लोगों ने प्रत्येक काल में अनवरत रूप से लग्न के साथ शांति की खोज की है। लेकिन जबकि सभी स्कूली पाठ्य-पुस्तक सैनिक हलचलों और युद्धों के वर्णनों से युक्त सामग्री से भरी रहती है, शांति के विचार इस दृष्टि से उतने भाग्यशाली नहीं बन पाते हैं तथा

आम तौर से गुमनाम रह जाते हैं। तो भी उनके विकास की खोज करना श्रेयस्कर और रुचिकर होगा। इस संबंध में यूरोपीय महाद्वीप के संदर्भ में शांति की समस्याओं के क्रम में दार्शनिक और राजनैतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन विशेषतौर पर शिक्षाप्रद है। इस विषय में यूरोप की प्राचीन, मध्यकालीन और पूँजीवादी युगीन—सभी अवधियों का इस संबंध में चिंतन अपनी छाप छोड़ता है।

उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान के विचारकों में इस सामान्य सिद्धांत पर कोई असहमति नहीं थी कि युद्ध—व्यापक जन-संहार—एक बुराई है, तथा शांति एक वरदान है, किन्तु उन्होंने इसे आंतरिक यूनानी समस्या के रूप में ही देखा। जहाँ तक बाहरी दुनिया का संबंध है उन्होंने किसी प्रकार की आंतियों की अनुमति नहीं दी। “युद्ध सबका पिता और राजा है।”—इस बात पर प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने जोर दिया था तथा इस सिद्धांत को प्रकृति और समाज दोनों की द्वन्द्वात्मकता के विकास के रूप में आगे बढ़ाया था। प्लेटो के आदर्श राज्य में शांति का शासन है, किन्तु जिन्होंने युद्ध में अपनी-अपनी सीमाओं से परे अपने आपको विशिष्ट सिद्ध किया उनका गुणगान किया गया है। अरस्तू ने स्पष्टता के साथ युद्ध के सामाजिक सार का उद्घाटन किया जो उनके समय के लिए असाधारण बात थी। उन्होंने युद्ध को ‘अधिग्रहण की स्वाभाविक क्रिया’ कहकर परिभाषित किया। उनके अनुसार युद्ध का वह कलात्मक अंश, जिसमें ‘शिकार करना सम्मिलित’ है—पूरी तरह न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि वह एक कला है जिसका अभ्यास “जंगली पशुओं और आदमियों के विरुद्ध होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने शासित होने के लिए ही बनाया है किन्तु जो समर्पण नहीं करते।” युद्ध के प्रति यह दृष्टिकोण, जाहिर है, दास प्रथा की प्रकृति से पैदा हुआ था तथा उसकी मानसिकता के अनुरूप था।

चौथी शताब्दी में मकदूनिया के उदय की ठोस परिस्थितियों तथा सिकंदर—जो अरस्तू का शिष्य था—की जीतो के दौरान, युद्धकला के इस प्रकार के मूल्यांकन ने मकदूनिया के विस्तारवाद को तर्कसंगत ठहराया। ईसापूर्व 338 के अगस्त में चैरोनेआ की लड़ाई के बाद, जिसने मकदूनिया के आधिपत्य के प्रश्न को अंतिम रूप से हल कर दिया था, मकदूनिया के फिलिप ने पराजित कोरिंथ में अखिल यूनानी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें व्यक्त यूनानी शांति संबंधी विचारों को सुपरिभाषित राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली। इस बात पर सहमति हुई कि—प्रथम, यूनानी राज्यों का एक महासंघ बनाया जाये जिनके बीच आपसी युद्धों पर प्रतिबंध लगाया जाये; द्वितीय : महासंघ और मकदूनिया के राजा के बीच स्थायी

सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक संधि पर हस्ताक्षर हों, तृतीय, पर्सियां से युद्ध शुरू किया जाये। सिकंदर के बाद के अभियानों ने यह जाहिर कर दिया कि कोरिथ सम्मेलन के भागीदारों—मकदूनियाई इनमें प्रमुख थे—ने तीसरे विन्दु को सर्व-प्रमुख समझा।

इसका निष्कर्ष है कि कूटनीति के इतिहास के इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानून की धारा ने साफ़तौर पर एक शोषक समाज की विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्ति का निर्धारण कर दिया, जिस प्रवृत्ति का रख उत्पत्ति के साधनों के प्रसार की ओर था। इसके अलावा इसमें यह इच्छा भी निहित थी कि सबसे अधिक शक्तिशाली भागीदार के साथ मिलकर आधिपत्य को सुदृढ़ बनाया जाये। जाहिर है इस संधि का निषाना सदा अन्य देश एवं जनगण ही बनते।

सदियों बीत गयी। साम्राज्य उठे और गिरे, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे बने और टूट गये, किन्तु वास्तव में राज्य की विदेश नीति के लक्ष्य उपरिवर्णित पैटर्न में ही सीमित रहे।

तीसरे देशों की ओर लक्षित क्षेत्रीय मित्रताओं के विचार के पनपने के लिए मध्य यूरोप उपजाऊ जमीन साबित हुआ। उदाहरण के लिए, सन् 1095 में क्लैरमोट से आयोजित रोमन कैथोलिक चर्च की कौंसिल में इसे आगे विकसित किया गया, जहाँ पोप अबन द्वितीय ने सभी ईसाई राज्यों को 'दैवी शांति' का उपदेश दिया और इसके साथ ही उसी समय 'क्राफ़िरो' के खिलाफ़ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया। होली-सी के प्रधान के पश्चिमी ईसाइयतशाही को अपील की कि वह पूर्वी ईसाइयतशाही को बचाने आये और तुर्कों से जेरुसलम को हथिया ले और इसके साथ ही उनसे वायदा करे कि वे विजेता अपने अच्छे उपयोग के लिए उपजाऊ जमीनें हासिल करेंगे। इस अपील के बाद का परिणाम क्या हुआ—यह सुपरिचित है: जहाँ तक तुर्कों के खिलाफ़ 'पवित्र युद्ध' का संबंध है, ईसाई राज्यों ने कठिनाइयों के बावजूद इस विन्दु पर एक समझौता किया, जिसके फल-स्वरूप चार सदियों की अवधि के दौरान बहुत से और जिहाद छिड़े। किन्तु ईसाई राज्यों के बीच में 'दैवी शांति' के लिए किये गये आह्वान अपने आप में पूरी तरह असफल सिद्ध हुए।

जिहादी के दौरान तथा उनके पश्चात् यूरोप झगड़ों एवं परस्पर संहारक युद्धों की विभीषिका में फँसा रहा। उसकी सीमाओं से परे संयुक्त 'युक्ति' मिशन यूरोप को शांति के अधिक निकट नहीं ला पाया। फिर भी, जब सन् 1453 में तुर्कों के आघातों के परिणामस्वरूप विजेंटाइन साम्राज्य घराशायी हो गया तथा ईसाई राज्य वास्तव में एक समान शत्रु के विरुद्ध खड़े हुए, तब भी यूरोपीय एकता की अपीलें बहरे कानों से ही टकराकर रह गयी। सन् 1459 में पोप पीयस द्वितीय द्वारा शांति कौंसिल के लिए ईसाई राजाओं को सम्मिलित करने का प्रयास

नितांत असफलता में समाप्त हुआ। उसे किसी ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। और जब वह मंतुआ पहुँचा, तो कांग्रेस के लिए प्रस्तावित जगह पर उसे वहाँ न तो कोई राजा मिला और न ही उनके प्रतिनिधि।

फिर भी, ईसाई राज्यों के सहमेल का विचार, जिसकी जड़े सभ्य जनगण के मध्य राजनैतिक शांति की प्राचीन अवधारणा में निहित थी—आगे के बहुत से वर्षों तक यूरोपीय राजनीतिज्ञों के दिमागों को आंदोलित करता रहा। साथ ही, वे दूसरे देशों के विरुद्ध लक्षित सैनिक और राजनैतिक सहमेल के अलावा यूरोपीय शांति के लिए किसी अन्य रूप की कल्पना तक नहीं कर पाये।

उदाहरण के लिए, 17वीं शताब्दी में बहुचर्चित, मैक्सीमिलीन सली की महत्वाकांक्षी योजना यही थी। प्रमुख फ्रांसीसी राजनेता तथा किंग हेनरी चतुर्थ के सलाहकार डक डे सल्ली ने उदीयमान फ्रांसीसी तानाशाही के हितों की वकालत की और एक साथ दो समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। सबसे पहले उसने हेप्सबर्ग राजाशाही को कमजोर करने की कोशिश की, जो फ्रांस का शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी था, और फिर उसने पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को इस दृष्टि से एकताबद्ध करने की कोशिश की कि बल्कन से तुर्कों को बाहर निकाला जाये। अप्रत्यक्षतः यह योजना मस्कोवी के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी निर्धारित की गयी थी, जो जार इवान चतुर्थ के अधीन बहुत मजबूती से स्थापित हो चुका था और दुदता के साथ शक्ति अर्जित कर रहा था।

अपनी योजना के समर्थन में एक दलील के रूप में सली ने सीमांत प्रदेशों की 'प्राकृतिक' धारणा को प्रस्तुत किया, जिसके बारे में उनका विश्वास था कि यह सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए, प्रसंगानुसार समझौतों के आधार पर (योजना यह थी कि पूर्वी यूरोप को 15 समान शक्तिशाली राज्यों में विभाजित किया जाय) स्थापित किया जाना था। इन देशों को एक महासंघ के चौखटे में फिट किया जाना था अर्थात् 'ईसाई गणतंत्र' के रूप में, जिसकी मुखिया सशस्त्र सेना युक्त एक महासंघीय कौंसिल होती तथा जो गृहयुद्धों तथा धार्मिक युद्धों को रोक सकती। यदि यह महान् योजना व्यवहार में उतार दी जाती, तो फ्रांस के 'प्राकृतिक सीमांत प्रदेशों' का विस्तार दक्षिण में पिरेनीज तक हो जाता और उत्तर और पूर्व में आल्प्स और राइन तक। बोरबोन हेप्सबर्गों के प्रभाव को क्षीण करके 'ईसाई गणतंत्र' पर आधिपत्य स्थापित कर लेते। सल्ली की प्रायोजना का यह प्रमुख लक्ष्य था। जहाँ तक उसके तुर्की विरोधी उन्मुखता का संबंध है, इसे समान खतरे को सामने रखकर प्रस्तावित सहमेल को सुदृढ़ करना था और उस भूमिका को सुदृढ़ करना था जो इसमें फ्रांसीसी ताज द्वारा अदा की जानी थी।

यद्यपि सली की योजना की प्रकृति काल्पनिक थी, फिर भी यह एक अग्रगामी कदम था क्योंकि यूरोपीय सेंटलमेंट की नींव रखने की ऐसी कोशिश थी जिसका

आधार 'प्राकृतिक सीमांत प्रदेशों' की तर्कसंगत धारणा थी तथा शक्ति संतुलन के एक प्रकार के समझौते की प्रक्रिया जिसे पुष्ट करती थी। यह कहना अनावश्यक है कि सली की प्रायोजना कार्यरूप लेने में असफल रही, क्योंकि यूरोप में 'प्राकृतिक सीमांत प्रदेशों' के सिद्धांत को कोई समर्थक नहीं मिला। किंतु सार्वभौमिक शांति के विचारों के सामान्य विकास में इसका अपना स्थान है। इस महान् योजना में निहित कुछ विचार बहुत बाद में प्रबोधन के बहुत से चिंतकों की रचनाओं में प्रति-ध्वनित होते रहे जिन्होंने दरअसल शांति की समस्या को गंभीर दार्शनिक अध्ययन की एक विषयवस्तु बना दिया।

प्रबोधन और उसका शांति का आदर्श

विनाशकारी सैनिक संघर्षों की ताजा लहर यूरोपीय महाद्वीप में यूज्वी संबंधों की स्थापना का प्रतीक थी इन्होंने भूतपूर्व सभी युद्धों—जिनमें 'सप्त वर्षीय युद्ध', 'तीस वर्षीय युद्ध' और 'सौ वर्षीय युद्ध' शामिल हैं—की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में विनाश किया। राष्ट्रीय सत्ताएँ स्थापित हुईं तथा तोप और तलवार से उपनिवेश जीत लिये गए। साथ ही, नए युग के परिघटन की ताजा लहर ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खोज की प्रेरणा पैदा की जो और अधिक स्वीकार्य हों। ऐसा प्रतीत हुआ कि यूरोप में राजनैतिक क्रियाकलाप शांति के आदर्शों से जितना दूर होते गए, विश्व व्यापी समझौते की दिशा में प्रगतिशील चिंतन की कोशिशें लगातार उतनी ही अधिक तेज होने लगीं। तात्कालिक परिणाम के रूप में सतत शांति के लिए संधि का विचार सामने आया। अपने समय के महान् विचारकों—थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, विलियम पेन, चार्ल्स सेंट पियरे, ज्यां-जेक्स रुसो, और अंततः इममान्युअल कांट—सबने इस विचार को अत्यंत महत्वपूर्ण अवदान दिया।

बहुत से दशकों तक सतत विश्व शांति के लिए संधि करने का विचार, प्राकृतिक विधान और सामाजिक अनुबंध की सामान्य धारणा के घटक के रूप में प्रबोधन के दार्शनिक अध्ययनों पर छाया रहा। यह अपनी सादगी और मानवी चिंतन पर आस्था के कारण लोगों को आकर्षित करता था। उनकी सुरक्षा और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार को आश्वस्त करने के उद्देश्य से प्रबोधन के चिंतक यह दलील देते थे कि लोगों को एक ही राज्य के निर्माण हेतु एक समझौता करना होगा। आखिर राज्यों को ऐसा करने से अर्थात् सुरक्षा को आश्वस्त करने और पारस्परिक विनाश को टालने का समझौता करने से कौन-सी बात रोकती थी?

सदाहरण के लिए, विलियम पियरे—जो अपनी रचनाओं में लॉक और हॉब्स के विचारों पर भरोसा करते थे और जो जितना अधिक दार्शनिक थे उतना ही अधिक राजनीतिज्ञ थे—ने अपनी पुस्तक 'एन एसे टुवाइंड्स दे प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीस आफ यूरोप' में लिखा—“शांति न्याय से कायम रहती है, जो कि सरकार का

एक प्रतिफल है जैसे कि सरकार समाज का और समाज सहमति का प्रतिफल होता है।¹ पेन के अनुसार, कानून की शक्ति ही लोगों में निहित शांति और न्याय की आकांक्षा को प्रतिबिम्बित करती है तथा इस यूरोपीय राज्यों के सामान्य सहमेल और सर्वोच्च संगठन के अपने त्रियाकलाप के आधार रूप में भी निहित रहना चाहिए। यह संगठन विवादपूर्ण प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से गठित कांग्रेस हो सकती है अथवा संसद। पेन सल्लो को महान् योजना का अपने शोधग्रंथ में उल्लेख करते हुए पश्चिमी यूरोप के राज्यों के अलावा रूस और तुर्की को भी सम्मिलित करते हुए संभावित महमेल की भौगोलिक सीमाओं को और अधिक विस्तार देते हैं।

प्रबोधन के प्रारंभिक काल के फ्रांसीसी दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ चार्ल्स द सेंट-पियरे ने अपनी मौलिक रचना 'प्रोजेक्ट द पेक्स पश्चिमुएल'—जो उत्प्रेक्षित में सन् 1712 की वेस्टफालियन कांग्रेस के शीघ्र बाद में प्रकाशित हुई थी—में समान-धर्मा विचार प्रकट किए गए थे। उत्प्रेक्षित की शांति ने स्पैनिश सक्सेशन के युद्ध को समाप्त कर दिया। सल्लो की ग्रेट डिजाइन में भिन्न सेंट-पियरे की महाद्वीपीय राज्यों के सहमेल की प्रायोजना में सीमाओं के परिवर्तनों का प्रावधान नहीं था, लेकिन मौजूदा सीमांत प्रदेशों के आधार को कायम रखते हुए उन्हें भविष्य के लिए एकजुट करने को प्रस्तावित किया गया था। उनका प्रस्तावित सहमेल किसी राज्य के विरुद्ध निर्देशित नहीं था; उन्होंने प्रबोधन के तत्त्वों अर्थात् विवेक, न्याय और कानून को लोगों के शांतिपूर्ण विकास की गारंटी देने वाले आदर्शों के रूप में घोषित किया था।

उदीयमान बूर्जुवा वर्ग तथा 'बर्ड एस्टेट' के विचारधारात्मक नेताओं ने निस्संदेह मानवता की सेवा की, किंतु इसलिए नहीं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (जो सदा कपोल कल्पित साबित हुए) की एक या दूसरी योजना को ईजाद किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक विधान और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबद्ध होने की वजह से ये योजनाएँ धरती पर टिकी हुई थी और न्याय के लिए अपनी खोज में, वे तर्क पर आधारित थी भाग्य एवं विधाता की ओर उन्मुख नहीं। बर्नाय इसके कि वे राजाओं और सामंतों की अनुकंपा पर भरोसा करते, उन्होंने मार्क्सवादी शांति को लोगों के स्वयं के अविभाज्य अधिकार के रूप में घोषित किया। शांति की समस्या को हल करने के तमाम प्रयत्नों—जो पहले के मध्य काल में किए गए थे—की तुलना में शांति के इन नए प्रयत्नों में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दृष्टि तथा सच्चा लोकतंत्र निहित था।

अठारहवीं सदी के दार्शनिकों और विशेषतया फ्रांसीसी दार्शनिकों के प्रति-

1. "यूरोप की वर्तमान और भावी शांति के निमित्त—एक प्रारंभिक प्रयत्न" लिखित 'यूरोप की शांति': 'शांति के फल' और अन्य ग्रंथों में; नवम्बर, 1712, न्यूयॉर्क, पृ. 6



अपने शासकों की ओर बढ़ाने चाहिए और उन्हें ताजोतख्त से नीचे उतरकर हमारे बराबर आने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसमें वे इंकार नहीं करेंगे ज्यों ही वे अपनी स्थिति की तुलना समानता की स्थिति के साथ करेंगे।”¹

शांति के प्रश्न के प्रस्तुतीकरण में प्रबोधन के दार्शनिकों द्वारा उठाये गये नये अप्रगामी कदम ने निश्चित रूप से जड़ता को तोड़ा था। किन्तु यह किसी व्यावहारिक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए नितांत अपर्याप्त था। यूरोप और अमरीका में जो दुर्दान्त घटनाएँ घटित हुईं उनके फलस्वरूप विवेक की विजय की आशा की भी वही गति हुई जो कि विघाता की इच्छा पर आश्रित अन्य बड़ी आशाओं की हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संघटन से संबंधित प्रबोधन के विचार सन् 1776 के स्वाधीनता के उस घोषणापत्र में सीधेतौर पर प्रतिध्वनित हुए जिसने संयुक्त राज्य अमरीका के निर्माण की घोषणा की थी। थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित इस घोषणापत्र—जिसे मावस ने ‘मानव के अधिकारों की प्रथम घोषणा’² की सज्ञा दी थी—पर स्पष्टतया फ्रांसिस वेकन, मॉटेस्क्यू, डिडेरोत तथा लॉक का प्रभाव था।

लेकिन यदि हम संयुक्त राज्य अमरीका की तत्काल निर्मित विदेश नीति के क्षेत्र से संबंधित व्यावहारिक क्रियाकलाप की ओर घूम कर देखें तो पाएँगे कि ज्यों ही उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की वैसे ही उन्होंने तत्कालित ‘शक्ति संतुलन’ की नीति के अन्तर्गत उन प्रगतिशील विचारों को त्याग दिया। बूर्ज्वा वर्ग के उन कट्टर विशेषज्ञों—जैसे जार्ज वाशिंगटन, एलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन एडम्स, जॉन जे और अमरीकी राज्य के अन्य जनकों—के हाथों में शक्ति संतुलन की नीति दुनिया में सबसे अधिक जनसंहारक लड़ाइयों का अधिकतम लाभ उठाने की इच्छा के रूप में परिवर्तित हो गयी। समुद्र पार का यह गणतंत्र एक ऐसे राज्य की नींव रख रहा था जो देश में सदियों तक असम्मानजनक गुलामी की संस्था को संरक्षित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विस्तारवाद की नीति का अनुसरण करे और विश्व शांति के प्रति कतई चिंतित न हो।

प्रबोधन के विचारों का फ्रांसीसी क्रांति के कार्यक्रम पर—जो सन् 1789 का मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणापत्र कहलाता है—और भी अधिक प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए इसकी दूसरी धारा में कहा गया था—“प्रत्येक राजनैतिक संगठन का उद्देश्य मानव के

1. डोम डिसकैप्स, पूर्वोक्त पृ० 185

2. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, चयनित रचनाएँ तीन खंडों में, खंड 2 मार्क्स, 1973, पृ० 22

प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकारों को सुरक्षित करना है। ये है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा तथा दमन का प्रतिरोध।”

अमरीका से भिन्न, क्रांतिकारी फ्रांस में जैकोबाइनी तानाशाही के पास ऐसा बल था जो कि इन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तुत था। सैनिक पराजयों के समय जबकि प्रतिक्रियावादी यूरोप की सेनाएँ फ्रांस के पास चारों ओर से छाई हुई थी, तथा हस्तक्षेपवादियों के ऊपर प्रथम विजयों के बाद, दोनों ही बार, जैकोबियनों ने दृढ़ता से क्रांतिकारी युद्ध की रणनीति लागू की। राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने विवरणों में मैक्सिमिलियन रौब्सपियरे ने साफ तौर पर घोषणा की कि किसी भी परिस्थिति में फ्रांसीसी गणतंत्र अपनी प्रभुसत्ता का समर्पण नहीं करेगा और अपने आंतरिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत ही देगा। साथ ही, यह भी कि अपनी राजनीतिक प्रणाली को किसी दूसरे देश पर हथियारों की ताकत से थोपने का उसका कोई इरादा न था।

जैकोबियनों की मान्यता थी कि ये सिद्धांत केवल तात्कालिक रणनीतिक नारे ही नहीं हैं, किन्तु ये विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं और उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेक एवं न्याय के सिद्धांतों पर जोर दें। तब में जैकोबियन मानवता के सभी हितों का पक्ष लेते रहे। रौब्सपियरे ने एक बार कहा कि यदि फ्रांस की स्वतंत्रता नष्ट होती है तो प्रकृति कफन से ढक जाएगी और मानव ज्ञान, अज्ञान, बर्बरता तथा तानाशाही की ओर वापस लौट पड़ेगा जो कि असीम सागर की भांति समूची दुनिया की तबाही के कारक बनेंगे। उनके शब्द एकदम सटीक भविष्यवाणी साबित हुए। 9वीं थर्मिडोर के प्रतिक्रांतिकारी राज्य-विप्लव ने जैकोबियनों के क्रियाकलाप की हत्या कर दी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में न्यायसंगत सिद्धांतों पर दिया जाने वाला बल भी समाप्त कर दिया गया।

इमानुअल कांट की ‘चिरंतन शांति’

सार्वभौमिक शांति का विचार समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत, नैपोलियनी युद्धों के प्रारंभ में यह और आगे विकसित हुआ; इस बार फ्रांस के बाहर ऐसा हुआ। जिस व्यक्ति ने इसका अध्ययन प्रारंभ किया तथा प्रबलता से इसका प्रचार किया वह था जर्मनी के पौराणिक दर्शन का संस्थापक इमानुअल कांट। उनकी विश्व दृष्टि, मार्क्स के शब्दों में, फ्रांसीसी बूज्वा क्रान्ति पर आधारित जर्मन सिद्धांत थी।

उस महान दार्शनिक ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों के शांति प्रयत्नों के निराशाजनक परिणामों का तथा उनकी व्यावहारिक सिफारिशों की असफलता का

विश्लेषण किया। वह अन्य किसी पूर्ववर्ती की तुलना में समस्या की संपूर्ण जटिलता को अधिक गहराई से समझने की क्षमता से संपन्न थे। संभवतः यही कारण है कि उन्होंने अपने शोधग्रंथ का आरंभ सदेह भरे प्रश्न को उठाकर किया—‘चिरंतन शांति’। इसका निर्णय हमें नहीं करना है कि वह डच सराय वाले की कब्र पर लिखे इस व्यंग्यात्मक अभिलेख का निशाना समूची मानवता है, अथवा वे शासक हैं जिनकी युद्ध पिपासा सहज शांत होने वाली नहीं है, अथवा वे दार्शनिक जो मधुर स्वप्न देखते हैं।¹

तथापि काट स्वयं शांति के इस स्वप्न को ऐसा नहीं मानते थे जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, वह स्थायी शांति को आवश्यक समझते थे और इससे भी अधिक उसको ऐतिहासिक विकास का एक अपरिहार्य परिणाम मानते थे। उनका तर्क था कि लोगों के बीच के संबंधों के सारतत्त्व में ही निहित तात्त्विक अंतर्विरोधों का फायदा उठाकर प्रकृति उन्हें उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाती है ताकि कालावधि में मानव जाति कानून के तत्वाधान में एकजुट हो जाए।

प्रकृति ने लोगों को पृथ्वी पर आबाद किया है। वह ऐसे हालात भी पैदा करती है ताकि पारस्परिक संबंध भिन्न इकाइयाँ उस जीवन की अच्छी बातों का विनिमय करें, जो जीवन लोगों को राज्य के रूप में एकताबद्ध करता है। जो पहले शत्रुता और झगड़े में अस्तित्वमान थे, उन्हें राज्यों के लोगों को सहमेल के रूप में रहने के लिए प्रकृति के द्वारा प्रेरित किया जाएगा। अपनी एक अन्य रचना में काट ने लिखा—“चाहे यह विचार कितना ही स्वप्निल क्यों न लगे और चाहे अब्बे द सेंट पियरे और रूसो की कितनी ही हँसी क्यों न उड़ी हो (शायद इसलिए कि उनकी आस्था वे इसके तुरंत क्रियान्वयन में थी।) फिर भी, यही वह अनिवार्य समाधान है जो लोगों को पारस्परिक विध्वंसात्मक प्रयत्नों की स्थिति में डुबकी लगाने से बचा सकता है।”²

चिरंतन शांति पर अपनी शोध रचना में काट ने उन सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया जिनके बारे में उन्हें विश्वास था कि वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में हमें आगे बढ़ाएंगे। उनमें ये हैं—(1) उस संघि को बंध नहीं समझा जाएगा जिसमें भावी युद्ध के लिए मौन या गुप्त सामग्री निहित है; (2) कोई भी स्वतंत्र राज्य पर चाहे वह छोटा हो या बड़ा—विरासत, विनिमय—क्रय या दान के आधार पर अन्य किसी राज्य का आधिपत्य कायम नहीं हो सकता (3) मौजूदा सेनाएँ (लगातार मीलों में व्याप्त) समयानुसार क्रमशः पूर्णतया समाप्त कर दी जाएंगी; (4) राष्ट्रीय ऋणों को राज्यों के बाहरी विभाजन के आधार पर अनुबंधित नहीं किया जाएगा;

1. इम्मानुअल काट, ‘स्वाधी शांति’ सः सेविस, व्हाइट बेक, न्यू यॉर्क, 1957, पृ० 3

2. काट्स बेसाम्प्लेट प्रिण्टन, बंड VIII बर्लिन, 1912, पृ० 24

(5) कोई भी राज्य ताकत के जोर पर दूसरे राज्य के विधान या उसकी सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा; (6) कोई भी राज्य, युद्ध के दौरान शत्रुता के कारण कोई ऐसे जघन्य कार्य नहीं करेगा जो आगे की शांति में पारस्परिक विश्वास को असंभव बना दें; जैसे कातिलों की नियुक्ति, विप्लव पदार्थों का उपयोग, संधिपत्र का उल्लंघन और विरोधी राज्य में देशद्रोह के लिए भड़काना।¹

ये सब सिद्धांत जो प्रबोधकों के विचारों को सूत्रबद्ध करते हैं, और बहुत-सी बातों में उन सीमाओं से परे भी जाते हैं, एकदम जनतांत्रिक हैं—यदि उनको इस रूप में समझा जाए कि ये उस समय सूत्रित किए गए थे जबकि संयुक्त राज्य अमरीका ने स्वाधीनता हासिल की ही थी और फ्रांसीसी गणतंत्र प्रतिक्रियावाद के खिलाफ क्रांतिकारी युद्धों में व्यस्त था।

यह जनतांत्रिक प्रवृत्ति घासकर अंतिम तीन बिन्दुओं में स्पष्टतया अभिव्यक्त हुई है जिनमें कांट ने स्थायी शांति को सुरक्षित करने के लिए शर्तें कायम की हैं। उनकी राय में शांति के लिए मुख्य सामाजिक-राजनैतिक पूर्वशर्त स्वतंत्रता एवं कानून पर आधारित सरकार का गणतंत्रीय रूप है, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं युद्ध और शांति के प्रश्नों को तय कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह राज्यों के ऐच्छिक सहमेल—जहाँ महासंघ के चौखटे के भीतर प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय संप्रभुता के अधिकार का उपभोग कर सके—पर आश्रित होगी। आचरण और नीति संबंधी शर्त यह होगी कि राज्यों के बीच ऐसे संबंधों का निर्माण किया जाये जिनके अंतर्गत कोई भी राज्य अन्य राज्यों की सीमाओं को हथिया नहीं सके।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कांट ने एक आदर्श गणतंत्र के लोकतांत्रिक कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र तक विस्तार करने के प्रयास किए। उनके अनुसार जनगणों की एक विशाल मंत्री—जिसमें हर राज्य को उसकी सुरक्षा और उसके कानून के प्रति सम्मान की गारंटी होगी—कानून के सिद्धांतों पर आधारित आंतरिक नागरिक व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य होगी।

जनगणों के सहमेल का अर्थ 'जनगणों के राज्य' की स्थापना नहीं थी, अर्थात् सहमेल का अर्थ किसी एक राज्य पर दूसरे राज्य का किसी छिपे रूप में आधिपत्य होना नहीं था। वास्तविकता में यह ऐच्छिक सहमेल का वह रूप था जो स्वतंत्रता और शांति की स्थिरता के लिए निर्मित किया जाना था। कांट ने इसे जिस रूप में देखा, स्पष्ट है कि, उसके पीछे महासंघ बनाने का इरादा था; उनकी समझ यह थी कि यह सहमेल "क्रमशः तमाम राज्यों तक फैल जाएगा और इस प्रकार स्थायी शांति की ओर ले जाएगा," यह एक वस्तुगत यथार्थ हो जाएगा। "क्योंकि यदि भाग्य निदिष्ट करता है कि एक शक्तिशाली और प्रबुद्ध जनगण अपने आप को एक

गणतंत्र में विकसित कर सकता है, तो वह अपने स्वभाव के अनुरूप स्थायी शांति की ओर भी अपने आप को प्रवृत्त कर सकता है—यह दूसरे राज्यों के साथ महासंघ का आधार निमित्त करता है ताकि वे इससे सबद्ध रह सकें और राष्ट्रों के कानून की धारणा के अधीन स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। यह महासंघ ऐमे अधिक-से-अधिक संघों के द्वारा क्रमशः व्यापक होता जाएगा।¹

कांट ने स्थायी शांति को एक मधुर स्वप्न या दार्शनिकों की एक हवाई आशा के रूप में ग्रहण नहीं किया। मानवता इसे स्वैच्छिक महासंघ के रूप में ही प्राप्त करती है जहाँ कि अंततः कानून और न्याय ही सर्वोच्च शासक होंगे। कांट ने उन मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित किया जो कि ऐसे समुदाय की नींव का निर्माण करेंगे। अथ केवल यह प्रश्न शेष रहता है कि इस उद्देश्य को व्यवहार में कैसे प्राप्त किया जाए और क्या यह मचमुच प्राप्य भी है। कांट का जवाब है—“स्थायी शांति की गारंटी महान् कलाकार प्रकृति से किसी भी रूप में कम नहीं है। अपनी यांत्रिक प्रक्रिया में प्रकृति को हम देखते हैं कि उसका लक्ष्य मनुष्यों के बीच में तारतम्य पैदा करना है—उनकी इच्छा के विरुद्ध और वास्तव में उनके बीच मतभेदों के होते हुए भी उनमें तारतम्य लाना है।”² और कांट एकदम निश्चित है कि “प्रकृति दृढ़तापूर्वक यह चाहती है कि अंततः सत्य की विजय हो। जिस काम को हम उपेक्षा करते हैं वह अपने आप ही होता है।”³

तो यह है कांट का जवाब। यह आसानी से देखा जा सकता है कि कोनिग्सबर्ग का संत डिसकैप्स से दूर नहीं गया है। वस्तुतः, हकीकत इससे उल्टी है। डिसकैप्स ने कम-से-कम शक्तियों से अपील करने की राय दी थी कि न्यायसंगत बनो और उन्हें न्याय के सामने झुकाओ, जबकि कांट की राय है कि हर बात प्रकृति पर छोड़ दी जानी चाहिए, उनके अनुसार प्रकृति ही इस प्रश्न का सबसे बढ़िया समाधान खोज निकालेगी।

वूर्ज्वी चिंतन की बंद गलियाँ

हमारे खयाल में कांट की ‘चिरंतन शांति’ अपने युग के दार्शनिक विचार को अंतिम विचारणीय देन थी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र उदीयमान वूर्ज्वी वर्ग के युग का प्रतिनिधित्व करती थी। यह कहा जा सकता कि उन्होंने न्याय और विवेक (इन पारिभाषिक शब्दों के वूर्ज्वी विश्लेषण के रूप में) के सिद्धांतों पर आधारित संबंधों की लंबे समय की खोज को एक निष्कर्ष दिया और, साथ ही उन्हें चुकता भी कर दिया। कांट के बाद अभिजात्य चिंतन ने

1. इम्मानुअल कांट, ‘स्थायी शांति’, पृ० 18-19

२. वही, पृ० 24

3. वही, पृ० 31

आधारतः कोई नई बात नहीं पैदा की, और जो कुछ उसने पैदा किया उससे मानवता को स्थायी शांति के अधिक निकट नहीं लाया जा सका। एंगेल्स ने नोट किया—“विवेक पर आधारित राज्य पूरी तरह ढह गया। प्रतिश्रुत शाश्वत शांति, विजय के अनंत युद्ध में परिवर्तित हो गई।”¹

पूँजीवादी समाज का इजारेदारी अवस्था में प्रवेश की विशिष्टता व्यापक प्रतिक्रियावाद और विश्व युद्धों के ऐसे खूनी अतिरेक रहे हैं इतिहास में जिनकी मिसाल नहीं मिलती। तब से सैन्यवाद एक ऐसा स्थायी कारक बन गया है जो पूँजीवादी देशों के सभी क्षेत्रों में फैल गया है। फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद एंगेल्स ने लिखा—“सैन्यवाद का आधिपत्य है और वह यूरोप को निगल रहा है।” उससे पहले उन्होंने लिखा था—“मेरा राज्य का मुख्य उद्देश्य हो गया है और अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य भी, लोगों के समुदाय केवल सैनिकों की भर्ती देने और उनको खिलाने के लिए ही रह गए हैं।”² वस्तुतः नई जीतों की तैयारी के लिए।

सैन्यवाद की बढ़ोतरी के साथ युद्ध की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। यह अनुमान लगाया जा चुका है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुए युद्धों में 30 लाख लोगोंने अपनी जानें गँवाई; 18 वीं शताब्दी में 50 लाख से अधिक जानें गईं; 19वीं सदी में लगभग 60 लाख जानें गईं और 20वीं सदी में प्रथम विश्वयुद्ध में एक करोड़ तथा द्वितीय विश्व युद्ध में पाँच करोड़ से अधिक जानें गईं। सैन्यवाद के मद्योत्सव की अनवरत बाढ़ और आक्रमण बूजवाँ चिंतन की सामान्य प्रवृत्ति हो गई जो इन परिस्थितियों के अधीन समस्या के किसी सकारात्मक समाधान को खोजने में निरंतर असमर्थ साबित हुआ या उसने वास्तव में युद्ध का गुणगान करना चालू कर दिया।

कांट के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने इस विषय-वस्तु पर चिंतन किया वह थे, जोहन गोटफ्राइड वोन हर्बर्ट और जोहन गोटलीब फिख्टे। कांट के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि हर्बर्ट ने रूसी की तरह एक क्रदम आगे बढ़ाया। वह जनसमुदाय की रचनात्मक भूमिका पर आस्था रखते थे। फिख्टे ने अपने तर्क जनगण के सहमेल बनाने के कांट के विचार का विकास किया। उनका विश्वास था कि ज्योंही यह सहमेल सारी दुनिया में फैल जाएगा—“चिरंतन शांति का आगमन हो जाएगा तथा मात्र वह ही राज्यों के बीच के वैध साहचर्य को संभव बनायेगी।”³ किंतु, क्योंकि उन्होंने कांट के कुछ विचारों को मात्र विकसित और जोर-शोर से प्रसारित किया, हर्बर्ट और फिख्टे दोनों ने ही इस समस्या के

1. फ्रेडरिक एंगेल्स, *इयूहरिंग भवषटन*, पृ० 303

2. वही पृ० 204

3. जोहन गोटलीब फिख्टे, *वर्क ऑफ़वॉल इन सेक्स बाइंड ज्वैटर बेंड* संडलेज डेत नेचरे-इनस। *डाय सिस्टम डेर सिटेनवेहर* (1798) पृ० 386

समाधान के रूप में कोई नई बात पैदा नहीं की, और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह कि उनके विचारों के आह्वान का अपेक्षाकृत उससे भी बहुत कम प्रभाव पड़ा जितना कि उनके प्रमिद्ध पूर्ववर्ती के अनेक विचारों का पड़ा था।

जहाँ तक 'चिरंतन शांति' की अन्य प्रायोजनाओं का संबंध है—मुख्यतया उदार शांतिवादी प्रकृति की—जो उस समय और बाद में फिर समूची उन्तीसवीं सदी में दिखाई दी, वे प्रायः बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुईं। दर्शन की विभिन्न शाखाओं की संकीर्ण शास्त्रीय सीमाओं में बँधी हुई होने के कारण वे कोई व्यापक सामाजिक हलचल पैदा नहीं कर पायी। यही नहीं, सैन्यवाद एवं आक्रमण के खिलाफ बूज्वा उदारवादियों के सकोची विरोध वस्तुतः अनेक छद्म-वैज्ञानिक सिद्धांतों—जो जाहिराना तौर पर सैन्यवाद और हमले को न्यायसंगत बताते थे—ने दबा दिया।

बूज्वा चिंतन का यह कायापलट इस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है कि यह अब शासक वर्ग के नये सामाजिक कानून के अनुरूप बन गया था। ज्यों ही पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद की अवस्था में प्रवेश किया वैसे ही बूज्वा वर्ग की शांति में रुचि घटने लगी, इसने अपने सारे प्रयत्नों को उपभोक्ता बाजारों तथा पूँजी विनियोजन के क्षेत्रों को विभाजित और पुनर्विभाजित करने में लगा दिया। इसकी व्यावहारिक सक्रियता इस प्रकार चालित होने लगी ताकि वह कच्चे माल के स्रोतों पर विचार करके जहाँ भी संभव हो वहाँ अधिक-से-अधिक ज़मीन हथिया सके। उसे इस बात का डर भी था कि कहीं ऐसा न हो कि मुक्त भूमि अथवा विभाजित भूमि के पुनर्विभाजन के भयंकर संघर्ष में वह पीछे रह जाय।¹ इसके मूल मंत्र का उद्घोष युद्ध की वकालत करने वाले जनरलों ने किया न कि विवेक एवं न्याय के आधार पर विश्व का पुनर्गठन करने का आह्वान करने वाले दार्शनिकों ने।

हेल्मथ वोन मोल्ट्के, जो जर्मन सैन्यवाद के स्तंभों में से एक था तथा कैसर विल्हेल्म और 'लीह चांसलर' बिस्मार्क का प्रिय था, ने युद्ध की पूर्व संध्या पर जोर दिया कि समस्त विभाजित ज़मीनों को पुनर्विभाजित किया जाए। उनके अनुसार चिरंतन शांति मात्र एक स्वप्न था, और वह भी गुलाबी नहीं। उनकी राय में युद्ध ईश्वर के द्वारा स्थापित विश्व व्यवस्था का एक तत्त्व है जिसमें मनुष्यों के सबसे श्रेष्ठ गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उनका आरोप था कि बिना युद्ध के विश्व का अधःपतन हो गया होता तथा वह भौतिकवाद के दलदल में लुप्त हो गया होता।

1. वी० आई० लेनिन, "साम्राज्यवाद . पूँजीवाद की सर्वोच्च अवस्था" संकलित रचनाएँ खंड 22, पृ० 262।

उन वर्षों में बूज्वा सामाजिक चिंतन अनेक भिन्न-भिन्न धारणाओं में बिखर गया, इनमें से प्रत्येक अलग रूप में युद्ध को अपरिहार्य सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। इस दृष्टि से कुछ बूज्वा विद्वानों ने सामाजिक विकास के सामाजिक नियमों के स्यात पर कुत्सित सामाजिक डार्विनवाद ('अस्तित्व के लिए संघर्ष' 'सबके खिलाफ सबका युद्ध') अथवा नव माल्यसवाद के नाम पर ('युद्ध अतिरिक्त जनसंख्या का परिणाम है') जैवीय नियमों को चलाने की कोशिशें की। अन्य कुछ विद्वानों ने युद्ध के कारणों को उपचेतनीय सहजातवृत्तियों में ढूँढा जिन्हें उनक़े अनुसार स्वयं प्रकृति ने मूलतः मानवीय मानसिकता के रूप में निर्मित किया है। तीसरे प्रकार के लोगो ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि "युद्ध की घटनाक्रियाओं" की अनैयता भी एक सामाजिक घटनाक्रिया तथा इसे मानव जाति पर लटकते हुए एक रहस्यमय प्रारब्ध की संज्ञा दी।

उन्नीसवीं सदी के पूंजीवादी विचारों के व्यापक वर्णक्रम में विषय के भविष्य के विषय में निराशावादी भविष्यवाणियों का स्पष्टतया वर्चस्व था। इसमें कुछ वस्तुगत तर्क भी था। सभ्यता के विनाश के काले चित्र, चाहे आंतरिक बुराईयों की वजह से हों अथवा उन अनिवार्य युद्धों के परिणामस्वरूप हों, दार्शनिकों की रचनाओं में या उपन्यासों में पृष्ठ दर पृष्ठ पर खिंचे मिलते हैं, बूज्वा चिंतन के गंभीर संकट को ही प्रतिबिंबित करते हैं और उस गतिरोध को दर्शाते हैं जिसमें इसने अपने आपको फँसा दिया था। इस परिस्थिति ने इस तथ्य को भी प्रतिबिंबित कर दिया कि मानवता का सामान्य पतन और उसका आत्मविनाश ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य हो सकता था, और रहेगा, यदि दुनिया केवल पूंजीवाद के नियमों के अनुसार ही जीवित रहती रही, और यदि दुनिया के समाजवादी रूपांतरण के अपने कार्यक्रम को लेकर भयङ्कर वर्ग इतिहास के रंगमंच पर प्रकट नहीं हुआ।

कल्पनालोक से एक वैज्ञानिक कार्यक्रम और राजनैतिक आचरण तक

मानवता का समस्त पूर्वानुभव अकाट्यता से सिद्ध करता है कि सार्वभौमिक शांति के विचार तब तक जड़ नहीं पकड़ सकते जब तक समाजशोषण पर आधारित है। इस आकर्षक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त विविध प्रयोजनाओं—जिन्होंने बहुत सी सदियों तक दार्शनिकों की कल्पना को उत्तेजित किया और राजनीतियों के दिमागों को घेरे रखा—में तीन सामान्य लक्षण थे। किसी-न-किसी रूप में वे सब वर्गीय समाज के शासकीय उच्च स्तर के हितों को ही प्रतिबिंबित करते थे; जिसके परिणामस्वरूप वे सब संकीर्ण और अस्थिर थे और न तो वे जनसमुदाय तथा नीचे के लोकतांत्रिक तबके को अपील करने का साहस ही कर सकते थे और न उन्होंने ऐसा किया ही; और अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि उन्होंने अपने आपको दिवांसिया साबित कर दिया।

अतः इससे क्या नतीजा निकाला जाय ? क्या इससे उस पुराने निराशावादी दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि इतिहास केवल एक ही बात सिखाता है अर्थात् यह कि इसने कभी किसी को कुछ भी नहीं सिखाया ? या इसके विपरीत, यह कि सार्व-भौम शांति का विचार केवल तभी सच्चाई में बदला जा सकता है जबकि सामाजिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित निश्चित ऐतिहासिक परिस्थितियाँ निर्मित कर दी गई हों ? अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली पीढ़ियों के विचारक शांति का रास्ता ढूँढ़ने में असफल रहे और इस विषय पर कई दफ़ा उन्होंने एकदम मासूमी भरे विचार प्रकट किए। फिर भी, जो आश्चर्यजनक है वह यह कि असीम युद्धों में खून में लथपथ लोग निराश नहीं हुए, निरुत्साहित नहीं हुए और शांति की निर्णायक विजय में उन्होंने अपना विश्वास कायम रखा।

कम्युनिस्ट इतिहास को जीवन का एक महान् शिक्षक मानते हैं बशर्तें उसके अनुभव को सही रूप में समझा जाय और लागू किया जाय। युद्ध और शांति की समस्या के सदृश में भी यही कहा जा सकता है। किसी भी विगत युग ने इस समस्या का आमूल समाधान प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि इस विषय में उनका दृष्टिकोण सकीर्ण था तथा उसमें पूर्वापेक्षाओं का व ऐसी सामाजिक शक्तियों का अभाव था जो शांति के कार्यक्रम को वास्तव में कार्यरूप देने में समर्थ हों। ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार का समाधान समकालीन युग में संभव बन चुका है जबकि अब पूँजीवाद समाज की अगुवाई में नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग वह समाजवादी हिराबल दस्ता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अधिक वर्चस्व है। इन स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की नई प्रणाली की स्थापना के लिए पूर्वापेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। तथा वैज्ञानिक कार्यक्रम—जो स्थायी लोकतान्त्रिक शांति की ओर उन्मुख है—का वास्तविक प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने युद्ध और शांति की समस्या के प्रस्तुतीकरण में मौलिक रूप से नये तत्व पैदा किए हैं। इस समस्या का विश्लेषण एक या दूसरे वर्ग के नीति संबंधी लक्ष्यों के प्रसंग में किया गया और इस प्रकार पहली बार एक सचमुच वैज्ञानिक आधार प्राप्त कर लिया गया है। इस विषय में लेनिन के द्वारा एक विशिष्ट भूमिका अदा की गई, जिन्होंने सार्वभौम शांति की प्राप्ति को समाजवादी क्रांति के कामों के साथ जोड़ा।

सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज के इस दृष्टिकोण “युद्ध अपने स्वयं के मुख्य लक्षणों में एक नीति है जिसने कलम को तलवार में बदल दिया है”¹ से सहमति व्यक्त करते हुए लेनिन ने “सरकारों तथा वर्गों की नीतियों से कटकर युद्ध को सड़क के अबोध व्यक्ति की युद्ध संबंधी अवधारणा का डटकर विरोध किया

1. वीम फ्रीग, हिटरलैसन्ग बर्क डैस ज़नरल्स कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज, एर्वाटंट डर्च डब्लू, वीम मोर्क, ड्रैस्डेन, 1885, पृ० 572

जिसके तहत युद्ध की शांति पर एक सामान्य हमले के रूप में देखने के प्रयास किए जाते हैं तथा इसके बाद उस भंग शांति को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस संदर्भ में टिप्पणी करते हुए लेनिन ने केवल यह कहा : “वे लड़े, और फिर उनमें मेल हो गया।”

यह पूर्णतया अज्ञान से भरा हुआ दृष्टिकोण है, ऐसा जिसे अनेक वर्षों पहले छोड़ दिया गया था, और युद्धों के किसी ऐतिहासिक युग के किसी भी कमोवेश सावधानीपूर्ण विश्लेषण के जो तिरस्कार योग्य है।

और तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला—“युद्ध अन्य जरूरतों से अपनाई गई नीति का सिलसिला है। सभी युद्ध उन राजनैतिक व्यवस्थाओं से अभिन्न होते हैं जो उनको पैदा करती हैं। वह नीति जिसे किसी राज्य, राज्य के किसी संबंधित वर्ग विशेष के द्वारा युद्ध से पहले से अपनाया जाता रहा है उसी को अनिवार्यतः युद्ध के दौरान भी जारी रखा जाएगा, कार्यवाही का रूप मात्र अकेला बदलता है।”¹

समस्या के इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण ने युद्ध को एक ‘अज्ञेय घटनाक्रिया’ की रहस्यमय महिमा से वंचित कर दिया और इसे मानव जाति के ‘युगों पुराने अभिशाप’ की संज्ञा से मुक्त कर दिया। अन्य सामाजिक घटनाक्रिया की तरह यह इतिहास की अन्य घटनाक्रियाओं की कतार में रख दिया गया जो ‘सार्वभौम शांति’ एक भावना मात्र थी उसे मजदूर वर्ग के आंदोलन के व्यावहारिक काम के स्तर तक ऊपर उठा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक विकास की समस्याएँ उनके आंगिक अंतःसंबंधों के परिप्रेक्ष्य में परखी गईं। मार्क्सवादी-लेनिनवादियों ने शांति मात्र की अवधारणा का एक नितांत नया विश्लेषण प्रस्तुत किया, उन्होंने इसे किसी नीति के परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में देखा, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे पर दमन करने को बिना शर्त अस्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सारे जनगणों के हितों का सम्मान किया जाय और उनके उस पवित्र अधिकार को माना जाय जिसको प्राप्त कर वे आजादी से अपने सामाजिक-राजनैतिक संघटन की अपनी व्यवस्था का चुनाव कर सकें।

यह मौलिक रूप से नया दृष्टिकोण पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संघटन सबंधी पूर्ववर्ती धारणाओं के लिए चुनौती था। सदियों और सहस्राब्दियों के दौरान जबकि सत्ता पर शोषकों का कब्जा था, जनसमुदायों के हित निरंतर कुचले जाते रहे। और इतिहास के पास अंतर्राष्ट्रीय मसलों को हल करने के लिए ताकत के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था। राजनैतिक नक्शा बार-बार खींचा जाता, मिटाया जाता और दुबारा खींचा जाता रहा—उन शोषक सत्ताधारियों की इच्छा के अनुसार जो अपने पक्षधरों की शक्ति के जोर से अन्य सीमाओं पर चढ़ बैठते थे, या प्रभाव

के नए क्षेत्रों पर दावा करते थे, या अन्य जनगण या राज्यों की कीमत पर अपनी अन्य सुविधाएँ बटोरते थे ।

अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की एकमात्र गारंटी ताकत के इस्तेमाल में समायी हुई थी, जो दरअसल साधारणतया हिंसा और आतंक का संतुलन मात्र था । इस प्रकार की स्थिति के पीछे वे अनवरत युद्ध थे जिनकी वजह से असुरक्षा की नींव पर टिका कोई भी राजनैतिक संयुक्त मोर्चा देर-सवेर अपनी अस्थिरता जाहिर कर देता और इसे सशोधित करने का मौका प्रस्तुत कर देता । साथ ही, जनगण के विशाल हितों और अधिकारों के हड़पे जाने के कृत्यों ने और नए अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और सशस्त्र लड़ाइयों को उभारा ।

यद्यपि कुछ राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों को गुलाम बनाने के लिए अपनाए गए साधन तथा उनके मुक्का-कानून के सूत्र सदियों तक कई बार बदलते रहे, फिर भी शोषक समाज में पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय सबंधों का सार वही रहा, क्योंकि वे निश्चित रूप से ताकत के जोर वाली नीति पर टिके हुए थे । और कूटनीति में भी अपने राजनैतिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों और तरीकों का अनुसरण किया जाता था । मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा—“अब तक समस्त विद्यमान शासकों और उनके कूटनीतिज्ञों ने अपने कौशल और प्रयासों का प्रयोग एक राष्ट्र को दूसरे के विरुद्ध करने में ही लगाया है तथा एक राष्ट्र का उपयोग दूसरे को अपने अधीन करने के लिए किया जाता रहा है; इस प्रकार तानाशाही शासन को ही कायम किया जाता है ।”¹

हर युग अंतर्राष्ट्रीय सबंधों की अपनी व्यवस्था पैदा करता है । ममकालीन अवधि में, जबकि मजदूर वर्ग और उसके मित्र सामाजिक विकास की प्रभावकारी शक्ति बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतांत्रिक सिद्धांत पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं । लेनिन ने लिखा—“उस पुरानी दुनिया के मुकाबले, जो राष्ट्रीय दमन, राष्ट्रीय कलह और राष्ट्रीय पृथक्ता की दुनिया है—मजदूर एक नए संसार का प्रतिरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ऐसे संसार का जो सारे राष्ट्रों के श्रमिक जनसमूहों की एकता का संसार होगा, एक ऐसे संसार का जिसमें विशेषाधिकार नहीं होंगे, आदमी के द्वारा आदमी का दमन नहीं होगा ।”² यह आधारभूत सिद्धांत-सूत्र मजदूर वर्ग की विदेश नीति के सार तत्त्व को ही अभिव्यक्त करता है और साफतौर पर स्थायी, लोकतांत्रिक शांति की सचमुच की कारगर गारंटियों को

1. कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, “जर्मनी की विदेश नीति” संकलित रचनाएँ, खंड 7, पृ० 165

2. वी० आई० लेनिन, “मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय प्रश्न” संकलित रचनाएँ, खंड 19, पृ० 92

परिभाषित करता है।

साफ़तीर पर दिखाई देता है कि शांति सामाजिक प्रगति से अलग नहीं की जा सकती। जैसे ही सामाजिक रूपांतरणों की आवश्यकता परिपक्व हो जाती है वह उनके लिए प्रवेश द्वार खोल देती है। किसी भी देश के विकास के ठोस रास्ते का एकमात्र निर्णायक जो उसे परिभाषित कर सकता है, और करना चाहिए, वह है वहां का जनगण जिसके पास सर्वसत्तात्मक अधिकार है कि वह स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करे और इसमें किसी बाहर के हस्तक्षेप को घुसपैठ न करने दे। न तो क्रांति का निर्यात, न प्रतिक्रान्ति का निर्यात, और न ही राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप—यह वह मोड़ है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक स्थायी व्यवस्था का भवन खड़ा किया जा सकता है। मात्र यह प्रवृत्ति मानवता को शांति, सुरक्षा और सहयोग की परिस्थितियों के अंतर्गत आगे की सामाजिक प्रगति की असली संभावना एवं क्षमता प्रदान कर सकती है।

शांति, लोकतंत्र, सामाजिक प्रगति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समग्र अवधारणा को ध्वस्त किए बिना इस त्रयी में से एक भी तत्त्व को बाहर नहीं किया जा सकता। साफ़तीर पर यही वह धारणा है जिसे कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद की अंतर्राष्ट्रीय दादागीरी, लूट और हिंसा की नीति का प्रतिरोध करते हुए जवाबी नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह नीति समकालीन ऐतिहासिक युग की आवश्यकताओं के समाधान के रूप में उदित हुई है और मजदूर वर्ग और समाजवादी हिराबल दस्ते की बिना पर घोषित की गई है। यह धारणा ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधारभूत कानूनों का पूरा विश्लेषण करती है और उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कामों का—जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत मुख्य प्रेरक शक्तियों से संबंधित हैं—अपने में समावेश करती है।

इसकी ठोस अभिव्यक्ति राज्यों के शांतिपूर्ण सह-संस्तित्व की नीति में होती है चाहे उन राज्यों की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्नता ही क्यों न हो। जैसा कि विश्व के दो व्यवस्थाओं में विभाजित होने से पहले ही लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं—'यूरोप के संयुक्त राज्यों के लिए नारे पर (1915)' और 'सर्वहारा क्रांति सैनिक कार्यक्रम (1916)' में सैद्धांतिक आधार पर इसे मूलबद्ध कर दिया था।

साम्राज्यवादी युग की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए लेनिन इस नतीजे पर पहुँचे कि आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में विषमता होने के कारण समाजवाद कुछ देशों अथवा किसी एक देश में ही पहले-पहल विजयी हो सकता है। फलस्वरूप समाजवाद और पूंजीवाद के समानांतर अस्तित्व का इतिहास की कमेबिश संधी अवधि तक कायम रहना संभव और स्वाभाविक दोनों ही हैं।

जहाँ तक हम अवधि में भिन्न व्यवस्थाओं वाले राज्यों के आपसी संबंधों का

सवाल है, 'शांति संबंधी आज्ञप्ति'—जोकि सोवियत राज्य की विदेशनीति से संबंधित पहला दस्तावेज है—मे मजदूर वर्ग की स्थिति को साफ़तीर पर प्रतिपादित कर दिया गया था। इसे लेनिन ने निर्धारित किया था और समाजवादी क्रांति की विजय के बाद दूसरे दिन अर्थात् 8 नवंबर 1917 को अखिल-रूसी सोवियत कांग्रेस में इसे स्वीकार कर लिया गया था। सोवियत सरकार ने सभी युद्धरत राज्यों और राष्ट्रों का आह्वान किया कि वे बिना किसी लेनदेन, और समा-मेलन तथा अर्थदान के न्यायसंगत जनतांत्रिक शांति की स्थापना के सदर्भ में वार्त्ता-लाप चालू करें। इसमें सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया था और विशेष तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के मजदूर वर्ग का और सभी सरकारों का। यह आज्ञप्ति सभी राष्ट्रों की समानता को मान्यता देने पर आधारित थी चाहे वे बड़े हो या छोटे और इसमें किसी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर किसी भी प्रकार के दमन को अस्वीकार कर दिया गया था। इसने विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नींव डाली।

अक्तूबर क्रांति द्वारा निरूपित इन सिद्धांतों ने, बिना अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि, अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। सोवियत राज्य अभी अस्तित्व में आते ही लेनिन द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत, निरंतर सोवियत विदेश नीति की आधारभूमि रहे हैं।

समाजवाद के विरोधी इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और उसके फलस्वरूप युद्ध की आतंक भरी अभिव्यक्ति का एक कारण, चाहे वह मुख्य कारण न भी हो, यह तथ्य ही है कि समकालीन दुनिया दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं में विभाजित है। यह खींच-तान किया हुआ आधारहीन तर्क है। यह या तो मार्क्सवाद की उनकी गलत समझ की वजह से है, या इस विषय में अपने अज्ञान को मार्क्सवादियों पर थोपने की उनकी इच्छा की वजह से है।

निस्संदेह, सोवियत राज्य का उदय, इसकी उपलब्धियाँ, विश्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का समेकीकरण क्रांति-कारी प्रक्रिया की गति देता है तथा मजदूर वर्ग के लोगों की चेतना के निर्माण को प्रेरित करता है—ये सब दुनिया-भर में वर्ग-संघर्ष को प्रेरित और तीव्रतर करते हैं। तथापि विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के सहअस्तित्व की नीति से इनका कोई वास्ता नहीं है। क्या हजारों वर्षों के मानव इतिहास की रक्तंरंजित युद्धों की शृंखला वस्तुतः विचारधारात्मक संघर्षों का ही परिणाम है? ये चाहे सैद्धांतिक प्रवृत्तियों में ढके हुए हों अथवा नहीं, उनका मुख्य कारण सदा से ही शोषक वर्गों की और अधिक दौलत मंद होने की लालसा रही है।

अनेक उदाहरण यह जाहिर करते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं और सिद्धांतों की भिन्नता ने राज्यों को एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व का निर्वहण

करने से नहीं रोका। हमारा कार्यक्रम कल्पनालोक से परे है—यह पूरी तरह राज-नैतिक क्रियाकलाप से परिपुष्ट हो चुका है।

समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति अविभाज्य हैं

विश्व-समाजवाद की सुदृढ़ता और हमारे इस ग्रह पृथ्वी पर समाजवादी दृष्टि-कोण का फैलाव कम-से-कम युद्ध के आतंक को तो तेज नहीं ही करते हैं, इसके विपरीत, समाजवादी देशों की विदेश नीति के आधार का निर्माण करने में यह विश्व दृष्टिकोण अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति को निर्धारित करता है और इस प्रकार यह एक शांति का कारक बन जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को पुष्टा करता है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राज्य की विदेश नीति की अलंघनीय आधारभूमि है। हेल्सिंकी सम्मेलन की अंतिम धारा में सजीव तथा व्यापक रूप से व्याख्यापित, यह सिद्धांत सोवियत गणतंत्र के नये संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है जिसमें कहा गया है—

“संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का आधार निम्नांकित सिद्धांतों का अनुपालन है—सर्वसत्तात्मक समानता; ताकत के उपयोग अथवा उसकी धमकी का पारस्परिक परित्याग; सीमाओं की अलंघनीयता का पालन; राज्यों की सीमा संबंधी अखंडता; झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा; आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप; मानवाधिकारों और मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति आदर; जनगणो के समान अधिकारों और अपनी नियति के आत्म-निर्णय का अधिकार; राज्यों के बीच में सहयोग; और सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों, और यू.एस.एस.आर. द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न कर्तव्यों को सुदृढ़ आस्था के साथ पूरा करना।”

यदि ये आधार सूत्र सार्वभौम मान्यता प्राप्त कर लें और सभी राज्यों के लिए निर्विवाद रूप से इनको विदेशी संबंधों का मानदंड समझ लिया जाय, तो लगभग 90 प्रतिशत तनाव के लिए उत्तरदायी कारण—जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिगाड़ते हैं—स्वतः समाप्त हो जायेंगे। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खड़ी होने वाली सर्वाधिक जलज्वार भरी राजनैतिक समस्याओं के शांतिपूर्ण निपटारे की विश्वसनीय गारंटी होगी।

जहाँ तक सोवियत संघ और दूसरे देशों का संबंध है, ये सिद्धांत उनकी सामाजिक व्यवस्था से सहज रूप से पैदा होते हैं। कारण यह है कि उन्होंने उन जड़ों को ही नष्ट कर दिया जो आक्रमण को पालती हैं : उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीवादी स्वामित्व को तथा उन ताकतों को जो उन्हें संगठित करती हैं—जैसे शोषक वर्गों को जो युद्ध में अपना हित समझते हैं और अपनी दौलत के साधनों को बढ़ाने

के उद्देश्य से दूसरे जनगणों को गुलाम बनाने में रुचि रखते हैं। इस अकेले सिद्धांत ने समाजवादी देशों को अन्य देशों के साथ उनके संबंधों के क्षेत्र में ऐसे विशिष्ट स्थान पर ला खड़ा किया है पिछली पीढ़ियों को जिसका ज्ञान तक नहीं था।

सोवियत संघ के जनगण तथा अन्य देशों के जनगण के हितों में आपस में, एक-दूसरे से कहीं भी टकराव नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत ये मूलतः एक-दूसरे से मेल खाते हैं। समाजवादी देशों और तमाम दुनिया के बाकी देशों के धार्मिक जन-समुदायों के बीच की सुदृढ़ एकजुटता वर्गहीन समाज के निर्माण के उनके समान लक्ष्य पर तो निर्भर करती ही है, दमन एवं आक्रमण का विरोध करने वाले साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की समान इच्छा पर भी आधारित है।

सोवियत संघ और दूसरे देशों, जहाँ मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियाँ सत्ता में हैं—ने अपने लिए कभी भी, और कहीं भी किसी प्रकार की खरस रियायतों की तलाश नहीं की। वे इस घात को पक्के तौर पर मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविक सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रणाली तभी बनाई जा सकती है जबकि सभी राष्ट्रों और राज्यों के बीच हितों का, चाहे वे बड़े हों या छोटे, अमीर हों या गरीब, औद्योगिक हों या विकासमान—पूरी तरह खयाल रखा जाए।

अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने और उसको लागू करने में समाजवादी देश अपने आपको पूरी तरह यथार्थ के ठोस विश्लेषण पर आधारित करते हैं न कि मनमाने लक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर। इससे वे इस योग्य हो जाते हैं कि वे प्रत्येक अवस्था की वस्तुगत आवश्यकताओं का लेखा-जोखा ले सकें और अपने आपको तदनुकूल कदम उठाने के लिए अभिमुख कर सकें।

समाजवाद की विदेश नीति सुसंगत एवं निरंतर गतिशील है तथा वह अक्सर-वादी टेढ़े-मेढ़ेपन की शिकार नहीं है। भिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले राज्यों के साथ अपने संबंधों में समाजवादी देश पर्याप्त लचीलापन काम में लेते हैं और जब आवश्यकता होगी है तो आपसी हित के मामलों पर समझौता करने से इन्कार नहीं करते। किन्तु इन समझौतों में किसी भी तरह से, तीसरे देशों की कीमत पर, खींच-तान करके, किसी प्रकार का लाभ उठाने की लालसा की गंध तक नहीं आती।

इतिहास में सोवियत संघ ही ऐसा पहला राज्य था जिसने साफ़-तौर पर अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की घोषणा की, वही वह पहला राज्य था जिनमें न तो कोई बात अपने देशवासियों से छिपायी और न ही दूसरे देशों के सोंगो से। इसके विपरीत, वह इन लक्ष्यों की अधिकाधिक जानकारी सारी दुनिया के धार्मिक जन-समुदाय को देने में हमेशा से ही अभिरुचि रखता रहा है। जितना अधिगम्य जनसमुदाय सोवियत विदेश नीति में परिचित होगा और उसके अगली उद्देश्यों को और अच्छी तरह समझेगा, उन अन्य देशों में उसके उतने ही अधिक पक्षधर हों

जाएँगे।

समाजवादी क्रांति समकालीन युग की वस्तुगत प्रक्रिया है। इसमें कम्युनिस्ट अपने इस विश्वास को गुप्त रहस्य बनाकर नहीं रखते कि आगे चलकर एक अवधि में पूँजीवादी व्यवस्था को एक वर्गहीन समाज के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। और स्पष्टतया इसलिए कि यह समाज के आंतरिक विकास की एक उपज है, जैसा कि लेनिन ने संकेत दिया कि कोई भी क्रांति किसी दूसरे देश में किसी आदेश या किसी ममझोते से फूटकर पैदा नहीं हो सकती।¹ यह एक प्रकार के जुए की तरह होगा कि सामाजिक परिवर्तन को कृत्रिम रूप से उत्तेजित किया जाए, बाहर से क्रांति को उभारा जाए या मानो उन्हें ताकत से धामे रखा जाए। जहाँ तक विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थितियों का संबंध है तो वे, जैसा कि सुशांत है, किसी भी देश में सरकार के वर्गीय सार तत्व को नहीं छूती। कम्युनिस्ट कभी और किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का फायदा नहीं उठाते कि दूसरे देशों के वर्ग-संघर्ष में हस्तक्षेप किया जाए, चाहे इसीलिए कि “कोई भी शक्ति पूँजीवाद को नष्ट नहीं कर सकती थी यदि इतिहास के द्वारा इसे निचोड़ा और नष्ट नहीं कर दिया होता।”²

इस प्रकार दीर्घकालिक लोकतांत्रिक शांति के लिए संघर्ष के कामों को मजदूर वर्ग के आजादी के संघर्ष के कामों के साथ जोड़ते हुए, समाजवाद की विदेश नीति वर्तमान क्रांतिकारी युग के मौलिक कानूनों के चहुँमुखी मूल्यांकन और इसकी वस्तुगत आवश्यकताओं पर आधारित होती है और प्रमुख संचालक शक्तियों के हितों को प्रतिबिंबित करती है। इसका अर्थ है कि समाजवाद के जन्म, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में उसकी विदेश नीति के सिद्धांतों के प्रवेश मात्र ने विश्व शांति के लक्ष्य को प्रथम बार विश्वसनीय आधार प्रदान किया है। समाजवाद हजारों वर्षों की आक्रामक और अंतर्राष्ट्रीय डकैती की नीति के मुकाबले प्रतिरूप के रूप में लेनिन द्वारा सार रूप में प्रस्तावित करता है—“युद्धों का अंत, राष्ट्रों में शांति, लूट और हिंसा की समाप्ति—यही है हमारा आदर्श।”³

छः दशकों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत राष्ट्र ने इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। समाजवाद की विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार के बतौर यह धारणा जो लेनिन द्वारा अक्टूबर क्रांति से पूर्व सूत्रबद्ध की गई थी—प्रमुख तत्व थी और सोवियत राज्य की उसकी

1. वी. आई. लेनिन—“मॉस्को की ट्रेड यूनियनों और फंक्टरी कमेटियों की चौथी कांग्रेस” संकलित रचनाएँ, खंड 27, पृ० 480

2. वी. आई. लेनिन, “युद्ध और क्रांति” संकलित रचनाएँ, खंड 24, पृ० 417

3. वी. आई. लेनिन, “क्रांति की समस्या” संकलित रचनाएँ, खंड 21, पृ० 293

पहली विदेश नीति के राजनैतिक उद्देश्य के रूप में उन्लिखित की गई थी। यह लेनिन की शान्ति आज्ञाप्ति थी। व्यावहारिक योजना के तौर पर। फिर भी, यह अवधारणा लम्बे अरसे तक सर्वहारा द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा करने के वाद भी विकसित नहीं की जा सकी।

इसके विपरीत, सोवियत गणतंत्र के आरंभिक वर्षों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने क्रियाकलाप को इस समझ पर आधारित किया कि साम्राज्यवाद के साथ नये सघर्ष अपरिहार्य बन गये थे। "हम युद्धों के एक कात्त में गुजर चुके हैं, और हमें दूसरे के लिए तैयारी करनी आवश्यक हो गई है" — लेनिन ने सन् 1920 में कहा था। उन दिनों दुश्मन में घिरे हुए उम नवजात समाजवादी राज्य ने युद्ध के प्रज्ज्वलित घेरे को तोड़ने तथा थोड़ी राहत प्राप्त करने पर सबसे पहले अपना ध्यान केन्द्रित किया। और जब तक वहाँ साम्राज्यवाद के साथ सशस्त्र संघर्ष की अनिवार्यता बनी रही, उसका काम दरअसल दम लेने की अवधि को यथासंभव लम्बा करने तक सीमित रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के इस सामान्य मूल्यांकन के महीपन को घटनाओं ने सही साबित कर दिया और उम विदेश नीति के सहीपन को भी जिसका कि पार्टी ने इस मूल्यांकन के आधार पर अनुसरण किया था।

अभी भी बहुत सा मार्ग तय करना बाकी था : सोवियत संघ में समाजवाद की संपूर्ण विजय को सुरक्षित करना था, द्वितीय विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद की आक्रामक ताकतों को पराजित करके गढ़ेड़ना बाकी था। यह अनिवार्य था कि सबसे पहले विश्व संघ पर शक्तियों के संतुलन को आमूलतः बदलकर समाजवाद के पक्ष में लाया जाय, इससे पहले कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे युग के व्यावहारिक कार्य के रूप में समाज के जीवन से युद्ध को बाहर निवालकर समाप्त करने के ऐतिहासिक काम को अजाम देने की व्यवस्था कर सके। इसके साथ ही यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि हमारे समय में समस्या का इस प्रकार का स्पष्ट प्रस्तुतीकरण वस्तुतः सामूची मानवता की सच्ची और विज्ञान आवश्यकता को मंजूरित करता है।

1. बी. आई. लेनिन, "सोवियतों की आठवीं अखिल-रूसी कांग्रेस" सङ्कलित पत्रिका, पृष्ठ 31, पृष्ठ 501।

आज का मूल मुद्दा

“युद्ध अथवा मानवता के अंत का प्रारंभ ।”

—जॉन बर्नास

युद्ध नई शक्ल में सामने आ रहा है

युद्ध और शांति की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए यह धुनियादी तौर पर जरूरी है कि अपने समय और इस युग की दो आधारभूत प्रक्रियाओं का जेखा-जोखा किया जाय : मजदूर वर्ग के मुक्ति और जन-सांघिक आन्दोलन का फैलाव तथा वैज्ञानिक नव प्राविधिक क्रांति का तीव्र विकास । दोनों तथ्य इस समस्या के प्रस्तुतीकरण और समाधान में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करते हैं ।

निस्संदेह, युद्ध सदा से ऐसी नीति रहा है जिमने कलम की जगह तलवार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । जब तक पूँजीवाद कायम है—इसके आक्रामक केंद्रों का राजनैतिक प्रवाह युद्ध के आतंक को अनिवार्यतः उत्पन्न करेगा ।

तथापि पिछले दिनो युद्ध एक नयी शक्ल में सामने आ चुका है, और युद्ध विरोधी शक्तियाँ इस हद तक विकसित एवं मजबूत हो चुकी हैं कि आज कोई भी आक्रमणकारी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनके प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकता । आक्रामक द्वारा कतिपय आर्थिक अथवा राजनीतिक लाभों की आशा करना एक बात है, जबकि शत्रु को हराकर रेगिस्तान, जो रहने योग्य भी न हो—पर कब्जा कर पाने की काल्पनिक संभावना की गणना करना एकदम दूसरी बात है । जब युद्ध विरोधी शक्तियाँ कमजोर, असंगठित और असुरक्षित हो तो यह एक बात है तथा तब एकदम दूसरी जबकि वे सैद्धांतिक एवं संगठनात्मक—दोनों आधारों पर स्वयं को संगठित करके समाजवादी देशों के समुदाय की शक्ति पर भरोसा करके सघर्ष चलाते हैं । यह भी एक बात है कि जबकि विगत समय में, तमाम भयानकताओं, अत्याचारों, सकटों और कष्टों—जो अनिवार्य रूप से युद्धों के साथ उभरते हैं—के

बावजूद, उनमें से कुछ “प्रगतिशील थे अर्थात् उन्होंने हानिप्रद और प्रतिक्रियावादी संस्थाओं के नष्ट करने में मदद करते हुए मानवता के विकास को लाभ पहुंचाया।”¹ और आज यह एकदम दूसरी बात है जबकि उन समस्याओं, जो इस समय की और भविष्य की पीढ़ियों के सामने दिखाई दे रही हैं, का चरित्र इतना बदल चुका है कि कोई भी सैनिक सघर्ष उन्हें हल नहीं कर सकता। इन समस्याएं कारकों में वस्तुतः युद्ध की भूमिका को ही बदल दिया है तथा समाज के जीवन में इसके स्थान को भी।

सबसे पहले हमें समस्या के वैज्ञानिक एवं प्राविधिक पहलू की जांच कर लेनी चाहिए। विगत दशकों और खासतौर से द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से तेजी से हुए आर्थिक विकास के फलस्वरूप इस क्षेत्र में चौकाने वाले परिवर्तन हो चुके हैं। एग्रेस्स ने लिखा है—“आर्थिक पूर्वापेक्षाओं पर स्पष्टतया सेना और नौसेना से अधिक कोई भी अन्य वस्तु निर्भर नहीं करती, हथियारबंदी, संरचना, संघटन, कार्यनीति और रणनीति ये सब राज्य के उत्पादन और संचार व्यवस्था की तत्कालीन अवस्था पर निर्भर करते हैं।”² पूंजीवाद ने एक ओर तो उत्पादक शक्तियों को बहुत ऊंचाई तक विकसित किया है—पूर्ववर्ती सामाजिक संरचनाएँ जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकती थी—वहाँ साथ ही सशस्त्र सेनाओं का आमूल पुनर्गठन भी अत्यंत व्यापक स्तर पर किया है।

दुनिया के नक्शे को ताकत के जरिए बदलने और उसे नये सिरे से बनाने के काम को अपने लिए निर्धारित करते हुए पूंजीवादी शक्तियों ने अपने सैन्य-संगठन में नये लक्षण पैदा किये हैं। अब सेनाएँ केवल युद्धकाल के लिए ही नहीं बढ़ायी जाती, किन्तु यह वृद्धि स्थायी और व्यापक हो गई है और नियमित सैनिकों से निर्मित होती है न कि भाड़े के सिपाहियों, भाड़े के सेनानायकों, भर्ती किये हुए लोगों से, जैसा कि पहले रिवाज था। पहले सेनाएँ सार्वजनिक अनिवार्य सैनिक भर्ती से निर्मित होती थी। उद्योगों और संचार साधनों का विकास उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप था। सैन्यवाद पूंजीवादी दुनिया का एकनिष्ठ साथी बन गया।

युद्धक्षेत्रों में सैनिक कार्रवाइयों का परिणाम अब नये हथियारों और नई रणनीतियों पर निर्भर करता है। एग्रेस्स की राय में सन् 1870-1871 का फ्रेंको-प्रशियन युद्ध युद्धकला में मोड़ का बिन्दु था। उन्होंने लिखा—“सर्वप्रथम, जो हथियार काम में लाये गये वे इतनी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं कि आगे की सारी प्रगति...आगे के सारे सुधार रणभूमि की दृष्टि से बहुत कम महत्व के रह जाते हैं। इसलिए इस दिशा में विकास का युग समाप्त हो चुका है। दूसरे, इस युद्ध ने सभी महाद्वीपीय शक्तियों को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि कठोरता के साथ

1. बी. आई. लेनिन, संकलित रचनाएँ, घट 21, पृष्ठ 299

2. एफ. एग्रेस्स, ह्यूमन मतघटन, पृष्ठ 200

प्रशा की सशस्त्र सैन्य प्रणाली अपनायी जाय और, इसके साथ ही सेना का ऐसा भार भी जो कुछ ही वर्षों में उनके विध्वंस का कारण बन जायगा।”

वस्तुतः सन् 1914-18 के प्रथम विश्वयुद्ध ने यद्यपि युद्धरत घटकों से सारे आणविक ससाधनों को अभूतपूर्व आयामों में एकत्रित करने की माँग की, तथापि उनकी सशस्त्र सेनाएँ फ्रँको-प्रशियन युद्धकाल की सेनाओं से कुछ मायनों में ही भिन्न थी तथा उनकी रणनीतियाँ व्यवहारतः अपरिवर्तित रही। सैन्य उपकरणों ने निस्सदेह एक कदम आगे बढ़ाया, किंतु यह परिवर्तन गुणात्मक न होकर मात्र परिमाणात्मक ही अधिक था। यद्यपि सेनाओं के युद्धाभ्यास और बारूद शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई, मूलतः नये किस्म के हथियारों—उदाहरण के लिए विपैली गैसों—की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। टैंक और विमानन युद्ध के अंतिम दिनों में ही दिखाई दिये। युद्ध में फौजों की कार्रवाई अपेक्षाकृत तग अग्रिम-दस्ते के स्तर पर केंद्रित रहती थी जो देश की नागरिक आबादी से साफ़तौर पर असंग होती थी।

समय के परिवर्तन के साथ, हथियारों का और अधिक आधुनिकीकरण हो जाने से और खासतौर से विमानन के विकास के कारण युद्ध अपने मँदानी चरित्र को न्यूनाधिक खोने लगा। वायुध्वंसकों के घने जाल, पर्वतीय मार्ग, रेडियो स्टेशन और सभी प्रकार के भीतरी और बाहरी सैन्य-प्रकृति के संचार साधनों की उपलब्धि मोर्चे के आगे और पीछे की पारंपरिक अवधारणा पर आघात करती है। और जब द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ तो इसने मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक के लाखों लोगों को तत्काल अपनी खूनी भँवर में फँसाकर उनका खून घूस लिया।

सबसे पहले द्वितीय विश्वयुद्ध ने इस बात को जाहिर किया कि गत दो दशकों में हथियारों के विकास में कितनी बड़ी तरक्की हुई। सेनाओं का यात्रिकीकरण, तोपखाने की बारूद शक्ति में वृद्धि, राकेट छोड़ने वाले तोपखाने का प्रकट होने और बैलिस्टिक और क्रूज प्रक्षेपास्त्रों के प्रथम नमूनों का दिखाई देने और वायुसेना के व्यापक उपयोग ने लाखों लोगों के लिए और भी बड़े संकट को पैदा कर दिया।

जब द्वितीय विश्वयुद्ध का अंत हुआ तब तक और भी भयंकर जनसंहारक हथियार दुनिया की देहलीख पर प्रकट हो चुके थे। एटम बम के नाम से ज्ञात इस हथियार का विस्फोट युद्ध के आखिरी दिनों में हिरोशिमा पर डाल कर किया गया था।

आणविक शस्त्रों तथा इनके छोड़ने के तरीकों के विकास ने युद्ध की पारंपरिक धारणा तथा उसकी प्रकृति में आमूल-मूल बदलाव ला दिया। आगे-पीछे की मोर्चा-बंदी, फौज और नागरिक जनसंख्या की प्रचलित धारणाएँ, रणनीतियों और

कार्यनीतियों के साथ 'मैदानी युद्ध' आदि सब आणविक विस्फोटों में भस्म हो गये और अब सैनिक इतिहास के सग्रहालय में रखे जा सकते हैं।

प्रमुख अमरीकी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री पॉल क्रॉसर ने ठीक ही कहा है, कि आणविक प्रक्षेपास्त्र रूपी नये हथियार के उदय के साथ ही सैनिक उपकरणों का विकास एक निश्चित दिक्कत रेखा के पार चला गया है। जो कोई देश आणविक-प्रक्षेपास्त्र की चपेट में आयेगा वह पृथ्वी की सतह में साफ़ हो जायेगा।

न केवल ताप-नाभिकीय युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण है, किंतु सैनिक क्रिया-कलाप का सम्भावित रास्ता भी है। यह कई दृष्टियों से आवश्यक है, जिसमें स्वभावतः नीनिगत उपकरण के रूप में आधुनिक युद्ध का मूल्यांकन भी शामिल है।

पश्चिम में, डेरे साहित्य है जिसमें आणविक युद्ध के खतरों को चित्रित किया गया है। इसके निकृष्टतम मृत्यु-परक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक बार छिड़ जाना पर यह सामाजिक जीवन को तत्काल विखंडित कर देगा, जिससे संचार साधन, यातायात और उत्पादन शून्य बिन्दु तक पहुँच जाएँगे। प्राचीन कालीन किलेबंदी का स्थान राडार चौकियाँ ले लेंगी जोकि समूचे क्षेत्र को घेर लेंगी। दबे-दबे आणविक मिसाइल छोड़ने वाले उपकरण उपयोग के लिए तैयार हैं, और कोई भी राष्ट्र नहीं जानता कि कौन कब उस पर हमला करने वाला है। सभी प्रक्षेपास्त्रों और प्रति-प्रक्षेपास्त्रों से, आक्रामक और प्रत्याक्रामक दोनों रूपों में हथियारबंद है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई आबादियों पर रासायनिक-क्षत्नीकी युद्ध लड़े जाएँगे तथा उनकी आवाज पृथ्वी के लोगों तक नहीं पहुँच सकेगी। समय-समय पर एक आक्रमणकारी आणविक मिसाइल अपने लक्ष्य को धीरती हुई निकलेगी और तब चाहे लदन हो, पेरिस हो या न्यू यॉर्क—वह धूल और धुएँ का विशाल गुब्बार बनते हुए बाहर किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ जाएगा। अब कोई भी युद्ध विशारद संभवतः नहीं जान सकता कि मैदान में और उससे ऊपर सीमा के आर-पार क्या हो रहा है, कौन रक्षात्मक है और कौन आक्रामक। युद्ध की अनवरत संकटमय हलचल जारी रहेगी जब तक कि अंतिम प्रयोगशाला छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं उड़ा दी जाएगी इत्यादि। आणविक विभीषिका इस प्रकार के डरावने के चित्र जो अत्यधिक बारीकी से खींचे गए हैं—निस्संदेह आतंकपूर्ण प्रभाव पैदा करते हैं।

आणविक हथियारों के युग में वे युद्ध की सर्व-सत्यानाशी प्रकृति को रेखांकित करते हुए ये चित्रण इस विचार को भी उद्घाटित करते हैं कि समकालीन विकास के फलस्वरूप अस्त्र-शस्त्र मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। भूतकाल में कोई भी राजनीतिज्ञ और सेनानायक युद्ध में जाकर, संभावित त्रुटिपूर्ण गणनाओं और

भूलों के वावजूद, इसके परिणामों का मूल्यांकन कर सकता था और सुनियोजित क्रियाकलापों के लिए मार्ग-दर्शन कर सकता था। वह हमेशा घटनाओं में हस्तक्षेप भी कर सकता था और यदि आवश्यक होता तो सैनिक कार्यवाहियों के जारी रहने को रोक सकता था। आधुनिक हथियार इस संभव को एकदम कठिन या नितांत असंभव भी बना देते हैं। किसी जिन को बोटल से बाहर निकाल दिया जाय तो वह स्वयं अपनी जिन्दगी जीने लगता है। और यह अकारण नहीं था कि ब्रिटेन के भौतिकी वैज्ञानिक और चिंतक जॉन बर्नास ने मही वक्त पर चेतावनी दी कि एटम बम का विकास "या तो युद्ध के अंत के आरंभ को, या मानवता के अंत को चिह्नित करता है।"¹

आणविक हथियारों के विषय में इतना ही काफ़ी है। उनका विकास कई दशकों से चल रहा है : उनकी विनाशक क्षमता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत से देशों के शास्त्रागार फ़िलहाल हथियारों के भयानक ज़ख़ीरे बने हुए हैं। हथियारों की दौड़ को तत्काल नहीं रोका गया तो दुनिया के संभावित हालात की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता।

इतना होने पर भी सैन्य-औद्योगिक समूह हठपूर्वक तथा हृदयहीनता के साथ अपनी आणविक-प्रक्षेपास्त्र क्षमता की वृद्धि को जारी रख रहा है, तथा अन्य जन-संहारक और विध्वंसक साधनों की खोज में लगा हुआ है। हथियारों की नित नई क्रिस्मे और नए तरीके पैदा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

उस समय जबकि हिरोशिमा और नागासाकी विध्वंस की आग में जल ही रहे थे और आणविक बमबाजी के शिकार रेडियेशन की कणता से मर ही रहे थे, फ़्रांसीसी जनरल चासिन एक नरभक्षी प्रस्ताव लेकर सामने आया। उसने लिखा—“आज तक, युद्ध लोगों के मारने का एक कमख़ोर साधन साबित हुआ है। यदि इस सङ्घित-युद्ध में तीन करोड़ रूसी लोग अपनी जिन्दगी खो भी बैठें—जिसकी सभावना की जाँच हम कर चुके हैं—तो भी अन्य पन्द्रह करोड़ बच जाएँगे और दस सालों में उनकी जनसंख्या फिर पहले के स्तर पर पहुँच जाएगी। अब, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि युद्ध का कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जो इमारतों को नुकसान पहुँचाए बिना लोगों को मारना संभव बना दे, किन्तु फिर इसी के साथ इस बात की सभावना भी न रहे कि बचे हुए लोग उनका उपयोग कर सकें। निश्चय ही, इसका तरीका रेडियोधर्मी बादलों का उपयोग ही हो सकता है। निस्संदेह, वर्तमान में यह तरीका पूरी तरह विकसित नहीं हो सका है और, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वह यह कि, इसका प्रयोग बहुत व्ययसाध्य है। तो भी, इसके विषय में गंभीरता से सोचा जा रहा है।”²

1. जे० डी० बर्नास, 'वर्ल्ड विदाउट ए वार' सदन, 1958, पृ० 7

2. जॉन बॉमोयर के 'डे डिस्टन्स ए टू मैन' पेरिस, 1950, पृष्ठ 97 से उद्धृत।

मैन्य-श्रीयोगिक समूह के रणनीतिज्ञ जीवाणविक हथियार के विकास को बढ़ाने के लिए भी बड़े लालायित हो रहे हैं। सचमुच, सन् 1972 में जीवाणविक (जीववैज्ञानिक) और जीवविप्रेने हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के निमित्त एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया और उसमें हस्ताक्षर लिये गए, और तब से इस पर सौ से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। किन्तु पश्चिम में बहुत से राजनैतिक सट्टेबाज अब भी जीववैज्ञानिक हथियारों के विकसित करने पर जोर देते हैं। हाल के वर्षों में जीवशल्य के क्षेत्र में सफलताओं के बाद ये समस्याएँ फिर से सार्वजनिक ध्यानाकर्षण की वस्तु बन गई हैं, जो अनेक ऐसी संभावनाएँ पैदा करती हैं जिनमें उत्पत्ति संबंधी विकास की अमीम संभावनाएँ खुली हैं, और साथ ही यह संभावना प्रबल होती जाती है कि एक अवयव के जीस को दूसरे अवयव के सैल में प्रत्यारोपित कर जीवाणु को 'पुनर्निर्मित' किया जाए।

वैज्ञानिकों की माँग है कि इस क्षेत्र में होने वाली शोध पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। पश्चिमी जर्मनी के पत्र 'स्टर्न' के वैज्ञानिक टिप्पणीकार अलरिक शिपक इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि किस प्रकार जेनोआ के व्यापारियों द्वारा यूरोप में अचानक प्लेग के कीटाणु ले आने से सन् 1348-1350 की महामारी तेजी से फैल गई और उसने सारे महाद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध से भी अधिक विनाश की चपेट में ले लिया। उनकी टिप्पणी के अनुसार—“शोधकर्ता इस मनहूस संभाव्यता से अधिकाधिक घबरा रहे हैं कि वे स्वयं परख नली में जीवाणु के निर्माण के जरिए सारी दुनिया में छूत फैलाकर उसे नष्ट करने का निमित्त बन सकेंगे। मनुष्य को परेशान करने वाले एक सौ साठ विभिन्न प्रकार के जीवाणु ऐसे हैं जिनका परिणाम रोग और मृत्यु होता है। हाल ही में वैज्ञानिक नये कीटाणुओं को संयुक्त करने की स्थिति में भी आ गए हैं जिनको उन्होंने स्वयं ने अदृश्य सूक्ष्म जीवित अवयवों की इस विविधता में पैदा कर दिया है। वे जीस के साथ परिचालित कर उन्हें सुधारते हैं और इस प्रकार जीवित कृत्रिम अवयवों को प्राप्त करते हैं”। इसके प्रतिफल के रूप में जो वस्तु अस्तित्व में आती है, वह इतनी नई है कि वैज्ञानिक स्वयं इसके विषय में भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं कि वे क्या बनाएँगे।”¹

अब हम जिस स्थिति में हैं वह बड़ी विचित्र है : प्रकृति के ऊपर आदमी की जितनी बड़ी शक्ति है, वह अपने हित में उसका उपयोग करने में उतना ही अधिक असमर्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण दिया जा रहा है। बहुत वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन चेचक से लड़ता आया है और अब

इसके प्रयास लगभग उन्हें सफलता का सेहरा पहनाने को है। सन् 1976 की वसंत में दुनिया भर में केवल चेचक के 13 रोगियों के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि औपधियों के आविष्कार से पूर्व इस छूत की बीमारी से लाखों की जिन्दगी नष्ट हो जाती थी। ये सब रोगप्रस्त इथोपिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। यदि और कोई मामले दर्ज नहीं किए गए तो सन् 1978 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यह घोषणा कर देगा कि दुनिया भर में चेचक का पूर्ण उन्मूलन हो गया। यह विज्ञान की महान विजय है।

किन्तु आज जब बहुत से देशों के डाक्टरों के पास उपयोगार्थ टीके की दवाइयाँ और सर्वाधिक आधुनिक तकनीकी साधन हैं—जिनमें हैलिकॉप्टर, देश पार के वाहन—और साथ ले जाए जा सकने वाले रेडियो आदिके साधन हैं—तथा वे इथोपिया के पहाड़ों में चेचक से लड़ रहे हैं (बहुत से विशेषज्ञों का विश्वास है कि वह इस रोग का पालना है), उधर पश्चिम में प्रयोगशालाएँ कृत्रिम रूप से अब अधिक भयंकर कीटाणुओं को करोड़ों लोगों को मारने के लिए तैयार कर रही है। क्या यह हमारे युग का विरोधाभास नहीं है?

जबकि कुछ वैज्ञानिक भयंकर कीटाणुओं और सैन्यवाद के बीच के अशुभ सह-मेल के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं, पश्चिम में ऐसे वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ हैं जो फ़िलहाल इसके संभावित लाभों का मूल्यांकन कर रहे हैं। लॉर्ड रिची-काल्डर, जो हथियारबंदी में ब्रिटेन के विशेषज्ञ हैं, का विश्वास है कि बहुत-सी बातों में छूतरोग एटम बम की अपेक्षा अधिक वांछनीय होगा। क्योंकि मौतों की संख्या की दृष्टि से यह आणविक हमले की आसानी से बराबरी कर सकता है और इसमें खर्च भी कम होता है।

पश्चिमी अनुमानों के अनुसार लगभग 2500 करोड़ डालर हथियारों के शोधकार्य पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं तथा उक्त कार्य में 400,000 इंजीनियर और शोधकर्त्ता लगे हुए हैं।¹ और, निस्संदेह ये विशाल प्रयत्न शुद्ध मानवीयता को दृष्टिगत रखकर नहीं किए जा रहे।

पश्चिमी राजनीतिज्ञों द्वारा वास्तविक या सभाव्य शत्रु को हानि पहुँचाने के निमित्त पर्यावरण को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने की व्यक्त संभावना को केवल वैज्ञानिक परिकल्पना मात्र नहीं समझा जा सकता। 'मौसम विज्ञान जन्म युद्ध' के विषय में चर्चा है, दुश्मन पर आक्रमण करने के साधनों के विकास के रूप में कृत्रिम भूकंपों, समुद्री तूफ़ानों, बवंडरों और विनाश तरंगों आदि पर काम हो रहे हैं। और अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ के धनत्वों की भारात्मक अस्थिरता पर नज़र है

1. निःशस्त्रीकरण या विनाश? अस्वीकरण और निःअस्वीकरण, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान, स्टॉकहोम, 1975, पृष्ठ 8

कि यदि उनको पिघला दिया जाय, चाहे अंशतः ही सही, व गतिशील कर दिया जाय और महामागर में घकेल दिया जाय तो दुश्मन की सीमा एक भयानक वाढ की चपेट में आ जाएगी। दरअसल, समकालीन हथियारों की दौड़ में संलग्न उन्मत्तों की मनोकल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है।

विज्ञान एवं प्रविधि द्वारा सभव बनाए गए अवसरों के अपराधपूर्ण दुरुपयोग के अतिरिक्त जनसंहार की समस्त प्रायोजनाओं का एक सामान्य लक्षण है जो उनकी मुख्य कमजोरी भी है : ये सब सभ्यता को चिनाश तथा मानवता को विध्वंस की ओर ले जाएंगे, वजाय किसी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के। जनसंहार के हथियारों के नए प्रकार और नई प्रणालियाँ, विश्वव्यापी और अनियंत्रित जनसंहार के हथियार (दोनों प्रकार से—सोघे परिणामों की दृष्टि से और विशेषतया उनके निष्कर्षों के दृष्टिकोण से) आवणिक युद्ध की तुलना में चाहे मात्रा में उससे भी अधिक घातक क्यों न हों—विदेश नीति के महत्वपूर्ण यंत्र नहीं रह गए हैं। नीति के अन्तर्गत के रूप में हटकर वे चिनाश के साधनों में बदल रहे हैं।

पश्चिम में यथार्थवादी विचारों के लोग इस स्पष्ट निष्कर्ष की अपेक्षा नहीं कर सकते। स्वयं जनरल डगलस मैकार्थर जिन्हें अन्य किसी अमरीकी सैन्य कमांडर की तुलना में जापान पर मिराए गए परमाणु बम के नतीजों को देखने का अधिक उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ था, ने संयुक्त राज्य अमरीका की सेनेट को बताया—“महानुभावो, मैं आपको बताता हूँ कि इसने उन मूलभूत धारणाओं को ही अवैध घोषित कर दिया जिनके आधार पर युद्ध को अंतिम आदेश के रूप में अपनाया जाता था, जब अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने में राजनीति असफल होती थी। अब उसकी असफलता इसमें अंतर्निहित हो गई है।”¹

निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि सामान्य समस्त सैनिक जुओं के विरुद्ध कभी भी पर्याप्त प्रभावकारी गारंटी नहीं रही। और यह सच भी होगा, किंतु यह भी सत्य है कि कोई भी राजनीतिज्ञ, जो वस्तुगत तथ्यों को स्वीकार करता है, ताप-नाभिकीय महाविपत्ति के आतंक की उपेक्षा नहीं कर सकता।

इससे यह नतीजा निकलता है कि जब हथियारों का विकास एक निश्चित स्तर में ऊपर उठता है तो राजनैतिक स्थिति तदनुकूल परिवर्तित हो जाती है। विज्ञान एवं प्रविधि के वस्तुगत विकास की दृष्टि से एक समय आता है जब मानवता के सामने युद्ध के विरुद्ध युद्ध की अनिवार्यता पेश आती है। व्यवहार में ऐतिहासिक मंच पर यह नई स्थिति तब पैदा हुई जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका एक ‘आणविक गतिरोध’ की अवस्था में पहुँच गए, यद्यपि सिद्धांततः

1. सुदूर पूर्व में सेना की स्थिति, ‘विदेशी सबंधों पर समिति के नामने मुनवाइयों’, सं० रा० सीनेट, 82 कांफ्रेंस, प्रथम सत्र, भाग 1, वाशिंगटन, 1951, पृष्ठ 148

यह संभावना काफी पहले सामने आ चुकी थी।

क्लॉजविट्ज़ ने पहले ही इसे संभव मान लिया था कि हमिषारी की विनाशात्मक शक्ति के बढ़ने के फलस्वरूप राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति और युद्ध छेड़ने के साधनों के बीच अंततः दरार दिखाई देगी। उन्होंने लिखा—“यदि युद्ध राजनीति का एक भाग है, तो परिणामतः यह उसके गुण-धर्म को भी ग्रहण करेगा। राजनीति की महिमा एवं शक्ति में वृद्धि के साथ युद्ध भी उसी पथ का अनुसरण करता है; और यह वृद्धि उस ऊँचाई तक पहुँच सकती है जब युद्ध की छवि निरंकुश बन जाय।”¹ दूसरे शब्दों में, युद्ध अपने ही नियमों के अनुसार जीना शुरू कर देता है राजनीतिक सीमाओं में जिसकी संगति नहीं बैठती।

अपने संस्मरणों में नादेज़दा क्रुसकाया ने लेनिन के इस सुप्रसिद्ध वक्तव्य को उद्धृत किया है—“आज आधुनिक उपकरण तेजी के साथ युद्ध के विनाशात्मक चरित्र को बढ़ाते हैं। लेकिन एक समय आयेगा जब युद्ध असंभव हो जायेगा।”² वर्तमान पीढ़ियाँ इस काल के उस बिंदु तक पहुँच चुकी हैं या अभी पहुँच रही हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह अभी से स्पष्ट है कि जन-विध्वंस के आधुनिक साधनों (जो संख्या में तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार बिन्दु पूर्णता तक पहुँचाया जा रहा है) ने मानव के सामने यह विकल्प रख दिया है या तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या आत्मविध्वंस।

फिर भी, जो विशेष महत्वपूर्ण है वह यह कि हमारे समय में यह सिद्धांत अब कोई अमूर्त नैतिक श्रेणी का विचार नहीं रहा, किंतु समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करने वाले राजनैतिक तथ्यों में उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ये हालात बड़ी मात्रा में मौजूदा दुनिया के जनमत को निर्धारित करते हैं, शांति के लिए संघर्ष में व्यापक जनप्रयासों को प्रेरित करते हैं और बहुत से पश्चिमी राजनीतिज्ञ भी औपचारिक रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के समर्थन में एक बड़ी दलील के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के भूतपूर्व विदेश मंत्री हेनरी किस्सिंजर ने कहा—“रणनीतिक आणविक संतुलन के युग में— जब दोनों पक्ष सभ्य जीवन को बरबाद करने की क्षमता रखते हैं, तो सह अस्तित्व का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी स्थितियों में शांति की आवश्यकता अपने आप में एक नैतिक आदेश है।”³ और जैसाकि अमरीकी राष्ट्रपति जॉन केंनेडी ने इसे व्यक्त किया था कि अंतिम निष्कर्ष के रूप में जो सूत्र हमें सबको जोड़ता है वह यह

1. बॉम क्रीड, हिटरलैंड वर्क इस अनरब्स कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज़, एंटीटर्ट डेक् डब्लू वॉन सेर्फ, ड्रेसडन 1885' पृ. 567

2. एन के क्रुसकाया, लेनिन के संबंध में 'मॉस्को' 1966' पृ. 40-41 (रूसी भाषा में)

3. द न्यूयॉर्क टाइम्स, जुलाई 16, 1975

है कि हम सब इस छोटे से ग्रह के निवासी हैं। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सबको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। और हम सब मरणशील हैं।

मभी अमरीकी प्रतिनिधियों के सोचने का तरीका यही नहीं था। एक ऐसा समय था कि वे अपनी आणविक इजारेदारी का उपयोग सोवियत संघ को डराने के इरादे से करते थे और समूची दुनिया पर अपने आधिपत्य के दम को 'न्याय संगत' करार देते थे। समाजवाद को शक्ति के इस असंतुलन को ठीक करना पड़ा। यह तब हुआ जब सोवियत संघ ने अपने स्वयं के आणविक और हाइड्रोजन हथियारों का विकास कर लिया। साधनों के स्फुरण और इसके फलस्वरूप युद्ध के चरित्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रयासों को भी संशोधित किया।

शान्तिकामी शक्तियों के पक्ष में : तनाव-शैथिल्य को दृढ़ समर्थन

महत्वपूर्ण होते हुए भी यह तथ्य अपने आप इस मुद्दे को समाप्त नहीं कर देता। लोगों के जीवन से युद्ध का निष्कासन बहुत बड़े प्रयासों की माँग करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना आवश्यक है जहाँ उन शक्तियों की बात में दम हो, और उन्हीं की चले भी जो तात्कालिक मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं और वैसा करने की योग्यता भी रखती है।

कम्युनिस्टों को पक्का भरोसा है कि ऐसा समय आयेगा जब दास-स्वामित्व प्रणाली व्यवस्था की भाँति युद्ध भी अतिजीवित रहकर समाप्त हो जाएँगे। तब और अधिक युद्ध नहीं होंगे। यह आस्था दुनिया के विकास की कम्युनिस्ट संभावना से पैदा होती है, जिसके लक्षण वर्तमान युग में स्पष्टतया दिखाई देने लगे हैं—आज की ठोस वास्तविकताओं के रूप में।

दरअसल, आज उन देशों—जहाँ मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता है, और जो युद्ध की पहल क़तई नहीं करते—की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दृढ़ भूमिका लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। उनके कार्य व्यापार का अर्थ एवं अंतर्वस्तु, सामाजिक, आर्थिक सैद्धांतिक तथा अन्य लक्ष्यों का समुच्चय—उन्होंने यह सब युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के अनिवार्य आह्वान के लिए व्यवस्थित किया है। अपने प्रयासों को केवल रचनात्मक कामों पर ही केंद्रित करते हुए, समाजवादी देशों ने शांति के लिए मजदूर वर्ग के संघर्ष के इतिहास में एक नये बुनियादी अध्याय की शुरुआत कर दी है। और आज यह मात्र मानवीय लक्ष्य ही नहीं है, किंतु समाज की वस्तुगत ऐतिहासिक आवश्यकता भी है। इतिहास में पहली बार पूर्णतया एक परिस्थिति का विकास हो चुका है जिसके तहत दूसरे लोगों के खिलाफ आक्रमण हमेशा के लिए प्रतिवर्धित किया जा चुका है, तथा बहुसंख्यक राज्यों के राजनीतिक शस्त्रागार से निष्कासित किया जा चुका है—उन देशों की आंतरिक व्यवस्थाओं तथा उनके विकास के वस्तुगत नियमों के अनुरूप।

समाजवादी समुदाय और इसकी घरेलू और विदेशी नीतियाँ दुनिया भर की नैतिक और राजनैतिक स्थिति पर अपना असर बढ़ाती चली जा रही है। समाजवाद ने राजनैतिक संघर्ष के सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पेश किये हैं जैसे कि शोषण की समाप्ति और सब प्रकार के शोषण तथा राष्ट्रीय दमन का उन्मूलन, असली जनतंत्र की प्राप्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपलब्धि, तथा मानव की भलाई के लिए विज्ञान और प्रविधि की उपलब्धियों का उपयोग। ये मुद्दे आधुनिक पीढ़ियों की ऐतिहासिक प्रगति के लिए केंद्रीय महत्व के हैं। फिर भी, समाजवाद ने व्यवहार में उतारकर दिखा दिया है कि इन कामों को कैसे पूरा किया जा सकता है।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने यह प्रस्तावित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुसंगत जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर टिका हुआ होना चाहिए। उन्होंने व्यवहार में यह दिखा दिया है कि शांति को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना है तथा उनकी सुरक्षा और जनगण के सहयोग को कैसे प्रबल बनाया जाना है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस में रखी गयी केंद्रीय समिति की रिपोर्ट में महासचिव एल० आई० ब्रेझनेव ने इस बात पर जोर देते हुए कहा—“आज समाजवाद दुनिया भर के अरबों लोगों के विचार और उनकी भावना पर जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। यह श्रमिक लोगों को उनकी स्वतंत्रता उनके सच्चे जनतांत्रिक अधिकार, उनका कल्याण, व्यापकतम संभव ज्ञान और सुरक्षा की एक सुदृढ़ चेतना को प्रदान करने का भरोसा दिलाता है। यह शांति सभी देशों की सर्वसत्ता के प्रति सम्मान की भावना और ममान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जन्म देता है अपनी स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के लिए संघर्ष में जनगण की सहायता में स्तंभ की भूमिका अदा है। निकट भविष्य में समाजवाद की असीम क्षमताओं एवं संभावनाओं का निस्संदेह रूप से उदय होगा जो पूँजीवाद की तुलना में उसकी ऐतिहासिक श्रेष्ठता को प्रमाणित कर देंगी।”

पूँजीवाद पर समाजवादी ताकतों की बढ़ती हुई प्रबलता, और विश्वक्रांतिकारी प्रक्रिया का तेज विकास समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को रूपांतरित कर रहे हैं। यह तथ्य सामाजिक-वर्गीय प्रेरणाओं के मजबूत होने, जनसमूह की भूमिका के उच्चतर होने में तथा जनसमूह की सामान्य जनतांत्रिक लक्ष्यों की ओर अभिमुखता में अभिव्यक्त होता है, तथा साथ ही सामान्य जनतांत्रिक लक्ष्यों व मुक्ति संघर्ष के लक्ष्यों, जोकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर श्रमिक वर्ग के लिए चुनौती बने हुए हैं, में भी व्यक्त होता है।

इजारेदार पूँजीवादी शासन के युग में जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पैदा हुए, पूँजीवाद के विभिन्न राष्ट्रीय दलों की ताकत के आधार पर ही उनका हल हो पाया।

और वह भी साम्राज्यवादी के आपसी अंतर्विरोधों की सीमाओं में आज दो व्यवस्थाओं के संघर्ष की स्थिति में तथा मुक्ति आंदोलन की मुख्यधारा में विकसित ये अंतर्विरोध एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक-वर्गीय अतर्वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में उत्पन्न संकटों के काल में न केवल एक दूसरे राज्य के हित आपस में टकराते हैं। (यद्यपि स्वभावतः उन्हें नकारा नहीं जा सकता), किंतु अनिवार्यतः प्रगतिशील विश्व शक्तियाँ और प्रतिगामी ताकतें भी टकराती हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न यह ही नहीं कि शोषक आपस में स्थान बदल रहे हैं बल्कि शोषण की प्रणाली की स्थितियों को ही बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधारणतया यह केवल किसी एक या दूसरे राष्ट्र की आजादी का ही प्रश्न नहीं है, अपितु सामाजिक प्रगति की संभावना का सवाल भी है।

विगत दशकों का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष वियतनाम की लड़ाई का था जो एक विचारणीय बिंदु है। वे कौन-सी शक्तियाँ थीं जो वहाँ एक-दूसरे के आमने-सामने थी और उनके उद्देश्य क्या थे? वास्तव में दुनिया की प्रतिगामी शक्तियों और प्रगतिशील ताकतों के बीच के एक ऐतिहासिक संघर्ष का दृश्य हिन्द चीन में घटित हुआ, यह उपनिवेशवाद और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बीच का संघर्ष था और यह पूँजीवाद और समाजवाद के बीच का संघर्ष था। वियतनामी लोग अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़े तथा वे अपनी चुनी हुई समाजवादी प्रणाली के लिए लड़े। वियतनाम की मजदूर पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव ले हुआन ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस में कहा—“हमारी पार्टी ने दो झंडों को ऊँचा उठाया, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांति का झंडा और दूसरा समाजवादी क्रांति का झंडा, तथा हमारी सारी जनता को संघर्ष में उतारने के लिए राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन को समाजवादी शक्ति के साथ एक प्रवाह के रूप में संयुक्त कर दिया। इसने राष्ट्र की शक्तियों को हमारे समय की क्रांतिकारी शक्तियों के साथ जोड़ दिया, आंतरिक शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ जोड़ दिया और दुश्मनों की क्रतारों के विभिन्न अंतर्विरोधों का लाभ उठाया। इस प्रकार आक्रामक के ऊपर विजय हासिल करने के लिए एक विशाल संगठित शक्ति पैदा कर दी।”¹

दक्षिण-पूर्व एशिया में जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दोस्तों ने वियतनामी लोगों को समाजवादी उपलब्धियों को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, जबकि मध्य-पूर्व में साम्राज्यवाद अरब देशों के प्रगतिशील शासनों को समाप्त करना चाहता है; अंगोला में जहाँ प्रतिक्रियावाद ने उस नव गणतंत्र के आंतरिक मामलों में एक सशस्त्र हस्तक्षेप किया, और इसी तरह बहुत से दूसरे

अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो हमारे समय में हो रहे हैं तथा जिनमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक-वर्गीय संघर्ष की उस अंतर्वस्तु को महसूस कर सकता है जो ठोस स्थितियों के मुताबिक विभिन्न रूपों में व्यक्त होती हैं।

इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विरोधों की गाँठें और भी अधिक उलझ रही हैं, बाहरी हस्तक्षेप का जनप्रतिरोध बढ़ रहा है और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक विरोधों को हल करने के लिए सैनिक उपकरण जो सामाजिक विरोधों से गुंथे हुए होते हैं, कम-से-कम उपयोग योग्य बनते जा रहे हैं।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्गीय प्रकृति की ताजा तुष्टि तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया में मिलती है। समाजवाद के पक्ष में प्रभावित संतुलन को और अधिक बदल जाने के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य विश्व की सामाजिक प्रगति का परिणाम भी है और भावी विकास के लिए प्रेरणादायक तत्त्व भी। आवश्यक रूप से इसका मतलब यथास्थिति के बना रहना नहीं है और न यह क्रांतिकारी संघर्ष को बाधा नहीं पहुँचा सकता, जैसा कि कई बार जोर देकर कहा जाता है, किंतु इसके विपरीत इसका अर्थ राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की व्यापक संभावनाओं के द्वार खोलना है। यह निर्विवाद है कि तनाव-शैथिल्य के विरोधी, वस्तुगत स्थिति को अनदेखा करके, इस पर स्वयं की व्याख्या थोपने के प्रयास करते हैं कुछ इस बात पर आमादा हैं कि वे इसे 'क्रैमलिन चाल' की संज्ञा दें, एक ऐसी 'एकमार्गी सड़क' कहे जिस पर चलने वाले लोग एकमात्र समाजवाद की ओर ही अग्रसर होते हैं, आदि।

विश्व की प्रगतिशील शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य को अच्छे-पड़ोसी-संबंधों को स्थापित करने के शक्तिशाली साधन और आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करने के उपाय के रूप में मानती हैं। इस दिशा में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के विषय पर आयोजित हेलसिंकी सम्मेलन के सर्वसम्मत समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तनाव-शैथिल्य की गतिशीलता विभिन्न कारणों के कारण हर जगह एक जैसी नहीं है। किंतु हर बात इसके सकारात्मक नतीजों को सुरक्षित रखने और गुणात्मक वृद्धि को मद्दे नज़र रखते हुए की जानी चाहिए। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा—“हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य को प्राप्त करने में बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़े हैं। इसी तरह तनाव-शैथिल्य की संचित पूँजी को सुरक्षित रखना भी आसान नहीं है। किंतु कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा हमें वापिस लौटने को मजबूर नहीं कर सकती। शांति को शाश्वत और अविनाशी बनाने के लिए किए गये काम की तुलना में कोई भी अन्य कार्य अनिवार्य, आवश्यक और महान् नहीं हो सकता।”

शांति दरअसल अविभाज्य है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य इसे मजबूत करता है। इस विषय में पूंजीवादी सिद्धांतकारों द्वारा अटकलबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। तथ्य स्वयं बोल रहे हैं।

यूरोप में यह सभी को ज्ञात है कि, अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य की स्थिति में ही समाजवादी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और अधिक मजबूत किया, जर्मन जनवादी गणतंत्र—जर्मनी की भूमि पर दुनिया के प्रथम मजदूरों और किसानों के राज्य ने—अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त की, सोस में काले कर्मियों का किला बह गया, पुर्तगाल में फ्रांसिज्म को शिकस्त दी गयी, सेना ने चारों ओर राजनैतिक परिवर्तन की एक नयी लूफानी लहर चल पड़ी, और प्रगतिशील ताकतों ने फ्रांस, इटली व अन्य देशों में नयी व बड़ी जीते हासिल की।

स्वभावतः यह कोई निरा सयोग ही नहीं था कि तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया का उदय हुआ और यूरोप में ही इसका विकास हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आंदोलन का पालना तथा समाजवाद का जन्मस्थान रहा है। दो विश्वयुद्धों की त्रासदी से उबरकर और फ्रांसिज्म के मुकाबले विजय हासिल करके यूरोप के लोग म्यूनिख समझौतावादियों की समर्पणवादी नीति को नहीं भूल सकते, तथा हमेशा ओरेइयोर और कोवेन्ट्री, ब्रूकेनवाल्ड और ओस्विस्सिम को सदा याद रखेंगे।

यही नहीं, यूरोपीय राज्य—अन्य महाद्वीपों के किसी भी देश की तुलना में दुनिया के बाकी भागों से जिनके हजारों आर्थिक, व्यापारिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संपर्क हैं—वे इस ग्रह पर होने वाले परिवर्तनों पर अपनी प्रतिप्रिया व्यक्त करने वाले पहले राज्य हैं।

एशिया में यह तनाव-शैथिल्य के युग में ही हुआ कि वियतनामी लोगों ने अपनी मातृभूमि की संपूर्ण स्वाधीनता और उसके एकीकरण के संघर्ष में निर्णायक जीत हासिल की। लाओस के लोक जनतांत्रिक गणराज्य और जनवादी कम्पूचिया का निर्माण किया गया।

अफ्रीका में तनाव-शैथिल्य के युग में ही इस महाद्वीप में औपनिवेशिक साम्राज्यों के अंतिम अवशेष समाप्त हुए तथा नये स्वाधीन राज्यों का समूह—अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी-बिसाऊ—अस्तित्व में आया।

सभी महाद्वीपों से, हर जगह, तनाव-शैथिल्य सामाजिक प्रगति के साथ-साथ चलता है। आधुनिक यथार्थ के दोनों तत्व बहुधा एक-दूसरे की परिपूर्ति करते हैं और उनको सुदृढ़ करते हैं।

‘एक जमाना था जब कई सदियों तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष प्रायः स्थानीय महत्व के हुआ करते थे तथा तीसरे देशों के हितों को ये सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करते थे। इस परिस्थिति ने अनेक ‘पृथक्तावादी’ नीतियों को बढावा दिया और बहुत से

मामलों में तीसरे देशों के विरोधों का लाभ उठाने का तथा उनमें झगडा कराने का लालच प्रस्तुत किया। आज कोई भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति वास्तव में पृथक् नहीं हो सकती, और कोई भी विस्फोटक संघर्ष विश्वयुद्ध की धमकी से कम नहीं माना जाता।

दोनों विश्वयुद्ध इस बात के चौकाने वाले प्रमाण हैं। तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बढ़ते हुए दायरे, और सबसे बढ़कर, सत्यानाश करने वाले विश्वव्यापी तापनाभिकीय युद्ध के आतंक ने देशों तथा जनगणों की पारस्परिक निर्भरता को वस्तुगत रूप से गहनतर बना दिया है। वस्तुतः सभी देशों की विदेशनीतियाँ पारस्परिक हितों और विरोधों के अविभाज्य समुच्चय का निर्माण करती हैं।

आज कोई भी विरोध या संघर्ष अनिवार्यतः विश्वनीति के अन्य स्नायु केंद्रों को प्रभावित करता है। कोई यदि सोवियत संघ और अमरीका के बीच के सशस्त्र संघर्ष की कल्पना करता हुआ उसे 'दो चीतों' की लड़ाई कहे, जैसा कि राजनैतिक लोक कथा में कहा गया है, जिसमें एक बाहरी दर्शक पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ सुरक्षित रूप से युद्ध को देखता दिखाया गया है, तो ऐसा करना यथार्थ की अपनी समस्त समझ एवं चेतना को खोना होगा। यह मानना अधिक तर्कसंगत होता कि यदि आक्रामक तीमरे विश्वयुद्ध को भड़काने की कोशिश में सफल हो गये तो उसे किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर सीमित रखना असंभव होगा।

'आक्रमण को मोड़ देना', 'सीमित सशस्त्र संघर्ष' और 'स्थानीय युद्ध' जैसी धारणाएँ भूतकाल के गर्भ में जा रही हैं, वापस कभी नहीं आएँगी। वास्तव में, अब यह अधिक आसान है कि तलवार को वापस म्यान में डालने की बजाय उसे क्लम की जगह रख दिया जाए। और जॉन फुलर की यह चेतावनी निर्विवाद रूप से तर्कसंगत थी—'बुराई बुराई को पैदा करती है, और यदि तुम सैमसन की तरह अंधे हो जबकि तुम अपने दुश्मन के घर के खंभों को नीचे गिरा देते हो, तो इसके खंडहर तुम्हें कुचल देंगे।' ¹ जब हर वस्तु इस तरह आपस में जुड़ी हुई है कि केवल एक ही चिनगारी सारे विश्व को जलाकर महा अग्निकुंड में बदल देगी—ऐसी स्थिति में केवल विश्वशांति ही लोगों की असली सुरक्षा गारंटी हो सकती है।

विश्व राजनीति के अग्रिम मोर्चे पर जन शक्तियों का उभार

इन परिवर्तनों का कारण और तदनुरूप परिणाम, वह बढ़ी हुई भूमिका है जो विशाल जनसमूहों के द्वारा अदा की जाती है। पहले शोषक देशों का विशिष्ट शासक वर्ग जनसमुदाय के बिखराव और उसकी राजनीतिक अज्ञानता का उपयोग, उनकी पीठ के पीछे से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सवाल का समाधान निकालने और उन पर अपनी इच्छा लादने के लिए किया करता था। आज इस प्रकार के किसी

उपाय को अपनाना एक कालदोष कहलाता है। सोवियत गणतंत्र पहला देश था जिमने उस गोपनीयता को तोड़ दिया जो कभी विदेश नीति को घेरे हुए होती थी। इसने ज़ार सरकार द्वारा की गयी गुप्त संधियों को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया और ऐसी कूटनीति को जन्म दिया जो सोवियत लोगों और विश्व के जनगणों दोनों के लिए खुले रूप से जाहिर हो। शांति मंवंधी आज़ाप्ति के वादविवाद को समेटते हुए लेनिन ने कहा था "हम किसी प्रकार की रहस्यात्मकता नहीं चाहते। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमेशा अपने देश के जनमत के सीधे निरीक्षण में काम करे।"¹ यह गुप्त कूटनीति पर उसको तोड़ने वाली चोट थी। विदेशनीति, पेशेवर विशिष्ट वर्ग के संकीर्ण दायरे का क्षेत्र नहीं रही। राष्ट्राध्यक्षीय पहलों और मंत्रियों के दफ़्तरों से पैदा होने वाली नीतियाँ मड़कों पर आ गईं, इन्होंने नए आयाम ग्रहण किए और वे सब लोगों के सरोकार बन गईं।

आज करोड़ों श्रमिक लोग न केवल राजनैतिक मामलों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, अपितु कारगर ढंग से प्रभाव डालने में समर्थ भी हैं। 8 नवम्बर सन् 1917 को शांति के विषय में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लेनिन ने कहा—“हमें ‘‘जनगण को युद्ध और शांति के प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने देने के लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी।’’² आज यह उद्देश्य एक यथार्थ बन चुका है, तथा इसने अन्य मामलों के अतिरिक्त हाल के वर्षों में शांति आंदोलन द्वारा अर्जित दायरे में अभिव्यक्ति पाई है।

इस आंदोलन का इतिहास स्वयं इस तथ्य को उजागर करता है। युद्धोत्तर शांतिनायकों का आंदोलन एक ऐसी विशाल हलचल के परिणामस्वरूप पैदा हुआ था जिसके दौरान आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान की स्टॉकहोम अपील पर पचास करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। औपचारिक रूप से यह आंदोलन अप्रैल 1949 में पेरिस में आयोजित कांग्रेस में शुरू हुआ था। शांति योद्धाओं का अपनी अगली कांग्रेस एक साल बाद शैफ़ील्ड में करने का इरादा था। लेकिन ब्रिटेन की लेबर सरकार ने, जिसके प्रधान क्लिमेंट एटली थे—उसकी इजाज़त न दी। उस निर्णय के पीछे क्या कारण थे? सब प्रकार की व्याख्याएँ प्रसारित की गईं: कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस में ‘पर्याप्त प्रतिनिधित्व’ का अभाव था, अन्य कुछ लोगों का आरोप था कि इस कांग्रेस में विभिन्न प्रश्नों पर इसका नज़रिया ‘पूर्वाग्रह पूर्ण’ होने की संभावना थी, कुछ अन्य लोगों के लिए यह एक ‘कम्युनिस्ट अभियान’ था। जनता को भड़काने वाली ये चालाकियाँ उतनी

1. बी. जार्ड, लेनिन 'द्वितीय अखिल रूसी मजदूरों और सैनिक डेप्यूटीज़ की कांग्रेस', सक्तित रज़नाए', खंड 26, पृष्ठ 254

2. वही, पृष्ठ 252

महत्वपूर्ण नहीं थी, जितना कि यह कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ग्रेट ब्रिटेन के शासक गिरोह ने शांति आंदोलन के लक्ष्यों के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने को राजनैतिक दृष्टि से श्रेयस्कर एवं उपयोगी माना। बहुत अरसे के बाद जब उसकी सारी थोथी दलीलें चुक गईं, तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया वैज्ञानिक फ्रेडरिक जूलिएट-व्यूरी को डोवर में गिरफ्तार कर दिया गया तथा उन्हें देशनिकाला दे दिया। बाद में वह कांग्रेस कारसा में संपन्न हुई।

इसके ठीक दो दशक बाद में शांतिकामी शक्तियों का विश्व सम्मेलन माँस्को में (अक्टूबर 1973 में) संपन्न हुआ। वस्तुतः इसमें विश्व के शांतियोद्धाओं की उस एकजुटता का प्रतिनिधित्व व्यक्त हुआ। जो बहुत से दूसरे आधुनिक जनतांत्रिक आंदोलनों के साथ कायम हो चुकी थी। यद्यपि जनतांत्रिक आंदोलन शांति के संघर्ष के समस्त विचारों को उसी रूप में नहीं अपनाते, तो भी वे इसके प्रस्तावकों को सहयोग देने की इच्छा रखते हैं। माँस्को कांग्रेस में एक हजार से अधिक राष्ट्रीय पार्टियों, संगठनों और आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 143 देशों और 120 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस मंच पर यह इतना व्यापक प्रतिनिधित्व था कि अपने सामाजिक सम्मान की परवाह करते वाला कोई विरला ही ऐसा राजनेता होगा जो शांति आंदोलन के प्रति खुल्लम-खुल्ला एक ऐसा नकारात्मक दख अपनाने का दुस्साहस करे जैसा कि पच्चीस साल पहले क्लिमेंट एटली ने अपनाया था।

वर्तमान में शांति शक्तियों के आंदोलन के आयाम विशाल हो गए हैं और उनमें सचमुच ही जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है किन्तु इसके पारिमाणिक परिवर्तनों की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन और अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य रूपरेखा के अनुसार ये हैं—पहला, समकालीन शांति आंदोलन सारे समाजवादी समुदाय के शक्तिशाली भौतिक आधार और उसकी सक्रिय विदेश नीति पर भरोसा करता है; दूसरा, आज, पहले से कहीं अधिक यह एक संगठित शक्ति के रूप में काम करता है जिसके पास सार्वभौम लोकतांत्रिक शांति के लिए एक ममान मंच है; तीसरा, इसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के पूरे विश्लेषण पर आधारित स्पष्टतया परिभाषित कार्यक्रम है।

ये सब तथ्य शांतिप्रिय शक्तियों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जीवन के स्वरूप को संशोधित करते हैं। उनमें अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य की ओर क्रमिक अभिमुखता और बदलाव का कारण प्रमुख रूप से अंतर्निहित है। जैसे-जैसे यह प्रक्रिया संचल होती जाती है, जनतांत्रिक लक्ष्य और श्रमिक लोगों की मुक्ति के बीच का घनिष्ठ अंतःसंबंध—घरेलू मामलों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में—दोनों में तेजी से मुखर होता जाता है। कमोवेश सभी अवधि तक अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखते हुए सामान्य जनतांत्रिक, राष्ट्रीय मुक्ति और दूसरे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन

जनसमुदाय को, क्रमशः समाजवाद को चुनने की ओर ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे समय में जनतांत्रिक आंदोलन ने अपने जनाधार को व्यापक करने के लिए अतुलनीय बड़े अवसर प्राप्त किए हुए हैं और साथ ही ये आंदोलन बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वहारा के द्वारा किए जाने वाले संघर्ष के नजदीक आ रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समाजवाद ने अपने लिए युद्धों को रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया है। (जो वास्तव में सामान्य लोकतांत्रिक मार्गों का हिस्सा है) और, इसके साथ ही सारी मानवता को, पूंजीवाद से समाजवाद के रूपांतरण के लिए सर्वोत्तम संभव पूर्वपेक्षाओं को प्राप्त करने के निमित्त स्वयं को प्रयत्नशील बना रखा है। आज की परिस्थितियों में उस पूंजीवाद को विवश करने का प्रश्न है, जो हमेशा बाहर प्रसार करने की नीति का अनुसरण करता है, ताकि लोगों के उस अधिकार को मनवाया जा सके जिसके तहत स्वयं के भविष्य के विषय में स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, यह आज के युग के प्रमुख वर्गीय अंतर्विरोध के समाधान की संभावनाओं का प्रश्न है अर्थात् मजदूर और पूंजी के बीच का, और बिना ताप-नाभिकीय युद्ध के भावी सामाजिक प्रगति का प्रश्न है—शांति के हालात में परिवर्तन की समस्या का एक प्रश्न।

लियोनिद ब्रेझनेव ने नोट किया था—“सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा इस बात को माना और अब भी मानती है कि दो व्यवस्थाओं—पूँजीवाद और समाजवाद के—के बीच का संघर्ष आर्थिक, राजनैतिक तथा वैचारिक क्षेत्र में भी जारी रहेगा। यह अपेक्षित ही है समाजवाद और पूँजीवाद के वर्गीय दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हैं तथा इनमें मेल संभव नहीं है। किन्तु हम ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य इस संघर्ष को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ देंगे जो युद्ध के विध्वंसों से मुक्त हो, जो खतरनाक युद्धों से दूर हो तथा जो एक अनियंत्रित हथियारों की दौड़ या होड़ से परे हो।”¹

साम्राज्यवाद ने अपने तर्क अपनी विदेश नीति की मुख्य दिशा के आर्थिक, राजनैतिक और वैचारिक क्षेत्रों में समाजवाद के विरुद्ध संघर्ष में बदल रखा है। फिर भी, विश्व समाजवाद का अस्तित्व ही साम्राज्यवादियों को मजबूर करता है कि वे सामान्य रूप से अधिक सचेत हों और विस्तार के युद्ध जैसे उग्रवादी रूप को टाल दें। शक्तिशाली प्रगतिशील ताकतों द्वारा हमला किए जाने पर तथा अपनी ताकत को मोर्चाबंदी में लगाने से पहले वह इस तथ्य पर गौर अवश्य करता है। कुछ दशकों पूर्व तक साम्राज्यवादी शक्तियों के शासक गिरोह अपने विरोधों को युद्ध से सुलझाने का साहस करते थे। यदि सोवियत संघ और समाजवादी समुदाय नहीं

1. एल. आई. ब्रेझनेव, ‘लेनिन के मार्ग का अनुसरण करते हुए’ मॉस्को, 1975 पृष्ठ 94-95

होता तो पूंजीवादी शक्तियाँ, विशेषतया संकटों के दौर में, हथियारों की ताकत से दुनिया का पुनर्विभाजन करने की पुनः कोशिश कर सकती थी। अब यह एकदम असंभव है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच के संघर्ष के साथ यदि तुलना की जाए तो साम्राज्यवादी खेल के आंतरिक अंतर्विरोध गौण महत्व के हैं। फलस्वरूप, समाजवाद पहले से ही अपना प्रभाव न केवल पूंजीवादी देशों के साथ सीधे संबंधों के क्षेत्र तक बढ़ा रहा है, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से, उनके आपसी संबंधों तथा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जीवन को भी प्रभावित कर रहा है।

शांतिपूर्ण सहयोग की बढ़ती हुई आवश्यकता

एक अन्य कारक का उल्लेख करना आवश्यक है : अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा पहले कहीं अधिक व्यापक तथा अधिक समावेशी हो रही है। आज, जबकि मजदूर वर्ग का मुक्ति संघर्ष वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति की पृष्ठभूमि का परिप्रेक्ष्य विकसित हो रहा है, पुरानी 'शास्त्रीय कूटनीति' की सीमाएँ अधिक-से-अधिक सिकुड़ती चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में ऐसी नई बड़ी समस्याएँ प्रविष्ट हो रही हैं, मानवता जिन्हें साझे प्रयास के जरिए अधिक तर्कसंगत श्रमविभाजन और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना करके ही सुलझाने में सक्षम होगी। यह बात व्यापार, विज्ञान और सांस्कृतिक सम्पर्कों और क्षेत्रीय तथा विश्व के पैमाने पर संयुक्त प्रायोजनाओं के विकास पर भी लागू होता है।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने शांतिकामी शक्तियों के विश्व सम्मेलन में दिए गए भाषण में इस मुद्दे को बहुत साफ़ तौर पर सामने प्रस्तुत किया—“व्यापार ने जनगणों और देशों को अति प्राचीन समय से जोड़ रखा है। हमारे समय में भी यही सच है। किन्तु आज आर्थिक सहयोग को सिर्फ़ व्यापार तक सीमित रखना अलाभकारी एवं अतार्किक ही माना जाएगा। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति की आवश्यकताओं और क्षमताओं को समान आधारों पर बाँट लेने और समय के साथ-साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए एकमात्र आधार व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन का लागू करना है। मैं कहूँगा कि अब यह स्वतः सिद्ध है। इसलिए पारस्परिक लाभदायक दीर्घकालिक और प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों रूपों में, नितांत आवश्यक है। निस्संदेह यह केवल यूरोप पर ही लागू नहीं होता, अपितु सभी महाद्वीपों, तथा आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था पर लागू होता है। एक अन्य कारण जिसकी वजह से हम ऐसे सहयोग की वकालत करते हैं, यह है कि हम इसे राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंध को भरपूर मजबूत करने का विश्वसनीय साधन मानते हैं।¹

1. एल. आई. ब्रेझ्नेव, 'लेनिन के मार्ग का अनुसरण करते हुए' मॉस्को, 1975. पृष्ठ 311-313

पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण, ऊर्जा स्रोतों की समस्या का समाधान, प्राकृतिक बिपत्तियों, महामारियों और व्यापक रूप से फैली हुई बीमारियों के खिलाफ संघर्ष बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और विश्व महासागर की संपदाओं और बहुत-सी विश्वव्यापी समस्याओं की खोजबीन और उनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली के संशोधन के लिए आह्वान करती है। उनका तुरंत समाधान पहले से ही सारी मानवता के हित में है, तथा उनका महत्व निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इनमें से कुछ समस्याएँ तो ऐसी हैं जो हाल ही में मानवता के सामने उपस्थित हुई हैं, जबकि दूसरी कुछ बहुत विकट हो चुकी हैं तथा अब वे और अधिक समय तक समाधान की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि समाज की उत्पादक शक्तियों के समकालीन विकास से उत्पन्न होना की वजह से वे इसकी बुनियादी आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती हैं और बहुत-सी बातों में सारे ग्रह के भविष्य को निर्धारित करती हैं।

इन समस्याओं को सुलझाने की ऐतिहासिक आवश्यकता उस संघर्ष के साथ मेल रखती है जो दरअसल आर्थिक मंचों की समूची व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए किया जा रहा है। यह दुनिया में अधिक समतावादी अर्थव्यवस्था कायम करने का प्रश्न है ताकि वह उस असमानतापूर्ण व्यवस्था का स्थान ग्रहण कर सके जो देशों को अति विकसित और अविकसित—जैसी असम्मानजनक श्रेणियों में विभाजित करती है तथा जो साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक प्रणाली की ही विरासत है।

साम्राज्यवाद के खिलाफ राजनैतिक आजादी के लिए दृढ़ संघर्ष—जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है—एशिया और अफ्रीका के युवा राज्यों द्वारा स्वतंत्रता हासिल करने के बाद राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष ने एक भिन्न प्रकार का चरित्र ग्रहण किया। अब आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सामाजिक रूपांतरण इसका मुख्य ध्येय है। राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के लिए उनके संघर्ष की इस अवस्था में विकासमान देशों को जो काम करने हैं वस्तुतः उनकी प्रकृति ही यह माँग करती है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमविभाजन में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। ये सिद्धांत व्यवहारतः विकासमान देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को सुनिश्चित करेंगे, और प्रमुखतया उनके प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करने के उनके संप्रभु अधिकार की गारंटी करेंगे।

यह एक बहुत बड़ा जटिल काम है जो एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों की नवउपनिवेशवादी व्यवस्था की बुनियादों से सीधा संबंध रखता है। इसके समाधान से साम्राज्यवादी आधिपत्य से जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उद्देश्य पूरा होगा। आकस्मिक नहीं है कि पिछले दशकों के अधिकांश सशस्त्र

संघर्ष अथवा स्थानीय युद्ध राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के क्षेत्र में ही भड़के। उनसे साम्राज्यवाद के उन प्रयासों की झलक भी मिलती है जिनका लक्ष्य किसी भी कीमत पर उनकी आजादी के सुदृढ़ीकरण की गति को धीमा करना था। वित्तु औपनिवेशिक प्रयामों का दादागिरी के प्रतिरोध एक दूसरी प्रवृत्ति के द्वारा किया जा रहा है—अर्थात् विकासमान देशों के द्वारा किए जाने वाले सक्रिय शांति-संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ताकि दुनिया में एक न्यायसंगत आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो सके। इस बात पर जोर देने के सभी आधार हैं कि यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जाएगी ज्यों-ज्यों एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के स्वतंत्र राज्य अधिकाधिक आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामाजिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे।

पश्चिमी यूरोप के देशों, उत्तरी अमरीका और जापान—जो कि विश्व पूंजीवाद के गढ़ हैं—में भी विप्लव जनसमूहों का जनतांत्रिक संघर्ष एक नई अंतर्वस्तु धारण कर रहा है। यह सावजनिक सक्रियता के पहले से अधिक व्यापक क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और मुक्ति आंदोलन के समाजवादी लक्ष्यों के साथ घनिष्ठता से गुंथता जा रहा है। औद्योगिक देशों में इजारेदारी विरोधी आंदोलनों के अग्रिम मोर्चे पर मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं। व्यापक जन-तांत्रिक और सामाजिक रूपांतरणों के उनके कार्यक्रमों में इजारेदारी के आधिपत्य को कुचलना और शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को आश्वस्त करना जैसी युनियादी माँगें हैं।

धक्काशाही का दिवालियापन

कठोर वर्ग-संघर्षों के दौर में विकसित होने वाले उपयुक्त परिवर्तन पश्चिमी रणनीतिज्ञों की इस बात के लिए मजबूर करते हैं, चाहे वे इसे पसंद करें अथवा नहीं, कि वे अपने पहले की कसौटियों और अनुमानों की समीक्षा करें और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए नए उपाय सोचें। इसकी अभिव्यक्ति अन्य बातों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की कोटि के रूप में शक्ति की अवधारणा के पुनर्मूल्यांकन में होती है।

इस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन के लिए वृज्वा राजनीतिक चिंतन को एक लंबे टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना पड़ा। सदियों से पूंजीवादी राज्यों ने अपनी विदेश नीति के लक्ष्य ताकत के जरिए प्राप्त किए हैं—या तो दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व थोपा है या स्वयं पर ऐसे आधिपत्य की संभावना के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इस परिस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति की विशेष धारणा को उभारा और किसी संबंधित राज्य की ताकत को एक विशेष अर्थ प्रदान किया। वस्तुतः यह सशस्त्र शक्ति के बराबर मान लिया गया। “बड़ी बटालियनें सदा ठीक होती हैं।” बहुत वर्षों तक पूंजीवादी देशों के मैनिक और राजनीतिक नेता नेपोलियन जिसने—‘शक्ति’ को

सैन्यशक्ति के समरूप मान लिया था—की इस सारगर्भित परिभाषा को, नितांत अकाट्य मानते रहे थे।

सिद्धांततः अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने संबंधी साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रयासों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कोई गंभीर परिवर्तन नहीं हुआ। यूं भी, प्राथमिकता के आधार पर सैन्यशक्ति का निर्माण, ताकि दूसरे देशों पर दबाव डाला जा सके, अपनी समस्त विविधताओं में वह बदनाम नीति थी जिसे 'जन प्रति-कार' की संज्ञा दी गई थी, तथा उन वर्षों में जिसे अमरीकी साम्राज्यवाद ने लागू करने की कोशिश की थी। इस समस्या के सिद्धांतिक अनुसंधानों के संबंध में वे इन्हीं धारणाओं के चक्र में घूमते रहे।

किसी राज्य की युद्ध की क्षमता के रूप में उसकी 'शक्ति' के निर्माण में कौन-कौन से घटकों का योग होता है इसे उस क्षेत्र के प्रसिद्ध अमरीकी अधिकारी हेस मोगेंथॉर्प ने चित्रित किया। तदनुसार ये घटक हैं : देश की भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता और सैनिक तैयारी—जिसमें शस्त्रीकरण के विकास का स्तर, सैन्य नायकों की प्रकृति और सशस्त्र सेनाओं की संख्या और उनकी कुशलता शामिल है। इनमें जनसंख्या और उसका राष्ट्रीय चरित्र (युद्ध के प्रति रुख) भी शामिल हैं, प्रचलित राष्ट्रीय रीति-रिवाज (सरकारी नीतियों के संबंध में रुख), और कूटनीति की कुशलता—जिसे देश की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है—आदि भी शामिल हैं। निष्कर्षतः "राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों द्वारा प्रत्यक्षतः राष्ट्रीय हित से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के मुद्दों पर अधिकतम प्रभाव डलवाने की कला" को भी ये अपने दायरे में ले लेते हैं।¹

फिर भी, जैसे समय गुजरा, यह फार्मूला यथार्थ के साथ एक स्पष्ट विरोध के रूप में सामने आया। विदेश नीति के मुख्य हथियार के रूप में सशस्त्र बल प्रयोग की परंपरागत धारणा अपनी प्रासंगिकता खोने लगी। और 'विशाल बटालियनों' की सर्वशक्तिमत्ता पर सबसे पहले संदेह प्रकट करने वालों में सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमरीका प्रमुख था।

शीत युद्ध के वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका ने हथियारों की दौड़ और जंगखोरी के सट्टे में 10,000,000 लाख डॉलर से ऊपर की विशाल धनराशि का व्यय किया। इसने महाविशाल युद्ध यंत्र का निर्माण किया, जैसा कि अन्य कोई देश आज तक नहीं कर पाया, और एक कल्पनातीत सैनिक क्षमता का निर्माण किया जो कि पृथ्वी पर से सारे देशों का सफाया करने में सक्षम है। किंतु क्या इससे दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ा, या क्या कम-से-कम इससे वह अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा कर सका? इस प्रश्न को इस बात के प्रमाण के रूप में

1. हेस जे० मोगेंथॉर्प, "राष्ट्रों के मध्य राजनीति, शक्ति और शांति के लिए संघर्ष", न्यूयॉर्क 1966 पृष्ठ 139

ही पेश करना पर्याप्त होगा कि हमारे युग में कइयों ने सशस्त्र सेनाओं के निर्माण का अर्थ यह मान लिया है कि इससे स्वतः राजनैतिक प्रभाव बढ़ जाता है।

यह सामान्य सत्य उस समय जाहिर हो गया जब वियतनाम में अमरीकी आक्रमण की पराजय के बाद सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राज्य अमरीका की शक्ति का किसी तरह यह अर्थ नहीं है कि वह सारी दुनिया पर शानेदारी या स्कूल मास्टरी कर सके।

वियतनाम में लगभग तीस साल तक लड़ाई चली। इसमें लगभग बीस लाख से अधिक जाने गईं, अन्य लाखों लोग अपंग हो गए और लाखों अपने पीछे अनाथ और शरणार्थी छोड़ गए, शहर और गाँव ध्वस्त हो गए तथा भूमि जहरीली बना दी गयी व क्षत-विक्षत कर दी गयी।

साम्राज्यवादी शक्तियों में पहले फ्रांस और बाद में संयुक्त राज्य अमरीका ने दुराग्रह के कारण हिंदचीन के जनगणों के स्वाधीनता अपनी पसंद की समाज व्यवस्था बनाने के उनके अधिकार को मानने से इनकार किया। संयुक्त राज्य अमरीका की महाविशाल सैन्य मशीनरी और पूँजीवादी विश्व की नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पर इसके परिणामस्वरूप आघात लगा।

संयुक्त राज्य अमरीका को वियतनाम पर हमला करने की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध में सरकारी आँकड़ों के अनुसार अमरीका का सीधा खर्चा 1,410,000 लाख डॉलर से ऊपर था। संयुक्त राज्य की वायुसेना ने 70 लाख टन से अधिक बम गिराए, या द्वितीय विश्व युद्ध में सभी मोर्चों पर पश्चिमी मित्र देशों के द्वारा जितना बम गिराया गया उससे तीन गुना से अधिक बम लंबे समय से पीड़ित हिंद चीन की धरती पर गिराए गए। यह भी याद रखने योग्य है कि सन् 1968 के अंत तक वियतनाम में संयुक्त राज्य अमरीका के इन सैन्य अभियान दलों में 580,000 से अधिक सैनिक भाग ले चुके थे।

इन प्रयासों का परिणाम सुपरिचित है। आज अधिकाधिक संख्या में राजनैतिक एवं लोक-नेता इस बात को मानने लगे हैं कि विदेश नीति के हथियार के रूप में सेना की ताकत अब प्रासंगिक नहीं रही। दरअसल, हमने दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रौजी हस्तक्षेप का न केवल परास्त होना देखा है, अपितु सन् 1947 में ट्रूमैन नीति के सहित लागू की गई अमरीका की विश्वनीति का दिवाला भी देख लिया।

वियतनाम युद्ध के सबक, और मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका के शासकीय गिरोह और दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा अपनाई गई सोवियत संघ के प्रति आणविक ब्लैक मेल की नीति की निष्फलता की बढ़ती हुई मान्यता ने इस आवश्यकता को बढ़ा दिया है कि विदेश नीति में सैन्य शक्ति की धारणा और उसकी भूमिका के स्थान पर दूसरे उपाय किए जाएँ। अमरीका के राजनैतिक

पर्यवेक्षक यह नतीजा निकालते हैं कि न तो अब, और न भविष्य में ही, सैन्य कुशलता और क्षमता को राजनैतिक लाभों की एकमात्र गारंटी मानी जा सकती है। अमरीकी विद्वान् राल्फ एन० बर्लो निम्नांकित अनुभव प्रकट करते हैं—“बड़ी ताकतों ने, कुछ हिचकिचाहट के साथ इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में सैन्यशक्ति की उपयोगिता घटती जा रही है।”¹ वह आगे नोट करते हैं कि बिल्कुल ऐसी संभावना है कि भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति कायम रहेगी, “दुनिया को अभी आगे के उस सैन्यशक्ति के पतन को और अधिक देखना है जिसे विदेश नीति के हथियार और दुनिया में सम्मान के मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।”²

अनेक पश्चिमी राजनीतिज्ञों ने इन विचारों को स्वीकार कर लिया है। उनका विश्वास है कि सैन्यशक्ति हमेशा राजनैतिक प्रभाव के बढ़ने की गारंटी नहीं होती। एक समय, कौड़ी ताकत में नगण्य होती भी ठोस राजनैतिक लाभ में रूपांतरित हो सकती थी किंतु अब यह असंभव है।

यह तथ्य बेहद लाक्षणिक है कि पश्चिमी राजनीतिज्ञ अब उस समीकरण चिह्न को हटा रहे हैं जिसे साधारणतया ‘शक्ति’ और ‘सैन्यशक्ति’ तथा ‘सैन्यशक्ति’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव’ के बीच लगाया जाता था। इसमें यह जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण पर क्रमशः जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इनका जितना अधिक क्रियान्वयन होगा, इनका उतना ही अधिक स्वागत होगा।

इस प्रकार ‘ताकत’ कूटनीति, पर आधारित जो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धक्काशाही या मुक्काशाही के रूप में लाई जाती रही है, दिवालियापन की ओर बढ़ रही है। यह अकाद्य तथ्य सभी क्षेत्रों में जाहिर होता है : वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति के विकास में, अथवा समाज के जीवन में सामाजिक-राजनैतिक रूपांतरणों में। दुनिया उस युग में पहुँच गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की माँग है कि विश्व की तत्कालिक आवश्यक समस्याओं को सलझाने के लिए नए मानदंड अपनाए जाएँ।

1. राल्फ एन० बर्लो, पूर्वी एशिया और संयुक्त राज्य मुरसा, वाशिंगटन, 1975, पृ० 1

2. वही, पृ० 70

अमिट शांति के आसार : मार्ग और प्रगाढ़ मैत्रियाँ

“क्या आप कृपा करके मुझे यह बताएँगी कि मैं यहाँ से किस ओर जाऊँ ?”

“यह तो इस पर निर्भर करता है कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो।”
बिल्ली ने कहा।

लैबिस कैरोल : “ऐलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड”

सैन्य-उद्योग समूह : मानवता के लिए एक चुनौती

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में 1970 का दशक शांतिप्रिय शक्तियों के पक्ष में गंभीर परिवर्तनों का काल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव शैथिल्य जो शान्ति के लिए संकल्पबद्ध जन-संघर्ष का प्रतिफल है—हमारे इस वर्तमान समय की अप्रगामी प्रवृत्ति बन चुकी है।

इन हालात में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी अपने शान्ति प्रयासों को पहले से अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान कर रही है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस ने शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा जनगणों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए आगे के संघर्ष के कार्यक्रम को सूत्रबद्ध किया। निःशस्त्रीकरण की समस्या उसका गर्भ है :

- हथियारों की दौड़ समाप्त करो;
- सभी आणविक हथियारों के परीक्षण बंद करो;
- रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाओ और उन्हें नष्ट करो;
- जनसंहार के हथियारों के नए प्रकारों और उनकी नई प्रणालियों के विकास पर प्रतिबंध लगाओ;
- सैनिक खर्चों में कटौती करो;
- अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सैन्य-शक्ति का उपयोग न करने की विश्व संधि

को अंतिम रूप दो।

ये ठोस मार्गें निःशास्त्रीकरण की समस्या को व्यावहारिक स्तर पर ले आती हैं और समस्त मानवता के लिए सही भावने में टिकाऊ शान्ति के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। जनसंहार के हथियारों से भरपूर इस दुनिया में इसके जरिए राजनैतिक तनाव-शैथिल्य से सैनिक-तनाव शैथिल्य की स्थिति में मानवता के रूपांतरण, सैन्यवाद पर अंकुश लगाने, युद्ध के भौतिक आधार को नष्ट करने और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की भरोसेमंद गारंटी के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

किन्तु शक्तिशाली ताकतें अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य का विरोध करती हैं। सैन्य-औद्योगिक समूह, जो सैन्यवादियों और कारखानेदार उत्पादक इजारेदारियों का अपवित्र गठजोड़ है, आज भी युद्ध के हथियारों पर लगातार जोर दे रहा है। साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद का प्रभावशाली गिरोह निरंतर पूँजीवादी देशों को आक्रामक कार्यवाही के लिए भड़काता है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के अनेक भड़के—जो दुनिया के कई हिस्सों में सुलग रहे हैं—किसी भी क्षण सशस्त्र संघर्षों के रूप में भड़क सकते हैं। कभी भी वे सैन्य मुठभेड़ों के रूप में, चाहे मध्यपूर्व में, साइप्रस में, अंगोला में या दूसरे क्षेत्रों या देशों में आग की लपटों में बदल सकते हैं। हमलावर ताकतें तनाव को और अधिक बढ़ा रही हैं, हथियारों की दौड़ को तेज कर रही हैं, लड़ाइयों को भड़का रही हैं और पुराने प्रतिक्रियावादी सैन्य शासनों को सहायता और समर्थन दे रही हैं।

1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। शान्ति काल में—और वह भी तब जबकि संयुक्त राज्य अमरीका के शासक और अन्य पूँजीवादी देशों के शासनतंत्र सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रहे थे कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य एक तथ्य है—संयुक्त राज्य अमरीका का सैनिक बजट द्वितीय विश्व युद्ध व कोरिया तथा वियतनाम के युद्धों के दौरान किये गये कुल सैनिक व्यय को पार कर गया। यह अमरीका के दो सौ वर्षों के अस्तित्व में की कभी इतना ऊँचा नहीं रहा और अब उसका रुझान स्पष्टतया और अधिक वृद्धि की ओर ही दिख रहा है। सन् 1976 में वह बजट 114 बिलियन डॉलर था, और वाशिंगटन की भविष्यवाणी के अनुसार 1980 तक 150 बिलियन डॉलर और सन् 1985 तक वह 200 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।¹

यदि तुलना की दृष्टि से एक लंबी अवधि को लिया जाय, तो हम पाएँगे कि संयुक्त राज्य और दूसरे पूँजीवादी देशों के सैन्य खर्चों में तेज वृद्धि की यह सामान्य प्रवृत्ति और अधिक वृद्धि की ओर सुनिश्चित रूप से मुखरित हो रही है।

इसका अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी स्थापना के बाद के 150 वर्षों में, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के वर्ष भी शामिल हैं, सैनिक उद्देश्यों (इस अवधि के अंतिम दशक में वह पहले से ही सफलतापूर्वक बाहरी प्रसार और सैन्यवाद में यूरोपीय शक्तियों में मुकाबला कर रहा था) पर 30 बिलियन डॉलर खर्च किए। सन् 1976 के आरंभ में प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सदस्य जॉन सिवलिंग (डेमो० ओहियो) ने कहा कि केवल पिछले तीन दशकों में ही, जबकि कहीं से भी संयुक्त राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं था, वाशिंगटन ने अपने भिन्न-भिन्न शस्त्रीकरण कार्यक्रमों पर 1.6 बिलियन डॉलर खर्च किए। ऐसे सभी संकेत हैं कि भविष्य में यह बक्र और अधिक ऊँचाई तक पहुँच जाएगा। सन् 1980 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका सैनिक उद्देश्यों पर कम-से-कम 630 बिलियन डॉलर खर्च करना चाहता है।

संयुक्त राज्य अमरीका के माघ और प्रायः इसके सीधे दवाव में, अन्य पूँजीवादी देश भी शस्त्रीकरण पर अपने खर्चों को निरंतर तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि सन् 1974 तक अपनी स्थापना के बाद के 25 वर्षों के दौरान नाटो के सैनिक खर्च सीधे तौर पर सात गुना से अधिक बढ़ गए।

क्या इस मानव श्रम के दुरुपयोग, उत्पादन क्षमताओं और भौतिक साधनों के अपव्यय का कोई अंत भी हो सकता है? आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति ने हथियारों की दौड़ को 'विशाल बटातियों' की संख्या बढ़ाने के स्तर से स्थानांतरित करके हथियारों की गुणात्मकता को सुधारने और सुपर-बम की खोज करने की स्थिति में पहुँचा दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सैनिक खर्चों की वृद्धि लगभग गुणोत्तर होती जा रही है।

विज्ञान और प्रविधि की प्रगति ने सैद्धांतिक अनुसंधान और उसकी क्रियामित—आविष्कार और उसके प्रयोग—के बीच के अंतराल को बहुत कम कर दिया है। सैन्य-औद्योगिक इजारेदारियों ने अपने मंडे इस बात को की गंठ बाँध ली है कि किसी भी उपलब्धि का हथियारों के उत्पादन में यथासंभव उपयोग किया जाय। बारूद का उपयोग इसके आविष्कार के सैकड़ों वर्ष बाद। पहले-पहल युद्ध में किया गया था। और आनेवास्त्यों को पूर्ण करने में लगभग तीन सौ वर्ष लगे। अब, यह तकनीकी तौर पर संभव है कि बिना किसी अपवाद के किसी वैज्ञानिक आविष्कार को तत्काल प्रयोग में लाया जा सके। भूतकाल में सशस्त्र सेनाओं का विकास नागरिक क्षेत्रों के विकास से आमतौर पर पिछड़ जाता था जबकि अब मामला इसके एकदम विपरीत है : युद्ध के साधनों को प्राथमिकता दी जाती है और आमतौर पर वे तीव्र गति में विकसित होते हैं। इस प्रकार विज्ञान अपने आपको युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति उपकरण के रूप में अनुभव करता है।

समकालीन अवधि के इस लक्षण पर जॉन फुलर—जिन्होंने द्वितीय विश्व-युद्ध का अध्ययन किया था—ने ध्यान दिया था। उन्होंने लिखा—“इसका क्या अर्थ है? कि विज्ञान से जुड़कर नागरिक संगठन की बजाय सैन्य-संगठन ने नेतृत्व हथिया लिया...”

“इस प्रकार विज्ञान को युद्ध द्वारा अनुशासित कर दिया गया ताकि युद्ध राज्य की पुष्टि नीचे डाली जा सके—शान्ति-राज्य में इसे जितना अनुशासित किया गया था उससे कहीं अधिक। यदि लगातार ऐसा ही चलता रहा, और निस्संदेह ऐसा ही होगा भी, तो यह सम्भ्यता को उस स्थायी आधार पर टिका देगा जिसे ‘युद्धपरता’ कहा जा सकता है; ऐसी स्थिति में आदमी की प्रतिभा का केन्द्रबिन्दु रचना नहीं विनाश होगा।”¹

वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति का हथियारों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का दूसरा पहलू यह है कि वह उनके अप्रचलन व अनुपयुक्तता का कारक बनता है। आदमी ने धनुष को हजारों वर्षों तक काम में लिया था, राइफलों को सदियों तक और एक ही प्रकार के टैंकों, हवाई जहाजों और युद्धपोतों का सशस्त्र सेनाओं द्वारा कई दशकों तक उपयोग किया जाता रहा। किन्तु आज ऐसा नहीं है, आधुनिक हथियार वस्तुतः कुछ ही वर्षों में अनुपयोगी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लड़ाकू वायुयानों और मिसाइलों की औसत जीवन-अवधि पाँच से सात साल से अधिक की नहीं होती।

अतः समकालीन स्थितियों में हथियारों को उसी तेजकदमी से परिष्कृत करना पड़ता है, और ऐसा लगभग सभी क्षेत्रों में करना होता है, उसी तीव्र गति से जिससे विज्ञान एवं प्रविधि विकसित हो रहे हैं। आज जब दर्जनों और सैकड़ों उद्योग सब प्रकार के हथियारों के विकास में भाग ले रहे हैं, यह अत्यन्त कठिन होता जा रहा है और कभी-कभी तो असंभव-सा कि उत्पादन की नागरिक और सैनिक शाखाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींची जा सके। युद्ध-उद्योग आधुनिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है, अपने हिस्से की आदेशात्मक माँग कर रहा है और हर जगह ऊपर की मलाई हड़प रहा है।

परिणामस्वरूप सैन्य-उपकरण—जिसे विज्ञान तथा प्रविधि के तीव्र विकास के साथ कदम मिला कर चलना पड़ रहा है—की कीमत में भीमकाय बढ़ोतरी हो रही है। अस्त्रों को रद्दी धातु में बदल जाने से रोकने के लिए इसे लगातार अपनी आधुनिकतम उपलब्धियों को आत्मसात करना पड़ रहा है—धातुकर्म और प्रकाशतंत्र

से इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबरनेटिक्स तक ।'

कुछ वर्ष पहले यूनेस्को 'कूरियर' ने लिखा था कि संयुक्त राज्य अमरीका की त्रिशूली पनडुब्बी सन् 1979 में पूरी कर दी जायगी जिसकी कीमत 18,000 लाख डालर होगी, जो मोरक्को के वार्षिक बजट के दुगने के करीब होती है ।¹

आज भी हालात ऐसे ही हैं । सन् 1976 तक दुनिया में सेना का खर्च कुछ स्रोतों के अनुसार 250 बिलियन डालर तथा अन्य के अनुसार 300 बिलियन था । दोनों में से एक भी संख्या अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और मध्यपूर्व के देशों की सारी राष्ट्रीय आय को एक साथ मिलाने पर भी उससे अधिक ऊँची रहेगी । और आगे के दस, बीस या तीस वर्षों में ये खर्च कितने बढ़ जाएँगे ? यदि हथियारों की दौड़ को समाप्त नहीं किया गया तो भावी पीढ़ियों के लिए कितनी खराब जिन्दगी हिस्से में आएगी ?

पूँजीवादी देशों में सैन्यवाद का वर्तमान क्रोधोन्माद हजारों हथियारों द्वारा प्रेरित है, सबसे बढ़कर संयुक्त राज्य अमरीका के औद्योगिक समूह द्वारा, जिसकी भूख शांत ही नहीं होती । यह एक साधारण-सी बात है कि शस्त्र उद्योग के लाभ नागरिक उद्योग शाखाओं की अपेक्षा दुगुने ऊँचे हैं या वे उनसे आधे हैं । खून सूँघने वाले हिंस्र जीवों की तरह, पूँजीपति अपने मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए कोई मौका पाते ही झपट पड़ता है, तथा युद्धादेशों के लिए पापमय धिनौने प्रतियोगी संघर्ष में घुस जाता है । स्वभावतः अधिक शक्तिशाली नियम सबसे ऊपर आ धमकते हैं, इसलिए कि हथियारों का निर्माण बड़े पैमाने की पूँजी वाला प्राथमिकता प्राप्त प्रभाव क्षेत्र बन चुका है । और यही वह ताकत है जो संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की सरकारों पर और उनकी घरेलू तथा विदेशी नीति पर सबसे अधिक प्रभाव रखती है ।

विश्व का प्रेस संयुक्त राज्य अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी०

1. निम्नांकित आँकड़े हथियारों की बीमत के गतिविज्ञान को जाहिर करते हैं—

प्रकार	53	1972	वृद्धि
	218	(1,000 डालर)	(कितना गुना)
सड़क विमान	70	12,000	226
बमवर्षक विमान	4,700	30,000	138
टैंक	8,700	900	13
सबमैरिन	55,000	175,000	37
विध्वंसक	1945	200,000	23
विमान वाहक	(1,000 डालर)	900,000	18

देखिए : जी० एम० क्रुजमिन, 'सैन्य-औद्योगिक संस्थान', मास्को, 1974, पृ० 91

(रूसी में)

2. यूनेस्को कूरियर, दिसंबर 1975

आइजनहावर के उस विदाई भाषण को प्रायः उद्धृत करता है जो जनवरी 1961 में दिया गया था और जिसमें उन्होंने निम्नांकित अनुभव प्रकट किया था—“विशाल सैन्य प्रतिष्ठान तथा बड़े शस्त्र उद्योग का संयोजन अमरीकी अनुभव में एक नई चीज है। इसके कुल प्रभाव—चाहे आर्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक ही क्यों न हों—को हर शहर में महसूस किया जा रहा है, हर राजकीय भवन और संघीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में महसूस किया जा रहा है। हम इसके विकास की आदेशात्मक आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। तो भी हमें इसके गंभीर निहितार्थों को समझने में भूल नहीं करनी चाहिए”¹।

“सरकार की परिषदों में हमें इसके अनुचित प्रभाव की उपलब्धि के खिलाफ चेतावनी देनी चाहिए, चाहे सैनिक-औद्योगिक समूह के द्वारा इसे चाहा गया हो अथवा न चाहा गया हो।”² और जब इस वक्तव्य का हवाला दिया जाता है तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से दूरदृष्टि से संपन्न तथा निरर्थक मानता है।

संयुक्त राज्य अमरीका का सैन्य-औद्योगिक समूह जो तेजी से विगत पन्द्रह वर्षों से बढ़ रहा है, ने एक ऐसी राष्ट्रव्यापी घटनाक्रिया के रूप में विकास कर लिया है जो वस्तुतः अमरीकी राष्ट्र के जीवन के समस्त क्षेत्रों में घुस जाती है। इसने अभूतपूर्व आयाम तथा स्वायत्त स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह अपने ही कानूनों के अनुसार जीवित रहता है, इससे भी अधिक यह कि वह सारे समाज पर उन्हे थोपने की कोशिश करता है। लियोनिद् ब्रेझनेव ने इस सम्बन्ध में नोट किया—“व्यावसायिक सैन्यवादियों और इजारेदारियों का अपवित्र गठबंधन युद्ध के हथियारों की बढ़ती भाग्यों का निर्माण कर रहा है, जिसे आम तौर पर सैन्य-औद्योगिक समूह के नाम से पहचाना जाता है, इन देशों में वह एक तरह से ‘राज्य के भीतर अलग राज्य’ बन चुका है और उसने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसे आत्म निर्भर कहा जा सकता है।”³

संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पूंजीवादी देशों में सैन्यवाद की बढ़ती ने सैन्य-औद्योगिक समूह के दबाव के अधीन अभूतपूर्व सवेग प्राप्त कर लिया है।

किन्तु यह वृद्धि फिलहाल उस अवस्था को पहुँच रही है जहाँ तब्दी पर सकेत है जो कहता है—“ठहरो, सड़क बन्द।” समकालीन सैन्यवाद का अतिप्राचीन आयाम, तथा हथियारों की दौड़ की निरर्थकता आपस में मिलकर—सैन्य-औद्योगिक समूह के निरन्तर गहराते सकट वातावरण ही बनाते हैं।

अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की दृष्टि से साम्राज्यवाद की सैनिक क्षमता फ़िल-

1. इवाइट डी० आइजन हावर 'द इवाइट हाउस इयर्स', वेडिंग पीस 1956-1961, सदन पृ० 616

2. एल० आर्द० ब्रेझनेव 'लेनिन के मार्ग का अनुसरण' मास्को, 1975 पृ० 320

हाल उन सीमाओं को पार कर गई है, जिनमें रहकर अपने वर्चस्व के लिए सघर्ष में उनका उपयोग कर सकती थी, तथा राजनैतिक लक्ष्यों की सीमाओं से भी परे चली गयी है। समकालीन पूँजीवाद ने एक ऐसी तलवार निर्मित की है जिसे वह न तो खींच सकता है और न ही उठा सकता है, बशर्ते वह स्वयं को नष्ट करने की जोखिम ही मोल न ले ले। एक बार नेपोलियन ने इच्छा व्यक्त की थी कि कितना अच्छा होता यदि उसके पास तोपखाने की जगह विद्युत होती। आज जब प्रबल शत्रुओं के पास आणविक मिसाइलें हैं और एक-दूसरे को कई बार नष्ट कर सकने की सामर्थ्य है तो आगे के लिए हथियारों की दौड़ बेतुकी हो जाती है।

हथियारों की दौड़ के आंतरिक पहलू क्या हैं? एक निश्चित अवस्था में सैन्यवाद अनिवार्यतः आर्थिक सीमाओं तक पहुँच जाएगा जिनके परे उसका भावी विकास राज्य की आंतरिक सुदृढ़ता को एक खतरा बन जाएगा। जैसाकि इवाइट डी० आइजनहावर ने कहा है—“सैनिक प्रतिष्ठान, जो स्वयं में उत्पादक नहीं होता, निश्चित रूप से देश की ऊर्जा, उत्पादकता और विचारशक्ति को अपने उपभोग की वस्तु बनाता है और यदि वह बहुत ज्यादा हड़प लेता है, तो हमारी कुल शक्ति घट जाती है।” तब से अमरीका का सैन्य-औद्योगिक समूह कैसर की गाँठ के समान फूल कर मोटा हो गया है तथा सारे आर्थिक ढाँचे को पीड़ित कर रहा है—सम्पूर्ण पूँजीवादी बाजार में, इसके साथ ही, कर-वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकटों की वृद्धि परिलक्षित होने लगी है। अब अधिकाधिक अमरीकी वैज्ञानिक अपने आपसे पूछते हैं कि क्या वह समय आ गया है, या ठीक नज़दीक आ रहा है, जब सैनिक आहूटों की वृद्धि का देश की आर्थिक स्थिति पर अधिकतम हानिकारक प्रभाव अनुभव किया जा सकेगा।

इस समस्या का सामाजिक-राजनैतिक पहलू भी बहुत विचारणीय महत्त्व रखता है। श्रमिक जन-समूह अनिश्चित काल तक इस तथ्य को बदलाति नहीं कर सकता कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ सैन्य-औद्योगिक समूह—जो राष्ट्र के खून को बहाता है—की बलिबेदी पर चढ़ाई जाती रहे।

अतः सैनिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कारक सैन्यवाद को वस्तुतः सीमित करते हैं और निःशस्त्रीकरण के पक्ष में काम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि दुनिया की राजनीति की विशिष्ट समस्याओं पर उनका प्रभाव कितनी तेज़ी से बढ़ेगा।

इस विषय में लियोनिद ब्रेज़नेव के शान्ति शक्तियों के विश्व सम्मेलन में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहा—“कहना न होगा कि साम्राज्यवाद के हमलावर गिरोहों द्वारा इधर हथियारों की दौड़ का विस्तार किया जा रहा है तथा अन्त-

राष्ट्रीय तनावशैथिल्य—जो अब शुरू हो चुका है—दो प्रतिपक्ष हैं जो विपरीत दिशाओं में गतिशील हो रही हैं। वे अनन्त काल तक समानान्तर रेखाओं की तरह साथ-साथ विकसित नहीं कर सकती।¹

अब चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के राजनैतिक सुधार की दिशा में प्रथम गंभीर कदम उठाए जा चुके हैं, मुख्य समस्या—जो दुनिया के भविष्य पर विचारणीय प्रभाव डालती है—वह है हथियारों की दौड़ को समाप्त करना। आज अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का अन्य कोई रास्ता नहीं है सिवाय राजनैतिक तनाव-शैथिल्य में सैनिक तनाव-शैथिल्य को और बढ़ाना और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर मर्वंतोमुखी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। यही स्पष्टतः वह नीति है जिसका सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देश अनुसरण कर रहे हैं।

रणनीतिक प्रचुरता की धारणा

वे पश्चिमी विद्वान, जो यह भ्रम पाले हुए हैं कि वे डरा-धमका कर या धीस-पट्टी से अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, एक भिन्न किस्म की मुद्रा धारण कर लेते हैं। हाल ही में पिछले दिनों यह स्पष्ट हुआ कि उनमें से अधिकांश की 'युद्ध' शब्द में कोई रुचि नहीं है तथा वे घोषणा करने लगे हैं कि यह आवश्यक हो गया है 'संघर्ष' से हटकर बातचीत के युग में' प्रवेश किया जाय। तो भी सैनिक कार्रवाइयों जो ताकत की स्थितियों द्वारा निर्धारित नीति के नतीजे हैं—दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों में भड़क उठती हैं। भिन्न-भिन्न बहानों के अधीन दबाव का उपयोग किया जाता है, अन्तरराष्ट्रीय कानून और प्रतिबद्धताएँ रौंद दी जाती हैं तथा प्रतिक्रिया-वादी शक्तियाँ हठपूर्वक एकतरफा लाभों के लिए सड़ रही होती हैं। हथियारों की दौड़—जोकि युद्ध की बुनियाद है—निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में जारी रह रही है।

जनवरी सन् 1976 में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति गेराल्ड फ़ोर्ड ने अपने सघीय संदेश में कहा—“हमारी सैन्य शक्तियाँ क्षमतावान और तैयार हैं...। हम लगातार अपनी सैनिक शक्तियों की कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बनाते हैं। जो बजट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें अमरीकी शक्ति की वह आवश्यकता व्यक्त हो रही है जो कि उस वास्तविक दुनिया के लिए आवश्यक है जिसमें हम रहते हैं।”²

कुछ समय बाद उन्होंने एक साक्षात्कार में अपने वक्तव्य के तात्पर्य की व्याख्या की—“अब मैं 'तनाव-शैथिल्य' शब्द का प्रयोग कतई नहीं करता, मैं सोचता

1. एन० अर्च० ब्रेज़नेव 'लेनिन के मार्ग का अनुसरण' 1975, पृ० 319

2. द न्यूयार्क टाइम्स, 20 जनवरी 1976

हैं कि हमें जो कहना चाहिए वह यह कि समुक्त राज्य महान् शक्तियों—सोवियत संघ, जिसके साथ चीन और अन्य देश होंगे—के साथ मिलेगा और तनावों को शिथिल करने की कोशिश करेगा ताकि हम शान्ति की नीति को ताकत के माध्यम से जारी रख सकें।”¹

(ज़ोर मेरा—वी० के०)

यह पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न नहीं है। आखिर, यदि किसी खास कारण से राष्ट्रपति फोर्ड ‘तनाव-शैथिल्य’ शब्द को पसन्द नहीं करते थे तो वह उसकी जगह और दूसरा शब्द काम में लेने के लिए स्वतंत्र थे। फिर भी जो समानार्थी शब्द प्रयोग किये गये थे—“शान्ति की नीति, ताकत के माध्यम से।”

इस कथन का क्या मतलब है? पश्चिम में ‘भय के संतुलन’ के माध्यम से शान्ति का कुख्यात विचार शीत युद्ध के अर्थ में समझा जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो तथाकथित यथार्थवादी राजनैतिक पर्यवेक्षकों की मौलिक रचनाओं से उद्धृत किए गए हैं, जो प्रत्यक्षतः अन्तर्राष्ट्रीय तनावशैथिल्य का समर्थन तो करते हैं, फिर भी हथियारों की दौड़ को जारी रखने की वकालत करते हैं।

“डराना-धमकाना तनाव-शैथिल्य का विलोम नहीं है, जैसी कि मौलिक परिवर्तनवादी विचारकों की राय है, किन्तु इसकी पूर्वापेक्षा है। यदि तनाव-शैथिल्य के लिए प्रयत्न करने में डराने को अस्वीकार कर दिया जाता है तब यह केवल पूर्वगामी व्यवस्था को ही हानि पहुँचाएगा।”²

एक और दृष्टिकोण है, जो भी ठीक उतना ही विरोधाभासपूर्ण है, “हथियारों की होड़ तनाव-शैथिल्य का एक स्थायी लक्षण रहेगा।” अभी तक मोटे तौर पर बराबरी कायम हो पाई है तथा तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया तेज़ हो गई है, किन्तु एक हल्का-सा अप्रत्याशित असंतुलन भी राजनैतिक तनावों को पैदा कर देगा जिसके परिणामस्वरूप यह नाज़ुक प्रक्रिया ख़तरे में पड़ जाएगी।”³

दो अन्य अमरीकी राजनीतिज्ञों, मस्की और ब्रोक, का विश्वास है कि तनाव-शैथिल्य शक्तिशाली सुरक्षात्मक क्षमता की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता, जिसका मतलब है कि समुक्त राज्य अमरीका को ऐसा करना पड़ेगा।

यहाँ ‘नई’ यथार्थवादी नीति के प्रतिपादक, या ‘यथार्थवादी निरोध’ के सिद्धांतकार पुरानी कहावत के अनुसार ठीक तरह से वर्णित किए जा सकते हैं—
“नहीं जानते हुए कि क्या किया जाना है, वे वही कर रहे हैं जो वे जानते हैं।” ये

1. द न्यूयार्क टाइम्स, 2 मार्च 1976

2. बोल्फ़ोर्ड वॉन नेशन, जिकरहोट इस एयानुमर्कलंड डर इन्ट्रानुग, बीन, 1972 पृ० 55

3. सरिस एल स्ट्रैटन, “कटोपोरेरी अमेरिकन फोरिन पॉलिसी, मिनिमल डिप्लोमेसी, डिपेंडिब स्ट्रैटजी, एंड डिस्टेन्ट मैनैजमेंट” सेक्विटन, मासाचुसेट्स टोरेंटो, सदन, 1974, पृ० 216, 217

‘यथार्थवादी चिंतक’ विश्व राजनीति में नए दृष्टिकोणों को अपना समर्थन व्यक्त करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, वे, दरअसल, पुराने दृष्टिकोणों से ही चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि सैनिक शक्ति का उपदेश देकर वे वास्तव में धक्का-शाही के युग में सौट जाने की ही वकालत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तनाव-औचित्य के जवाब में, हाल ही के वर्षों में उभरी ‘यथार्थवादी निरोध’ की अवधारणा—अमरीका एवं अन्य पूँजीवादी देशों के बहुत-से राजनीतिज्ञ जिसके पक्षधर हैं—मूलतः अंतर्विरोधों से भरी हुई है।

साम्राज्यवाद के ‘परमाणविक इजारेदारी’ से ‘परमाणविक महानता’ में और ‘परमाणविक महानता’ से ‘परमाणविक समता’ में अर्थात् एक हद तक समाजवाद के साथ सशस्त्र शक्ति के संतुलन में संक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रमिक समेकीकरण को चिन्हित किया। सशस्त्र शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन, प्रमुखतः सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच में संतुलन का परिवर्तन, तेजी से साम्राज्यवाद की हमलावर प्रवृत्तियों को बढ़-चढ़कर नियंत्रित करता है और संयुक्त राज्य अमरीका के शासक गिरोह को मजबूर करता है कि वह ‘विशाल प्रतिरोध’ की खुली जंगखोर नीति को ‘उदार प्रत्युत्तर’ की नीति के रूप में तब्दील करे, जिसे कि नई स्थिति में और अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। यह संतुलन उन्हें ‘यथार्थवादी निरोध’ के रूप में व्यक्त नवीनतम अवधारणा का स्थानापन्न खोजने के लिए भी विवश करता है।

दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सुदृढ़ता की प्रक्रिया अभी तक पर्याप्त मात्रा में समेकित नहीं हो पायी है तथा नितांत अंतर्विरोधी और अनिश्चित बनी हुई है। ‘यथार्थवादी निरोध’ की नीति (जिसे ‘ढराने-धमकाने के माध्यम’ से सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाना है) को किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए स्वीकार्य आधारभूमि के रूप में नहीं माना जा सकता। दरअसल यह उसी ‘आतंक के संतुलन’ की नीति की निरंतरता ही है।

वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है इतिहास में जिसके समतुल्यों का अभाव हो। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है जबकि विशिष्ट क्रिस्म की परिस्थितियों के कारण, नीति विशेष ने अपना खुद का संवेग प्राप्त कर लिया, तथा उसे जन्म देने वाले कारणों के अस्तित्वहीन हो जाने के लंबे समय बाद, जो कार्य रूप में परिणत हो पाईं। यथार्थ का विरोध करते हुए इस प्रकार की नीति प्रायः ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गतिरोधों में बदल गईं जिन्हें युद्ध के द्वारा ही सुलझाया जा सका। राजनीतिज्ञों ने हठपूर्वक जितना अधिक इस मार्ग का अनुसरण किया, इसका दुःखद परिणाम उतना ही अधिक संभाव्य बनता गया।

हमारे आणविक युग में अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को सैनिक उपायों से सुलझाने की बात जाहिरा तौर पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा बनती है।

है। 'यथार्थवादी दिशा' के प्रतिनिधि यह स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कि परिणामस्वरूप वे परंपरागत 'शक्ति की नीति' को पूरी तरह संशोधित कर लेंगे तथा निःशस्त्रीकरण की तरफ मुड़ जाएंगे। तो भी, अभी वे 'यथार्थवादी' इस स्थिति से ऐसे आवश्यक निष्कर्ष निकालने को तत्पर नहीं दिखते। असामंजसपूर्ण विरोधी तत्वों को समन्वित करना उनका लक्ष्य है: एक ओर तापनाभिकीय युद्ध को समाप्त करने की महती आवश्यकता को स्वीकार करना और उसके साथ ही हथियारों की दौड़ को जारी रखने का समर्थन करना।

'यथार्थवादी' नीति के प्रतिपादकों के विचारों से कम-से-कम दो नतीजे निकाले जा सकते हैं। सर्वप्रथम, वे विचार पूंजीवादी राजनैतिक चिंतन के विकास की उस अवस्था से जुड़े हैं जो 'परमाणविक गतिरोध' से उलझी हुई है, और दूसरे, वे समस्या के सकारात्मक समाधान की खोज की निरर्थकता को प्रमाणित करते हैं।

अपने समय में हेनरी किंजिजर, तब तक जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अत्युत्कृष्ट प्रोफेसर मात्र थे, ने उस विरोधाभास वाली स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्व्योक्ति का सहारा लेते हुए उसे 'अतिमार क्षमता' कहकर परिभाषित किया था। दो वैमनस्यपूर्ण आदिवासी जन-जातियाँ ज़हरीले तीरों से लैस एक गहरी घाटी में आमने-सामने रहती हैं और दोनों ही दुश्मन पर मरणातक चोट करने की सामर्थ्य से संपन्न हैं। किन्तु इससे पहले कि चोट खाए दुश्मन पर ज़हर का असर हो दूसरी जनजाति भी प्रत्याक्रमण कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि पहले हमला करने वाला मैदान भार नहीं पाएगा। विनाश दोनों का होगा।

फिर भी, सारा सबेत इस ओर है कि साम्राज्यवाद इस निष्कर्ष को मानने से इन्कार करता है। वह घुमावदार रास्तों की तलाश करता है ताकि वह अपने आपको किसी प्रकार से अधूरी स्वीकृतियों तथा आधे मन से किये गये प्रयासों—जो संपूर्ण समस्या का हल कर ही नहीं सकते—तक सीमित रख सके। वह पुरानी नीति को जारी रखने के लिए नए अवसर ढूँढता है।

किंजिजर को भी विश्वास है कि अमरीका अपनी सारी योजनाओं का आधार इस मान्यता को नहीं बना सकता कि युद्ध, यदि शुरू हो जाय तो वह सार्वभौम होगा, अतः उनका कहना है कि एक ऐसी रणनीतिक धारणा की खोज की जानी चाहिए जो अमरीका के कूटनीतिज्ञों को अधिकाधिक कार्य स्वतंत्रता प्रदान करे और साथ ही इस बात का पता लगाने में मदद करे कि आणविक युग क्या वास्तव में भयाक्रांत ही रहेगा।

पश्चिमी रणनीतिज्ञों ने, इन नए भौकों की इस रूप में खोज तथाकथित सीमित युद्ध नीति के रूप में की, तथा 1960 के दशक के आरंभ में इसका बेहद व्यापक प्रसार हुआ। इसके सिद्धांतकार यह सलाह देते थे कि शक्तिशाली दुश्मन की

सहज बुद्धि पर भरोसा किया जाय। उनका कहना था कि चूँकि एक संपूर्ण युद्ध आत्मविनाश की आशंका को व्यक्त करता है, इसके काल्पनिक भागीदारों में यह पर्याप्त समझ होगी कि वे उसे सम्पूर्ण विनाश की ओर न ले जाएँ। यह संभव है कि उसे बीच में ही रोक दिया जाय और छोटे-से युद्ध (आणविक हथियारों के 'सीमित मात्राओं' में प्रयोग पर आधारित) से सन्तुष्ट रहा जाय। उनका दावा था कि ऐसे छोटे युद्धों को, आणविक संघर्ष की तुलना में, नियंत्रित किया जा सकता है।

यह स्पष्ट है कि 'सीमित युद्ध' की धारणा केवल एक ऐसा उपेक्षाभाव है जो आणविक युग की नई गुणात्मक परिस्थिति को अनदेखा करता है। इस प्रकार इससे यह भ्रम पैदा किया गया कि शोषक वर्ग की परम्परागत नीति—जो दादा-गीरी, ब्लैकमेल और हिंसा की नीति है—को बिना किसी गम्भीर सशोधन के आगे भी जारी रखा जा सकता है। इस नीति के समर्थन में जो दलीलें दी गयी थी वे केवल भद्र पुरुषों के अलिखित समझौतों के सदृश—दोनों अतिवादी छोरों से बचने से सम्बन्धित—तक सीमित थी, क्योंकि अस्त्र सार्वभौम विनाश का भय ही अंतर्राष्ट्रीय नीति में शक्ति के विवेकशील प्रयोग को जन्म दे सकता है। ऐसी तर्क-संगति को कैसे आश्वस्त किया जा सकता था, और वह क्या आकार ग्रहण करती, और कौन-सी ऐसी प्रभावशाली गारंटियाँ थी कि जिनसे आणविक शक्तियाँ इसका समर्थन करेंगी—ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें अनुत्तरित छोड़ दिया गया है।

अतः कोई आश्चर्य नहीं कि 'सीमित युद्ध' की अवधारणा का बचाव करना बेहद कठिन सिद्ध हुआ—खासकर इसलिए भी कि 1960 के दशक में ही, सैनिक रणनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पश्चिमी विशेषज्ञ इसे पर्याप्त संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। उदाहरण के लिए, जार्ज केनन की टिप्पणी बेहद विवेकसम्मत थी, "यह मानना कि परमाणविक युद्ध की स्थिति में दुश्मन के साथ हथियारों की विनाश क्षमता तथा उनके निशानों (जहाँ वे मार करेंगे) के बारे में किसी प्रकार का अलिखित अथवा कामचलाऊ समझौता सम्भव हो पायेगा, मुझे एकदम क्षीण तथा शेखरिल्ली की जैसी आशा प्रतीत होती है।"¹

प्रतिष्ठित अमरीकी विद्वान हेस मौगेन्थॉ ने भी सीमित युद्ध की नीति की आलोचना की थी। महत्वपूर्ण यह है कि प्रारंभ में इस विचार के प्रति उनके मन में आस्था थी। किंतु इससे दूर जाते-जाते अंत में वह इसके विरोधियों के खेमे में पहुँच गये। उन्होंने ठीक ही नोट किया कि परमाणविक युद्ध कोई शतरंज का खेल तो है नहीं जहाँ हर स्थिति को शांति से धैर्य से परखा जाता है। इसकी हल-चल किन्हीं खास स्थायी नियमों के अधीन नहीं होती ज्यों ही यह शुरू हुई कि

1. जॉर्ज एफ. केनन 'रणा, दि एटम एंड द बेस्ट' न्यूयॉर्क, 1958, पृ० 57-58

होगी। किसिजर ने लिखा था—“अस्थिरता तब अधिक होगी जबकि दोनों पक्षों के पास दस-दस मिसाइलें हों, इसकी तुलना-संतुलन उस समय ज्यादा मजबूत हो जायगा, यदि प्रतिपक्ष के पास मानो 500 मिसाइलें हों।”¹

तर्क पद्धति की इस धारा का निहितार्थ यह है कि हथियारों की दौड़ कोई बुराई नहीं है बल्कि यह एक बरदान है जो स्थिरता कायम करने की सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करती है, एक प्रकार की शांति की गारंटी है। संक्षेप में, हथियारों की दौड़ को निःशस्त्रीकरण के समतुल्य विकल्प के रूप में घोषित किया जाता है। यह तर्क न केवल खतरनाक है, बल्कि आत्मघाती भी है। किन्तु इससे ‘यथार्थवादियों’ को एक मौका मिल जाता है ताकि वे शांति और राजनैतिक तनाव-शैथिल्य के पक्ष में बोल सकें और साथ ही और किसी भी ऐसे प्रस्ताव का विरोध कर सकें जो सैनिक तनाव-शैथिल्य और निःशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने वाले हों। इससे यह संभव हो जाता है कि चितन के स्तर पर जन भावना की कद्र करने के साथ ही सैन्य-औद्योगिक समूह के हितों की हिफाजत भी की जा सके।

हमें यह पूछने का हक है कि क्या मानवता इस तर्क को गंभीरता से ले सकती है। क्या हम इस तथ्य से तसल्ली प्राप्त कर सकते हैं, जैसाकि सेवानिवृत्त फ्रांसीसी एडमिरल मार्क द जॉयबेयर लिखते हैं—“आणविक शक्तियाँ, वे इसे पसंद करे अथवा नहीं, व्यापक संघर्ष—जिसमें अस्वीकार्य अदृश्य जोखिम निहित है—को टालने की दृष्टि से एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने को अभिशप्त हैं।”² क्या जनसाधारण ऐसी शांति को शांति के रूप में स्वीकार कर सकता है? इसका केवल एक ही उत्तर है, नहीं, हरमिज नहीं।

‘आणविक शांति’ को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी के रूप में देखना असंभव है। पॉल कौसर इस ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कभी भी ऐसी स्थिति उभर सकती है जब दो आणविक शक्तियाँ, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका एक-दूसरे को बन्दूकों की नलियों में से देखने लगे। उस दशा में चुनाव करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी : कि आतंक-ग्रस्त होकर शत्रु द्वारा हमले की पहल का द्रुतज्वार किया जाय, या आतंक की दशा में बटन दबा दिया जाय तथा बड़े पैमाने पर आणविक आक्रमण शुरू कर दिया जाय। शत्रुओं में से किसी एक द्वारा, दूसरे शत्रु को स्तब्ध करने के उद्देश्य से किये गये हमले के साथ ही खतरा क्रमशः बढ़ जायगा। वस्तुतः ‘आणविक शांति’ का निर्मम सार तत्त्व यही है।

‘यथार्थवादियों’ द्वारा अभिशंसित अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पैटर्न के अनुसार,

1 हेनरी ए किसिजर, ‘द नैसेसिटी फॉर चॉइस’ प्रोस्पेक्ट्स आफ अमेरिकन फॉरिन पॉलिसी, लंदन, पृ० 217

2 मार्क द जॉयबेयर, ला पेक्स न्यूक्लियर, पेरिस, 1975, पृ० 65

गारण्टियां है ही नहीं। दूसरी तरफ, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनसंहारक हथियारों की विनाशालय शक्ति में और अधिक वृद्धि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सीधे खतरे को बढ़ा देता है।

अतः 'यथार्थवादी दिशा' के व्याख्याकार आज की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या के समाधान के रूप में कोई भी जवाब नहीं दे सकते। स्थायी शान्ति और सहयोग की सम्भावनाओं के स्थान पर वे जो प्रस्तुत करते हैं वह दरअसल शीत युद्ध की अंशतः मशोषित किम्मा है। दूसरी तरफ, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि 'यथार्थवादी दिशा' बूज्बा राजनैतिक और सैन्य चिंतन के द्वारा विश्व घटनाओं की सहो अवस्था पर अधिक ध्यान देने की बदली हुई प्रवृत्ति का गंभीर संकेत देती है।

सामान्यतया 'यथार्थवादी दिशा' को संक्रमण काल—जब पश्चिमी रणनीति विदेश नीति की कतिपय पारम्परिक रुढ़ियों को त्यागने को विवश तो है कि मौजूदा दौर के परिवर्तनों को समझने को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं हैं—के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संक्रमण काल की एक स्पष्ट प्रवृत्ति 'यथार्थवादी दिशा' एक तरफ तो विरोधी शक्तियों के नितांत विरोधी प्रभाव प्रति संवेदनशील है, और दूसरी ओर यह स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के विकास सम्भावनाओं के सब प्रकार के मनमाने कामचलाऊ प्रबन्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती है।

शीतयुद्ध की खंदकों में

विचारधारात्मक और राजनीतिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण कितना ही सार्थक क्यों न हो, तनाव-शैथिल्य के मौजूदा विरोधियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : वे जो कि तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को शून्य तक पहुँचना चाहते हैं और वे जो इसे अपने संकीर्ण स्वार्थी हितों की दृष्टि से इसकी व्याख्या करते हैं तथा इस तरह लोकतंत्र और समाजवाद को नुकसान पहुँचाते हैं।

उनका वस्तुतः इसी प्रकार का दृष्टिकोण था, धुर दक्षिणी पाश्चिम में शीत युद्ध के ऐसे कट्टर डायनासाॅर हैं जो हिंसा एवं अक्रमण को पूरा करने का उपदेश देते हैं, इनके पंथ को मान्यता देते हैं। सम्राट फ्रैंडर्नैंड द्वितीय—जो यह कहा करते कि "विघर्षियों के शासन वाले देश से तो रेगिस्तान ही बेहतर है"—के दर्शन वस्तुतः इन लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह में खता है : समाजवादी संमुदाय शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व से तो युद्ध की आशंका ही बेहतर है। रीगन, वामीनी, गोल्डवाटर, जैक्सन, शैलसिजर तथा सोवियत-विरोध के अन्य समर्थक चाहे वे अमरीका में हों या पूँजीवादी दुनिया में अन्यत्र—या तो तनाव-शैथिल्य को तथ्य के रूप में मानने से इन्कार कर देते हैं या उसे इस रूप में प्रस्तुत कर

जो इसे केवल शीत युद्ध के सशोधित रूप में ही परिणत कर देता है। वे आश्चर्यजनक अड़ियलता के साथ यथार्थ के तथ्यों की उपेक्षा करते हैं तथा गुजरे हुए समय के अपने दृष्टिकोणों पर अड़े हुए हैं।

इस प्रकार 1960 के दशक के मध्य में अमरीका के वामपंथी नेताओं में प्रमुख, बेरी गोल्डवाटर, समस्त सड़को-चौराहों पर चिल्लाते फिरे कि वह कम्युनिस्टों की जीत के हातात में जीवित रहने से बेहतर तो यही मानेंगे कि दुनिया में राजशाही वापस कायम हो जाय। तब से पुलो के नीचे बहुत-सा पानी प्रवाहित हो चुका है। ह्वाइट हाउस में राष्ट्रपति की कुर्सी के असफल उम्मीदवार अपने मंजोरूँचार से अमरीकी जनता को न तो मनवा सके और न ही डरा सके। तनाव-शैथिल्य एक तथ्य बन गया और सोवियत अमरीका सम्बन्धों में विचारणीय प्रगति हुई।

किन्तु गोल्डवाटर तथा उनके साथी—साम्राज्यवाद के 'ब्लैक हण्ड्रेड्स' से सम्बद्ध—समाजवाद के प्रति इसके अलावा किसी अन्य रख को अपनाने को तैयार नहीं है। उनका आदर्श वाक्य है—“कार्थेज का सत्यानाश करो।” दुनिया पर आधिपत्य करने वाले आज के दावेदारों की समाजवादी देशों के बारे में इसके अलावा और कोई नजरिया हो ही नहीं सकता। इन्ही गोल्डवाटर ने सन् 1976 के चुनाव अभियान के दौरान, तथा हाल के वर्षों में अन्य पश्चिमी दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञों ने इस सम्बन्ध में अपना रख बिल्कुल साफ रूप में, बिना किसी लाग-लपेट के, सबके सामने रख दिया। अमरीकी विदेशी सम्बन्धों के विशेषज्ञ रोबर्ट स्ट्रासज़-हूप, विलियम किटनर और स्तेफ़ान पोस्सोनी ने अपनी पुस्तक 'अमरीका के लिए एक अग्रगामी रणनीति' में लिखा—“हम उस राजनीतिक व्यवस्था का जीवित रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें स्वयं के विकास की निरन्तर विकासमान सामर्थ्य एवं हमारे विनाश का निष्ठुर संकल्प, दोनों ही निहित हो। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं कि हम दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए 'केटोवादी' रणनीति अख्तियार करें।”¹ दस वर्ष पश्चात्, सन् 1970 में पोस्सोनी ने, इस बार जे० पॉर्नेल्ले के सहयोग से, जो नीति प्रतिपादित की उसमें उनके पुराने युद्धोद्धोष की गूँज सुनाई पड़ती है। 'प्रविधि की रणनीति' नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा : “हमें अपने दुश्मन को आणविक शक्ति के द्वारा अन्तरिक्ष युद्ध में पराजित करने की सामर्थ्य हासिल करनी ही होगी।”²

निस्सन्देह, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सामान्यीकरण के विरोधियों में सभी

1. रॉबर्ट स्ट्रासज़-हूप, विलियम आर० किटनर और स्तेफ़ान टी० पोस्सोनी 'ए फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी फॉर अमेरिका', न्यूयार्क, 1961, पृ० 405-06

२ 'द स्ट्रेटेजी ऑफ़ टेक्नालॉजी, विनिंग द डिस्टाइविंग वार' कैबिज, 1970

इतने स्पष्टवक्ता नहीं हैं। वे जो अपने सम्मान को गोल्डवाटर या प्रोस्मोनी में ऊँचा समझते हैं अपने सावैज्ञानिक वक्तव्यों में अधिक सतर्कता बरतते हैं। वे अनिवार्यतः तनाव-शैथिल्य का सीधा विरोध नहीं करते, बल्कि साथ ही, वे इसके आगे के विकास को अनेक सीमाओं और शर्तों को बाँध देते हैं, जिससे यह या तो बिल्कुल अयंहीन हो जाता है या साम्राज्यवाद को वे लाभ पहुँचाते हैं जिनसे वह 'ताकत के जोर' की नीति के माध्यम में प्राप्त करने में अमफल रहा था।

प्रायः दो सिद्धान्त—जिनमें से प्रत्येक दूसरे को काटता है—सूत्रबद्ध किये जाते हैं। एक ओर, इस बात पर जोर दिया जाता है कि तनाव-शैथिल्य को सभ्य बनाने का सारा श्रेय 'दबाव' को जाता है—'सं० रा० अमरीका का सैनिक श्रेष्ठता', 'नाटो की बढ़ी हुई शक्ति' इत्यादि को। इसका श्रेय कुछ आर्थिक कठिनाइयों, जो समाजवाद को घेरे हुए हैं, को भी दिया जाता है जिन्होंने सोवियत संघ को मजबूर कर दिया कि वह शांतिपूर्ण मुद्रा धारण करे। दूसरी तरफ़, हर प्रयास ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है कि सोवियत संघ और मजबूत समाजवादी समुदाय का, पूँजीवादी देशों की अपेक्षा तनाव-शैथिल्य में अधिक क़ायदा होगा, कि तनाव-शैथिल्य एकमात्र सड़क है, और यह बात भी कि, समाजवादी देश इसके लाभों का बड़ा हिस्सा हज़म कर जाते हैं। इस विचित्र तर्क से तो यह अर्थ निकलता है कि दो व्यवस्थाओं के आपसी मुकाबले में, साम्राज्यवाद ने समाजवादी देशों को ऐसी अच्छी स्थिति में पहुँचा दिया है उन्हें जहाँ कि 'एक तरफ़ा' क़ायदे मिल रहे हैं।

यह ज़ाहिरा तौर पर बेतुकेपन की हद है। किन्तु शीतयुद्ध के बाज़ या तो अपनी तर्क-पद्धति के बेतुकेपन से अपरिचित हैं अथवा जानबूझकर उसे स्वीकार करने से इन्कार कर रहे हैं। वे अपनी सोवियत-विरोधी नीति को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और हथियारों की दौड़ को बरकरार रख सकते हैं। यदि सोवियत संघ ताकत से सामने झुक सकता है, तो यह ज़रूरी है कि दबाव बढ़ाया जाय और अमरीका की सैनिक श्रेष्ठता को और बढ़ाया जाय; तथा यदि सोवियत संघ तनाव-शैथिल्य में रुचि रखता है और पश्चिम के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक सम्बन्धों का विकास करना चाहता है तो उसे इस बात पर मजबूर किया जाना चाहिए कि यह सब प्रकार की रियायतें 'अदा' करे। उनके आधारसूत्र कुछ भी क्यों न हों, निष्कर्ष निश्चित रूप से वही है: अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद के सोवियत-विरोधी मोर्चे को हर सम्भव तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए।

अतीत की तरह ही, अब भी वे 'सोवियत घमकी', 'लाल खतरे' तथा 'क्रैमलिन प्रसारवाद' (उनका आरोप है कि यह अकेला तत्त्व ही उनकी विदेश नीति की असफलताओं तथा समूची पूँजीवादी दुनिया के संकटों के लिए जिम्मेदार

है) के नारे उछालकर अपने दृष्टिकोण एवं नीति को तर्क-संगत सिद्ध करते हैं। और यह घिसा-पिटा सिद्धांत एक नये प्रश्न को जन्म देता है। क्या वह समय नहीं आ गया है जबकि सं० रा० अमरीका और इसके नाटो दोस्त 'सोवियत संघ को नियन्त्रित करके' विश्व व्यवस्था की यथास्थिति की रक्षा करने की ओर उन्मुख हों? इस प्रकार, वस्तुतः जो कुछ हमारे सामने है वह ताकत की जोर-जबरदस्ती को कुल्यात नीति का एक नया संस्करण मात्र है। शीतयुद्ध की खंदकों में तंग होकर बैठे हुए लोगों की मानसिकता इसी तरह की है।

यूरोप में तनाव-शैथिल्य के विरोधियों को वर्तमान समय के चीनी नेतृत्व से भी सक्रिय समर्थन प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, दुनिया में चीन ही एक ऐसा राज्य है जिसका नेतृत्व तृतीय विश्वयुद्ध के पक्ष में खुला समर्थन करता है और पेकिंग का हथ, उसका निकृष्ट सोवियत-विरोधवाद पूँजीवादी विश्व के उन राजनैतिक और सैद्धांतिक रणनीतिज्ञों के लिए चिंतन का आधार साबित हो जाता है जो तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को जानबूझकर बारूद से जलाकर राख कर देना चाहते हैं।

‘बहुध्रुवी’ विश्व और ‘बृहत् राजनीति’

ताकत के जोर वाली नीति की छाया लगातार पश्चिमी राजनीतिज्ञों—जब वे समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को धोपने का प्रयास करते हैं और इन सम्बन्धों के विकास की भविष्यवाणी करते हैं—को अक्सर प्रभावित करती है। इसका एक संकेत तो ऐसे अनेक प्रतिरूपों में मिलता है जिन्हें बहुध्रुवी विश्व की संज्ञा दी जाती है तथा जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वे उन अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के वर्तमान सहमेल का स्थान ले लेंगे जो दो ‘महाशक्तियों’ के बीच की प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित है।

इस धारणा को परिपुष्ट करने के लिए साम्राज्यवाद के सिद्धांतकार तथ्यों के साथ बाजीगरी करते हैं। वे उस, दो सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्थाओं में सम्पन्न विषय-विभाजन की जगह—जिन व्यवस्थाओं में उनके सम्बन्धों की जटिलता निहित है, तथा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की द्वि-ध्रुवीय आकृति के रूप में साधारणतया अभिव्यक्ति है—उस धारणा को स्थापित करना चाहते हैं जो सम्पूर्ण समस्या को तोड़-मरोड़कर इसे संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच के संघर्ष के रूप में चित्रित एवं प्रस्तुत करते हैं।

जैसे-जैसे व्यक्तिगत देशों या क्षेत्रीय समूहों की शक्ति बढ़ी, सोवियत-अमरीकी संघर्ष क्रमशः दूसरे केन्द्रों की प्रतिद्वन्द्विता के जरिए काफी बढ़ गए। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के द्विध्रुवीय स्वरूप को जिसके बारे में जोर देकर कहा

जाता है कि जड़ से उखाड़कर उसकी जगह जिस बहुध्रुवीय स्वरूप ने ले ली थी, उसकी सीमाओं में, अधिक-से-अधिक विरोधी देशों तथा गठबन्धनों की प्रतिस्पर्धा है, दो व्यवस्थाओं—समाजवाद तथा पूंजीवाद—के बीच की प्रतियोगिता नहीं है। पश्चिमी सिद्धान्तकार इस धोखेभरे सूत्र का उपयोग अनेक प्रकार के मनमाने तात्पर्यों और अर्थों के निर्माण के लिए करते हैं। किन्तु जैसे-जैसे बहुध्रुवीय विश्व की धारणा नित नई किस्में पैदा करता है (अमरीका-रूस-चीन : 'प्रतिस्पर्धा का त्रिकोण'; अमरीका-पश्चिमी यूरोप-जापान; 'सहयोग का त्रिकोण'; पश्चिम में अमरीका-पश्चिमी यूरोप-सोवियत संघ का एक त्रिकोण, पूर्व में अमरीका-सोवियत संघ-चीन-जापान का चतुष्कोण आदि)। वैसे-वैसे उसका खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रियावादी आधार और इस विचारधारा का शीतयुद्ध की नीतियों से सीधा रिश्ता तेजी के साथ अभिव्यक्त हो रहा है।

वस्तुतः 'बहुध्रुवीय' विचारधारा के आलोक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की संरचना ही 'शक्ति केन्द्रों' के स्थायी वैमनस्यपूर्ण सघर्ष का रूप ग्रहण कर लेती है। साथ ही, पश्चिम में इस तथ्य को किसी तरह नहीं छुपाया जाता कि यह केवल उनके आर्थिक और राजनैतिक सघर्ष का ही प्रश्न नहीं है, अपितु हथियारों में शक्ति संतुलन का भी प्रश्न है, जिसमें आणविक हथियार भी शामिल हैं, क्योंकि यह मान लिया गया है कि देर-सबेर तमाम 'शक्ति केन्द्र', 'आणविक बलब' के सदस्य बन जाएंगे।

शीतयुद्ध परम्परा को जारी रखते हुए, 'बहुध्रुवीय' नीति के प्रतिपादक इस मान्यता के आधार पर कार्य करते हैं कि प्रस्तावित 'शक्ति संतुलन' में आधिपत्य की भूमिका संयुक्त राज्य अमरीका को अदा करनी चाहिए। 'सब' भविष्यवाणी करता है कि "संयुक्त राज्य अमरीका निकट भविष्य में ही, दो निर्णायक त्रिभुजों के शिखर पर खड़ा होगा। अमरीका-सोवियत संघ-चीन त्रिभुज—जो कि शान्ति, युद्ध, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, निःशस्त्रीकरण तथा हथियारों पर नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा अमरीका-जापान-पश्चिमी यूरोप त्रिभुज—जो कि विकसित दुनिया के साथ अन्तर्क्रियाओं तथा अधिकांश राष्ट्रों की समृद्धि की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है—के शिखर पर खड़ा होगा।

दरअसल बलों की 'पूर्व एशिया और सं० रा० अमरीका की सुरक्षा' में भी हमें यही विचार मिलते हैं। बलों का विश्वास है कि दुनिया के इस हिस्से में सुनिश्चिन् करने के लिए यह अनिवार्य है कि सोवियत संघ को त्रिभुज में 'शक्ति संतुलन' कायम हो। निर्णायक के रूप में वो अन्य भागीदारों के बीच के सघर्ष का पूरा मांभ।

शीतयुद्ध की मानसिकता को बनाये रखते हुए कई विदेशी लेखक यह प्रस्तावित करते हैं कि विश्व की बहुध्रुवीय संरचना को वस्तुतः सोवियत संघ को सैनिक और राजनैतिक रूप से घेरने के लिए ही काम में लिया जाना चाहिए। विलियम किटनर अपनी योजना का खुलासा करते हुए लिखते हैं—‘एक बार पांच शक्तियों का विश्व उदित हो जाय तो इसकी अन्तर्निहित सुदृढ़ता के लिए तर्क संगति बिठायी जा सकती है। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ, और चीन प्रसारवादी शक्तियाँ हो सकती हैं। उनकी शत्रुता—उनके आपस के गहरे एवं व्यापक संघर्षों से उत्पन्न—ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाय तो बात अलग है, वरना उनकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन पर इसलिए भी अंकुश लगाया जा सकेगा कि दूसरे शक्ति केन्द्र पास ही स्थित हैं जैसे, पश्चिमी यूरोप जो सोवियत यूनियन के पास है, और जापान जो चीन और सोवियत संघ दोनों के पास है। द्विपक्षीय झगड़ों के खड़े होने पर, जैसे पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ, चीन और जापान या सोवियत संघ और जापान के बीच में, ऐसी स्थिति में दोनों अर्थात् पश्चिमी यूरोप और जापान के लिए यह विचारणीय प्रेरणा होगी कि वे संयुक्त राज्य अमरीका का अघोषित समर्थन प्राप्त कर सकें।’¹ इस प्रकार कोई भी आकृति बने, और कितने ही ‘ध्रुव’ उभरें, संयुक्त राज्य अमरीका को महान् ‘निर्णायक पंच’ होने का सम्मानजनक हतवा स्वतः मिल जाता है, और सोवियत संघ की निम्नलिखित संघर्षपूर्ण पक्षों में से एक होकर अत्यन्त विनीत भूमिका निभाने की बन जाती है।

वास्तव में ‘बहुध्रुवीय’ धारणा का उद्देश्य मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विश्व के दो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं वर्ग विभाजन के सिद्धांत की जगह विभिन्न ‘शक्ति केन्द्रों’ के अस्तित्व के विषय में मनमाने प्रबन्ध के सिद्धांत को घोषणा है। उनके अनुसार ये शक्ति केन्द्र इस अवस्था में होंगे कि एक-दूसरे से लगातार संघर्ष में रहेंगे और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तनाव चलता रहेगा तथा शीतयुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्थायी प्रतिमान बन जाएगा।

पहली नज़र में यह एक भिन्न और विपरीत सूत्र प्रतीत होता है जिसने ‘बृहत्’ राजनीति की धारणा को या ‘अटलांटिक अन्तर्निर्भरता’ की रणनीति—जो सं० रा० अमरीका और पश्चिमी यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो रही है—को उभारा तथा आगे बढ़ाया है। इस धारणा को प्रकट करने के लिए इसके लेखक बूज्वा सिद्धांतकारों की सामान्य पद्धति का सहारा लेते हैं। कुछ उपलब्ध प्रक्रियाओं को

1. साट्ट—इंफ्लेक्शन फॉर आर्थ्स कंट्रोल् इन द 1970—सम्पादित डब्लू० आर० किटनर और आर० एल० फाल्ट्जब्राऊ, जे० आर० यूनियर्सिटी ऑफ विट्सवर्ग प्रेस, 1973, पृ० 179

हुकर सिंगरे है कि विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संगठन के निर्माण की जरूरत है जो समूची मानवता के कल्याण में रुचि रखता हो, और जो अपने खुद के लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था के लिए काम कर सके। उनका विश्वास है कि ऐसा संगठन बहुराष्ट्रीय विश्व व्यापक संघ ही हो सकता है।

इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि अमरीकी इजारेदारियाँ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण सबसे ज्यादा दूरगामी योजनाओं को मन में रखती हैं। अमरीकी वैज्ञानिक सेयोम ब्राउन इस बिन्दु पर किसी सन्देह की गुजायश नहीं छोड़ते। उनका विश्वास है कि विशाल इजारेदारियाँ, जिनमें प्रमुख अमरीकी इजारेदारियाँ हैं, विश्व राजनीति में पहले से कहीं बड़ी भूमिका अदा करेंगी। और अधिराष्ट्रीय सम्पर्कों की एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगी जो कि अन्य कड़ियों तथा राज्यों को अपने अधीन बना लेंगी।¹

समकालीन अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर इसी प्रकार के विचार एक अन्य अमरीकी अध्येता प्रोफेसर रिचर्ड स्टलिंग ने, जो 'मैक्रो पालिटिक्स : इंटरनेशनल रिलेशंस इन ए ग्लोबल सोसायटी' पुस्तक के लेखक भी हैं, ने प्रकट किए हैं। वह कठोरता से, और बहुधा औचित्यपूर्ण ढंग से अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में ताकत के उपयोग की धारणा की आलोचना करते हैं। वह लिखते हैं—“राजनीतिज्ञ की सर्वोच्च कुशलता हिंसा का प्रबन्ध करना नहीं है लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जिनमें हिंसा की संभावना न्यूनतम हो।”² वह अन्तराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त एवं व्यवहार को संचालित करने वाले दृष्टिकोण के रूप में सूक्ष्म राजनीति के विस्थापन की चर्चा यह कहते हुए करते हैं कि इस प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति उतनी ही महत्वपूर्ण और युगांतरकारी होगी जितनी (भौतिकी के क्षेत्र में) कापरनीकस द्वारा की गयी क्रान्ति।

स्टालिन पूँजीवादी/देशों की 'विश्वस्तरीय एकजुटता' के विचार को प्रत्यक्षतः वस्तुगत वैज्ञानिक फ़ार्मूलों का जामा पहनाते हैं जबकि रोबर्ट क्लीन स्पष्ट शब्दों में इसके राजनैतिक सार को उद्घाटित करते हैं। इस तथ्य पर अफ़सोस व्यक्त करते हुए कि अमरीका की सैन्य शक्ति का क्षय प्रारम्भ हो गया है, वह इस स्थिति के निदान के लिए संयुक्त राज्य के नेतृत्व में एक नये सैन्य गठबंधन—जिसमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, एफ़० आर० जी० (जर्मन गणसंघ), फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, इराक, जापान, ताईवान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हों—का निर्माण प्रस्तावित करते हैं। क्लीन का विश्वास है कि इसमें मैक्सिको, स्पेन, ईरान, टर्की, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि वह दक्षिण अफ्रीका पर ही आकर क्यों रुक गये तथा इस सूची में उन्होंने अन्य दो दर्जन देशों के नाम क्यों नहीं जोड़ दिये, किन्तु यह एकादम स्पष्ट है कि वह शीत युद्ध की अवधि की विश्व आधिपत्य की अखिल अमरीकी नीति को वह चमका-दमका कर प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार अपने आधारभूत लक्ष्यों की दृष्टि से 'बृहत् राजनीति' या 'परस्पर निर्भरता' की अवधारणा सार रूप में 'बहुध्रुवीय' विश्व के प्रति रूपों के साथ मेल खाती है। यहाँ हमें एक ऐसी इच्छा का आभास मिलता है जो पूँजीवादी देशों और नवस्वतंत्र राज्यों के एक समूह के निर्माण के उद्देश्य को समर्पित है: सं० रा० अमरीका के नेतृत्व में तथा सोवियत संघ और समूची समाजवादी दुनिया के प्रतिरोध के लिए।

वैचारिक संघर्ष या मनोवैज्ञानिक युद्ध

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वूर्वा चिंतन के कुछ प्रतिनिधि, वे जो अभी तक पुराने दकियानूसी विचारों से चमत्बृत हैं, शीतयुद्ध के ध्वस्त गढ़ों की मरम्मत करने के माँके की तलाश में हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय तनावशैथिल्य के प्रतिरोध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के पूर्णतया भिन्न पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। साथ ही, अन्य पश्चिमी मिडान्तवार तथा राजनीतिज्ञ तनावशैथिल्य के झंडे के नीचे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा इस प्रकार 1950 और 1960 के दशकों के कम्युनिस्ट विरोधी छद्म-उदारवादी रक्षान को कामम रखने की फ़िराक में हैं।

भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के देशों के बीच में व्यापक संघर्ष कायम करने के नाम पर इस रक्षान के पोषक तनावशैथिल्य की प्रक्रिया

हितों के पक्ष में व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं।

नियतिवाद और 'दो व्यवस्थाओं के अभिसरण' के

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों व सहयोग का फैलाव उनके लिए पूँजीवादी और समाजवादी विश्वों के बीच की वर्ग-विभाजक रेखा को काटने तथा समाजवादी देशों के भीतर अपने सैद्धान्तिक प्रभाव को जमाने के साधन मात्र हैं।

विल्हेल्म ग्रेव—जो जर्मन गणराज्य के भूतपूर्व चांसलर कोनरड एडिनावर के भूतपूर्व सहायक थे तथा जो शीतयुद्ध के उत्साही प्रचारक थे—टिप्पणी करते हुए कहते हैं—“आगे चलकर तनावशैथिल्य की नीति संशोधित लक्ष्यों और तरीकों की ओर संक्रमण का प्रतिबिम्ब बन जाती है : वह उन सारे अल्पकालिक प्रयासों की अस्वी-कृति है जो पूर्वी यूरोप के जनगणों को कम्युनिस्ट शासनतंत्र में मुक्ति दिलाने के लिए किए जाते हैं”¹। यह आवश्यक है कि पूर्वी ब्लॉक में आंतरिक परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं की ओर मुड़ा जाय, जिसके दौरान पूर्वी राज्यों की सामा-जिक-राजनैतिक प्रणाली के क्रमिक पुनर्गठन की दृष्टि से हरसंभव सहायता दी जायगी।”²

समाजवादी समुदाय में राजनैतिक विकृति पैदा करने की दूरगामी योजनाओं के अनुसरण में, और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समूची प्रणाली की विकृति में, पश्चिमी रणनीतिज्ञ प्रमुखतः राष्ट्रवाद पर भरोसा करते हैं। यह मात्र सयोग नहीं है कि हाल के वर्षों में अमरीका तथा अन्य पूँजीवादी देशों में बहुत से विदेश नीति विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, खास कर तनाव-शैथिल्य के क्षेत्र में, बार-बार राष्ट्रीय कारक की ओर मुड़ते रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास के ब्रितानी प्रोफ़ेसर एफ़० एच० हिस्ले ने एक पुस्तक प्रकाशित की; ‘राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था’ लेखक की राय में राष्ट्रवाद ऐतिहासिक विकास की प्रमुख संचालन शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य के आलोक में इस सिद्धान्त का उनका विश्लेषण, काफ़ी दिसपस्प है।

पूँजीवादी विद्वानों के बहुमत से अलग हट कर, हिस्ले राष्ट्रवाद को एक ऐतिहासिक श्रेणी के रूप में देखते हैं, किन्तु अन्य विद्वानों की तरह वह भी राष्ट्र-वाद की सामाजिक वर्ग-प्रकृति को दृढ़तापूर्वक नकारते हैं। इस बात पर खोर देते हुए कि किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के समाज में, अगर वह अत्यधिक विकसित है तो, राष्ट्रवाद अन्तर्निहित होता है, वह अपने इस सिद्धान्त का विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सीमा तक कर देते हैं। इससे भी बढ़कर वह राष्ट्रवाद को शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के घटक के रूप में चित्रित करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों के सही, मूल्यांकन को सामान्य सूचकांक के रूप में घटित कर दिया जाय तो, इससे ‘शक्ति सतुलन’ पैदा होने के

1. विल्हेल्म जी० ग्रेव, ‘ग्लोब डेर त्राफ़्ट इन डेर वेल्ट पोलिटिक, प्योरी अड प्रैक्सिस डेर इटरनेशनालेन दे जी हुगन, डूसैलडोर्फ, बीन,’ 1970, पृ० 614

कारण, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करता है।¹

हिस्ले तनावशैथिल्य का अपने ही तरीके से पक्ष लेते हैं। उनका कहना है कि समकालीन युग में “इतिहास में पहली बार उनके (आणविक शक्तियों के) पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं कि वे, अपने स्वयं के बीच हो सकने वाले आगे के युद्ध से अपने आपको इसलिए अलग रखें ताकि काबू न की जा सकने वाली हिमा को टाला जा सके।”² लेकिन वह यह नहीं मानते कि इस उद्देश्य को भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तथा उनका दावा है कि समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय हितों—जो उनकी दृष्टि में असंपृक्त एवं आत्मनिर्भर शक्ति है—पर सर्वाधिक गौर करने पर निर्भर करता है।

अतः, निकट से जाँच करने पर हिस्ले का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रतिरूप जो राष्ट्रवाद के झंडे के तले दुनिया में सामाजिक-राजनीतिक यथास्थिति बनाये रखने के प्रयास का ही दूसरा नाम है।

पिछले दिनों पश्चिम में एक अन्य सिद्धान्त जो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ है वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तनावशैथिल्य और ‘दुनिया की राजनीति के विसैनिकीकरण’ के माध्यम से ही अन्ततः ‘विराजनैतिकीकरण’ हो सकता है। उदाहरण के लिए, इसी प्रश्न की जाँच सेयोम ब्राउन की पुस्तक ‘विश्व राजनीति में नई शक्तियाँ’ में की गई है। लेखक इस मान्यता को लेकर आगे बढ़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की नई व्यवस्था जो ‘शीतयुद्ध के भूराजनैतिक और सैद्धान्तिक आधारों की समाप्ति की परिस्थितियों में’ फिलहाल नई शक्ल धारण कर रही है, पूर्ववर्ती द्विध्रुवीय व्यवस्था से समुचित रूप से भिन्न होगी, प्रमुखतया उसके बहुकेन्द्रवाद की दृष्टि से उन्होंने लिखा—“अटलांटिक के दोनों ओर तथा जापान के राजनेताओं के सामने यह सिद्ध हो चुका है, कि 1950 के दशक का जकड़बंद गठबंधनों का प्रतिरूप बेटिकाऊ है और 1960 के दशक के ढीले-ढाले सम्बन्ध भी बहुत से मुद्दों पर छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। गठबंधन अधिकाधिक एक बड़े जाल में रूपांतरित हो रहा है जिसमें शत्रुतापूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध आपस में एक-दूसरे को काटते रहते हैं। और यह जो वाद वाला संक्षण है वह आगे बढ़कर कम्युनिस्ट क्षेत्र के बाहर की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की धुन को परिभाषित और व्यवस्थित करता है।”³ ब्राउन की मान्यता है कि कम्युनिस्ट विश्व भी उसी अपकेन्द्रीय प्रवृत्ति से कमोवेश

1. एफ. एच. हिस्ले, ‘नेशनलिज्म एंड दि इंटरनेशनल सिस्टम, लंदन, सिडनी, ऑक्फोर्ड, टोरंटो, 1973, पृ० 147

2. वही, पृ० 154

3. सेयोम ब्राउन, ‘न्यू फोर्सेज इन वर्ल्ड पोलिटिक्स’, पृ० 44

मात्रा में प्रभावित होता है।

तब शीतयुद्ध की अवधि के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था की जगह कौन-सी प्रणाली लेगी? नहीं, यह बहुध्रुवीय विश्व नहीं होगा जिसमें अधिक तथा कम मजबूती वाले 'शक्तिकेन्द्रों' का सम्मिश्रण हो। ब्राउन की राय में यह एक ऐसा विश्व होगा जोकि विभिन्न मुद्दों के इर्द-गिर्द बने विभिन्न गठबंधनों (एक-दूसरे को काटते हुए) से निर्मित होगा, एक प्रकार का "बहुतंत्र जिसके प्रति समर्थन व निष्ठा व्यक्त करने में राष्ट्र-राज्य, उपराष्ट्रीय दल और पारराष्ट्रीय विशेष हित और समुदाय आदि सब आपस में होड़ करेंगे, तथा इसके अन्तर्गत विरोधों का समाधान, परिवर्तनशील शक्ति-सम्बन्धों के संदर्भ में अस्थायी सौदेबाजी के आधार पर होगा।"¹ इस प्रकार की ताकिकता का सैद्धान्तिक पूर्वाग्रह स्पष्ट है। दरअसल, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की 'विसंज्ञांतिकीकरण' वाली धारणा की एक नई व्याख्या मात्र है तथा इसे असदिग्ध रूप से राष्ट्रीय रंग दे दिया गया है।

पूँजीवाद और समाजवाद के वर्ग विभाजन को धुँधलाने के लिए वूर्जवाँ सिद्धांतकार इन दिनों खासतौर से उन तथाकथित सार्वभौम समस्याओं के बारे में अटकलें लगा रहे हैं जो प्रायः कृत्रिम रूप से भड़कायी हुई भावुकताओं के लिए आधारबस्तु बन जाती है। और यहाँ आकर दोनों—खुले कम्युनिस्ट-विरोधी और पूँजीवादी चिंतन में उदार-समीक्षात्मक रुचि वाले—चितक प्रतिनिधि बड़े धाव से 'आधुनिक सभ्यता' के पापों का भंडाफोड़ करने वालों की भूमिका अदा करते हैं। वे मानवता की उन विनाशों से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं जो परिस्थिति-जन्य संकट, जनसंख्या विस्फोट, अति शहरीकरण इत्यादि के द्वारा पैदा होते हैं। इन तथा इसी तरह की अनेक अन्य समस्याओं को उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ से काट दिया जाता है तथा वूर्जवाँ प्रचारतंत्र द्वारा अतिशक्तिपूर्ण तरीके से इन्हें अधिराष्ट्रीय अधिसामाजिक स्वरूप वाली प्राकृतिक विपदाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ही दलीलें इसलिए काम में ली जाती हैं कि समाज-वाद को सैद्धान्तिक आधार पर पूँजीवाद के साथ समझौता करने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया जा सके और वह भी इस बार हमारे ग्रह को बचाने के बहाने से। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश इस बात के लिए लाञ्छित किए जाते हैं कि उनमें सैद्धान्तिक 'पूर्वाग्रह', 'असहनशीलता' तथा मानवता को एक ऐसे समय 'विभाजित' करने की प्रवृत्ति है; जब उसे एक करने की आवश्यकता है चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं में भिन्नता की उपेक्षा भी करनी पड़े, ताकि, उनके कथनानुसार विनाशकारी प्राविधिक विकास से उत्पन्न होने वाले समानसुतरों से संघर्ष किया जा

सके। अतः यह सूत्र 'समभिमुखता' सिद्धांत की ही वह नई किस्म है जो 'विसंवाति-कीकरण' के समर्थन में नई दलील के रूप में काम करने के लिए प्रस्तुत की जाती है।

किन्तु शायद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कोई दूसरा ऐसा पहलू नहीं है जो कि प्रचार की व्यापक अटकल बाजियों का उस सीमा तक विलय हो जितना कि अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कों का व्यापक होना तथा सूचना का आदान-प्रदान है। प्रायः काफ़ी समाजवाद के विरोधी प्रायः यह काल्पनिक विश्वास पैदा करते हैं कि पश्चिमी शक्तियाँ समाजवादी विश्व के साथ सभी प्रकार के संपर्कों का विस्तार करना चाहती हैं; लोगों और विचारों के एक 'स्वतंत्र' विनिमय के वे पक्ष में हैं। समाजवादी देशों, जिन्हें 'बंद समाज' कहा जाता है, पर उसका विरोध करने का आरोप लगाया जाता है। यही कारण है कि समाजवादी देशों पर दबाव बढ़ाने की अपीलें की जाती हैं ताकि वहाँ की आबादी को, अन्तर्राष्ट्रीय तनावशैथिल्य के झंडे के नीचे लाकर, पश्चिमी विचारधारात्मक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रेरित किया जा सके।

फिर भी, इस प्रश्न पर सोवियत संघ का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है जिसमें निरी अटकलबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। लियोनिद् ब्रेझ्नेव ने इस विषय में कहा—“यह अक्सर सुनने में आता है कि पश्चिमी देश सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को महत्त्व देते हैं, और खासतौर पर विचारों के आदान-प्रदान, सूचना-प्रसार और राष्ट्रों के बीच संपर्क को विशेष महत्त्व देते हैं। हमें अपने तहेदिल से यह घोषणा करने की इजाजत दें, कि हम भी इसके पक्ष में हैं, बशर्ते यह सहयोग एक-दूसरे की संप्रभुता, कानून और उसके रीति रिवाजों के प्रति सम्मान रखकर कायम किया जाय तथा इसमें की जनगणों पारस्परिक आध्यात्मिक समृद्धि, पारस्परिक विश्वास तथा शांति के विचारों और अच्छे-पड़ोसीपन की भावना को बढ़ावा मिले।”

यह दृष्टिकोण भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के राज्यों के बीच लेनिन की शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति से ही उभरा तार्किक रूप है। यह समकालीन सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों—अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं विचारधारा—को अपने में समेटता है तथा उनके विशेष लक्षणों को भी प्रतिबिंबित करता है। अधिक क्षेत्र में कारगर सहयोग के विकास की आधारशिला रखना पारस्परिक लाभ का सिद्धांत है। राजनीति में इसका मुख्य लक्षण एक-दूसरे के मामलों में अहस्तक्षेप का है; प्रत्येक देश के स्वाधीनता के संप्रभु अधिकार के प्रति सम्मान रखना ताकि वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी घरेलू समस्याएँ मुलझा सके। विचारधारा के

क्षेत्र में—जहाँ समझौते के लिए कोई गुंजायश नहीं है—‘शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ है। व्यापक सांस्कृतिक सहयोग, सूचना का आदान-प्रदान और प्रत्येक देश की संप्रभुता तथा सभी जनगणों के रीति-रिवाजों के प्रति आपसी सम्मान के आधार पर विभिन्न संपर्क।

सोवियत संघ और अन्य सामाजवादी देश न तो अपनी विचारधारा और न ही अपनी संस्कृति को किसी अन्य पर थोपते हैं, किन्तु वे अनिवार्यतः इस पक्ष में हैं कि सारी मानवता की पहुँच के भीतर सांस्कृतिक मूल्यों को लाया जाय। वही एक केन्द्रीय और अत्याज्य शर्त है जो विश्वप्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का उत्स है, क्योंकि सच्ची संस्कृति दूसरे देशों के सांस्कृतिक क्रिया व्यापार, प्रगति और परंपराओं को दबाती नहीं है, बल्कि उन्हें समृद्ध करती है, वह लोगों को आपस में विभाजित नहीं करती, अपितु उन्हें निकटतर लाती है।

दुनिया में ऐसा दूसरा कोई भी देश नहीं है जहाँ चिंतन और संस्कृति सम्बन्धी सभी लोगों की सर्वकालिक संबंधों के उपसन्धि को इतना ऊँचा मूल्यांकन प्राप्त हो तथा उनका इतना व्यापक प्रसार किया गया हो जितना कि सोवियत संघ में हुआ है। दुनिया के प्राचीन आदर ग्रथ और समसामयिक रचनाएँ सोवियत संघ में करोड़ों प्रतिष्ठों के संस्करणों में छापी जाती हैं। सोवियत नाट्य-गृहों के रंगमंचों पर अनेक विदेशी लेखकों के नाटक खेले जाते हैं, देश के सिनेमार्स और टी० बी० पर दुनिया के जाने-माने कलाकार और मंचीय व्यक्तित्व प्रदर्शित होते हैं। सोवियत संघ में तथा अन्य समाजवादी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना के आदान-प्रदान व जनगणों के पारस्परिक संपर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। केवल सन् 1975 में ही 580 लाख से अधिक विदेशी यात्रियों ने पारस्परिक आर्थिक सहायता परिपद के सदस्य राज्यों की यात्रा की और लगभग 350 लाख समाजवादी समुदाय के लोगों ने विदेशी राज्यों की यात्राएँ की। अतः ‘बंद समाज’ की चर्चा का क्या अर्थ हो सकता है?

जून सन् 1976 में यूरोप की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के सम्मेलन में लियोनिद् ब्रेझ्नेव ने कहा था—“नहीं, समाजवादी देश एक ‘बंद समाज’ नहीं है, हम प्रत्येक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए खुले हैं, और हम हर प्रकार के संपर्क का विस्तार करने के लिए तैयार हैं, तनावशायित्व की अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करने में अग्रणी हैं। किंतु युद्ध, हिंसा, जातिवाद और घृणा को प्रचारित करने वाले प्रकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। और इससे भी अधिक विदेशी गुप्तचर सेवाओं के सदस्यों और उनके द्वारा खड़े किये किये सोवियत विरोधी घुसपैठियों संगठनों के लिए भी ये हमेशा बंद रहेंगे। संपर्कों की ‘स्वतंत्रता’ की चर्चा के बहाने पश्चिम, कभी गंदी, के लिए

स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।”

अब यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कों तथा सूचना के क्षेत्र में क्या स्थिति है। लेकिन सारतः इस सरल मुद्दे को अधिक-से-अधिक भ्रमपूर्ण बनाने की इच्छा की वजह से वूर्वा प्रचार तंत्र प्रायः ‘वैचारिक संघर्ष’ और ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ की धारणाओं को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है। प्रश्न को जितना सलीके से प्रस्तुत किया जाता है उतना ही वह अम्बाभाविक लगता है : या तो वह वैचारिक संघर्ष का परित्याग या ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ की निरंतरता। मिद्वांततः इस प्रकार का प्रस्तुतीकरण दिवालियापन ही प्रदर्शित करता है तथा व्यवहार में वह किसी-न-किसी रूप में जनगणों के बीच में शान्ति और सहयोग की प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाता है।

वैचारिक संघर्ष ऐतिहासिक प्रक्रिया की हमेशा एक वस्तुगत-घटनाक्रिया बनी रहेगी। यह तब तक अनिवार्य है जब तक कि विरोधी वर्ग कायम रहते हैं। किन्तु यदि किसी के लिए यह संभव नहीं कि वह ‘वैचारिक संघर्ष’ को समाप्त कर दे तो इसके लिए वे सरकारें और शासकीय राजनैतिक पार्टियाँ, जिनके ऊपर इसे अंजाम देने की जिम्मेवारी है, सोचें और चुनें कि उन्हें क्या साधन और कौन से तरीके काम में लेने होंगे। यह एक बात है कि विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, उनके लाभों को सिद्ध किया जाय और व्यावहारिक अनुभव को इस दृष्टि से फैलाया जाय कि जनमत को जीता जा सके (वैचारिक संघर्ष) तथा इससे पूरी तरह भिन्न बात यह है कि जनता को गलत सूचनाएँ दी जाएँ, दूसरे देशों को लाञ्छित किया जाय और उनकी वर्तमान व्यवस्था में सैद्धांतिक दृष्टि से तोड़-फोड़ की जाय (मनो-वैज्ञानिक युद्ध)।

तनावशैथिल्य किसी भी रूप में वैचारिक संघर्ष के ह्रास का सूचक नहीं होता। यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे ठोस सिद्धांत और निर्धारित किए जाएँ जो बिना-शर्त ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ के तरीकों को प्रतिबधित कर दें क्योंकि मनोवैज्ञानिक युद्ध के इन तरीकों ने लम्बे समय से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को जहरीला बना रखा है।

अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य पूँजीवाद और मजदूर वर्ग की प्रकृति को और न उनके उद्देश्यों को ही संशोधित करता है। पूँजीवाद और समाजवाद के बीच का संघर्ष अनिवार्य है।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया—“विश्व की घटनाओं और तनाव-शैथिल्य में सकारात्मक

परिवर्तन समाजवादी विचारों के व्यापक फैलाव के लिए अनुकूल अवसरों का निर्माण करते हैं। लेकिन, दूसरी ओर दो व्यवस्थाओं के बीच का वैचारिक मुकाबला पहले से कहीं अधिक तीखा, तथा साम्राज्यवादी प्रचार पहले से कहीं अधिक धूर्तता-पूर्ण होता जा रहा है।”

प्रतिक्रियावाद के अड़ियल प्रतिरोध के बावजूद विश्व में वैचारिक और राजनैतिक वातावरण लोकतांत्रिक शक्तियों के पक्ष में परिवर्तित हो रहा है।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस के निर्णयों के आधार पर सोवियत संघ द्वारा शक्तिशाली शान्ति प्रयासों के तेज किये जाने, शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा जनमुक्ति संघर्ष के लिए आगे का संघर्ष कार्यक्रम—सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस में स्वीकृत किया गया था—तथा सोवियत संघ द्वारा युद्ध शुरु किये जाने की सारी चर्चा की कलाई खोल दी थी। इस परिस्थिति ने सोवियत-विरोध के सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक मूलधार—कम्युनिज्म की आक्रामक प्रकृति के बारे में प्रचारित मिथक—की घज्जियाँ उड़ा दी।

यह बहुत महत्व की बात है कि व्यापक जनमत के द्वारा समर्थित तनाव-शैथिल्य का मार्ग दुनिया भर में राजनैतिक सक्रियता को प्रेरित और त्वरित करता है। नितांत भिन्न सैद्धांतिक और राजनैतिक उन्मुखताओं से अधिकाधिक संयुक्त जनशक्तियाँ शान्ति के लिए विशाल और व्यापक संघर्ष में सम्मिलित हो रही हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक सचमुच की लोकतांत्रिक प्रणाली के निर्माण हेतु एक समान कार्यक्रम के आधार पर एकता कायम करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें प्रतिक्रियावादियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और राजनैतिक काम गहनता से जटिल बन जाता है, अर्थात् प्रतिक्रियावादियों द्वारा विकट राजनैतिक समस्याओं के समाधान में जनभागीदारी को यथासंभव रोकने के काम और संयुक्त साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चे में लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता को भटकाने या बिखराने के काम को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।

साथ ही, दुनिया के मजदूर वर्ग की समझ में यह आने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय भुक्ति और सामाजिक प्रगति से अलग नहीं की जा सकती। व्यवहार में दुनिया के सभी हिस्सों के नए जनगण इस बात से सहमत हो रहे हैं कि वास्तविक सतत शांति-असली लोकतांत्रिक आधार पर ही टिकी रह सकती है अर्थात् उन सिद्धांतों पर जिन्हें हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने मान दिया है। इस सत्य की चेतना और सतर्कता उस व्यापक सिद्धांत को काट देती है, जिसे पूँजीवादी प्रचार ने बहुत वर्षों से इस्तेमाल किया है,

कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की 'अंतर्विरोधी' प्रकृति और इसके शांति के नारों और वर्गीय क्रांतिकारी उद्देश्यों में 'असंगति' है।

ये सब तथ्य समकालीन वैचारिक सघर्ष में गम्भीर परिवर्तन पैदा करते हैं। इसके केन्द्र में युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भिन्न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रश्न हैं—यह एक ऐसा तथ्य है जिसे इस युग की नियमितता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। संसार के विकास की हरेक अवस्था एक या दूसरे प्रकार के सघर्ष को आगे बढ़ा देती है अथवा एक विशेष समस्या को उपस्थित कर देती है जो अधिकतम मात्रा में सारी मानवता के हितों से सम्बन्धित होती है। वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार का मुख्य मुद्दा शांति के लिए सघर्ष और आन्दोलन है जो प्रमुख रूप से सामाजिक प्रगति और मानवता के अस्तित्व की ही संभावनाओं को निर्धारित करता है। अतः यह स्वाभाविक है कि सबसे अधिक भयंकर वैचारिक सघर्ष इस पर लड़े गए हैं और लड़े जाते हैं।

तनाव-शैथिल्य के माध्यम से

तनाव-शैथिल्य की नीति ने अब तक जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया है। इससे इस सच्चाई की पुष्टि होती है कि हथियारों की दौड़, विरोधी पक्षों के किसी अस्थिर 'संतुलन' के निर्माण अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 'सैद्धांतिकीकरण' के जरिए शांति की सुरक्षा और उसकी सुदृढ़ता के महान् कार्य को पूरा किया जा सकता, बल्कि यह सब भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। समकालीन विश्व में शक्तियों के वास्तविक सहसम्बन्ध को प्रतिबिम्बित करते हुए मात्र यही सिद्धांत ऐतिहासिक प्रगति की महान् आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

बहुत बार पश्चिम में इस प्रकार की बातें करने वाली आवाजों को सुना जाता है कि तनाव-शैथिल्य से पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद को अधिक फायदा पहुँचता है।

किन्तु वे इसे चाहे या न चाहे, यह दावा कम्युनिस्ट-विरोधियों द्वारा प्रसारित एक बुनियादी झूठ को ही जलट कर रख देता है, और वह है समाजवाद की तथाकथित आक्रामकता से संबंधित है। बहुत-से दशकों तक पूंजीवादी सिद्धांतकार सोवियत 'प्रसारवाद' और 'सोवियत खतरे' के बारे में बढ़-चढ़कर बातें करते रहे। दरअसल यह वही सिद्धांत था जिसे ताकत के जोरवाली स्थितियों की रीति और अनेक शीत-युद्ध के दौर की साम्राज्यवादी जगजगदी नीतियों को एक सैद्धांतिक दलील के रूप में काम में लिया जाता रहा। अब यह इस रूप में जलट गया कि

समाजवाद शांति के विषय में अधिक चिंतित है और वह पूंजीवाद से अधिक इससे फायदा उठाता है। अंतर्विरोध विलकुल स्पष्ट है।

कम्युनिस्टों ने अपनी शान्ति की इच्छा को कभी छिपाकर नहीं रखा है। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा इस धारणा को बनाए रखा है कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव शैथिल्य आवश्यक है और सारे ही राष्ट्रों के लिए फायदेमंद है। हेलसिंकी सम्मेलन के निष्कर्षों को आधार बनाते हुए, सियोनिद ब्रेझनेव ने इस बात पर जोर दिया है कि शांति का सुदृढ़ीकरण एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए, न तो विजेता न ही पराजित, मैदान मारने वाले या मैदान खोने वाले महत्त्वहीन हैं। यह विवेक की जीत है। हरेक लाभान्वित होगा : पूर्व और पश्चिम के देश, समाजवादी और पूंजीवादी राज्यों के सभी लोग, चाहे गठबन्धनों में शामिल हों या तटस्थ, चाहे बड़े हों या छोटे। यह उन सबके लिए फायदेमंद है जो हमारे ग्रह पर शांति और सुरक्षा की भावना को अपने हृदय में घरोहर के रूप में बनाए रख रहे हैं।¹

यह वक्तव्य इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानवता का शांतिपूर्ण विकास, जो युद्ध का एक विकल्प है, केवल एक आकांक्षा ही नहीं है किन्तु वह इतिहास की एक आवश्यकता भी है और एक ऐसा उद्देश्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे अनवरत और बृद्ध उपायों की एक ऐसी ठोस योजना का स्वरूप दिया गया है, जो परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक नई प्रणाली का निर्माण कर सकती है और उसे करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, हेलसिंकी के सुझावों और निष्कर्षों ने यूरोप के वातावरण को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। सम्प्रभु अधिकारों के प्रति पारस्परिक सम्मान और राज्यों की सीमा सम्बन्धी एकसूत्रता के प्रति आदर, जो हेलसिंकी सम्मेलन के भागीदारों की मूल भावना थी, ने उनके घरेलू और विदेशी मामलों में अहस्तक्षेप और शक्ति के उपयोग तथा घमकी के परित्याग आदि ने अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण पर अनुकूल प्रभाव डाला। सभी यूरोपीय राज्यों की सीमाओं की अलंघनीयता पर हुई सहमति ने यूरोपीय सुरक्षा को आवृष्ट कर देने में विशेष भूमिका अदा की। विज्ञान, प्रविधि, संस्कृति और कला के विभिन्न क्षेत्रों में बहु-विध सहयोग स्वभावतः उपयोगी और लाभदायक है।

इस प्रकार हेलसिंकी सम्मेलन के पश्चात् का यूरोप यह जाहिर करता है कि शीतयुद्ध के अवशेष को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया का गहरा होना इस बात को संभव बना देगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में से पृथक्तावाद और संदेह को दूर किया जा सके और ऐसा करना सारी मानवता को लाभ पहुंचाएगा।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बढ़कर इस बात को महत्व देती है कि राजनैतिक तनाव-शैथिल्य के लिए संघर्ष को जारी रखना इस दृष्टि से आवश्यक है कि तनावों की शेष स्थितियों को समाप्त किया जा सके, अन्तर्राष्ट्रीय विरोधों का न्यायसंगत हल प्राप्त किया जा सके तथा आपसी समझ और विश्वास को मजबूत किया जा सके। यह आवश्यक है। ब्रेझनेव ने कहा, "संसार में ऐसा वातावरण बनाने के लिए, जिसमें शक्तिशाली हमलावरो—जो तलवारें खींचने और दुःसाहस करने में खुशी महसूस करते हैं—का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक जनगण संकल्प-बद्ध हो, तथा जिसमें विश्व के सभी भागों के अधिकाधिक जनगण के लिए शांति, सुरक्षा और एक शांतिपूर्ण भविष्य में विश्वास एक यथार्थ बन जायेंगे।"¹

इस समस्या का समाधान बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की नई व्यवस्था के निर्माण में सिर्फ पहली अवस्था है। आज गुणात्मक रूप से नए दौर की आवश्यकता जहाँ राजनैतिक तनाव-शैथिल्य का पूरक सैनिक तनाव-शैथिल्य हो तेजी के साथ व्यक्त हो रही है। हथियारों की दौड़ को समाप्त करना अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का अहम मसला बन रहा है, क्योंकि मानवता और अधिक युद्ध के प्रसार तथा उसके भौतिक आधार के पुष्ता करने को सहन नहीं कर सकती। तनाव-शैथिल्य की आगे की प्रगति हथियारों में कटौती और क्रमशः मार्बम और पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर निर्भर करती है। लियोनिद ब्रेझनेव ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस को बताया—“आज, यह उद्देश्य पहले से कहीं बहुत बड़ा है।”²

इस दिशा में पहलकदमी की जा चुकी है। तीन स्तरों में आणविक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने की सन्धि पर हस्ताक्षर करने, उनका आगे उत्पादन न करने, रणनीतिक, सुरक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के परिसीमन पर सोवियत-अमरीकी समझौतों का निष्कर्ष और आणविक युद्ध को रोकने, युद्धकारक आक्रामक हथियारों के परिसीमन पर नई सन्धि का प्राख्य तैयार करने पर सहमति और इसी प्रकार के दूसरे कामों को निःशस्त्रीकरण के मार्ग पर एक सफलतापूर्वक आरम्भ माना जा सकता है तथा यह एक अच्छा उदाहरण भी है कि इस जटिल और तात्कालिक आवश्यकता वाली समस्या को जिसने अपने आपको इससे पहले कभी मानवता के सामने भयंकर रूप से प्रस्तुत नहीं किया था किस प्रकार हल किया जा सकता है।

निष्कर्षतः, राजनैतिक और सैनिक तनाव शैथिल्य को आगे चलकर तमाम देशों के बीच समानता, सम्प्रभुता और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आधार पर उपयोगी सहयोग की स्थापना करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह इस प्रकार का सहयोग है जो उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की नई प्रणाली की मूल

1. एल० आई० ब्रेझनेव, 'लेनिन के मार्ग का अनुसरण', मास्को, 1975, पृ० 547

2. दस्तावेज और प्रस्ताव, 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस', पृ० 27

अन्तर्वस्तु का निर्माण करता है जिसे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित देखना चाहती है।

यह सीधा किंतु शानदार परिदृश्य आर्थिक, वैज्ञानिक और प्राविधिक महयोग के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान के लिए और आज की और भविष्य की विश्वव्यापी समस्याओं को सुलझाने हेतु संयुक्त प्रयामों के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है।

शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की यही सम्भावना है। किन्तु वर्ग-शांति से इसकी कही समानता नहीं है न यह और किसी भी प्रकार से, सिद्धांतों और राज्य की राजनैतिक प्रणालियों की मौलिक भिन्नताओं को मिटाती ही है। इसकी क्रियामयिती का यह कर्तई अर्थ नहीं है कि मजदूर वर्ग का पूँजीवादी प्रणाली के दमन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या मेल हो जाय। इसके विपरीत यह एक वर्गहीन समाज के निर्माण के उनके धाँछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन-समुदाय को सर्वाधिक अनुकूल अवसर प्रदान करती है और इसके साथ ही ताप-ताभिकीय युद्ध की लपटों में अपने आत्म-विनाश की आशंका को दूर करती है।

इस सम्भावना को न पलटी जा सकने वाली सम्भावना होना है; क्योंकि यह इस समसामयिक युग की—जो मानवता के पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण का युग है—अन्तर्वस्तु को अभिव्यक्त करती है।

अध्याय : 11

भविष्य की दृ

"सभी भादयियों की जिन्दगियों में होता है एक इति
युगों की प्रवृत्ति को अरित करते हुए; उगे ममागर को
भविष्यवाणी कर मरता है मगभग गटीर, घटनाओं में
की जीवन में अभी तक अपटित, जो अनेकों में,
प्रारम्भों में, पही अन्त कोपित !
कान इन घटनाओं को मना है... जन्म देता है..."

—ब्रितिसम दोरगपौपर—'रिग है

नहीं किया गया तो। एक वस्तुगत और सर्वग्राह्य अर्थात् वैज्ञानिक पूर्वानुमान ने सामाजिक प्रगति को अलग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य अर्जित की जाय और आज के लिये हुए निर्णयों के सम्भावित परिणामों का लेखा-जोखा लिया जाय।

इसका मतलब है कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति के युग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जिसमें लोभों के लिए यह लाजिमी हो गया है कि वे न केवल भूत और वर्तमान के आधार पर भविष्य का नक्शा तैयार करें, अपितु भविष्य की अपनी पूर्वदृष्टि के आधार पर वर्तमान को परिभाषित करें। मानवता की वैज्ञानिक एवं प्राविधिक समताएँ इतनी विशाल हो चुकी हैं कि उनकी अधिकतम एवं निरापद सिद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

निस्सन्देह, यह प्रश्न भूतकाल में भी उपस्थित हुआ था, लेकिन उतना तीव्रता के साथ पहले कभी सामने नहीं आया था, जितना कि आज, क्योंकि मनुष्य पहले कभी इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि वह आज है। दूसरी तरफ़, दशकों और सदियों में फैले हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन ने कई पीढ़ियों के जीवन को अपने में समेट लिया। इसके बदले में इसने व्यक्तियों के सामाजिक उत्तरदायित्व को उनके वंशजों की तुलना में कम कर दिया। अपनी सक्रियता से सीधे आर्थिक फायदे हासिल करने की शीघ्रता में हमारे समय से पूर्व के लोगों ने इस तथ्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी भूलों और उनके त्रुटिपूर्ण अनुमानों की कीमत आखिर भावी पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। सदियों बाद उक्त क्रियाकलाप के परिणाम मानवता पर प्राकृतिक विपत्तियों के समान आ पड़े। फ्रेडरिक एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'प्रकृति की द्वन्द्वात्मकता' में लोगों के ऐसे क्रियाकलापों के अप्रत्याशित परिणामों के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जोकि उन्होंने मात्र तत्काल फल प्राप्ति की क्षणिक प्रेरणा के वशीभूत होकर किये थे।

“उन लोगों ने, जिन्होंने मैसेपोटामिया, ग्रीस, एशिया माइनर में तथा अन्यत्र जंगलों को इसलिए नष्ट कर दिया था कि उन्हें उपजाऊ जमीन मिल जाय, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे इन देशों की मौजूदा दयनीय स्थिति की आधारशिला रख रहे थे।...वे जिन्होंने यूरोप में आलू फैलाया यह नहीं जानते थे कि इन माँड़युक्त कन्दों के साथ वे गंधमाला भी फैला रहे हैं।...जब अरबों ने स्पिरिटों का भबका लगाना सीख लिया, यह उनके मस्तिष्कों में नहीं आया कि ऐसा करके वे उस समय तक अज्ञात अमरीकी महाद्वीप की आदिवासी जातियों के जन-संहार के हथियारों में से एक प्रमुख हथियार का निर्माण कर रहे हैं।”¹

इसका परिणाम यह होता है कि सीधा भौतिक लाभ उठाने को फिराक में

लोगो ने, केवल प्रारम्भिक और स्पष्टतम परिणाम पर ही ध्यान देकर, इस आदिम मिद्धान्त को ही निर्देशक आधार बनाया था कि “मेरे जीवन भर के लिए काफी है”, तथा इसे सहजवृत्ति से स्वीकार कर लिया था।

समकालीन युग इस दर्शन को हमेशा के लिए उलट देता है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति, जो समाज के विकास को एक असाधारण मात्रा में बढ़ा रही है, ने मानवता को इन्कलाबी तूफान के बीच में डाल दिया है—जैसा कि अमेरिकन विद्वान् एल्विन टॉफ़लर का मानना है। एक बार जिसके प्रकट होने में सदियों लग जाती थी, अब उसी के व्यवस्थित होने में दशक या केवल कुछ वर्ष हो लगते हैं। लोग तेजी से यह जानने लगे हैं कि वे स्वयं, न कि उनके वंशज, अपने क्रिया-कलाप के फलों का भोग करेंगे।

हेगेल ने एक बार यह विचार प्रकट किया था—“विश्व-इतिहास में यह अक्सर घटित होता है कि सामान्यतया मानवीय क्रियाकलाप से भिन्न परिणाम भी उत्पन्न होते हैं, बजाय उनके जिन्हें कि लोग हासिल करना चाहते हैं और दर-असल जिन्हे हासिल करते हैं, बजाय उन परिणामों के जिन्हे वे सीधे तौर पर जानते हैं और उनके जिन्हें वे चाहते हैं; वे अपने हितों को प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेते हैं, किन्तु इससे और आगे के नतीजों को भी पैदा करते हैं—ऐसे जो उनमें छिपे हुए थे, किन्तु जिसके विषय में उन्हें अन्दाज तक नहीं था और जो उनकी योजनाओं में ही निहित नहीं थे।”¹ यह आधार वाक्य कुछ अर्थ रखता है जो किसी भी अर्थशास्त्री, परिस्थिति वैज्ञानिक, समाज-वैज्ञानिक आदि के लिए स्पष्ट होना चाहिए, खास कर आज के समकालीन गतिशील युग के आलोक में तीव्र गति से हो रहे विश्व-विकास तथा मनुष्य की बढ़ी हुई शक्ति की स्थिति में लोगों ने अपने क्रियाकलाप में वह भी देखना प्रारम्भ कर दिया है ‘जोकि उनमें छुपा हुआ है’—उनकी प्रारम्भिक योजनाओं में जो परिणाम सम्मिलित नहीं होते।

इन परिस्थितियों में भविष्य में अभिरुचि को मौजूदा कार्य व्यापार की अन्तिम स्वीकृति के रूप में मान लेने की बात अब अटकलबाजी का प्रश्न नहीं रहा और सबसे बढ़कर वह प्रतिदिन की जिंदगी के लिए व्यावहारिक महत्व का आर्थिक मुद्दा बन चुका है। हमारी दुनिया में जबरदस्ती घुसकर सामाजिक-आर्थिक तथा वैज्ञानिक शिखर पर बैठा भविष्य, एक प्रकार से, समकालीन पीढ़ियों को अपनी तथा आगे आने वाली पीढ़ियों, दोनों की, नियतियों की सामाजिक रूप से जिम्मेवारी सौंपता है।

जर्मनी के विद्वानों, हेगेन वेनहॉर और अर्नुस्ट श्माक ने लिखा—“जिस दुनिया में हम रहेंगे, कोई ‘प्रतिश्रुत भूमि’ नहीं होगी। यह सोचना अक्षम्य भ्रम होगा कि भविष्य के कई सकारात्मक पहलू, जो हमारे सामने 1970 के दशक की देहलीज़ पर प्रकट हो रहे हैं, हमारे कामों और फैसलों के लिए हमें जिम्मेवारी से बरी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विज्ञान एवं प्रविधि के द्वारा दिये गये अवसरों का लाभ उठाने के लायक भी रहेंगे कि नहीं। भविष्य प्रत्येक व्यक्ति, समूह, राज्य और राष्ट्र को समान रूप से जिम्मेवार बनाता है।”¹ यहाँ स्वाभाविक रूप से हम यह जोड़ना चाहेंगे कि हमारे समय में भविष्य के विषय में चिंतन पहले से कहीं अधिक बढ़े आयाम प्राप्त कर रहा है। पहले की तुलना में कहीं अधिक पक्ष इसमें निहित हैं तथा यह निरन्तर जटिल बनता जा रहा है। यह चिंतन प्रमुखतया सामाजिक समस्याओं पर केन्द्रित है।

भविष्यविज्ञान एवं विचारधारा

सन् 1817 में जब रौबर्ट ओबन² ने—जो एक 46 वर्षीय सफल कारखाने-दार उत्पादक थे, जिन्हें लन्दन के सर्वाधिक विशिष्ट घरानों में जिनमें बकिंघम पैलेस भी सम्मिलित है, सम्मान दिया जाता था—‘टाइम्स’ के पृष्ठों के माध्यम से और उस शहर की मीटिंगों में, जो शहर व्यापारिक दुनिया का हृदय था, अपने कम्युनिस्ट कल्पना लोक की घोषणा की थी, तो उसे व्यापक प्रचार मिला, किन्तु व्यावसायिक समुदाय ने उसकी योजना को आकस्मिक पागलपन की एक क्रिया मात्र माना।

यह नया डॉन क्विक्जोट कौन था? एक भद्र और उदार हृदय व्यक्ति, या एक ऐसा व्यवसायवादी जो लोगों की आत्माओं के ऊपर प्रसिद्धि और शक्ति की अपनी प्यास को शांत करना चाहता हो? या एक पागल आदमी जिसने अपने आपको खुदा या एक पैगम्बर के रूप में कल्पित कर लिया हो? व्यवसायी दुनिया ने स्वयं को असमंजस में पाया। इसमें आश्चर्य की बात थी ही क्या? दूर्ज्वा वर्ग तब एक उभरता हुआ वर्ग ही था, अभी तो ठीक अपनी क्षमताओं का दोहन शुरू

1. हेगेन एच० वेनहॉर/अनस्ट श्माक, ‘फाह्र प्लान इन दार्ई ज़ुकुनफ्ट दाइजेस्ट’, 1970, पृ० 11

2. रौबर्ट ओबन—उस कल्पनावादी समाजवाद के संस्थापक जो एक सामाजिक निसा के रूप में मार्क्सवाद के सैद्धांतिक स्रोतों में से एक था। पूँजीपति उत्पादक ओबन ने अपने कारखाने में कुछ प्रगतिशील सुधार लागू करने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने आगे मान लिया कि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए केवल सुधार लागू कर देनी ही काफी नहीं है बल्कि जीवन की सारी प्रणाली का पुनर्गठन आवश्यक है।

ही कर रहा था। उत्पादन करो, उत्पादन करो और फिर बार-बार उत्पादन करो : उन दिनों में बड़े व्यापार का यही आधारभूत सिद्धान्त था तथा व्यापारी-वर्ग वर्तमान में इतना तल्लीन था कि भविष्य के बारे में वह सोच ही नहीं सकता था। उसके फलस्वरूप तमाम पूर्व कथनों और भविष्यवाणियों को समय की वर-बादी समझा जाता था तथा यह माना जाता था कि उनका निजी उद्योग के हितों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। ओवन के विचारों को गम्भीरता से नहीं लिया गया, मानो वे किसी स्वप्नदृष्टा या पागल आदमी के अनर्गल प्रलाप हों।

स्थितियाँ बदल चुकी हैं, तथा कोई आधुनिक व्यापारी विशुद्ध राजनैतिक मामलों और सामाजिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों, दोनों में आँखें मूंदकर या भविष्य-कथनों की उपेक्षा करके व्यवसाय करने को पागलपन ही मानेगा। दीर्घकालिक पूर्वकथन प्रतियोगितात्मक संघर्ष का एक हिस्सा है जो इजारेदारियों के क्रिया-कलापों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक रक्षानों का मूल्यांकन और आगे की सम्भावनाओं का पूर्वानुमान एक साधन है जिसके आधार पर अनुकूल अवसरों का उपयोग किया जाता है तथा जहाँ कहीं सम्भव हो, अप्रत्याशित स्थितियों का मुकाबला किया जाता है।

बहुत-सी बातों में आज का स्पर्धापूर्ण संघर्ष उससे भिन्न है जिसका एग्रेल्स ने अपनी पुस्तक 'इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की दशा में वर्णन किया है—“यद्यपि कार-खानेदार उत्पादक जान सकता है कि प्रत्येक देश में वार्षिक तौर पर प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा की खपत होती है,” उन्होंने लिखा, “वह यह नहीं जान सकता कि किसी भी समय बहा कितना माल उपलब्ध है, तथा यह जानने की सम्भावना तो और भी कम है कि उसके प्रतिद्वंद्वियों ने वहाँ कितना निर्यात कर दिया है। वह कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के आधार पर लगा सकता है, वस्तुओं की उपलब्ध मात्राओं और उस समय की आवश्यकताओं के आधार पर अनिश्चित एवं कामचलाऊ अन्दाज ही लगा सकता है। उसे अपने माल के निर्यात में भाग्य पर ही भरोसा करना पड़ता है। अपने हर काम में वह अनुमान—जोकि संयोग पर आश्रित होता है—को आधार बनाता है।”

यह स्थिति—जो कि इजारेदारी पूर्व के पूँजीवाद की लक्षणिक है—आज भिन्न नजर आती है। कोई भी व्यापारी आँखें मूंद कर—सब कुछ संयोग पर छोड़ कर—धन विनियोजित नहीं कर सकता। वे चोटी पर पहुँचने के लिए उत्पादन के विषय में पूर्व कल्पना करनी होगी और बाजार की आवश्यकताओं और भावों के उतार-चढ़ावों को पूर्वानुमानित करना होगा। इन समस्याओं को कमोबेश सही रूप से मुलज्ञान के लिए अनेक कारकों को मद्दे नजर रखना होगा, और न केवल विशुद्ध

आर्थिक कारकों मात्र को ही, अपितु व्यापक सामाजिक प्रकृति के कारकों को भी। इसका अर्थ है कि इजारेदारियाँ दोनों प्रकार की—आर्थिक और सामाजिक—भविष्यवाणियों में अभिरुचि रखती है।

यहाँ एकाधिकार पूर्व के पूंजीवाद से भिन्न, जिसका चारित्रिक लक्षण उस क्षण की आवश्यकताओं की ओर उन्मुखता था, आज का समकालीन एकाधिकार-वादी पूंजीवाद, इसके अतिरिक्त, भविष्य को दृष्टि में रखकर भी अपनी गणना लगाता है। इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक-आर्थिक पूर्वानुमान के लिए बूर्जुआ राज्यों द्वारा तेज़ी से बढ़ाए जाने वाले आवंटनों में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका में लगभग 9 करोड़ डॉलर वार्षिक इस उद्देश्य के लिए एक दशक पहले खर्च किए जाते थे। जाहिर है, यह कोई संयोग नहीं था कि इजारेदारियों द्वारा सब प्रकार के पूर्वानुमान—जिसमें आर्थिक व सामाजिक भी सम्मिलित थे—से सम्बन्धित अनेक समूह, आयोग, संस्थान और एजेंसियाँ इजारेदारियों द्वारा स्थापित किये गये थे।

अतः सामाजिक पूर्वानुमान सबसे पहले इजारेदारियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के रूप में दिखाई दिए, और समकालीन पूंजीवाद की भविष्योन्मुखता के लिए भी बुनियादी कारण यही है।

कम्युनिज़म का उठता हुआ ज्वार, जिसके आगमन को पूंजीवाद अधिकाधिक स्पष्टतया महसूस करने लग गया है, उत्पादन के पुराने सम्बन्धों की सारी प्रणाली को ही साफ़ कर देगा, यह मान कर पूंजीवादी दुनिया 'पानी के नीचे साँस लेने' तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के भीषण प्रयत्न कर रही है। यह सामाजिक क्रांति के पूर्वाभास था जिसने पूंजीवाद को अपने भविष्य के विषय में सोचने को विवश कर दिया और; यदि सम्भव हो तो, कम्युनिस्ट भविष्य के विरुद्ध 'पूर्वाधिकार हेतु युद्ध' छेड़ देने की स्थिति बना दी ताकि वह अपने अस्तित्व को अधिकतम सीमा तक लम्बा कर सके।

एक ओर, पश्चिमी समाजशास्त्री वैज्ञानिक कम्युनिज़म के विश्वसनीय विकल्प, जो वस्तुतः बूर्जुआ व्यवस्था का भविष्य में प्रक्षेपण मात्र रह जाता है, की सरगमीं से खोज कर रहे हैं। दूसरी ओर वे कम्युनिस्टों से सामाजिक प्रगति के लोक-हितकारी विचारों को उधार लेने की चेष्टा करते हैं और यह भ्रामक विश्वास पालते हैं कि उन्हें पूंजीवादी समाज में ही क्रियान्वित किया जा सकेगा। भविष्य विज्ञान के प्रति सनक कम्युनिस्ट-विरोधी कार्यनीतियों में अपेक्षाकृत नया लक्षण है। ऐतिहासिक विकास के प्रवाह को बहुधा को अज्ञेय और अननुमेय अथवा पूर्व अकथनीय माना जाता था, तथा मानसवाद के सामाजिक विकास के पूर्व कथन की सम्भावना के विचार को कल्पनालोक की धारणा कहकर तिरस्कृत किया जाता था। पहले भविष्य विज्ञान शब्द का ही, जिसकी अवसराहना करते हुए उसे

आसमानों तक पहुँचाया जाता है—बिल्कुल भिन्न अर्थ था और उसका निशान 'मार्क्सवादी कल्पनालोकी चिन्तन' था। इसी सन्दर्भ में 'भविष्य विज्ञान' शब्द का प्रचलन अमरीकी विद्वान, ओस्तिप फ्लैकसीम द्वारा प्रारम्भ किया गया। भविष्य विज्ञान के आविष्कारक समस्त घटनाओं के ऐतिहासिक प्रवाह की भविष्यवाणी करने के सारे प्रयत्नों को 'छद्म वैज्ञानिक' कहकर अभिशप्त करते थे। उन्होंने लिखा—“चाहे किसी भी दृष्टिकोण से कोई इतिहास की प्रक्रिया को पूरी तरह तर्कसंगति देने की कोशिश करे, उसे ईश्वरीय शास्त्र प्रमाण के रूप में निर्मित करना असम्भव होगा। इसकी अपेक्षा हमें मनुष्य के इतिहास को मानव जातियों की एक अनन्त भ्रमण यात्रा के रूप में चित्रित करना पड़ेगा वह इधर-उधर यात्रा करते हुए बार-बार अपरिचित समुद्री किनारों पर उतरा।”¹ इसको सरलता से प्रस्तुत करने के चक्कर में फ्लैकसीम ने न केवल सामाजिक पूर्वकथन की सम्भावना को ही त्याग दिया है, अपितु इतिहास की प्रक्रिया के नियतिवाद को भी त्याग दिया है।

1970 के दशक में इस चित्र में काफी हद तक परिवर्तन आया। समाजवादी देशों की आर्थिक उपलब्धियों और पूँजीवादी अन्तर्विरोधों के बढ़ने में न केवल समाज की बढ़ती हुई शक्ति का ही प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया, अपितु दूसरों को अपने से सहमत करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि कम्युनिस्टों का ऐतिहासिक भविष्यकथन सही रहा है। इन तथ्यों के प्रकाश में पूँजीवाद के ऐतिहासिक परिदृश्य से सम्बन्धित प्रश्न नई शक्ति के साथ उभरा। इस विषय में जर्मन विद्वान् ऐरिक फ्रोम ने चिल्लाकर कहा—“पश्चिमी दुनिया एक अन्धी गली में है, इसने अपने बहुत-से आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और जीवन में अपनी सार्थकता और लक्ष्य को खो दिया है। बिना इस लक्ष्य के पश्चिमी समाज को भूतकाल के अन्य किसी समाज की तरह अपना तेजस्विता और आन्तरिक शक्ति को भी खोने को मजबूर होना पड़ेगा।”²

इस 'तेजस्विता और आन्तरिक शक्ति' को वापस प्राप्त करने के प्रयास में, पश्चिमी सिद्धांतकार भविष्य-विज्ञान का सहारा लेते हैं तथा पूँजीवाद और समाजवाद के बीच के ऐतिहासिक विरोध को भविष्य में स्थानांतरित कर देते हैं। पहले यह कहा जाता था कि इतिहास के प्रवाह के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, वह असम्भव है और इसलिए दुनिया के लिए कम्युनिस्ट परिदृश्य स्वप्नदृष्टाओं के आविष्कार से अधिक और कुछ नहीं, और इसलिए कम्यु-

1. ओस्तिप के० फ्लैकसीम, 'हिस्ट्री एण्ड फ्यूचरोलॉजी, मैसेनहेम, 1966, पृ० 100

2. ऐरिक फ्रोम, डेर मादन मेस्क अंड सेन बुकुपुत, फ्रेकफर्ट, 1969, पृ० 323

निस्टो पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि भविष्य को पहले से नहीं देखा जा सकता। अब इस बात पर जोर दिया जाता है कि मानवता के भविष्य के विषय में पूर्वकथन सम्भव है, वशतः, किसी तरह 'कम्युनिस्ट कल्पनालोको' को नकार दिया जाय और पूर्वानुमान या भविष्यवाणियाँ पूँजीवादी प्रतिमानों के आधार पर की जाएँ।

इन प्रतिबन्धों के साथ भविष्य-विज्ञान कम्युनिस्ट-विरोधी धारणाओं को सूचित करने में अपनी भूमिका अदा करता है। जहाँ कि पहले भविष्य की खोज-बीन करना किसी व्यक्ति विशेष कल्पना बिहारियों का क्षेत्र माना जाता था, आज भविष्य-वैज्ञानिक अध्ययन व्यापक और सुव्यवस्थित आधार पर किया जाता है। रिचर्ड निक्सन ने एक बार यह घोषणा की थी कि : "अमरीका का स्वप्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसे स्वप्नदर्शियों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है।"

अब लगभग सभी पूँजीवादी देशों में भविष्यव्यता ज्ञान की दर्जनों सरकारी और निजी संस्थाओं में धूम मची है तथा इससे जुड़े हुए कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे अध्ययन हटसन संस्थान, स्टैनफोर्ड विश्व-विद्यालय, दि अमेरिकन एकेडेमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज कमीशन ऑन दि इयर 2000 (सन् 2000 पर कला और विज्ञान आयोग की अमरीकी अकादमी)। रिसोर्सेज फ़ार द फ्यूचर, रैड निगम तथा अन्य में; फ्रांस में—ल, एतोसिएशन इंटर-नेशनल द फ्यूचरिबल्स, वकिंग ग्रुप फ़ॉर द ईयर 1985 ब्रिटेन; में—मैनकाइंड—2000, कमिटी फ़ॉर द नेक्स्ट थर्टी ईयर्स; जर्मनगण परिसंघ में—गेसेलशेफ़्ट फ़ार जुकुण्ड्समै जम एण्ड म्यूजिक और ट्यूबिजन में भविष्य-विज्ञान के संस्थानों आदि में किये जा रहे हैं।

रोम, वियना, टोक्यो, ओस्लो और अन्य नगरों में भी ऐसे केंद्र हैं जो भविष्य की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमरीका 600 से अधिक भविष्य विज्ञान के संगठन हैं।

इन संगठनों—जिन्हें राज्य तथा शक्तिशाली इजारेदारियों की आर्थिक सहायता प्राप्त है—के समस्त ससाधन कम्युनिस्ट भविष्य के विकल्प तथा पूँजीवाद के 'भविष्य-वैज्ञानिक औचित्य' की खोज पर संकेद्रित कर दिये गये हैं। कम्युनिज्म-विरोध के विचारकों ने अनेक ऐसे सिद्धांतों का सूत्रपात किया है जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ये वस्तुतः पूँजीवाद के समयन में प्रचारात्मक मूल्य ही रखते हैं।

पूँजीवादी-भविष्य-वैज्ञानिक इन उद्देश्यों को छिपाते नहीं। जैसे उनमें से एक ओटिस डडले डंकन, "जब सामाजिक विश्लेषण की कोई रचना जो—भविष्य के

से मुक्त है—आस्था जगती है तो वह विचारधारा बन जाती है; इसमें आस्था वाले लोग इसके बौद्धिक एवं नैतिक कंदी बन जाते हैं।” इन सिद्धांतों में छ तो आशा को बनाए रखते हैं, तथा कुछ लोगों में भ्रम पैदा करते हैं; तीसरे दृष्टि से उनको हताश करते हैं, जबकि कुछ और हैं जो आतंकित करने के काम में लाये जाते हैं। किंतु उन सबका उद्देश्य मजदूर वर्ग को आध्यात्मिक निहत्था कर देना है।

एच० जी० वेल्स के भावुक नायक जो शुद्ध उत्सुकतावश अपनी ‘टाइम मशीन’ इतरे से भरी यात्रा आरम्भ करता है, से भिन्न आधुनिक पूँजीवादी भविष्य-वास्तव में बड़े ध्वांसहारिक होते हैं। वे भविष्य में अपने भ्रमणों पर हमेशा तैयारशुदा फार्मूला साथ रखते हैं जिसके अनुसार वे अपनी कम्युनिस्ट-विरोधी तबाजियों को प्रमाणित कर सकें। भविष्य की वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ के बहाने वे आमतौर पर या तो सामाजिक यथास्थितिवाद का पूर्वानुमान हैं या समाजवादी आदर्शों की हार के विषय में भविष्यवाणियाँ वधारते

इस भ्रम में तल्लीनता कर रहे हैं कि किसी तरह भविष्य में बहिर्वेशित जिम्मेदारी पूँजीवाद कम्युनिज्म के विरोध में खड़ा करके सामाजिक क्रांति तगमन को विलम्बित किया जा सकेगा, पूँजीवादी विज्ञान एक बार फिर सा करता है कि भविष्य के विषय में क्रांतिकारी मार्क्सवादी शिक्षण को चुनौती प्य।

लेकिन इन प्रयत्नों के माध्यम से पूँजीवादी विद्वान एक खतरनाक साहसिक, जो पहले ही उनमें से कुछ के लिए गम्भीर खबराहट पैदा कर चुका है, अपने पर ले लेते हैं।

इतिहासिक प्रक्रिया का पूर्वानुमान

बहुत से लोगों ने भविष्य को पढ़ने की कोशिश की है। केवल बहुत ही कम नू विचारक वास्तव में घटनाओं के क्रम का पूर्वानुमान करने में समर्थ हो सके हैं कि एक अनिश्चित संख्या के सभी प्रकार के पूर्वानुमान मृतजात भविष्य-वाणियों के रूप में प्रकट होकर समाप्त हो चुके हैं।

एल्विन टॉफ़लर ने अपनी पुस्तक ‘फ्यूचर शॉक’ में कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध है। “सन् 1865 में एक अखबार के सम्पादक ने अपने पाठकों को बताया सुविज्ञ लोग जानते हैं कि तारों के माध्यम से आवाज को प्रसारित करनाभव है”। मुश्किल से एक दशक बाद मिस्टर वेल्स की प्रयोगशाला से

निस्टो पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि भविष्य को पहले से नहीं देखा जा सकता। अब इस बात पर जोर दिया जाता है कि मानवता के भविष्य के विषय में पूर्वकथन सम्भव है, वशर्ते, किसी तरह 'कम्युनिस्ट कल्पनालोको' को नकार दिया जाय और पूर्वानुमान या भविष्यवाणियाँ पूँजीवादी प्रतिमानों के आधार पर की जाएँ।

इन प्रतिवन्धों के साथ भविष्य-विज्ञान कम्युनिस्ट-विरोधी धारणाओं को सूचित करने में अपनी भूमिका अदा करता है। जहाँ कि पहले भविष्य की खोज-बीन करना किसी व्यक्ति विशेष कल्पना बिहारियों का क्षेत्र माना जाता था, आज भविष्य-वैज्ञानिक अध्ययन व्यापक और सुव्यवस्थित आधार पर किया जाता है। रिचर्ड निक्सन ने एक बार यह घोषणा की थी कि : "अमरीका का स्वप्न इतना महत्वपूर्ण है कि उसे स्वप्नदर्शियों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है।"

अब लगभग सभी पूँजीवादी देशों में भविष्यव्यता ज्ञान की दर्जनों सरकारी और निजी संस्थाओं में धूम मची है तथा इससे जुड़े हुए कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसे अध्ययन हडसन संस्थान, स्टैनफोर्ड विश्व-विद्यालय, दि अमेरिकन एकेडेमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज कमीशन ऑन दि इयर 2000 (सन् 2000 पर कला और विज्ञान आयोग की अमरीकी अकादमी)। रिसर्सेज फॉर द फ्यूचर, रैड निगम तथा अन्य में; फ्रांस में—स, एसोसिएशन इंटर-नेशनल द फ्यूचरिबल्स, वकिंग ग्रुप फॉर द ईयर 1985 ब्रिटेन; में—मैनकाइंड—2000, कमिटी फॉर द नेक्स्ट थर्टी ईयर्स; जर्मनगण परिसंघ में—गेसेलशेफ्ट फर जुकुण्ड्स जेन एण्ड म्यूजिक और ट्यूबिंजन में भविष्य-विज्ञान के संस्थानों आदि में किये जा रहे हैं।

रोम, वियना, टोक्यो, ओस्लो और अन्य नगरों में भी ऐसे केंद्र हैं जो भविष्य की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमरीका 600 से अधिक भविष्य विज्ञान के संगठन हैं।

इन संगठनों—जिन्हें राज्य तथा शक्तिशाली इजारेदारियों की आर्थिक सहायता प्राप्त है—के समस्त संसाधन कम्युनिस्ट भविष्य के विकल्प तथा पूँजीवाद के 'भविष्य-वैज्ञानिक औचित्य' की खोज पर संकेंद्रित कर दिये गये हैं। कम्युनिज्म-विरोध के विचारकों ने अनेक ऐसे सिद्धांतों का सूत्रपात किया है जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ये वस्तुतः पूँजीवाद के समर्थन में प्रचारात्मक मूल्य ही रखते हैं।

पूँजीवादी-भविष्य-वैज्ञानिक इन उद्देश्यों को छिपाते नहीं। जैसे उनमें से एक ओटिस डब्ले डंकन, "जब सामाजिक विश्लेषण की कोई रचना जो—भविष्य के

चित्र से मुक्त है—आस्था जगाती है तो वह विचारधारा बन जाती रखने वाले लोग इसके बौद्धिक एवं नैतिक कंदी बन जाते हैं।”¹ से कुछ तो आशा को बनाए रखते हैं, तथा कुछ लोगों में भ्रम पैदा नैतिक दृष्टि से उनको हताश करते हैं, जबकि कुछ और हैं जो आत लिए काम में लाये जाते हैं। किंतु उन सबका उद्देश्य मजदूर वर्ग को रूप से निहत्था कर देना है।

एच० जी० वेल्स के भाबुक नायक जो शुद्ध उत्सुकतावश अपनी ‘टा पर खतरे से भरी यात्रा आरम्भ करता है, से भिन्न आधुनिक पूंजीवाद ज्ञानी वास्तव में बड़े ध्यावहारिक होते हैं। वे भविष्य में अपने भ्रमणों पर एक तैयारशुदा फार्मूला साथ रखते हैं जिसके अनुसार वे अपनी कम्प्युनिस्ट भटकलबाजियों को प्रमाणित कर सकें। भविष्य की वैज्ञानिक भविष्य करने के बहाने वे आमतौर पर या तो सामाजिक यथास्थितिवाद का पूव करते हैं या समाजवादी आदर्शों की हार के विषय में भविष्यवाणियाँ ब है।

इस भ्रम में तसल्ली तलाश करते हुए कि किसी तरह भविष्य में बहिवें राज्य-इजारेदारी पूंजीवाद कम्प्युनिज्म के विरोध में खड़ा करके सामाजिक के आगमन को विलम्बित किया जा सकेगा, पूंजीवादी विज्ञान एक बार की कोशिश करता है कि भविष्य के विषय में क्रांतिकारी मार्क्सवादी शिक्षण को चुनौ दी जाय।

लेकिन इन प्रयत्नों के माध्यम से पूंजीवादी विद्वान एक खतरनाक साहसिक कार्य, जो पहले ही उनमें से कुछ के लिए गम्भीर घबराहट पैदा कर चुका है, अपने सिर पर ले लेते हैं।

ऐतिहासिक प्रक्रिया का पूर्वानुमान

बहुत से लोगों ने भविष्य की पढने की कोशिश की है। केवल बहुत ही कम महान् विचारक वास्तव में घटनाओं के क्रम का पूर्वानुमान करने में समर्थ हो सके हैं, जबकि एक अनिश्चित संख्या के सभी प्रकार के पूर्वानुमान मृतजात भविष्य-वाणियों के रूप में प्रकट होकर समाप्त हो चुके हैं।

एल्विन टॉफ़लर ने अपनी पुस्तक ‘फ्यूचर शॉक’ में कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध किया है। “सन् 1865 में एक अखबार के सम्पादक ने अपने पाठकों को बताया कि ‘सुविज्ञ लोग जानते हैं कि तारों के माध्यम से आवाज को प्रसारित करना असम्भव है...’।”¹ मुश्किल से एक दशक बाद मिंस्टर बेल की प्रयोगशाला में

1. ‘द पब्लिक इंटरेस्ट’, अंक 17, 1969, पृ० 107

टेलीफोन की आवाज़ फूट निकली और उसने दुनिया को बदल दिया ।

"उसी दिन जबकि राइट बन्धुओं ने उड़ान भरी, अखबारों ने उस घटना की रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनके सम्पादक—जो गम्भीर व विवेकशील थे तथा जिनके पाँव जमीन पर टिके हुए थे—आसानी से इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि ऐसा हो चुका है । क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही तो एक प्रसिद्ध अमरीकी खगोलज्ञ, साइमन न्यूकोम्ब, ने संसार को भरोसा दिलाया था कि 'ज्ञात वस्तुओं का कोई भी सम्भव मिश्रण, मशीनरी के ज्ञात स्वरूप और शक्ति के ज्ञात स्वरूप को किसी भी व्यावहारिक यंत्र में एक जगह इस रूप में संयोजित व व्यवस्थित नहीं किया जा सकता कि उसका उपयोग करके आदमी लम्बी दूरियों तक उड़ पाए ।"

"इसके कुछ समय बाद ही एक दूसरे विशेषज्ञ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि घोड़ाबिहीन गाड़ी के चलन के प्रयोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा कमजोर दिमाग वाले ही कर सकते हैं । छः साल बाद दस लाखवीं फ़ोर्ड एक ऐसेम्बली लाइन पर चल पड़ी ।"¹

वैज्ञानिकों को प्रकृति विज्ञान और प्रविधि में एक या दूसरी प्रवृत्ति की सम्भावनाओं का सही मूल्यांकन करने से और भविष्य की शक्त का प्राप्त करने से वैज्ञानिकों को किसने रोका है ?

सर्वप्रथम, उनकी आत्मपरकता तथा उनके व्यावहारिक पूर्वाग्रह ने रोका है जो भविष्य के भीतर प्रक्षेपित हैं । वे अनिवार्यतः भूतकाल की धारणाओं के वशीभूत हैं, उन मतांशों के, जो प्रतिदिन की वास्तविकता के द्वारा धोये गए हैं और मानसिकता के कुछ प्रतिरूपों को निर्धारित करते हैं ।

इसे पहले से देख पाने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मपरकता को और पुरानी रूढ़ियों को दूर फेंका जाय, अन्यथा पूर्वकथन और भविष्यवाणी के सारे प्रयास घोर असफलता में समाप्त हो जाएंगे ।

यह प्रकृति विज्ञान और तकनीकी ज्ञान और उत्पादन के विकास पर तो लागू होता ही है, किन्तु इससे भी अधिक समाज के जीवन पर भी लागू होता है जहाँ पूर्वानुमान के प्रयासों में बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक बन जाता है, तथा जो काफी अधिक मुश्किल काम है ।

भविष्य केवल उनके लिए खुलता है जो वास्तविकता की समूची जटिल यंत्र-विधि को समझने की योग्यता रखते हैं, उसके दृश्य और अदृश्य उत्तोलकों का ज्ञान रखते हैं ।

सामाजिक प्रगति के सन्दर्भ में इस पद्धति का विकास मार्क्स, एंगेल्स और

लेनिन द्वारा किया गया। इतिहास उनके विचारों एवं उनकी धारणाओं की विजय को प्रमाणित करता है और उनकी पद्धति के सही होने की पुष्टि करता है। जो बात बड़े-से-बड़े विज्ञान कथालेखकों की आँखों से छिपी रही उसे यह पद्धति प्रकाश में ले आती है।

लेनिन के साथ अपनी मुलाकातो, तथा रूस के भविष्य के सम्बन्ध में उनके विचारों का स्मरण करते हुए, एच० जी० वेल्स ने अपनी पुस्तक 'रशा इन द शैडोज' में लिखा—“गहरे स्फटिक सरीभे रूस में मुझे उस तरह का घटित होता कुछ नहीं दिखता जो कि क्रैमलिन में बैठे इस छोटे से आदमी को दिखता है : वह देखता है कि सड़ी गली रेलों की जगह नए विद्युत् पातायात के साधन लगाए जा रहे हैं, वह देखता है कि नई सड़कों का जाल सारे देश की धरती पर पूरी तरह फैल रहा है, वह देखता है कि फिर से एक नया और अधिक खुशहाल कम्युनिस्ट औद्योगिकीकरण उदित हो रहा है।”¹ क्रांति के नेता ने उससे भी काफ़ी दूर तक देखा : बीस साल गुजरे और सोवियत संघ दुनिया के औद्योगिक उत्पादन के कुल परिमाण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर पहुँच गया।

‘माक्सवादी-लेनिनवादी पूर्वानुमान भूत और वर्तमान के वस्तुगत नियमों और प्रवृत्तियों की गहन वैज्ञानिक समझ से प्रस्फुटित होता है। लियोन लावाली, जो ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ के घोषणापत्र को सामाजिक भविष्यवाणी का उदाहरण मानते हैं, की मान्यता है कि “माक्स और एंगेल्स ने, इसके मूलभूत सिद्धांतों को (भूतकाल के) पूर्वगामी समाजों के अध्ययन, तथा पूँजीवादी समाज—वे जिसमें जी रहे थे (वर्तमान) के विश्लेषण के आधार पर सूत्रबद्ध किया था।” इसके बाद वह आगे कहते हैं—“इस आधार पर उन्होंने उन नियमों की खोज की जो एक नीचे की सामाजिक अवस्था से ऊपर की सामाजिक अवस्था में संक्रमण को संचालित करते हैं, और इस प्रकार उन्होंने पूँजीवाद की समीक्षा निमित्त की तथा सामाजिक विकास के विज्ञानसम्मत मार्ग पर चलकर उन्होंने सामाजिक विकास की अगली अवस्था—कम्युनिज्म—की भविष्यवाणी की।”²

अपने समय के पूँजीवादी समाज की ऐतिहासिक प्रक्रिया और सामाजिक षटनाक्रम का वैज्ञानिक दृष्टि से विवर्णन करते हुए, माक्स और एंगेल्स ने उत्पादक शक्तियों के विकास की सामान्य प्रवृत्ति को उद्घाटित किया जो देर-सबेर उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्धों को अनिवार्यतः समाप्त कर देगी। इसके माथे हैं कि कम्युनिज्म एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है।

1. एच० जी० वेल्स, 'रशा इन द शैडोज', लंदन, पृ० 135-36
2. लियोन लावाली, 'पोअर अन कंसेप्शन मार्क्सिस्ट डे ला प्रोलेटियट', पेरिस, 1970,

अतः मार्क्सवाद की सामाजिक भविष्यवाणी के वैज्ञानिक आधार यथार्थ के अभिज्ञान की द्वन्द्वात्मक और भौतिकवादी पद्धति के लागू करने में निहित हैं। यह पद्धति किसी भी अध्येता से अपेक्षा रखती है कि सामाजिक घटना क्रियाओं की पड़ताल उनके विकास की प्रक्रिया में ही की जाय। लेनिन ने लिखा—“कौन नहीं जानता कि किसी भी सामाजिक घटना-क्रिया की, उसके विकास की प्रक्रिया में, परीक्षा करेंगे तो उसमें अतीत के अवशेष, वर्तमान की बुनियाद तथा भविष्य के बीज अनिवार्य रूप से प्रकट होंगे।”¹

उन उत्पादक शक्तियों का जिन्हें उनके विकास की प्रक्रिया में पूँजीवादी समाज ने एकत्रित किया, अध्ययन करते हुए मार्क्स और एंगेल्स ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि कम्युनिज्म न तो एक कल्पनालोक है और न ही एक स्वप्न, किन्तु उनके विकास का चरम लक्ष्य तथा आवश्यक परिणाम है।

लेनिन के शब्दों में, “मार्क्स का सिद्धांत विकास के सिद्धांत—जोकि सर्वाधिक सुसंगत, सम्पूर्ण, सुविधारित एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुत है—का आधुनिक पूँजीवाद के सन्दर्भ में व्यावहारिक रूप है। मार्क्स के सामने स्वाभाविक तौर पर जो प्रश्न था वह पूँजीवाद के अवश्यभावी अधःपतन तथा भावी कम्युनिज्म के भविष्य के सन्दर्भ में इस सिद्धांत के उपयोग से जुड़ा हुआ था।”²

लेनिन की दृष्टि में ये इस बात में निहित है कि कम्युनिज्म ऐतिहासिक रूप से पूँजीवाद से विकसित होता है तथा यह पूँजीवाद से उत्पन्न सामाजिक शक्ति के कार्य-व्यापार का परिणाम है। भविष्य के बारे में मार्क्स ने कोई अटकलबाजी नहीं की। उन्होंने कम्युनिज्म की समस्या को एक प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता के तरीकों से प्रस्तुत किया जो जैविक संरचना के विकास का अध्ययन इस आधार पर करता है कि यह कैसे पैदा हुई और किस दिशा में विकसित हो रही है।

मार्क्स और एंगेल्स, दोनों, ने जोर देकर कहा कि उनकी भविष्य सम्बन्धी धारणाएँ अपने समय की तथ्यात्मक, ऐतिहासिक, भौतिक एवं सामाजिक घटना-क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं—“हमारे दृष्टिकोण तथा समकालीन समाज और भविष्य के गैर-पूँजीवादी समाज की भिन्नता को प्रकट करने वाले लक्षण स्पष्टतया वे निष्कर्ष हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों और विकास की प्रक्रियाओं से निकाले गए हैं, तथा उनका कोई भी सैद्धांतिक या व्यावहारिक मूल्य नहीं है यदि इन प्रक्रियाओं के सन्दर्भ से हटाकर भंगे रूप में अलग से

1. बी० आई० लेनिन 'लोगो के दोस्त कौन हैं और वे सामाजिक जनवादियों से कैसे सड़ते हैं', संकलित रचनाएँ, खंड 7, पृ० 179

2. लेनिन, 'राज्य और क्रांति' संकलित रचनाएँ, खंड 25, पृ० 457-58

माक्सवाद-लेनिनवाद की शक्ति इस बात में निहित है कि यह घटनाक्रियाओं को उनके विकास की प्रक्रिया में परीक्षित करता है । निम्नांकित उदाहरण इस प्रयास को यथेष्ट से अधिक रूप में चित्रित करता है । माक्स ने विश्वव्यापी पैमाने पर सर्वहारा क्रांति की बात कही, जो कि पूर्व-इजारेदारी पूंजीवाद की परिस्थितियों के अधीन पूर्णतया सही अवधारणा थी । किन्तु जब पूंजीवाद देश विकास की साम्राज्यवादी अवस्था में प्रविष्ट हो गए तो एक नई सामाजिक प्रवृत्ति—उनके असमान विकास—ने स्वयमेव अपने-आपको प्रकट कर दिया । इसकी जाँच करने पर लेनिन ने बुलंदी के साथ यह भविष्यवाणी की : "असमान आर्थिक और राज-नैतिक विकास पूंजीवाद का चरम नियम है । अतः पहली बार अनेक या किसी अकेले पूंजीवाद देश में समाजवाद की विजय सम्भव है ।"²

इस प्रकार माक्सवाद-लेनिनवाद समाजशास्त्रीय पूर्वकथन की जटिल पद्धति को अपनाता है । इससे न केवल परिमाणात्मक संशोधन का पूर्वकथन ही सम्भव होता है अपितु एक या दूसरी घटनाक्रिया के गुणात्मक संशोधन के विषय में भी पूर्वकथन सम्भव हो जाता है । परिणामस्वरूप किसी घटनाक्रिया को उसकी प्रगति के रूप में जाँचा जाता है, जबकि वह अभी अपने सबसे ऊँचे बिन्दु की ओर बढ़ रही है, जब परिमाण गुण में बदल ही रहा है और सामाजिक घटनाक्रिया अपनी विपरीतता में बदल रही है । इस पद्धति को धन्यवाद कि इसके आधार पर नितांत नई सामाजिक घटनाक्रियाओं के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है ।

माक्सवादियों ने अपने-आपको कभी भी भविष्य में उत्पादक शक्तियों के सामान्य बहिर्गमन तक सीमित नहीं रखा । कुछ मर्यादाओं के साथ यही बात प्राविधिक प्रक्रियाओं और आर्थिक रक्षानों के विषय में भी की जा सकती है, किन्तु सामाजिक घटनाक्रियाओं के बाटे में नहीं । उदाहरण के लिए, जब उत्पादक शक्तियों के विकास की विश्व-व्यापी और ऐतिहासिक दृष्टि से जाँच करते हुए, इसको अनंतता में नहीं डाल दिया जाता जैसा कि भविष्यविज्ञानी प्रायः करते हैं । विचारणीय बिन्दु यह है कि अपने विकास की प्रक्रिया में उत्पादक शक्तियाँ उत्पादक सम्बन्धों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करती रहती हैं जो उनकी प्रगति में गतिरोध पैदा कर देता है या उसे एकदम रोक देती है ।

इसीलिए, न तो माक्स-एंगेल्स ने और न लेनिन ने ही भविष्य—उसकी समस्त विशिष्टताओं के विस्तृत विवरण सहित—को जानने की आकांक्षा पाली और न

1. माक्स-एंगेल्स, वर्क, खंड 36, पृ० 429
2. लेनिन, 'यूरोप के संयुक्त राज्यों के नारे के सम्बन्ध में', संकलित रचनाएँ, खंड 21, पृ० 342

तियवार भविष्यवाणियाँ करने का इरादा व्यक्त किया। मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास की सामान्य प्रवृत्तियों व मुख्य आकृतियों पर ही जोर दिया। मार्क्सवादियों के लिए कम्युनिस्ट समाज की विजय ऐतिहासिकतः पूर्वनिर्धारित है और उत्पादक शक्तियों के विकास की, तर्कसंगत परिणति है। लेकिन जैसा कि लेनिन ने लिखा—
 “किन अवस्थाओं से गुजरकर व किन व्यावहारिक साधनों के जरिए मानवता इस सर्वोच्च लक्ष्य तक आगे बढ़ेगी हम नहीं जानते और जान भी नहीं सकते।” “एक अन्य स्थान पर लेनिन ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा—” हम यह दावा नहीं करते कि मार्क्स जानते थे या मार्क्सवादी जानते हैं कि ‘अ’ से ‘ज्ञ’ तक समाजवाद का यही रास्ता है। इस प्रकार का कोई दावा करना निरी मूर्खता होगा। जो कुछ हम जानते हैं वह है उस रास्ते की दिशा, और वे वर्ग शक्तियाँ जो इसका अनुसरण करती हैं; विशिष्ट व्यावहारिक विस्तार केवल लाखों लोगों के अनुभवों के बीच में से होकर प्रकाश में आएगा जब वे सब कुछ अपने स्वयं के हाथों में ले लेंगे।”²

जहाँ तक ऐतिहासिक प्रक्रिया की मुख्य दिशाओं का सम्बन्ध है, मार्क्सवाद-लेनिनवाद की प्रस्थापनाओं ने, दुनिया को बदलने वाली बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में आश्चर्यजनक रूप से सही भविष्यवाणी की : जैसे—दुनिया के क्रांतिकारी आन्दोलन के केन्द्र को बदलकर उसे पूर्व की ओर कर देना, सर्वहारा क्रांति का रूस के द्वारा उद्घाटित किया जाना, प्रथम विश्वयुद्ध का चरित्र और उसके नतीजे, संक्रमण काल की आवश्यकता, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, पूँजीवाद का इजारेदारी के रूप में विकास विज्ञान का सीधे तौर पर उत्पादक शक्ति के रूप में रूपांतरण, समाजवाद में संक्रमण के स्वरूपों की विविधता, ‘आणविक गतिरोध’ की स्थिति आदि के बारे में।

ये सब पूर्वकथन किसी भविष्यवक्ता अथवा किसी प्रतिभा की कल्पना की उपज नहीं थे, किन्तु सामाजिक पूर्वानुमान की उस वैज्ञानिक पद्धति के परिणाम थे जिसे मार्क्सवाद के आदर ग्रन्थों ने प्रतिष्ठित किया था। बूज्वा भविष्य विज्ञान भी वैज्ञानिक आधार रखने का दावा करता है। इसके पास बहुत शानदार गणक केन्द्र हैं जिनकी सेवाओं का वे उपयोग करते हैं तथा भविष्य वैज्ञानिकों ने सामाजिक पूर्वानुमान की अनेक पद्धतियाँ विकसित कर ली हैं।

कुल मिलाकर, बूज्वा वैज्ञानिकों का अनुभव जो इन पद्धतियों के (जो निस्सन्देह

1. लेनिन, ‘राज्य और क्रांति’, पृ० 472

2. लेनिन, ‘जनवादी की दावों से’, संकलित रचनाएं, खंड 25, पृ० 281

शुद्ध रूप से परिमाणात्मक है) सामू करने में उन्हें मिला, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्राविधिक भविष्यकथन के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भविष्य वैज्ञानिक बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं तथा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। किंतु इन पद्धतियों को अधिरचना के स्तर पर स्थानांतरित करने तथा सामाजिक सम्बन्धों के विकास को स्थापित करने के प्रयास समीक्षा की कसौटी पर घरे नहीं उतरते। कोई भी गुणात्मक पद्धतियाँ पूँजीवादी भविष्यवक्ताओं की कमजोरियों अर्थात् उनके चिंतन की क्षुब्धता को जो पूँजीवाद की पक्षधरता से पैदा होती है, को दूर नहीं कर सकती हैं। फलस्वरूप, कोई भी उपकरण और कोई भी पद्धति विज्ञान चाहे उनको उगके सूक्ष्मतरंग विस्तारों के द्वारा कितना ही विस्तृत करके क्यों न रखा गया हो—सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। निष्कर्षतः सामाजिक सम्भावनाओं की क्षति की घोषणा करके, अवैज्ञानिक एवं धूर्ततापूर्ण भविष्यवाणियाँ करके, या प्रकट रूप से प्रचारात्मक स्वभाव की पक्ष समर्थक भविष्यवाणियाँ करके अपने कार्य की इतियी कर देंगे।

पश्चिमी भविष्यज्ञानियों की वैज्ञानिकों के रूप में यह धासदी है कि उनके प्रस्थान मार्ग पर ही उन्हें वर्गों की सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखना पड़ता है, और इसलिए उनकी भविष्यवाणियाँ जीवन के सम्पर्क में आने पर ताश के पत्तों के मकान की तरह ढह पड़ती हैं। उनमें से बहुत-सी तो इसी क्षण ढह रही हैं, यानी सन् 1974-75 के संकट के सन्दर्भ में भविष्यज्ञानियों ने जिसकी न तो 'पूर्व कल्पना की थी' और न भविष्यवाणी ही की थी। इस संकट के सामने वैल, काहन, गॉल्ड्रेय, टॉफ़लर तथा अन्य विचारकों द्वारा चित्रित उज्ज्वल प्राविधिक सम्भावनाएँ हवाई किलो से अधिक सिद्ध नहीं हुईं।

इन स्थितियों में बूज्वा भविष्यशास्त्र ने अपना अधिकांश आत्मविश्वास खो दिया, तथा यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इसके विशेषज्ञ अपनी कार्य-नीतियों में सुधार करने को विवश हुए हैं। आज उनके शत्रु नाना प्रकार के अस्पष्ट वक्तव्यों से शुरू होते हैं। पहले जो आत्मविश्वास और सफ़ाई के साथ अभिव्यक्त किया जाता था, वही अब अधिक बारीकी से, पूर्व के कपटी भाग्य फल बताने वालों के तरीके को अपनाते हुए, प्रस्तुत किया जाता है।

इस दृष्टि से अमरीकी भविष्यशास्त्री हरमन काह्न की ताज़ा पुस्तक, जिसका शीर्षक 'आगामी 200 वर्ष' है, बेहद दिलचस्प है। रैंड कर्पोरेशन के निदेशक तथा एक अन्य पुस्तक—'सन् 2000 का साल' के लेखक काहन वस्तुतः इस बात को जानते थे कि उनके पहले के पूर्व कथनों का क्या हुआ, तथा संभवतया इसीलिए उन्होंने अपने शत्रुविचारों में एक रोचक नव-प्रयोग जोड़ दिया। उनके वैचारिक सिद्धांत वही रहे, तथा अमरीका के भविष्य में उनका आशावाद 1970

के दशक के संकट के बावजूद बना रहा। वह आश्वस्त करने की चेष्टा करते हैं कि आगामी 200 वर्षों में अमरीकी लोग 'समृद्धि' एवं दौलतमंदी प्राप्त कर लेंगे। किन्तु काहन काफी सतर्कता बरतते हुए कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच्ची साबित नहीं होगी, यदि भुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं हासिल किया गया तो।

फ्रांसीसी भविष्यशास्त्री एडमंड स्टिलमैन अपने भविष्य कथन में कि फ्रांस सन् 1980 तक आर्थिक क्षेत्र में यूरोप का नेतृत्व करेगा, इसी प्रकार की शर्त लगा देते हैं। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिचर्ड वेल्सी का कहना है कि सन् 2000 तक ऊर्जा उपभोग के सम्बन्ध में उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होगी यदि अगले दो दशकों में रानैतिक स्थिति में स्थिरता रही और ब्रिटेन तथा दूसरे पूंजीवादी देशों की आर्थिक वृद्धि लगातार जारी रही।¹

यह है भविष्यवाणी का एक सरस और भरोसेमंद तरीका जिसे अक्सर काम में लिया गया।

पश्चिमी भविष्यशास्त्रियों द्वारा किये गये असाधारण दावों से पाठक का प्रायः सामना होता है। जैसे अमरीकी राजनीतिवेत्ता वी० पी० बैकविड ने बहुत बड़ा निबंध लिखा जिसको उन्होंने एक अर्धगर्भित शीर्षक—“आगामी 500 वर्षः प्रमुख सामाजिक प्रवृत्तियों की वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ” दिया। वह इस बात से सुरक्षा अनुभव करते हैं कि वह अपने शत्रुओं के लिए जिम्मेवारी उठाने के वास्ते उपलब्ध नहीं होंगे, और इस तरह उनका सम्मान पूरे पाँच सौ वर्षों तक के लिए सुनिश्चित हो जाएगा।

अन्य अमरीकी भविष्यशास्त्रियों ने अपने पूर्वकथनों की अन्य प्रकार से 'गारंटी देने' के तरीके खोजे। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार सन् 1980 में मानवता के लिए कम-से-कम एक सौ विश्वविपत्तियों के आने के कारण उसके समाप्त होने का योग है। इनमें विश्व प्रलयप्रवाह, एक और हिमयुग का आरामन, ताप नाभिकीय युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, परिस्थितिजन्य संकट, यंत्रमानवों (रोबोट) के द्वारा मानव का दासकरण और उसी प्रकार की अन्य प्रकार की महा-विपत्तियाँ शामिल हैं। और जब उनमें से प्रत्येक सौ में से एक की संभावना है, तथा जब वे कुल मिला कर सौ बतायी गयी हैं, तो यह तो माना ही जा सकता है कि उनमें से कम-से-कम एक तो निश्चित ही घटित होगी।²

पश्चिम के भविष्यज्ञानियों में अग्रणी एल्विन टॉफ़लर भी इन स्पष्टोक्त, नितांत

1. रिचर्ड बैले, 'ट्रैडिशनल इनर्जी रिसोर्सेज, प्रेडिक्ट स्टेट एण्ड क्यूचर डिवेलपमेंट', प्रयुक्त, चं० 4, सं० 2, जून 1972, पृ० 103-114

2. देविष्ट, ई० ए० अरब बर्गली 'भविष्यवाणियों की भूल-भूलैया में', मास्को, 1975, पृ० 216

ठोस भविष्यवाणियों के औचित्य पर संदेह व्यक्त करते हैं और अपने महयोगियों का अधिक सावधान और सतर्क बनने के लिए आह्वान करते हैं। वह लिखते हैं—“कोई भी गंभीर भविष्यवादी ‘भविष्यवाणियों’ में नहीं उलझता। वे दूरदर्शन की देववाणियों और समाचारपत्रों के ज्योतिषियों के लिए छोड़ दी जाती हैं। कोई भी, जो हल्के तौर पर भी पूर्वकथन की जटिलताओं से परिचित है, दावा नहीं कर सकता कि उसे आगामी कल का एकांतिक ज्ञान है”।

“इसका मतलब है कि भविष्य के विषय में कोई भी वक्तव्य इस रूप में होना चाहिए कि उसमें उसकी विशेषक शर्तें—‘अगर, मगर, और दूसरी ओर’ आदि भी साथ में रहें।”

अस्पष्ट तथा द्विअर्थी शर्तों की सहायता से अपने पूर्वकथनों की विश्वसनीयता एवं संभाव्यता में वृद्धि करने के बूज्बा भविष्यवक्ताओं के प्रयास बूज्बा भविष्य-विज्ञान के संकट तथा विश्वव्यापी ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रमाणित करने की उसकी असमर्थता को ही उजागर करते हैं। ‘देल्फी की देववाणियों’ से नाम मात्र को अलग, भविष्य विज्ञान नीमहकीमी में परिवर्तित हो रहा है।

वहुत से सीधे-सादे लोगों ने इन देववाणियों की द्विअर्थी भविष्यवाणियों को सही ढंग से न समझ पाने व उनकी आदिम तथा सपाट व्याख्या करने के कारण भारी मूल्य चुकाया है।

“क्या मैं पर्सियनों के विरुद्ध युद्ध छोड़ दूँ?” लीडिया के राजा क्रोसस ने देल्फी में अपोलो के मंदिर के पादरियों से पूछा और सीधा उत्तर प्राप्त किया : “यदि तुम हिलीज नदी को पार करोगे तो एक बड़ा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा।” क्रोसस इस उत्तर से खुश था और उसने एक बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया। यह दूसरी बात है कि वह उसका खुद का ही बड़ा साम्राज्य था। क्या कोई इस गलत समझ के लिए किसी देववाणी को लाञ्छित कर सकता है?

क्या पूंजीवाद और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति एक-दूसरे के अनुकूल हैं ?

पूँजीवादी भविष्यशास्त्र ने सामाजिक रूपांतरणों की अनिवार्यता से इन्कार करके अपने आपको एक बंद गली में फँसा दिया है; यद्यपि ये रूपांतरण निरंतर बढ़ती हुई तीव्रता के साथ घटित होते जा रहे हैं। जॉन बर्नल की मान्यता थी कि विज्ञान और कंप्यूटरों का युग अपरिहार्य रूप से समाजवाद का युग है।

समकालीन प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक विज्ञान का प्रत्यक्ष उत्पादक शक्ति के रूप में रूपांतरण है। तो भी, निजी उद्योग की परिस्थितियों के

अंतर्गत इस नयी विवेकता का मानवता के विशाल हितों में पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा सकने का संवर्धन तथा व्यक्ति के उपयोग के लिए उपभोक्ता मालो का उत्पादन एक ही चीज नहीं है। अपने सामाजिक प्रयोजन एवं प्रकार्य की दृष्टि से ज्ञान सारे समाज से सम्बन्धित है, इसका कारगर संचय और इसकी क्रियान्विति केवल सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही संभव है जो वस्तुतः उन मानदंडों से भिन्न है जो पूँजीवादी समाज द्वारा निर्धारित हैं।

जहाँ तक समाज का सम्बन्ध है विज्ञान पर किए जाने वाले खर्च हमेशा अथवा लगभग हमेशा कारगर साबित होते हैं। वे आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में भी न्याय संगत है जबकि यह ज्ञात हो कि किसी पीढ़ी विशेष के जीवनकाल में किसी प्रकार के व्यावहारिक शोध-परिणामों के निकलने की आशा नहीं की जा सकती। संभाव्य सामाजिक परिणाम के निकलने की स्थिति में, तथा तात्कालिक निजी लाभ के न होने पर भी सत्य की खोज का अपना औचित्य है, चाहे उसकी सफलता की न्यूनतम संभावना ही क्यों न हो। पौधे (जो दूसरों को खाने के लिए फल उपलब्ध करेंगे) रोपते हुए बूढ़े आदमी की परंपरागत छवि विज्ञान की समकालीन प्रगति तथा इसके विकास की आवश्यकताओं के आवश्यक लक्षण की प्रतीक ही है।

वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति के युग में विज्ञान के प्रति रुझान, पहले से कहीं अधिक, समाज के विकास को निर्धारित करता है और भविष्य के प्रति इसके दृष्टिकोण को भी तय करता है। विज्ञान के लिए समाज का जितना अधिक सरोकार आज व्यक्त होगा, उतने ही अच्छे फल वह फल प्राप्त करेगा। इसलिए समाज की ओर से विज्ञान की तरक्की के लिए जो प्रयास आज किए जा रहे हैं वे एक प्रकार से सुरक्षित पूँजीनिवेश हैं जो कभी व्यर्थ नहीं होंगे तथा जो भविष्य में लाभार्थों की गारंटी करते हैं।

पूँजी का दृष्टिकोण क्या है? विनियोग के औचित्य के इसके अपने मानदंड हैं। सर्वाधिक सामान्य मापदंड है 'लागत-खपत' अर्थात् यथाशीघ्र खर्चों की पूर्ति जिसके साथ अधिकतम विश्वसनीय गारंटियाँ हों। व्यापार इस सुनहरे नियम, जिसने दूर्ज्वा वर्ग को कभी निराश नहीं किया, को वैज्ञानिक विकास पर भी लागू करता है तथा ज्ञान को वह एक माल के रूप में समझता है जिसे उत्पादित किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है।

सामान्य विनियोजन की अपेक्षा वैज्ञानिक शोध में लगाये गये धन से लाभ-प्राप्ति देर से होती है। इसमें बहुत बड़ी जोखिम निहित है क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक अपने काम की भूल-चूक के विषय में कोई गारंटी नहीं देता। और यद्यपि समकालीन पूँजीवाद इस जोखिम को उठाने को विवश है, क्योंकि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रान्ति ने ज्ञान के संचय को किसी भी उत्पादन की आवश्यकता कड़ी बना दिया है, इसका तात्कालिक लक्ष्य सदैव मुनाफ़ा कमाना है। विज्ञान एवं प्रविधि की

उपलब्धियों के प्रति—प्रतियोगितात्मक संघर्ष पर आधारित—नजरिया अन्ततः उनके विकास को अवरुद्ध कर देता है। यह खासतौर पर दीर्घकालिक वैज्ञानिक शोध के लिए सही है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रविधि के विकास के लिए सैन्यवाद अपनी सारी शाखा-प्रशाखाओं के साथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। किन्तु जैसा कि मार्क्स ने अपने समय में इंगित किया था कि हथियारों की दौड़ पर किये हुए खर्चें “आर्थिक दृष्टि से, राष्ट्र द्वारा अपनी पूँजी के एक हिस्से को पानी में बहाने के समान होते हैं।”¹ सैन्य प्रेरणा समाज को समृद्ध नहीं बनाती, बल्कि उसे लूटती है; अर्थव्यवस्था का सैनिकीकरण वैज्ञानिक विकास को एकपक्षीय तथा विरूपित कर देता है, कुछ अध्ययनों को प्रेरित करके व अन्य को बाधित करके, वैज्ञानिक शोध की प्रणाली में असंतुलन का कारण बनता है। उत्पादन की अन्य शाखाओं की भाँति, हथियारों के निर्माण के उद्योग में भी व्यापक उद्देश्य मुनाफ़ाखोरी ही है।

“यह एक ऐसा युग है जिसमें मुनाफ़ाखोरी का उद्देश्य अक्सर प्रमुख होता है, दरअसल इस सीमा तक, कि दूसरे उद्देश्यों को ताक पर रख दिया जाता है”, नॉर्वर्ट बीनर ने लिखा, “जनसमुदाय के लिए विचारों का भूतस्थ डॉलर और सेंट के आधार पर अनुमानित किया जाता है, तो भी डॉलर और सेंट नए विचारों की तुलना में अस्थायी मुद्रा है। कोई भी नई खोज, जो नए प्रयोग का मार्ग-दर्शन करने की स्थिति तक पहुँचने में पचास साल लगा देती है, अक्सर उन लोगों को लाभ नहीं पहुँचा पाती जिन्होंने उसके लिए खर्च किया था, फिर भी यदि ये खोजें न की जाएँ, तथा हम उन्हीं पर निर्भर करते रहे जो कि पहले ही की जा चुकी हैं तो इसका अर्थ यही होगा कि हम अपने बच्चों तथा उनके भी बच्चों (अगली दो पीढ़ियों) के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।”

यह एक बहुत सही टिप्पणी है, फिर भी यह नोट किया जाना चाहिए कि समकालीन पूँजीवाद ने विज्ञान की प्रगति को अवरुद्ध नहीं किया है। इसके विपरीत, वह विभिन्न वैज्ञानिक शोधों को जोर-शोर से प्रेरित करता है। किन्तु एक तो यह विकास अत्यधिक असमान होता है तथा दूसरे यह है जो निजी उद्योग की प्रणाली से ही पैदा एक अन्य विरोधी प्रकृति का सामना करता है। बड़ा व्यापार वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति के परिणामों पर एकाधिकार कायम करने की किराक में रहता है और मुनाफ़ों को एकत्रित करने के लिए ही उनका उपयोग

1. मार्क्स-एंगेल्स, *मारवाइज*, खंड IV, पृ. 29 (रूसी में)

2. नॉर्वर्ट बीनर, *आइ एम ए मेमेमेटिजियन*, न्यू यॉर्क, 1956, पृष्ठ 161-62

करता है। बहुत प्रायः इजारेदारियाँ वैज्ञानिक एवं प्राविधिक उपलब्धियों को संवारने व छिपाने की जीतोड़ कोशिश भी करती है उनसे जितना ज्यादा अतिरिक्त मूल्य बटोर सकती है बटोरती हैं और बाज़ार में अपने प्रतिद्वन्द्वी व्यापारियों को कुचलती है।

फिर भी, शोध और विकास में प्राप्त उपलब्धियों पर एकाधिकार केवल एक अल्पजीवी और स्थानीय आर्थिक प्रभाव ही पैदा करता है। विज्ञान की प्रगति और तदनु रूप सारे समाज की प्रगति को घोसा करके यह बाद वाली प्रकृति अनिवार्यतः क्लीमत वसूल करती है। पूंजीवाद विज्ञान के विकास और पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक मूल्य और प्रगति के मानदंडों के बीच की असमाधानीय विरोधमूलक भ्रांति की ओर तेजी से प्रवृत्त हो जाता है। पूंजीवादी प्रणाली स्वयमेव पुराने उत्पादन सम्बन्धों और वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति द्वारा पैदा की गई नई उत्पादक शक्तियों के सतत विकास की आवश्यकता के बीच में पंसे जाती है।

“जो निश्चित है वह सिर्फ एक बात है,” अमरीकी विद्वान् रॉबर्ट हेल्ब्रॉनर अनुभव करते हैं, “वह है समाज के भीतर विज्ञान के सक्रिय उपयोग के नए विचार और सामाजिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद के विचार के बीच गभीर असामंजस्य का होना है”। अंत में पूंजीवाद को विज्ञान की तराजू में तोला जाता है और उसे न केवल एक प्रणाली के रूप में किन्तु एक दर्शन के रूप में भी दरिद्र पाया जाता है।¹

विज्ञान का सीधे तौर पर उत्पादक शक्ति के रूप में रूपांतरण प्रक्रिया का केवल एक पक्ष है। व्यक्त की नई माँगों के स्तर पर दूसरा पक्ष विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्रांति काम में और अधिक प्रतिभा को समाहित कर देती है; आज का मजदूर अब केवल मशीन का पुर्जा मात्र नहीं रह सकता—एक विचारशून्य स्वचालन के रूप में। स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों को चालना देने के लिए उसे एक उन्नत कुशल विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित होना चाहिए, जो, इसके अतिरिक्त अपने काम के परिणामों के विषय में भी बढ़-चढ़ कर रुचि रखता हो।

अतः पूंजीवाद के सामने सिसा की समूची प्रणाली को आमूलचूल पुनर्गठित करने तथा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का चुनौती भरा काम उपस्थित हो जाता है। बहुत से पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने इस विषय में लिखा है। अमरीकी विद्वान पीटर ड्रकर की राय में, तात्त्विक रूप से नया तथ्य यह है कि समाज और अर्थ-

व्यवस्था का विकास तब तक पूरी तरह प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि सभी को उनकी योग्यताओं व सामर्थ्य के अनुरूप शिक्षा न मिले। एक अशिक्षित व्यक्ति शीघ्र ही अनुत्पादक हो जाता है, और आज के समाज को 'शिक्षित समाज' होना चाहिए ताकि वह उन्नति एवं विकास कर सके तथा जीवित रह सके। लेकिन इकर द्वारा निरूपित समयकी यह भाँग एक बार फिर पूँजीवाद के मूलतः मानवता-विरोधी सामाजिक मानदंडों से रू-व-रू होती है। शिक्षा-प्रणाली परंपरागत पूँजीवादी समाज के साथे में प्रारम्भिक जन शिक्षा के रूप में ढली है। 'जनशिक्षा', एल्विन टॉफ़लर लिखते हैं, "एक ऐसा उम्दा यन्त्र था जो औद्योगिकवाद के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुकूल प्रौढ़ों को ढालने के लिए पैदा किया था।"¹

इसका मतलब है कि पूँजीवादी उत्पादन की आवश्यक जानकारी रखने वाले शिक्षित मजदूरों की आवश्यकता थी। कुछ समय तक इससे अधिक और किसी बात की आवश्यकता नहीं। किन्तु अब अधिक बौद्धिक कार्य ने स्थिति को घस्तुतः बदल दिया है। एक आधुनिक मजदूर को अब और अधिक मासपेशियों की ताकत की आवश्यकता नहीं होती; किन्तु जटिल और कभी-कभी रचनात्मक उत्पादन समस्याओं को सुलझाने की योग्यता की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम के स्थान पर एक खास तौर से प्रशिक्षित ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित स्वचालित प्रणालियाँ तेजी से प्रवेश पा रही हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रारम्भिक शिक्षा की पुरानी प्रणाली अब इस काबिल नहीं है कि उत्पादक शक्तियों के आगे के विकास को आश्वस्त कर सके। 'शिक्षा में क्रांति' एक तात्कालिक आर्थिक आवश्यकता में बदल रही है और सामयिक उत्पादन की महत्वपूर्ण शक्ति का रूप धारण कर रही है।

भविष्य में व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास, मनुष्य की क्षमताओं और बौद्धिक योग्यताओं के कार्यान्वयन की अपेक्षा रहेगा। पूँजीवाद के अधीन ऐसे श्रमिकों का उदय नितांत समस्यामूलक है, क्योंकि इसने न तो ऐसे हालात पैदा किए हैं और न ही वह ऐसा कर सकता है जिससे इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास हो। दर-असल, एक विरोधी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और इजारेदारियों की यह इच्छा कि हिंसा और क़त्ल के प्रचार के द्वारा व्यक्ति को नष्ट किया जाए और उसको अति लुच्छ सिद्ध किया जाए, उपभोक्ता मनोविज्ञान पैदा किया जाए और तथा-कथित लोक-संस्कृति को विकसित किया जाए। मानवी व्यक्तित्व के उसके आध्यात्मिक तत्व को जान-बूझकर नष्ट-भ्रष्ट करना एक प्रकार के संघर्ष का वह रूप है जिसे वर्तमान साम्राज्यवाद सामाजिक क्रांति के विरुद्ध जारी रखता है; यह मजदूर वर्ग को बौद्धिक रूप से निहत्था करने का ही एक तरीका है। यदि पूँजीवादी इस रुख को बदल देते और व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास को प्रोन्नत करने

की चेष्टा करते तो उनके लिए वह अपनी ही मौत की सजा पर दस्तखत करने के समान होता। अतः ऐतिहासिक संदर्भ में श्रम का बौद्धिकीकरण पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के साथ नितांत असंगत ठहरता है। पूँजीवाद न केवल एक आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनी उम्र से अधिक जीवित रह लिया है, अपितु आध्यात्मिक मूल्यों की प्रणाली के रूप में भी, जिसका दिवालियापन वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति द्वारा लाये गए सामाजिक बदलावों की स्थिति में जिसका दिवालियापन प्रकट हो रहा है, व्यर्थ सिद्ध हो चुका है।

बौद्धिकीकृत श्रम के लिए परंपरागत पूँजीवादी प्रणाली में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की वजह से दूसरे प्रकार के अन्य प्रोत्साहनों को दिए जाने की आवश्यकता पैदा होती है। उदाहरण के लिए एक मशीन चालक का काम बड़े स्नायविक और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि गुणात्मक रूप से नए मनोवैज्ञानिक स्रोत का निर्माण किया जाए जो उत्पादन के दौर में स्नायविक प्रणाली में निरंतर होने वाली क्षतियों की पूर्ति करने में समर्थ हो। श्रमशक्ति के पुनरोत्पादन की समस्या अपने आपको एक नए आसक्त में प्रस्तुत करती है, अतः श्रम के भौतिक और नैतिक प्रोत्साहनों से संबंधित प्रश्नों का एक नया समाधान ढूँढा जाना चाहिए।

सामाजिक मूल्य लोगों के क्रियाकलापों को प्रेरित करते हैं। किन्तु वे उत्पादक शक्तियों के विकास और मानवता के एक सामाजिक-आर्थिक स्वरूप से दूसरे में संक्रमण के साथ बदलते हैं तथा प्रत्येक ऐसा संक्रमण लोगों के बीच नए संबंध पैदा करता है। मार्क्स ने ऐसे संबंधों के तीन प्रकारों के बारे में लिखा—“व्यक्तिगत निर्भरता के संबंध, पहले नितांत आदिम—समाज के ये पहले रूप थे जब लोगों की उत्पादकता एक भगव्य सी सीमा तक और अलग-अलग स्थानों में विकसित थी। व्यक्तिगत निर्भरता जो भौतिक निर्भरता पर आधारित थी, वह समाज का दूसरा बड़ा ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत सार्वभौम सामाजिक विनिमय की, सार्वभौम संबंधों, सामाजिक जरूरतों और सार्वभौम योग्यताओं की व्यवस्था निर्मित होती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व जो व्यक्तित्वों के सार्वभौम विकास पर आधारित हो, सबकी सामूहिक सामाजिक उत्पादकता की अधीनता को सबकी सामाजिक संपदा के रूप में स्वीकार्य हो—ऐसी है तीसरी अवस्था।”¹

इन तीनों में से प्रत्येक के व्यापार के लिए उत्तरदायी होवे नैतिक प्रोत्साहन।

होते हैं जो कार्य दबाव, भी तथा

भौतिक पारिवारिक, सामंत

पूँजीवाद

भी काम में संलग्न हों, उनके काम की इतिश्री हथियारों के निर्माण में होती है— बहुत समय से एक सूक्ति बन चुका है। मानसं ने लिखा—“हर वस्तु अपने में स्वयं का उलटा समाहित किए हुए दिखाई देती है, हम देखते हैं कि वे मशीनें जो आदमी की मेहनत को हल्का करने की आश्चर्यजनक शक्ति रखती हैं और उसे अधिक फलदायी बना सकती हैं, लोगों के लिए भूख और थकान लाती हैं। किसी विचित्र जादू की वजह से नए और अब तक न खोजे हुए घन के साधन भी गरीबी के साधनों में बदल जाते हैं। यह ऐसा है मानो प्राविधिक ज्ञान की जीते नैतिक पतन की कीमत पर हासिल की गई हों।”¹ यह टिप्पणी इतनी सामयिक है कि ऐसा लगता है जैसे यह आज ही व्यक्त की गई हो।

लेकिन जबकि अतीत में ये रूपांतरण, चाहे वे लोगों को डेर-सी तकलीफ देते थे, फिर भी उनके जीवन के लिए खतरा नहीं पैदा करते थे, आज उनके पास आत्मप्रचुर शक्ति आ चुकी है, वह अनियंत्रित बन चुकी है और सम्भ्यता के अस्तित्व को ही खतरा पैदा कर रही है। पहले पूंजीवाद की बीमारियों, जबकि वे लाखों-करोड़ों के लिए कष्टों और गरीबी के अभिशाप का कारक हुआ करती थी, का स्वरूप स्थानीय हुआ करता था, वे आज ऐसी मारक बीमारियों में परिवर्तित हो चुकी हैं तथा विशालकाय महामारियों का रूप धारण कर चुकी हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी मृत्यु की आशंका से प्रस्त है।

युद्ध और शांति की समस्या को लें। निरंतर बना हुआ नाभिकीय खतरा भी पूंजीवाद के पुराने नासूर के बहुत बड़े हुए रूप को ही प्रकट करता है—उसकी आक्रामक प्रकृति को। नाभिकीय गतिरोध, जो कि वैज्ञानिक एवं प्राविधिक की क्रांति का ही परिणाम है। हथियारों की दौड़ की वह ऐतिहासिक सीमा है जिसके पर पूंजीवाद का आत्म विनाश भंडराता है। ऐसा लगता है कि फिर भी किसी जादुई गति की वजह से वह डार्नड्स के बेपैदे के पीपों को—युद्ध की भौतिक और तकनीकी तैयारी के रूप में भरता चला जाता है। और इसलिए जो निष्कर्ष निकलता है वह विरोधाभास पूर्ण तो है ही, एक उजागर तथ्य भी है: कि पूंजीवादी व्यवस्था हथियारों की दौड़ को बढ़ाती चली जा रही है, तथा इस प्रकार एक ओर तो मानवता को एक ताप-नाभिकीय महाविपत्ति की तरफ धकेल रहा है तथा दूसरी ओर आत्म-विनाश के रास्ते को साफ कर रही हैं।

विश्व-व्यापी महत्व की एक अन्य सामयिक समस्या, भौगोलिक वातावरण जन्य विपत्ति, को लें। प्राकृतिक ससाधनों का अनैतिक दोहन, सैन्यवाद की ही भांति, पूंजीवाद का एक अन्तर्निहित नियम है। प्रकृति के बारे में, घरती को उजाड़ने की पूंजीवादी रणनीति ने पर्यावरण जन्य संकट को मानवता के असली

घतरे के रूप में बदल दिया है। ऐसा कहने के पीछे एक तर्कसंगति है कि नियोजित वैज्ञानिक प्रयास के अभाव में और सर्वाधिक संकल्पवद्ध अंतर्राष्ट्रीय उपायों के लागू करने की कमी की वजह से इसे असमाधानीय समझा जा सकता है।

पश्चिम में इन दिनों इस बात की व्यापक चर्चा चल पड़ी है कि वातावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। यह उन शक्तियों के द्वारा प्रोत्साहित है जो प्रायः असली सामाजिक सारतत्त्व तथा समस्या के कारणों में मिलावट करने में संलग्न हैं अपनी सारी राजनीतिक सट्टेवाजी में इसका उपयोग कर सकें। 22 जनवरी सन् 1970 के अपने संघीय सदेश में, संयुक्त राज्य अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने (उनके देश पर जीवमंडल के प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी धायत होती है) जनता के नाम एक अलंकारिक अपील करते हुए कहा—“1970 के दशक की भीषण समस्या है—क्या हम प्रकृति के साथ शांति कायम करें तथा हमारे द्वारा अपनी हवा, धरती व पानी को पहुँचाई क्षति का प्रायश्चित्त करें?”¹

समस्या के इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण के विरोध में कुछ भी कहना कठिन ही होता यदि यह साफ़तौर पर इतना पाखंडपूर्ण न होता। निस्संदेह जिस क्षति की चर्चा निक्सन ने की है वह बड़ी है और महामारी की गति से बढ़ रही है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका जिसकी जनसंख्या 1970 के दशक के आरंभ में दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 5.7 प्रतिशत थी, उसने दुनिया के प्राकृतिक ससाधनों के 40 प्रतिशत का उपयोग किया और पृथ्वी ग्रह के कुल 50 प्रतिशत को प्रदूषित किया। विशेषज्ञों के अनुसार अब तक संयुक्त राज्य अमरीका उस आलोच्य रेखा को पार कर चुका है जबकि उपभोगशुदा प्राकृतिक साधनों का पुनर्भरण स्वाभाविक प्रक्रिया में नहीं होता तथा उसके लिए विशेष उपाय आवश्यक होते हैं।

कोई यह सोच सकता है कि इसने अमरीका के शासक तंत्र को इन वास्तविक कारणों को उद्घाटित करने के लिए तथा जीवमंडल की रक्षा के लिए प्रभावशाली संपर्प छेड़ने को उत्साहित किया होगा।

तो भी, इस क्षेत्र में वाछिन परिणाम, जैसा कि सर्वत्र सभी स्वीकार करते हैं, अब तक असंतोषजनक है। पूँजीवादी देशों में प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करने के निमित्त जो भावपूर्ण अपीलें की गईं वे मृतपत्र बनकर रह गईं। स्पष्ट है कि तब तक किसी प्रगति की आशा नहीं की जा सकती जब तक कि उन पूँजीवादी इजारे-दारियों के विरुद्ध कोई संकल्पवद्ध उपाय नहीं किए जाते जो प्रकृति को खोखला करने और उसे प्रदूषित करने की आपराधिक सन्नियता के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पूँजीवादी प्रचार तंत्र, जिसी पर भी दोष मढ़ सकता है—जनसंख्या

1. ग्यु. एस. न्यूज एंड वॉर्ल्ड रिपोर्ट, अक्टू-5, 2 दिसम्बर 1970, पृ. 60

पर, औद्योगीकरण, विज्ञान और प्रविधि के विकास पर—तार्किक वह इजारेदारी पूंजीवाद को अपराध से बरी कर सके। गाइ वायोलैंट, जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया है, लिखते हैं: “हम हर वस्तु से प्रदूषण पैदा करते हैं—अपनी चिमनी के धुएँ से, अपनी कारों के धुएँ से, अपने भोजन की जूटन और बचे-खुचे से, अपने स्नानघरों के पानी से, अपनी सांझी के धोवन से, अपने अखबारों के कागज से, प्लास्टिक बोतलों से, टिन के डिब्बों से—सभी लोगों को दोष दिया जाना चाहिए क्योंकि सब उपभोक्ता हैं—साथ ही सबसे बड़े प्रदूषक वही करते हैं जो औद्योगीकरण के हितों के अनुकूल होता है।”¹

‘घर’ में पर्यावरण संवर्धनी संकट की व्याख्या अधिकांशतः मिथ्या दुविधा के रूप में की जाती है : या तो सादगी भरे मितव्ययता के उपाय काम में लो ‘या प्राकृतिक संसाधनों को निक्षेप कर दो; या तो आर्थिक विकास को धीमा कर दो या ‘जीवन स्तर’ को नीचा बना लो। साम्राज्यवादी सिद्धांतकारों में से सर्वाधिक इस तथ्य के छिपाने के प्रति चिंतित हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो साफ़तौर पर संकीर्ण कोटि के विशेष प्रयास पर आधारित है तथा जिसका आधार तत्काल मुनाफ़ा कमाना है, का सामना प्राकृतिक संपदा के वैज्ञानिक दोहन से ऐसा विरोध है जिसका समाधान संभव नहीं है। इसलिए भौगोलिक वातावरण के संकट का दोष औद्योगिक विकास के मत्थे मढ़ दिया जाता है। ‘वैदेशिक’ उपयोग के लिए वातावरण की रक्षा से संबंधित सिद्धांत को अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान को स्थगित करने के लिए काम में लिया जाता है तथा इस विश्वजनीन समस्या पर चिंतित होने का ये बहाना मूलभूत सामाजिक प्रश्नों से जनसमूह को काट दिया जाता है।

यहाँ कुछ और भी कहने की आवश्यकता है। यद्यपि ऊपरी तौर पर अमरीकी प्रचार तंत्र इस बात से चिंतित-सा लग रहा है कि आधुनिक औद्योगिक विकास के कारण वातावरण को नुकसान पहुँच रहा है, पेंटागन (ख़ासकर निवसन के राष्ट्र-पतित्व के दौर में) ने हिंदचीन में व्यापक तौर पर निष्पत्रकों और जड़मूल नाशकों को काम में लिया। प्रोफ़ेसर मैथ्यू मिसेल्सन के नेतृत्व में गठित जीववैज्ञानिकों के दल, जिसने मौके पर जाकर इस समस्या का अध्ययन किया, द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन ने यह रहस्य उद्घाटित किया कि दक्षिणी वियतनाम की सीमा का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल, जो संयुक्त राज्य अमरीका में मैसाचुसेट्स राज्य की अपेक्षा बड़ा क्षेत्र है—निष्पत्रकों के भयंकर विनाशात्मक प्रभावों से ग्रस्त हो गया।

यह स्वाभाविक ही है कि, अमरीकी प्रचार तंत्र इन तथ्यों के विषय में बिल्कुल चुप है और पर्यावरण की इस समस्या को वर्ग-सघर्ष में विजली के कोड़े के रूप में

कॉम में ले रहा है। साम्राज्यवादी प्रचार सेवाएँ वातावरण प्रदूषण को एक ऐसी समस्या के रूप में प्रस्तुत करती हैं जो, उनकी योजना के अनुसार, सामाजिक विरोधों को पृष्ठभूमि में डाल देंगी।

यह इस तथ्य के बावजूद किया जाता है कि वातावरण संकट एक नई सामाजिक और राजनीतिक समस्या के रूप में विकसित हो रहा है जो अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से घनिष्ठता के साथ गुंथा हुआ है। यह संकट—जो समस्त मानवता के विशाल क्रियाकलाप के लिए खतरा उत्पन्न करता है और जिसने अब तक लाखों श्रमिकों को नुकसान पहुँचाया है—पूँजीवादी प्रणाली की तर्कहीनता को ही और अधिक प्रमाणित करता है।

पश्चिम में इस तथ्य को तेजी से स्वीकारा जा रहा है। “तो हम एक निर्णायक प्रश्न की ओर आते हैं—आधुनिक प्रविधि का सोलोमन कौन होगा जो उस सारी अच्छाई को तराजू में तोल सके जो परिस्थिति विज्ञान और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध इसमें से पैदा होती है?” ब्रिटिश परिस्थिति वैज्ञानिक बेरी कॉमनर लिखते हैं और निम्नांकित निष्कर्ष निकालते हैं—“दरअसल, हम जानते हैं कि आधुनिक प्राविधिक ज्ञान, जिसे निजी तौर पर हथिया लिया गया है, यदि उस सामाजिक अच्छाई—परिस्थितिमंडल—को ही नष्ट कर देता है जिस पर यह आधारित है तो यह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता।

“अतः एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जो सामाजिक लेन-देन के मुकाबले मूलतः निजी लेन देन पर आधारित है अधिक समय तक उपयुक्त नहीं रहती और इस विशाल सामाजिक भलाई की व्यवस्था करने में तेजी से प्रभावहीन हो रही है। अतः इस प्रणाली के परिवर्तन की आवश्यकता है।”¹ महत्वपूर्ण भौगोलिक वातावरण के कारणों के द्वारा भी यह अनिवार्य बनाया जा रहा है कि मानवता का संक्रमण पूँजीवाद से साम्यवाद में हो।

हमने केवल दो विश्वव्यापी मुद्दों पर बहस की है। किंतु यदि हम अनेक अन्य समस्याओं को लें—असमान आर्थिक विकास, पुरानी सैन्य आर्यों बेरोजगारी, संस्कृति का पतन और व्यक्तित्व का विनाश, नागरिक गवट, विनाशमान देशों की ग्रामीण और उनका पिछड़ापन, और इस सूची की ओर आगे तक ले जाने पर, हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, यानी कि उनमें से किसी बिंदु को पूँजीवाद में अनग नहीं किया जा सकता। उत्पादन की पूँजीवादी पद्धति को समाप्त करना ही निगमदेह एवमात्र प्रभावशाली तरीका है जिसके तहत जनममुदाय के हितों और मानव प्रगति के हक में हम उन समस्याओं को गुलामा कर सकते हैं।

1. बेरी कॉमनर, ‘द क्वांटिफाइड साइड, नेचर, वैन एण्ड टेंशननेस’, ‘यूएसए’, 1972, पृ० 197

2. वही, पृ० 237

वर्तमान और भविष्य की विश्वव्यापी समस्याओं के सामने पूँजीवाद की नपुंसकता बूज्वा विचारधारा के उस संकट की पुष्टि करती है जो उसकी अपनी नितांत असहायता और हताशा को अभिव्यक्ति देता है। बूज्वा साहित्य, सिनेमा, रेडियो और टेलिविजन घोषणा करते हैं कि सामाजिक, साइबरनेटिक और आनु-वंशिक अभियांत्रिकी के परिणामस्वरूप, ताप-नाभिकीय युद्ध के अनिर्घटित जीव-वैज्ञानिक कारकों के प्रभाव के कारण पर्यावरण से उत्पन्न घुटन और इसी प्रकार की अन्य स्थितियों आदि की वजह से मानवजाति का विनाश अवश्यभावी है। संक्षेप में, मानवजाति अपनी समस्याओं को काबू करने में असमर्थ है, वह अंधी गली में अटक गई है और उसका विनाश अवश्यभावी है।

अमरीकी विद्वान हब्लू० चागर लिखते हैं कि प्रतीकात्मक अर्थ में बीसवीं सदी का आदमी उस एक बच्चे के समान है जो टोकरी में अंतिम फ़सले की देहलीज पर पड़ा बिलबिला रहा है। अपनी आवेगपूर्ण निष्कपटता में वह ऐसी नियति की कृपा पर फेंक दिया गया है जो कल्पना से भी परे है।

ये निराशावादी भावनाएँ अभिशप्त एवं हताश पूँजीवादी दुनिया के विचारकों की खास भूमिकाएँ हैं, जो इसके सन्निकट विनाश की सारी मानवता के लिए महा विपत्ति मानते हैं। जैसाकि सेनिन ने लिखा—“वे लोग हताश ही हो सकते हैं जो बुराई के कारणों को नहीं समझते, मुलज्जाव का कोई मार्ग नहीं देख पाते, और संघर्ष के लिए असमर्थ होते हैं।”¹

कम्युनिस्ट भविष्य को भिन्न आलोक में देखते हैं। धार्मिक मानवता की खुश-हाली के लिए संघर्ष के अनुभव पर विश्वास रखते हुए, और महान् अकतूबर समाजवादी क्रांति के बाद के छः दशकों में प्राप्त अनुभव पर भरोसा करते हुए, वे जनकल्याण पर आधारित आशावाद के साथ भविष्य की ओर आगे देखते हैं। सोवियत लोग आगे के लिए विश्व-शांति की सुदृढ़ता और स्वतंत्रता, लोकतन्त्र और समाजवाद के लिए संघर्ष में भावी प्रगति के लिए किए जाने वाले तेजस्वी ऐतिहासिक कामों को संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ करते चले जा रहे हैं।

1. वी० आई० सेनिन, “एल० एन० तॉलस्तॉय एंड द माडर्न सेवर मूवमेंट” संकलित रचनाएँ
खंड 16, पृ० 332

आधुनिक विश्व अत्यधिक असमान है। हमारे समय और हमारे युग की मौलिक समस्याएँ, भावी पीढ़ियों की ऐतिहासिक नियति दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं पूँजीवाद और समाजवाद—और दो शत्रुतापूर्ण वर्गों—ब्रज्वा और सर्वहारा के जटिल और विरोधपूर्ण संघर्ष में निर्णीत होने जा रही हैं।

और लगातार बढ़ती हुई भूमिका वैचारिक संघर्ष के लिए महान् संघर्ष में एक विशाल इसका नतीजा, कम्युनिस्ट विश्व-दृष्टिकोण की निर्णायक जीत इतिहास द्वारा पूर्व-निर्धारित है। मरणासन्न वर्गों की द्वेषपूर्ण प्रतिरोध तथा प्रत्याक्रमण के उनके अड़ियल किंतु निरर्थक प्रयासों का यही कारण है।

बौद्धिक क्रिया व्यापार हमेशा से ही मानव जीवन का सबसे जटिल और नाजुक क्षेत्र रहा है और रहेगा। प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः यह विविध प्रकार के, और अक्सर अन्तर्विरोधपूर्ण, सामाजिक, राजनैतिक, सैद्धांतिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और अन्य कारकों के प्रभाव में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक समूह और स्तर के सैद्धांतिक विचारों की जटिल सरगम में एक वर्ग द्वारा निर्धारित, समाज द्वारा अनुकूलित और स्वयं की आत्मपरकता के द्वारा भावात्मक क्षणों से उद्बलित स्थितियों का एकांतिक सम्मिश्रण होता है। यह सब किसी अवधि विशेष के विशिष्ट सामाजिक जीवन को अनुपम संयोगों और वर्गों को पैदा करता है।

आज के समकालीन वैचारिक संघर्ष की विरोधात्मक प्रवृत्ति का यही कारण है। फिर भी यह अपनी न उलटी जा सकने वाली तक संगति के अधीन होती है : विचारों के संघर्ष में अनिवार्यतः उन्हीं की जीत होती है जो शब्दों में ही नहीं लेकिन काम में भी जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से सामंजस्य व संगति रखते हैं और जन-समुदायों की तात्कालिक समस्याओं के सुलझाने के ठोस तरीके अपनाते हैं। यह साधारण सत्य कम्युनिस्ट विचारधारा की सफलता और गति-शीलता को पूर्व-निर्धारित करता है।

यह निर्विवाद है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के निर्णय किया गया है,

—“सैद्धांतिक और राजनैतिक शिक्षा के भावी सुधार के विषय में” (1979) में कहा गया है। देश के लगभग सभी लोगों ने इसे पढ़ लिया है और यह मूलभूत महत्व की बात है।

वैचारिक और शैक्षिक कार्य की आगे बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि इस अवधि के उन बड़े कार्यों को पूरा किया जा सके जिनको सोवियत संघ के नए संविधान में सुनिश्चित किया गया है और जो विकसित समाजवाद की अवधि तथा सोवियत जनवाद की स्थितियों से उत्पन्न हो रहे हैं।

लेनिन का यह सूत्र, कि राज्य जन-चेतना से ही अपनी शक्ति हासिल करता है, इतना प्रासंगिक पहले कभी नहीं रहा जितना कि आज है, जब जन-समुदाय हर चीज को ममझता है और प्रत्येक का मूल्यांकन करने में समर्थ है, और हमेशा सचेतन और सतर्क होकर काम करता है। दूसरी ओर, वैचारिक और राजनैतिक शिक्षा को और अधिक ऊँचे स्तर तक ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर वैचारिक संघर्ष की पैनी तीव्रता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह एक तथ्य है कि साम्राज्यवादी प्रचारतंत्र चुनकर पेकिंग के आधिपत्यवादियों के सोवियत-विरोधवाद के साथ घुल मिल कर काम करता है। अपने प्रयत्नों का एकत्रीकरण करते हुए उन्होंने सोवियत लोगों के धितन पर एक दुष्ट आक्रमण कर दिया है और अपने आप से बाहर होकर दुनिया के लोगों की आँखों में सोवियत यथार्थ को लोहित कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में लोगों की सैद्धांतिक शिक्षा कम्युनिस्ट निर्माण के कार्यों को पूरा करने के प्रयत्नों में तथा विश्व में शांति और प्रगति के लिए संघर्ष का एक प्रमुख तत्त्व है। सफल सैद्धांतिक कार्य सोवियत संघ के आर्थिक, सामाजिक-राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास के मार्ग को एक बड़ी हद तक निर्धारित करता है। बहुत प्रकार से यह सोवियत संघ को इस बात में समर्थ बनाता है कि वह विकसित समाजवाद की अन्तर्निहित सम्भावनाओं का उपयोग कर सके और अपनी शांतिपूर्ण विदेश नीति का अनुसरण कर सके। इस प्रयास में समाजवादी समुदाय के देशों की भागीदारी है।

नए समाज की मौत के विषय में पूँजीवादी-भविष्यवाणियों के बावजूद समाजवाद क्यों ताकत हासिल करता चला जा रहा है? समाजवाद ही जन-साधारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उन समाधानों की खोज में इतना सफल क्यों हो रहा है मानवता जिन्हें अपने सारे इतिहास के दौरान खोज पाने में असफल रही? पूँजीवाद सभी राष्ट्रों और देशों को पिछड़ेपन और जड़तापूर्ण अस्तित्व में रहने को विवश क्यों करता है, जबकि समाजवाद समय की अल्प अवधि में ही उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर करता है? नूजवाँ वर्ग सदियों से चले आ रहे राष्ट्रीय विरोधों की तेज धार को कुंठित करने में असमर्थ क्यों रहा है जबकि

समाजवाद एक अल्प ऐतिहासिक अवधि में ही जनगण का एक नया ऐतिहासिक समुदाय बनाने में सफल हो गया जो कि अब कम्युनिस्ट समाज का निर्माण कर रहे हैं ! और अंत में, यह ऐसा क्यों है कि समाजवाद की विदेश नीति ही हमलावर ताकतों के खिलाफ संघर्ष में लोगों के लिए शांति और लाभदायक सहयोग के अवसर प्रदान करती है ?

ये प्रश्न, अपने सही स्वरूप में पूंजीवाद के लिए चुनौती है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार अकाट्यरूप से यह पुष्ट करता है कि हमारे इस युग के लिए मात्र बैज्ञानिक कम्युनिज्म का सिद्धांत ही मानवता के लिए सामाजिक और राजनैतिक मुक्ति का रास्ता प्रदर्शित करता है और केवल समाजवाद ही आज के समकालीन विश्व की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है।

माक्सवाद-लेनिनवाद के वैचारिक झंडे के नीचे सोवियत लोगों ने साठ वर्षों में ही समस्त क्षेत्रों—आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक—के क्रिया-कलाप में ऐतिहासिक जीतें हासिल की हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माक्सवादी-लेनिनवादी विचार अनेक यूरोपीय, एशियाई और लेटिन अमरीकी देशों में जिन्होंने समाजवाद का रास्ता अपनाया, राज्य विकास को प्रेरित करने वाले सैद्धांतिक आधार बन चुके हैं। माक्सवाद-लेनिनवाद ही पूंजीवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा है, जो शांति, लोकतंत्र और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज की वास्तविक वर्तमान कठिन परिस्थितियों में केवल कम्युनिस्ट आन्दोलन ही इस सम्मान का हकदार है कि उसने ऐसी समस्याओं को उभारा है जिनका हल विलम्ब सहन नहीं कर सकता, अर्थात् द्वितीय विश्वयुद्ध के दुष्परिणामों का विलीनीकरण, विश्व शांति को सुदृढ़ करना और मजदूर वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक उपलब्धियों का विस्तार करना। इस सूची में वे मूलभूत मुद्दे भी हैं; जैसे, सभी लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुटता, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का आगे का विकास और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु। यही वजह है कि विचारों के संघर्ष में बैज्ञानिक कम्युनिज्म का सिद्धांत और व्यवहार दुनिया भर के लगातार बढ़ते हुए बहुसंख्यक मजदूर लोगों के दिलों-दिमाग को, पहले से कहीं ज्यादा, जीतता जा रहा है।

कम्युनिस्टों के पास, स्वभावतः, सारे प्रश्नों के कोई तैयारशुदा जवाब नहीं हैं। लेकिन उनके पास ऐतिहासिक विकास की मूलभूत प्रकृति के सम्बन्ध में एक बहुत स्पष्ट विचारधारा है। वे अभिज्ञान की विज्ञान-आधारित पद्धति पर अपने क्रांतिकारी सिद्धांत और एक नई दुनिया बनाने के साठ से अधिक सालों के प्राप्त अनुभव पर विश्वास करते हैं। उन्हें यह कहने का पूरा हक है कि वे जानते हैं कि मानवजाति का कहीं और कैसे मार्गदर्शन किया जाता है और यह घोषणा करने की उनके पास हर प्रकार की तर्कसंगति है कि यह रास्ता श्रमिक जनगण को शांति

और सामाजिक न्याय की प्राप्ति की तरफ ले जायगा।

“कवियों की कल्पना ने प्रारम्भिक युगों के अज्ञान और भद्देपन में स्वर्णयुग को मानव जाति के झूले में रख दिया है; किन्तु इस युग को लौह युग के रूप में माना जाना चाहिए”।” महान् फ्रेंच विचारक हेनरी द सेंट-साइमन ने लिखा। “मानव जाति का स्वर्णयुग हमारे पीछे नहीं है, वह आगे आने वाला है, भविष्य में स्थित है; यह समाज व्यवस्था के पूर्ण होने में है; हमारे पूर्वजों ने इसे नहीं देखा; हमारे बच्चे एक दिन उसे प्राप्त करेंगे और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें।”।

कम्युनिस्ट समस्त धर्मजीवियों का इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सक्रियता से काम करने का आह्वान करते हैं।

